अमरीका में मज़दूर आन्दोलन

फास्टर रही डलेस

एस. आर. सुनेजा पब्लिकेशन्ज़
नई दिल्ली

राज सुनेजा
एस. आर. सुनेजा
पब्लिकेशन्ज़
नई दिल्ली

अनुवादक : यशपाल

—: मुद्रक :—
नीलकमल प्रिंटर्स
(प्रा०) लिमिटेड,
दिल्ली-६

विषय-सूची

प्रस्तावना

अमरीका में संगठित मज़दूरों की संख्या इस समय करीब डेढ़ करोड़ है। इस संगठित श्रमिक शक्ति का देश के भावी आर्थिक और राजनीतिक विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। हमारी लोकतन्त्रीय ज़ीवन-पद्धति को कायम रखने में सहायता पहुँचाने में स्वतन्त्र श्रमिक संगठनों के महत्त्व को अमरीकी जनता अब सामान्यतः स्वीकार करने लगी है, किन्तु श्रमिक-संगठनों की बढ़ती हुई शक्ति ने श्रम-सम्बन्धों के क्षेत्र में नयी और गम्भीर समस्याएँ पैदा कर दी हैं। अपनी इस वर्तमान स्थिति के बावजूद, तथ्य यह है कि श्रमिक आन्दोलन इतना शक्तिशाली इधर हाल ही में हुआ। मान्यता प्राप्त करने और जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए श्रमिक संगठनों को बहुत लम्बा और कड़ा संघर्ष करना पड़ा, कभी-कभी तो रक्तपात भी हुआ। श्रम-आन्दोलन के वर्तमान रूप को तब तक सही-सही नहीं समझा जा सकता जब तक कि इसे इस लम्बे और कड़े संघर्ष की पृष्ठभूमि में समझने की कोशिश न की जाय।

इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य वास्तव में सामान्य पाठक को यह बताना है कि अमरीका में श्रमिक-आन्दोलन का उस धुँधले उपनिवेशी युग से आरम्भ होकर 'न्यू डील' और फिर द्वितीय विश्वयुद्ध के हलचल-भरे दिनों में किस प्रकार विकास होता गया। राष्ट्रीय संगठनों पर विशेष बल दिया गया है, जैसे, राष्ट्रीय श्रम-संघ, 'नाइट्स आव लेबर', अमरीकी श्रमसंघ और औद्योगिक संगठन समिति। एक ही पुस्तक में श्रमिक आन्दोलन के हर पहलू का विवेचन सम्भव नहीं। अलग-अलग संघों के इतिहास, श्रमिक संगठनों में महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की भूमिका, श्रमिकों की शिक्षा और संघों के समाज-कल्याण कार्यों और अमरीकी श्रम-आन्दोलन का अन्य देशों के श्रम-आन्दोलन से सम्बन्ध जैसे विषयों पर अलग-अलग विस्तार से चर्चा न कर सारे आन्दोलन के समष्टि रूप का विवेचन करना ही उचित समझा गया। राष्ट्र के विकास की पृष्ठभूमि में श्रमिक आन्दोलन के इस

इतिहास को प्रस्तुत करने में, इन सारी सीमाओं के बावजूद, आशा है कि इसका समकालीन स्वरूप अधिक स्पष्ट रूप में पेश किया जा सका है जो कि आन्दोलन की सही धारणा बनाने के लिए बहुत आवश्यक है।

अमरीकी श्रम-आन्दोलन पर पहले भी अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और लेखक को वर्तमान पुस्तक की रचना में इन अध्ययनों से बहुत सहायता मिली। जिनका हवाला पुस्तक के अन्त में 'पुस्तक विवरण' में दिया गया है। परन्तु जहाँ कहीं यह महसूस हुआ कि और खोज करनी आवश्यक है, लेखक ने उसके लिए मूल स्रोतों का सहारा लिया। अनेक सहयोगियों ने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि को सर्वांश में या आंशिक रूप से पढ़ा, इसके लिए लेखक प्रो० अल्मा हर्बस्ट, हेनरी आर० स्पेन्सर और राबर्ट ई० मैथ्यूज, डेविड और रूथ एस० स्पिन्ज़ का बहुत आभारी है। लेखक, राबर्ट एल० क्रोवेल और आर्थर बी० टर्टलोट का भी, जो उस 'सिरीज' के क्रमश: प्रकाशक व सम्पादक हैं, जिसकी यह पुस्तक एक भाग है, उनके सुझावों और सलाह के लिए ऋणी है। एकदम अस्पष्ट पाण्डुलिपि को बार-बार टाइप करने के लिए लेखक एडिथ स्नोर और सैली डलेस का आभारी है। अपनी अन्य पुस्तकों की तरह इसके लिए भी लेखक मारियन डलेस का बहुत कृतज्ञ है जिन्होंने पाण्डुलिपि का अध्ययन किया और समय-समय पर बहुत विचारपूर्ण एवम् रचनात्मक सुझाव दिये।

—फास्टर रही डलेस

संशोधित संस्करण की प्रस्तावना

इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुए दस वर्ष से अधिक हो चुके और आज जब मैं पुनः संशोधित संस्करण की भूमिका लिखने बैठा तो ऐसा प्रतीत होता है कि १९४९ की भूमिका में जो कुछ लिखा, उसमें कोई नयी बात जोड़ने को नहीं है। १९६० की स्थिति को देखते हुए यह निश्चित रूप से दुहराया जा सकता है कि अमरीकी जनता, श्रमिकों की उत्तरदायित्व की भावना में यदा-कदा शंकालु हो जाने के बावजूद, यह मानने लगी है कि श्रमिक संगठन लोकतंत्रीय जीवन पद्धति की महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। साथ ही, ये शक्तिशाली संगठन आज भी ऐसी गम्भीर समस्याएँ पैदा करते रहते हैं जिनका प्रभाव सम्पूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों पर पड़ता है। ये ऐसी समस्याएँ नहीं हैं जिन्हें अन्तिम रूप से और सदा के लिए हल किया जा सके। अमरीकी समाज में संगठित श्रम आन्दोलन का दर्जा और स्वयं मजदूरों का दर्जा उन सभी परिवर्तनों और नयी बातों से प्रभावित होता रहता है जो निरन्तर विकासशील राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निहित हैं।

अमरीकी श्रम संघ (अमेरिकन फेडरेशन ऑव लेबर) और औद्योगिक संगठन समिति (कांग्रेस ऑव इंडस्ट्रियल आर्गनाइजेशन्स) का विलय गत दशाब्दी के श्रम आन्दोलन के इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है, लेकिन इससे श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। लैन्ड्रम-ग्रिफिन कानून, जो १९५९ में पास हुआ; भी एक काफी महत्त्वपूर्ण घटना है परन्तु औद्योगिक मामलों में सरकार की भूमिका के इतिहास के विकास-क्रम में इसका वैगनर कानून या टेफ्ट-हार्टले कानून से मुकाबला नहीं किया जा सकता। वास्तव में गत दशाब्दी में संगठित श्रम आन्दोलन ने उन उपलब्धियों को सुदृढ़ बना लिया जो उनको 'न्यू डील' और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान प्राप्त हुई थीं। यद्यपि अमरीकी श्रम संघ और औद्योगिक संगठन समिति के विलय से जो आशाएँ थीं वे पूर्णतः पूरी नहीं हुईं, और हाल ही में श्रमिक संघों को असफलताओं का सामना भी करना पड़ा जिनका भविष्य पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, परन्तु राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मार्ग निर्धारित करने में श्रमिक संघों की भूमिका आज भी सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बनी हुई है।

'लेबर इन अमेरिका' के इस नये संस्करण को तैयार करने में मैंने ऐसी सामग्री इसमें शामिल कर ली जो मुझे उपयुक्त लगी, श्रम-आन्दोलन के इतिहास के सम्बन्ध में इधर हाल में लिखीं महत्त्वपूर्ण रचनाओं को शामिल करने के लिए पुस्तक के अन्त में 'पुस्तक विवरण' को भी बढ़ा दिया और १९६० के आरम्भ तक के विकास के विवरण को इसमें शामिल कर लिया है। उल्लिखित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने निष्पक्षता के साथ समकालीन विकास-क्रम की व्याख्या करने की चेष्टा की है।

मई, १९६० फास्टर रही डलेस

१ : औपनिवेशिक अमरीका

औपनिवेशिक अमरीका में श्रम की प्राप्ति के मुख्य साधन करार-बद्ध नौकर अथवा गुलाम थे। १७ वीं और १८ वीं शताब्दि में स्वतंत्र श्रमिक बहुत थोड़े थे। लेकिन अटलाण्टिक समुद्र के किनारे बिखरे हुए छोटे-छोटे शहर जैसे-जैसे विकसित और समृद्ध होते गए वैसे-वैसे मिस्त्रियों और कारीगरों का महत्व बढ़ता चला गया जो या तो सीधे 'पुरानी दुनिया' से आए थे अथवा अपना करार पूरा कर लेने के बाद करार-बद्ध मजदूर के दर्जे से ऊपर उठ कर स्वतंत्र रूप से जीवनयापन कर रहे थे। इनमें बढ़ई, राज, जहाज बनाने वाले, पाल बनाने वाले, चमड़ा रंगने वाले, जुलाहे, मोची, दर्जी, धातु का काम करने वाले, टीन की चीजें बनाने वाले, खिड़कियों में शीशे लगाने वाले और मुद्रण का काम करने वाले शामिल थे।

इन श्रमिकों में से दक्ष कारीगर पहले स्वतंत्र रूप से अपने कारोबार करते थे, लेकिन जैसे-जैसे शहर विकसित होते गए, कुशल श्रमिकों ने अपनी छोटी-छोटी खुदरा दुकानें खोल लीं जिनमें वे दिहाड़िये और अप्रैण्टिस रखकर मजदूरी पर उनसे अपना काम करवाते थे। १८ वीं सदी के समाप्त होते-होते तक इन दिहाड़ियों ने स्थानीय मजदूर-समाज बनाने शुरू कर दिए थे जो पहली यूनियनों के बीज रूप थे जो बाद में जाकर संगठित मजदूर आन्दोलन के रूप में अंकुरित हुए।

उस जमाने की आर्थिक पद्धति इतनी सरल थी कि २० वीं सदी के जटिल औद्योगिक ढांचे से उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। मुट्ठीभर स्वतंत्र शिल्पियों तथा मिस्त्रियों की स्थिति का हमारे आधुनिक समाज के विशाल औद्योगिक श्रमिक समुदाय की स्थिति के साथ कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं है। औपनिवेशिक जमाने में मजदूरों के विरोध प्रदशन के कभी-कभार जो इक्के-दुक्के उदाहरण मिलते हैं उनमें और आजकल की राष्ट्र-व्यापी हड़तालों में जिन्होंने हाल के वर्षों में कोयला खानों, इस्पात तथा मोटर निर्माण के उद्योगों में उत्पादन, जिस पर हमारी परस्पर निबद्ध अर्थतंत्र सम्पूर्ण रूप से आश्रित है,

ठप्प कर दिया है इतना अधिक अन्तर है कि उससे ज्यादा अन्तर होना संभव नहीं है। फिर भी कुछ बुनियादी परिस्थितियां उस जमाने में भी कार्यशील रहीं जिन्होंने अमरीकी श्रम के समस्त इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।

१७ वीं और १८ वीं शताब्दि में मजदूरों की लगातार कमी रहने से मजदूरी की दर यूरोपीय स्तर से ऊँची रही। नई दुनिया में तरक्की के अवसरों ने वर्ग-विभाजन की पक्की रेखाएँ जो पुरानी दुनिया की सामन्ती विरासत थी, खत्म कर दीं और नए-नए प्रदेशों में जाकर बसने की आकांक्षा ने सामान्यतः एक प्रबल व्यक्तिवाद की भावना उत्पन्न की। औद्योगिक क्रांति ने जहां पुरानी आर्थिक व्यवस्था को बिल्कुल बदल दिया, वहां अमरीकी जीवन पद्धति के ये मूल तत्व, जिन्होंने श्रमिकों पर ही नहीं, अपितु हमारे समाज के अन्य सब वर्गों पर प्रभाव डाला, ज्यों के त्यों कायम रहे। ये तत्व श्रमिकों को लोकतंत्रीय प्रगति की उस व्यापक धारा में ले आए, जिसने हमारे इतिहास को विशिष्टता प्रदान की और अमरीका के संगठित मजदूर आन्दोलन को विशिष्ट तथ अद्वितीय बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया।

शुरू-शुरू के प्रवासियों ने वर्जीनिया तथा मैसाच्युसेट्स में उतरते ही अमरीका में, जो उस वक्त जंगल ही जंगल था, मजदूरों की अनिवार्य आवश्यकता अनुभव की। जेम्सटाउन की पहली यात्रा और बाद की तीन यात्राओं में वर्जीनिया कम्पनी ने साहसी व्यक्तियों, सैनिकों तथा भद्रजनों की मिलीजुली जमात भेजी। इतने असन्तोषजनक सामान से एक स्थिर बस्ती बसाने में अधिकाधिक निराश कप्तान जॉन स्मिथ ने अन्त में जोरदार विरोध-पत्र भेजा। उसने वर्जीनिया कम्पनी को लिखा, "जब तुम दुबारा आदमी भेजो तो मेरी प्रार्थना है कि हमारे पास इस समय जैसे आदमी हैं उन्हें हजार की संख्या में भेजने के बजाय अच्छे साज-सामान से लैस सिर्फ ३० बढ़ई, किसान, माली, मछियारे, राज तथा लकड़हारे भेज देना।"

प्लाइमाउथ की हालत कुछ अच्छी रही। उसके छोटे से यात्री दल में ज्यादातर शिल्पी, कारीगर व अन्य मजदूर थे। उनके नेताओं को भी लन्दन के बड़े भद्दे ढंग से "मोचियों, दर्जियों, फेल्ट बनाने वालों और ऐसे ही जाने वाले लोगों के लायक गाइड" बताया था। १६३० में

मैसाच्युसेट्स वे के प्युरीटन प्रवासियों में भी शिल्पियों व किसानों की बहुतायत थी। लेकिन इस लाभ के वावजूद न्यू इंग्लैण्ड के संस्थापकों ने वर्जीनिया के लोगों की तरह शीघ्र ही ऐसे लोगों की कमी महसूस की जो सन्तोषपूर्वक समाज के छोटे काम कर सकें। मैसाच्युसेट्स के गवर्नर ने १६४० में मजदूरों को उनके काम पर स्थिर रखने की कठिनाइयों का निराशापूर्ण उल्लेख किया। ये मजदूर निरन्तर सीमावर्ती इलाकों में जाते रहते थे जहां मजदूरी ज्यादा मिलती थी अथवा वे जमीन लेकर स्वतंत्र किसान बन जाते थे। कौटन मेथर "ईश्वर से विशेष प्रार्थना किया करते थे कि वह अच्छा नौकर भेजे..."

प्रवास के इन प्रारम्भिक दिनों में यद्यपि पहली और मुख्य मांग किसानों तथा लकड़हारों की होती थी, तथापि दक्ष मजदूरों की मांग भी तेजी से बढ़ी।

प्रवासियों में से ही लोग, चाहे पहले वे कुछ भी काम करते रहे हों, बढ़ई, राज, जुलाहे और मोची बनने के लिए मजबूर हो जाते थे। लेकिन दक्षिणी वागानों और न्यू इंग्लैण्ड के शहरों में, दोनों जगह दक्ष शिल्पियों तथा मिस्त्रियों की सदा आवश्यकता रहती थी।

मजदूरों सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए अमरीका के अलग-अलग स्थानों पर बहुत भिन्न-भिन्न प्रकार के उपाय अपनाए जाते थे। बस्ती औरों से पहले वसने तथा प्राकृतिक वातावरण के कारण न्यू इंग्लैण्ड ज्यादातर स्वतंत्र श्रमिकों पर निर्भर करता था। दक्षिण को अन्ततोगत्वा पूर्ण रूप से नीग्रो गुलामों पर निर्भर करना पड़ा। १७ वीं सदी में अधिकांश बस्तियों में तथा १८ वीं सदी में बीच की वस्तियों में ज्यादातर मजदूर करार-बद्ध नौकरों में से भर्ती किए जाते थे। अनुमान लगाया गया है कि नई दुनिया में जितने भी प्रवासी बसने के लिए आए उनमें से कम से कम आधे और सम्भवत: उनसे भी ज्यादा किसी न किसी करार के अन्तर्गत ही आए और अपने करार की शर्तें पूरी करने के बाद ही पूर्णत: स्वतंत्र नागरिक बने।

इस प्रकार के प्रतिज्ञा-बद्ध मजदूर पाने के तीन ज़रिए थे। वे स्त्री, पुरुष और बच्चे जिनके पुरानी दुनिया से रवाना होने से पूर्व ही इकरारनामे पर दस्तखत किए हुए होते थे, किराया चुका कर स्वतंत्र हो जाने वाले (रिडेम्पशनर) जो बस्तियों में आने के बाद अपना श्रम वेचकर नई दुनिया में लाये जाने का अपना किराया चुका देने के लिए राजी हो जाते थे और

सजायाफ़्ता जिन्हें अमरीका निर्वासित कर दिया जाता था ! एक वार वस्तियों में आ जाने के बाद इन सब लोगों का एक सामान्य करार-बद्ध वर्ग ही बन जाता था जो कुछ नियत वर्षों तक बिना कोई मजदूरी लिए अपने स्वामी के पूर्ण नियंत्रण में काम करते थे।

मजदूरों की मांग इतनी ज्यादा थी कि उनकी भर्ती का व्यापार चमक उठा। औपनिवेशिक बागानों तथा ब्रिटिश कम्पनियों के एजेण्ट इंग्लैड के गांवों और कस्बों में घूमते थे और बाद में वे यूरोप में और विशेष रूप से राइनलैण्ड के युद्ध ग्रस्त क्षेत्रों में गए और लोगों को अमरीका जाकर बसने के लाभ बताते थे। देहाती मेलों में वे पर्चे बांटते थे, जिनमें इस नई दुनिया के चमत्कारों का खूब लुभावना वर्णन रहता था और कहा जाता था कि वहां के सौभाग्यशाली आदमियों के मुंह में भोजन स्वयं आ पड़ता है और हर आदमी को अपनी जमीन का मालिक बनने का मौका मिलता है। ये वायदे प्रायः इतने लुभावने और जोश पैदा करने वाले होते थे कि नादान और भोले लोग इकरारनामों पर खुशी से हस्ताक्षर कर देते थे, बिना यह सोचे-समझे कि जिस नए जीवन में वे प्रवेश कर रहे हैं, उसमें क्या कठिनाइयां हो सकती हैं। इस प्रकार से लोगों को भर्ती करने वाले ये एजेण्ट जिन्हें ब्रिटेन के देहातों में 'क्रिम्प' और यूरोप में 'न्यूलैण्डर' कहा जाता था, ठग्गी और छलकपट करने में संकोच नहीं करते थे।

इन परिस्थितियों में हजारों व्यक्ति इंग्लैण्ड से "सब्जबाग़ दिखाकर" लाए गए और इस प्रकार की हरकतों को रोकने के लिये कोशिश करने के बजाय स्थानीय अधिकारी प्रायः उनको प्रोत्साहन देते थे। यह जो आम धारणा बनी हुई थी कि इंग्लैण्ड की आबादी जरूरत से ज्यादा है उसके कारण वे गरीबों और आवारा लोगों को, जिनके पास आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं होता था, और जो वैसे समाज पर शायद भार बन कर रहते, समुद्र पार भेज दिए जाने के लिए उत्साह से मंजूरी दे देते थे। वस्तुतः कभी कभी मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को पकड़वा मंगाते और उनके सामने प्रवास अथवा जेल का विकल्प रखते थे। यह यतीमों और अन्य किशोरों की, जिनके पालन पोषण का कोई ज़रिया नहीं था, देखभाल करने का भी एक आसान तरीका पाया गया। किडनैपिंग (अपहरण) शब्द की उत्पत्ति बस्तियां बसाने के इस कठोर तरीके से।

१६१९ में लन्दन की कॉमन कौन्सिल ने "एक झुण्ड में से १०० बच्चे छांट लिए जिन्हें कुछ वर्षों तक अप्रेण्टिस के तौर पर काम करने के लिये वर्जीनिया भेजा जाना था।" प्रिवी कौंसिल ने इस वात की जांच की और "इतनी गरीव आत्माओं को कष्ट और विनाश से उवारने के लिये" अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए वर्जीनिया कम्पनी को यह अधिकार दिया कि "अगर कोई वालक किसी किस्म की गड़बड़ी करता है तो अपने उद्देश्य के मुताविक वह उन्हें जेल भेज सकती है, सजा दे सकती है या उनके साथ अन्य प्रकार के वर्ताव कर सकती है और इस प्रकार उन्हें अपनी सहूलियत के मुताविक अधिक से अधिक तेजी से वर्जीनिया भेज सकती है।"

लगभग ४० वर्ष वाद वर्जीनिया कम्पनी द्वारा इस रिवाज का दुरुपयोग किए जाने पर शायद प्रिवी कौंसिल की आंखें खुलीं। पता चला कि ग्रेवसेण्ड्स पर दो जहाज लंगर डाले खड़े हैं उनमें बच्चे व अन्य नौकर दोनों हैं "जिन्हें धोखा व प्रलोभन देकर लाया गया है और जो अपने छुटकारे के लिए चीख पुकार मचा रहे हैं।" यह आदेश दिया गया कि जिन किन्हीं लोगों को उनकी इच्छा के विरूद्ध रोक रखा गया है—"यह इतनी वर्वर और अमानवीय चीज थी कि स्वयं प्रकृति और उससे भी ज्यादा ईसाई उससे घृणा किए विना नहीं रह सकते थे—" उन्हें तुरन्त रिहा कर दिया जाए।

इन परिस्थितियों में यह फर्क करना वहुत कठिन था कि कौन अपनी इच्छा से जा रहा और किसे जवर्दस्ती ले जाया जा रहा है, विशेषकर तव जव कि वे नादान गरीव और अवोध वालक उपनिवेशों में ऐसे करारबद्ध नौकरों की संख्या निस्सन्देह काफी थी जो शायद उस किशोरी की करुण गाथा को प्रतिध्वनित करें जिसका "सोट-वीड फैक्टर या मेरीलैण्ड की एक यात्रा" नामक १७०८ में प्रकाशित लघु पुस्तिका में वर्णन आया है।

इस प्रदेश के सव से सुखद समय में
मैं दुर्भाग्य से फंसा ली गई,
और शायद मैं यहां अन्य
किसी लार्ड या लेडी की तरह ही लगती थी,
तव मैं कोई गुलाम नहीं थी क्योंकि

सजायाफ़्ता जिन्हें अमरीका निर्वासित कर दिया जाता था। एक वार वस्तियों में आ जाने के वाद इन सव लोगों का एक सामान्य करार-वद्ध वर्ग ही वन जाता था जो कुछ नियत वर्षों तक विना कोई मजदूरी लिए अपने स्वामी के पूर्ण नियंत्रण में काम करते थे।

मजदूरों की मांग इतनी ज्यादा थी कि उनकी भर्ती का व्यापार चमक उठा। औपनिवेशिक वागानों तथा ब्रिटिश कम्पनियों के एजेण्ट इंग्लैंड के गांवों और कस्बों में घूमते थे और वाद में वे यूरोप में और विशेष रूप से राइनलैण्ड के युद्ध ग्रस्त क्षेत्रों में गए और लोगों को अमरीका जाकर वसने के लाभ वताते थे। देहाती मेलों में वे पर्चे वांटते थे, जिनमें इस नई दुनिया के चमत्कारों का खूव लुभावना वर्णन रहता था और कहा जाता था कि वहां के सौभाग्यशाली आदमियों के मुंह में भोजन स्वयं आ पड़ता है और हर आदमी को अपनी जमीन का मालिक वनने का मौका मिलता है। ये वायदे प्रायः इतने लुभावने और जोश पैदा करने वाले होते थे कि नादान और भोले लोग इकरारनामों पर खुशी से हस्ताक्षर कर देते थे, विना यह सोचे-समझे कि जिस नए जीवन में वे प्रवेश कर रहे हैं, उसमें क्या कठिनाइयां हो सकती हैं। इस प्रकार से लोगों को भर्ती करने वाले ये एजेण्ट जिन्हें ब्रिटेन के देहातों में 'क्रिम्प' और यूरोप में 'न्यूलैण्डर' कहा जाता था, ठग्गी और छलकपट करने में संकोच नहीं करते थे।

इन परिस्थितियों में हजारों व्यक्ति इंग्लैण्ड से "सव्जवाग़ दिखाकर" लाए गए और इस प्रकार की हरकतों को रोकने के लिये कोशिश करने के बजाय स्थानीय अधिकारी प्रायः उनको प्रोत्साहन देते थे। यह जो आम धारणा वनी हुई थी कि इंग्लैण्ड की आवादी जरूरत से ज्यादा है उसके कारण वे गरीवों और आवारा लोगों को, जिनकें पास आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं होता था, और जो वैसे समाज पर शायद भार वन कर रहते, समुद्र पार भेज दिए जाने के लिए उत्साह से मंजूरी दे देते थे। वस्तुतः कभी कभी मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को पकड़वा मंगाते और उनके सामने प्रवास अथवा जेल का विकल्प रखते थे। यह यतीमों और अन्य किशोरों की, जिनके पालन पोषण का कोई ज़रिया नहीं था, देखभाल करने का भी एक आसान तरीका पाया गया। किडनैपिंग (अपहरण) शव्द की उत्पत्ति वस्तियां वसाने के इस कठोर तरीके से ही हुई है।

१६१९ में लन्दन की कॉमन कौन्सिल ने "एक झुण्ड में से १०० बच्चे छांट लिए जिन्हें कुछ वर्षों तक अप्रेंण्टिस के तौर पर काम करने के लिये वर्जीनिया भेजा जाना था।" प्रिवी कौंसिल ने इस बात की जांच की और "इतनी गरीब आत्माओं को कष्ट और विनाश से उबारने के लिये" अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए वर्जीनिया कम्पनी को यह अधिकार दिया कि "अगर कोई बालक किसी किस्म की गड़बड़ी करता है तो अपने उद्देश्य के मुताबिक वह उन्हें जेल भेज सकती है, सजा दे सकती है या उनके साथ अन्य प्रकार के बर्ताव कर सकती है और इस प्रकार उन्हें अपनी सहूलियत के मुताबिक अधिक से अधिक तेजी से वर्जीनिया भेज सकती है।"

लगभग ४० वर्ष बाद वर्जीनिया कम्पनी द्वारा इस रिवाज का दुरुपयोग किए जाने पर शायद प्रिवी कौंसिल की आंखें खुलीं। पता चला कि ग्रेवसेण्ड्स पर दो जहाज लंगर डाले खड़े हैं उनमें बच्चे व अन्य नौकर दोनों हैं "जिन्हें धोखा व प्रलोभन देकर लाया गया है और जो अपने छुटकारे के लिए चीख पुकार मचा रहे हैं।" यह आदेश दिया गया कि जिन किन्हीं लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रोक रखा गया है—"यह इतनी बर्बर और अमानवीय चीज थी कि स्वयं प्रकृति और उससे भी ज्यादा ईसाई उससे घृणा किए बिना नहीं रह सकते थे—" उन्हें तुरन्त रिहा कर दिया जाए।

इन परिस्थितियों में यह फर्क करना बहुत कठिन था कि कौन अपनी इच्छा से जा रहा और किसे जबर्दस्ती ले जाया जा रहा है, विशेषकर तब जब कि वे नादान गरीब और अबोध बालक उपनिवेशों में ऐसे करारबद्ध नौकरों की संख्या निस्सन्देह काफी थी जो शायद उस किशोरी की करुण गाथा को प्रतिध्वनित करें जिसका "सोट-वीड फैक्टर या मेरीलैण्ड की एक यात्रा" नामक १७०८ में प्रकाशित लघु पुस्तिका में वर्णन आया है।

इस प्रदेश के सब से सुखद समय में
मैं दुर्भाग्य से फंसा ली गई,
और शायद मैं यहां अन्य
किसी लार्ड या लेडी की तरह ही लगती थी,
तब मैं कोई गुलाम नहीं थी क्योंकि

दो वर्ष में दो वार मेरे वस्त्र वहुत फैशनदार और नए थे;
मेरी शमीज भी नीली लिनन की नहीं थी;
किन्तु अव स्थिति वदल गई है, अव मैं
प्रतिदिन कुदाल पर काम करता हूं और नंगे पैर
मकई के खेत साफ करके या सूअर चराकर
मैं अपना उदासी-पूर्ण समय विताती हूं;
अपहृत और मूर्ख वनाई गई मैं वहां से
एक घृणित विवाह-शय्या से वचने के लिए भाग आई
किन्तु यहां आ कर मैंने देखा कि
मैं और भी वुरे लोगों में फंस गई हूं।

जैसे जैसे समय गुजरता गया "हिज़ मैजेस्टी के सप्तवर्षीय यात्रियों" में अटलाण्टिक को पार करके आने वाले प्रवासियों में जेलखाने के आदमियों की संख्या वढ़ती गई। इनमें पहले ज्यादातर "वदमाश, आवारा और भिखारी" थे जिनमें सुवार की कोई गुंजायश नहीं रह गई थी किन्तु १८ वीं सदी में कुछ और ज्यादा गम्भीर अपराधियों को भी समुद्र पार निर्वासन के योग्य व्यक्तियों की सूची में शामिल कर लिया गया। मेरीलैण्ड वस्ती में इन आवासियों की क्रांति से पूर्व की सूची में : जिसमें १११ महिलाओं समेत ६५५ व्यक्तियों के नाम थे, व्यापक प्रकार के अपराधों का उल्लेख था—हत्या, वलात्कार, डकैती, घोड़ों की चोरी तथा वड़ी लूट जैसे जुर्म शामिल थे। महिलाओं में ऐसी वहुत सी थीं जिन्हें उस जमाने के वर्णनों में संक्षेप में "लम्पट" कहा गया था।

इंग्लैण्ड के जेलखानों से इस गन्दगी के आने पर उपनिवेश वहुत क्रुद्ध थे। "उनमें से अविकांश वड़ी वदमाशियां करते हैं . . . . . . नौकरों को विगाड़ देते हैं जो पहले वहुत अच्छे थे।" इन उपनिवेशों के लिये उन्हें नियंत्रित करना अविकाविक कठिन होता गया। किन्तु उनके विरोव के वावजूद यह परिपाटी जारी रही और कुल मिलाकर कोई ५० हजार सजायाफ्ता ज्यादातर मध्यवर्ती वस्तियों में भेजे गए। मेरीलैण्ड में, जहां उन्हें फैंकना शायद सवसे ज्यादा पसन्द किया जाता था, समस्त १८ वीं सदी में प्रतिज्ञावद्ध नौकरों में उन्हीं की संख्या ज्यादा रही।

पेंसिलवेनिया गजट में १७५१ में एक व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा : "हमारी मां जानती है कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। उपनिवेशों में सुधार और खुशहाली के मुकावले अगर किसी घर में सेंध लगा ली, दुकान से कुछ उठा लिया, या डकैती कर ली तो क्या हुआ? अगर कभी-कभार किसी लड़के को भ्रष्ट करके फांसी पर लटका दिया गया, किसी लड़की को भ्रष्ट कर दिया गया, किसी पत्नी के छुरा घोंप दिया गया, किसी पति का गला काट दिया गया या कुल्हाड़े से किसी वच्चे का सिर फोड़ दिया गया तो क्या हुआ ? वेंजामिन फ्रैंकलिन ने तीखेपन से कहा कि "हमारी बस्तियों में अपनी जेलें खाली करने की उनकी नीति एक जनसमुदाय द्वारा दूसरे जनसमुदाय के अवतक किए गए महानतम अपमान और घृणा की क्रूरतम अभिव्यक्ति है।" इसके परिणाम अमरीकियों के वारे में डा० सेम्युअल जान्सन की प्रसिद्ध उक्ति में एक विल्कुल भिन्न दृष्टि से प्रकट हुए : "श्रीमन् उनकी जाति सजायाफ्ताओं की है और उन्हें फांसी पर लटकाने से घटकर हमारे किसी भी वर्ताव पर उन्हें सन्तोष करना चाहिए।"

सजायाफ्ता, आवारा और देहातों से "फुसलाकर" लाए गए वच्चे हों, या किराया देकर छुटकारा पाने वाले हों; नई दुनिया में प्रवास के लिए स्वेच्छा से गए हों या अनिच्छा से दोनों ने ही अटलाण्टिक पार की यात्रा में ऐसी असुविधाएं और कठिनाइयां उठाईं जिनकी तुलना वदनाम "मिडल पैस्सेज" पर नीग्रो गुलामों द्वारा उठाए गए कष्टों से ही की जा सकती है। व्हाइट गिनी मैन में वे अन्धाधुन्ध भर दिए गए। छोटे से जहाजों में जिनका वजन २०० टन से अधिक नहीं होता था, प्रायः ३०० तक यात्री ठूंस दिए जाते थे जिससे वहुत घिचपिच रहती थी, स्थान वड़ा अस्वास्थ्यकर हो जाता था और खान-पान की चीजें वहुत कम होती थीं। टाइफस आदि वीमारियां सदव ही वहुत से यात्रियों का खात्मा कर देती थीं। कभी-कभी तो ५० फी सदी तक आदमी मर जाते थे और वच्चे तो इस यात्रा की विभीषिका से, जो सात सप्ताह से १२ सप्ताह तक होती थी, शायद ही वच पाते थे।

जर्मन पैलाटिनेट से भरती किए गए रिडेम्पशनरों के एक अनुभव में वताया गया है कि यात्रा के दौरान इन जहाजों में भयावह कष्ट, वदवू,

जहरीली गैसें, भय, उलटियां, मितलियां, बुखार, पेचिश, सिरदर्द, गर्मी बढ़ना, कब्ज, फोड़ा-फुंसी स्कर्वी, कैन्सर, मुंह की सड़ांद और ऐसी ही अनेक बीमारियां हो जाती थीं जो सब की सब बासी, तेज नमक वाले भोजन व मांस से, तथा बहुत बुरे और गन्दे पानी से उत्पन्न होती थीं जिससे अनेक बड़ी दयनीय हालत में मर जाते थे। इतना ही नहीं चीजों की कमी, भूख, प्यास, पाला, गर्मी, सीलन, चिन्ता, अभाव, व्यथा और पश्चात्ताप का भी बड़ा भारी कष्ट था। और भी अनेक मुसीबतें थीं जैसे जूं, जो लोगों के बदन पर, विशेषकर बीमार लोगों पर इस कदर फैल जाती थी कि उन्हें शरीर पर से उलीचकर फैंकना पड़ता था। यह कष्ट अपनी चरम अवस्था पर तब पहुँचता है जब दो-तीन रात तक तूफान आता रहता है और हर कोई यह समझने लगता है कि अब यह जहाज सब यात्रियों को अपने साथ लेकर समुद्र के गर्भ में समा जाएगा। जब इस प्रकार का दृश्य उपस्थित होता है तब लोग बहुत भक्तिभाव से प्रार्थना किया करते हैं।"

बन्दरगाह पर पहुंच जाने के बाद भी यह जरूरी नहीं कि आवासियों की कठिनाइयों का अन्त हो जाए। जिनके लिए पहले से ही करार कर लिए गए होते हैं उन्हें तो उनके अज्ञात मालिकों को सौंप दिया जाता है। अगर रिडेम्पशनरों को तुरन्त कोई रोजगार नहीं मिलता था तो जहाज के कप्तान या वे व्यापारी, जिन्होंने उनका यात्रा-खर्च दिया होता था उन्हें बेच देते थे। इन परिस्थितियों में अक्सर परिवार भी छिन्न-भिन्न हो जाते थे क्योंकि पत्नियां और बच्चे उसी को सौंपे जाते थे जो सबसे ऊँची बोली बोलता था। गुलामी की शर्तें उमर के अनुसार अलग-अलग होती थीं और उसकी अवधि एक से ७ वर्ष तक होती थी। प्राय: २० वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए जो किसी खास प्रतिज्ञा-पत्र से बंधे नहीं होते थे, "देश के रीति-रिवाज के मुताबिक" गुलामी की अवधि ४ वर्ष होती थी।

औपनिवेशिक अखबारों में प्राय: गुलामों की बिक्री के विज्ञापन छपे होते थे। २८ मार्च, १७७१ को 'वर्जीनिया गजट' में निम्न घोषणा प्रकाशित हुई:

> लीड्स टाउन में जस्टीशिया जहाज अभी हाल में आया है, जिस पर करीब १०० स्वस्थ नौकर हैं।

इनमें स्त्री, पुरुष व बच्चे सभी हैं, अनेक दक्ष कारीगर हैं—जैसे लुहार, मोची, दर्जी, बढ़ई, जायनर, एक कूपर (टीन का काम करने वाला), कई चांदी के कारीगर, जुलाहे, एक जौहरी व अन्य कारीगर हैं। बिक्री २ अप्रैल, मंगलवार को रैपनहाक नदी पर लीड्स टाउर्न में शुरू होगी। टामस हैज को मंजूरशुदा जमानत और बाण्ड दिए जाने पर मुनासिब ऋण भी मिल सकेगा। —थोमस हॉज

अगर प्रवेश के बन्दरगाह में बिक्री नहीं हो पाती थी तो रिडेम्पशनरों को लाने वाले उन्हें आगे हांक ले जाते थे, बिल्कुल भेड़-बकरी की तरह और तब सार्वजनिक मेलों में उन्हें नीलाम किया जाता था।

बाहर से नौकर लाना बड़ा मुफीद काम था। कुछ बस्तियों में प्रत्येक आवासी को ५० एकड़ जमीन की मिल्कियत प्रदान की जाती थी और प्रतिज्ञा-बद्ध नौकरों की बिक्री तो सदा होती ही थी। हट्टे-कट्टे किसानों और विशेषकर दक्ष कारीगरों की प्राय: बहुत ऊँची कीमत मिलती थी। १७३९ में विलियम बायर्ड ने राटरडम में अपने एजेन्ट को लिखा कि वह बड़ी संख्या में भेजे गए नौकरों को भी सम्हाल सकता है। "मैं नहीं जानता कि जो पैलाटाइन अपना किराया नहीं चुकाते वे फिलाडेल्फिया में कब से बिक रहे हैं। किन्तु यहां वे चार वर्ष से बिक रहे हैं और उन पर ६ से ९ पौण्ड तक मिल जाते हैं। बड़े व्यापारी १० पौण्ड तक भी दे सकते हैं। अगर ये कीमतें ठीक जंचें तो मुझे विश्वास है मैं, प्रतिवर्ष दो जहाज भरे यात्री बेच सकता हूँ..."

प्रतिज्ञा-बद्ध मजदूरों के साथ जैसा बर्ताव होता था उसमें काफी भिन्नताएं होती थीं। १७ वीं सदी के जॉन हैमण्ड के वर्णन में बताया गया है कि "लीह और राशेल, या दो भाग्यशाली बहनों वर्जीनिया और मेरीलैण्ड को इतना कठिन और ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता था जितना इंग्लैण्ड में किसानों या हाथ के कारीगरों को।" काम के घण्टे सूर्योदय से सूर्यास्त तक होते थे लेकिन गर्मियों में दोपहर को ५ घण्टे विश्राम मिलता था, शनिवार को आधे दिन काम करना होता था और सैब्बथ अच्छे कामों में बीतता था "एक प्रतिज्ञाबद्ध नौकर जॉर्ज आलसप्प ने स्वयं १६५९ में मेरीलैण्ड के जीवन का करीब-क़रीब प्रशंसनीय चित्रण किया है। उसने कहा, "इस प्रान्त के नौकर, जिन्हें इंग्लैड में लोग 'गुलाम'

कह कर वदनाम करते हैं, लन्दन के अधिकांश यांत्रिक अप्रैण्टिसों के मुकावले अधिक स्वतंत्रता से रहते हैं। जो चीज भी सुविधाजनक और आवश्यक है उससे वे वंचित नहीं हैं।

लेकिन अन्य वर्णनों में उस वक्त की जिन्दगी का अधिक कठोर चित्रण पाया जाता है। औपनिवेशिक कानूनों में यद्यपि यह विधान था कि मालिक अपने नौकरों को पर्याप्त भोजन, निवास और कपड़े प्रदान करे, फिर भी ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब मालिक अपने नौकरों से ज्यादा से ज्यादा काम लेते थे और खाना कम देते थे। इसके अलावा नौकर जहां काम करते थे उससे दूर उन्हें नहीं जाने दिया जाता था और सराय के मालिक को हिदायत थी कि वे इन नौकरों को अपने यहां न आने दें और न उन्हें शराब वेचें। छोटे-छोटे अपराधों के लिए उनकी नौकरी की अवधि वढ़ा दी जाती थी और अवज्ञा या सुस्ती दिखाने पर उनके मालिक उन्हें कोड़ों की या अन्य शारीरिक सजा दिया करते थे। नाजायज औलाद के कारण नौकरानियां ज्यादा अरसे तक वन्धन में रखी जा सकती थीं और उनके मालिक कभी-कभी इस प्रकार की परिस्थिति जानवूझ कर उत्पन्न करने के लिये षड्यंत्र रचा करते थे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 'वाद के परीक्षणों से जाहिर हुआ कि कुछ व्यभिचारी मालिकों ने अपनी नौकरानियों के वच्चे पैदा कर दिए और फिर भी वे उनकी सेवाओं का लाभ उठाने का दावा करते हैं।"

प्रतिज्ञा-वद्ध नौकरों को साथी ईसाई समझा जाता था और कम से कम ऐसे मसलों में उन्हें अदालत में जाने का हक था। उनकी हैसियत नीग्रो गुलामों से भिन्न थी। लेकिन उनके मालिकों के अर्ध-मालिकाना हकों के कारण उनके लिए किसी आघात या अपमान का प्रतीकार करवा सकना अत्यन्त कठिन था। यद्यपि दयालु मालिक अपने नौकरों के साथ अच्छा वर्ताव करते थे, तथापि इस रिपोर्ट पर विश्वास करना कठिन नहीं कि उनसे प्रायः इतना कठिन श्रम और नौकरी कराई जाती थी जितना न्यूगेट से लाए गए, किसी भी नीच से नीच आदमी से कराई गई है।"

अदालती रिकार्डों में जानवूझ कर दुर्व्यवहार करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इन्हें नमूना भले ही न माना जाए, किन्तु स्थिति पर ये अच्छा प्रकाश डालते हैं। वार्ड नाम की एक मालकिन ने अपनी नौकरानी को पीठ

पर इतना मारा और फिर घावों पर आनन्द ले ले कर नमक छिड़का कि वह शीघ्र मर गई। जूरी के यह फैसला देने पर कि इस प्रकार की कार्रवाई "अयुक्तियुक्त और ईसाइयत के खिलाफ" है, मालकिन वार्ड पर ३०० पौण्ड तम्बाकू देने का जुर्माना किया गया। एक अन्य मामले में मालकिन मोनिंग ग्रे ने अदालत को चुनौती देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में वह अपने नौकरों को "खेलने या खाली नहीं बैठने देगी" और जिस अभागे ने शिकायत की थी उसे नंगा करके ३० कोड़े लगाए गए। एक तीसरा मुकदमा एक अन्य नौकरानी के पक्ष में गया। उसे एक मालिक की नौकरी से मुक्ति दे दी गई जो उसे बार-बार मारता था यहां तक कि एक बार रविवार की सुबह जब उसने उसे एक पुस्तक पढ़ते हुए देखा तो उसने तीन टांगों वाला स्टूल (तिपाई) उसके सिर पर दे मारा। अदालती रिकार्डों के अनुसार वह चिल्लाया: "तू कुटिल, नीच, अपने हाथ में किताब लिए तू क्या कर रही है?"

एक नौकर जब बहुत ही तंग आ गया तो उसने बदला लिया। उसकी अपनी कहानी के अनुसार "मेरी मालकिन बदजबान थी। वह न केवल घर में मुझे गाली गलौज देती और कोसती रहती थी, जब कभी मैं घर आता तो मुझे निरन्तर तीखे ताने और कटु शब्द कहती, बल्कि जब मैं बाहर सुख से शांति से काम कर रहा होता था तो गुस्ताखी से एक जीते-जागते भूत की तरह मेरे पीछे लगी रहती।" आखिर होश-हवास खो कर एक दिन उसने कुल्हाड़ा लिया और न केवल अपनी बदजबान मालकिन की, बल्कि मालिक और एक नौकरानी की भी हत्या कर दी।

औपनिवेशिक अखबारों में भागे हुए नौकरों के बारे में विज्ञापन अक्सर निकलते रहते थे। ऐसा एक नोटिस एक बार एक अंग्रेज नौकर के बारे में निकला जिसका "उसके रंग का लम्बा चेहरा है, पतले नासिका द्वार हैं और ऊपर के सामने दांत निचले दांतों पर विलक्षण ढंग से आगे की ओर बढ़े हुए हैं।" एक अन्य नोटिस में सारंगी बजाने वाले एक मोची का जिक्र था जो "आमोद-प्रमोद के स्थानों और मदिरालयों में जाना बहुत पसन्द करता है। शराब पीने का आदी है और जब पी लेता है तो उसे [illegible] है।" बहुत से अन्य विज्ञापनों में बढ़ई, नाई, दर्जी, [illegible] और अन्य कारीगरों तक के लिए विशेष इनाम प्रस्तुत किए जाते थे। उनके कपड़ों का [illegible]

मिलता है उसके अनुसार वे नाना प्रकार के रंगों की वास्कटें और पीले कोट पहनते थे। एक भगोड़ा डवल ब्रेस्ट का केपकोट, जिसमें सफेद धातु के बटन लगे थे, नीले रंग की एक पुरानी जाकेट, अच्छे जूते और बड़े सफेद बक्सुए धारण किए हुए था। जुराब नहीं पहनता था, केवल चुराकर ही पहनता था।

८ सितम्बर, १७४५ को मेरीलैण्ड गजट में अधिक प्रसन्नतादायक नोटिस निकला। जॉन पवेल यह रिपोर्ट दे सका कि "जिस आदमी को पहले भगोड़ा विज्ञापित किया गया था वह देहात में सिर्फ देसी शराब पीने गया था।" नोटिस में आगे लिखा था: चूंकि वह अपने मालिक के पास लौट आया है, सब लोग जिन्हें अपनी घड़ियों की मरम्मत करानी है अब "उपयुक्त दरों पर बहुत अच्छी तरह" मरम्मत करा सकते हैं।

जो नौकर अपने करार की शर्तें निष्ठापूर्वक पूरी कर लेते थे उन्हें काफी पुरस्कार दिए जाते थे। जमीन तो सिर्फ अपवाद रूप में ही दी जाती थी लेकिन कुछ मामलों में कम से कम मेहनती लोगों को "एक अच्छी जागीर" दी जाती थी और किसी न किसी प्रकार का "मुक्ति-सम्पत्" दिए जाने का सर्वत्र रिवाज था। उदाहरणार्थ मैसाच्युसेट्स में कानून में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख था कि जिन नौकरों ने ७ वर्षों तक परिश्रम और वफादारी से सेवा की है उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा जाना चाहिए। इसका अभिप्राय न केवल अलग-अलग उपनिवेशों में भिन्न था अपितु हरेक की करार की शर्तों के मुताबिक भी भिन्न-भिन्न होता था। "मुक्ति-सम्पत्" में सामान्यतः कम-से-कम कपड़े, कुछ किस्म के औजार तथा शायद ऐसे मवेशी शामिल होते थे, जिनसे नौकर स्वतंत्र रूप से खेती कर सके। कुछ प्रकार के करार-पत्र ऐसे थे, जिनमें कहा गया था: "हर वर्ष की समाप्ति पर एक सूअर और करार की समाप्ति पर एक जोड़ा पोशाक।"

इस प्रकार समस्त १७ वीं और १८ वीं शताब्दि में प्रतिज्ञावद्ध नौकर—स्त्री हो या पुरुष—अपनी जिन्दगी बनाने की आशा कर सकते थे। १७२४ में ह्यू जोन्स ने लिखा: "एक बार जब वे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तब दैनिक मजदूरी कर सकते हैं या थोड़ी सी रकम देकर एक बाग ठेके पर ले सकते हैं और यदि वे दक्ष और मेहनती हैं और लापरवाह नहीं हैं तो ओवरसीयर बन सकते हैं या अपना लुहार, बढ़ई, दर्जी, लकड़ी काटने वाले, कूपर या राज

आदि का काम जारी रख सकते हैं।"

अधिकांश लोग इन अवसरों का लाभ उठाते थे। जब वे स्वतंत्र किसान या श्रमिक बन जाते थे तो अपने पहले हालात को भूल जाते थे। अन्य लोग देश के पिछले स्थानों में साधनहीन और उत्साह-हीन भटकते रहते थे, जिससे दक्षिण की बस्तियों में गरीब गोरों का एक अलग वर्ग बन गया। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी का भाग्य कैसा भी रहा हो, जैसे-जैसे देश का विकास और विस्तार हुआ, प्रतिज्ञाबद्ध नौकरों ने औपनिवेशिक अमरीका के निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया।

उपनिवेशों में स्वतंत्र मजदूरों में आवासी शिल्पी और मिस्त्री शामिल होते थे जो अपना अमरीका आने का खर्चा स्वयं दे देते थे। इनके अतिरिक्त वे प्रतिज्ञाबद्ध नौकर शुमार किये जाते थे जिन्होंने अपने करार की शर्तें पूरी कर दी होती थीं। लेकिन इस प्रकार के श्रमिक फिर भी बहुत कम मिलते थे और अटलाण्टिक समुद्र के तटवर्ती शहरों में सदा ही श्रमिकों की बहुत कमी रहती थी। ऊँची मजदूरी और अपेक्षाकृत अच्छी काम की हालतें भी श्रमिकों का पश्चिम की ओर जाना नहीं रोक सकीं। सीमा पर जमीन सस्ती होने के कारण वह तटवर्ती शहरों से लोगों को खींचती रहती थी।

एक औपनिवेशिक अधिकारी ने १७६७ में बोर्ड आफ ट्रेड को लिखा : "जिस देश में हर किसी को काम करने के लिये जमीन उपलब्ध है, उसमें लोगों की प्रतिभा स्वभावतः कृषि की ओर ले जाती है और वह हर अन्य व्यवसाय पर हावी हो जाती है। इसका सबसे प्रबल प्रमाण विभिन्न व्यवसाय करने वाले यूरोप से लाए गए नौकर हैं। जैसे ही उन के करार की अवधि खत्म होती है वे तुरन्त अपने मालिकों को छोड़ देते हैं और जमीन का एक छोटा-सा टुकड़ा खरीद लेते हैं। इसको निवास योग्य बनाने में पहले ३-४ वर्षों तक वे बड़ी दीन-हीन और गरीबी की हालत में रहते हैं। लेकिन इन सब कष्टों को वे बड़ी खुशी से सह लेते हैं। जमीन का मालिक बनने का सन्तोष उनकी हर कठिनाई पर विजय पा लेता है और वे उस आराम देह जीवन की अपेक्षा जो उन्हें और उनके परिवार को अपना पुश्तैनी धन्धा करने से प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार की जिन्दगी को अधिक पसन्द करते हैं।"

इस स्थिति का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव न्यू इंग्लैण्ड पर पड़ा जहां प्रतिज्ञाबद्ध

नौकर अपेक्षाकृत कम संख्या में थे। वहां मजदूरी की दरें इतनी बढ़ गईं और दक्ष और अदक्ष दोनों प्रकार के मजदूर इतनी स्वतंत्र प्रकृति के हो गए कि औपनिवेशिक अधिकारियों को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। फलस्वरूप स्वतंत्र मजदूरों पर असर डालने वाला अमरीका में पहला श्रम कानून बना। कानून के जरिये अधिकतम मजदूरी निश्चित कर दी गई, धन्धे में तब्दीली बन्द कर दी गई और निम्न वर्ग के लोगों को निम्न स्तर पर रखने के लिए पोशाक और व्यवहार में भेदभाव कर दिया गया।

१६३० के जमाने में भी मैसाच्युसेट्स की जनरल कोर्ट ने बढ़ई, जायनर, राज, लकड़ी काटने वालों, फूंस की झोंपड़ी बनाने वालों तथा अन्य कारीगरों के लिए दो शिलिंग प्रतिदिन की, तथा दिहाड़ियों के लिए १८ पेंस प्रतिदिन की अधिकतम मजदूरी निश्चित की। इसके साथ यह व्यवस्था भी की गई कि "सब श्रमिक सारे दिन काम करेंगे, सिर्फ भोजन और विश्राम के लिए उन्हें उपयुक्त समय मिलेगा।" इस प्रकार की मजदूरी को शराब के लिए भत्ते से पूरा करने के रिवाज को ध्यान में रखते हुए (जिसके बिना यह दुखद अनुभव देखने में आया कि अनेक काम करने से इन्कार कर देते हैं) अदालत ने यह भी घोषणा की कि जो कोई व्यक्ति किसी श्रमिक को आवश्यकता के बिना ही तेज शराब देगा, उसपर प्रत्येक अपराध के लिए २० शिलिंग जुर्माना किया जाएगा।

४० वर्ष बाद एक अन्य कानून में भी मजदूरी की इन सामान्य दरों को दोहराया गया। अधिक स्पष्टता से यह कहा गया कि "काम का दिन भोजन के अलावा १० घण्टे का काम" समझा जाना चाहिए और यह कानून और ज्यादा कारीगरों पर लागू किया गया। बढ़ई, राज, पत्थर की इमारतें बनाने वालों, कूपरों और दर्जियों के लिए दो शिलिंग प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई, जूतें बनाने वालों, कूपरों और लुहारों के लिए एक चीज के बनाने के विशेष रेट निश्चित किए गए और अन्त में नए कानून में कहा गया कि "चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि दस्ताने, काठी और टोप बनाने वाले अथवा अन्य कारीगरों को न्यायोचित मात्रा से कहीं अधिक पारिश्रमिक मिलता है, इसलिए उन्हें अन्यों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार उसमें कमी करनी चाहिए।"

अधिकतम मजदूरी की इन दरों की भरपाई कुछ हद तक, जीवन के लिए
 वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण करके की जाती थी किन्तु बड़ी अदालत

का स्पष्ट अभिप्राय मालिकों की मदद करना तथा 'सार्वजनिक हित की दृष्टि से' मजदूरों को उनके काम के स्थानों पर ही रखना था।" न्यू इंग्लैण्ड के धार्मिक नेताओं की पौराणिक नजर में कारीगरों, मजदूरों और नौकरों की मजदूरी की अत्यधिक मंहगाई दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम पैदा करने वाली थी। उन्होंने सख्ती से कहा : "इस श्रम का फल कई लोगों द्वारा इतनी ठाठ-बाट की पोशाकों में, जो उनके स्थान और पद के लायक नहीं है, तथा आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने में खर्च किया जाता है। उसका अधिकाँश सराय और मदिरालयों में तथा अन्य बुरे कामों में खर्च कर दिया जाता है जो ईश्वर का अपमान धर्म की अवमानना, और हम में से भद्र और ईश्वर-भक्त लोगों को महान दुख देने वाला है।"

हमारे पूर्वजों की निगाह में अर्थनीति और नैतिकता का चोली-दामन का साथ था। कम मजदूरी और अधिक काम मजदूरों के लिए कल्याणकारी है, उनके इस उच्च-आदर्श का एक व्यावहारिक लाभ था, जो बाद की पीढ़ियों ने दर-गुजर नहीं किया। २०वीं सदी में नहीं, तो १९वीं सदी में काम के अधिक घण्टों का उसी पुराण-पन्थी भावना से समर्थन किया जाता था और कहा जाता था कि काहिली दूर करने और मजदूरों को हानिकारक प्रलोभनों से बचाने के लिए ये जरूरी है। फैक्ट्री जीवन के "हितकारी अनुशासन" को बाद में मालिकों ने मदिरालयों और संलापगृहों के, जिन्होंने औपनिवेशिक जमाने की सरायों का स्थान ले लिया था, हानिकारक आकर्षण को मिटाने वाले की संज्ञा दी।

मजदूरों द्वारा विशेष खपत पर और ज्यादा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध एक अन्य कानून द्वारा लगाया गया जिसमें निर्धारित किया गया था कि मजदूरों को किस प्रकार की पोशाकें पहननी हैं। इस आज्ञा में कहा गया था : "हम इस चीज पर अपनी अत्यन्त घृणा व्यक्त करते हैं कि समाज में नीचा स्थान रखने वाले स्त्री-पुरुष कुलीन लोगों की पोशाक पहनें।" प्रतिबन्ध में "सोना या चांदी के गोटा या बटन लगाना या बूट पहन कर चलना, एक ही पद की स्त्रियों के लिए रेशम या मलमल के दुपट्टे ओढ़ना शामिल था, जिसकी अधिक सम्पन्न या शिक्षित लोगों को तो अनुमति दी जा सकती थी लेकिन जिन्हें हम इस प्रकार की अवस्थाओं वाले व्यक्तियों द्वारा पहना जाना किसी भी हालत में

वर्दाश्त नहीं कर सकते।"

ये कानून अमल में नहीं लाए जा सके। यद्यपि अधिकारीगण अधिक वेतन की मांग को असहिष्णुता, रविवार को छुट्टी न मनाने, जुआ खेलने और मिलजुलकर नाचने से जोड़ते रहे, जिन्हें "शैतानी वुराइयां समझा जाता था, जिनकी ओर मनुष्य की प्रकृति सहज झुक जाती है" तो भी वे स्थिति को काबू में नहीं रख सके। बड़ी अदालत ने अन्त में यह काम स्थानीय नगर सरकारों को सौंप दिया तो भी मजदूरी की दर तथा सामाजिक रीति-रिवाज निश्चित करने में मनमाने कानून के वजाय श्रमिकों की कमी ही अधिक निर्णायक सिद्ध हुई।

यद्यपि अधिकांश प्रवासी अपनी जमीन खुद जोतते थे और रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं, जैसे कपड़े, घर का फर्नीचर, अनेक प्रकार के औजार और वर्तन खुद बना लेते थे तो भी जैसे-जैसे १८वीं सदी वीतती गई, शिल्पियों व कारीगरों का महत्व बढ़ता गया। उनमें से बहुत से घूमते-फिरते श्रमिक थे जो कोई भी बताया गया काम करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर घूमते थे या फारम वाले परिवारों की जरूरत की चीजें आर्डर पर बनाते थे। कभी-कभी एक ही आदमी कई धन्धे करता था। लुहार औजार बनाने का भी काम करता होता था चमड़ा रंगने वाला जूते भी बनाता और साबुन उवालने वाला चर्वी की चीजें भी वेचा करता था। किसी कारीगर के धन्धे कहां तक विस्तृत हो सकते थे इसका अनुमान जून, १७७५ में न्यूयार्क गजट में प्रकाशित एक विज्ञापन से लगाया जा सकता है। जॉन जूलियस सोर्ज ने घोषणा की कि वह कृत्रिम फल बना सकता है, वार्निश का काम कर सकता है, सफाई करने वाले द्रव, साबुन का पानी, साबुन, मोमबत्तियां, कृमिनाशक द्रव्य और शराब बना सकता है तथा महिलाओं के माथे और भुजाओं पर से बाल सफा कर सकता है।

औपनिवेशिक नगरों के और विकास के साथ-साथ कारीगरों की मांग भी वढ़ी। छोटी-छोटी खुदरा दूकानें ज्यादा संख्या में खुलती गईं जिनमें एक वड़ा कारीगर अनेक दिहाड़ियों को अर्थात् कारीगरों व मिस्त्रियों को दैनिक मजदूरी पर काम देता था और लड़कों को, जो कोई धन्धा होता था उसके ...स की ट्रेनिंग देता था। छापेखाने, कपड़ों की सिलाई तथा जूते बनाने

की दुकानें, कैबिनेट बनाने की दुकानें और बेकरियां इस प्रकार के संस्थानों में शुमार होती थीं। काम सामान्यत: आर्डर पर किया जाता था और दुकानें प्रायः बड़े कारीगर का घर भी होती थीं जहां दिहाड़िये और अप्रैण्टिस काम करने के अलावा रह भी सकते थे। इसके साथ ही इमारती व्यवसाय के फलने-फूलने पर बड़े बढ़ई तथा राजों ने भी दिहाड़िये और अप्रैण्टिस रखने शुरू कर दिए।

न्यू इंग्लैण्ड तथा बीच की बस्तियों, दोनों जगह सब तरह की छोटी-छोटी मिलें जिनमें दक्ष व अदक्ष दोनों प्रकार के मजदूरों की जरूरत रहती थी, जहाज निर्माण घाट, रस्सी बंटने के स्थान, शराब खींचने की भट्टियां, कागज और बारूद के काराखने थे। दक्षिण के बड़े-बड़े बागानों पर घरेलू निर्माण कार्य ने दक्ष मजदूरों की आवश्यकता उत्पन्न की। राबर्ट कार्टर के बगीचे में एक लुहार खाना, कपड़े की धुलाई की मशीन, अनाज की चक्की, नमक का कारखाना तथा कताई-बुनाई दोनों होती थीं, जहां उसने स्वतंत्र गोरे श्रमिक और नीग्रो गुलाम दोनों काम पर लगा रखे थे।

बड़े पैमाने पर निर्माण-कार्य की कम-से-कम शुरूआत हो चुकी थी। १८ वीं सदी के मध्य तक पेंसिलवेनिया, मेरीलैण्ड और न्यूजर्सी में लोहे के कारखाने स्थापित हो चुके थे जिनमें काफी संख्या में लोग काम करते थे। उपनिवेश में सब से ज्यादा विख्यात लोहा मास्टर पीटर हासेनक्लेवर द्वारा स्थापित कारखाने में ६ धमन भट्टियां, ७ फोर्ज और एक स्टाम्पिंग मिल थी और कहा जाता है कि उन्हें चलाने के लिये वह जर्मनी से ५०० मजदूर लाया था। मैनहीम, पेंसिलवेनिया में हेनरी स्टीगल के कांच के कारखाने में काफी आदमी काम करते होंगे क्योंकि उसमें एक संयंत्र इतना बड़ा था कि "कांच को पिघलाने वाले कक्ष के ईंटों की गुम्बद में एक गाड़ी और चार घूम सकते थे।" लिनन के कारखाने, जिनमें १४-१५ करघे होते थे, कपड़े की मिलों में बदलते हुए रोजगार की पूर्व-भूमिका थे। १७६९ में बोस्टन की एक निर्माता कम्पनी के पास ४०० मजदूर थे और ६ वर्ष बाद अमरीकी निर्माण कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए निर्मित युनाइटेड कम्पनी आव फिलाडेल्फिया कपड़े बनाने के काम में ४०० महिलाएं लगा रखी थीं। इनमें

इसके अतिरिक्त निर्माण उद्योगों में कर्मचारियों के अलावा अन्य श्रेणियों के मजदूरों का महत्व भी बढ़ रहा था। इनमें ज्यादातर नाविक तथा मछुए थे और हर नगर में दैनिक-मजदूरों का अपना कोटा होता था। समाज के सम्पन्न वर्ग की जरूरतें पूरी करने के लिए घरेलू नौकर कभी ज्यादा संख्या में उपलब्ध नहीं होते थे। "सहायता की कमी है और वह दुर्लभ है। सहायता देने वालों को खुश करना मुश्किल है और वह अनिश्चित भी है" यह औपनिवेशिक समाज की चिर-परिचित शिकायत रहती थी।

क्रांति नजदीक आने पर जब लोगों की सेनाओं में जरूरत पड़ी तो मजदूरी कमाने वालों के लिए अवसर बढ़े और श्रमिकों की उपलब्धि कम हो गई, जिससे मजदूरी की दरें और ऊँची चढ़ीं। मजदूरी की दरें निश्चित करने तथा मूल्य नियंत्रण के पहले प्रयत्नों को बार-बार दोहराना पड़ा। महाद्वीपीय कांग्रेस के आर्टीकल्स आव ऐसोसियेशन में इस प्रकार के नियंत्रणों के महत्व पर बल दिया गया और अनेक राज्य सरकारों ने उन्हें लागू करने का बीड़ा उठाया। सन् १७७६ में प्रौविडेन्स में आयोजित एक सम्मेलन में, जिसमें मैसाच्युसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड द्वीप और कनैक्टिकट के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, मूल्य तथा मजदूरी के नियंत्रण के सामान्य कार्यक्रम पर समझौता हो गया। कृषि मजदूर की अधिकतम दैनिक मजदूरी ३ शिलिंग ४ पेंस नियत की गई (जो एक सदी पूर्व की दर से तिगुनी से भी ज्यादा थी) और कारीगरों तथा मिस्त्रियों की मजदूरी भी इस प्रकार नियत की जानी थी जिससे इस नई दर पर कृषि-मजदूरी के साथ उसका उचित सम्बन्ध स्थापित हो सके। संबन्धित राज्यों ने इस प्रस्ताव पर तुरन्त कार्रवाई की जो अन्तर्राज्यीय समझौता का शुरू का एक उदाहरण था, और जब यह मामला महाद्वीपीय कांग्रेस के सामने लाया गया तो बाकी राज्यों को भी उसने कहा कि वे भी "इसी प्रकार के कदम उठाएं।"

लेकिन मजदूरी की दर निश्चित करने तथा मूल्य नियंत्रण के बारे में आपस में समझौता करने में अन्य सम्मेलन इतने सफल नहीं हुए, जितना प्रौविडेन्स का सम्मेलन। दक्षिण के राज्य उत्तरी राज्यों के लिए निर्धारित मानदण्ड अपनाने में अनिच्छा जाहिर करने लगे थे और इस विषय में विभिन्न के अनुभव भी विभ्रम और विरोध उत्पन्न करने वाले थे। यद्यपि स्थानीय

रूप से कहीं कहीं इस बारे में आगे भी कार्रवाई की गई, तथापि महाद्वीपीय कांग्रेस ने अंत में यह निर्णय कर लिया कि सारा प्रोग्राम ही न केवल अव्यावहारिक है "बल्कि बड़े बुरे परिणाम पैदा करने वाला है जो सार्वजनिक सेवा के लिए बहुत हानिकारक और व्यक्ति के लिए बहुत उत्पीड़क है।" इसने राज्यों को इस विषय में मौजूदा कानून रद्द कर देने की सलाह दी और इस प्रकार नियंत्रित अर्थतंत्र स्थापित करने का यह पहला प्रयत्न आगे कोई प्रगति न कर सका।

औपनिवेशिक जीवन की परिस्थितियों के कारण यद्यपि अमरीका में सामाजिक और आर्थिक समानता पुरानी दुनिया के किसी भी स्थान से ज्यादा थी तो भी श्रमिकों को राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त नहीं थी। मतदान का अधिकार सिर्फ सम्पत्ति वालों को ही प्राप्त था और दक्ष कारीगर तथा मिस्त्री अपने अधिकारों पर बल देने में उतने ही असमर्थ थे, जितने दिहाड़िये। लेकिन १७८० की दशाब्दि तक तटवर्ती नगरों के श्रमिक व्यापक अधिकारों की अधिकाधिक मांग करने लगे थे। उस आन्दोलन का समर्थन कर, जिसकी बदौलत अमरीका आजाद हुआ ये श्रमिक न केवल सुदूर इंग्लैण्ड के उत्पीड़न के खिलाफ बल्कि स्वदेश में शासक वर्ग के नियंत्रणों के खिलाफ भी अपना विरोध प्रकट कर रहे थे।

क्रांति में छोटे व्यापारियों, कारीगरों तथा मिस्त्रियों का योग विशेष रूप से मैसाच्युसेट्स में बहुत महत्वपूर्ण रहा। जब-जब भी व्यापारियों और किसानों का उत्साह मन्द होता प्रतीत हुआ तब-तब उन लोगों के, जिन्हें टोरी उपहासपूर्वक 'मोबिलिटी' या 'रैबल' (समाज में नीचा स्थान रखने वाले) कहा करते थे, जोश से 'देशभक्ति की ज्वाला' और प्रदीप्त हुई। बोस्टन के लोकप्रिय दल में, जिसका नेतृत्व सेम्युअल ऐडम्स के कुशल हाथों में था, ज्यादातर जहाज गोदियों के मालिक जहाजी श्रमिक, ईंटों की चिनाई करने वाले, जुलाहे और चमड़ा रंगने वाले शामिल थे, जो ब्रिटिश अधिकारियों अथवा औपनिवेशिक सामन्तों दोनों के शासन के समान रूप से विरोधी थे। 'आजादी के पुत्र' और बाद में कारेस्पोंडेंस कमेटियों में सामान्यतः गोदी, जहाजी घाट अथवा रस्सी बंटने के कारखानों के मजदूर भर्ती किए जाते थे।

प्रसिद्ध "लायल-नाइन" में जिसे वह सामूहिक कार्रवाई भड़कानी थी, जिससे वोस्टन हत्याकाण्ड हुआ और वोस्टन टी पार्टी में दो शराव खींचने वाले, दो कसेरे, एक मुद्रक, एक जौहरी, एक पेण्टर तथा एक जहाज का कप्तान शामिल था।

इस प्रकार की ताकतों का संगठन अन्य उपनिवेशों में भी था। वाल्टीमोर की दि ऐंशेंट ऐण्ड आन रेवल मैकेनिकल कम्पनी, चार्ल्सटन की फायरमेन्स ऐसोसियेशन और फिलडेल्फिया की हार्ट ऐण्ड हैण्ड कम्पनी—इन शहरों में 'सन्स आव लिवर्टी' की केन्द्र बिन्दु थीं। इनमें से प्रत्येक की पंजिका यह जाहिर करती है कि उनके सदस्य मुख्यत: छोटे व्यापारी और कारीगर थे।

इसका यह मतलब नहीं कि क्रांतिकारी आंदोलन में औपनिवेशिक समाज के अन्य तत्वों ने पूरा भाग नहीं लिया। ब्रिटिश करों के खिलाफ पहले-पहल व्यापारियों ने ही विरोध प्रकट किया और सन्स आव लिबर्टी को संगठित करने में पहले इसी वर्ग ने नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन मिस्त्रियों, कारीगरों तथा छोटे व्यापारियों ने औपनिवेशिक स्वाधीनता के पक्ष में ज्यादा क्रांतिकारी मांगें प्रस्तुत कीं और जव व्यापारी समझौते के लिए झुकते प्रतीत होते थे तो वे अपना आन्दोलन जारी रखते थे। उनका उत्साह टोरियों में अक्सर यह भय पैदा कर देता था कि क्रांतिकारी आंदोलन वेकावू होता जा रहा है। गवर्नर मारिस ने एक वार उत्तेजित होकर लिखा कि 'मोविलिटी' के मुखिया संभ्रांत वर्ग के लिए खतरनाक हो गए हैं और उन्हें कैसे कावू में रखा जाय, यह एक अहम सवाल वन गया है।"

उन्हें कावू में नहीं रखा जा सका। उनके प्रदर्शनों से, जिनसे कभी कभी दंगे हो जाते और अव्यवस्था फैल जाती थी ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति आम लोगों का विरोध जाहिर होता था और वह वढ़ता भी जाता था। उदाहरणार्थ वोस्टन हत्याकाण्ड औपनिवेशिक श्रमिकों और ब्रिटिश सैनिकों में झगड़े का सीधा परिणाम था। जनरल गेज ने वताया : "रस्सी वंटने के एक कारखाने में २६ वीं रेजिमेण्ट के कुछ सैनिकों के साथ एक विशेष झगड़ा हो गया। यह झगड़ा उकसाया मजदूरों ने, यद्यपि यह कहा जा सकता है कि कसूर दोनों तरफ था। इस झगड़े से लोग इतने उत्तेजित हुए कि ५ मार्च की रात उन्होंने आम विद्रोह कर दिया।"

कारीगरों और मिस्त्रियों का क्रांति में योग यद्यपि काफी पहले कबूल किया जा चुका है तो भी संविधान को अपनाने में उनका क्या योग रहा यह निश्चित करना कठिन है। नई सरकार की स्थापना में जहां तक पुरानी विचारधारा प्रतिक्षिप्त होती थी, जिसमें आजादी के संघर्ष में प्राप्त लोकतंत्रीय सफलताएं कम कर दी गई थीं और व्यक्ति के हितों के बजाय सम्पत्ति के हितों की रक्षा पर बल दिया गया था, श्रमिकों से उसकी स्वीकृति का विरोध किए जाने की आशा की जा सकती थी। सांविधानिक सम्मेलन में उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं था और उस सम्मेलन के विचार-विमर्श में उनके और सामान्यतः आम लोगों के अधिकारों का कोई खयाल नहीं रखा गया। तो भी कुछ शहरों में उस संविधान को स्वीकार किए जाने के पक्ष में मजदूरों के प्रदर्शन हुए और न्यूयार्क शहर में संघवादियों की विजय में उनका समर्थन भी आंशिक कारण रहा है।

स्वाधीनता आंदोलन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना में मजदूरों का कुछ भी योग रहा हो, इन वर्षों में उन्हें कोई खास प्राप्तियां नहीं हुईं। अमीर और कुलीन लोगों की सरकार के अलैग्जेण्डर हैमिल्टन जैसे प्रबल पक्षपाती लोगों के अनुदार विचारों का यह जताने के लिए उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। १८ वीं सदी की समाप्ति के वर्षों में अमरीका लोकतंत्रीय समाज से कितना दूर था। हर जगह "समानता की भावना" का भय छाया हुआ था जो क्रांति के जमाने में बहुत ज्यादा प्रतीत होता था और जिससे यह समझा जाता था कि अगर लोकतंत्र-प्रेमी लोगों को और ज्यादा रियायतें दी गई तो राष्ट्र की स्थिरता को खतरा पैदा हो जाएगा।

टामस जैफरसन को भी, जिसने जोरों से यह घोषणा की कि "सरकार पर प्रभाव में सब लोगों का हिस्सा होना चाहिए" इस बात का कोई ख्याल नहीं था कि जिन लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाना है और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति की अनुमति प्रदान की जानी है उनमें जायदाद-हीन श्रमिकों को भी शामिल किया जाए। जिस लोकतंत्र के वह समर्थक थे वह छोटे किसानों का लोकतंत्र था और उन्हें इस बात का बड़ा सन्देह था कि क्या कारीगरों, मिस्त्रियों और मजदूरों में जिन पर खुदमुख्तार होने की जिम्मेदारी

प्रभाव नहीं है, समानता की उस भावना का विकास कभी हो सकता है जो एक स्वतंत्र समाज के सुचारू ढंग से चलते रहने के लिए आवश्यक है।

जैफरसन अमरीका में निर्माण-उद्योगों का विकास करने के कट्टर विरोधी थे क्योंकि उन्हें शहरी श्रमिकों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या का हमारी संस्थाओं पर प्रभाव पढ़ने का डर था। वह यह पसन्द करते कि हमारे कारखाने यूरोप में ही रहें, बजाय मजदूरी कमाने वालों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करने का खतरा मोल लेने के, जिनके सिद्धान्त और तौर-तरीकों को वे सन्देह की निगाह से देखते थे। यूरोप में जो कुछ हो रहा था, उसकी एक भयावह कल्पना करके जैफरसन ने लिखा: "बड़े शहरों की भीड़ विशुद्ध सरकार को उतना ही बल प्रदान करती है जितना फोड़े मानव शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं।"

इस प्रकार स्वाधीनता की घोषणा के बड़े-बड़े वायदों के बावजूद अमरीकी समाज में मजदूरी कमाने वाले वर्ग की राजनीतिक स्थिति में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ था। इसका जीवन स्तर यूरोप की अपेक्षा उन्नत था किन्तु क्रांति के बाद के जमाने में जब मंहगाई बढ़ी तो अटलाण्टिक के तटवर्ती कस्बों में श्रमिकों की दशा अत्यधिक गरीबी से शायद ही कभी अच्छी रही हो। जॉन ले ने जब कि १७८४ में मिस्त्रियों और मजदूरों की मजदूरी के बारे में बड़ी शिकायत की, जिसे वह बहुत ज्यादा समझता था, तब अदक्ष श्रमिक का वेतन मुश्किल से ही कभी १५ शिलिंग प्रति सप्ताह से ज्यादा होता था जो ४ डालर से भी कम के बराबर था।

"इस तुच्छ मजदूरी पर", जॉन बैक मैकमास्टर ने लिखा है, "अत्यन्त किफायत करके ही कोई मिस्त्री अपने बच्चों को भुखमरी से और स्वयं को जेल से मुक्त रख पाता था। निचले और अंधेरे कमरों में, जिसे वह अपना घर कहता था, सजावट और उपयोग की उन बहुत सी चीजों का अभाव था, जो आजकल गरीब से गरीब घरों में भी पायी जाती हैं। फर्श पर फैलाई हुई रेत गलीचे का काम देती थी, उसकी मेज पर कोई कांच नहीं होता था, अलमारी में कोई चीनी का बर्तन नहीं होता था, दीवार पर कोई कलैण्डर नहीं होते थे। स्टोव क्या होता है, वह अनभिज्ञ था, कोयला उसने कभी देखा नहीं था, माचिस का कभी नाम नहीं सुना था। पेटियों और पीपों के टुकड़ों को पत्थर

की रगड़ से उत्पन्न चिनगारी से या पड़ौसी की अंगीठी से लाए गए अंगार से आग सुलगाकर उसकी पत्नी मोट-झोटा खाना बनाती थी और उसे रांग की रकाबियों में परोसती थी। ताजा मांस उसे हफ्ते में मुश्किल से एक बार मिल पाता था और अपनी भावी पीढ़ी के मुकाबले उसकी कहीं ज्यादा कीमत देता था.....अगर कारीगर के भोजन को रूखा-सूखा समझा जाए तो उसके कपड़े तो घृणास्पद मानने होंगे। पीले सावर की खाल या चमड़े का एक पजामा, एक चारखाने वाली कमीज, एक लाल फलानैल की जाकेट, एक जंग लगा हुआ टोप जो किनारों पर से उठा होता था, मवेशी के चमड़े के जूते, जिस पर पीतल के बड़े-बड़े बक्सुएं लगे होते थे और एक चमड़े का लबादा यही कुछ पोशाकें उसकी अलमारी में मिलती थीं।"

इस प्रकार के जीवन में कितनी भी तंगियां हों—और यह नहीं भूलना चाहिए कि उस समय अमीरों के पास भी सुख-सुविधा की बहुत सी ऐसी चीजें नहीं थीं, जिन्हें आजकल आवश्यक समझा जाता है तो भी अमरीका तब भी शानदार अवसरों की भूमि थी। कारीगर और मिस्त्री विश्वासपूर्वक अपना जीवनस्तर उन्नत करने की आशा कर सकते थे और श्रेणी-विभाजन पक्का न होने से परिश्रमी और स्फूर्तिमान लोगों को और ज्यादा उन्नति करने में कोई रुकावटें नहीं थीं। इतना ही नहीं, जो समाज अब भी कृषि और हाथ की कारीगरी पर निर्भर करता था उसमें कारीगर की एक मानी हुई प्रतिष्ठित हैसियत थी जो उसकी तुच्छ आर्थिक स्थिति की कुछ अंशों में भरपाई कर देती थी। उसके जीवन-यापन का तरीका भले ही सादा रहा हो, वह उद्योगों से अछूते एक सरल समाज में रह रहा था।

क्षितिज पर दूर-गामी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे थे जो उस समाज को जिसमें वह रह रहा था और उसकी अपनी हैसियत पर प्रभाव डालेंगे। प्रगति के नाम पर वे उसके लिए कहीं अधिक उन्नत जीवन स्तर को प्राप्त करने की सम्भावनाएं खोल देंगे; ऐसी संभावनाएं जो यहां या अन्य किसी देश में श्रमिकों को पहले कभी प्राप्त नहीं हुईं। लेकिन इन परिवर्तनों के लिए अनुकूलन की बड़ी जरूरत थी, जो बड़ी कठिन साबित हुई और १९
का श्रमिक प्रायः अनुभव करता था कि औद्योगिक प्रगति जो
करती दीखती है वह उससे अछूता है। अपनी आशाओं तथा

की पूर्ति में नई वाधाएं उत्पन्न होने पर राष्ट्र के श्रमिकों ने आगे चलकर यह अनुभव किया कि जिन अधिकारों की प्राप्ति के वे हकदार हैं उन्हें वे एक संगठन के जरिये ही प्राप्त कर सकते हैं।

—:o:—

२ : पहली यूनियनें

मजदूर संगठनों की वास्तविक शुरूआत तब तक नहीं हुई, जब तक १९ वीं सदी के शुरू में व्यापारी पूंजीपतियों के अभ्युदय से, जो थोक व्यापार करते थे आर्थिक समाज में परिवर्तन नहीं हो गया। औपनिवेशिक जमाने में मास्टर श्रमिकों ने जो दिहाड़ियों और अप्रैण्टिसों को सामान्य परियोजना या संयुक्त व्यवसायों के लिए काम पर जुटा लेते थे और उन्हें मजदूरी देते थे, आधुनिक मायनों में कोई मालिक-मजदूर का सा सम्बन्ध कायम नहीं किया था। दिहाड़ियों और मास्टरों के हितों में, जो साथ-साथ काम करते थे, कोई फर्क नहीं था। विभिन्न चीजों के निर्माण के लिए जो मूल्य सूची निर्धारित होती थी, उसी से मजदूरी की दर तय होती थी और व्यापारी, मास्टर और दिहाड़िये के काम काफी हद तक एक ही व्यक्ति में केन्द्रित होते थे।

इन परिस्थितियों में मास्टर और दिहाड़िये अपनी कारीगरी के स्तर को कायम रखने, मूल्य सूची को स्थिर रखने तथा सामान्यतः अनुचित प्रतियोगिता से अपनी रक्षा करने के लिये मिलकर कार्रवाई करते थे। ऐसे भी अवसर आते थे, जब दिहाड़िये मास्टरों के खिलाफ, जब वे मालिक की तरह व्यवहार करते थे, विरोध प्रकट करते थे। उन धन्धों में जिनमें उनके बहुत करीब के रिश्ते कायम नहीं हो पाते थे, कभी कभी ऐसे झगड़े खड़े हो जाते थे जिनसे इक्का-दुक्का हड़तालें और आदिम किस्म के मजदूर विद्रोह हो जाते थे। किन्तु सामान्यतः १७ वीं और १८ वीं सदी में आर्थिक गठन इतना सरल था कि श्रमिकों द्वारा कोई महत्वपूर्ण संयुक्त कार्रवाई संभव नहीं थी। लेकिन व्यापारी पूंजीपतियों के आविर्भाव से उत्पन्न परिणामों पर विचार करने से पूर्व औपनिवेशिक जमाने में जो विरोध-प्रदर्शन या हड़तालें हुईं उन पर इस दृष्टि से विचार किया जा सकता है कि उन से उन परिस्थितियों पर क्या प्रकाश पड़ता है जिनसे अन्ततोगत्वा यूनियनों के रूप में मजदूर संगठन बने।

जिसे श्रमिकों का क्षोभ कहा जा सकता है उसका सबसे पहला रिकार्ड

१६३६ ई० का है। मेन के तट के सामने रिचमण्ड द्वीप में रावर्ट ट्रैलानी का काम करने वाले मछुओं ने, वेतन रोक लिए जाने पर "विद्रोह" कर दिया वताते हैं। लगभग ४० वर्ष वाद न्यूयार्क के लाइसेंसदार कूड़ा उठाने वालों ने, जिन्हें ३ पेंस फी वोझ की दर से सड़कों पर से कूड़ा उठाने का आदेश दिया गया था, न केवल इतनी कम मजदूरी के खिलाफ विरोध जाहिर किया, वल्कि "मिलकर उस आदेश को पूरी तरह मानने से इन्कार कर दिया।" १८ वीं सदी में औपनिवेशिक प्रेस में कभी-कभी इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख रहता था और सन् १७६८ में न्यूयार्क में दिहाड़िये दर्जियों का 'वाक आउट' मालिकों के खिलाफ शायद पहली वास्तविक हड़ताल थी, जिसमें कुछ आधुनिकता की छाया थी। अपनी मजदूरी में कमी के कारण कोई २० श्रमिकों ने हड़ताल कर दी और खुल्लमखुल्ला यह घोषणा की कि अपने मास्टर की परवाह न करते हुए वे निजी काम करेंगे। अखवार में उनके नोटिस में लिखा था कि "लोमड़ी और कुत्ते के चिन्ह पर खुराक समेत ३ शिलिंग ६ पेंस की दैनिक मजदूरी पर वे काम पर वापस आ जाएंगे।"

कभी-कभी स्वयं मास्टर अपने हितों की रक्षा के लिए उनसे मिल जाते थे, जैसा कि 'न्यू इंग्लैंड कूरैण्ट' में नाइयों के झगड़े के वारे में पहले प्रकाशित एक विवरण से पता चलता है। ३२ मास्टर नाई "अपने उद्घोषक के साथ गोल्डनवाल में एकत्र हुए" और "सवने मिलकर शेविंग की दर ८ शिलिंग से वढ़ाकर १० शिलिंग फी तिमाही करने और कृत्रिम वाल वनाने की मजदूरी ५ शिलिंग वढ़ाने तथा उनकी टाई वनाने की मजदूरी १० शिलिंग वढ़ाने का निश्चय किया। यह भी प्रस्ताव किया गया कि उनकी विरादरी का कोई नाई रविवार की सवेरे हजामत या वाल नहीं वनाएगा। यह ऐसा प्रस्ताव था जिस पर कूरैण्ट ने आक्षेप पूर्वक लिखा है कि "यह समझा जा सकता है कि अतीत में इस प्रकार की परिपाटी इन लोगों में वहुत आम रही है।"

क्रान्ति के युग में, जिसमें युद्ध के कारण कीमतें वहुत चढ़ीं, श्रमिकों ने और ज्यादा विरोध प्रदर्शन किए, जिन्होंने देखा कि कीमतें उनकी मजदूरी की दर से वहुत ज्यादा तेजी से चढ़ रही हैं। इसका उदाहरण न्यूयार्क के मुद्रकों ने दिया। १७७८ में दिहाड़ियों ने उन परिस्थितियों में वेतन वृद्धि की माँग की और उसमें सफल हुए जिनमें आज की छाया दिखाई देती है लेकिन सिर्फ

इस बात का फर्क है कि उन्होंने अपनी माँग बड़ी नम्रता से रखी।

'रायल गजट' में दिहाड़ियों का जो विरोध-पत्र प्रकाशित हुआ, उसमें कहा गया था : "जीवन की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य चूँकि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इसलिये यह आशा नहीं की जा सकती कि हम अपनी वर्तमान मजदूरी पर काम जारी रख सकते हैं। इसलिये हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे वर्तमान तुच्छ वेतन में ३ शिलिंग प्रति सप्ताह और जोड़ दिए जाएँ। इस पर यह ऐतराज उठाया जा सकता है कि इस समय आदमियों की कमी के कारण मास्टर मुद्रकों को तंग करने की दृष्टि से यह प्रार्थना-पत्र दिया गया है लेकिन यह सही नहीं है। वस्तुतः जीवन की हर वस्तु के दाम आकाश को छूने लगे हैं और आगे ठंड मौसम आ रहा है। हमें विश्वास है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आजकल के कठिन समय का अनुचित लाभ उठाए। हम तो सिर्फ जिन्दा रहना चाहते हैं जो मजदूरी की वर्तमान दरों पर असम्भव है।"

गजट के सुप्रसिद्ध टोरी प्रिन्टर और प्रकाशक जेम्स रिविंगटन ने इस पत्र के संक्षिप्त उत्तर में लिखा : "मैं उपर्युक्त प्रार्थना को मंजूर करता हूँ।"

इन वर्षों में और इनसे तुरन्त बाद के वर्षों में अन्य संयुक्त विरोध-प्रदर्शन या हड़तालें की गईं। १७७९ में फिलाडेल्फिया में नाविकों ने, १७८५ में न्यूयार्क में जूते बनाने वालों ने और १७८६ में फिलडेल्फिया में दिहाड़ी मुद्रकों ने हड़तालें कीं। इन मुद्रकों ने घोषणा की : "हम अपने उन भाइयों की मदद करेंगे जो ६ डालर प्रति सप्ताह से कम की मजदूरी पर काम करने से इन्कार कर देने के कारण बेकार हो जाएँगे।" मालिकों ने पहले तो उनकी माँग मंजूर करने से इन्कार कर दिया लेकिन अन्ततोगत्वा यह हड़ताल सफल रही।

इमारती व्यवसाय के श्रमिक भी बेचैन हो रहे थे और फिलाडेल्फिया में दिहाड़ियों तथा मास्टर मुद्रकों के बीच चिरकाल से सुलगता आ रहा संघर्ष सन् १७९१ में फूट पड़ा। दिहाड़ियों ने घोषणा की कि उनके मालिक उस हर तरीके से, जो उनका लोभ उन्हें सुझा सकता है, मजदूरी की दर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से काम के छोटे दिन और ओवर-टाइम के लिए अतिरिक्त वेतन की माँग की। उन्होंने जोरों से शिकायत की कि "इस समय उन्हें गर्मियों के सम्पूर्ण लम्बे दिन में काम करना पड़ता है और

इस पर भी अनेक बार यह सान्त्वना तक नहीं मिली कि उनकी इस मेहनत में तुरन्त किसी पुरस्कार की आशा से कोई मिठास भर दिया जाएगा।"

इस झगड़े का क्या हल निकला, मालूम नहीं है। मास्टरों ने कम मजदूरी के लिए धन्धे को कोसा और घोषणा की कि "एक भी मामले में उन्हें सताने या तंग करनें की अभिलाषा का पता नहीं लगा है।"

ये हड़तालें किसी भी तरह ऐसे संगठनों की नहीं थीं, जिन्हें मजदूर यूनियन कहा जा सके। मजदूर सिर्फ अस्थायी तौर पर अपनी किसी मांग पर ज़ोर डालने के लिए अथवा अपने हितों की रक्षा के लिए संयुक्त प्रयत्न के हेतु परस्पर मिल जाते थे। जो व्यापारिक संगठन उस वक्त थे भी और १८ वीं सदी के आखिरी हिस्से में उनकी संख्या काफी थी, वे कोई आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं अपितु परोपकार की भावना से बनाए गए थे। वे पारस्परिक सहायता संस्थाएँ थीं जिनमें दिहाड़िये और मास्टर दोनों शामिल होते थे और जो अपने सदस्यों को बीमारी या मृत्यु की अवस्था में विभिन्न प्रकार से सहायता पहुँचाते थे। १७६० तक न्यूयार्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन जैसे शहरों में प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यवसाय में इस प्रकार की संस्था बन गई थी। कुछ संस्थाएँ तो ऐसी थीं, जिनका क्षेत्र बहुत व्यापक था। जैसे—न्यूयार्क में जनरल सोसाइटी आव मैकेनिक्स, मैसाच्युसेट्स की ऐसोसियेशन आव मैकेनिक्स आव दि कामनवेल्थ और अल्बानी मैकेनिक्स सोसाइटी।

जिन सदस्यों को बीमारी या दुर्घटना के कारण किसी मदद की जरूरत हो सकती थी उन्हें तथा गरीबी की हालत में मृत्यु के बाद उनकी विधवाओं और यतीम बच्चों की सहायता करके ये संस्थाएँ मास्टरों और दिहाड़ियों को "निजी अथवा सरकारी दया से राहत पाने के पतनकारी प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयत्न करती थीं।" श्रमिक स्वाभिमानी थे। इस प्रकार शुरू के जमाने में भी, जैसा कि एक सोसाइटी के चार्ट में कहा गया है, वे राहत की माँग "एक अधिकार के तौर पर" करने के लिए तैयार थे।

बहुत सी पारस्परिक सहायता संस्थाओं का सामाजिक पहलू भी था जो आपस में मिल-बैठने के लिए कमरों और मनोरंजन की व्यवस्था करती थीं। १७६७ में फिलाडेल्फिया में आयोजित फ्रैंडली सोसाइटी आव ट्रेड्समेन हाउस पैंटर्स के नियमों से इस के कार्य क्षेत्र की व्यापकता तथा इनके व्यवहार पर

कार्पेण्टर्स के नियमों से इन के कार्य-क्षेत्र की व्यापकता तथा इनके व्यवहार पर सख्त अंकुश रखने वाले विनियमों का पता चलता है। जो सदस्य "अपशब्द कहता, शराब में धुत्त होकर आता या कोई उपद्रव करता या क्लब के समय जुए को प्रोत्साहन देता था उसे संस्था के सामान्य कोष में ६ पेंस जुर्माना देना पड़ता था।"

यद्यपि आर्थिक गतिविधियां सामान्यत: इन संस्थाओं के कार्य क्षेत्र में नहीं आती थीं। न्यूयार्क में दिहाड़िये जहाजी श्रमिकों की संस्था की यह व्यवस्था थी कि अगर संगठन ने मजदूरी निश्चित करने का कोई भी प्रयत्न किया तो स्वंयमेव भंग कर दी जाएगी। तो भी यह लाजिमी था, कि समय आने पर ये संस्थाएं रोजगार की समस्या पर ध्यान दें। इस प्रकार पारस्परिक सहायता संस्था तथा वास्तविक व्यापार संगठन में स्पष्ट भेद कर सकना लगभग असम्भव हो गया। तथापि जूता बनाने वाले दिहाड़ियों की संघीय संस्था को जो १७६४ में फिलाडेल्फिया में कायम हुई अमरीका में मजदूरी कमाने वालों का पहला व कुछ स्थायी संगठन बताया जाता है और वह सम्भवत: पहली ट्रेड यूनियन कहलाए जाने की अधिकारी है। इसके सदस्यों में सिर्फ जूता बनाने वाले दिहाड़िये ही थे। इसने १७६६ में हड़ताल की, मास्टरों की दूकानों पर धरना दिया और १२ वर्ष तक इसका अस्तित्व रहा।

फिलाडेल्फिया में जूता बनाने वालों का संगठन स्थापित होने के कुछ महीने बाद न्यूयार्क के दिहाड़िये मुद्रकों ने इस व्यवसाय में यूनियनों की एक कड़ी स्थापित की और दो वर्ष बाद न्यूयार्क में दिहाड़िये कैबिनेट निर्माताओं की कुछ अधिक स्थायी संस्था बनी। इस बाद के संगठन ने अखबारों में एक पूरी मूल्य सूची प्रकाशित की,—जिसका अभिप्राय मजदूरी की दर निश्चित करना ही था—और यह भी व्यवस्था की कि "कुर्सी बनाने वाले दिहाड़िये प्रतिदिन १० घण्टे काम करेंगे और बत्तियों का इंतजाम मालिकों को करना होगा।"

संगठन सम्बन्धी ये प्रायोगिक शुरुआत उन व्यापारिक संस्थाओं के सामान्य विकास की ओर इंगित करती थीं जो व्यापारी पूंजीपतियों के अभ्युदय के बाद बनी। उस समय यूनियनों को चिर काल तक व्यापारिक [illegible]

कहा जाता रहा था। खुदरा दुकानों और आर्डर पर माल सप्लाई करने का स्थान जब दुकानों ने ले लिया और मास्टर और दिहाड़ियों के बीच पुराने सरल सम्बन्ध टूट गए तभी वस्तुतः मजदूरों ने मालिकों के खिलाफ संगठन स्थापित करने की मजबूरी महसूस की। किन्तु १९ वीं सदी के शुरू होने पर एक के बाद एक धन्धों में कुशल कारीगरों तथा मिस्त्रियों ने ऐसी संस्थाएं बनाने में मुद्रकों तथा जूता-बनाने वालों के पहले उदाहरणों का अनुकरण किया जिनका घोषित उद्देश्य "मालिकों की जाल साजियों के खिलाफ" अपने हितों की रक्षा करना तथा अपने श्रम की वाजिब मजदूरी प्राप्त करना था। इन संस्थाओं में संभव है, परस्पर सहायता के तत्व तब भी बाकी बच रहे हों लेकिन मुख्यतः जोर अब आर्थिक पहलू पर दिया जाने लगा था।

व्यापारी पूँजीपतियों को बाहर से माल मंगाने तथा स्वदेश में बड़े उद्योग स्थापित करने दोनों में दिलचस्पी थी। उनकी कोशिश बड़े बाजार स्थापित करने और उन्हें सस्ते माल से पाटने की रहती थी। पूंजी चूँकि उनकी मुट्ठी में रहती थी इसलिए बड़ी तादाद में वे कच्चा माल खरीद सकते थे, अपने यहाँ काम करने वाले मिस्त्रियों व कारीगरों को काम करने के लिए उपयुक्त स्थान और अन्ततोगत्वा औजार दे सकते थे, तैयार माल को गोदामों में भर कर रख सकते थे, और तब उन्हें देश के सब हिस्सों में भेज सकते थे। छोटी-छोटी खुदरा दुकानें जो किस्म के बढ़ियापन और कारीगरी पर जोर देती थीं इस प्रकार के बड़े पैमाने के उत्पादन का मुकाबला नहीं कर सकती थीं।

१९ वीं शताब्दि के प्रारम्भ में जब व्यापार के विस्तार के लिए और भी ज्यादा अनुकूल अवसर प्रदान किए तो यह रुझान बढ़ता चला गया। परिवहन के साधनों, नहरों, सड़कों तथा नावों—में सुधार से अटलाण्टिक तट के शहरों के व्यापारियों के लिए व्यापार का क्षेत्र बढ़ गया। पश्चिम की ओर जाने वाले राजपथों पर ऊँचे-ऊँचे त्रिपाल से ढके ठेलों की भीड़ लगी रहती थी जो पश्चिमी न्यूयार्क तथा ओहायो घाटी की नई बस्तियों के लिए पूर्व के कस्बों और नगरों में बने कपड़े, जूते, फर्नीचर, रसोई का सामान, औजार और लोहे के बर्तन ले जाते थे। एक राष्ट्रीय बाजार बनने लगा था जो खुदरा व्यापार और आर्डर पर तैयार किए जाने वाले माल के स्थानीय बाजार पर छा गया और [illegible] ने आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। छोटे पैमाने पर उसी तरह

का विकास हो रहा था जैसा औद्योगिक क्रान्ति के बाद के दौर में सामूहिक उत्पादन से हुआ होता। थोक व्यापार से खुदरा व्यापार का नेस्तनाबूद हो जाना १८८० और १८९० के दशकों में औद्योगिक संस्थानों के मिल जाने से स्थानीय कारखानों के लुप्त हो जाने का पूर्व परिचायक था।

व्यापार की इस नई दुनिया में अत्यन्त कड़ी प्रतियोगिता में ठहर सकने के लिये माल की कीमतें कम करने की निरन्तर आवश्यकता के कारण मालिकों ने वेतन न बढ़ने देने, अपने कर्मचारियों के काम के घण्टे बढ़ाने और सस्ते श्रम के नए साधन ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने परम्परागत अप्रैण्टिस प्रणाली के बन्धनों को तोड़ने की कोशिश की; जहां कहीं संभव हुआ, उन्होंने स्त्रियों और बच्चों को काम पर लगाना शुरू कर दिया; उनसे बहुत देर तक कम वेतन पर सख्त काम लिया जाता तथा जेलों के मजदूरों को ठेके देने शुरू कर दिए। दक्ष कर्मचारियों के लिए, चाहे उनका कुछ भी धन्धा रहा हो, मालिकों के इस प्रकार के कदम न केवल जीवन स्तर को नीचे ले जाने का बल्कि उनकी हैसियत पर भी चोट करने का खतरा उत्पन्न कर रहे थे। इस घटना-चक्र का मुकाबला करने के लिये वे तुरन्त एक हो गए और उन्होंने यह महसूस किया कि संयुक्त कार्रवाई से ही वे अपने अधिकारों की रक्षा की आशा कर सकते हैं।

कुछ अरसे तक तो कारीगर और मिस्त्री अपने मालिकों का बराबरी के स्तर पर मुकाबला करते रहे। दक्ष श्रमिकों की कमी, जो औपनिवेशिक जमाने की एक खासियत थी अमरीकी अर्थतंत्र में अब भी एक बुनियादी तथ्य था। अलैग्जेण्डर हैमिलटन ने निर्माताओं पर अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट में लिखा है: "अमरीका में निर्माण उद्योगों की स्थापना का विरोध इसलिए किया गया कि तीन कारणों से उनकी सफलता संदिग्ध थी। ये थे—श्रमिकों की कमी, श्रम की मंहगाई और पूंजी का अभाव।" इसके अलावा विस्तार पाती हुई सीमाएँ अब भी बहुत से श्रमिकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी हुई थीं, जिन्हें पश्चिमी बस्तियों में सस्ती जमीन आसानी से मिल जाने और काम-धन्धे के ज्यादा अवसर मिल जाने की आशा रहती थी। आहोपो घाटी में सड़कों और नदी मार्गों के साथ-साथ जो नए शहर बस रहे थे उनमें पूर्व की पुरानी बस्तियों की अपेक्षा भी अधिक मजदूरी की पेशकश की जाती थी।

इस जमाने के अखबारों में श्रमिकों की इस माँग की अनेक साक्षियाँ मिलती हैं। नौकरियों के लिए बहुत से विज्ञापन निकलते थे "दो या तीन दिहाड़िये कूपर स्मिथ (टीन-डिब्बों का काम करने वाले) चाहिएँ; अच्छा वेतन दिया जाएगा।" ६ से ८ तक बढ़ई चाहिएँ; उन्हें औजारों का उपयोग करने दिया जाएगा"; और ४-५ ईंटों की चिनाई करने वाले दिहाड़िये चाहिएँ।" सन् १८०३ में न्यूयार्क में सिटी हाल की इमारत बनाने वाले ठेकेदारों को पत्थर तराशने वालों के लिये फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर तथा चार्ल्सटन के अखबारों में विज्ञापन निकालना पड़ा जिसमें ऊँचे वेतनों व सब औजारों की मरम्मत का वायदा किया गया था, तथा यह आश्वासन दिया गया था कि यद्यपि शहर के अन्य भागों में पीला बुखार फैला हुआ है तो भी श्रमिकों को उससे डरने की ज़रूरत नहीं है।

तो भी दक्ष श्रमिकों ने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि उन्हें मालिकों के बढ़ते हुए साधनों के खिलाफ रक्षात्मक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। १९ वीं सदी की पहली दशक में मजदूरी जीवन-यापन के खर्चे के अनुपात में नहीं बढ़ी और न ही वे अदक्ष मजदूरों के मुकाबले अपनी मजदूरी का स्तर कायम रख सके। सन् १८१८ के आस-पास औसत मजदूरी कुछ विशिष्ट व्यवसायों जैसे, जहाज बनाने वाले बढ़इयों को छोड़कर १.२५ डालर प्रति दिन रह गई थी। उदाहरणार्थ न्यूयार्क के कम्पोजीटर ८ डालर प्रति सप्ताह और बाल्टीमोर में दिहाड़िये दर्जी ९ डालर प्रति सप्ताह कमा रहे थे। इसके मुकाबले नहरों तथा सड़कों पर, इमारतों के निर्माण तथा ऐसे ही अन्य कार्यों में मजदूरों की भारी माँग ने दिहाड़ियों की मजदूरी ४ डालर प्रति सप्ताह से क्रान्ति की समाप्ति पर ७ डालर प्रति सप्ताह तक पहुँचा दी और कभी-कभी तो उनकी मजदूरी इससे भी ज्यादा होती थी जब उनको खाना दिया जाता था और निवास का प्रबन्ध किया जाता था तब तो उनका पूरा वेतन बिल कारीगरों और मिस्त्रियों से भी ज्यादा हो जाता था। जेनेसी नदी से बफैलो तक बनाई जाने वाली ड़क के लिए जब मजदूरों की माँग निकली तब उन्हें प्रति मास १२ डालर तन, मुफ्त खाना तथा निवास और प्रतिदिन ह्विस्की की एक बोतल का वायदा किया गया। यद्यपि दक्ष कारीगर अब भी अपेक्षाकृत आरामदायक परिस्थितियों में, विशेषकर विदेशियों की निगाह में जो उनकी तुलना यूरोप के

मजदूरों से करते थे, रह रहे थे, तो भी उन्होंने महसूस किया कि परिस्थितियाँ उनके विपरीत जाती रही हैं और पुराने स्तर कायम रखना उनके लिये अब पहले से मुश्किल होगा।

इन परिस्थितियों में जिन संगठनों ने दक्ष मजदूरों की स्थिति की रक्षा का प्रयत्न किया, वे सामान्यतः मुद्रकों, जूता बनाने वालों, दर्जियों, बढ़इयों, कैविनेट बनाने वालों, जहाज बनाने वालों, कूपर तथा जुलाहों के संगठन थे। इनमें भी मुख्य दिहाड़िये मुद्रक तथा जूता बनाने वाले थे। यह मान लिया गया है कि उनकी अग्रिम युनियनें थीं और वे १६ वीं सदी के पहले २० वर्षों में सक्रिय संस्थाओं को न केवल न्यूयार्क और फिलाडेल्फिया में बल्कि वोस्टन, वाल्टीमोर अल्वानी, वाशिंगटन, पिट्सबर्ग और न्यूयार्क में भी कायम रखने में सफल रहे। करीव-करीव हर नगर में इमारती व्यवसाय के सदस्य भी संगठित थे और अन्य संस्थाओं में मिलें खड़ी करने वालों, पत्थर काटने वालों, हाथ-करघे के जुलाहों और टोप बनाने वालों की संस्थाएं शामिल थीं। १८२० से पहले फैक्ट्री कर्मचारियों का कोई संगठन नहीं था। यद्यपि उस वर्ष तक कपड़ों के कारखानों में १ लाख मजदूर काम करने लगे थे और विकसित होने वाले मजदूर आन्दोलन में महिलाओं के भाग लेने का भी कोई प्रमाण नहीं था।

शुरू की ये व्यवसाय संस्थाएँ वस्तुतः कारीगरों की यूनियनें थीं, जिनकी सदस्यता बहुत सीमित थी क्षेत्र भी इनका बिल्कुल स्थानीय था। जो मजदूर उनके सदस्य थे वे उनके कठोर नियमों से बंधे होते थे। उन्हें यूनियन की कार्रवाई गुप्त रखनी होती थी, शपथ लेकर मजदूरी की प्रचलित दर पर डटे रहना होता था और अन्य श्रमिकों के मुकाबले साथी सदस्यों को काम दिलाने में सहायता देनी होती थी। संस्था में प्रवेश की फीस ५० सेण्ट थी और हर महीने ६ से १० सेण्ट चन्दा देना पड़ता था। नियमित बैठकों में हाज़िरी जरूरी थी और वगैर वाजिव कारण के अनुपस्थित रहने पर जुर्माना किया जाता था। इसके अलावा अनुशासन बहुत कड़ा था और बार-बार शराब में मदहोश होने, भीषण अनैतिकता या संस्था की बैठक के समय किसी साथी सदस्य को अपशब्द कहने जैसे अपराधों पर सदस्य को यूनियन से निकाला जा सकता था। संस्थाओं को इस बात की बड़ी चिन्ता रहती थी कि जिस शिल्प का वे प्रतिनिधित्व करती है उसका उन्नत स्तर कायम रखा जाए और

इस प्रकार यह निश्चित किया जाय कि उनके सदस्यों में समाज के सब उत्तम कारीगर शामिल हैं।

मूल उद्देश्य वही रहे जो हमेशा ही संगठित श्रमिकों के रहे हैं, अधिक वेतन, काम के कम घण्टे और काम की हालतों में सुधार। अप्रशिक्षित कर्मचारियों, विदेशियों और लड़कों और अन्ततः महिलाओं को काम पर लगा कर मजदूरी की दरों को कम करने की मालिकों की कोशिशों से उस चीज पर अमल करने की जोरों से कोशिश की जाने लगी जिसे आजकल 'वन्द कारखाना' कहा जाता है। न्यूयार्क की टाइपोग्रैफिकल सोसाइटी ने जोरदार शिकायत की कि नौसिखियों की वहुतायत, अप्रैण्टिसों के काम सीखकर चले जाने और अधकचरे दिहाड़ियों से 'पूरे कर्मचारियों' की मजदूरी की दरों पर आघात पहुँचा है। अन्य संस्थाओं के और संभवतः उनमें से अधिकांश के सहयोग से इसने अपने एक नियम का कड़ाई से पालन किया कि उसका कोई सदस्य ऐसे कारखाने में काम नहीं करेगा जो ऐसे सदस्यों को काम पर रखता हो जो संगठन के सदस्य नहीं हैं। इस जमाने में और उसके वाद भी जो मालिक ऐसे कारीगर और मिस्त्री भरने की शोशिश करते थे, जो यूनियन के सदस्य नहीं होते थे, उनके खिलाफ अनेक हड़तालें हुई और संस्था के नियमों का कड़ाई से पालन किया गया। प्रतीत होता है कि शिल्पियों के खिलाफ प्रयुक्त दवाव से किसी अन्य जमाने की अपेक्षा इस जमाने में 'वन्द कारखाने' का सिद्धान्त का पालन करने के लिए अधिक संगठित प्रयत्न किया गया। न्यूयार्क में जूते वनाने वाले दिहाड़ियों की यूनियन के संविधान में किसी भी यूनियन रहित संस्थान में न केवल काम करने की मुमानियत थी वल्कि शहर में आने वाला कोई दिहाड़िया अगर एक महीने के अन्दर-अन्दर संस्था में शामिल नहीं होता था तो उस पर जुर्माना भी कर दिया जाता था।

मालिकों के साथ व्यवहार में इन संस्थाओं ने सामूहिक सौदेवाजी के सिद्धान्त लागू किए। फिलाडेल्फिया के जूता निर्माताओं के मामले में १७९९ में एक शिष्टमण्डल समझौते का प्रस्ताव लेकर मालिकों से मिला और ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जब दिहाड़ियों ने एक मूल्य सूची प्रस्तुत करके लम्बी वार्ता के बाद समझौते किए। जव संस्था और मालिकों के वीच समझौते हो जाते थे तव संस्था के एक सदस्य को प्रायः एक कारखाने से दूसरे कारखाने

में घूम-फिरकर यह देखने के लिये कहा जाता था कि समझौते का पालन किया जा रहा है या नहीं। अन्य मामलों में समझौते के परिपालन पर निगरानी रखने के लिए "चलती-फिरती समितियां" नियुक्त की गईं।

उस जमाने में हड़तालें प्रायः शान्तिपूर्ण होती थीं जिनसे मजदूर मजदूरी सम्बन्धी वार्ता भंग हो जाने पर, अथवा जब मालिक समझौते की शर्तों का पालन करने से इन्कार कर देते थे या संस्था के सदस्यों से अतिरिक्त अन्य लोगों को काम पर लगाया जाता था, अपने हितों की रक्षा करने का यत्न करते थे। कर्मचारी अपना काम छोड़कर घर बैठ जाते थे, जब तक कि कोई समझौता नहीं हो जाता था। संघर्ष हिंसात्मक रूप में नहीं प्रायः अखबारों के कालमों में चलता था। मालिक व श्रमिक दोनों अखबारों में नोटिस निकाल कर जनता के सामने अपना-अपना पक्ष रखते थे। जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपील और जवाबी अपीलें यह जाहिर करती हैं कि श्रम-सम्बन्धों का उपयुक्त आधार निश्चित करने के लिये जनमत का कितना अधिक महत्व था।

लेकिन ऐसे भी अवसर आए जब हड़तालियों ने अधिक उग्र कदम उठाए। फिलाडेल्फिया के जूता-निर्माताओं की हड़ताल में ६ मजदूर काम करते रहे और उन्हें मालिक के मकान के ऊपर के कमरे में छिपा कर रखा गया। हड़ताली उनकी टोह लेते रहे और एक रविवार को जब वे पास की सराय में गए तो उनको उन्होंने बुरी तरह पीटा। एक दूसरे अवसर पर, निर्धारित वेतन न देने के कारण एक कारखाने का बायकाट किया गया और मालिक ने ५० नए मजदूरों के लिए विज्ञापन दिया तो हड़तालियों ने मजबूती के साथ धरना दिया। जो गैर-यूनियन श्रमिक हड़तालियों का स्थान लेते थे उनके खिलाफ बड़ा रोष फैलता था और उन पर जिन्हें घृणा से "स्कैब" कहा जाने लगा था, हमले की वारदातें असाधारण बात नहीं थी।

नाविकों की बार-बार की गई हड़तालों में कोलाहलपूर्ण प्रदर्शन और कभी कभी हिंसा भी हुई। न्यूयार्क में एक हड़ताल में, जिसमें नाविकों ने साप्ताहिक वेतन १० डालर से १४ डालर किए जाने की मांग की थी, इतना उपद्रव हुआ कि अंत में हड़तालियों के प्रदर्शन को सिपाहियों द्वारा भंग कराना पड़ा। एक और दफ़ा नाविकों ने एक जहाज पर चढ़कर उसे लूटने की कोशिश

की, जिसके मालिक से वे विशेष रूप से रुष्ट थे। उनके आयोजित हमले की बात का पता लगते ही कुछ नागरिकों ने जहाज पर रक्षात्मक मोर्चे सम्हाल लिए और जब हड़तालियों ने, एक वाद्यवादक दल की आड़ में झण्डे लिए हुए पीछे की तरफ से उस पर चढ़ने की कोशिश की तो उन्हें "तीन बार पीछे धकेल दिया गया, उनकी नाकें तोड़ दी गई सो अलग।" नाविक संगठित नहीं थे और बहुत उपद्रवी थे कारीगर और मिस्त्री इस प्रकार के तौर-तरीकों को पसन्द नहीं करते थे, जिन्हें वे दक्ष कारीगरों के लिए शोभा की बात नहीं समझते थे।

मजदूरों की संस्थाओं के विकास तथा उनकी उग्र हलचलों से मालिकों को अधिकाधिक चिन्ता होने लगी थी। उन्होंने शीघ्र ही अधिक वेतन की मांग मंजूर न करने और 'बन्द कारखाना' पद्धति का मुकाबला करने के लिये परस्पर सहयोग करना शुरू कर दिया। बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियां जब मजदूरों की भूतपूर्व स्वतंत्र स्थिति पर चोटें कर रही थीं, तब उन मजदूरों ने जहां आत्मरक्षा के लिए अपने संगठन स्थापित किए, वहां मास्टरों को भी प्रतियोगितात्मक पूंजीवादी समाज में अपनी स्थिति को कायम रखना मुश्किल प्रतीत होने लगा। जब वे स्वयं अपने बलबूते पर संगठित कर्मचारियों का सामना नहीं कर सके तो उन्होंने अदालतों की शरण ली और मजदूरों की संस्थाओं को व्यापार में रुकावट डालने वाले संगठन और षड्यंत्र कहकर उन्हें बदनाम किया।

पहले पहल १८०६ में फिलाडेल्फिया के जूता-निर्माण मजदूरों की संस्था पर मुकद्मा चलाया गया। अदालत में केस रखा गया कि इन उग्र जूता-निर्माताओं ने अधिक वेतन की मांग करते हुए बार-बार हड़तालें की हैं। अदालत का जज मालिकों का पक्षपोषक सिद्ध हुआ। जूरी के सामने अभियोगपत्र पढ़ते हुए उसने हड़ताल को "सार्वजनिक शरारत और निजी-नुकसान से भरा" बताया और उन १२ आदमियों के लिए यह सोचने की गुंजायश नहीं छोड़ी वह उनसे किस प्रकार के फैसले की आशा करता है।

उसने कहा: "अपनी मजदूरी बढ़वाने के लिये मजदूरों के संगठित को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। एक तो स्वयं को लाभ पहुँचाने

की दृष्टि से और दूसरे उनको नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से जो उनकी संस्था में शामिल नहीं होते, कानून दोनों की निन्दा करता है"....इस प्रकार के निर्णय का आधार पुराने कानून में निहित यह सिद्धान्त था, कि जहाँ कहीं दो या तीन व्यक्ति मिलकर कुछ करने का षड्यंत्र रचते हैं, सार्वजनिक हित खतरे में पड़ता ही है, यद्यपि 'वे अलग-अलग उस काम को करने के हकदार होते हैं। इस सिद्धान्त को उन संगठनों पर भी जिनका उद्देश्य केवल अपने वेतनों में वृद्धि करवाना था, लागू करने से शायद न्याया-धीश के मन में भी सन्देह उत्पन्न हो गया था लेकिन शीघ्र ही उसने उसे अपने मन से निकाल फैंका। उसने कहा कि "अगर नियम स्पष्ट हैं तो हमें उन पर चलना पड़ेगा, यद्यपि जिस सिद्धान्त पर वे आधारित हैं, वह हमें समझ नहीं आता। हम उसे इसी लिए नहीं ठुकरा सकते क्योंकि वह हमें समझ नहीं आता।"

४ वर्ष बाद न्यूयार्क के जूता-निर्माता मजदूरों की और १८१५ में पिट्स-बर्ग में जूता-निर्माताओं के एक और संगठन पर इसी प्रकार का मुजरिमाना साजिश का आरोप लगाया गया। किन्तु अब वेतन-वृद्धि के लिए किए जाने वाले संगठित प्रयत्नों की एक दम निन्दा ही नहीं की जाती है। न्यूयार्क के जज ने इस उद्देश्य के मजदूरों के संगठित होने के अधिकार से सर्वथा इंकार नहीं किया लेकिन उसने कहा कि "जिन साधनों का वे इस्तेमाल कर रहे हैं वे "बहुत मनमाने और दबाव डालने वाले हैं और अपने साथी नागरिकों को उतने ही कीमती अधिकारों से वंचित करने वाले हैं, जितने कीमती वे अपने अधिकारों को समझते हैं।" पिट्सबर्ग के केस में एक और मुद्दे पर बल दिया गया। किसी मालिक के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करके अपनी मांगें पूरी करवाने की कोशिश में मजदूरों का संगठन करने के कार्य को न केवल इसलिए अवैधानिक साजिश बताया गया कि इससे मालिक को नुकसान पहुँ... बल्कि इसलिए भी कि इससे समाज को भी हानि होती है। जज ने... में जाने से ही इंकार कर दिया कि ज्यादती मजदूरों की है या म... मज़दूरों की संस्था की इसलिए निन्दा की, क्योंकि यह "एकाधि... उत्पन्न करती या व्यवसाय की समस्त स्वाधीनता को सीमित ...

साजिशों के इन फतवों ने मजदूरों में व्यापक रोष ...

वे पूछने लगे कि क्या अन्य सब संगठनों जैसे व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, खिलाड़ियों और नृत्य, दावत और भोजों के लिए स्त्री-पुरुषों के संगठनों को तो अनुमति रहेगी और निन्दा केवल भुखमरी के खिलाफ गरीब मजदूरों के संगठन की ही की जाएगी ?

जनता के नाम एक अपील में कहा गया कि "स्वाधीनता तो सिर्फ नाम-मात्र रह जाएगी, अगर वह काम करने पर, जिसका देश के कानून हमें अधिकार देते हैं, हमारे ऊपर जीवन-यापन के अल्प साधनों की पैमाइश के लिए जमादारों की नियुक्ति की जानी है, अगर अपने परिवारों के भरण-पोषण के लिए उपयुक्त और न्यायपूर्ण वेतन प्राप्त करने की कोशिशों के लिए हमें जेलों में डाल दिया जाना है और सिर्फ इसलिए हमें गम्भीर अपराधी और हत्यारा समझा जाना है कि अपने श्रम के लिए जिसे हम पर्याप्त मेहनताना समझते हैं उसे लेने या इन्कार करने के अपने अधिकार का हम दावा करते हैं।"

स्थानीय नीतियों में भी इस मामले का समावेश हो गया। अमरीका में अंग्रेजी कानूनों के सामान्य उपयोग के प्रश्न पर एक बार संघवादियों और जैफरसनी रिपब्लिकनों के बीच कड़ा विवाद खड़ा हो गया और रिपब्लिकनों ने अंग्रेजी कानून के अलोकतन्त्रीय सिद्धान्तों को मजदूर यूनियनों पर लागू करने को स्वाधीनता के सम्पूर्ण ध्येय के लिए एक चुनौती करार दिया। उन्होंने कहा कि संगठन बनाने के अधिकार को अन्य बुनियादी अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता और उन्होंने श्रमिकों का बड़े उत्साह से पक्ष लिया।

प्रमुख जैफरसनी अखबार 'फिलाडेलफिया औरोरा' ने सन् १८०६ में लिखा कि "क्या इस चीज पर विश्वास किया जा सकता है कि ऐसे समय जब कि नीग्रो की हालत सुधरने वाली है, गोरों की हालत गुलामों की सी बनाने की कोशिश की जा रही है ? क्या अमरीका अथवा पेंसिलवेनिया के संविधानों में ऐसी कोई चीज है जो एक व्यक्ति को दूसरे से यह कहने का अधिकार प्रदान करती है कि उसके श्रम का मूल्य क्या होगा ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रेजी कानूनों की बदौलत ही इस प्रकार की चीजें संभव हैं।"

यह विवाद अगले अनेक वर्षों तक चलता रहा लेकिन मजदूरों के खिलाफ निर्णय कायम रहे। इनसे मजदूरों की न तो आगे और संस्थाएँ बनना रुका

और न ही हड़ताल और बहिष्कार बिल्कुल समाप्त हुए। लेकिन जब मालिक झगड़ों को अदालतों में ले जाते थे तो मजदूरों को साजिश के आरोपों से अपना बचाव करने में बड़ी परेशानी होती थी।

अगर ये मामले श्रम-संगठनों के प्रारम्भिक आन्दोलन पर पहली चोट थे तो नई यूनियनों को शीघ्र ही अपने अस्तित्व के लिए अधिक गम्भीर खतरों का सामना करना पड़ा। १८१९ में देश में भीषण मन्दी आई। जैसे-जैसे कारोबार ठप्प हुए, मजदूरों की माँग स्वतः घट गई और दक्ष मजदूरों को भी काम पाने में बड़ी कठिनाई होने लगी। अब वे इस स्थिति में नहीं रहे कि ऊँचे वेतनों के लिए डटे रह सकें या 'बन्द कारखाना' प्रणाली को लागू करवा सकें। जो कोई काम उन्हें दिया जाता उसके लिए मजदूरी की दर और काम की हालतों की परवाह किए बिना वे उसे स्वीकार कर लेते थे। इन परिस्थितियों में युवा यूनियनें अपनी सदस्यता कायम नहीं रख सकीं और शीघ्र ही भंग हो गईं। हालांकि कुछ यूनियनें जिन्दा रह सकीं फिर भी जैसे ही यह आर्थिक विपदा देश में फैली अधिकांश यूनियनें देखते-देखते खत्म हो गईं।

१९ वीं सदी में बार-बार ऐसा ही हुआ। समृद्धि के दिनों में जब मजदूरों की बढ़ती हुई माँग ने उन्हें सौदेबाजी की प्रभावशाली शक्ति दी तब मजदूर यूनियनें खूब फली-फूलीं और जब कभी मन्दी आई और काम-धन्धे की कमी ने हर आदमी को दूसरों की परवाह किए बिना अपनी ही फिक्र करने पर मजबूर कर दिया तब वे खत्म हो जाती थीं। कठिन समय में भी मजदूर अपनी यूनियन की शक्ति को बनाए रख सकें, इसका पहला मौका १८९० के बाद के दशक में आया।

लेकिन यह अभी सुदूर भविष्य के गर्भ में था। सदी के प्रारम्भिक वर्षों में नवनिर्मित यूनियनों का क्षेत्र इतना सीमित था और वे इतनी अनुभवहीन थीं कि मालिकों ने जब कभी वेतनों का स्तर गिराने और "बन्द कारखाना" पद्धति को तोड़ने के लिए हर अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की तब वे यूनियनें मुकाबला कर सकें, इसकी कोई सम्भावना नहीं थी। लेकिन जैसा कि बाद में ढर्रा ही पड़ गया, सन् १८२२ के बाद जब समृद्धि लौटी तो यूनियनें भी फिर पनपीं। कारीगरों और मिस्त्रियों की जो थोड़ी संस्थाएं इस मन्दी

में भी किसी प्रकार जीवित रह सकीं उनको अपने सदस्यों की सौदेवाजी की ताकत बढ़ जाने से मानो नवजीवन मिला और जो संगठन खत्म हो गए थे, उनके स्थान पर नए संगठन बन गए।

न केवल मुद्रकों, जूता बनाने वालों, दर्जियों बढ़इयों व अन्य दक्ष श्रमिकों की यूनियनें फिर से हरी-भरी हो गईं बल्कि न्यू इंग्लैण्ड की कपड़ा मिलों में फैक्ट्री मजदूरों के बीच संगठन की पहली बार प्रायोगिक शुरुआत हुई। इसके अलावा ये नई यूनियनें विशेष रूप से सक्रिय थीं और अपनी मांगें मनवाने के लिये हड़तलों या बहिष्कार का आश्रय लेने से नहीं हिचकिचाती थीं। अधिक वेतन तथा काम के कम घण्टे दोनों के लिए सफल हड़तालों के समाचार उस वक्त के अखबारों में देखने को मिलते हैं। बफैलो में दर्जियों ने, फिलाडेल्फिया में जहाज बनाने वाले खातियों, बाल्टीमोर के फर्निचर बनाने वालों ने और न्यूयार्क में पेण्टरों, दर्जियों, पत्थर काटने वाले दिहाड़ियों और यहां तक कि सामान्य मजदूरों ने भी सफल हड़तालें कीं। कारखाने के मजदूरों में संगठन की बदौलत महिला कर्मचारियों ने भी पहली हड़ताल की, जब १८२४ में पाटुकट (रोड आइलैण्ड) में जुलाहों ने काम बन्द कर दिया। जिस बैठक में इन महिलाओं ने उक्त कदम उठाने का निश्चय किया, उसकी रिपोर्ट 'नेशनल गजट' में इस प्रकार छपी :—"कितना भी विचित्र लगे, यह हड़ताल बिना किसी शोर-शराबे के चलाई गई और इसमें मुश्किल से ही कोई भाषण हुआ।"

इन स्थानीय मजदूर संस्थाओं के पुनरुज्जीवन और उग्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मजदूरों के संगठन की खातिर एक ऐसा कदम उठाया गया जो कारीगरों की सीमा को लांघ जाता था। १८२७ में फिलाडेल्फिया में मैकेनिक्स यूनियन आव ट्रेड ऐसोसियेशन की स्थापना हुई। आज की शब्दावली में इसका अभिप्राय है—यूनियनों का संघ या केन्द्रीय संगठन। यह देश में मजदूरों का ऐसा पहला संगठन था जो एक से अधिक व्यवसाय के श्रमिकों को एक प्लेटफार्म पर लाया और इससे फिलाडेल्फिया के मजदूरों
-व्यापी आधार पर मिलकर कार्रवाई कर सकना संभव हुआ।
५। संघ खातियों की एक हड़ताल से बना जो १० घण्टे के दिन की
रहे थे और जिन्हें इमारती व्यवसाय के राज, पेन्टर और ग्लेजियर

जैसे अन्य मजदूरों का समर्थन प्राप्त हुआ। हड़ताल विफल हो गई लेकिन साथ-साथ काम करने का इससे जो अनुभव प्राप्त हुआ उससे और ज्यादा स्थायी संगठन बनाया जा सका। सब विद्यमान श्रमिक संस्थाओं को संघ में शामिल होने को कहा गया और जिन व्यवसायों में कोई यूनियन नहीं थी उनसे कहा गया कि वे तुरन्त संगठित हों और अपने प्रतिनिधि भेजें।

मिस्त्रियों की यूनियन का जन्म यद्यपि १० घण्टे का दिन कराने के लिए की गई हड़ताल से हुआ था तो भी इसकी मुख्य चिन्ता अधिक वेतन और काम के कम घण्टे जैसे प्रारम्भिक उद्देश्यों की नहीं थी। उत्पादकों के लिए समानता की व्यापक आवाज़ बुलन्द करके श्रमिक संस्थाओं में एक नई गतिविधि का सूत्रपात किया गया। नई आर्थिक व्यवस्था से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण मजदूर अपनी आर्थिक व सामाजिक स्थिति के बारे में अधिकाधिक चिन्तित रहने लगे थे। जब मजदूरों को यह अहसास हुआ कि नई श्रेणियां बनती जा रही हैं तो फिलाडेल्फिया के मजदूरों ने अपवे वर्ग की स्थिति को कायम रखने के कुछ उपाय सोचे। वे स्वयं को मालिकों के खिलाफ डटे श्रमिक नहीं समझते थे बल्कि "उत्पादक व यांत्रिक वर्ग" के सदस्य समझते थे जिनका लक्ष्य सारे समाज की समृद्धि और कल्याण की चिन्ता करना था।

नए संगठन के संविधान की भूमिका में कहा गया है कि "अगर आम लोगों को अपने श्रम से अपने व अपने परिवार के लिए जीवन के भरपूर सुख सुविधाओं का उपयोग करने लायक बनाना है तो मकान, फर्निचर और कपड़ों की खपत अब की अपेक्षा कम से कम दुगनी करनी होगी और जिस मांग से मालिक अपना गुजारा कर सकें, या धन-संचय कर सकें उसे भी समानुपात में बढ़ाना होगा। इसलिए इस संघ का वास्तविक उद्देश्य संभव हो तो उन बुराइयों को दूर करना है जिनका मानव-श्रम का मूल्य गिरने से उभरना अनिवार्य है...और ऐसी अन्य संस्थाओं के साथ, जो अब के बाद सारे देश में बनेंगी, समाज के सब वर्गों तथा व्यक्तियों के बीच मानसिक, नैतिक, राजनीतिक तथा वैज्ञानिक शक्तियों के न्यायपूर्ण संतुलन की स्थापना में सहयोग करना है।"

इन उद्देश्यों के, जिनमें ऊंचे वेतन के लिए क्रयशक्ति के सिद्धान्त का सुझाव दिया जाने लगा था, निश्चित राजनीतिक प्रयोजन थे। मैकेनिक्स

यूनियन आव ट्रेड ऐसोसियेशन्स ने ट्रेड यूनियन हरकतों में वस्तुतः कभी सीधा हिस्सा नहीं लिया बल्कि वह एकदम राजनीति की ओर मुड़ गई। इसने फिलाडेल्फिया के मिस्त्रियों और कारीगरों को "सजातीयता की भावना के बन्धन काट डालने और समान अधिकारों के झण्डे के नीचे एकजूट होने" का आह्वान किया। इसने स्थानीय कार्यालय के लिए उम्मीदवार नामजद करने की अपील की जो श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

—:o:—

३ : श्रमिकों की पार्टियां

मैकेनिक्स यूनियन ग्राव ट्रेड ऐसोसियेशन ने जब अपने सदस्यों को सार्वजनिक पदों के लिए उम्मीदवार नमाजद करने की प्रेरणा दी तब उसने मजदूरों के लिए एक नई चीज शुरू की जो बाद में श्रमिक पार्टियों का व्यापक राजनीतिक ग्रान्दोलन बन गई। यह शीघ्र ही पेंसिलवेनिया ग्रौर न्यूयार्क जैसे शहरों में भी फैल गया ग्रौर उसे न केवल न्यूयार्क की स्थानीय पार्टियों में बल्कि ऊपरी राज्यों की वस्तियों मैसाच्युसेट्स ग्रौर न्यू इंग्लैण्ड के ग्रन्य हिस्सों में भी व्यापक समर्थन मिला। ग्रन्ततोगत्वा कम से कम एक दर्जन राज्यों में श्रमिकों की पार्टियां बन गईं। पश्चिम में ग्रोहायो तक ग्रौर ग्रटलाण्टिक समुद्र-तट के साथ-साथ किसानों, कारीगरों ग्रौर मिस्त्रियों के स्थानीय समुदायों ने ग्रपने-ग्रपने राजनीतिक उम्मीदवार नामजद किए ग्रौर कई स्थानों पर उन्हें चुना। कुछ ग्ररसे तक उनका बड़ा महत्व रहा ग्रौर कभी-कभी स्थानीय चुनावों में वड़ी पार्टियों के वीच वे सन्तुलन का काम करते थे।

१८३० के दशक के प्रारंभिक दिनों में मजदूरों के ग्रखवारों का भी खूब विस्तार हुग्रा। इस प्रकार के कम से सम ६८ ग्रखवार श्रमिकों के हितों की रक्षा कर रहे थे ग्रौर उन की हालत में सुधार के लिए ग्रान्दोलन कर रहे थे। उनके उत्साह ग्रौर विश्वास की कोई सीमा नहीं थी। "नेवार्क विलेज क्रानिकल" ने मई, १८३० में लिखा कि "मेन से जार्जिया तक कुछ ही महीनों में हमें क्रांति के लक्षण दिखाई देते हैं जो '७६ की क्रांति को छोड़कर ग्रौर किसी क्रान्ति से हीन नहीं हैं।" इसके कुछ दिन बाद 'ग्रल्वानी वर्किंगमेंन्स ऐडवोकेट' ने लिखा : "समस्त विशाल गणराज्य में किसान, मिस्त्री ग्रौर श्रमिक इसके कानूनों व प्रशासन में स्वाधीनता ग्रौर समानता के उन सिद्धान्तों का जो स्वाधीनता की घोषणा में प्रतिपादित हैं, पुट देने के लिए एकत्र हो रहे हैं।"

ये घटनाएं जैक्सनी लोकतंत्र की जिसके साथ श्रमिकों की राजनीतिक गतिविधियां धीरे-धीरे घुल मिल गईं जागती हुई ताकतों की ग्रभिव्यक्ति ग्रौर पहले पहल फिलाडेल्फिया में व्यक्त की गई समान नागरिकता की मांग का

इजहार दोनों थीं। देश इन वर्षों में तेजी से फैल रहा था। नए पश्चिमी प्रदेशों में निवास के द्वार खुलने, सड़कों व नहरों के निर्माण उद्योग के निरन्तर विकास तथा सब जगह शहर बनते जाने से उत्फुल्ल विश्वास की भावना उत्पन्न हो गई थी। देश के श्रमिक मूलतः यही चाहते थे कि राष्ट्र के विकास तथा समृद्धि के लाभों में पूर्ण भाग लेने का उन्हें भी हक हो और उन्होंने महसूस किया कि १८२० के दशक की मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें उन अवसरों से वंचित किया जा रहा है, जिन्हें प्राप्त करने का उन्हें हक है। मताधिकार के लिए जायदाद की मिल्कियत की शर्त को हटाकर हाल में उन्होंने जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त की थी उसके बाद वे अपने हितों की रक्षा के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करने को तैयार थे।

इसमें सन्देह नहीं कि व्यावसायिक पूंजीवाद के अभ्युदय से अर्थ तंत्र में जो तब्दीलियां हो रही थीं उनके फलस्वरूप मजदूरों की आम हालत निरन्तर गिरती जा रही थी। समाज में साधारण श्रेणी-भेद ज्यादा गहरे हो चले थे। तत्कालीन आलोचकों ने देखा कि एक तरफ तो पैदावार करने वाला गरीब मजदूरों का आम समूह है और दूसरी ओर सम्पन्न अनुत्पादक संभ्रान्त वर्ग है जिसने विशेष अधिकारों का दुर्ग खड़ा कर रखा है। बैंकिंग तथा अन्य एकच्छत्र उद्योगों ने इस भेद को और बढ़ाया और अधिकांश मजदूरों ने यह देखा कि उनकी काम की हालतों में कोई सुधार नहीं हो रहा है, यद्यपि वाणिज्य और व्यापार का विस्तार हो रहा है और राष्ट्र समग्र दृष्टि से अधिक समृद्ध हो रहा है।

मजदूरियां बढ़ीं लेकिन उतनी नहीं जितनी चीजों की कीमतें। काम के सामान्य घण्टे १२ और १५ रहे। गर्मियों में कारीगर और मिस्त्री सवेरे ४ बजे से ही काम शुरू कर देते थे। १० बजे एक घण्टे तक लंच करते थे और फिर ३ बजे खाना खाते थे जिसके बाद सूरज छिपने पर ही उस दिन के काम से छुट्टी मिलती थी। उन्हें प्रायः उस मुद्रा में मजदूरी दी जाती जिसकी कीमत गिरी होती थी और वह निरन्तर घटती-बढ़ती रहती थी। अगर मालिक [illegible] न दे पाएं तो मजदूरों की शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं थी और [illegible]जदूर अपनी कोई देनदारी न निबाह पाएं तो उन्हें ऋणग्रस्तता पर जेल [illegible] दी जा सकती थी।

इसके अलावा श्रमिकों ने महसूस किया कि सरकार बिल्कुल संभ्रान्त लोगों की तरफ है और उसकी नीतियां उन अवस्थाओं को बनाए हुए हैं जो सभी मजदूरों की हालत को बिगाड़ रही हैं। दोनों बड़े दलों में से किसी में भी उनका विश्वास नहीं था, चाहे वे मजदूरों के प्रति अपनी सद्भावना का कितना भी बखान करें, क्योंकि सार्वजनिक पदों पर जो भी व्यक्ति चुने जाते थे वे हमेशा उसी वर्ग के होते थे, जिसे वे अपना उत्पीड़क मानने लगे थे। अब तक वे अपने खिलाफ झुकते हुए शक्ति-सन्तुलन को ठीक करने में राजनीतिक दृष्टि से असहाय थे। मताधिकार से लैस होने के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि वे उन नीतियों को अब चुप-चाप स्वीकार नहीं करेंगे जो विशाल बहुमत के हितों की परवाह न करते हुए कुछ गिने चुने प्रिय व्यक्तियों के लिए सरकार, वित्त और व्यवसाय में विशेष अधिकार सुरक्षित रखने का यत्न करती थीं।

अपने निजी दल बनाकर मजदूरों ने अपने ही उत्पादक वर्ग के सदस्यों को सरकार में स्थान दिलाने का प्रयत्न किया और उन्हें विश्वास हो गया कि इस प्रकार वे जनता का हित कर रहे हैं। उनकी पार्टी के प्लेट-फार्मों से विशेषाधिकार के हर मामले पर विशेषकर बैंकिंग एकाधिकार पर जोरदार आक्षेप किए जाते थे। लेकिन समान नागरिकता की स्थापना के सामान्य उद्देश्य के प्रतीक के रूप में उनकी सबसे पहली मांग निश्चित रूप से मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा की थी। हर सरकारी काम-काज में "जन सामान्य" के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की चेष्टा करते हुए उन्होंने यह महसूस किया कि आम लोगों के लिए शिक्षा प्रभावशाली लोकतंत्र की तरफ पहला कदम है। इससे ज्यादा विशिष्ट आधार पर मजदूरों ने कर्जदारी के लिए कैद की व्यवस्था और गिरवी रखी गई चीज को हस्तगत करने के कानूनों के खात्मे, गरीबों के लिए बहुत कष्टकारी सैनिक कवायद के रिवाज में संशोधन करने, सब सरकारी अधिकारियों के प्रत्यक्ष चुनाव, कर लगाने में ज्यादा समानता और चर्च तथा राज्य को बिल्कुल अलग कर देने की भी मांग की।

इस प्रकार मजदूरों के राजनीतिक आन्दोलन, और उनके स्थानीय के निर्माण में उदार-सुधार की भावना निहित थी। यह आन्दोलन ब के किसी भी मजदूर आन्दोलन की अपेक्षा अधिक व्यापक था। लो

महान उभार में जिससे राष्ट्रीय मंच पर ऐण्ड्र्यू जैक्सन का समान्य जन के हितों के प्रवक्ता के रूप में आविर्भाव हुआ, पूर्वी शहरों में श्रमिकों का विद्रोह नई पश्चिमी वस्तियों में किसानों के विद्रोह से अधिकाधिक जुड़ता चला गया। संभव है १८२८ में सभी श्रमिकों ने डैमोक्रेटों का समर्थन न किया हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जब जैक्सम ने उनके द्वारा पेश किए गये मामलों में अधिकाधिक दिलचस्पी दिखाई तो उनका भारी बहुमत जैक्सन के पक्ष में हो गया। 'समाज के अदना सदस्यों' के हितों की वकालत करते हुए वह उनमें मिस्त्रियों, मजदूरों और किसानों को खास तौर से शामिल करता था। जैक्सनी लोकतंत्र का आधार जैफरसनी लोकतंत्र से ज्यादा व्यापक था और उसमे सामन्तों की व्यक्तिवादी भावना और पूर्व के श्रमिकों की समता की भावना दोनों का समावेश था।

मजदूरों द्वारा बनाई गई पार्टियों का १८३० के दशक के जटिल व परिवर्तमान राजनीतिक ढांचे में उलझ जाना अनिवार्य था। किन्तु उनका अंतिम भाग्य कुछ भी रहा हो, सुधारों की मांग में तेजी लाने और प्रगतिवादी सिद्धान्तों को बढ़ावा देने में उनका प्रभाव महत्वपूर्ण था। मैसाच्युसेट्स में श्रमिकों की पार्टी की भूमिका पर टीका करते हुए एक ह्विग अखबार ने बड़ी चिढ़ के साथ यह आरोप लगाया कि "मजदूरवाद और जैक्सनवाद" में कोई फर्क नहीं है। यह बात अगर हमेशा ही सच नहीं थी तो भी यह तो निश्चित था कि जैक्सनी लोकतंत्र ने जो विजय हासिल की वे अधिकांश में मजदूरों के सहयोग से प्राप्त की गई थी।

मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक सत्ता के महत्व का अन्य प्रकार से भी दिग्दर्शन हुआ। जैक्सन द्वारा सामान्यजन के हितों की वकालत किए जाने के विरोध में नव संगठित ह्विगों ने कुछ अरसे तक संघवादी परम्पराओं को कायम रखने की कोशिश की जो अमीर और सामन्ती लोगों की सरकार के पक्ष में थी। उन्होंने विशेष रूप से "हर चलते हुए आदमी को मताधिकार दिए जाने का" विरोध किया। लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि वे छोटे किसानों और र मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक सत्ता को रोकने में असमर्थ हैं तो वे टेक बदलने लगे। जैक्सन पर वर्ग संघर्ष बढ़ाने का आरोप लगाते हुए — : र५ बाद के टोरियों ने फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट पर लगाया, उन्होंने कहा

दिया गया और १६ अक्टूबर को उसने एक रिपोर्ट निकाली, जिसकी २० हजार प्रतियाँ बाद में वितरित की गईं। उसमें मौजूदा सामाजिक व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किये गए थे और न्यूयार्क विधान सभा के लिए उन लोगों में से "जो अपने ही श्रम से जीते हैं, परोपजीवी नहीं" राजनीतिक उम्मीदवार नामजद करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने को कहा गया था। ४ दिन बाद यह सम्मेलन हुआ। जब सब गैर-श्रमिकों को "जैसे बैंकरों, दलालों, अमीरों आदि को" सभा-भवन से चले जाने की चेतावनी दी गई उसके बाद मजदूर विधान सभा के लिए एक मुद्रक, दो मशीन-चालक, दो खातियों, एक पेण्टर तथा एक मोदी को उम्मीदवार नामजद करने पर सहमत हो गए।

लेकिन शुरू से ही मजदूरों की नई पार्टी के नेतृत्व के प्रश्न पर प्रतिद्वन्द्विता और साजिशों से मजदूरों में फूट का खतरा पैदा हो गया। इस पर कई अत्यन्त व्यक्तिवादी सुधारकों का प्रभुत्व स्थापित हो गया जिनका दर्शन और विचार उन व्यावहारिक माँगों से कहीं ज्यादा उग्र थे जिनमें मजदूरों की मुख्यतः दिलचस्पी थी। न्यूयार्क की श्रमिक पार्टी पर और मजदूरों की आम राजनीतिक गतिविधियों की दिशा पर उक्त प्रकार के चार व्यक्तितों का विशेष रूप से प्रभाव था।

शुरू-शुरू में पार्टी ज्यादातर एक मशीन-चालक, स्किडमोर के प्रभाव में थी, जिसने मजदूरों को १० घण्टे का दिन कायम करने के लिए "अपने सामन्ती उत्पीड़कों को झुकाने" के साधन के रूप में अपना प्रोग्राम व्यापक कर देने के लिए राजी कर लिया। स्किडमोर ने स्वयं शिक्षा पाई थी, मजदूरों के हितों का वह एक उग्र और कट्टर चैम्पियन था और कृषि के सम्बन्ध में उसने एक ऐसी विचारधारा अपनाई जो सम्पत्ति के वर्तमान अधिकारों के सम्पूर्ण आधार पर कुठाराघात करने वाली थी। वह कहता था कि जब कोई व्यवित जुलाहा, राज, धातु का कारीगर या अन्य मजदूर बनने के लिए जमीन पर अपने मौलिक और कुदरती अधिकार को छोड़ता है तब उसे समाज से यह गारण्टी प्राप्त करने का हक है कि "अपने युक्तियुक्त श्रम की बदौलत वह अन्यों के समान आराम से रह सकेगा।" जो प्रणाली इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं करती वह उसकी राय में गलत थी और वह बुनियादी राजनीतिक [illegible]ों के पक्ष में मजदूरों के विद्रोह का नेतृत्व करने की आशा करता था।

उसके विचार शीघ्र ही एक बड़े निबन्ध के रूप में प्रकाशित किए गए जिसका उसने लम्बा-चौड़ा शीर्षक रखा : "सम्पत्ति के लिए मनुष्य का अधिकार; वर्तमान पीढ़ी के वयस्कों के समान वितरण का प्रस्ताव और हर आने वाली पीढ़ी के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वयस्क बनने पर उसका समान उत्तराधिकार" स्किडमोर ने खास तौर से प्रस्ताव किया कि कर्जा और सम्पत्ति के सब दावे तुरन्त रद्द कर दिए जाएँ, और समाज की सम्पत्ति समग्रतः नीलाम कर दी जाए, जिसके साथ ही हर नागरिक की क्रयशक्ति बराबर हो। सम्पत्ति के इस प्रकार के कम्युनिस्टी विभाजन के बाद सब उत्तराधिकार का खात्मा कर समानता को निश्चित रूप से कायम रखा जा सकेगा।

इस क्रान्तिकारी प्रोग्राम के सब परिणामों को अच्छी तरह समझे बिना न्यूयार्क-श्रमिक पार्टी के सदस्यों ने अपने मूल प्लेटफार्म का खाका खींचने का काम स्किडमोर को सौंप दिया। यह प्लेटफार्म इस सीधे वायदे पर आधारित था। "सब मानव-समाज, हमारा भी और दूसरे भी मूलतः गलत बने हुए हैं" और इसमें जमीन के व्यक्तिगत स्वामित्व तथा सम्पत्ति के उत्तराधिकार दोनों की निन्दा की गई थी। लेकिन इसकी ज़्यादा स्पष्ट धाराओं में उन उद्देश्यों का उल्लेख था जो सब कहीं श्रमिकों के आन्दोलन के लिए आधारभूत थीं। प्लेटफार्म में सामूहिक शिक्षा, ऋण के लिए कैद की प्रणाली की समाप्ति, ऋण चुकाए जाने तक मिस्त्रियों की जायदाद को हथियाये रखने और लाइसेंसदार एकाधिकार की समाप्ति की माँग की गई थी।

एक दूसरा नेता जो स्किडमोर के कार्यक्रम को कम-से-कम आंशिक रूप में स्वीकार करता था लेकिन बाद के वर्षों में श्रमिक आन्दोलन में जिसका स्किडमोर से कहीं ज्यादा प्रभाव रहा जार्ज हेनरी एवन्स था। उसका धन्धा मुद्रण का था और उसने न्यूयार्क-पार्टी के मुखपत्र के रूप में "वर्किङ्गमेन्स ऐडवोकेट" की स्थापना की जो उन वर्षों में मज़दूरों का सबसे महत्वपूर्ण अखबार था। इसमें वह मजदूरों के हितों को बढ़ावा देने वाले लेख और सम्पादकीय निरन्तर लिखा करता था। स्किडमोर के प्रभाव को ज़ाहिर करते हुए पहले उसके अखबार ने यह नारा दिया, "सब बच्चों को बराबर की शिक्षा पाने का हक है; सब वयस्कों को समान सम्पत्ति का, और सारी मानव-जाति को समान अधिकार प्राप्त करने का हक है।" लेकिन बाद में उसके विचारों में

संशोधन हो गया यद्यपि वह जीवन-भर बुनियादी कृषि-सुधारों का कट्टर पक्षपाती बना रहा।

सब टोरियों की नज़र में मज़दूरों की पार्टी को बदनाम कराने के लिए मानो इस प्रकार के नेता पर्याप्त नहीं थे, इसकी गतिविधि में अन्य प्रकार के क्रान्तिकारी सुधारकों राबर्ट डेल ग्रोवन और फ्रांसिस राइट के भाग लेने से यह और बदनाम हुई। न्यूहार्मनी (इण्डियाना) में जहाँ कि राबर्ट डेल ग्रोवन के पिता अंग्रेज-सुधारक राबर्ट ग्रोवन ने फैक्ट्री प्रणाली की जगह अपने सामाजिक कार्य-क्रम पर अमल करने की कोशिश की थी, सहकारी समाज से हाल में न्यूयार्क आकर इन दोनों ने स्वभावतः ही मज़दूरों के आन्दोलन को अपने विशिष्ट प्रकार के सुधारों को लागू करने का माध्यम बना लिया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए "फ्री इंक्वाइरर" की स्थापना की और शीघ्र ही यह नए दल के समर्थन में प्रचार करने लगा।

राबर्ट डेन ग्रोवन इस वक्त छोटे कद का, नीली आंखों, लाल-पीले बालों वाला २८ वर्ष का नवयुवक था जिसके आदर्शवाद और सच्ची दयानतदारी ने उसे वस्तुतः प्रभावशाली बना दिया था। लड़खड़ाती आवाज और भद्दे हाव-भाव के बावजूद मज़दूरों की सभाओं में वह ओजस्वी भाषण देता और वह लिखता भी बहुत काफी और बहुत अच्छा था। वह सम्पत्ति के अधिक समान वितरण में दृढ़ विश्वास रखता था, संगठित धर्म के विरुद्ध था, तलाक के अधिक उदार कानूनों का हामी था, लेकिन उसकी मुख्य दिलचस्पी मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा में थी। वह एकात्म-भाव से यह महसूस करता था कि केवल इसी से समाज का पुनरुत्थान हो सकता है और उसने शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार भी किया था जिसमें एक प्रकार की 'राज्य संरक्षकता" प्रणाली की आवश्यकता बताई गई थी।

इस योजना के अनुसार सब बच्चों को चाहे वे अमीर के हों या गरीब के, अपने घरों से हटा कर राष्ट्रीय स्कूलों में रखा जाता जहाँ उन्हें लोकतन्त्र की भावना उत्पन्न करने के लिए एक ही तरह का खाना मिलता, एक ही तरह के सारे कपड़े पहनते और सबको एक से विषयों की शिक्षा दी जाती। "इस ... ईश्वर करे, भोग-विलास, दर्प और अज्ञान हमारे में से दूर हो और हम ...इयों का राष्ट्र बन जाएं, जैसा कि हम साथी नागरिकों को होना चाहिए।"

उक्त बात राज्य संरक्षकता पर एक रिपोर्ट में कही गई है। मज़दूरों ने यद्यपि इस विशिष्ट कार्यक्रम का पूरी तरह समर्थन नहीं किया तो भी ग्रोवन ने उनके शिक्षा सम्बन्धी विचारों के विकास में बहुत योग दिया।

जिन सुधारकों का श्रमिकों की पार्टी से सम्बन्ध रहा उन सबमें फ्रांसिस राइट सबसे ज्यादा उत्साही, सबसे ज्यादा आकर्षक और समकालीन लोगों की नज़रों में सबसे ज्यादा खतरनाक थी। यद्यपि वह एक स्वतन्त्र विचारक थी और महिलाओं के अधिकारों तथा आसान तलाक की इतनी ज्यादा पक्षपाती थी कि उस पर सामान्यतः स्वच्छन्द प्रेम की वकालत करने का आरोप लगाया जाता था तो भी उसने उग्र आन्दोलनकारी की भूमिका अदा नहीं की। लम्बी, पतली, घुंघराले लाल-भूरे वालों वाली यह महिला मज़दूरों की सभाओं में, जिनमें वह निरन्तर भाषण किया करती थी, चकाचौंध उत्पन्न कर देती थी। टोरी लोग जितने हैरान उसके क्रांतिकारी विचारों से होते थे, उतने ही एक महिला द्वारा सभामंच पर आने के दुःसाहसपूर्ण गुस्ताखी से स्तब्ध रह जाते थे किन्तु जो उसके भाषण को सुनते थे उनमें शायद ही कोई उसके प्रभाव से अछूता रह पाता हो। वाल्ट ह्विटमैन ने, जिसका खाती पिता उसे फ्रांसिस राइट की एक सभा में ले गया, बाद के वर्षों में लिखा कि "मेरे लिए वह एक मधुरतम स्मृति रही है। हम सब उससे प्रेम करते थे, उसके आगे शीश झुकाते थे। उस कमनीय हरिणी-सी के दर्शन हमें आनन्द विभोर कर देते थे.........उसका शरीर और आत्मा दोनों सुन्दर थीं।"

फैनी राइट स्काटलैंड में पैदा हुई थी और शुरू से ही जेरेमी बेंथम के प्रभाव में आने के कारण युवावस्था में ही सुधारों की उग्र चैम्पियन बन गई और बाद में जीवन भर रही। इस देश में आने पर शुरू में उसने गुलाम नीग्रो के हित-साधन का काम अपने हाथ में लिया और नाशोबा (टेनेसी) में उसने एक बस्ती बसाई जहां अपने खर्चे से कुछ गुलाम खरीद कर वहां रखे और उन्हें अन्ततोगत्वा आजादी के लिए और अमरीका से बाहर बसने के लिए तैयार किया। उसकी यह योजना जब फेल हो गई तो वह न्यू हार्मनी के समाज में आ मिली और तब रावर्ट डेल ग्रोवन को "फ्री इन्क्वाइरर" के सम्पादन में सहायता देने के लिए उसके साथ न्यूयार्क आ गई।

नाशोबा और न्यू हार्मनी में अपनी निराशाओं से वह मायूस नहीं हुई,

सुधार के लिए उसका उत्साह ज़रा भी ठण्डा नहीं पड़ा श्रौर बड़े उत्साह से उसने श्रमिक श्रान्दोलन को श्रपना लिया। इसमें उसने केवल सामाजिक श्रसमानता के खिलाफ विरोध की वल्कि पीड़ितों की तरफ से विद्रोह की झलक दिखाई दी, जिसके लिए इतिहास में कोई श्रौर उदाहरण नहीं था। 'फ्री इन्क्वाइरर' में उसने लिखा कि मानवजाति ने श्रव तक जो संघर्ष किए हैं उन से वर्तमान संघर्ष इस वात में भिन्न है कि यह स्पष्ट श्रौर खुला वर्ग संघर्ष है . . . . दुनिया के पीड़ित लोग श्रपनी पीठ पर से उन वूटधारी सवारों को उतार फेंकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिनका मज़दूरों को मृत्युपर्यन्त भूखा मार-मार कर उनसे काम लेने का श्रधिकार श्रव नहीं चलेगा। मजदूर काहिली के खिलाफ, मेहनत पैसे के खिलाफ श्रौर न्याय कानून तथा विशेषाधिकार के खिलाफ उठ खड़ा हुश्रा है।"

श्रखवारों ने फेनी राइट को कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे "बदनाम विदेशी" कहकर उसका महत्व घटाने की कोशिश की श्रौर उसे "नास्तिकता का महान रेड हारलट" बताया। लेकिन उन्होंने उसे कितनी भी गालियां दीं, सार्वजनिक मंचों पर श्रौर प्रेस में वह वेशर्मी से श्रपने "भयावह सिद्धान्तों" का प्रतिपादन करती रही।

जव श्रमिकों की पार्टी ने इस प्रकार के लोगों के नेतृत्व में सन् १८२९ में न्यूयार्क के चुनाव दंगल में श्रपने दूकानदार श्रौर कारीगर उम्मीदवारों के साथ कदम रखा तो टोरी हक्के-वक्के रह गए। पहले तो उन्होंने इसी वात का नारा लगाया कि उनके हितों को कोई खतरा नहीं है किन्तु जव मज़दूरों के वोट भारी संख्या में नई पार्टी को मिलते दिखाई दिए तो वे पूर्णतः सचेत हो गए। 'कूरियर ऐण्ड इन्क्वाइरर' ने विरोध प्रकट किया कि "हमें श्राश्चर्य श्रौर भय के साथ पता लगा है कि "नास्तिक टिकट" जिसे गलती से 'श्रमिक टिकट' कहा जाता है, शहर में श्रन्य हर विधान सभाई टिकट से कहीं आगे है। हमारी क्या दशा हो गई है। एक टिकट खुल्लमखुल्ला श्रौर जान वूझकर सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ, सम्पत्ति के श्रधिकारों के खिलाफ खड़ा होता है श्रौर हर टिकट से श्रागे बढ़ रहा है।" "न्यूयार्क कमशियल ऐडवर्टाइजर" की चीख-र तो श्रौर भी ज्यादा तेज़ थी उसने लिखा "समाज, पृथ्वी श्रौर स्वर्ग से ..।ड़ित, श्रनीश्वरवादी श्रौर निराश चोरी श्रौर नास्तिकता के वशीभूत......

ऐसे हैं ये देवदूत जो इस शहर में अनेक व्यस्कों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए घसीट रहे हैं ।"

लेकिन जब चुनाव का परिणाम निकला तो इस प्रकार की आशंकाएं अतिरंजित निकलीं। श्रमिकों की पार्टी शहर पर छा नहीं गई। तो भी उसने चुनाव में डाले गए २१ हज़ार वोटों में से ६००० वोट प्राप्त किए और अपने एक उम्मीदवार को जो खाती था, विधान सभा में भेजा। 'वर्किंगमेन्स ऐडवोकेट में जार्ज हेनरी एवन्स ने आवेशपूर्ण सम्पादकीय में लिखा। "आज़ादी के सूर्य ने ५० वर्ष तक अपना स्थिर और अपरिवर्तनशील रास्ता व्यर्थ में ही तय नहीं किया और तब एकदम अपनी इस उत्प्रेक्षा को भूलकर कुछ नरमी से कहा कि चुनाव परिणाम ने अवाम के हितों को हमारी उज्वल से भी उज्वल आशाओं से अधिक सिद्ध किया है।"

तो भी पार्टी के स्वयंभू नेताओं के विचारों में काफी मतभेद पैदा होने लगे थे और टामस स्किडमोर के अत्यधिक उग्रतावाद के खिलाफ आम सदस्यों के विद्रोह से शीघ्र ही आन्तरिक फूट और ग्रुपीय झगड़े उत्पन्न हो गए। दिसम्बर १८२९ की एक सभा में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसमें श्रमिकों ने साफ यह कहा कि "व्यक्तियों अथवा जनता में सम्पत्ति के अधिकार में उथल पुथल करने की उनकी कोई इच्छा या इरादा नहीं है।" रावर्ट डेल ओवन ने जब स्किडमोर के परित्याजित नेतृत्व को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो राज्य संरक्षकता के उसके कार्यक्रम के खिलाफ भी विरोध खड़ा हो गया। श्रमिक शिक्षा को अपने कार्यक्रम में सबसे ऊँचा स्थान देने को तो तैयार थे लेकिन उन्होंने कहा कि "किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर वे नास्तिकता, कृषक-वाद या वर्गीय सिद्धान्तों को थोपने के प्रयत्न का समर्थन नहीं करेंगे।" उन्होंने कहा कि स्कूल-प्रणाली "एक ऐसी योजना पर आधारित होनी चाहिए कि प्यार करने वाले मां-बाप अपनी सन्तान के समाज का आनन्द ले सकें।"

इन आंतरिक संघर्षों की जिन्हें कुछ हद तक मज़दूरों का समर्थन चाहने वाले राजनीतिक नेताओं ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उभारा
मूल संगठन में एक त्रिमुखी फूट के रूप में हुई स्किडमोर और
यायियों ने, जिन्हें वह अपने साथ रख सका, सीधे कृषि-अ

वना लिया एक अन्य ग्रुप ने, जिसके हितों की जार्ज हेनरी एवन्स ने वर्किंगमेन्स ऐड्वोकेट द्वारा वकालत की थी और जिसका ओवन पन्थी तथा फैनी राइट अब भी समर्थन करते थे मूल पार्टी को अक्षुण्ण रखने के लिए संघर्ष करते रहे। एक नए नेतृत्व में एक तीसरा ग्रुप एक अन्य मजदूर अखवार 'इवनिंग जरनल' के सहयोग से वन गया और जिस होटल में इसकी वैठकें की जाती थीं उसके नाम पर 'नार्थ अमेरिकन पार्टी' कहलाया।

पिछले दो ग्रुपों में खास तौर से कटुता और निरंतर संघर्ष वना रहा। वे शीघ्र ही प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिज्ञों का समर्थन करने लगे, मैदान में प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवार खड़े करने लगे, अपने-अपने अखवारों के पन्नों से एक-दूसरे पर शाब्दिक ईंट-पत्थर फेंकने लगे और एक दूसरे की सभाएं भंग करने लगे। मूल श्रमिक पार्टी ने जव यह देखा कि ओवन और फैनीराइट के क्रांतिकारी विचारों के कारण उस पर निरन्तर आक्षेप किए जा रहे हैं, तव उसने जोरों से उन आरोपों का प्रतिवाद किया। उसने कहा कि "नास्तिकता और कृपिवाद कोरे राजनीतिक काग भगोड़े हैं जैसे कि पहले १८०१ में डैमोक्रैटों को आतंकित करने के लिये खड़े किए गए थे।" नार्थ अमेरिकन पार्टी पर स्थानीय राजनीतिज्ञों के हाथ बिक जाने का आरोप लगाया गया और श्रमिकों से कहा गया कि वे "राजनीतिक पार्टियाँ बदलने वाले, चालवाज़ और पद के भूखों" से वचें। उनका कुछ प्रभाव पड़े इसके लिए एकता आवश्यक थी—इसलिए उनसे कहा गया कि युद्ध के अभिजात घोड़े को नीच गधे के साथ जुए में मत जोतो।"

न्यूयार्क में जहां अन्तर्दलीय प्रतिद्वन्द्विता जोरों पर थी, वहाँ अलवानी, ट्राय, स्केनेक्टडी, रोचेस्टर, सिराक्यूज़ तथा आवर्न जैसे शहरों में स्थानीय दल उठ खड़े हुए। श्रमिकों का एक राज्य सम्मेलन बुलाने तथा गवर्नर व ले० गवर्नर पदों के लिए उम्मीदवार खड़े करने की योजना वनाई गई। इस सम्मेलन में अन्त में १३ काउण्टियों के ७८ प्रतिनिधि शामिल हुए लेकिन जब प्रतिद्वन्द्वी प्रतिनिधि मण्डलों ने सम्मेलन में भाग लिया तो न्यूयार्क शहर में [illegible] वहुत खतरनाक सावित हुई। वागडोर पेशेवर राजनीतिज्ञों ने [illegible] और वे मजदूरों के वोट एक डैमोक्रैटिक उम्मीदवार के समर्थन में [illegible] में कामयाव हुए। 'ऐडवोकेट' चिल्लाया: "मज़दूरों को धोखा

दिया गया है" और कहा कि उसके अनुयायी अपना निजी उम्मीदवार नामज़द करेंगे।

इसके फलस्वरूप जो विभ्रम फैला उसमें १८३० में मज़दूरों के तीन ग्रुपों ने शहर के चुनावों के लिए अपने अलग-अलग उम्मीदवार खड़े किए और गवर्नर पद के लिए प्रतिद्वन्द्वी उमीदवार का समर्थन किया। एकता के बिना श्रमिक पार्टी पेशेवर राजनीतिक प्रभावों और टमानी हाल पेशेवर राजनीतिकों के प्रलोभनों का आसानी से शिकार बन गई और उसका मूल रूप नष्ट हो गया। डैमोक्रेट राज्य का और स्थानीय दोनों चुनाव जीत गये और न्यूयार्क में मज़दूरों के बीच और कोई प्रभावशाली संगठन बनाने का काम ठप्प हो गया। 'वर्किंगमेन्स ऐडवोकेट' ने लिखा "कि अन्ततोगत्वा मज़दूरों के लक्ष्यों की पूर्ति में कोई और चीज इतनी प्रभावशाली रुकावट नहीं बन सकती जितना एक खास आदमी के चुनाव के तात्कालिक उद्देश्य के लिए अन्य पार्टी के साथ सहयोग।" लेकिन मज़दूरों के वोट डैमोक्रैटिक पार्टी की तरफ जा चुके थे।

अगर न्यूयार्क के कारीगरों और मिस्त्रियों का स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाने की कोशिशों का अनुभव अल्पकालिक रहा तो अन्य मज़दूरों की पार्टियों की गतिविधि के बारे में भी यही कहानी कही जा सकती है। अनेक बार, विशेषकर पेंसिलवेनिया और मैसाच्युसेट्स में वे कुछ अरसे के लिए अपने उम्मीदवारों के समर्थन में मज़दूरों के वोट प्राप्त कर सकीं और स्थानीय राजनीति पर महत्वपूर्ण और कभी-कभी निर्णायक असर डाल सकीं। किन्तु जैसा कि न्यूयार्क में हुआ, आन्तरिक संघर्ष और बाहरी दबाव से इनमें भी फूट पड़ गई और ये धीरे-धीरे छिन्न-भिन्न हो गई। स्वयंभू नेताओं ने सुधार के लिये अपने-अपने नुस्खों पर ज़ोर दिया जो कि स्किडमोर, ऐवन्स, ओवन और फैनी राइट के कार्यक्रमों के समान ही प्रायः मज़दूरों के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाते थे। और जब सुधारक खदेड़ दिए गए तब राजनीतिज्ञों ने शीघ्र आकर बागडोर सम्हालने और मज़दूरों के वोट बड़े दलों में से किसी एक के पक्ष में प्राप्त करने की कोशिश की।

मैसाच्युसेट्स में सन् १८३२ में किसानों, मिस्त्रियों और श्रमिकों का न्यू

इंग्लैण्ड ऐसोसियेशन बनाकर श्रमिकों का एक व्यापक राजनीतिक संगठन बनाने का प्रयत्न किया गया। इस ग्रुप ने स्थानीय चुनावों में जो सफलता प्राप्त की उस से प्रेरित होकर इसने गवर्नर पद के लिये अपना उम्मीदवार खड़ा किया लेकिन ऐसोसियेशन शीघ्र ही उस समय के एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के दलदल में फंस गई जिसमें गवर्नर पद के लिए उसके अपने उम्मीदवार ने मज़दूरों से डैमोक्रैटों का समर्थन करने के लिये कहा।

मज़दूरों की पार्टियों की अपनी ही बदौलत विफलताओं के बावजूद जिन सिद्धान्तों के लिए वे लड़े उनमें से बहुत-सों का व्यापक रूप से मान लिया जाना जैक्सनी लोकतन्त्र की ज्यादा बड़ी ताकतों के साथ उनके अन्तिम रूप से विलय की खास बात थी। जैसा कि हमने देखा, दोनों बड़े दल मज़दूरों की नई राजनीतिक शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। किन्तु ह्विगों की अपेक्षा डैमोक्रेट मज़दूरों के उद्देश्यों का ज्यादा खुल्लमखुल्ला समर्थन करते थे। जब जैक्सन ने युनाइटेड स्टेट्स बैंक के खिलाफ अपना संघर्ष छेड़ा और अनेक मोर्चों पर एकाधिपत्य तथा विशेषाधिकार पर जोरदार प्रहार किये तब कारीगर, मिस्त्री और मज़दूर स्वभावतः उसके साथ हो गये। यद्यपि मज़दूरों ने समग्र दृष्टि से किसी एक दल को कभी वोट नहीं दिया तो भी सन् १८३२ में उन्होंने सामान्यतः एकाधिपत्य के दुश्मन और अवाम के मित्र के रूप में जैक्सन का स्वागत किया।

टोरियों ने उन शब्दों में अपनी चेतावनी दी जो बाद में एक सदी बाद एक अन्य ज़माने में, जब वर्ग संघर्ष ज्यादा तीव्र था, एक राष्ट्रपतीय चुनाव में दोहराये गए। एक फैक्ट्री मालिक ने अपने कर्मचारियों से कहा—"जैक्सन को चुनो और तुम्हारी सड़कों पर घास उगेगी, मिलों में उल्लू अपना घोंसला बनाएंगे और लोमड़ियां सड़कों में अपनी मांद बनाएंगी।" किन्तु फिर भी मज़दूरों ने उसे जिताने में मदद की। न्यूयार्क में वे यह गीत गाते हुए वोट डालने गए :

मिस्त्रियों, गाड़ी वानों, मज़दूरों को
एक निकट संबन्ध बनाना चाहिए
और अमीर संभ्रान्त लोगों को इस

चुनाव में अपनी ताकत दिखानी चाहिए।
याँकी डूडल, अभिमानी बैंक
मालिकों को निकाल बाहर करो
सिर्फ़ हार्टफोर्ड फेड्स जैसे लोग
ही गरीबों और जैक्सन का विरोध करते हैं।

१८३० के दशक में राजनीतिक मोड़ और करवटें एक अलग चीज हैं किन्तु प्रगतिशील सिद्धान्तों का निरन्तर विकास और उन सुधारों की वास्तविक प्राप्ति जिन्हें मजदूर चाहते थे, बिल्कुल अलग चीज है। श्रमिक दलों के मूल उद्देश्यों का आम समर्थन जैसे-जैसे ज़ोर पकड़ता गया और समाज के उदार वर्गों ने सामान्यतः उसका पक्षपोषण किया वैसे-वैसे उन मांगों की पूर्ति में जो पहले मजदूर-अखबारों की मोटी-मोटी सुर्खियों में रखी गई थीं, निरन्तर प्रगति हुई।

पहली माँग शिक्षा में सुधार की थी। श्रमिकों के हर अखबार के सम्पादकीय स्तम्भ के शीर्ष पर जो माँग रखी गई और जिस पर न्यूयार्क के आन्दोलन में भी बहुत बल दिया गया था वह थी—"समान सार्वभौम शिक्षा" जिन बच्चों के माँ-बाप निजी संस्थाओं का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे उनकी आवश्यकताओं पर अब तक बहुत अस्पष्ट ध्यान दिया जा रहा था। टैक्स से चलाए जाने वाले स्कूलों में न्यू इंग्लैण्ड शेष देश से आगे था किन्तु न्यूयार्क, न्यूजर्सी, पेंसिलवेनिया और डेलावेयर जैसे धनी आबादी वाले और समृद्ध राज्यों में भी (पश्चिम में नए राज्यों तथा दक्षिण के पिछड़े हुए राज्यों के बारे में तो कहा ही क्या जाए) श्रमिकों व अन्य गरीब परिवारों के बच्चों के लिए सिर्फ खैराती स्कूल की व्यवस्था थी, जो अपर्याप्त, अकुशल और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति को गिराने वाली थी। १८२९ में पब्लिक स्कूल सोसाइटी ने एक रिपोर्ट में बताया कि न्यूयार्क में ५ से १५ वर्ष के बीच की आयु के ऐसे २४००० बच्चे हैं जो स्कूल बिल्कुल गए ही नहीं और करीब इतने ही बच्चे खैराती तथा निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। कुछ वर्ष बाद पेंसिलवेनिया में एक विस्तृत रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य के ४ लाख बच्चों में से २॥ लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। समस्त देश में १० लाख से अधिक बच्चे स्कूल नहीं

जा रहे थे और इसी अनुपात में पूर्ण निरक्षरता भी व्याप्त थी।

जैसा कि इन आँकड़ों से पता चलता है, शिक्षा के लिए अवसरों की कमी और पब्लिक स्कूलों के साथ, क्योंकि वे खैराती स्कूल थे, जुड़ी हीनता दोनों पर श्रमिक क्रुद्ध थे। रावर्ट डेल ओवन तथा फ्रांसिस राइट के सब सिद्धान्तों को अपनाये बिना ही वे सब उससे इस बात में सहमत थे कि मुफ्त, लोकतंत्रीय शिक्षा पर बल दिया जाए जो अमीर और गरीब सब के बच्चों को पूर्ण समानता के आधार पर उपलब्ध हो। श्रमिकों ने अपनी इस मांग का आधार स्वाधीनता की घोषणा में निहित समान अधिकारों की विचारधारा को बनाया और इस युक्ति से उसकी पुख्ता किलेबन्दी की कि सब बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वे समझदारी के साथ वोट दे सकें। शिक्षा में अमरीकियों की इस पीढ़ी से ज्यादा विश्वास कभी भी किसी जनसमूह का नहीं रहा जो शिक्षा को "मानव जाति को दिया गया महत्तम वरदान" समझते थे। अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की माँग करने में मज़दूर इससे ज्यादा दृढ़-निश्चयी नहीं हो सकते थे।

फिलाडेल्फिया में श्रमिकों के ग्रुप की एक खास रिपोर्ट में कहा गया है: "इसलिये समितियों को लगा कि वास्तविक बुद्धिमत्ता के व्यापक प्रसार के बिना स्वाधीनता नहीं रह सकती; एक गणराज्य के सदस्यों को मानव और नागरिक के नाते अपने समान अधिकारों और कर्त्तव्यों के स्वरूप के बारे में एक-सी शिक्षा मिलनी चाहिए..." इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि केवल पब्लिक स्कूलों की एक प्रभावशाली प्रणाली ही बच्चों को अल्पायु में समाज के घातक प्रभावों के प्रलोभनों से बचा सकती है और 'इस प्रकार सुधार-गृहों के लिए काफी 'मसाला' प्रदान कर सकती है या असहिष्णुता का शिकार बन सकती है जो "निजी शान्ति और सार्वजनिक गुण" को नष्ट कर डालता है। लेकिन शिक्षा के महत्व पर जोर प्रायः यही कह कर दिया गया। यह उस लोकतन्त्रीय सरकार का, जिसका अमरीका एक नमूना है, आधार ही है। १८२९ में न्यूयार्क की पुनर्गठित श्रमिक पार्टी ने उस शिक्षा-प्रणाली की

रखी" जो गरीब और अमीर और विधवा के बच्चों तथा यतीम बच्चों ही छत के नीचे एकत्र कर दे और जहाँ भेद का आधार वंश या कुल अपितु अधिक मेहनत, गुण और सफलताएँ हों।"

इस विषय में राय अलग-अलग थी कि शिक्षा किस प्रकार की दी जानी चाहिए। लेकिन अधिकांश मामलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण और कला-विषयों दोनों के महत्व पर बल दिया गया। फिलाडेल्फिया के श्रमिकों की एक और रिपोर्ट में अनुरोध किया गया कि सार्वजनिक संस्थाएँ "ऐसे स्थानों पर होनी चाहिएँ, जिनमें स्वास्थ्य अच्छा रहे, यन्त्र-विद्या, कला-विषयों अथवा कृषि का अच्छा अभ्यास हो और साथ ही प्राकृतिक विज्ञानों और अन्य उपयोगी साहित्य का ज्ञान कराया जाए।"

इस शिक्षा-आन्दोलन को मज़दूरों के अलावा अन्य वर्गों का भी सहयोग प्राप्त था। बहुत-से सुधारकों ने यह काम अपने हाथ में लिया और उस पर उत्तरोत्तर ज़्यादा ध्यान दिया गया। साथ ही टोरियों ने इसका चिरकाल तक विरोध किया जो यह समझते थे कि पढ़ाई का लाभ कुछ ही लोगों तक सीमित रहना चाहिए और गरीबों की शिक्षा के लिए अमीरों पर टैक्स लगाना सर्वथा अनुपयुक्त है। 'नेशनल गज़ट' ने कहा: "अगर व्यापार, कारखाने चलाने हैं और मज़दूरों से ठीक तरह काम लेना है तो सार्वभौम समान शिक्षा तब तक असम्भव है. जब तक शिक्षा का स्तर बहुत गिराया न जाए और उसका दायरा तंग न किया जाये।"

तो भी समान, लोकतंत्रीय, वैज्ञानिक व्यावहारिक शिक्षा के लिए ज़ोरों से चलाया गया यह आन्दोलन फलीभूत होने लगा। राज्यों के विधानमंडल इस विषय पर पहले किसी भी समय की अपेक्षा ज़्यादा गम्भीरता से ध्यान देने लगे और शनैः-शनैः नए कानून बनाए गए, जिनमें पहले स्थानीय नगरपालिकाओं को सार्वजनिक शिक्षा के लिए टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया और बाद में उन्हें यह टैक्स लगाने की हिदायत की गई। घटनाचक्र में यह मोड़ शायद तब आया जब पेंसिलवेनिया ने, जहाँ मज़दूर इतने सक्रिय थे, अन्त में १८३४ में एक मुफ्त और टैक्स समर्थित प्रणाली अपनाई। इस कार्य-क्रम वाला बिल हारते-हारते बचा। एक विरोध-याचिका पर कार्रवाई करते हुए जिस पर ३२००० हस्ताक्षर थे, सीनेट ने "गरीबों की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने वाली" एक धारा को बदलने की कोशिश की। किन्तु समानता के आधार पर सब के लिये मुफ्त पब्लिक स्कूल प्रणाली का सिद्धान्त आखिर विजयी हुआ। अन्य राज्यों ने भी इस का अनुकरण किया और अन्त में वह

विजय प्राप्त हुई जिसके लिए मज़दूरों ने इतने लम्बे अरसे तक संघर्ष किया था।

एक और मामला जिसके लिये मज़दूरों ने इस काल में बहादुरी और सफलता के साथ संघर्ष किया, कर्जदारी के लिए कैद की व्यवस्था की समाप्ति थी। कोई आदमी जब अपने आर्थिक दायित्वों को पूरा न कर सके तब उसे जेल के सींकचों में बन्द कर देने की पुरानी परिपाटी १८२० के दशक में भी लगभग सभी जगह चल रही थी। दशक के अन्त में बोस्टन जेल अनुशासन सोसइटी ने अनुमान लगाया कि प्रतिवर्ष कर्जदारी के लिए कोई ७५००० आदमी जेलों में बन्द किए जा रहे हैं और कम-से-कम इनमें से आधे मामले २५ डालर से कम कर्ज़ के थे। एक मामले में तो एक महिला को ३.६० डालर कर्ज के लिये अपने घर तथा अपने दो बच्चों की देख-भाल से अलग घसीट कर जेल में डाल दिया गया। एक दूसरे मामले में एक व्यक्ति को पंसारी का ५ डालर बकाया होने पर जेल भेज दिया गया यद्यपि यह कर्ज तब चढ़ा था जब वह व्यक्ति बीमार था। एक जेल में ३२ व्यक्ति ऐसे पाये गए जिन्हें १ डालर से भी कम कर्ज़ के अभियोग में कैद किया गया था।

स्पष्ट ही इस प्रणाली का गरीबों पर बहुत बुरा असर पड़ा और इसके अन्याय ने गहरा घाव किया। मज़दूरों के एक राजनीतिक उम्मीदवार ने कहा कि "जो कानून गरीबी को अपराध मानता है, जबकि इन्हीं कानूनों ने गरीबी को अनिवार्य बना दिया है और गरीब को शैतान, वह न केवल क्रूर और आततायी है, बल्कि बेहूदा और विद्रोहजनक है।" परिस्थितियों की इन तकलीफों के साथ-साथ कर्जदारों की जेलों में अत्यन्त भीड़ रहती थी और वह अस्वास्थ्यकर थी। उनमें कैदियों को भोजन देने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी और वे सब-के-सब प्रायः खैरात पर जिन्दा रहते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूजर्सी में अपराधियों के लिए तो "खाना, बिस्तर और ईंधन था।" किन्तु कर्जदारों के लिये सिर्फ "दीवारें, सींकचे और कुण्डे" ही थे।

यह सुधार बहुत पहले हो जाना चाहिये था किन्तु फिर भी व्यापारी-वर्ग ...सक विरोध किया। जौन क्विन्सी ऐडम्स भी यह कहने के लिए मजबूर ... कि कर्ज़दारी के लिये कैद की व्यवस्था के खात्मे से सम्पत्ति को सुरक्षा

और करार की पवित्रता पर खतरनाक असर पड़ेगा। व्यापारी और वकील इस प्रकार की धारणाओं को ज्यादा महत्व देते थे बजाय इस चीज के जिसे राष्ट्रपति जैक्सन ने "दुर्भाग्य और गरीबी पर पीस देने वाली ताकत आजमाने" का अन्याय कहा था।

मज़दूरों के आन्दोलन की बदौलत पहले ऐसे कानून पास हुए जिनसे ग़रीब कर्जदार दिवालिया होने की कसम खाकर छुटकारा पा सकता था और बाद में उस रकम की मात्रा निश्चित कर दी गई जिसे न चुकाने पर उसे जेल में डाला जा सकता था। लेकिन शीघ्र ही एक के बाद एक सभी राज्यों को इस प्रणाली को बिल्कुल खत्म कर देने का अपरिहार्य तर्क स्वीकार करना पड़ा। ओहायो ने यह कदम सन् १९२८ में उठाया और उसके बाद एक दशक में ही न्यूयार्क, न्यूजर्सी, कनेक्टिकट, वर्जीनिया, तथा अन्य राज्यों ने उसका अनुकरण किया। यह परिपाटी देश के कुछ हिस्सों में बनी रही लेकिन १८३० के दशक की समाप्ति तक इसका बिल्कुल खात्मा दिखाई देने लगा था।

मिलीशिया प्रणाली पर प्रहार भी, जो ज्यादातर श्रमिकों की पार्टियाँ किया करती थीं, सफल रहा। अधिकांश राज्यों में तीन दिन की वार्षिक कवायद और परेड में हर नागरिक का भाग लेना लाज़िमी था। उनको इसका सारा खर्चा खुद करना होता था और साज-सामान भी स्वयं ही जुटाना पड़ता था। तिस पर भी अगर कोई इस परेड में शामिल नहीं होता था तो उस पर जुर्माना किया जाता या उसे जेल की हवा खानी पड़ती थी। श्रमिकों के लिए इस नियम का परिपालन न केवल मज़दूरी का नुकसान करना था, बल्कि उनका बहुत खर्चा भी होता था। दूसरी ओर अमीर लोग बिना किसी कठिनाई के उतना ही जुर्माना देकर आसानी से अपने इस उत्तरदायित्व से बच जाते थे। १८३० के बाद इस अनिवार्य सेवा में या तो सुधार कर दिया गया या वह बिल्कुल ही समाप्त कर दी गई। राष्ट्रपति जैक्सन ने १८३२ में अपने वार्षिक सन्देश में इस प्रश्न की ओर ध्यान खींचा और यह अनुरोध किया कि यह प्रणाली जहां कहीं भी प्रचलित है, जैसे कि न्यूयार्क में वहां इसकी असमानताओं की सावधानी से जांच की जानी चाहिए।

श्रमिकों की पार्टियों का उद्भव किसी वर्ग-आन्दोलन का प्रतीक बिल्कुल नहीं था और यह पूर्ण रूप से एक मज़दूर आन्दोलन भी नहीं था। मज़दूरों की

सामाजिक स्थिति में जो परिवर्तन हो रहे थे उससे वे चक्कर में पड़ गए और हक्के-बक्के रह गए थे और उन्होंने किसी-न-किसी प्रकार उत्पादक और उसके श्रम के सुफल पर जीने वाले के बीच अधिक समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया।

उनका आन्दोलन जब सिद्धान्तवादी सुधारकों और पेशेवर राजनीतिज्ञों के हाथ गया तो वे महसूस करने लगे कि राजनीति में उनका प्रवेश बिल्कुल फजूल है। समानता का महान और सुदूर लक्ष्य चमचमाती मृगतृष्णा-सा प्रतीत हुआ। शनैः-शनैः वे ज्यादा व्यावहारिक लक्ष्यों की ओर लौट आए। ये थे अधिक वेतन और काम के कम घण्टे जिनकी उनके राजनीति के चक्कर में पड़ने के बाद उपेक्षा हो रही थी। आम मज़दूर यह अनुमान करने लगे कि इन तात्कालिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक कार्रवाइयों से अपने जीवन-स्तर को कायम रख सकना उनके लिए ज्यादा संभव है।[1] फ़िलाडेल्फिया के 'नेशनल लेबरर' ने इस नए रुख को अभिव्यक्त करते हुए लिखा : "मज़दूर यूनियनें राजनीतिक कभी नहीं बनेंगी क्योंकि इसके सदस्यों ने अनुभव से यह सीख लिया है कि उनकी संस्थाओं में राजनीति के समावेश ने उनकी अवस्थाओं में सुधार के हर प्रयत्न को बेकार कर दिया है।"

मूल श्रमिक दलों ने जो सामाजिक लाभ प्राप्त किए थे वे इस जोरदार वक्तव्य का कम से कम आंशिक रूप में खण्डन करते हैं। तो भी मज़दूर सारी १९ वीं सदी में दलीय संघर्षों में कभी प्रभावशाली राजनीतिक संगठन नहीं बना सके। जब बाद में एक राष्ट्रीय-दल स्थापित करने की कोशिश की गई तो वह बिल्कुल विफल रही। १८३० के दशक का अनुभव इस चीज का पहला साक्षी है कि मज़दूरों के लिए अलग दल बनाने का कोई वास्तविक आधार नहीं था इसके उद्देश्य मोटे तौर पर उदार थे और जब कभी भी मजदूर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से पर्याप्त दबाव डाल सके तभी बड़े दलों ने उन्हें अपना लिया। न्यूयार्क की श्रमिक पार्टी का अपने मूल नेताओं के उग्र कृषि-वाद के साथ घनिष्ठता का नाता अल्पकालीन ही रहा। मज़दूरों के अपने विचार ही बुनियादी तौर पर पौराणिक थे और जो समानता वे चाहते थे उसे वे देश के मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के भीतर ही चाहते थे। उद्भूत

होते हुए पूंजीवाद को नष्ट करने के बजाय उसके लाभों में वे हिस्सा बंटाना चाहते थे। फैनी राइट वर्ग संघर्ष पर धुआँधार भाषण दे सकती थी लेकिन इस प्रकार की भावनाएं स्वयं मज़दूरों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं।

मज़दूरों को एकजूट रखने के लिए कोई एक सिद्धान्त उपलब्ध नहीं था। यूरोप में अपने समकालीन मज़दूरों की तरह मताधिकार प्राप्त करने के लिए मिल-जुल कर राजनीतिक कार्रवाई करने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि १८२० के दशक में लोकतंत्री सिद्धान्तों की राष्ट्र-व्यापी जीत के एक अंग के रूप में वे मताधिकार पहले ही प्राप्त कर चुके थे। न ही वे इंग्लैण्ड और यूरोप के मज़दूरों की तरह समाजवाद के झण्डे तले एकत्र हो सकते थे। अमरीकी मज़दूरों के हित सामान्य लोगों के हित के साथ इतने अधिक जुड़े हुए थे कि उन्हें अलग से अपना तीसरा राजनीतिक दल बनाने के लिए कोई आधार नहीं मिल सकता था। विकसित होते हुए अर्थतंत्र ने, भिन्न-भिन्न वर्गों के निरन्तर मेल-जोल ने और सीमान्त के व्यक्तिवाद ने उन रास्तों का निर्माण किया जिनके साथ-साथ यूरोप की स्थिति से बिल्कुल विपरीत अमरीका के मज़दूर आन्दोलन का विकास होना था।

१८३० के दशक की मज़दूर पार्टियों से अगर कुछ समय के लिए एक मज़दूर दल बनता दिखाई भी दिया तो भी जैक्सनी लोकतंत्र की आम प्रगति में उनके सन्निवेश से इस प्रकार का रुझान बिल्कुल उलट गया।

—:o:—

४ : १८३० के दशक में मज़दूरों की ताकत

मज़दूरों की शुरू-शुरू की पार्टियां अल्पकाल में ही बनीं और खत्म हो गईं। उनके राजनीतिक प्रभाव के बारे में कुछ भी दावा किया जाए, अलग राजनीतिक संगठनों के रूप में उनका अस्तित्व इतना क्षण-स्थायी था कि श्रमिक आन्दोलन के इतिहास में उन्हें कोई बड़ा स्थान नहीं मिल सकता। मज़दूर सोसाइटियों का फिर से आर्थिक कार्रवाइयां करने लगना कई प्रकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण घटना थी। इन वर्षों में, विशेषकर १८३३ से लेकर १८३७ तक जैक्सन के दूसरे शासन काल में जब समस्त देश में सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में काफी प्रगति की जा रही थी तब यूनियन सम्बन्धी गति-विधियां इतनी व्यापक तथा उग्र थीं कि उतनी आगे कई दशाब्दियों तक नहीं हुईं।

जैसा कि राजनीति में मजदूरों के प्रवेश ने जाहिर कर दिया था, बदलती हुई सामाजिक परिस्थिति में वे अपनी अवमानना की भावना अनुभव करते रहे। पुनरुज्जीवित ट्रेड यूनियनों का मुख्य कार्य वेतन और काम के घण्टे ही रह गया लेकिन उनमें समाज में अपनी हैसियत फिर से पाने की सदस्यों की लालसा भी प्रतिक्षिप्त होती थी। जिस समाज को वे जानते थे, वह चूंकि भंग होता दिखाई दे रहा था और जो कारीगर कभी स्वतंत्र थे वे सिर्फ मज़दूरी कमाने वाले बनते जा रहे थे इसलिए कारीगरों और मिस्त्रियों ने पहले से भी ज्यादा इस बात की आशा रखी कि यूनियनों के सदस्य बन कर वे श्रम की प्रतिष्ठा को फिर से कायम कर सकेंगे और अपने सामाजिक तथा आर्थिक महत्व के प्रति समाज को अधिक सजग कर सकेंगे।

१८३४ में एक मजदूर नेता ने लिखा कि "मालिक और कर्मचारी के बीच भेदभाव की रेखा जैसे-जैसे चौड़ी होती गई वैसे-वैसे कर्मचारी की हालत अनिवार्य रूप से एक गुलाम की सी होती चली गई जो समाज के सर्वोत्तम हितों और हमारी सरकार की प्रकृति के खिलाफ थी।" मजदूर सोसाइटियों ने मज़दूरों में एकता पैदा करके, जो उनकी मालिकों की पूर्ण और निःसहाय

गुलामी से रक्षा करती, इस रुख का मुकाबला करने की कोशिश की।

१८३० के दशक के प्रारम्भ की अवस्था यूनियनों के विकास के लिए आशाजनक थी। एक तरफ तो बढ़ती हुई समृद्धि ने मजदूरों की सौदेबाजी की ताकत को मजबूत किया और दूसरी ओर बढ़ती हुई कीमतों में मालिकों द्वारा वेतन कम रखने की कोशिश किए जाने से वे आत्मरक्षा के लिए संगठित होने को मजबूर हो गए। न केवल सभी वर्गों के श्रमिकों में मजदूर सोसाइटियों की संख्या तेजी से बढ़ी बल्कि इन स्थानीय यूनियनों का नगर-व्यापी संघ बनाने की और कोशिशें की गई जिससे मजदूरों की एकता और ज्यादा मजबूत हो। इतना ही नहीं इससे भी ज्यादा व्यापक एक संगठन बनाने का यत्न किया गया जो एक सच्चे राष्ट्रीय-मजदूर आन्दोलन की स्थापना की पूर्व-छाया था। इसके अलावा इन यूनियनों के सदस्यों के उग्र रवैये के कारण हड़तालें हुई जिन्हें अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए मजदूरों के लम्बे संघर्ष का नाटकीय अध्याय कहा जाता है।

यह गतिविधि इतनी सामान्य हो गई कि कोई भी कारोबार इसकी व्यापक रूप से फैलने वाली उग्रता से बच नहीं सका। अप्रैल १८३६ में न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा : "नाइयों ने हड़ताल कर दी है। अब सिर्फ सम्पादकों को हड़ताल करना बाकी रह गया है।"

शांतिकाल में रहन-सहन का खर्चा पहले कभी इतनी तेजी से नहीं बढ़ा था, जितनी तेजी से १८३० के दशक के प्रारम्भिक काल में जबकि सट्टेबाजी और मुद्रास्फार का जोर था। बैंकों से ऋण आसान शर्तों पर मिल जाने और नोटों के फैलाव से, जो यूनाइटेड स्टेट्स बैंक पर राष्ट्रपति जैक्सन के सफल प्रहारों का तात्कालिक परिणाम था, सब तरफ कीमतें चढ़ गईं। न्यूयार्क में आटे का मूल्य १८३४ में ५ डालर का एक पीपे के बजाय अप्रैल १८३५ में ८ डालर का एक पीपा और एक वर्ष बाद १२ डालर का एक पीपा हो गया। अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें भी इसी प्रकार चढ़ीं। कपड़ों और घर के सामान की कीमतों में असाधारण वृद्धि हुई और किराये २५ से ४० प्रतिशत तक बढ़ गए। यह आम अनुमान था कि १८३४ और १८३६ के बीच रहन-सहन का खर्चा कोई ६६ प्रतिशत बढ़ गया।

ऊँचाई की ओर कीमतों के इस अभियान में वेतन निश्चित रूप से पीछे रह गए और मालिकों ने अपने माल की लागत कम रखने के लिये जो और कदम उठाए उनसे मजदूरों के जीवन स्तर पर और ज्यादा बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ। अनेक धन्धों में अप्रैण्टिसशिप प्रणाली का वस्तुतः खात्मा हो जाने से युवा अर्ध-प्रशिक्षित लड़के प्रशिक्षित दिहाड़ियों को दिए जाने वाले वेतन दर से आधी दर पर रख लिए गए। पुरुषों की जगह स्त्रियां कम वेतन पर रखी गईं। ये ज्यादातर दर्जीगीरी, सिलाई, और जूते गांठनेके काम पर लगाई गई (उस वक्त के अनुमान के अनुसार इन कामों में लगे २० हजार मज़दूरों में से १२००० को सप्ताह में १.२५ डालर से ज्यादा नहीं मिलता था)। किन्तु उनसे मुद्रकों, सिगार बनाने वालों और अन्य कर्मचारियों के लिए भी नई प्रतियोगिता खड़ी हो गई। १८३६ में फिलाडेलफिया कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि "५८ सोसाइटियों में से २४ पर स्त्री-मज़दूरों का गम्भीर प्रभाव पड़ा है जिससे पूरे के पूरे परिवार गरीब हो गए हैं और जिससे मलिकों के सिवा किसी को लाभ नहीं हुआ।" अन्त में जेल में बन्द मज़दूरों का व्यापक रूप से आश्रय लिया गया। मिस्त्रियों और कारीगरों ने कटुता से शिकायत की कि ठेके जेलों को देने की इस बढ़ती हुई प्रवृति से सजायाफ्ताओं को कुछ भी लाभ हुआ हो, "चीजें उस दाम से, जिस पर कोई ईमानदार मिस्त्री अपना और अपने परिवारा का गुज़ारा कर सकता है, ४० से ६० प्रतिशत तक नीचे चली गई हैं।"

इन परिस्थितियों में शायद ही कोई ऐसा शहर रहा हो जिसमें मज़दूरों ने अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित रूप से कार्रवाई न की हो। फिलाडेल्फिया में जूता बनाने वालों ने अपना फिर से संगठन किया; जुलाहों ने एक नई सोसाइटी बनाई और ईंटें चिनने वालों, नल का काम करने वालों लुहारों, सिगार-निर्माताओं, कंघे बनाने वालों, जीन साजों तथा अन्य धन्धे करने वालों ने अपनी यूनियनें बनाईं। न्यूयार्क की पुरानी सोसाइटियों में फिर से जीवन स्पन्दित हो उठा। छापेखाने के मज़दूरों, जूता बनाने वालों, और दर्जियों ने एक बार फिर नेतृत्व सम्हाला और फर्निचर, हैट तथा टोकरियां बन ने वाले, ताला बनाने वाले, पिआनो बनाने वाले और रेशमी टोप बनाने वाले यूनियनों में शामिल हुए। वाल्टीमोर के संगठनों में जूता बानाने वाले,

पत्थर तराशने वाले, टीन के डिब्बे बनाने वाले, गलीचे बनाने वाले और गाड़ियां बनाने वाले शामिल हुए। अटलाण्टिक तट के किसी भी शहर के बारे में उत्तर के न्यूयार्क, वाशिंगटन, पिट्सबर्ग और लुइसविल राज्यों के बारे में तथा पश्चिम के अन्य निर्माण केन्द्रों के बारे में भी यही कहानी कही जा सकती है।

परम्परागत मिस्त्रियों तथा कारीगरों के अतिरिक्त और श्रमिकों में संगठन कम से कम कुछ प्रगति कर रहा था। अब तक मैसाच्युसेट्स और रहोड आइलैण्ड में तेज़ी से विकसित होते हुए कपड़ा उद्योग स्थापित हो चुके थे, कनेक्टिकट के कारखाने हाथ की और दीवार की घड़ियां बना रहे थे और पेंसिलवेनिया में लोहे की फाउण्ड्रियां बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास की पूर्व-भूमिका थीं। इन संस्थानों में सामान्य कर्मचारियों के अलावा मशीन-चालक, इंजन चालक, माल ढोने वाले, नावों पर काम करने वाले फायरमैन, स्टेज ड्राइवर, सड़कों पर और नहरों के पुलों पर गेटकीपरों का काम करने वाले मज़दूरों के नए वर्ग बन गए थे। ये मज़दूर जहां अब भी ज्यादातर असंगठित थे, वहां सूती कपड़ों के कारखानों के, टिनप्लेट तथा लोहे की चद्दरें बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों तथा अन्य समूहों के कर्मचारियों की अग्रगामी यूनियनों को अधिकाधिक सहयोग मिल रहा था।

स्त्रियों को भी, उनकी अपनी मज़दूर सोसाइटियां बनाकर मज़दूर आन्दोलन में लाया गया। बाल्टीमोर में एक युनाइटेड सीमस्ट्रेस सोसाइटी, न्यूयार्क में लेडीज़ शू-बाइण्डर्स ऐण्ड फिमेल बुकबाइण्डर्स सोसाइटी तथा फिमेल यूनियन ऐसोसियेशन और फिलाडेल्फिया में फिमेल इम्प्रूवमेण्ट सोसाइटी बनी। न्यू इंग्लैण्ड की कपड़ा मिलों में महिला कर्मचारियों में संगठित गतिविधि के एक प्रारम्भिक चिन्ह के रूप में १८३८ में स्त्री-उद्योगों की रक्षा और विकास के लिए लिन और विसिनिटी की फिमेल सोसाइटी और एक वर्ष बाद फैक्ट्री गर्ल्स ऐसोसियेशन बना।

इस काल में न्यूयार्क में मज़दूर सोसाइटियों का क्या रूप था, इसकी चित्रमय झाँकी उस शहर में हुए एक प्रदर्शन के विवरण में मिलती प्रदर्शन १८३० में फ्राँसीसी राज्यक्राँति की सफलता के उपलक्ष्य में किया गया था। यद्यपि प्रदर्शन का नियन्त्रण पेशेवर राजनीतिज्ञों

हाथ में ले लिया था तो भी मजदूर इस पर हावी थे। एक परेड में, जिसकी लम्बाई करीब तीन मील थी, और जिसे लगभग ३० हज़ार आदमियों की भीड़ ने आनन्दमग्न होकर देखा, मज़दूरों के प्रतिनिधि मण्डलों की उपस्थिति सबसे प्रमुख थी।

खूब मेहनत से बनाई गई झाँकियाँ, जैसा कि 'वर्किंगमेंस एडवोकेट' ने लिखा, उस दिन का विशेष आकर्षण थीं। मुद्रकों के दो प्रेस थे, जो उन्होंने मैसर्स रस्ट ऐण्ड हो से उधार लिए थे। इनको उन्होंने खूब सजाया और चमकाया था और चार घोड़ों वाली दो अलग-अलग बग्घियों पर उन्हें रखा था। चुस्त, उछलते-कूदते घोड़ों पर चढ़े हुए कसाई भी अपने व्यवसाय के लायक खास पोशाकों में प्रदर्शन में उपस्थित थे। उनकी एक गाड़ी पर एक बैल की खाल में भुस इस चतुराई से भरा गया था कि वह बिल्कुल जीवित प्रतीत होता था और उसे फीतों और फूलों से खूब अच्छे ढंग से सजाया गया था। एक अन्य गाड़ी पर कसाई की दुकान बनाइ गई थी जिसमें "कीमा तैयार किया जा रहा था और उससे दर्शकों का बड़ा मनोरंजन हो रहा था।"

जूता बनाने वालों ने प्रदर्शन के लिए व्यापक पैमाने पर और शानदार ढंग से तैयारी की थी। उनकी एक गाड़ी पर दो नवयुवतियाँ जूते गाँठ रही थीं। भाप के इंजन बनाने वालों ने एक पूरे आकार के इंजन का प्रदर्शन किया ("पाइपों से आनेवाला धुआं ऊपर उठ रहा था, पानी के पहिये घूम रहे थे") और फर्निचर बनाने वालों ने इतना बढ़िया फर्निचर दिखाया था कि एडवोकेट के रिपोर्टर ने उसकी खूबियों का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाया। संगतराश और मुलमची (मुलम्मा चढ़ाने वाले) जैफर्सन और लफायेट के सुन्दर सुनहरे फ्रेमों वाले चित्र लिए जलूस में चल रहे थे। तम्बाकू वाले बीड़ी-सिगरेट बांट रहे थे और भीड़ से वाह-वाह लूट रहे थे। जीन, साज और कवच बनाने वालों ने भी अपनी गाड़ियों पर अपनी बनाई हुई चीजें खूब सजा रखी थीं। जिल्दसाजों ने एक विशाल पुस्तक की झाँकी बनाई जिसे चार मजबूत घोड़े खींच रहे थे और कुर्सी बनाने वालों ने बड़े नद र ढंग से रास्ते में एक "ग्रीशियन पोस्ट मेपल चेयर" बना रखी थी।

हंसी-खुशी के नारों, दोलायमान झण्डों, तिरंगे फीतों और सितारों से सजे झण्डों की वजह से यह जलूस बड़ा भव्य बन गया था। सलामी मंच के आस-

पास विशाल भीड़ में से कुछ को ही जगह दी जा सकी थी। आदरणीय भूतपूर्व राष्ट्रपति मोनरो इस स्थान पर तब तक सम्मानित अथिति के रूप में रहे जब तक "वायुमण्डल की शीतलता" ने उन्हें वहाँ से हटने के लिए मजबूर नहीं कर दिया। इस अवसर पर जोशीले भाषण हुए और मुद्रक सेम्युअल वुडवर्थ द्वारा लिखा गया एक गीत मार्सलेज की धुन में पार्क थियेटर के आर्केस्टा के साथ इस प्रकार गाया गया :

पवित्र आदेश का स्वागत करने के लिये
सामूहिक गीत ज़ोर से गाओ।
मुदित हो, मुदित हो, प्रेस का प्रभुत्व होगा
और सारा संसार आज़ाद होगा।

उस रात विभिन्न सोसाइटियों ने स्मृति-भोज दिए (नवे वार्ड के रहमदिल प्रतिनिधियों ने कर्जदारों की जेल में बन्द कैदियों को भोजन भेजा गया) और श्रमिकों का विशाल समुदाय मेसोनिक हाल में एकत्र हुआ। "मानसिक भोजन के आस्वादन" की पूर्व भूमिका के रूप में बढ़िया भोज हो चुकने के बाद फ्राँसीसी क्राँतिकारी आन्दोलन और उसमें मज़दूरों के योग पर एक जोशीला व प्रशंसात्मक भाषण दिया गया।

उस शाम के वक्ता ने अपने व्याख्यान को समाप्त करते हुए आह्वान किया : "मिस्त्रियो और मज़दूरो, मानसिक स्वाधीनता के अपने गौरवमय अध्यवसाय में आगे बढ़ो; समान शिक्षा तुम्हारा ध्रुवतारा हो और यूनियन और दृढ़ता तुम्हारा आधार स्तम्भ; वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे इन सत्प्रयत्नों को विजयश्री प्राप्त होगी और तुम्हारा देश फैशन के कीड़े और पार्टी के घृणित कीड़े से मुक्त होगा और उसके स्थान पर विशुद्ध समानतावाद का वृक्ष उगेगा और वह अधिकारों की वास्तविक समानता के बढ़िया फल प्रदान करेगा। तब आदमी की परख उसके वचन से नहीं काम से होगी; एक मेहनती नागरिक के रूप में समाज के लिए उसकी उपयोगिता से होगी; इस बात से नहीं कि वह कितना बढ़िया कपड़ा पहनता है।"

भाषण के बाद जामों का सिलसिला चला। बीच-बीच में उपयुक्त गीतों

और कथाओं के साथ-साथ १४ औपचारिक और ३१ ऐच्छिक जाम पिए गए। भोज में शामिल होने वाले उत्साही लोगों ने पेरिस के श्रमिकों और न्यूयार्क के श्रमिकों के कल्याण के लिए जाम पीए। जैफर्सन और लफायेट, बोलीवर, सच्चे डैमोक्रैटों, सार्वभौम शिक्षा और मुक्त जांच के लिए जाम पीए गए।" मूल श्रमिकों के लिए इस कामना के साथ जाम पीए गए, कि वे दाएं या बाएं न झुक जाएं" साइमन प्योर्स के लिए भी इस कामना के साथ जाम पिए गए कि फैंनी राइटवाद, कृपकवाद या अन्य किसी वाद के नारों से वे भयभीत न हों, बल्कि सच्चे समानतावाद पर दृढ़ रहें।"

कुल ४५ बार जाम पीए गए और श्रमिक हर्षित होते रहे। 'वर्किंगमेंस ऐडवोकेट' अन्त में लिखता है कि अत्यधिक प्रसन्नता और एकता शाम के आयोजनों की विशेषता थी और यह मजमा भोर तक चला और जिस प्रकार उसका मनोरंजन किया गया, उससे वह सन्तुष्ट था।

मज़दूर सोसाइटियों का तेजी से विकास होने से अपने समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनमें स्वभावतः निकट सम्बन्ध स्थापित करने का आन्दोलन शुरू हो गया। इस सहयोग का उदाहरण फिलाडेल्फिया में मैकेनिक्स यूनियन आव ट्रेड ऐसोसियेशन ने प्रस्तुत किया, लेकिन जैसा कि हमने देखा, यह ग्रुप तुरन्त ही राजनीति के अखाड़े में आ उतरा। ट्रेड यूनियन बनाने में अब मज़दूरों का उद्देश्य स्थानीय मज़दूर सोसाइटियों की यूनियनें बनाने का था जिन्हें आज की शब्दावली में केन्द्रीय मजदूर परिषदें कहा जा सकता है। यह उनकी संयुक्त गतिविधि का आधार था। इन नए संगठनों में से एक के संविधान में "मिस्त्रियों और श्रमिकों की सोसाइटियों तथा ऐसोसियेशनों के, जो यह देख लेने के बाद कि वे अपने खिलाफ तैनात अनेक ताकतों का मुकाबला करने में असमर्थ हैं, आपसी सुरक्षा के लिए मिलकर एक हो गई हैं, समूह को ही मजदूर यूनियन कहा गया है।"

इन नई केन्द्रीय मज़दूर परिषदों में न्यूयार्क की जनरल ट्रेड्स यूनियन [illegible]स महत्वपूर्ण थी और फिलाडेल्फिया, बोस्टन, बाल्टीमोर, वाशिंगटन, [illegible]नसिन[illegible], पिट्सबर्ग, लुईसविल तथा अन्य निर्माता शहरों में भी इसी प्रकार [illegible] संगठन स्थापित हुए। १८३६ में इनकी संख्या १३ हो गई थी, जिनके साथ

न्यूयार्क में ५२, फिलाडेलफिया में ५३, बाल्टीमोर में २३ और बोस्टन में १६ सोसाइटियाँ इनसे सम्बद्ध थीं।

इस गतिविधि में अन्तिम समन्वयकारा कदम १८३४ में उठाया गया जबकि सब व्यवसायों का एक राष्ट्रीय संगठन बनाने का आह्वान किया गया। न्यूयार्क, ब्रुकलिन, बोस्टन, फिलाडेलफिया, पोकीपसी और न्यूयार्क की स्थानीय सोसाइटियों के प्रतिनिधियों की न्यूयार्क में बैठक हुई और उन्होंने राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन बनाई। इसका उद्देश्य मज़दूर वर्ग के कल्याणकार्यों को प्रोत्साहन देना, देश के हर हिस्से में मजदूर यूनियनों की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाना और कारीगरों तथा श्रमिकों के लिए उपयोगी जानकारी को प्रकाशित करना था। श्रमिकों की पार्टियों की विफलता को देखते हुए नए नेताओं ने निश्चय कर रखा था कि नए संगठन को राजनीतिक क्षेत्र में नहीं घसीटा जाएगा। मैसाच्युसेट्स के एक मज़दूर नेता ने कहा: श्रमिकों का "किसी दल से सम्बन्ध नहीं है। वे न तो जैक्सनवाद के चेले हैं और न ही क्ले-वाद, वान बुरेन-वाद, बेबस्टर-वाद या अन्य किसी वाद के बल्कि सिर्फ मज़दूरवाद के शिष्य हैं।"

इन दिनों मजदूरों का राष्ट्रीय संगठन वस्तुतः प्रभावशाली नहीं था। उसे गृहयुद्ध के बाद के दिनों में वाणिज्य के राष्ट्रीयकरण तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। किन्तु इस प्रकार का संघ बनाने का प्रयत्न ही १८३० के दशक में मज़दूर आन्दोलन की शक्ति और जीवट का साक्षी है। स्थानीय सोसाइटियों, नगर मज़दूर परिषदों और राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के प्रयत्नों के फलस्वरूप समस्त देश में यूनियनों के अन्तर्गत ३ लाख सदस्य हो गए। आपेक्षिक आधार पर इतने अधिक मज़दूर आगे आधी सदी तक ट्रेड यूनियनों के सदस्य नहीं रहे। न्यूयार्क में सभी मजदूरों का कोई दो-तिहाई हिस्सा ५० के करीब मज़दूर यूनियनों में से किसी न किसी यूनियन का सदस्य था।

अपने अधिकारों की रक्षा के अधिकाधिक सक्रिय प्रयत्नों में मज़दूर यूनियनों के सदस्यों ने अपने मालिकों द्वारा उनकी उपयुक्त मांगें पूरी करने से इन्कार कर देने पर हड़ताल की धमकी देने और वस्तुतः हड़ताल कर देने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जब मालिकों ने वेतन कम रखने या कम वेतन पर अप्रशिक्षित मज़दूर लाने की चेष्टा की तो लगभग हर व्यवसाय में

और हर शहर में हड़ताल हो गई। मुद्रक और बुनकर, दर्जी और कोच-निर्माता, राज और जिल्दसाज सब अपना काम छोड़ कर वाहर आ गए। न्यूयार्क में १·५० डालर प्रतिदिन कमाने वाले खातियों ने १.७५ डालर की मज़दूरी के लिए हड़ताल कर दी और जब उसमें सफल हो गए तो २ डालर की दर के लिए हड़ताल कर दी।

न्यू इंग्लैण्ड की कपड़ा मिलों में काम करने वाली लड़कियों ने फिर हड़ताल कर दी। "बोस्टन ट्रान्सक्रिप्ट" की रिपोर्ट के अनुसार 'उनकी एक नेता पम्प पर चढ़ गई और महिलाओं के अधिकारों और अमीर-सामन्तवाद के अन्यायों के वारे में एक भड़कीला भाषण दिया जिसका उसके श्रोताओं पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्हें यदि मरना भी पड़े तो भी अपनी मांग पर अड़े रहने का निश्चय कर लिया।" इससे पहले की मज़दूर सोसाइटियों द्वारा भड़काई गई हड़तालों की पहली लहरों की भांति ये हड़तालें भी सदा शान्तिपूर्ण रहीं किन्तु वे इतनी आम हो गईं कि व्यापारी अधिकाधिक चौंक उठे। उस समय के अखबारों में १८३३ और १८३७ के बीच कम से कम २६८ हड़तालें दर्ज हैं।

जैसा कि बाद में हुआ, मालिकों ने इन उपद्रवों का कारण यह नहीं बताया कि मज़दूरों को कुछ वाजिब शिकायतें हैं, बल्कि इन उपद्रवों को उग्र तथा विध्वंसक आन्दोलनकारियों की, जिन्हें सामान्यतः विदेशी समझा जाता था, कारस्तानी बताया। न्यूयार्क-वासी एक टोरी फिलिप होन ने जो पहले मेयर रह चुका था, अपनी डायरी में लिखा: "मुझे आशंका है कि उपद्रवी तत्व सक्रिय हैं। मज़दूर यूनियनों की शरारती परिषदों और अन्य असन्तुष्ट व्यक्तियों के संगठनों द्वारा भड़काए गए आयरिश व अन्य विदेशियों के दल इतनी शक्ति और महत्व प्राप्त कर रहे हैं जिसे शीघ्र ही शांत करना कठिन हो जाएगा।" मज़दूरों की कुछ भी शिकायतें हों (और होन ने मंहगाई अत्यधिक बढ़ जाने का स्वयं भी ज़िक्र किया है) वह महसूस करता था कि कोई भी हड़ताल चाहे वह कितनी भी व्यवस्थित हो, एक "गैर-कानूनी कार्रवाई" है।

समस्त पूर्व में १० घण्टे के दिन की मज़दूरों की माँग संगठित हड़तालों में सामने आई। काम के घण्टों में कमी के लिए पहले भी आन्दोलन

हो चुके थे। इसी की पृष्ठभूमि में सन् १८२७ में फिलाडेल्फिया में मैकेनिक्स यूनियन ग्राव ट्रेड ऐसोसियेशन का निर्माण हुग्रा ग्रौर दो वर्ष बाद न्यूयार्क में मज़दूर पार्टी बनी। लेकिन ग्रब मज़दूर मालिकों को अपनी मांगें मानने के लिए मजबूर करने के हेतु ग्रपना प्रबलतम ग्रस्त्र इस्तेमाल करने के लिए उद्यत थे।

फिलाडेल्फिया में दिहाड़िये खातियों के एक प्रस्ताव में कहा गया : "सब मनुष्यों को उनके सृष्टा ने समान ग्रधिकार प्रदान किए हैं। उन्हें ग्रपने मन का विकास करने तथा ग्रात्म-सुधार के लिए पर्याप्त समय प्राप्त करने का समान ग्रधिकार है। इसलिए हम समझते हैं कि १० घण्टे मेहनत से किया गया काम एक दिन की मज़दूरी के लिए बहुत काफी है।"

इसी स्वर में न्यू इंग्लैंड के श्रमिकों ने भी छोटे दिन के लिए माँग की ग्रौर ग्राश्चर्य की बात है कि 'बोस्टन ट्रान्सक्रिप्ट' जैसे कन्ज़रवेटिव ग्रखबार ने उनकी माँग का समर्थन किया। उसने लिखा : "जब कोई मिस्त्री ग्रीष्म के लम्बे दिन में १० या १२ घण्टे श्रम कर चुके तो उसका काम खत्म समझा जाना चाहिए जिससे वह कुछ समय ग्रौर पर्याप्त शक्ति बाकी रहते ग्रपने परिवार में लौट जाए ग्रौर कुछ घण्टे ग्रपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने तथा ग्रपने मस्तिष्क का विकास करने में व्यतीत कर सके।"

काम के कम घण्टों के लिए मज़दूरों के लम्बे संघर्ष के ग्रन्य कालों में लम्बे समय तक कठिन श्रम का मज़दूरों के स्वास्थ्य ग्रौर कल्याण पर बुरा ग्रसर पड़ने या बेरोजगारी के खतरे का सामना करने के लिए काम को ज्यादा ग्रादमियों में बाँटने के महत्व पर बल दिया गया किन्तु १८३० के दशक में ग्रात्म-शिक्षा के लिए, जिसे हाल में मताधिकार प्राप्त मज़दूरों को नागरिक के रूप में ग्रपने कर्त्तव्य ग्रच्छी तरह निबाहने लायक बनाने के लिए ग्रावश्यक समझा जाता था, समय मिलने की युक्ति पर ज्यादा जोर दिया जाता था ग्रौर इस युक्ति में मज़दूरों के ध्येय को ग्रागे बढ़ाने की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ग्रन्य दृष्टियों से भी काफी वजन था। इस बात के बहुत प्रमाण मिलते हैं कि मज़दूरों को ग्रपनी व ग्रपने बच्चों की शिक्षा में बहुत दिलचस्पी थी। उस समय के व्याख्यान गृहों में मज़दूरों की भारी भीड़ एकत्र होती थी, चलते-फिरते पुस्तकालयों का रिवाज़ बढ़ रहा था ग्रौर मुफ्त पब्लिक स्कूलों की ज़ोरदार माँग

की जा रही थी। ये सब बातें इस बात की साक्षी हैं कि मज़दूरों को शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी चिन्ता थी, क्योंकि उनका यह गहरा विश्वास था कि शिक्षा ही एक सफल लोकतन्त्र का अधिकार प्रदान कर सकती है।

१८३५ में बोस्टन में हड़ताली कर्मचारियों के एक परिपत्र में कहा गया कि "हम चिरकाल तक घृणित क्रूर, अन्यायपूर्ण और अत्याचारी प्रणाली के शिकार रहे हैं जो काम पर गये हुए मिस्त्री को अपनी सब मानसिक और शारीरिक ताकत खत्म कर देने के लिये मजबूर करती है। हमें अधिकार है और हमें अमरीकी नागरिकों तथा समाज के सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्य निबाहने हैं जो हमें एक दिन में १० घण्टे से अधिक काम करने से मना करते हैं।"

किन्तु इस प्रकार की युक्तियों का मालिकों पर ज्यादा असर नहीं हुआ। एक अखबार ने लिखा "१० घण्टे के दिन का प्रस्ताव काम के घण्टों के बारे में आदेश जारी करके उद्योगों की स्नायु पर ही और नैतिकता पर प्रहार करता है। सवेरे और शाम को कई उपयोगी घण्टों का अवकाश निश्चय ही असहिष्णुता और विनाश का कारण बनेगा।" व्यापारियों तथा जहाज़-मालिकों द्वारा 'बोस्टन कूरियर' में प्रकाशित एक वक्तव्य में काम के घण्टों में कमी का समाज पर गम्भीर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने पर जोर दिया गया और "खाली रहने से बुरी आदतें पड़ जाने की संम्भावना पर चिन्ता व्यक्त की गई।" काम के कम घण्टों पर आपत्ति का कारण चाहे व्यावसायिक मुनाफों पर विपरीत असर पड़ने की संम्भावना ही मुख्य रहा हो, किन्तु वस्तुतः यह प्रदर्शित भय ही कि अवकाश का मज़दूरों की नैतिकता पर बुरा असर पड़ेगा और असहिष्णुता पैदा करेगा, जो कि औपनिवेशिक न्यूइंग्लैण्ड के मालिकों के रवैये में स्पष्ट था, सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करने की प्रणाली में टोरियों द्वारा किसी भी परिवर्तन के विरोध का आधार बन गया।

किन्तु एक के बाद एक शहर में संगठित श्रमिकों ने इस प्रकार की युक्तियों को मानने से इन्कार कर दिया और अपने रास्ते पर जमे रहे। उनकी सब जगह यही माँग रही कि सवेरे ६ बजे से शाम को ६ बजे तक काम का दिन हो, और इस बीच एक घण्टे का विश्राम नाश्ते के लिए और एक घण्टे का ।म भोजन के लिए मिलना चाहिये। बाल्टीमोर में सन् १८३३ में इस र के लिए १७ व्यवसायों के कर्मचारियों ने मिलकर कदम उठाया।

दो वर्ष बाद बोस्टन के खातियों ने राजों, पत्थर तराशने वालों और अन्य मकान-मजदूरों के सहयोग से इसी माँग के लिये हड़ताल कर दी। दोनों हड़तालें फेल हो गईं। दूसरी ओर फिलाडेलफिया में ज्यादा अच्छी तरह संगठित और व्यापक रूप से सहायता प्राप्त एक अन्य हड़ताल ने १८३५ में शानदार विजय प्राप्त की जिसका दूर-दूर तक प्रभाव पड़ा।

यह हड़ताल कोयला उठाने वालों तथा अन्य सामान्य मजदूरों ने की थी किन्तु शीघ्र ही उनमें जूता बनाने वाले, हाथकरघा बुनकर, सिगार-निर्माता, जीन-साज, मुद्रक और मकान-मज़दूर शामिल हो गये। बोस्टन में श्रमिकों के अनुभवों के बारे में एक परिपत्र का फिलाडेलफिया के मज़दूरों की एकता को मजबूत करनें में जादू का सा असर हुआ और उसने हार न माननें के उनके संकल्प को दृढ़ किया। एक सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें गाजे-बाजे के साथ प्रदर्शन पट्ट लिये हुए—जिन पर लिखा था। "६ बजे से ६ बजे तक"—सब व्यवसायों के कर्मचारियों ने सड़कों पर कूच किया।

उनके नेता जॉन फेरल ने, जो एक हाथकरघा बुनकर और जोशीला मज़दूर नेता था, लिखा: "हम सार्वजनिक कार्य विभाग के दफ्तर पर कूच करते हुए गए और उसके कर्मचारी हमारे साथ शामिल हो गए। काम बन्द हो गया, कारोबार ठप्प हो गया, आस्तीन चढ़ा ली गईं, लबादा पहन लिय गाया, औज़ार हाथ में ले लिए गये। सब जगह यही दृश्य दिखाई देता था। अगर किसी हमलावर दुश्मन की तोप ने हमारी पितृभूमि पर चुनौती दी होती तब भी फिलाडेलफिया के नागरिकों में संघर्ष के लिये उत्पन्न उत्साह इससे ज्यादा न होता; खून चूसने वाला सामन्ती वर्ग, वहीं भयभीत और आतंकित अलग खड़ा रहा। वह समझता था कि बदले का दिन आ पहुँचा है किन्तु लोगों ने अपने दुश्मनों से उनके द्वारा लादे गए अन्याय का बदला लेने की कोशिश भी नहीं की।"

पहले पहल शहर की सामान्य परिषद् ने घुटने टेके। उसने सब सरकारी कर्मचारियों के लिए १० घण्टे का दिन स्वीकार कर लिया। इसके बाद मास्टर खातियों और मास्टर जूता-निर्माताओं की बारी आई। अन्य मालिकों ने भी शीघ्र ही उनका अनुकरण किया और सारे शहर में १० घण्टे के दिन का रिवाज कायम हो गया। फेरल ने लिखा: "मशीन कर्मचारी युद्ध और

सच्चे रहे। वे इसलिए जीते क्योंकि वे संगठित और एकनिष्ठ रहे। अखबार, जो लोकमत के कूच को नहीं रोक सके, न ही उसे अपने न्यायपूर्ण उद्देश्य से भटका सके, अब हमारी रक्तहीन क्रांति की घोषणा कर रहे हैं।"

यह आन्दोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया और कई मामलों में ऐसी ही सफलता प्राप्त की गई। शीघ्र ही मिस्त्रियों और कारीगरों के लिए सब कहीं सूर्योदय से सूर्यास्त के बजाय १० घण्टे का दिन कायम हो गया, न्यू इंग्लैण्ड के कपड़ा उद्योगों के लिए जो कारखाने स्थापित हो रहे थे और अन्य निर्माता उद्योगों में इसके बाद भी बहुत अरसे तक काम का दिन १२ घण्टे और उससे अधिक का ही रहा। कुछ धन्धों में तो १८३० के दशक में प्राप्त किए गए लाभ भी जाते रहे। किन्तु फिलाडेल्फिया तथा अन्य शहरों में की गई हड़तालों में मज़दूरों ने अपनी संगठित और दृढ़तापूर्ण कार्रवाई से वास्तविक विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा संघ सरकार ने सब सरकारी कार्यों के लिए शीघ्र ही १० घण्टे का दिन नियत कर दिया। इस विषय पर काँग्रेस को जो अनेक ज्ञापन दिए गए, उन पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया किन्तु जब हड़ताली जहाज़ी मज़दूरों ने १८३६ में राष्ट्रपति जैक्सन से सीधी अपील की तो फिलाडेल्फिया के नौ-सैनिक घाट में भी यह प्रणाली जारी हो गई। ४ वर्ष बाद वान बुरेन ने यह घोषणा कर अपने राजनीतिक समर्थन के लिए मजदूरों का ऋण स्वीकार किया कि सब सरकारी परियोजनाओं में काम का दिन १० घण्टे का होगा

मज़दूरों की अधिक वेतन और काम के कम घण्टे की दोनों माँगों का मालिकों ने यथा सम्भव दीर्घकाल मुकाबला किया। जहाँ कहीं भी उन्हें मुमकिन दिखाई दिया, वे सस्ते मज़दूर लगा कर अपने कर्मचारियों की सौदे-बाज़ी की ताकत पर चोट करते रहे। लेकिन जहाँ दक्ष मिस्त्रियों और कारी-गरों का सवाल होता, मालिकों को अपनी स्थिति कायम रख सकने में कठिनाई होती। कारीगरों की यूनियनें एक *क्लोज़्ड शाप (बन्द कारखाना) नियम लागू कराने में सफल हो गईं जिसने मालिकों के हाथ बाँध दिए। पब्लिक कार्डों के जरिये, ज़िसमें वे किसी भी दिहाड़िये को जो यूनियन में शामिल नहीं

*ऐसा संस्थान जिसमें मालिक सिर्फ यूनियन के सदस्यों को ही काम पर रखता है।

होता था, "अनुचित" करार देकर और उस संस्थान को जहाँ कोई "अनुचित" कर्मचारी काम पर लगाया गया होता, "गन्दा" कह कर वे श्रम बाजार पर प्राय: अपना नियंत्रण रखती थीं। यह हमेशा ही सच नहीं होता था किन्तु उस वक्त के रिकार्डों से दक्षता की अपेक्षा वाले धन्धों में संगठित श्रमिकों की एक अप्रत्याशित शक्ति जाहिर होती है।

इन परिस्थितियों में मालिक अधिकाधिक पारस्परिक सुरक्षा संगठनों की ओर झुके जो मजदूरों के "प्रत्येक घातक संगठन का विरोध करने के लिए मिलकर काम करने को तैयार थे। न्यूयार्क में मालिकों, चमड़े का प्रोसेसिंग करने वालों और चमड़े के व्यापारियों ने जनरल ट्रेड्स यूनियन के खिलाफ मोर्चा लिया और आपस में यह निश्चय किया कि वे "ऐसे आदमी को काम पर नहीं लगाएंगे जो उस या ऐसी किसी सोसाइटी का सदस्य है जिसका उद्देश्य मज़दूरों के काम करने की शर्तें तय कराना है।" फिलाडेल्फिया में मास्टर मुद्रकों ने ट्रेड यूनियन विरोधी ऐसोसियेशन की स्थापना के लिए आह्वान करने वालों का नेतृत्व किया। अनेक प्रस्ताव पास करके ट्रेड यूनियनों को स्वेच्छाचारी, अन्यायपूर्ण, हानिकारक और सबको बराबर कर देने वाली प्रणाली का, जो मास्टरों को सिर्फ दिहाड़िया बनाकर छोड़ देगी, शक्तिशाली साधन घोषित किया। एक प्रस्ताव में कहा गया कि मालिकों को श्रमिकों की किसी भी सोसाइटी के हस्तक्षेप के बिना कर्मचारियों के साथ काम की कुछ भी शर्तें तय करने का अधिकार है।

मालिकों के संगठन जब पुन: मज़दूर संगठनों का मुकाबला नहीं कर सके तो एक बार फिर अदालतों का आश्रय लिया जाने लगा। यूनियनों को व्यापार में रुकावट डालने वाला षड़यंत्र बता कर उन्हें तोड़ने का आन्दोलन पुन: जोर से चलाया गया और सदी के प्रारम्भिक वर्षों की भाँति इन वर्षों में भी अनुदार न्यायाधीशों ने मालिकों का पूरा साथ दिया।

'पीपल वर्सेज फिशर' केस में जिसका १८३५ में न्यूयार्क की सुप्रीम कोर्ट में निबटारा हुआ, इस युग में इस चीज का पहला महत्वपूर्ण प्रदर्शन था कि मजदूर यूनियनों के प्रति अदालतों के विरोध में कोई तब्दीली नहीं आई है। जेनीवा, न्यूयार्क में दिहाड़िये जूता-निर्माताओं की एक सोसाइटी पर मजदूरी बढ़ाने की साजिश करने और इस प्रकार, जैसा कि वादियों ने दावा किया,

वाणिज्य को नुकसान पहुँचाने और मौजूदा कानून के अनुसार दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। मुख्य-न्यायाधीश ने मालिकों के पक्ष में फैसला दिया। 'समाज का सर्वोत्तम हित-साधन तभी तो सकता है, जब श्रम की कीमत स्वयमेव नियमित होने दी जाए।' इस सिद्धान्त के आधार पर उसने घोषणा की कि जूता बनाने वाले वेतन-वृद्धि के लिए अपना संगठन करके पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं क्योंकि "इस उद्देश्य के लिए साज़िश सामान्य कानून की भावना के विरुद्ध है।"

फैसले के अन्त में कहा गया: "प्रतियोगिता वाणिज्य की जान है। अगर प्रतिवादी सामान्य जूते १ डालर फी जोड़ी से कम में नहीं बना सकते तो भले ही वे इससे इन्कार कर दें किन्तु उन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि अन्य लोग भी इससे कम कीमत पर काम नहीं करेंगे...प्रतिवादियों का हस्तक्षेप गैरकानूनी है। उनका रवैया न केवल व्यक्ति-विशेष को सताने का है बल्कि आम लोगों के लिए असुविधा और परेशानी उत्पन्न करता है।"

इस निर्णय का असर यह हुआ कि अन्य मालिकों को मज़दूर सोसाइटियों के दमन के लिए प्रोत्साहन मिला, भले ही उन सोसाइटियों ने हड़तालें न की हों और जब अदालतें खुल्लमखुल्ला मज़दूर-विरोधी नीति अपनाती रहीं तो श्रमिकों और उनके साथ सहानुभूति रखने वालों में विरोध का तूफान उठ खड़ा हुआ। १८३६ में एक और मामले के बाद यह विरोध अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। इस मामले में अध्यक्ष न्यायाधीश ने जूरी पर दिहाड़िये दर्जियों की एक सोसाइटी को वाणिज्य में रुकावट डालने वाली साजिश का अपराधी घोषित करने के लिये जोर दिया था।

'न्यूयार्क इवनिंग पोस्ट' में विलियम कलेन ब्रायण्ट ने लिखा: "इन दर्जियों की इसलिए निंदा की गई, क्योंकि उन्होंने पेश की गई मज़दूरी की दरों पर काम करने से इन्कार कर दिया था। क्या इससे ज्यादा घिनौनी किसी चीज की कल्पना की जा सकती है? अगर यह गुलामी नहीं है तो हम उसकी परिभाषा ही भूल चुके हैं। मेहनत बेचने के लिए व्यक्ति का ऐसोसियेशन बनाने का अधिकार खतम कर दीजिए तो आप उसे किसी एक मास्टर के लिए अथवा एक ही स्थान पर काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं...।"

न्यूयार्क के उत्तेजित मज़दूर नेताओं ने शहर में पोस्टर बाँटे, जिनपर एक कफन का चित्र अंकित था। इसमें श्रमिकों से कहा गया था कि जिस दिन दर्जियों के लिए सजा की घोषणा की जानी है उस दिन वे अदालत में पहुँचे।

पोस्टर में कहा गया था। "सोमवार, ६ जून, १८३६ को इन मज़दूरों को सामन्ती वर्ग की नारकीय भूख को मिटाने के लिए सजा दी जाएगी। सोमवार को मजदूरों की आज़ादी दफना दी जाएगी, न्यायाधीश ऐडवर्डस प्रार्थना पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक मज़दूर जाओ! जाओ! और समानता के कफन पर मिट्टी गिरने की दुःखद ध्वनि को सुनो! अदालत के कमरे, सिटी हाल और सारे पार्क को शोकातुरों से भर जाने दो!" लोग आशा से कम ही संख्या में अदालत पहुँचे और उनकी भीड़ पूर्णतः शान्त रही। किन्तु दर्जियों को सजा दिए जाने के एक सप्ताह बाद एक अन्य आम सभा हुई, जिसमें २७,००० व्यक्ति जमा हुए और जिस न्यायाधीश ने फैसला दिया था, उसका बुत जलाया गया।

इन मुकदमों के खिलाफ प्रतिक्रिया वस्तुतः इतनी उग्र थी कि जूरी भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और दो अन्य साजिशों के मुकदमे में 'अपराधी नहीं' का फैसला सुनाया गया। १८४२ में मैसाच्युसेट्स सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कामनवेल्थ बनाम हण्ट के केस में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जो यूनियनों की वैधानिकता के लिए एक दृढ़ आधार प्रदान करता प्रतीत होता था।

यह केस बोस्टन के दिहाड़िये जूता निर्माताओं की सोसाइटी का था जिसके सदस्यों ने अपने संगठन से सम्बन्ध न रखने वाले दिहाड़ियों को काम पर रखने वाले किसी भी मालिक के लिए काम न करने का निश्चय किया था। मुख्य न्यायाधीश शा ने कहा कि सोसाइटी का प्रत्यक्ष उद्देश्य एक ही व्यवसाय में काम करने वाले व्यक्तियों को सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना है और इसे गैर-कानूनी नहीं समझा जा सकता, न ही मैं यह मानता हूँ कि गैर-सदस्य दिहाड़ियों को काम पर रखने वाले मालिकों के लिए काम करने से इन्कार कर देने के कारण जूता-निर्माता कोई अपराधपूर्ण साधन अपना रहे हैं। उन्होंने एक सम्भावित समानान्तर सोसाइटी का उदाहरण दिया

जिसके सदस्य भड़कीलेदिहाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले मालिक के लिए काम न करने का निश्चय करके सहिष्णुता का अत्यन्त प्रशंसनीय उद्देश्य पूरा कर रहे हों। दूसरे शब्दों में एक कानूनी उद्देश्य के लिए मिलकर कार्रवाई करने का निश्चय अनिवार्य रूप से अपराधपूर्ण साजिश ही नहीं है। न्यायाधीश के फैसले के अन्त में कहा गया : "इस प्रकार के एसोसियेशन की वैधानिकता इसके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनाये जाने वाले साधनों पर निर्भर करेगी।"

इस निर्णय के बाद भी चूँकि मज़दूर सोसाइटियों को यह सिद्ध करना पड़ता कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने जो साधन अपनाये हैं, वे पूर्णतः वैधानिक हैं, इसलिए यह फैसला भी मजदूरों के लिए पूरी जीत नहीं था। इसने वस्तुतः निन्दा करने में कुछ टैकनिकल मुद्दों का सहारा लिया था। किन्तु तो भी यूनियन बनाने और 'बन्द कारखाना' के सिद्धान्त को भी पर्याप्त समर्थन मिला। इसके बाद काफी अरसा बीतने पर ही मज़दूरों को अपना वैधानिक बचाव करना पड़ा ; ट्रस्ट विरोधी कानूनों के अन्तर्गत नए सिरे से साज़िश के अभियोगों और हड़तालों व बायकाटों क खिलाफ़ आदेशों के मनमाने प्रयोग के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा।

१८३० के दशक में श्रमिकों को अपने १० घण्टे के आन्दोलन में, साजिश सम्बन्धी कानूनों का विरोध करने में और अपनी हड़तालों में अपनी आम ट्रेड यूनियनों का सक्रिय समर्थन प्राप्त रहा। ये संगठन स्थानीय सोसाइटियों की माँगों का समर्थन करने और मज़दूरों द्वारा हड़ताल किए जाने पर वित्तीय सहायता देने के लिए जो कुछ कर सकते थे, इन्होंने किया। न्यूयार्क, फिला-डेल्फिया और बोस्टन में जहाँ-कहीं भी ये बड़ी ट्रेड यूनियनें बनीं, इस नेतृत्व की बदौलत मज़दूरों में निकट सहयोग रहा। केन्द्रीय संगठन को मासिक चन्दा दिया जाता, जिससे एक हड़ताल-कोष स्थापित हो सका और कई मामलों में हड़ताल करने वाली अन्य सोसाइटियों के सदस्यों की सहायता के लिए अतिरिक्त रकम की सहायता दी गई। कभी-कभी यह सहायता एक नगर से दूसरे नगर को भी दी जाती थी। फरवरी, १८३६ में जब फिलाडेल्फिया के जिल्दसाजों ने न्यूयार्क की जनरल ट्रेड्स यूनियन से सहायता के लिए प्रार्थना की तो इस सहायता के पक्ष में तुरन्त एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

इसमें सब सदस्यों से "अपने साथी कारीगरों की मदद करने के लिए कहा गया, जिन्हें इस प्रतिकूल समय में सामन्ती अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।" न केवल न्यूयार्क की यूनियनों ने ही बल्कि वाशिंगटन, वाल्टिमोर, अलबानी और नेवार्क की यूनियनों ने भी जिल्दसाज़ों की मदद के लिए अलग-अलग राशियाँ भेजीं।

राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों का जिनकी पहली बैठक १८३४ में हुई थी और जिन्होंने बाद के दो वर्षों में अपने सम्मेलन किये थे, जनरल ट्रेड यूनियन जैसा एकजूट संगठन नहीं था। यह वार्षिक सम्मेलन के अलावा कुछ नहीं था जिसमें मज़दूर सम्बन्धी मामलों पर बहस की जाती थी और जो कभी-कभी १० घंटे का दिन, जेल-मज़दूर या सार्वजनिक जमीनों जैसे मामले पर काँग्रेस को ज्ञापन भेज दिया करता था। यद्यपि इसने सीधी राजनैतिक कार्रवाई में भाग लेने से इन्कार कर दिया, तो भी जैक्सन डैमोक्रेटों द्वारा किए जा रहे बहुत-से सुधारों का इसने समर्थन किया। इसने अमरीकी बैंकिंग प्रणाली पर आक्षेप किये और उसे कानून-सम्मत एकाधिकार प्रणाली बताया जो अमीरों को और अमीर तथा गरीबों को और गरीब बना देती है।" किन्तु यह आन्दोलन कोई वर्ग-संघर्ष का आन्दोलन नहीं था। इसके अखबार 'दि यूनियन' ने २१ अप्रैल, १८३६ को लिखा : "ट्रेड यूनियन बनाने का हमारा उद्देश्य अनुत्पादक वर्ग के प्रति शत्रुता की भावना उत्पन्न करना नहीं, बल्कि अपनी व अन्यों की जो जीवन की आवश्यक वस्तुओं तथा वैभव की चीजों के उत्पादक हैं, हैसियत को ऊँचा करना है।"

मज़दूरों के हित-साधन में नेशनल ट्रेड्स यूनियन का शायद सबसे बड़ा योग देश के विभिन्न भागों से बुलाकर मज़दूर नेताओं को एक जगह जुटाना था। इसने उन्हें सामान्य उद्देश्य की भावना प्रदान की और उनके कार्यों को जैसे १० घण्टे के आन्दोलन को सहयोग प्रदान किया जिससे उन्हें मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थानीय संघर्ष जारी रखने में प्रोत्साहन मिला।

उग्र हाथ-करघा बुनकर जॉन फेरल, जिसने फिलाडेल्फिया में १० घण्टे के आन्दोलन की सफल हड़ताल का नेतृत्व किया था, इस सम्मेलन में प्रमुख व्यक्ति था। वही एक ऐसा आदमी था जिसने मज़दूर सोसाइटियों द्वारा सीधी आर्थिक कार्रवाई किए जाने पर सबसे अधिक बल दिया और राजनीतिक

प्रलोभनों द्वारा मुख्य उद्देश्यों से भटक जाने के खतरों के विरुद्ध सबसे अधिक बार चेतावनी दी। उसने लिखा: "सब दलों के पदाधिकारियों तथा पद के इच्छुकों ने अपने-अपने जाल में फँसाने के लिए प्रलोभन दिये किन्तु अनुभव ने हमारी सहायता की; शर्मीले युवा हरिण की भाँति हम उनके प्रलोभनों को स्वीकार करने में सकुचाए, उनके सहायता के प्रस्तावों के प्रति कृतज्ञता अनुभव की किन्तु उनसे कह दिया कि कि हम अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं और उनकी रक्षा के लिये सजग हैं;" फिलाडेल्फिया जनरल ट्रेड्स यूनियन के संगठन में उसकी सूझ-बूझ, पहल और स्फूर्ति शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। इसकी मूल संगठन समितियों में से एक का वह चेयरमैन रहा था, उसकी गतिविधियों में सतत संलग्न रहता था और उसके "जोशीले भाषणों" का उल्लेख यूनियन की कार्रवाई सम्बन्धी प्रत्येक रिपोर्ट में होता था।

फिलाडेल्फिया का एक दूसरा डेलीगेट विलियम इंगलिश था, जो कुछ समय तक जनरल ट्रेड्स यूनियन का सैक्रेटरी रहा था। वह एक दिहाड़िया जूता-निर्माता था तथा मज़दूरों के हितों का जोशीला और अत्यन्त साहसी चैम्पियन था। उसके आलोचक कहा करते थे कि उसका कोई विचार ऐसा नहीं होता था जो किसी का चुराया हुआ अथवा किसी से उधार लिया हुआ न हो किन्तु उसके आवेशपूर्ण भाषणों को लोग ध्यान से सुनते थे।

न्यू इंग्लैण्ड के श्रमिकों का मुख्य प्रतिनिधि चार्ल्स डगलस था जो न्यू इंग्लैण्ड के किसानों, मिस्त्रियों व अन्य मदूज़रों के एसोसियेशन का एक संस्थापक तथा 'न्यू इंग्लैंड आर्टिजन' का सम्पादक था। न्यू इंग्लैंड की एसोसियेशन यद्यपि मैसाच्युसेट्स के राज्य-आन्दोलनों में सीधे उलझ गई थी तो भी राजनीतिक गतिविधियों के खिलाफ उसका विरोध जॉन फेरल से कम नहीं था। उसकी मुख्य दिलचस्पी कपड़ा मिलों के कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने में थी और वह इस श्रेणी के मज़दूरों के पहले प्रवक्ताओं में से था।

नेशनल ट्रेड्स यूनियन की कम-से-कम एक बैठक में भाग लेने वाला उसका साथी सेठ लूथर था, जिसे 'आर्टिजन' का तथाकथित 'सफरी एजेण्ट' और अन्य बहुत से आन्दोलनकारियों का नमूना कहा जाता था। वह इस युग के एक मज़दूर नेताओं में से एक था, लम्बा, पतला तम्बाकू चबाने वाला,

आदतन चमकीली हरी जकेट पहनने वाला यांकी जो फैक्ट्री वाले नगरों में घूम-फिर कर मजदूरों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए आह्वान करता था। उसने बार-बार नारा लगाया कि "आप समाज के किसी वर्ग को, गरीबों की लाश पर खड़े हुए बिना दूसरों से ऊँचा नहीं उठा सकते" और अपनी इस मान्यता के समर्थन में उसने कई पर्चे निकाले, जिनमें कपड़ा-मिलों में फैक्ट्री मैनेजरों के चाबुक-तले काम करती हुई स्त्रियों और बच्चों का कठोर जीवन चित्रित किया गया था। उसकी शैली भयानक, विडम्बनापूर्ण और अत्यन्त रंगी हुई थी लूथर ने लिखा : "अमीरों के सुसज्जित और सुगन्धित कमरों में काँपते हुए गलों से जहाँ संगीत प्रवाहित होता है वहाँ कपड़ा-मिलों में गरीब स्त्री और बच्चे की नसें इस शान-शौकत को बनाए रखने के लिए किये जाने वाले अत्यधिक परिश्रम के कारण करीब-करीब मरणासन्न वेदना से काँप रही है।"

नेशनल ट्रेड्स यूनियन का प्रथम अध्यक्ष ऐली मूर था जो पहले चिकित्सा का विद्यार्थी था किन्तु बाद में इस धन्धे को छोड़कर एक दिहाड़िया मुद्रक बन गया और मजदूर आन्दोलन में कूद पड़ा। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, जिस कारण उसे अन्ततः राजनीतिक मंच से हटना पड़ा किन्तु तब तक वह अपने आपको यूनियन की गतिविधियों में एक कुशल संगठनकर्ता और प्रभावशाली प्रशासक सिद्ध कर चुका था। लम्बा, सुन्दर, घुंघराले काले बालों वाला जो उसके चौड़े मस्तक से पीछे की ओर बहाए गए होते थे, हमेशा अच्छे कपड़े पहनने वाला और प्रायः हाथी दांत की मूठ वाली बेंत रखने वाला वह व्यक्ति उस वक्त के लोगों के कथनानुसार रोमांचक भाषण शक्ति का धनी था। नेशनल ट्रेड्स यूनियन में अपने पद पर आने से पूर्व वह न्यूयार्क में जनरल ट्रेड्स यूनियन का अध्यक्ष था और 'महान ध्येय' में मजदूरों को पायोनियर बता कर उसने झिलमिल होते हुए मजदूर आन्दोलन के सुप्त स्वर को गुञ्जा-रित किया था।

मूर ने कहा : "देशभर में मिस्त्रियों के हितों के सच्चे प्रतिनिधियों की ओर सारे लोगों की आंखें आशा से लगी हुई हैं क्योंकि अगर यहां पर्याप्त सफल हो जाए और 'यूनियन' के लोगों की आशाएं पूरी हो जाएं तो हर क्षेत्र में इसी प्रकार की अन्य यूनियनें भी बनेंगी"......और फिर उसने

श्रोताओं को चेतावनी दी : "किन्तु अगर ये फेल हो गई तो देश के अभिमानी सामन्त बड़े उल्लासपूर्ण हृदय से और नारकीय सन्तोष के साथ उसका स्वागत करेंगे।"

मूर ने शीघ्र ही मज़दूर क्षेत्रों में अपनी स्थिति को सक्रिय राजनीति में प्रवेश का सोपान बना लिया और यूनियनों तथा पेशेवर राजनीतिज्ञों के सहयोग से उसी वर्ष कांग्रेस में पहुँच गया और तभी वह नेशनल ट्रेड्स यूनि- नियन का निर्वाचित अध्यक्ष बन गया। इसमें काम करते हुए उसने मजदूरों के हितों के प्रवक्ता के रूप में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और यूनियन द्वारा कांग्रेस को विभिन्न ज्ञापन भिजवाने में उल्लेखनीय भाग लिया। जब कभी वह बोलता, मज़दूरों के अधिकारों के पक्ष में उसकी युक्तियों को और "थोड़े से विशिष्ट अधिकार प्राप्त लोगों को हृदयहीन लोलुपता" पर उसके तीव्र प्रहारों को बड़े ध्यान से सुना जाता था।

दिहाड़िये दर्जियों पर साजिश सम्बन्धी मुक़दमा चलने से न्यूयार्क में जो आम उत्तेजना फैली उसके बाद अप्रैल, १८३६ में एक बार उसने असाधरण नाटकीय परिस्थितियों में मज़दूरों के पक्ष की वकालत की। दक्षिण कैरोलिना के प्रतिनिधि ने श्रमिकों के सम्भावित विद्रोह के खिलाफ चेतावनी दी थी। यद्यपि वह इतना बीमार था कि अपनी बेंत के सहारे ही स्थिर खड़ा रह सकता था तो भी मूर ने अपने श्रोताओं को ऐसी गूंजती आवाज में भाषण दिया जो सदन के हर कोने में पहुँची। दृढ़ता के साथ उसने पूछा की राज्य की तीन-चौथाई आबादी से बना हुआ वर्ग राज्य के हितों और सुरक्षा के खिलाफ़ कैसे साजिश कर सकता है? और जब उसके श्रोता ध्यानपूर्वक उसकी बात सुन रहे थे और एक दक्षिणी कांग्रेसमैन यह गुनगुनाते सुना गया कि क्रान्ति का मुख्य पादरी अपना प्रिय गीत गा रहा है, तब स्पीकर की ओर मुखातिब होकर मूर ने कहा : "मज़दूर गैर-कानूनी रूप से पूंजी को हड़प जाएंगे, इससे ज्यादा खतरा इस बात का है कि पूंजी श्रम के लाभों को अन्यायपूर्ण ढंग से खुद हड़प लेगी।"

"डैमोक्रैटिक रिव्यू" के लिए दृश्य का वर्णन करते हुए एक रिपोर्टर लिखता है : " मेरी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। मैंने उसका चेहरा पहले से भी सफेद होता हुआ देखा जब तक कि एक घातक रंग उसके चेहरे पर नहीं छा गया,

उसके हाथ आसमान में ठहर गए, वह शून्य को पकड़ता प्रतीत हुआ—लगता था कि जैसे उत्तेजित भीड़ के सामने हाथ फैलाए एक मुर्दा खड़ा है। उसकी आँखें बन्द थीं—वह लड़खड़ाया और सम्पूर्ण सदन की भागदौड़ और कोलाहल के बीच वह अपने एक दोस्त की भुजाओं में मूर्छित होकर गिर पड़ा।"

मूर इस बीमारी से तो उठ खड़ा हुआ किन्तु उसने सदन में भाषण देना बन्द कर दिया। उसके मित्रों ने अनुभव किया कि उसका स्वास्थ्य इतना खराब हो चला है कि अपने उत्तेजित हो जाने वाले संवेदनशील स्वभाव के कारण वह अब सार्वजनिक भाषण देने का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता किन्तु उसके व्याख्यान के बहुत जल्दी ४ संस्करण छप गए और अदालतों द्वारा यूनियनों को अवैधानिक करार दिए जाने का सिलसिला कुछ रुका। जनमत अधिकाधिक उनके पक्ष में होता जा रहा था। न्यूयार्क इवनिंग पोस्ट में विलियम कलेन ब्रयाण्ट ने पूछा : "मजदूर वर्ग पर बिना किसी कारण इन अमर्यादित हमलों से सिवाय इसके क्या लाभ होगा कि वे आम विद्रोह कर दें।"

इस जमाने के मजदूर आन्दोलन की एक सदी के बाद के आन्दोलनों से तुलना नहीं की जा सकती। यह अमरीकी समाज की उन परिस्थितियों से उद्भूत हुआ था जिनका उस जमाने की परिस्थितियों से दूर का ही सादृश्य था जबकि बड़े पैमाने पर माल तैयार करने वाले कारखानों में बड़ी संख्या में मजदूर काम करते थे। जैसा कि हमने देखा, शुरू की मजदूर सोसाइटियों के सदस्य अपेक्षाकृत स्वतन्त्र मिस्त्री और कारीगर ही थे जो स्वयं को एक स्थायी और विशिष्ट मजदूर वर्ग का सदस्य कहलाना पसन्द नहीं करते थे।

उस समय के अमरीकी समाज में उनके खयाल से सिर्फ दो ही विभाजक रेखाएं थीं। एक सामन्तवाद और लोकतन्त्र के बीच और दूसरी अमीर और गरीब के बीच। मालिक और कर्मचारी का श्रेणी भेद वे नहीं मानते थे। जैसा कि न्यू इंग्लैंड ऐसोसियेशन के एक भाषण में बताया गया वे इस बात से बहुत क्षुब्ध थे कि जो लोग लोकमत बनाने का सामर्थ्य रखते थे वे उपयो[illegible] श्रमिकों को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। वे जमाने की इस चा[illegible] क्रुद्ध होते थे जिसमें कुछ लोग कठिन परिश्रम के बिना ही जीविका क[illegible] साधन जुटा लेते थे और समाज के अधिक उपयोगी और परिश्रमी

निरन्तर परिश्रम का जीवन विताने को मजवूर करते थे और फिर भी उन्हें अपने परिश्रम के फल का एक बड़ा भाग नहीं मिल पाता था। समाज में उनका स्थान हीनता का नहीं तो नीचा जरूर माना जाता था और वही स्त्री-पुरुष और बच्चे उनसे घृणा करते थे जिनका ऐंशो-आराम उनके परिश्रम के फल पर ही निर्भर करता है। १८३० के दशक की मज़दूर यूनियनों को काम की हालतें सुधारने की जितनी चिन्ता थी, उतनी ही श्रम की प्रतिष्ठा और श्रमिकों के लिए सम्मान प्राप्त करने की भी थी।

१८३० के दशक की मज़दूर यूनियनों के उच्च उद्देश्य के वारे में कुछ भी कहा जाए और अपने व्यापक तथा तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति में उन्होंने कुछ भी सफलताएं प्राप्त की हों, उनके दिन गिने-चुने थे। १८३७ में समृद्धि यकायक जाती रही जिसने उनके विकास और सफलताओं के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान की थी। कल्पनाओं का वुलवुला बेरहमी से फट पड़ा। कीमतें जैसे ही तेज़ी से गिरीं, सम्पूर्ण राष्ट्र को कठिन समय ने आ घेरा। वाणिज्य तथा व्यापार के स्रोत सूख गए, निर्माण तेजी से घट गया और अटलाण्टिक तट तथा पश्चिम में दोनों जगह के कभी समृद्ध रहे नगरों और कस्बों में कारोबार ठप्प हो गए।

श्रमिकों के सामने घटते हुए वेतन और वेकारी की समस्याएं फिर मुंह वाए खड़ी हो गईं, जैसा कि मंदी के दिनों में सदा होता है। जब काम का विकल्प अपने और अपने परिवारों के लिए भुखमरी हा रह गया तो मज़दूरों ने १८१९ की भांति मालिकों द्वारा बदला लिए जाने के डर से यूनियनें छोड़ दीं और जब स्थिति अच्छी थी तब प्राप्त किए लाभों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कोई हड़तालें नहीं कीं। दिहाड़िया मज़दूरों की सोसाइटियों का जो कभी इतनी शक्तिशाली लगती थीं, कुछ अपवादों को छोड़कर विस्तर बिल्कुल गोल हो गया। नई आर्थिक परिस्थितियों में वे कुचली गईं और उनके इस विनाश में उनके अखबार संगठन भी रातोंरात गायब हो गए। १८३७ की मन्दी ने विकसित होते हुए मज़दूर आन्दोलन को उसी प्रकार रोक दिया जिस प्रकार १८ वर्ष पहले की मन्दी ने मूल मज़दूर सोसाइटियों की कमर तोड़ दी थी। इसके बाद आधी सदी तक ट्रेड यूनियनवाद उतना जोर और तकत नहीं पकड़ सका, जितना ताकतवर वह १८३७ की मन्दी से पहले था।

अगर मज़दूर संगठन इस वित्तीय और आर्थिक संकट को सह गए होते तो उनका बाद का इतिहास कुछ दूसरा ही होता। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति का अमरीकी समाज पर पूरा प्रभाव पड़ा तब मज़दूरों के सामने आई नई समस्यायों का शायद मजबूत ट्रेड यूनियन संगठन सामना कर पाते। क्रांति की लम्बी छाया १८३० के दशक में अमरीका पर छाने लगी थी और फैक्ट्री मज़दूरों का वर्ग निरन्तर बढ़ रहा था। संगठित दक्ष कर्मचारी इन निर्बल मज़दूरों के साथ सहयोग करने को तैयार थे और वे उद्योगीकरण के इस प्रारम्भिक दौर में अदक्ष कर्मचारियों के बीच एक प्रभावशाली यूनियन की स्थापना में सहयोग दे सकते थे। किन्तु ऐसा होना न था। निर्माण का शनैः-शनैः विस्तार मज़दूरों को हतोत्साह करता गया और मज़दूर यूनियनें आम मज़दूरों के सामने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रख सकीं जिससे वे अपने हितों की सफलतापूर्वक रक्षा कर पाते।

५ : उद्योगीकरण का प्रभाव

सन् १८४२ में अपनी अमरीका यात्रा के दौरान चार्ल्स डिकेन्स लावेल (मैसाच्युसेट्स) गए जहाँ न्यू इंग्लैण्ड के नए कपड़ा-निर्माताओं ने देश का पहला औद्योगिक नगर स्थापित किया था। वहां ज्यादातर नवयुवती महिलाएं और लड़कियाँ काम करती थीं जो डिकेंस को मूर्तिमान अच्छाई का अवतार ही प्रतीत होती थीं—सुखी, सन्तुष्ट और आदर्श व्यवहार वाली, अपने साफ और अच्छे टोपों, गरम लबादे और शाल वाली लड़कियां "अच्छी पोशाकें पहने हुई थीं किन्तु मेरे ख्याल से अपनी हैसियत से ज्यादा ऊँची नहीं। उस दिन मैंने विभिन्न कारखानों में जो कर्मचारी देखे, मुझे याद नहीं आता कि उनमें से किसी के भी चेहरे पर मैंने दुःख की छाया देखी हो।"

इस अंग्रेज़ यात्री ने कारखानों में सुव्यवस्थित कमरों की, जिनमें से कुछ की खिड़कियों में फूल उग रहे थे, ताजी हवा आते रहने की, सफाई तथा सुविधाओं की प्रशंसा की। महिला कर्मचारियों के लिए अधेड़ उम्र की महिलाओं की निगरानी में चलने वाले आवासों का और तीन अन्य आश्चर्यजनक चीज़ों का उसके मन पर बहुत असर पड़ा। ये चीजें थीं, अनेक घरों में शामिलात पियानो बाजे थे, लगभग सब नवयुवतियां चलते-फिरते पुस्तकालयों की सदस्य थीं और 'लावेल आफरिंग' नाम की एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसमें फैक्ट्री कर्मचारियों के ही लेख तथा कहानियां छपती थीं। इस औद्योगिक स्वर्ग पर सुखी मन से दृष्टिपात करते हुए डिकेंस ने इसकी इंग्लैंड के कारखानों से तुलना की और "अपने देशवासियों से इस नगर तथा दुखः के उन विशाल घरों के बीच फर्क पर विचार करने की प्रार्थना की।"

यद्यपि यह कहा जा सकता है कि सन् १८४२ में भी फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को बहुत ज्यादा घण्टे काम करना पड़ता था, उनके आवास-गृहों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी और उनका जीवन पूर्णतः -तुल्य फैक्ट्री मालिकों की व्यवस्था और नियंत्रण में रहता था तो भी ।ह। डिकेन्स ने लावेल का जो चित्र खींचा है वह मनगढ़न्त नहीं था।

अन्य यात्रियों ने भी उसके आम अनुभवों की पुष्टि की है। उन्होंने भी आनन्ददायक वातावरण, चलते-फिरते पुस्तकालयों और व्याख्यान भवनों के सांस्कृतिक अवसरों तथा नवयुवतियों की अच्छी पोशाक के बारे में लिखा है जो न केवल अपने सावधानी से संवारे हुए बालों पर साफ टोप ही पहनती थीं वल्कि रेशमी मोजे पहनती थीं और धूप के छाते लिए रहती थीं। लावेल किसी को मनोरंजक भले ही न लगता हो, जैसा कि फ्रांसीसी यात्री माइकेल चेवालियर ने लिखा है किन्तु यह "साफ, अच्छा, शांत और गम्भीर था।"

औद्योगिक क्रांति के इन प्रारम्भिक दिनों में लगता है कि कम-से-कम अमरीका के कुछ हिस्से यूरोप में इस युग के कुछ अभिशापों से बचे हुए थे। पहली कपड़ा मिलें स्थापित करने वाले मैसाच्युसेट्स के पूंजीपति कर्मचारियों को उन तकलीफों से बचाना चाहते थे जो विदेशों में फैक्ट्री प्रणाली के विकास के कारण मजदूरों को भुगतनी पड़ रही थीं। वे अपने लिए मजदूर न्यू इंग्लैंड के किसानों में से और ज्यादातर औरतों और लड़कियों में से लाना चाहते थे और आकर्षक परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने मन-पसन्द मजदूर मिल भी गए। र्‌होड आइलैण्ड की मिलों में, स्थिति बिल्कुल भिन्न थी जहां पूरे के पूरे परिवारों पति, पत्नी और बच्चों सब को नगर में आने के लिए प्रेरित किया गया और जो सब करघे व तकुए चलाया करते थे, उनका निष्ठुरता से शोषण किया जाता था। किन्तु लावेल की पृष्ठभूमि में विचार वस्तुतः एक महिला छात्रावास का था, जहां औरतें पढ़ने के बजाय मिलों में काम करती थीं।

उनके स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि नैतिकता की भी रक्षा करने की पूरी कोशिश की जाती थी। उन्हें सख्त निगरानी में आवास गृहों में रहना पड़ता था जिनके द्वार रात को १० बजे बन्द कर दिए जाते थे। उन सब से गिरजा घर जाने की आशा की जाती थी। व्यभिचार जैसे नैतिक अपराधों की तो बात ही क्या है, गलत आचरण तथा नृत्य जैसे अपराधों में भी उन्हें नौकरी से अलग कर दिया जाता था, लेकिन जहां तक पुरुष कर्मचारियों का सम्बन्ध है, लावेल मैन्युफैक्च-रिंग कम्पनी ने यह व्यवस्था कर रखी थी कि "जो कोई पुरुष कर्मचारी महिला कर्मचारियों के साथ ठीक बर्ताव नहीं करेगा, या कम्पनी के अहाते में धूम्र-पान करेगा या शराब पीएगा उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा।"

काम के घण्टे जरूर ज्यादा थे लेकिन वे उतने कष्टदायक नहीं थे, जितने

लगते हैं। करघों की देख-भाल इतना मुश्किल काम नहीं था, जितना कि फैक्ट्री के अन्य काम आगे चलकर हो गए और नवयुवतियों को आराम करने, पढ़ने, आपस में बात करने और खिड़कियों में रखे गमलों को पानी से सींचने का मौका मिल जाता था। अपनी खुराक और निवास का खर्चा चुकाने के बाद उनके पास अपने वेतनों में से मुश्किल से ही २ डालर प्रति सप्ताह बच पाता था किन्तु कृषक परिवारों के सदस्यों को, जिन्होंने नकद आमदनी कभी देखी ही नहीं थीं, यही रकम कारूं का खजाना प्रतीत होती थी। इसे वे बैंक में जमा करा देती थीं और कहा जाता है कि लावेल की लड़कियों का बैंकों में ५०० डालर का औसत हिसाब रहा करता था।

इस प्रारम्भिक काल की परिस्थितियों तथा बाद के वर्षों की परिस्थितियों में मुख्य भेद यह था कि मज़दूर अब भी अपने आप को किसी भी प्रकार स्थायी रूप से काम पर लगा हुआ नहीं समझते थे। अधिकांश नवयुवतियाँ देहातों से लावेल में कुछ ही वर्ष काम करने आती थीं जिससे वे शादी के लिए आवश्यक पैसा जुटा सकें या ओहायो और नए पश्चिमी प्रदेशों में स्कूल टीचर का काम करने के लिए पर्याप्त पैसा बचा सकें। इसके अलावा अगर उन्हें काम पसन्द न हो या मन्दी के समय उन्हें काम न दिया गया हो तो वे आसानी से अपने गांव के घर में लौट सकती थीं। मिलों के साथ उनका न तो ज्यादा सम्बन्ध था और न वे उन पर पूर्णतः निर्भर करती थीं।

तथापि इस प्रकार के जीवन की अपेक्षाकृत सुखद परिस्थितियां ज्यादा दिन नहीं रहीं। डिकेन्स की लावेल यात्रा के समय ही दूरगामी परिवर्तन होने लगे थे। जब कपड़ा मिलों में प्रतियोगिता बढ़ी तो मिल मालिकों की पितृ-तुल्य देखभाल का स्थान सख्त नियंत्रणों ने ले लिया जिनका मज़दूरों के कल्याण से कोई सम्बन्ध नहीं था। मज़दूरी की दरें घटा दी गईं, काम के घण्टे बढ़ा दिए गए और फैक्ट्री के काम में विभिन्न प्रक्रियाओं की रफ्तार बढ़ाई गई। ११॥ घंटे से १३ घण्टे का दिन और औसतन ७५ घण्टे का सप्ताह कर दिया गया। महिला कर्मचारियों को १८४० के दशक के बाद के वर्षों में खुराक के खर्च को निकाल कर १.५० डालर प्रति सप्ताह मिल रहा था और उन्हें ४-४ करघों देखभाल के लिए मजबूर किया जा रहा था जबकि १८३० के दशक में दो करघों की देखभाल किया करती थीं। होलयोक मैसाच्युसेट्स में

एक मिल मालिक ने जब यह देखा कि उसके कर्मचारी "सुस्ती से काम कर रहे हैं क्योंकि वे नाश्ता करके आए हैं तो उसने आदेश जारी कर दिया वे नाश्ता करने से पहले काम पर आएं। एक अन्य कारखाने के एजेण्ट ने कहा कि "मैं अपने कर्मचारियों को बिल्कुल मशीन ही समझता हूँ।" मैं जो कुछ भी उन्हें देता हूँ उसके लिए जब तक वे मेरे लिए काम कर सकते हैं मैं उनसे काम लेता हूं और जो कुछ मैं उनमें से निचोड़ सकता हूं, निचोड़ लेता हूँ।"

ये परिस्थितियां जब धीरे-धीरे बिगड़ती चली गईं तो पहले के सन्तोष का स्थान कटुता भरी शिकायतों ने ले लिया। 'लिन रिकार्ड' ने लिखा कि "ये सामन्ती और उग्र स्वभाव के मालिक महिला कर्मचारियों पर बुरी तरह धौंस जमाते हैं, मानो उनके स्वामी हों।" मजदूरों के प्रबल मित्र आरेस्टेस ब्राउनसन ने लिखा: "मजदूरों का यह विशाल समुदाय पहले से कभी भी बहतर नहीं है बल्कि उसके स्वास्थ्य, आत्मा और नैतिकता का भारी ह्रास हुआ है। कपड़ा मिलों में मजदूरों के हितों की वकालत करने वाला मजदूरों का एक नया अखबार 'वायस आव इण्डस्ट्री' मालिकों की नीति पर प्राय: ही यह आक्षेप किया करता था। ऐबट लारेंस को लिखे गए एक खुले पत्र में इस अखावर ने लिखा: "तुम्हारी फैक्ट्री प्रणाली यूरोप की फैक्ट्री प्रणाली से बदत्तर है। तुम अपने फैक्ट्री मज़दूरों को गरीब अंग्रेज मजदूरों के तहखाने और बरसातियों से अच्छे सोने के कमरे प्रदान नहीं करते हो। चौकीदार ६ व्यक्तियों के लिए सिर्फ एक कमरा देने पर मजबूर है और गरम रहने वाली और घुटन वाली एक बरसाती में प्राय: १२ से १६ तक महिलाएं घुसा दी जाती हैं। यूरोप की अपेक्षा यहां तुम अपनी फैक्ट्री रूपी जेलों में कर्मचारियों को दो-तीन घण्टे ज्यादा समय तक बन्द रखते हो...तुम उन्हें भोजन करने के लिए सिर्फ़ आध घण्टे की छुट्टी देते हो...तुम उन्हें मशीनों पर इतने ज्यादा अरसे तक खड़े रहने के लिए मजबूर करते हो कि उनकी नसें फूल जाती हैं, पैर सूज जाते हैं तथा अन्य अनेक बीमारियां हो जाती हैं जो जान लेकर ही जाती हैं और ये बीमारियां किसी-किसी को नहीं प्राय: सभी को रहती हैं।"

फैक्ट्री में काम करनेवाली लड़कियों ने स्वयं ही "हमारे लिए तैयार किए गए जुए पर" अधिकाधिक रोष प्रकट किया और मज़दूरी में कटौती तथा काम के घण्टों में वृद्धि का मुकाबला करने की कोशिश की। हमने देखा कि

१८३० के दशक में भी उन्होंने हड़तालों का परीक्षण किया था और अब एक दशक बाद भी उन्होंने वेतन बढ़ाए बिना अतिरिक्त करघों पर काम करने से इंकार कर देने और काम के घण्टे घटाने की माँग करने का निश्चय किया। किन्तु इस उद्देश्य में वे कोई प्रगति नहीं कर सकीं, फलस्वरूप अपने गांव के घरों में लौटने लगीं। तथाकथित "गुलामों के सौदागर" जो वरमौण्ट और न्यू हैम्पशायर तक के देहातों में अपना जाल फैलाने के लिए घूमा करते थे, आसान काम और अधिक मज़दूरी का प्रलोभन देकर अब मिल कर्मचारियों की भरती नहीं कर पाते थे क्योंकि सब जान गए थे कि ये सब वायदे झूठे हैं। न्यू इंग्लैंड की किसान लड़कियां मिलें छोड़-छोड़ कर जा रही थीं।

तथापि उनका स्थान मज़दूरों के एक ऐसे नये वर्ग ने लिया जो अपने हितों की रक्षा में उनसे भी कमज़ोर साबित हुआ। सदी के मध्य में आव्रजन की बड़ी लहर आने से आयरिश और जर्मन लड़कियों तथा कुछ फ्रांसीसी कैनेडियनों की बाढ़ सी आ गई जिनके पास मिलों में काम करने के सिवा कोई चारा ही न था चाहे उन्हें कितना ही कम वेतन मिले और कितना ही ज्यादा काम क्यों न करना पड़े। इन परिस्थितियों में हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। सस्ते प्रवासी मज़दूरों के आगमन से, जैसा कि मैसाच्युसेट्स के विधान-मण्डल की एक समिति ने लिखा है. "कल कारखानों वाले स्थानों में समाज की हालत बिल्कुल बदलकर दयनीय होती जा रही थी।"

उद्योगीकरण में वृद्धि से काम की हालतों का क्या हाल हुआ इसका ज्वलन्त उदाहरण यद्यपि कपड़ा मिलों में मिलता है, फिर भी अन्य उद्योग-धन्धों में भी हालत वैसी ही थी। १८३० के दशक में लिन के जूता निर्माताओं को बहुत स्वच्छन्दता थी। उनके अपने वर्कशाप थे और अगर धन्धा ठप्प हो जाता था तो वे खेती या मछली-पालन का काम करने लगते थे। मज़दूर के जीवन के बारे में शायद एक अत्यधिक काव्यमय वर्णन में कहा गया है कि "वसन्त ऋतु के आगमन पर उसकी आशाओं का क्षितिज फैल जाता था। उसे कम कपड़े और कम ईंधन की ज़रूरत होती थी! बैंक अधिक आसानी से ऋ[illegible] देते थे, स्वाम्पाशौट में हैडॉक (मछली) इतनी सस्ती मिलने लगती थी [illegible] कीमत उद्धृत करने लायक नहीं होती थी; लड़के डैंडेलियन (एक

प्रकार की सब्ज़ी) खोदकर निकाल लिया करते थे और यदि उस विचार ने वसन्त ऋतु के लिए सारे जाड़ों को सूअर सम्हाल कर पाल रखा हो तो वसन्त ऋतु में सूअर का मांस और डैण्डेलियन उसके मेनू में कोई तुच्छ चीजें नहीं होती थीं। किन्तु मास्टरों ने निर्माण पर अपना नियन्त्रण शनैः शनैः कड़ा कर दिया। जूते बनाने वालों ने धीरे धीरे देखा कि उन्हें अपनी निजी वर्कशापों से और खाली समय में मछली पकड़ने और खेती करने के कामों से घसीट कर नई फैक्ट्रियों में धकेल दिया गया है, जिनकी मशीनी प्रक्रियाओं से वे अब कोई प्रतियोगिता नहीं कर सकते।

'दिहाड़िये मोचियों के अखबार 'दि-ग्रील' के पन्नों में उन निर्माताओं के खिलाफ बार-बार रोष प्रकट किया गया जो कहने को तो मजदूरों को गुज़ारे लायक मज़दूरी देते थे "किन्तु अन्य उपायों से उन्हें बिल्कुल हीन कर देते थे और उनका वह आत्मसम्मान भी जाता रहता था, जिसके कारण मिस्त्री और मज़दूर संसार में गौरवशाली बने हुए थे।" लिन के विरोध प्रदर्शनकारी मोचियों ने बड़े शहरों में अपने साथी कारीगरों को मिलकर कार्रवाई करने और यह दिखा देने का आह्वान किया कि "हम किसी विदेशी तानाशाह के दास या विनीत प्रजा नहीं, बल्कि स्वतन्त्र अमरीकी नागरिक हैं।" इस आन्दोलन का कुछ परिणाम नहीं निकला। एक प्रकार की जिन्दगी निश्चित रूप से ढल रही थी, मोची और कपड़ा मज़दूर फ़ैक्ट्री प्रणाली के मज़बूत शिकंजे में बुरी तरह फंस गए थे।

छापेखाने के उद्योग में भी नए प्रेसों के आविष्कार तथा भाप की शक्ति के उपयोग के कारण क्रांति हो रही थी। इन घटनाओं से न केवल आदमी बेकार हो रहे थे और मज़दूरी घट रही थी बल्कि इससे मुद्रकों का अपने ही व्यापार पर से नियन्त्रण हट कर बाहर के प्रबन्धकों के हाथ में जाने लगा। मालिक व कर्मचारी के बीच व्यापक खाई के कारण एक अत्यन्त स्वतन्त्र व्यवसाय भी तबदील हो गया। उनके संगठन के लम्बे इतिहास ने मुद्रकों की सहायता की और वे अप्रैण्टिसों तथा काम की हालतों के बारे में पूर्ननिमन के नियमों पर काफी सफलता से अमल करवाते रहे किन्तु नई ताकतों का उन्हें भी सामना करना पड़ रहा था जिसके कारण उन्हें अपनी मज़दूरियां तथा अपनी आम हैसियत को कायम रखने में अधिकाधिक कठिनाई हो रही थी।

अन्य व्यवसायों के अलावा शक्ति-चालित करघों ने हाथ करघा बुनकरों की हालत खराब कर दी उनकी मजदूरी, जो पहले भी ज्यादा नहीं थी १८४० के दशक के मध्य तक आधी रह गई, दिहाड़िये टोप-निर्माताओं के वेतन भी' जिन्हें अपेक्षाकृत अच्छे पैसे मिलते थे, १८३५ और १८४५ के मध्य १२ डालर प्रति सप्ताह से घटकर ८ डालर प्रति सप्ताह रह गए और जर्मन आवासियों के, जो बहुत तेज, खराब और बहुत ही कम मेहनताने पर काम करते थे, थोक उत्पादन से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा में फर्निचर बनाने वालों को ५ डालर साप्ताहिक कमाने के लिए भी अपने काम के घण्टे बढ़ाने पड़े।"

सिर्फ न्यू इंग्लैण्ड की कपड़ा मिलों में ही नहीं, किन्तु समस्त उद्योग में मज़दूरियों में कटौती जितनी मशीनों के प्रयोग से हुई उतनी ही सस्ते मज़दूरों की ज्यादा सप्लाई से हुई। हमारे राष्ट्रीय इतिहास की प्रथम आधी सदी में करीब दस लाख आव्रजक अमरीका आए किन्तु १८४६ से १८५५ तक के अकेले ही दशक में ३० लाख आव्रजक बाहर से आए। आयरलैण्ड में अकाल पड़ने और यूरोप में क्रांतिकारी विद्रोहों का सख्ती से दमन किए जाने के कारण अधिकाधिक संख्या में मज़दूर अटलांटिक सागर के इस पार आ रहे थे और इन नवागन्तुकों में अब किसानों के बजाय मिस्त्रियों और मज़दूरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वे पूर्व में बसने की कोशिश करते थे, तेज़ी से बढ़ते हुए शहरों और उद्योगों के केन्द्रों की ओर खिचते थे ओर सभी काम जिनमें दक्षता की विशेष आवश्यकता नहीं होती थी उससे कहीं कम मज़दूरी पर कर लेते थे, जिसे पहले से रह रहे कारीगर और मिस्त्री अच्छे जीवन-यापन के लिए आवश्यक समझते थे। शायद पहली बार आव्रजन के कारण मज़दूरों की बहुतायत हो रही थी जिसने सस्ती जमीन और पूर्व से पश्चिम में सीमा की तरफ मज़दूरों के प्रवास की प्रवृत्ति के असर को भी मिटा डाला था। यह एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा था, जो आगे चलकर १८८० और १८९० के दशकों में और भी स्पष्ट हुआ जब कि आव्रजन अब से भी ज्यादा बढ़ा और दक्षिण-पूर्व यूरोप के नादान, अदक्ष और गरीब किसानों से ज्यादा संख्या में काम लेने की प्रवृत्ति की झलक १८५० के दशक में ही मिल रही थी।

समुद्रतट क निकटवर्ती शहरों में मजदूरों की सामान्य हालत से इस अव-प्रभाव का पूरा खाका सामने आ जाता है। १८५० के दशक के प्रारम्भ

में न्यूयार्क टाइम्स और न्यूयार्क ट्रिब्यून में अलग अलग एक मज़दूर परिवार के बजट का उल्लेख किया गया। दोनों बजटों में मकान किराया, भोजन, ईंधन और कपड़े की न्यूनतम ज़रूरतों के लिए कम से कम ११ डालर प्रति सप्ताह के खर्च का अनुमान लगाया गया। इस बजट पर टिप्पणी करते हुए होरेस ग्रीले ने कहा : "क्या मैंने मज़दूरों के लिए बहुत अधिक सुविधाओं की कल्पना की है ? उनके लिए आमोद-प्रमोद, आइसक्रीम, स्वादिष्ट भोजन और ताजी हवा लेने के लिए नदी किनारे रविवार को सैर के लिए पैसा कहां से आएगा ?" इमारती व्यवसाय के मज़दूरों के अलावा, जिनके अपेक्षाकृत अधिक वेतन करीब-करीब इस बजट के बराबर थे, शायद ही कोई शहरी मजदूर ऐसे होंगे जो इस बजट की राशि के पास तक भी आते हों। ऐसे भाग्यशाली न तो फैक्ट्री मज़दूर थे, और न ही कपड़ा उद्योग में काम करने वाले स्त्री या पुरुष कर्मचारी और आम मज़दूर तो निश्चित ही नहीं थे। अपना बजट प्रकाशित करने से कुछ पहले ग्रीले ने वस्तुतः अनुमान लगाया था, कि "हमारे शहर में सामान्य मज़दूरों की औसत आय, जिनकी संख्या हमारी आबादी की दो-तिहाई से कम नहीं है, परिवार के प्रति सदस्य के हिसाब से मुश्किल से ही एक डालर प्रति सप्ताह से ज्यादा बैठती है।"

उस समय के वर्णनों में इस बात की पर्याप्त साक्षी मिलती है कि न्यूयार्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन जैसे शहरों में गन्दी बस्तियां बनने में अपर्याप्त मज़दूरी का कितना अधिक योग रहा। अमीरों के आरामदेह, विशाल और सजे-सजाए बंगलों के मुकाबले अत्यन्त भीड़भाड़ सफाई की सुविधाओं का अभाव, गन्द और बीमारी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी। न्यूयार्क में १८,००० आदमी तहखानों में रहते थे। ये लोग सील वाले अंधेरे, गैर-हवादार एक-एक कमरे में ६ से २०-२० आदमी तक स्त्री-पुरुष व बच्चे सभी एक साथ ठुंसे रहते थे। बदनाम फाइव प्वाइण्ट्स में सैकड़ों परिवारों को टूटी-फूटी इमारतों में ठूंस दिया गया था; उनके लिए बाहर शौचालय ही सफाई की एकमात्र सुविधा थे। बोस्टन में भी ऐसी ही बुरी गन्दी बस्तियां थीं। आन्तरिक स्वास्थ्य पर १८४९ में एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा : "यह सारा जिला मानों मानव प्राणियों का एक छत्ता है जिसमें न सुविधाएं हैं और न सामान्य आवश्यक चीजें। बहुत सी जगह उन्हें जानवरों की तरह लिंग, आयु

और भद्रता का ख्याल किये विना ही एक ही जगह ठूंस दिया जाता था। युवा स्त्री-पुरुष एक ही कमरे में साथ-साथ सोते थे और कभी-कभी तो पत्नी, पति, भाई और वहन सब एक ही विस्तर में सोते थे।"

टामस जैफर्सन ने जब यह कहा था कि बड़े शहरों की भीड़ शुद्ध सरकार के निर्माण में उतना ही योग देती है जितना एक फोड़ा मानव शरीर की शक्ति में योग देता है, तब उन्होंने जिस स्थिति की कल्पना की थी वह आ गई प्रतीत होती थी। स्वयं मज़दूर आव्रजन को "गरीब और पराश्रित आबादी का जनक" कह कर उसकी मुखालफित करने लगे। वायस आव इण्डस्ट्री ने लिखा कि "इन आव्रजकों के अपने देश में जो बुरी हालत थी उसने उन्हें अमरीका में शोषण का ज्यादा लाचार शिकार बना दिया और मालिक जो कुछ भी उन्हें दें, उसी पर १४ से १६ घण्टे तक काम करके वे सन्तुष्ट थे।"

उद्योगों की स्थापना और बढ़ते हुए आव्रजन ने काफी हद तक मज़दूरों को संगठित होने से रोके रखा। १८३७ के आंतक से पूर्व मज़दूरों में जो हौसला था उससे वे उस वक्त के मुकाबले की कोई राजनीतिक या ट्रेड यूनियन गतिविधि नहीं कर सके। उद्योगों से निःसृत नई शक्तियों के आगे स्तब्ध मज़दूर बेतहाशा पलायन के मार्ग ढूंढ रहे प्रतीत होते थे। संगठन को करीब-करीब भुला दिया गया। इसके बदले मज़दूर उन दिनों के सामान्य सुधार आन्दोलनों में उलझ गए जो अमरीकी समाज में मशीनों तथा कारखानों द्वारा लाए गए परिवर्तनों के खिलाफ मध्यम वर्गीय, मानवता के नाम पर किए गए विद्रोह के प्रतीक थे। १८४० का दशक मुख्य रूप से अस्पष्ट, आदर्शवादी तथा काल्पनिक सुधार थे जिनमें से प्रत्येक को उसके उत्साही प्रवर्तक उस ज़माने की सब बुराइयों का रामबाण इलाज बतलाते थे। कम्यूनिज्म और भूमिसुधार, गुलामी की समाप्ति और स्त्रियों के अधिकार के लिए आन्दोलन, मद्यपान में संयम और शाकाहार......यानी सामाजिक परिवर्तन के उद्वेग के प्रतीक आन्दोलन और प्रचार का कोई अन्त नहीं था।

सुधारक स्वयं अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए मज़दूरों का समर्थन पाने [illegible]ोशिश-करते रहते थे। अगर मज़दूरों के मामलों पर विचार करने के [illegible]म। कोई सभा या सम्मेलन बुलाया जाता था तो उसमें इनके झुण्ड-के-

झुण्ड चले आते थे और कभी-कभी उन पर पूरी तरह हावी हो जाते थे। १० घण्टे के दिन का फिर से आन्दोलन शुरू करने के लिए १८४४ में न्यू इंग्लैण्ड के मजदूर ऐसोसियेशन की जो पहली औपचारिक सभा बुलाई गई थी, उसमें सुधारकों की बड़ी और प्रभावशाली जमात के मुकाबले मजदूर सोसाइटियों के प्रतिनिधि तो इक्के-दुक्के ही थे। ब्रुक फार्म के जार्ज रिपले, होरेस ग्रीले और अल्बर्ट ब्रिसबेन, वेण्डल फिलिप्स और विलियम लायड गैरीसन, चार्ल्स ए० डाना, विलियम एच-चैनिंग और राबर्ट ओवन अपने नए शिष्यों की उत्सुकतापूर्ण तलाश में सभी वहां मौजूद थे। "उत्पादक वर्ग की उन्नति, औद्योगिक सुधार तथा सब प्रकार की गुलामी और दासता के उन्मूलन में दिलचस्पी रखने वाले हर किसी के लिए" बड़े जोश और उत्साह से सभा के द्वार खोल दिए गए। इस प्रकार की हरकतों के पीछे प्रेरक भावना कितनी भी उदार क्यों न हो, वह अत्यन्त अस्पष्ट और अनिश्चित थी।

इस जमाने में मजदूर "ऐसोसियेशन-वादियों" के लुभावने वायदों के चक्कर में आ गए। स्वतंत्र तथा समाजवादी समाजों का निर्माण करके, जिनके सब सदस्य एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम करेंगे, ऐसोसियेशनवादियों ने औद्योगिक क्रांति के प्रभावों से बचने का रास्ता प्रदान करने का वचन दिया और पहले जमाने की सरल सोसाइटियां फिर से स्थापित करने की आशा प्रकट की। यह विचार मुख्यतः चार्ल्स फोरियर के काल्पनिक समाजवाद की उपज थी—व्यवस्थित संगठन प्रणाली वाले इस वाद का उद्देश्य मज़दूरों की हैसियत को ऊँचा करना और उत्पादन बढ़ाना दोनों थे और इसका अमरीका में सूत्रपात ऐल्वर्ट ब्रिसबेन ने किया था। १८४० में ब्रिसबेन ने 'सोशल डेस्टिनी आव मैन प्रकाशित किया, जिसमें फोरियर के कार्यक्रम का खुलासा किया गया था किन्तु ऐसोसियेशन के विचारों के प्रचारों में उसके वे लेख ज्यादा प्रभावशाली साबित हुए जो वह न्यूयार्क ट्रिव्यून में होरेस ग्रीले द्वारा प्रदान किए गए स्तम्भ में लिखा करता था।

ग्रीले वस्तुतः समाजवाद के इस संयमी रूप को विकसित करने में, जिसे वह मज़दूरों की भलाई के लिए अपने सामान्य समर्थन का एक अंग समझता था, यथासंभव सब कुछ कर रहा था। वह एक आदर्शवादी यांकी था जो किसान का लड़का होते हुए मुद्रण व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए न्यूयार्क में

आया था। मजदूरों की सभाओं में वह सुपरिचित था। उसके गोल चांद से दाढ़ी-मूंछ वाले चेहरे को हज़ारों मज़दूर जानते थे। उसने कहा : "जिनके पसीने से सब चीज़ें और ऐश्वर्य का सामान बनता और उपलब्ध होता है उनको इन चीज़ों में इतना कम हिस्सा क्यों मिले ?" मज़दूरों पर औद्योगिक क्रांति का जो शोषणकारी प्रभाव पड़ रहा था उसे वह शायद अपने समकालीन सार्वजनिक नेताओं से ज्यादा अच्छी तरह समझता था और यह महसूस करता था कि समाज का स्थायी कल्याण उनके संगठन पर निर्भर करता है। उसने ट्रिब्यून के कालम न केवल ब्रिसबेन के लिए खोल दिए, बल्कि वह समाजवाद पर एक यूरोपीय संवाददाता कार्ल मार्क्स द्वारा भेजी गई साप्ताहिक चिट्ठी भी प्रकाशित किया करता था।

ट्रिब्यून के ज़रिये फोरियरवाद के बहुत से अनुयायी बन गए और ब्रिसबेन द्वारा उत्तर अमरीकी ऐसोसियेशन के लिए अपनी योजना पेश किए जाने से भी पहले मज़दूरों के एक ग्रुप ने पश्चिमी पेंसिलवेनिया में सिलवेनिया ऐसोसियेशन बना लिया। अन्य वर्गों ने भी इसी परीक्षण का अनुकरण किया और ब्रुक फार्म के आदर्शवादी संस्थापकों को भी, जिनकी बस्ती उस समय के रीति-रिवाजों के खिलाफ एक बौद्धिक विद्रोह की प्रतीक थी, फोरियर पन्थी ऐसोसियेशन के स्वरूप और संगठन को अपनाने के लिए राज़ी कर लिया गया। कुल मिलाकर १८४० के दशक में कोई ४० समाज बनाए गए जिनके शायद ८००० सदस्य थे।

इन्हें सफलता नहीं मिली और एक-एक करके खत्म हो गए। उत्तर अमरीकी ऐसोसियेशन ने १८५४ में काम बन्द कर दिया। सामुदायिक रहन-सहन और सामुदायिक उत्पादन व्यावहारिक साबित नहीं हुआ। न ही उनसे किसी भी प्रकार मज़दूरों की जरूरतें पूरी हुई। उत्साहपूर्ण प्रचार के बावजूद उद्योगीकरण का जवाब उसके असर से बचने की कोशिश करना नहीं था। ऐसोसियेशन वादियों के आशामय स्वप्न आर्थिक और सामाजिक ताकतों की, जिनका न तो आसानी से मुकाबला किया जा सकता था और न जिनका रुख मोड़ा जा सकता था, चट्टान पर टकरा कर चूर-चूर हो गए।

[illegible] न जब खत्म हो गए तो मज़दूरों के हित के लिए उपभोक्ता [illegible]दकों, दोनों की सहकारी समितियों के रूप में उनका आंशिक

विकल्प प्रदान करने की कोशिश की गई। सहकारिता के समर्थकों ने कहा : "उद्योग की दिशा और लाभ उत्पादकों के हाथ में रहने चाहिएं।" मैसाच्युसेट्स, न्यूयार्क तथा देश के अन्य भागों में संरक्षणात्मक यूनियनें स्थापित की गईं जिन्होंने स्वयंभू कारखाने स्थापित करने का काम हाथ में लिया। इनमें बना सामान यूनियन के सदस्यों के लाभ के लिए थोक कीमतों पर बेचा जाता था। अन्य अनेक सहकारी समितियां भी कायम हुईं, जैसे जर्नीमैन मोल्डर्स यूनियन फाउण्ड्री, जिसने सिनसिनाटी में अपना कारखाना लगाया और बोस्टन की टेलर्स ऐसोसियेटिव यूनियन और न्यूयार्क में शर्ट स्युअर्स को-आपरेटिव यूनियन डिपो। किन्तु ये चाहे उपभोक्ताओं की सहकारी समितियां हों या उत्पादकों की, प्रारम्भ की ये सोसाइटियां ऐसोसियेशनों से ज्यादा सफल नहीं रहीं। इनकी विफलता के अनेक कारण थे किन्तु बुनियादी तौर पर अमरीकी रहन-सहन और शायद अमरीकियों का स्वभाव सहकारिता के विकास के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके बजाय अमरीकी प्रतियोगिता तथा एक नवीन विकासमान देश में अवसरों को अधिक से अधिक लाभ उठाने में व्यक्तिगत प्रयत्नों को ज्यादा पसन्द करते थे। सहकारिता ने भविष्य में भी बार-बार सिर उठाया और आंशिक सफलता भी प्राप्त की किन्तु न तो १८४० के दशक में और न बाद में ही यह मज़दूरों के सामने विद्यमान समस्याओं का कोई वास्तविक समाधान निकाल सकी।

एक अन्य और महत्वपूर्ण सुधार, जिसे मज़दूरों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ कृषिक्वाद था। शुरू की मज़दूरों की पार्टियों के खात्मे का आंशिक कारण यह भी था कि कृषि के बारे में स्किडमोर के क्रांतिकारी विचारों को अपनाने के कारण उनमें आन्तरिक संघर्ष पैदा हो गया था और बाहर से आक्षेप किए जाने लगे थे। किन्तु नई नीति में समस्त सम्पत्ति पर चोटें नहीं की जाती थीं, जैसी कि स्किडमोर ने "सम्पत्ति के लिए मानव का अधिकार" में की थीं १८४० और १८५० का कृषिवाद-कहीं ज्यादा नरम था। इसका सिद्धान्त यह था कि लोगों का वर्तमान सार्वजनिक भूमि पर स्वाभाविक अधिकार है और वह १६०-१६० एकड़ के प्लाटों के टुकड़ों के रूप में समान रूप से सब को बांट दी जानी चाहिए जो अहस्तान्तरणीय हो और जिसे ऋण चुकाने के लिये भी जब्त न किया जा सके। यह कहा गया कि इस कार्यक्रम के ज़रिये मज़दूरों

को राष्ट्रीय सम्पत्ति में उचित हिस्सा मिलेगा और वह पूंजीपतियों पर पूरी तरह निर्भर रहने से मुक्त रहेंगे।

इस सुधार का मुख्य प्रतिपादक जार्ज हेनरी इवान्स था। न्यूयार्क में मज़-दूरों की पार्टी के भंग हो जाने के बाद १८३६ में वह स्वास्थ्य की खराबी के कारण रिटायर होकर न्यूजर्सी के फार्म में चला गया था और फिर १८४४ में ही अपने नए संदेश के साथ प्रकट हुआ। अपने पुराने अखबार 'वर्किंगमेन्स ऐडवोकेट' को फिर चालू करके वह मौके-बे-मौके कृषिवाद का ही राग अलापता रहा और उसने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये कांग्रेस से कार्रवाई की मांग की। ऐडवोकेट में उसने लिखा : "पहला काम यही करने का है। इसके बिना किसी भी बड़े सुधार की कोशिश करना उसी तरह बेकार है जैसे औज़ारों के बिना काम पर जाना। फालतू मिस्त्रियों को पश्चिम के कस्बों में, जहां बीचों-बीच बड़े-बड़े सार्वजनिक चौक और सार्वजनिक भवन हैं, अपनी-अपनी ज़मीनों पर भेज दीजिए जिससे जो लोग शहरों में रह जाएं, उन्हें पूर्ण रोज़गार मिले......" मुश्किल से ही मज़दूरों की कोई सभा ऐसी होती होगी, जिसमें वह अपनी योजना पेश न करता हो, इस बात की परवाह किए बिना ही कि अगर संभव हो तो भी क्या मजदूर यकायक अपने खूंटों को छोड़कर दूर पश्चिम में खेती करने के लिये जाना पसन्द करेंगे?

१८४५ में राष्ट्रीय सुधार ऐसोसियेशन की स्थापना उसकी गतिविधियों की चरम परिणति थी। अपने पहले के अनुभवों के कारण वह तीसरी पार्टी की राजनीतिक कार्रवाइयों में अविश्वास करने लगा था और उसके नए संगठन का उद्देश्य सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने वाले सब उम्मीदवारों से यह शर्त स्वीकार कराना था कि मज़दूरों के वोटों के बदले वे उसके कार्यक्रम का समर्थन करेंगे। यह वही तरीका था जिसे आधी सदी बाद अमरीकी श्रमिक संघ ने अपनाया, अर्थात् अपने मित्रों को पुरस्कृत करो और दुश्मन को सजा दो। इवान्स यह दिखलाना चाहता था कि कृषिवादी जो कुछ कहते हैं, वह करना भी चाहते हैं। नेशनल रिफ़ार्म ऐसोसियेशन की सदस्यता की प्रतिज्ञा में कहा गया था : "हम, जिनके नाम यहां दर्ज हैं और जो मनुष्य को जमीन [illegible]सका स्वाभाविक अधिकार दिलाना चाहते हैं, गम्भीरतापूर्वक शपथ लेते [illegible] हम किसी ऐसे आदमी को किसी भी विधायक पद के लिए वोट नहीं

देंगे जो यह लिखित वचन नहीं देगा कि चुने जाने पर वह अपने प्रभाव का उपयोग राज्यों तथा अमरीका में सार्वजनिक ज़मीन की आगे सौदेबाज़ी होने से रोकने में और उस ज़मीन को वस्तुतः उस पर बसने वालों के मुफ्त उपयोग के लिए रिजर्व करवाने में ही करेगा।"

यद्यपि इस कायक्रम का समर्थन सिर्फ मज़दूर ही नहीं कर रहे थे तो भी नेशनल रिफार्म ऐसोसियेशन के साथ उनके निकट सम्बन्ध मूल केन्द्रीय समिति की सदस्यता से ज़ाहिर हो जाता है। इसमें चार मुद्रक, दो मोची, एक कुर्सी बनाने वाला, एक खाती, एक लुहार, एक जिल्दसाज, एक मशीनचालक, एक चित्रों के फ्रेम बनाने वाला और एक कपड़े बेचने वाला शामिल था। इसके अलावा इवान्स का १८३० के दशक के जॉन कैमरफोर्ड और जान फेरल जैसे मज़दूर नेताओं से सम्बन्ध था, जो क्रमशः न्यूयार्क में जनरल ट्रेड्स यूनियन और फिलाडेल्फिया ट्रेड्स यूनियन के अध्यक्ष रहे थे। १८३७ के आतंक के बाद फिर से प्रकाशित होने वाले मज़दूरों के नए अखबारों ने भूमि सुधारों को अपनी एक बुनियादी माँग का रूप दिया।

पूर्वी राज्यों में पूंजीपतियों तथा मालिकों ने इस आन्दोलन का ज़ोरदार विरोध किया। उनके एक प्रवक्ता ने काँग्रेस में कहा: "अपनी नीति से तुम हमारे महान निर्माण उद्योगों पर प्रहार कर रहे हो......तुम हमारे हज़ारों निर्माताओं तथा मज़दूरों को बेकार कर रहे हो...... तुम वास्तविक जायदाद की कीमत घटा रहे हो। तुम हमारे उत्पादक मज़दूरों को मुफ्त ज़मीन और रेलों में मुफ्त सफ़र का भ्रष्ट वायदा देकर उन्हें अपने पुराने घरों से दूर घसीट ले जाना चाहते हो और इस प्रकार हमारी आबादी घटाना और फलस्वरूप पुराने राज्यों में बच रहने वाले लोगों का बोझ बढ़ाना चाहते हो।" किन्तु इस आन्दोलन के समर्थन में पश्चिम के किसान व अन्य प्रवासी पूर्व के मज़दूरों से मिल गए "अपने वोट से अपने लिए फार्म प्राप्त करो" के आकर्षक नारे के साथ नेशनल रिफार्म ऐसोसियेशन काफी प्रगति करता प्रतीत हुआ।

इस कार्यक्रम से १८४० के दशक के मज़दूरों को लाभ नहीं हुआ और औद्योगिक उत्पीड़न से उनको राहत देने में इसकी उपयोगिता भी संदिग्ध थी। किन्तु इवान्स के आन्दोलन का सीधा परिणाम यह हुआ कि सन् १८६२ में होमस्टेड ऐक्ट पास हुआ। इसके मातहत उन्हें जमीन पर अहस्तान्तर-

णीयता और कर्ज की हालत में जब्ती से मुक्ति का अधिकार तो नहीं मिला किन्तु सब वास्तविक प्रवासियों को मुफ्त जमीन देने की व्यवस्था ज़रूर हो गई।

इस सदी के मध्य में जितने मानवतावादी आन्दोलन किये गए उनमें भूमि-सुधार का आन्दोलन अन्य बहुत-से आन्दोलनों की अपेक्षा मज़दूरों के लिए ज्यादा हितकारी था। इसका सर्वाधिक तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि १० घण्टे के दिन के लिए पुनः आन्दोलन छेड़ा गया। १८३० के दशक में कारीगरों और मिस्त्रियों के लिए तो प्रायः इसकी व्यवस्था हो गई थी किन्तु फैक्ट्री कर्मचारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। नया आन्दोलन मुख्यतः मज़दूरों के इस नए वर्ग के लाभ के लिए था। पहले के आन्दोलन की तरह इसने ट्रेड यूनियन आन्दोलन की शक्ल अख्त्यार नहीं की—क्योंकि फैक्ट्री कर्मचारी संगठित नहीं थे—बल्कि इसने राज्य विधानमंडलों पर निजी उद्योग में काम के अधिकतम घण्टे तय करने के लिए राजनीतिक दबाव डाला। नेशनल रिफार्म ऐसोसियेशन के स्वरूप में काफी परिवर्तन भी किया गया, जिससे १० घण्टे दिन की मांग को उसका एक सहायक स्तम्भ बनाया जा सके और इसे मज़दूरों की अन्य ऐसोसियेशनों ने भी, जिनकी स्थापना इस विशेष उद्देश्य के लिए ही की गई थी, अपना लिया।

इसके लिए सबसे लम्बा संघर्ष मैसाच्युसेट्स में चला जहाँ कपड़ा उद्योग के विकास के कारण सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी और जहां सुधार का विरोध भी सबसे अधिक हुआ। सब स्थानीय ऐसोसियेशनों को मिलाकर एक संयुक्त कार्रवाई का आह्वान सबसे पहले सन् १८४४ में किया गया जिसकी बदौलत न्यू इंग्लैण्ड वर्किंगमेंस ऐसोसियेशन की स्थापना हुई। फोरियरवादियों तथा भूमि सुधार के पक्षपातियों दोनों ने इस संगठन का नियन्त्रण अपने हाथों में लेने की कोशिश की और कुछ दिनों तक लगा कि इसने मज़दूरों का ध्यान १० घण्टे के प्रश्न से हटा दिया है किन्तु फिर भी इस सुधार के पक्ष में आंदोलन ज़ोर पकड़ता ही गया। याचिकों की भरमार हो जाने के बाद (लावेल आई हुई एक याचिका १३० फुट लम्बी थी और उस पर ४,५०० दस्तखत मैसाच्युसेट्स की बड़ी अदालत सरकारी तौर पर जांच कराने के लिए हुई।

इसकी समिति ने रिपोर्ट दी कि कपड़ा मिलों में काम का दिन ऋतु के मुताबिक ११ घण्टे २४ मिनट से लेकर १३ घण्टे ३१ मिनट तक होता है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि काम के कम घण्टों और भोजन के लिए अधिक समय मिलने से मजदूरों को लाभ होगा। इसने दृढ़ता से यह भी कहा कि जब कभी सार्वजनिक सदाचार या समाज की भलाई खतरे में हो तब काम के घण्टों का नियमन करना विधानमण्डल का अधिकार और कर्तव्य है। किन्तु इस प्रकार के पूर्व-कथनों के बावजूद इस समिति ने ज्यादातर इस तर्क के आधार पर कि उद्योग राज्य से बाहर चले जाएंगे, यही कहा कि कोई कार्रवाई न की जाए। विधान सम्बन्धी जिम्मेदारी को दरकिनार करते हुए समिति ने कहा : "इसका इलाज हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमें कला और विज्ञान के उत्तरोत्तर सुधार, मानव की किस्मत के अधिक कीमती अंकन, पैसे के प्रति कम प्रेम और सामाजिक सुख तथा बौद्धिक उत्कृष्टता की प्राप्ति के प्रति अधिक उत्साह युक्त प्रेम की ओर निहारना होगा।"

फैक्ट्री कर्मचारियों ने रिपोर्ट को "औद्योगिक इजारेदारी के प्रति दब्बूपन और गुलामी की प्रतीक" बताकर उसकी निन्दा की और ऐसा संघर्ष छेड़ा जो राज्यों की सीमाओं को लांघ गया और जिसने सारे देश में मजदूरों को जगा दिया। नई युक्ति-प्रत्युक्तियां पेश की गईं। १८३० के दशक की भांति मजदूरों ने इस बार इस चीज़ पर बल नहीं दिया कि उन्हें आत्मशिक्षा तथा नागरिकता के कर्तव्य निबाहने के लिए खाली समय की जरूरत है बल्कि कहा कि कम घण्टे काम लिए जाने से काम की किस्म सुधरेगी। किन्तु मालिकों को उत्पादन की लागत की ज्यादा चिन्ता थी। मजदूरों के उक्त विचारों का विरोध करने के लिए उन्होंने कहा कि काम के कम घण्टों का मतलब होगा कम दिन का वेतन। साथ ही उन्होंने मजदूरों की भलाई और हित चिन्ता का फिर दावा किया। उनमें से एक ने कहा कि "अगर मजदूरों को ज्यादा समय तक फैक्ट्री जीवन के लाभदायक अनुशासन से दूर रखा गया और इस प्रकार बिना इस बात का निश्चय किये कि उनके समय का सदुपयोग होगा उन्हें अपनी इच्छा और स्वच्छन्दता पर छोड़ दिया गया तो उससे मजदूरों की नैतिकता को जरूर नुकसान होगा।"

मैसाच्युसेट्स में जब यह बहस अभी जारी थी, अन्य राज्यों में अधिक

कम से कम आंशिक विजय प्राप्त करने में सफल हो गए। सन् १८४७ में राष्ट्र के इतिहास में पहली बार न्यू हैम्पशायर राज्य ने १० घण्टे के दिन का कानून पास किया। अगले वर्ष पेंसिलवेनिया ने एक बिल पास किया, जिसमें कहा गया था कि कपास, ऊन, रेशम, कागज, थैले के कपड़े और पटसन के कारखानों में कोई व्यक्ति १० घण्टे दैनिक या ६० घण्टे प्रति सप्ताह से अधिक काम नहीं करेगा "और १८५० में मेन, कनैक्टिकट, रहोड आइलैंड, ओहायो, कैलिफोर्निया और जार्जिया में भी किसी न किसी तरह के १० घण्टे के दिन के सम्बन्ध में कानून बने। किन्तु हर राज्य के कानून में एक त्रुटि रह गई। १० घण्टे के कानून का "विशेष करारों" के ज़रिये उल्लंघन किया जा सकता था। मालिक किसी को भी तब तक काम पर न लेकर, जब तक वह १० घण्टे से ज्यादा समय तक काम करने को तैयार न हो, वस्तुतः कानून की अवहेलना कर सकता था और अन्य मालिकों के साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए तन कर खड़े होने वाले किसी भी मज़दूर का नाम काली सूची में दर्ज करा सकता था।

मालिकों ने विशेष करार सम्बन्धी धारा के समावेश की इस आधार पर वकालत की कि वह नागरिक के अपनी समझ के अनुसार अपनी सेवाएं बेचने के अधिकार की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। बाद के वर्षों में यह युक्तितब और भी ज़ोर से पेश की जाने लगी जब १४ वें संशोधन का अर्थ यह लगाया गया कि वह राज्य के कानूनों के किसी उल्लंघन से करार करने की व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा करता है। इसकी दिखावटी अच्छाई का भंडाफोड़ होरेस-ग्रीले ने किया, जिसने यद्यपि पहले १० घण्टे के कानून का विरोध किया था।

१८ सितम्बर, १८४७ के ट्रिब्यून में उसने लिखा : "जब असलियत यह है कि आदमी से, जिसे अपने परिवार का भरण-पोषण करना है, और साल भर के लिए मकान किराये पर लेना है, यह कहा जाए कि 'अगर तुम दिन में १३ घण्टे या जितनी देर हम कहें, उतनी देर काम करो, तब तो रह सकते हो, ... । अपना कागज़-पत्र समेट कर चलते बनो, और तुम यह भी अच्छी तरह ... लो, कि अब के बाद तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा, "तब श्रम की ...नत की और उसे अपने करार स्वयं करने देने की नीतियों की बातें

करना क्या अत्यन्त दम्भपूर्ण वकवास नहीं है ?"

मैसाच्यूसेट्स में मज़दूर ऐसा ही सोचते थे और १० घण्टे के काम के दिन के प्रश्न पर उनके सम्मेलन बुला कर अपना संघर्ष जारी रखते हुए उन्होंने आग्रह पूर्वक ऐसे प्रभावशाली कानून की मांग की, जिससे काम के दिन का केवल मानीकरण ही न हो बल्कि काम के घण्टे वस्तुतः कम होने चाहिएँ और तत्सम्बन्धी कानून पर अमल होना चाहिए......" १८५२ में कहा गया कि "हम साफ-साफ कहे देते हैं कि हमारा उद्देश्य ऐसा कानून पास कराना है जो कठोर और असंदिग्ध शब्दों में कम्पनियों को किसी भी मज़दूर से १० घंटे से अधिक समय तक काम लेने से रोके और उसकी अवहेलना करने पर पर्याप्त सज़ा की व्यस्था हो। यही न्यायपूर्ण कानून है और इस विषय पर हम इतना ही कानून चाहते हैं।"

यह सीधी स्पष्ट माँग न तो मैसाच्युसेट्स में पूरी हुई और न अन्य किसी राज्य में। जो कानून पास किए गए उन्हें विशिष्ट करार सम्बन्धी धारा के समावेश ने वेकार कर दिया और फैक्ट्री मालिकों ने जिन हालतों और शर्तों पर चाहा, मज़दूरों से काम लिया। न्यू हैम्पशायर के विल के बारे में एक अखबार ने दृढ़ता से लिखा : "१० घण्टे का कानून मज़दूरों के काम का समय कम नहीं करेगा। कानून के बनाने वाले ही नहीं चाहते कि उसका कोई ऐसा नतीजा हो और हम समझते हैं कि मज़दूरों को धोखा देने में भी यह विफल रहेगा, जोकि इस कानून को बनाने वाले राजनीतिक छलियों का एकमात्र उद्देश्य प्रतीत होता है।"

१० घण्टे के आन्दोलन को जीवित रखने का अंतिम प्रयत्न अनेक औद्योगिक कांग्रेस आयोजित करके किया गया। ये नेशनल रिफार्म्स ऐसोसियेशन तथा न्यू इंग्लैण्ड वर्किंगमेन्स ऐसोसियेशन जैसे संगठनों की उपज थी। ये कांग्रेसें पहले राष्ट्रीय आधार पर आयोजित की गई और बाद में राज्यीय तथा स्थानीय सम्मेलनों के रूप में। किन्तु मज़दूरों के काम के उद्देश्यों की पूर्ति करने के बजाय ये सम्मेलन अस्पष्ट और संदिग्धतापूर्ण रहे जिनमें पुनः एक बार ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के बजाए सुधारक ज्यादा एकत्र होते थे। उन्होंने सुधारों के पक्षपाती उम्मीदवारों को राजनीतिक समर्थन का वचन प्रदान करके मुफ्त ज़मीन सहकारिता तथा १० घण्टे के दिन के पक्ष में कानून को प्रभावित करने की

कोशिश की। किन्तु कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि हर तरह की राजनीति को इस आन्दोलन से दूर रखने की चेष्टा की गई, जैसा कि जार्ज हेनरी इवान्स ने नेशनल रिफार्म्स ऐसोसियेशन के लिए वकालत की थी, तो भी राजनीतिज्ञ उस पर सफलता पूर्वक हावी हो रहे थे। उदाहरणार्थ न्यायार्क में औद्योगिक कांग्रेस ने सदस्यता पहले मज़दूर संगठनों तक ही सीमित रखने की कोशिश की किन्तु शीघ्र ही उसका पूर्ण नियन्त्रण पेशेवर राजनीतिज्ञों के हाथ में आ गया।

राजनीति में मज़दूरों की अनुभवहीनता, और पेशेवर राजनीतिज्ञों की प्रवंचनापूर्ण चतुराई की कहानी फिर दोहराई गई। १८५० में जेम्स गॉर्डन वेनेन ने न्यूयार्क की औद्योगिक कांग्रेस के वारे में "न्यूयार्क हैरल्ड" में उसने मानों भविष्यवाणी की कि इसकी बागडोर कुछ खड़यन्त्रकारियों के हाथ में चली जाएगी जो इसका निजी लाभ के लिए उपयोग करेंगे और मज़दूरों को सबसे ऊँची बोली बोलने वालों को वेच डालेंगे। तब इस शहर में पहले खेले गए मज़ाकिया नाटक फिर दोहराए जाएँगे जिनमें मज़दूरों को जरूरतमन्द और महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों के उत्थान की सीढ़ी बनाया जाएगा और ये राजनीतिज्ञ अपनी महत्वाकांक्षा की चोटी पर पहुँचते ही मज़दूरों को लताड़ देंगे।

१८५० के दशक के कई वर्ष बीत जाने पर ही मज़दूर अपने आपको सुधार ऐसोसियेशनों और सम्मेलनों की अस्पष्ट वाचालता में खो जाने से मुक्ति पा सके और सीधी-सादी ट्रेड यूनियन गतिविधि पर लौट सके। आर्थिक परिस्थितियों में सुधार से भी—यद्यपि १८५७ में अल्पकालीन मन्दी से उसमें कुछ रुकावट पड़ी—अस्पष्ट मानवतावादी उपचारों की मृगतृष्णा को छोड़ने में सहायता मिली। मज़दूरों की सौदेबाजी की ताकत एक बार फिर मज़बूत हो गई और हड़तालों के कारगर अस्त्र के ज़रिये प्रभावशाली कार्रवाई का मार्ग खुल गया। किन्तु इस समय की यूनियनों की विचारधारा १८३० के दशक की सोसाइटियों के विचारों से एक महत्वपूर्ण मामले में कुछ भिन्न थी। मज़-
की एकता की उन्हें अधिक चिन्ता नहीं थी बल्कि अपने निजी सदस्यों
आवश्यकताएँ पूरी करने पर उनका ध्यान ज्यादा केन्द्रित रहता था। नगर

में केन्द्रीय संगठनों की अथवा ज़नरल ट्रेड्स यूनियनों जैसे मज़दूर संघ बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई।

इन दोनों ज़मानों की यूनियनें ज्यादातर कारीगरों और मिस्त्रियों की थीं, जिन्हें दक्ष कर्मचारी समझा जाता है और वे प्रायः पुराने चले आ रहे धन्धों तक सीमित थीं। किन्तु पहले जमाने की यूनियनें जहां अदक्ष मज़दूरों और फैक्ट्री मज़दूरों के संगठनों से सहानुभूति रखती थीं और उनके द्वारा बनाई गई सोसाइटियों से सहयोग करने को उद्यत थीं वहाँ १८५० के दशक की ट्रेड यूनियनों को इस प्रकार के मज़दूरों में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। दक्ष और अदक्ष कर्मचारियों के बीच नई विभाजक रेखाएं खींची जा रही थीं और दक्ष श्रमिक अपनी हलचलों को अदक्ष श्रमिकों के साथ किसी भी तरह मिलाना नहीं चाहते थे।

इन वर्षों में मज़दूर आँदोलन के सीमित कार्य-क्षेत्र का कारण यह था, कि फैक्ट्रियों और मिलों में मज़दूरों का जो विशाल समुदाय काम पर लग रहा था उसे संगठित करने में अलंघ्य बाधाएं अधिकाधिक महसूस की जाने लगीं थीं। इनका संगठन बना सकने की पहले जो कुछ आशा थी भी, वह भी दो मूल कारणों से खत्म हो गई। पहली बात तो यह है कि उस समय के फैक्ट्री मज़दूरों में अधिकांश स्त्रियाँ और बच्चे थे जो पुरुष कर्मचारियों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार थे और कर सकते थे और दूसरी बात यह कि पुरुष मज़दूरों की संख्या भी आव्रजकों के कारण निरंतर बढ़ती रहती थी जो काम की हालतों की परवाह किए बिना कोई भी काम स्वीकार कर लेते थे। सब मज़दूरों की एकता की बात बिल्कुल भुला दी गई और फिर वह गृह-युद्ध के बाद ही पनपी। किन्तु १८५० के दशक की यूनियनों का यह रवैया शायद अमरीकी श्रमिक संघ के उस रवैये की ही पूर्व-भूमिका थी, जबकि उसने सब मज़दूरों की एकता के ज्यादा धूमिल लक्ष्य के बजाय दक्ष मज़दूरों में मज़बूत ट्रेड यूनियनों की स्थापना पर बल दिया।

फलस्वरूप १८५० के दशक की पुनरुज्जीवित ट्रेड यूनियनों ने जहां अपने सदस्यों के लिए अप्रैण्टिसशिप के नियम, 'बन्द कारखाना', अधिक वेतन और काम के कम घण्टे रखने की आवश्यकता पर बल दिया वहाँ उन्होंने

समस्त मज़दूर आन्दोलन को ही मजबूत करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। अपने पूर्ववर्तियों का-सा उत्साह और जोश उनमें नहीं था। १८३० के दशक में मज़दूरों ने जिस चीज़ पर बहुत ज्यादा बल दिया था उस समानता को राजनीतिक दबाव या सुधार के ज़रिये प्राप्त करना असम्भव मान कर वे शायद ज्यादा व्यावहारिक बन गई थीं जैसा कि एक सोसाइटी के प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया, उन्होंने महसूस किया कि वर्तमान परिस्थितियों में "श्रम और पूंजी के बीच एक स्थायी विरोध पैदा हो गया है . एक तो श्रम की अधिक से अधिक कीमत लेना चाहते हैं और दूसरा उसकी कम से कम कीमत देने की कोशिश करता है।" किन्तु इस आधार पर पूंजी का मुकाबला करने की उनकी कोशिशें बहुत कामयाब नहीं हुईं।

इस ज़माने की सबसे दिलचस्प घटना राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों की स्थापना का पहला वास्तविक प्रयत्न था। नेशनल टाइपोग्रैफिकल यूनियन, नेशनल मोल्डर्स यूनियन और मशीनिस्ट्स ऐण्ड ब्लैकस्मिथ्स नेशनल यूनियन की स्थापना हुई और रेलवे-इंजीनियरों ने एक नेशनल प्रोटैक्टिव ऐसोसियेशन कायम किया जिसमें १४ राज्यों तथा ५५ रेलों के प्रतिनिधि थे। मोचियों, अपहोल्स्ट्री बनाने वालों, नल का काम करने वालों, पत्थर काटने वालों और कपड़ा मिलों के कताई-मज़दूरों ने अन्य प्रारम्भिक राष्ट्रीय यूनियनें बनाईं। इनमें से कोई संगठन बहुत सफल तो नहीं रहा किन्तु उन्होंने बाद के वर्षों में ज्यादा प्रभावशाली कार्रवाई करने का मार्ग साफ किया।

अन्य मामलों में मज़दूरों के आम संगठन जानी-मानी परिपाटी पर चल रहे थे। स्थानीय यूनियनों ने अपने सदस्यों के लाभ के लिए कई चीज़ें चला रखी थीं, अपने सदस्यों से चन्दा उगाहती थीं, हड़ताल कोष रखने का प्रयत्न करतीं, मालिकों से समूहिक सौदेबाज़ी करतीं और उचित माँगें स्वीकार न किए जाने पर हड़ताल करने के लिये तैयार रहती थीं। कभी-कभी हड़तालें व्यापक रूप से होती थीं। २० अप्रैल, १८५४ को न्यूयार्क ट्रिब्यून ने लिखा: "इस व अन्य शहरों के सब नहीं तो कुछ धन्धों में वेतन वृद्धि के लिए हर वसन्त ऋतु में नया संघर्ष छेड़ा जाता है।" लोकमत स्वीकार करता था जब वेतन बढ़ती हुई मंहगाई के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं तब मज़दूरों। बेचैन होना वाजिब है और यूनियनों की मांगों को अखबारों का सहानु-

भूतिपूर्ण समर्थन प्राप्त होता था। ट्रेण्टन डेली स्टेट गज़ट ने २४ अप्रैल १८५७ को उस शहर के मास्टर और दिहाड़िये खातियों के बीच हुए एक नये समझौते पर टीका-टिप्पणी करते हुए लिखा : "आदमियों को अपने श्रम का हमेशा उचित मुआवज़ा मिलना चाहिए और हमारा विश्वास है कि उनकी मांग शायद ही कभी ज्यादा होती हो।"

इस काल की समाप्ति पर एक हड़ताल से, जो १८६० की फरवरी के शुरू में हुई थी, गम्भीर चिन्ता उत्पन्न हो गई। यह हड़ताल अब तक के अमरीकी इतिहास में सबसे व्यापक सिद्ध हुई। यह हड़ताल नैटिक और लिन (मैसाच्युसेट्स) के मोचियों ने की थी और सारे न्यू इंग्लैंड में फैल गई। कोई २५ नगरों में मिस्त्रियों के ऐसोसियेशन बनने के साथ-साथ अन्त में लगभग २०,००० मजदूरों ने हड़ताल कर दी। अधिक वेतन की मांग को हड़ताल का कारण बताते हुए मोचियों ने घोषणा की कि उन्होंने यह कदम अपने और निर्माताओं दोनों के हित में उठाया है क्योंकि "आम लोगों की सम्पदा जितनी बढ़ेगी, उतनी ही वास्तविक जायदाद की कीमत बढ़ेगी; उससे तैयार माल की मांग बढ़ती है और समाज की नैतिक सम्पदा तथा बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है।"

इस हड़ताल पर अखबारों में सुर्खियाँ दी गई : "उत्तर में क्रान्ति", "न्यू इंग्लैंड के मज़दूरों का विद्रोह" और "श्रम व पूंजी में संघर्ष का आरम्भ।" श्रम सम्बन्धी उपद्रवों में पहली बार सेना व पुलिस बुलाई गई किन्तु बहुत से नगरों में कोई हिंसात्मक काण्ड नहीं हुआ और नागरिकों ने मज़दूरों के साथ हमदर्दी प्रकट की तथा उनका समर्थन किया। अनेक स्त्री-कर्मचारियों ने भी हड़ताल में भाग लिया और प्रदर्शनों तथा परेडों में उन्होंने दिखा दिया कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनमें कितना जोश और उत्साह है। न्यूयार्क हैरल्ड के एक रिपोर्टर ने मारबल हैड से लिखा : "वे अपने मालिकों के खिलाफ़ इस प्रकार नारे लगाती हैं कि पहली फ्रांसीसी राज्य क्रांति में भाग लेने वाली सुन्दर स्त्रियों की याद आ जाती है।"

दूसरे सप्ताह की समाप्ति से पहले ही मालिक हड़तालियों से राज़ीनामा करने लगे। अधिकांश मामलों में उन्होंने यद्यपि न तो यूनियनों को मान्यता दी और न उनके साथ कोई लिखित करार किया; तो भी उन्होंने तनख्वाहें

बढ़ा कर काफी हद तक मज़दूरों की मागें पूरी कर दीं। हड़ताल सफल रही।

१८५० के दशक की समाप्ति निकट आने पर गुलामी का सवाल मज़दूर आन्दोलन पर असर डालने लगा, जिस प्रकार कि देशभर में आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि के हर पहलू को उसने प्रभावित किया था। उत्तर के मज़दूरों में भी इस मामले में वैसी ही मत-विभिन्नता थी, जैसी समाज के अन्य वर्गों में। न्यू इंग्लैण्ड में और विशेपकर कपड़ा मिल के मज़दूरों में गुलामी की प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में जनमत वहुत प्रवल था किन्तु देश के अन्य हिस्सों में नीग्रों के प्रति सहानुभूति इतनी ज्यादा नहीं थी कि लोग उनकी स्वाधीनता के लिए युद्ध करने को तत्पर होते। विकासमान औद्योगिक केन्द्रों में यह महसूस किया गया कि गोरे मजदूर का गुलाम होना भी उतना ही बुरा है, जितना नीग्रो का गुलाम होना इसलिए बेहतर है कि सुधार गोरे मजदूर से शुरू किया जाए। १८६० में लिंकन के चुनाव के वाद भी बहुत सी यूनियनों ने बीच का रास्ता निकालने वाले उन प्रस्तावों का समर्थन किया जो उत्तर और दक्षिण के मतभेदों को दूर करने के लिए प्रस्तुत किए गए।

वस्तुत: ३४ प्रमुख ट्रेड यूनियनें १८६१ के प्रारम्भ में संयुक्त कार्रवाई के लिए एक हो गईं और उन्होंने सरकारी कदम का विरोध करने के लिये "रियायत, पर अलगाव नहीं", नारे के साथ एक राष्ट्रीय मज़दूर सम्मेलन बुलाया। मैकेनिक्स ओन' में वड़े तीखे शब्दों में उन्होंने कहा : "राजनीतिक आन्दोलन-कारियों तथा देश द्रोहियों के नेतृत्व में देश तेज़ी से रसातल को जा रहा है और अगर जन सामान्य अपनी शक्ति के साथ उठ खड़ा नहीं होगा और अपने प्रतिनिधियों को यह नहीं बताएगा, कि उन्हें क्या करना है तो यह अच्छा पुराना जहाज़ टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। "२२ फ़रवरी को फिलाडेल्फिया में उनकी सभा हुई जिसमें कवायद की गई, भाषण दिए गए तथा क्रिटेण्डन समझौते के पक्ष में प्रस्ताव पास किये गए। किन्तु यह कोई बहुत प्रभावशाली चीज़ नहीं रही, और उन ताकतों पर कोई खास असर नहीं डाल सकीं, जिन्होंने शीघ्र ही राष्ट्र को युद्ध में ढकेल दिया।

एक बार युद्ध की घोषणा हो जाने पर राष्ट्रपति लिंकन की अपील पर मज़दूर वड़ी संख्या में सेना में भरती हुए और जो युद्ध के उग्र विरोधी थे उनमें बहुत-सों ने सेना के लिए सबसे पहले अपने नाम लिखाए। अनेक मामलों

में तो मज़दूरों के ग्रुप-के-ग्रुप सेना में भरती हो गए। इस प्रकार के एक संगठन द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में कहा गया : "युद्ध के लिए सरकार की सेना में भरती होने का निश्चय करके यह यूनियन तब तक के लिए अपना काम बन्द करती है, जब तक संघराज्य सुरक्षित नहीं हो जाता या हम वीर-गति को प्राप्त नहीं करते।"

युद्ध से मज़दूरों की परेशानियाँ बहुत बढ़ गईं। उन्हें सेना में जबरन भर्ती किया जा सकता था जबकि अमीर जुर्माना देकर उससे बच सकते थे। इसके अतिरिक्त मंहगाई बढ़ जाने से मज़दूरों को बहुत कष्ट हुआ जबकि निर्माताओं और व्यापारियों के लिए इसका मतलब अधिक मुनाफ़ा था। दबादब नोट छापे जाने से जब मँहगाई बढ़ती ही चली गई तो असन्तोष की गूँज भी सुनाई पड़ने लगी। मज़दूरों ने पूछा : "एक राष्ट्र के रूप में हमें इस युद्ध से क्या लाभ होगा ? क्या हम अपनी संस्थाएँ सुरक्षित रख सकेंगे, अपने संविधान को बचा सकेंगे, या लोगों को असहाय गरीबी और अपराध के गड्ढे में ढकेल देंगे ?" युद्ध के प्रयत्नों में वे अपना पूरा योग देने को तैयार थे किन्तु मुनाफ़ाखोरों तथा सज्जेबाज़ों के खिलाफ उनका गुस्सा उबल रहा था।

१८६३ तक न्यूयार्क की स्थिति से बड़े दुःखद रूप में यह बात सामने आई कि जो लोग पैसा बनाने की स्थिति में होते हैं उन्हें युद्ध से कितना लाभ हो सकता है। होटलों, थियेटरों, जौहरियों तथा विलास की चीज़ों के अन्य विक्रेताओं का व्यवसाय खूब चमक रहा था। "शॉडी", जैसा कि मुनाफा-खोरों को कहा जाता था, अपने धन को लापरवाही और बेशर्मी से भरी फ़ज़ूलख़र्ची के साथ ख़र्च कर रहे थे। 'हार्पर्स' ने कहा : "ये लोग अपनी वास्केट में बढ़िया हीरों के बटन लगाते हैं और स्त्रियाँ सोने-चाँदी का पाउडर अपने मुँह पर लगाती हैं।" मुसीबतज़दा मज़दूरों को ऐसा कोई मुनाफा नहीं होता था और उन्होंने जब माँग की कि उनके वेतनों का बढ़ती हुई मँहगाई के साथ कुछ-न-कुछ युक्तियुक्त सम्बन्ध होना चाहिए तो शीघ्र हड़तालें हो गईं।

शिकागो में ईंटों की चिनाई का काम करने वालों ने वेतन-वृद्धि का आग्रह किया, न्यूयार्क में कण्डक्टरों और कोचवानों ने हड़ताल कर दी; सेण्ट लुई में मुद्रकों ने अधिक वेतन के लिए हड़ताल कर दी; खाती, पेण्टर और

प्लम्बर सब कहीं उनकी माँगें पूरी न किए जाने पर काम छोड़ देने की धमकी दे रहे थे; लोहे की ढलाई करने वाले १५ प्रतिशत वृद्धि की माँग कर रहे थे; जहाज़ बनाने वालों तथा खलासियों ने हड़ताल कर दी और लोकोमोटिव इंजीनियरों ने भी अपने सदस्यों को आह्वान किया।

कभी-कभी इस प्रकार की गड़बड़ियों का मुकाबला करने के लिए मार्शल-ला घोषित किया गया जबकि सेनाओं ने हड़तालें तोड़ीं। किन्तु ह्वाइट हाउस में मज़दूरों का एक दोस्त बैठा था। हो सकता है कि अब्राहम लिंकन ने एक संगठित मज़दूर आन्दोलन के परिणामों को पूरी तरह न समझा हो लेकिन उनकी सहानुभूति मज़दूरों के साथ थी। एक सम्भावित अपवाद के अलावा शायद वे हड़ताल में सरकार के हस्तक्षेप का समर्थन न करते। युद्ध से पहले उन्होंने कहा था : "ईश्वर का धन्यवाद है, हमारे यहाँ ऐसी श्रम-पद्धति है जिसमें मज़दूर हड़ताल कर सकते हैं" और समस्त राष्ट्रीय संकट-काल में मज़दूरों में उन्होंने अपना विश्वास तथा उनके अधिकारों के प्रति आदर दृढ़ता से कायम रखा। जिस लोकतन्त्र का वह बखान किया करते थे उसका आधार यह विश्वास था कि "मज़दूर सभी सरकारों के स्तम्भ होते हैं।" कांग्रेस को अपने पहले वार्षिक सन्देश में उन्होंने कहा था : "श्रम का अस्तित्व पूँजी से पहले और स्वतन्त्र है। पहले श्रम न होता तो पूँजी कभी पैदा नहीं हो सकती थी।" १८६४ में न्यूयार्क वर्किंगमेन्स डैमोक्रैटिक रिपब्लिकन ऐसोसियेशन के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हुए उन्होंने अपने ये विचार दोहराये : "श्रम का स्थान पूँजी से ऊँचा है और उसका कहीं ज़्यादा आदर किया जाना चाहिए।"

इन परिस्थितियों में गृह-युद्ध में मज़दूरों की ताकत बढ़ गई और ट्रेड-यूनियनों को नव-जीवन प्राप्त हुआ। १८६३ और १८६४ के बीच उनकी संख्या ७९ से २७० हो गई और यह अनुमान लगाया गया कि संगठित मज़दूरों की संख्या २ लाख से अधिक थी जो यद्यपि ३० वर्ष पहले की संख्या से तो कम थी किन्तु १८४० या १८५० के दशकों की संख्या से कहीं अधिक थी। इसके अलावा इन यूनियनों में से ३२ यूनियनें राष्ट्रीय आधार पर संगठित थीं और जो १८५० के दशक की यूनियनों से ज़्यादा स्थायी थीं। इनमें सबसे प्रमुख पुनर्गठित आयरन मोल्डर्स इण्टरनेशनल यूनियन थी किन्तु मशीन-चालक

और लुहार, लोकोमोटिव इंजीनियर, अमेरिकन माइन्र्स ऐसोसियेशन तथा सन्स ग्राव वल्कन (गले लोहे पर काम करने वाले) अन्य मजबूत संगठन थे जिनमें मजदूर-आन्दोलन का वदलता हुआ स्वरूप दृटिगोचर हो रहा था।

युद्ध-काल में ट्रेड-यूनियनों के पुनरुत्थान के साथ-साथ संगठित मजदूरों के विचार सामने लाने और मजदूर-सम्बन्धी सुधारों की वकालत करने के लिए मजदूरों के अखवार फिर प्रकाशित होने लगे। मशीन-चालकों तथा लुहारों की यूनियन के अखवार 'फिंचर्स ट्रेड्स रिव्यू' इन अखवारों में सवसे प्रमुख था जिसके सम्पादक-मण्डल में अन्य यूनियनों के प्रतिनिधि भी थे। इसकी वदौलत यह समस्त मजदूर-आन्दोलन का राष्ट्रीय प्रवक्ता वन गया। इसका सम्पादक जोनाथन फिंचर एक सुयोग्य और अथक रिपोर्टर तथा मजदूर-सम्बन्धी मामलों पर वेलाग टिप्पणीकार था। अन्य श्रमिक-पत्रों में शिकागो से प्रकाशित होने वाला नया वर्किंगमेन्स ऐडवोकेट, न्यूयार्क ट्रेड्स ऐडवोकेट तथा वीकली-माइनर शामिल थे।

एक अन्य तरक्की नई मजदूर-सभाओं की स्थापना के रूप में की गई जो पुरानी जनरल ट्रेड्स यूनियनों की तरह की थीं। पहले-पहल रोचेस्टर (न्यूयार्क) की यूनियनों ने इस प्रकार का संगठन वनाया और फिर वहुत जल्दी हर शहर में इस प्रकार की मजदूर-सभाएँ वन गईं। ये वास्तविक शक्ति का स्रोत वन गईं। उन्होंने यूनियन की माँगें मानने के लिए मालिकों को मजबूर करने के साधन के रूप में मजदूरों को एक नया हथियार प्रदान किया। यह नया हथियार था—वायकाट। वायकाट के वारे में उस वक्त की एक रिपोर्ट में कहा गया : इस उद्देश्य के लिए सव यूनियनें मिल जाती हैं। जब उत्पीड़न का कोई मामला सामने आता तो मजदूर सभा की एक समिति उत्पीड़क से मिलती और शिकायत दूर करने की माँग करती। अगर माँग पूरी नहीं की जाती है तो हर यूनियन को सूचित कर दिया जाता है और सदस्य उस घृणित संस्थान से माल खरीदना वन्द कर देते हैं।" ये मजदूर-सभाएँ आमोद-विहारों (पिकनिक), नृत्यों तथा अन्य सामाजिक गतिविधियों का भी आयोजन करती थीं और कहीं-कहीं तो पुस्तकालय तथा वाचनालय चलाती थीं।

गृह-युद्ध के वाद मजदूरों का रुख आक्रामक हो गया। वे अधिक व्यापक राष्ट्रीय-संगठन वनाने के लिए भी तैयार थे। नई यूनियनों को एक ही

आन्दोलन में लाने की कोशिश कर रहे थे जो पूँजी की संगठित ताकतों का अधिक प्रभावशाली ढंग से सामना कर सकता। किन्तु इसे अभी एक बड़ी लम्बी मंज़िल तय करनी थी।

—:o:—

६ : राष्ट्रीय संगठन की ओर

गृह-युद्ध और १९ वीं शताब्दि की समाप्ति के बीच अमरीका में उद्योगों का अत्यधिक विस्तार हुआ। रेलों ने सारे महाद्वीप में फैल कर अपना एक जाल-सा बिछा दिया और देश को एक आर्थिक इकाई के सूत्र में बांध दिया। इस्पात मिलों की चिमनियां जिनसे पिट्सबर्ग के ऊपर का आसमान धूसरित रहता था, एक विशाल उद्योग के विकास की प्रतीक थीं, जो मेसाबी पहाड़ियों में पाये जाने वाले लोहे के अतुल भण्डार के कारण सम्भव हुआ। पश्चिमी पेंसिलवेनिया तथा ओहायो में खोदे जाने वाले कुओं से तेल फूट पड़ा। शिकागो तथा सेण्ट लुई के विशाल बूचड़खानों में प्रतिदिन हजारों मवेशी और सूअर काटे जा रहे थे। न्यू इंग्लैंड की कपड़ा मिलों में बड़ी चहल-पहल रहती थी और न्यूयार्क तथा पूर्व के अन्य शहरों में सिले-सिलाए कपड़ों का उद्योग स्थापित हुआ। सब कहीं नई फैक्ट्रियां और मिलें खड़ी होकर मशीन की विजय और बड़े पैमाने पर उत्पादन के तरीकों के विकास का ऐलान कर रही थीं। अटलाण्टिक सागर के तट के साथ-साथ और मध्य पश्चिम में जैसे-जैसे नये शहर और निर्माण केन्द्र स्थापित होते चले गए, वैसे-वैसे अमरीका की शक्ल बदलती चली गई।

इन सब घटनाओं के पीछे मूल बातें थीं—राष्ट्र के असीम साधन, उसका महान् श्रमिक कोष तथा नए उद्योगों के माल की अतृप्त माँग, किन्तु औद्योगिक विस्तार के लिए तात्कालिक प्रेरणा दूरदर्शी, महत्वाकांक्षी और निर्दयी व्यापारिक नेताओं तथा महाजनों के एक ग्रुप ने प्रदान की। जे गोल्ड, इ० एच० हैरीमैन तथा जेम्स जे० हिल ने रेलों का, कार्नेगी ने इस्पात का और राक फेलर ने तेल का साम्राज्य स्थापित कर लिया। कार्पोरेशन को सब कहीं व्यापारिक संगठन का रूप स्वीकार कर लिया गया और अपने प्रतियोगियों को निर्दयता से कुचल देने वाले उपर्युक्त प्रकार के व्यक्तियों के नेतृत्व में किए जाने वाले विलय और एकीकरण से उद्योग और ज्यादा सार्वदेशिक रूप ग्रहण करता जा रहा था। बीसियों उद्योगों में—तेल, इस्पात, खाँड, अलसी का

तेल, स्टोव और रासायनिक खाद के उद्योगों में बड़े बड़े ट्रस्ट बन गए। एकाधिकार उद्योगपति का ध्येय था और उदासीन सरकार तथा उदासीन अदालतों ने, जो खुली छूट देने के आर्थिक सिद्धान्त के हामी थे, उन नीतियों को बेलगाम छोड़ दिया जिनकी बदौलत आर्थिक सम्पदा और शक्ति एक ही जगह इतनी ज्यादा जमा हो गई, जैसी उससे पहले अमरीका में कभी नहीं हुई थी।

श्रमिक वर्ग इस औद्योगिक विस्तार के ज्वार में बह गया। यद्यपि उनके बिना घटनाचक्र इस प्रकार करवट नहीं ले सकता था, तो भी आर्थिक विकास की दिशा निश्चित करने में उनकी कोई आवाज़ नहीं थी। श्रमिक तो कम्पनी मालिकों के हाथों में करीब-करीब निःसहाय मोहरे बन कर रह गए। कभी के स्वतन्त्र कारीगर जब फैक्ट्रियों, मिलों और फाउण्ड्रियों में चले आए, जहाँ विशेष दक्षता की कोई कीमत नहीं थी और जहाँ उन्हें सामूहिक उत्पादन की जटिल प्रक्रियाओं में से सिर्फ एक ही स्वचालित काम करना होता था तब उनकी पहले की सौदेबाजी की ताकत जाती रही। उद्योग मज़दूरों को महज़ एक माल समझता था, जिसे सस्ते-से-सस्ते दामों पर खरीदा जा सके। उनके प्रति जिम्मेदारी उद्योग के कच्चे माल के प्रति जिम्मेदारी से ज्यादा नहीं समझी जाती थी।

"एकाधिकार की इस प्रकृति के प्रारम्भ से पूर्व अभी जब वाणिज्य-उद्योग बड़ी पूँजी वाले थोड़ी-सी बड़ी कम्पनियों के बजाय थोड़ी-थोड़ी पूँजी वाली छोटी-छोटी असंख्य कम्पनियों के हाथ में था।" एडवर्ड बेलामी ने अपने प्रसिद्ध काल्पनिक रोमान्स 'लुकिंग बैकवर्ड' में लिखा : "श्रमिक का स्थान अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण था और मालिक के साथ अपने सम्बन्धों में उसे काफी आज़ादी प्राप्त थी। इसके अलावा थोड़ी-सी पूंजी अथवा कोई नया विचार किसी आदमी को अपना कारोबार चलाने लायक बनाने के लिए काफी था श्रमिक निरन्तर काम देने वाले बन रहे थे और इन दोनों श्रेणियों के बीच कोई पक्की विभाजक रेखा नहीं थी। तब मज़दूर यूनियनें अनावश्यक थीं और हड़तालों का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। किन्तु जब थोड़ी पूंजी वाली छोटी कम्पनियों का स्थान विशाल पूंजी वाले संस्थानों ने ले लिया तो नज़ारा ही बदल गया। छोटे मालिक के लिए व्यक्तिगत मज़दूर का जो महत्व था वह बड़े कार्पोरेशन के सामने नगण्य और निश्शक्त हो गया और इसके साथ ही

ऊपर तरक्की कर मालिक बन जाने का रास्ता उसके लिए बन्द हो गया। आत्मरक्षा के लिए वह साथियों के साथ मिलकर यूनियन बनाने पर मजबूर हुआ।"

मज़दूरी की दरें चूंकि पूर्णत: पूर्ति और मांग के नियम के आधार पर तय होती थीं इसलिए मालिकों ने हरचन्द यह कोशिश की कि मज़दूरों की सप्लाई किसी तरह कम न पड़े। गृह-युद्ध के दौरान देश के उद्योगपतियों ने इस तरफ और ज्यादा आश्वस्त होने के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के हेतु पहला क़दम उठाया। १८६४ में एक करार-श्रम कानून पास हुआ जिसमें यह अनुमति दी गई थी कि सम्भावित आव्रजकों को पेशगी यात्रा-किराया देकर अमरीका लाया जा सकता है और पेशगी की यह रकम बाद में उनके काम से लग जाने पर उनकी मज़दूरी से काटी जा सकती है। इससे प्रोत्साहित होकर १० लाख डालर की पूंजी से अमेरिकन एमिग्रेण्ट कम्पनी बनी और मुख्य न्यायाधीश चेज़, नौसेना के मन्त्री वेल्स सेनेटर सुमनरे और हेनरी वार्ड बीचर जैसे प्रमुख व्यक्तियों का समर्थन पाकर उपलब्ध मज़दूरों का कोष स्थापित करके उसने विस्तृत होते हुए अर्थतन्त्र की आवश्यकताएं पूरी करने का बीड़ा उठाया उसने अमरीका के निर्माताओं, रेल-कम्पनियों और अन्य उद्योग-धन्धों के लिए ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, नार्वे और स्वीडन से मज़दूर और विशेषकर दक्ष मज़दूर लाने के अपने कार्यक्रम की घोषणा की। उसके विज्ञापन में घोषणा की गई कि वह अल्पकालीन नोटिस और युक्ति-युक्त शर्तों पर खनिज, इस्पात मजदूर, मशीन चालक, लुहार, मोल्डर और हर तरह के मिस्त्री दे सकती है।

अमेरिकन एमिग्रैण्ट कम्पनी के एजेण्ट शीघ्र ही रेल कम्पनियों, जहाज़ कम्पनियों तथा बहुत-सी उद्योग कम्पनियों के एजेण्टों के साथ मिलकर शीघ्र ही करीब-करीब उसी प्रकार उद्योगों के लिए करार-बद्ध मजदूर जुटाने लगे, जिस प्रकार दो सदी पूर्व 'न्यू इंग्लैंड' ने प्रतिज्ञाबद्ध नौकर जुटाए थे। एक मज़दूर सम्मेलन में पेश की गई भयपूर्ण रिपोर्ट में कहा गया: "ये मज़दूर जब यहां आते हैं तो इनकी जेब में कुछ नहीं होता, फलस्वरूप वे इतनी कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर होते हैं, जिससे वे अपना पेट भी अच्छी तरह नहीं भर सकते......हम इन लोगों से प्रतियोगिता किसी भी प्रकार नहीं कर सकते।"

कैलिफोर्निया में और महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली रेलवे के निर्माण में मज़दूरों की आवश्यकता चीनी कुलियों से पूरी की गई और पश्चिमी तट की बस्तियों की अपनी विशिष्ट समस्याएं उठ खड़ी हुई। मैसाच्युसेट्स में उन्हें जूता-उद्योग में लगाने का असफल परीक्षण किया गया, यद्यपि यह परीक्षण छोटे पैमाने पर किया गया था। बोस्टन कामनवेल्थ ने जून १८७० में उनके बारे में कहा : "वे हमारे साथ हैं। बादामी आंखों वाले, चोटी रखने वाले, अत्यन्त मेहनती, सब परिस्थितियों में काम कर सकने वाले, उच्च नैतिकता वाले ये चीनी, जिनकी संख्या ७५ है नार्थ ऐडम्स नगर में बहुत मेहनत से जूते बनाते हैं।"

समय के साथ-साथ यूरोपीय आव्रजकों की संख्या शनैः-शनैः बढ़ती गई। १८८० में करीब ५ लाख देश में आए और अगली दशाब्दि में ५० लाख से अधिक अर्थात् पिछले १० वर्षों के मुकाबले लगभग दुगने। जहां से ये लोग आते थे, वे स्थान भी धीरे-धीरे बदले। ज़्यादातर आव्रजक उत्तर-पश्चिमी यूरोप से नहीं बल्कि दक्षिण-पूर्वी यूरोप से आ रहे थे। अटलाण्टिक के आर-पार जहाज़ चलाने वालों में ज़्यादातर इटालियन, पोल, चेक, स्लोवाक, हंगेरियन, यूनानी और रूसी थे जो अज्ञानी, अदक्ष निर्धन किसान थे। ये खानों, मिलों और कारखानों के लिए कभी न समाप्त होने वाले सस्ते श्रमिक कोष का काम कर रहे थे।

अमरीकी मज़दूरों के अपना जीवन-स्तर उन्नत करने के प्रयत्नों को सदा आव्रजन बेकार करता रहा, किन्तु सदी की समाप्ति के समय वेतन कम रखने में इसका प्रभाव पहले से ज़्यादा दिखाई दिया। क्योंकि यूरोप से आयात करके न केवल अदक्ष मज़दूरों की सप्लाई सदा बढ़ाई जाती रही बल्कि पश्चिम में मुफ्त ज़मीन का उपलब्ध होना शनैः-शनैः बन्द हो जाने से बेकारी और मन्दी के दिनों का एक और आसरा मज़दूरों के हाथ से जाता रहा। लोगों के पश्चिम की तरफ बसते चले जाने का दबाव कम करने में पहले चाहे कुछ भी अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा हो, किन्तु अब सीमा बन्द हो जाने का मतलब था कि अमरीका के इतिहास में एक बिल्कुल नया युग शुरू हो गया है। अवसर अब भी मिलते थे किन्तु पश्चिम में बस्तियाँ बसने के जमाने के मुकाबले बहुत थोड़े।

१८४० और १८५० के दशकों में ही मज़दूर यह अनुभव करने लगे थे कि उनकी काम की हालतें बिगड़ रही हैं किन्तु दक्ष कारीगर और मिस्त्री तब भी अपना वह स्तर कायम रख सके, जो विदेशी यात्रियों पर गहरा प्रभाव डालता था। अब जबकि काम की तलाश में अधिकाधिक मज़दूर कारखानों, मिलों और वर्कशापों में जा रहे थे तब वे अपनी पहले की आज़ादी बिल्कुल खो बैठे और वेतन भी पहले से कम हो गए। शहरों और कस्बों में, जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे कि मज़दूर उनमें खप नहीं पाते थे, साथ-साथ भीड़-भड़क्के में रहते हुए वे वेतनों में कटौती तथा बेकारी की निरन्तर विभीषिका में काम करते थे। कभी-कभी कुछ थोड़े से व्यक्तियों को अब भी आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ने का मौका मिल जाता था—अनेक उद्योगपति मज़दूरों में से ही बने—किन्तु ज़्यादातर मज़दूर चाहे विदेशी हों या स्वदेशी, मज़दूर की श्रेणी से ऊपर उठकर मालिक बन जाने और इस प्रकार सम्पन्न सामन्त वर्ग में शामिल हो जाने की आशा नहीं कर सकते थे। शिकागो के 'वर्किंगमेंस ऐडवोकेट' ने सन् १८६६ में ही कहा था कि "इस वृत्त में मज़दूरों के घुस आने की आशा करना उनको भुलावे में डाले रखना है, जिससे उनका ध्यान अपने वास्तविक हित की बातों से फिरा रहे।"

"प्रगति तथा गरीबी" का क्रूर विरोधाभास, जिसका १८७० के दशक में हेनरी जार्ज ने उल्लेख किया, तब भी कोई नई बात नहीं थी और समय के साथ-साथ वह ज़्यादा प्रत्यक्ष होती गई। आर्थिक विकास और विस्तार के तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता था और इसी प्रकार राष्ट्रीय आय बढ़ी और सामयिक दृष्टि से देश का जीवन-स्तर उन्नत हुआ। लेकिन तो भी करोड़ों आदमी घनी आबादी वाली गन्दी बस्तियों में अत्यन्त ग़रीबी की हालत में रहते थे। उनको प्रायः सामान्य सुख-सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती थीं, जिन्हें उनका श्रम दूसरों को सुलभ कराता था। वे सिर्फ़ अपने परिवारों को भूख और अभाव से मुक्त रखने के लिये संघर्ष करते रहते थे। जिनमें अब भी कोई विशेष दक्षता रह गई थी, उनके लिए यद्यपि परिस्थितियां कुछ अच्छी थीं, तो भी अधिकांश लोग बहुत थोड़े वेतन के लिए इतने ज़्यादा घण्टों तक करते थे कि उनकी स्थिति वाणिज्य तथा उद्योग की सबको दिखाई देने समृद्धि के साथ मेल नहीं खाती थी और अतएव दुःखदायी

मशीनों के सूत्रपात से जब मज़दूरों के काम के अधिकाधिक विभाग बन गए, और ज़्यादा से ज़्यादा काम अर्धदक्ष या अदक्ष श्रमिकों द्वारा किया जाने लगा तब मालिक पहले ज़माने के मिस्त्रियों और कारीगरों के बजाय 'अधकचरे' आदमियों को काम पर लगाने लगे। बाहर से आने वाले मज़दूर स्थानीय मज़दूरों की रोज़ी के लिए खतरा पैदा कर रहे थे और थोड़े-थोड़े दिनों बाद आने वाले बेकारी के भूत ने कारीगरों की एक ज़माने की सुरक्षा को खत्म कर दिया था। इसके अलावा जब वाणिज्य राष्ट्र-व्यापी बन गया तब विभिन्न निर्माण क्षेत्रों में प्रतियोगिता का अर्थ था कि मूल्य और वेतन अब स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक तय नहीं होंगे। आर्थिक परिवर्तनों के फल-स्वरूप जिन पर स्थानीय मालिकों या कर्मचारियों का कोई वस नहीं होता था, घटते-बढ़ते रहते थे।

इस नए राष्ट्रीय बाज़ार में, उदाहरणार्थ, ट्रॉय और पिट्सबर्ग, फिलाडेल्फिया अथवा डेट्रायट में स्टोव बनाने वालों को शिकागो और सेण्ट लुई में स्टोव बनाने वालों के साथ मुकाबला करना पड़ता था। पूर्व में वेतन दर पश्चिम के वेतन दरों से बंध गए। ट्राय या सेण्ट लुई में लोहे का सांचा बनाने वाले यदि मंदी के दिनों में अपने वेतनों में कटौती नहीं होने देना चाहते तो उन्हें केवल स्थानीय परिस्थितियों से आगे देखकर देश के अन्य भागों में अपने जैसे मज़दूरों के वेतन कायम रखने के उपायों पर गौर करना होता था।

इन नई परिस्थितियों में यह अधिकाधिक स्पष्ट हो गया कि मज़दूरों को राष्ट्र-व्यापी आधार पर अपना संगठन करके राष्ट्र-व्यापी उद्योग की चुनौती का स्वयमेव मुकाबला करना होगा। इसका मतलब था कि पहले-राष्ट्रीय यूनियनें बनाने की कोशिश की जाए, जिससे किसी धन्धे के मज़दूर किसी भी तरफ से आने वाली प्रतियोगिता से अपने वेतन दरों की रक्षा कर सकें। और दूसरे मालिकों के आपसी हितों के मुकाबले मज़दूरों के आपसी हितों का संगठन किया जाए। मज़दूरों के नए नेताओं ने संगठित पूंजीवाद की शक्ति का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय यूनियनों, राजनीतिक मज़दूर दलों, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य श्रमिक सुधार संगठनों का एक प्रकार का संयुक्त मोर्चा बनाने का यत्न किया तब मज़दूरों की एकता सर्वत्र चर्चा का विषय बनी हुई थी।

गृह युद्ध के तुरन्त बाद के वर्षों में इस राष्ट्रीव्यापी संगठन का निर्माण करने की कोशिश करते हुए भी मज़दूर औद्योगिक युग की नई ताकतों से इस प्रकार हक्के-बक्के हो रहे थे कि उन्हें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। उन्हें विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों में घसीटा गया, सुधार के नये वायदों से ठगा गया और वह समाजवादी सिद्धान्त तथा वर्ग संघर्ष के क्रांतिकारी विचारों के बारे में उठ रहे विवादों के चक्कर में फंस गया। आर्थिक कार्रवाई के मुक़ाबले राजनीतिक कार्रवाई के लाभों तथा व्यापक और बड़ी यूनियनों के मुकाबले कारीगरों की यूनियनें बनाने के लाभों पर निरन्तर बहसें होती रहती थीं।

अनेक बार श्रम-सम्मेलन में विचाराधीन महीन सिद्धान्तों की परवाह न करते हुए मज़दूरों ने बागडोर अपने हाथ में ले ली। पूंजीवादी शोषण की एड़ी के नीचे स्वयं को अधिकाधिक घिसता हुआ देखकर उन्होंने उस नेतृत्व की उपेक्षा कर दी जो आर्थिक परिस्थितियों की वास्तविकताओं से आँखें मूंदे हुए था और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यकायक विद्रोह कर दिया। गृह युद्ध से पहले हड़तालें, स्थानीय, अल्पकालीन और शांतिमय होती थीं किन्तु सदी के उत्तरार्ध में उनका स्वरूप बिल्कुल बदल गया। देश को व्यापक और उग्र औद्योगिक संघर्ष का सामना करना पड़ा।

श्रमिकों का एक राष्ट्रीय संगठन बनाने की दिशा में पहला कदम १८६६ में उठाया गया। कुछ यूनियन नेताओं ने जो १८३० के दशक में इसी प्रकार के आन्दोलनों को बिल्कुल भूल चुके थे, राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जिसे वे अमरीका में "अपनी किस्म का पहला" बतलाते थे। यह कांग्रेस बाल्टिमोर में की गई जिसमें विभिन्न स्थानीय यूनियनों, मज़दूर सभाओं तथा राष्ट्रीय यूनियनों के ७७ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का घोषित उद्देश्य समस्त मज़दूरों में एक नई एकता स्थापित करना था। राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन का निर्माण करते हुए इस बात की व्यवस्था की गई कि न केवल मौजूदा ट्रेड यूनियनों के दक्ष कर्मचारी ही बल्कि अदक्ष कर्मचारी और किसान भी उसके सदस्य बन सकें। अन्त में सब श्रमजीवी अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए उठ खड़े हुए और मालिकों को उनके

अधिकार कबूल करने की चुनौती देने लगे।

राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन शुरू से ही सुधारवादी और राजनीतिक विचारों की थी। सब मज़दूरों के लिए एक सामान्य कार्यक्रम बनाने का यह पहला प्रयत्न था, किन्तु इसमें अब भी गृह युद्ध से पहले का वही दिवास्वप्न दिखाई देता था कि औद्योगिक ज़माने की जुटती हुई ताकतों के बावजूद उत्पादक अपने मन चाहे समाज का निर्माण कर सकते हैं। सीमान्त समाज की स्वाधीनता और वैयक्तिकता ने १६ वीं सदी के अमरीकी मज़दूर के लिए, सभी साक्षियों के विपरीत होने के बावजूद यह मानना करीब-करीब असंभव कर दिया कि मज़दूरी कमाने वाले वर्ग का अस्तित्व स्थायी हो गया है।

राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के नेता काम की हालतों में तुरन्त सुधार के लिए संगठित ट्रेड यूनियन दबाव जैसे व्यावहारिक लक्ष्यों में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्होंने घोषणा की कि मज़दूर आन्दोलन ट्रेड यूनियनों पर निर्भर है और हर श्रमिक से किसी न किसी ट्रेड यूनियन में शामिल होने की अपील की। किन्तु बाल्टिमोर के सम्मेलन में उन्होंने राजनीतिक कार्रवाई को मज़दूरों के हितसाधन का सबसे प्रभावशाली साधन बताया और हड़तालों की उन्होंने तीव्र निन्दा की। राजनीतिक कार्रवाई के बजाय आर्थिक कार्रवाई करने के पक्षपाती मज़दूरों का तुरन्त ही एक राजनीतिक दल बनाने के प्रस्ताव को हराने में तो कामयाब हो गए तो भी सम्मेलन यह प्रस्ताव पास करने में सफल हो गया कि उपर्युक्त दल "यथा सम्भव जल्दी से जल्दी" कायम किया जाए।

"अमरीका के श्रमिकों के नाम एक सन्देश" में राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन के आम उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। इसमें मुख्यतः इस बात पर बल दिया गया कि मज़दूरों के लिए पहला लक्ष्य हर राज्य में ८ घण्टे का दिन प्राप्त करने का है। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे इस आन्दोलन का पहले के १० घण्टे के दिन के आन्दोलन से कहीं गहरा उद्देश्य था और कुछ समय तक लगा कि मज़दूरों की सब गतिविधियों पर यही मांग छायी हुई है। किन्तु राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन ने १८४० के दशक के आन्दोलन को पुनरुज्जीवित करते हुए उपभोक्ताओं और उत्पादकों, दोनों की सहकारी संस्थाएं स्थापित करने की कोशिश की और इनके लिए आसानी से पूंजी
८ कराने के खयाल से मुद्रा तथा बैंकिंग के सुधार के आन्दोलनों में ज्यादा

और ज्यादा दिलचस्पी ली। सन् १८६६ में सजायाफ़्ता मज़दूरों की भरती का खात्मा, अमरीकी श्रमिकों के स्तर को गिरने न देने के लिए आव्रजन को और विशेषकर पश्चिमी तट पर काम के लिए चीनी कुलियों के आव्रजन की रोक थाम, सार्वजनिक भूमि सिर्फ वास्तविक प्रवासियों को देने और राष्ट्रीय सरकार द्वारा एक श्रम विभाग की स्थापना किए जाने के अन्य लक्ष्य भी अपनाएं गए।

इन मुख्यत: राजनीतिक लक्ष्यों के साथ-साथ श्रमिकों के व्यापक संगठन के लिए भी अपील की गई। उद्योगों में महिलाओं का हित स्वीकार किया गया; नई यूनियन ने सिलाई करने वाली महिलाओं, फैक्ट्री मज़दूरनियों तथा अन्य श्रमिक महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से संगठित सहयोग प्रदान किया और महिला श्रमिकों की यूनियन ट्राय लाण्ड्री वर्कर्स की एक मुखिया को ऐसो-सियेशन का एक सहायक सचिव बना दिया गया। नीग्रों के संगठन को भी प्रोत्साहन दिया गया—किन्तु मज़दूर आन्दोलन में उनके सम्भावित योग को पहली बार स्वीकार करते हुए भी उन्हें राष्ट्रीय मजदूर यूनियन में शामिल करने के बजाय, उनसे अपनी अलग यूनियन बनाने को कहा गया।

इस नए संगठन के निर्माण से पहली बार राष्ट्रव्यापी आधार पर मज़दूरों का नेतृत्व पनपा और जिन व्यक्तियों ने इनकी हरकतों में प्रमुख भाग लिया उनमें अन्यतम विलियम एच० सिलविस थे, जिन्हें १८६८ में इसका अध्यक्ष चुना गया। उनको अध्यक्ष चुनने वाले सम्मेलन में भाग लेने वाले मज़दूर नेताओं पर टीका करते हुए 'न्यूयार्क सन' ने जब यह कहा कि "उनका नाम घर-घर में आदमियों की ज़बान पर रहता है" तो वह मानो इस बात की साक्षी दे रहा था कि सारे ही देश में उन्होंने कितनी ख्याति अर्जित कर ली थी।

इस समय सिलविस ४० वर्ष का, मध्यम आकार वाला मज़बूत, खूबसूरत रंग का हल्की दाढ़ी-मूछों वाला आदमी था जिसके "चेहरे और आँखों से सूझ-बूझ फूटी पड़ती थी।" शायद ही कोई मज़दूर नेता ऐसा होगा जो ध्येय के प्रति उससे ज्यादा एकनिष्ठ, मज़दूरों के लिए अपने सम्पूर्ण निजी स्वार्थ को होम कर देने वाला हो या जिसे अपने साथी कर्मचारियों की उनसे अधिक वफ़ादारी और स्नेह प्राप्त हो। उन्होंने वस्तुत: मज़दूरों के लिए स्वयं को खपा

दिया। एक बार उन्होंने कहा : "मुझे यूनियन का काम बहुत प्रिय है और मैं इसे अपने परिवार या ज़िन्दगी से भी प्यारा समझता हूँ मैं इसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने को तत्पर हू।"

मज़दूरों को क्या नीतियां अपनानी चाहिएँ, इस बारे में उनके विचार बहुत बदलते रहे। उनके विचार बहुत अनिश्चित तथा असंगत थे। किन्तु किसी ख़ास मौके पर उनकी टेक कुछ भी रही हो, वह बड़े उग्र होकर उसकी वकालत करते थे। एक बार उन्होंने अपने आलोचकों को दुमुंही झगड़ालू गिरोह कहा था—किन्तु उनके सबसे तीखे बाण हमेशा नए पूंजीवादी वर्ग के लिए रिज़र्व रहते थे, जिनके बारे में वह दृढ़ता से यह महसूस करते थे कि वे मज़दूरों का शोषण कर रहे हैं। इस वर्ग को वह पैसे के घमण्ड में चूर, अभिमानी, क्रोधी.....जिस किसी के साथ सम्पर्क में आया उसी को उड़ा देने या मुरझा देने वाला बताया।"

सिलविस एक वैगन-निर्माता का लड़का था और १८२८ में उसका अन्नोफ, पसिलवेनिया में उसका जन्म हुआ था। जब वह अभी लड़का ही था, तब उसने स्थानीय लोहे की फाउण्ड्री में काम किया था। १८४० के दशक में किसी समय उन्होंने अप्रैण्टिसशिप का कोर्स पास करके "आज़ादी का चोगा" पहना था और उन्होंने एक दहाड़िये मोल्डर की नई हैसियत प्राप्त की थी। वह बढ़िया गरम कोट, सफेद कमीज़, ऊनी मोज़े, मुलायम चमड़े के जूते और बढ़िया रेशमी हैट पहनते थे। फिलाडेलफिया में और उसके आस-पास अपना कारोबार जारी रखते हुए वह स्थानीय स्टोव और हौलोवेअर मोल्डर्स यूनियन में शामिल हो गए और तुरन्त एक सक्रिय मज़दूर संगठनकर्ता बन गए। सब मोल्डरों को एक ही संगठन में लाने की उनकी लगन थी और ज़्यादातर उन्हीं के प्रयत्नों से १८५९ में फिलाडेलफिया में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें १८ स्थानीय यूनियनों के ४६ प्रतिनिधियों ने नेशनल मोल्डर्स यूनियन की स्थापना की।

गृह-युद्ध छिड़ते ही यह ख़त्म हो गई और सिलविस स्वयं कुछ अरसे के लिए सेना में भरती हो गए। किन्तु सन् १८६३ में वह अपने मनपसन्द काम में फिर आ जुटे और पुनरुज्जीवित आइस मोल्डर्स इण्टरनेशनल यूनियन के [illegible] चुने गए। उन्होंने पूरे मनोयोग से इस संगठन का निर्माण किया और

अपने अथक उत्साह से उन्होंने नए तौर-तरीकों से मज़दूरों का संगठन किया। देश के इस पार से उस पार आते-जाते—जबकि उन्हें रेल-किराये के लिए पैसा पास न होने के कारण इंजन ड्राइवर के केबिन में बैठ जाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती थी एक के बाद एक शहर में वह स्थानीय मोल्डरों के ग्रुपों से मिले और उन्हें स्थानीय यूनियन बनाने में सहायता दी तथा राष्ट्रीय यूनियन का उन्हें सदस्य बनाया। १८६४ में वार्षिक सम्मेलन के लिए लौटते हुए वह यह दम भर सके कि "एक वर्ष के अल्प काल में ही हमारी यूनियन पिद्दी से दैत्याकार बन गई है।" ५३ स्थानीय यूनियनों और कुल ७,००० सदस्यों (जो शीघ्र ८५०० हो गए) वाली आयरन मोल्डर्स इण्टरनेशनल यूनियन १८६५ तक देश भर में सबसे मज़बूत सुसम्बद्ध संगठन बन गया।

इस ज़माने में जब सिलविस इतनी अधिक यात्राएं किया करते थे और न्यू इंग्लैंड, समुद्र तट के राज्यों, मिडवेस्ट और कनाडा में इतने अधिक श्रमिकों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क में आए तो वह उसे अपनी ज़िन्दगी का सबसे सुखी काल समझा करते थे। किन्तु जो थोड़ी-बहुत पूंजी उनके पास थी वह इसमें ख़त्म हो गई और वह मोल्डरों द्वारा दी गई तुच्छ राशियों पर निर्भर हो गए। इन दिनों का वर्णन करते हुए उनके भाई लिखते हैं कि वे अपने कपड़ों को तब तक नहीं छोड़ते थे, जब तक वे फटकर तार-तार नहीं हो जाते थे। जो शाल उन्होंने अपने मृत्यु-दिवस तक पहने रखा वह छोटे-छोटे छेदों से भरा पड़ा था। ये छेद अनजान शहरों में मोल्डरों के, जिसका संगठन करने की वह कोशिश कर रहे थे कलछों से पिघले हुए लोहे के छिटक कर गिर जाने से हुए थे।"[४]

सिलविस ने जिस योग्यता से संगठन किया प्रशासन भी उसी योग्यता से किया। नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से राष्ट्रीय यूनियन में केन्द्रित था, यूनियन के सब सदस्यों पर प्रति व्यक्ति टैक्स लगा हुआ था जिससे पर्याप्त बड़ा हड़ताल कोष स्थापित हो गया और यूनियन कार्ड जारी करने से और मज़दूर अखबारों में मज़दूरों के साथ दगा करने वालों के चित्र छपने से बन्द कारखाना प्रणाली को अपनाया जाना संभव हुआ। सिलविस का सामूहिक सौदेबाजी में बहुत विश्वास था और वह हड़तालों को प्रोत्साहन नहीं देता था किन्तु जब मज़दूरों के पास हड़ताल के सिवा कोई चारा नहीं रहता था तो वह उनका

पूरी तरह समर्थन करने को तैयार रहता था ।......"तब परिणाम इस बात पर निर्भर करता था कि कठोरतम प्रहार कौन कर सकता है ।"

१८६७-६८ के जाड़ों तक मोल्डर्स यूनियन की नीतियां सब कहीं सफल रहीं किन्तु उस कठिन मौसम में राष्ट्रीय स्टोव निर्माता और आयरन फाउण्डर्स ऐसोसियेशन ने पूरी शक्ति से जवाबी प्रहार किया । वेतनों में कटौती की गई और यूनियन के सदस्यों को खाली बिठा दिया गया । जब मज़दूरों ने हड़ताल की तो मालिक इतने मजबूत हो गए थे कि उन्होंने तालाबन्दी कर दी । संघर्षरत मोल्डर महीनों तक यथाशक्ति लड़े किन्तु उनका हड़ताल कोष समाप्त हो गया और अन्त में आन्तरिक कलह ने उनके संयुक्त मोर्चे को तोड़ डाला और वे मालिकों की शर्तों पर वापस काम पर आने लगे । सिलविस ने यूनियन को बिल्कुल नेस्तनाबूद होने से तो बचा लिया किन्तु हड़ताल विफल हो जाने से उसका पहले की सी शक्ति और प्रभाव जाता रहा ।

इस अनुभव से वह इतना निरुत्साहित हुआ कि वह अपना अधिक से अधिक ध्यान ट्रेड यूनियनवाद से हटाकर सामान्य श्रम-सुधारों की ओर देने लगा और इस प्रकार नई राष्ट्रीय मजदूर यूनियन में अपने कार्य के लिए व्यापक क्षेत्र पाया । वह यूनियन संगठन को, कानून द्वारा काम का दिन ८ घण्टे का कराने के आन्दोलन को, सहकारी संस्थाओं के निर्माण तथा मुद्रा सुधार को पहले की ही भांति जोर-शोर से अपना समर्थन प्रदान करने को तैयार था । अपने पहले के विचारों से पीठ फेर कर उसने अपना सारा प्रभाव इन सुधारों को राजनीतिक कार्रवाई से प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मजदूर यूनियन की नई विचारधारा के पोषण में लगा दिया"। इसका अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले परिपत्र में उसने कहा : "हमारा नारा सुधार हो... सम्पन्न सामन्तशाही मर्दाबाद, आम जनता जिन्दाबाद ।"

राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन की बैठकों से यह साफ जाहिर हो गया कि वह राजनीतिक सुधारों की ओर ज्यादा झुकती जा रही है । जो प्रतिनिधि १८६८ के सम्मेलन में हाजिर हुए (महान औद्योगिक प्रश्नों पर जिनके दार्शनिक और राजनीतिज्ञतापूर्ण विचारों की न्यूयार्क हैरल्ड ने बहुत तारीफ की थी) वे ८ घंटे की लीगों, भूमिसुधार ऐसोसियेशनों, एकाधिकार विरोधी सोसाइटियों अन्य अनेक राजनीतिक ध्येयों का प्रतिनिधित्व करते थे । उनमें प्रमुख दो

महिलाओं को मतदान का अधिकार देने के कट्टर समर्थक एलिजाबेथ केडी सैण्टन और सूसान बी-एन्थनी थे। उनकी उपस्थिति ने तहलका मचा दिया, क्योंकि यद्यपि सिलविस और अन्य नेता महिलाओं को मताधिकार दिए जाने का समर्थन करते थे, तो भी सामान्यत: प्रतिनिधिगण इतनी दूर तक जाने को तैयार नहीं थे। मताधिकार के हिमायती नेताओं को उन्होंने सम्मेलन में केवल तभी आने देना मंजूर किया जब उन्होंने उन नेताओं को स्पष्ट बता दिया कि उन्हें आने देने का मतलब यह नहीं है कि उनके "विचित्र विचारों" का वे समर्थन करते हैं। तो भी हैरल्ड ने देखा कि मिस ऐन्थनी "बड़े मजे से उक्सा रही थी और दढ़ियल प्रतिनिधियों पर उसने अपनी कोई कम छाप नहीं छोड़ी।"

इसी सम्मेलन में राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन ने एक कदम उठाया जिससे स्पष्ट यह पता चलता था कि आगे चलकर यह एक तीसरा दल बन जाएगा। इसने कई राज्यों में मज़दूर सुधार दलों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया और उनसे सीधी राजनीतिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। ट्रेड यूनियनिस्टों ने यह देखा कि उनके हित तो ज्यादा और ज्यादा उपेक्षित होते जा रहे हैं और ऐसी चीजें उनका स्थान ले रही हैं, जिनके साथ उनका अगर सम्बन्ध है तो बिल्कुल परोक्ष है। गृह युद्ध से पहले की मज़दूर कांग्रेसों का पुराना इतिहास दोहराया जा रहा है। राष्ट्रीय मज़दूर यूनियनके मामले में प्राप्त तजुर्बे में सिर्फ इतना ही फर्क था कि उस पर सुधारवादियों का (आनन्ददायक ढंग से उकसाने वाली मिस ऐंथनी के बावजूद) कब्जा उतना नहीं था जितना मज़दूर नेताओं का जो स्वयं सुधारक बन गए थे। सिलविस इस रुझान का ज्वलन्त उदाहरण था किन्तु अन्य लोग भी जो कभी ट्रेड यूनियनवादी रहे थे १८६० के दशक की समाप्ति तक सुधार तथा राजनीतिक गतिविधियों के कम उत्साही समर्थक नहीं रह गए थे।

सिलविस के अध्यक्ष चुने जाने पर राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन को जो ताकत मिली वह बहुत थोड़ी देर रही। १८६९ में इसके वार्षिक सम्मेलन से कुछ ही पहले उनका अचानक देहान्त हो गया। मज़दूर आन्दोलन पर यह प्रबल आघात था और इसने "सब श्रमिकों पर निराशा का पर्दा डाल दिया। शायद ही कोई यूनियन ऐसी हो जिसने सिलविल की प्रशंसा में प्रस्ताव पास न किए

हों, और अपने यशस्वी जीवन के चरम शिखर पर पहुँचे हुए एक महान नेता की अपूर्णीय क्षति पर श्रमिकों के पत्रों में असंख्य अग्रलेख लिखे गए। 'वर्किंगमेंस ऐडवोकेट' काले वार्डर में प्रकाशित हुआ।

यूरोप में इण्टरनेशनल वर्किंगमेंस ऐसोसियेशन के नेताओं से भी शोक संदेश प्राप्त हुए। यह पहला अन्तर्राष्ट्रीय संगठन था जिसके साथ सिलविल ने "गरीबी और अमीरी के बीच संघर्ष के लिए" गठबन्धन करने की कोशिश की थी। एक पत्र में, जिस पर अन्य लोगों के अलावा कार्ल मार्क्स के भी दस्तखत थे, कहा गया कि संसार ऐसे परखे हुए चैम्पियनों की अकाल मृत्यु को, जिस पर हम सबको समान रूप से अत्यन्त शोक है, सहन नहीं कर सकता।"

सिलविस ने मज़दूरों के लिए कितना कुछ किया इसका पता मोल्डर्स इण्टरनेशनल यूनियन के निर्माण में उनके उत्साह से और राष्ट्रीय मंच पर मज़दूरों के अधिकारों के हक में उनके प्रभावशाली समर्थन से पता चलता है। उन्होंने स्वयं को मज़दूरों का सच्चा प्रवक्ता बना लिया था और उनकी वाणी का आदर किया जाता था। उनका जीवन यद्यपि अल्प रहा तो भी वह देश के पहले राष्ट्रीय नेता थे।

वह यदि और जिन्दा रहते तो राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन का इतिहास अब से ज़्यादा भिन्न होता, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके जीवित रहते हुए ही यह यूनियन एक संदिग्ध राजनीतिक रेखा को छूने लगी थी और सिलविस ने सुधार के लिए इसकी शक्तियों के भटकाव को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा ही दिया था। कुछ भी हो, इसके दिन गिने-चुने रह गये थे। सिलविस के साथी और जहाज बनाने का काम करने वाले कर्मचारियों की अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन के मुखिया रिचर्ड एफ० ट्रैवलिक अब इस यूनियन के नए अध्यक्ष बन गए थे। उनकी भी दिलचस्पी शुरू-शुरू में ट्रेड यूनियनवाद से हटकर राजनीति पर केन्द्रित हो रही थी। उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन ने अन्तिम छलाँग लगाई और १८७२ के वार्षिक सम्मेलन में यह राष्ट्रीय मज़दूर सुधार पार्टी बन गई। एक कार्यक्रम स्वीकार किया गया, जिसमें मुख्यतः मुद्रा-सुधार पर बल दिया गया और इलिनायस के जज डेविड डेविस को अध्यक्ष नामज़द किया गया। जब डेविस ने अपना नाम

५स ले लिया तो राजनीतिक आन्दोलन बिल्कुल ठण्डा पड़ गया और उसके

ठण्डा पड़ते ही राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन के दिन भी समाप्त हो गए।

राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन यद्यपि इतनी अल्पकालीन और असफल रही तो भी उससे संबन्धित कुछ बातों पर ज्यादा रोशनी डालने की जरूरत है। इनमें पहली चीज़ ८ घण्टे के दिन के लिए कानून बनवाने का आन्दोलन है, जिसे १८६६ में "सबसे अहम सवाल घोषित किया और जिस पर अब भी अमरीकी श्रमिकों का ध्यान केन्द्रित है।" यह उन सिद्धान्तों पर आधारित था जो उन पुरानी युक्तियों से भी ज्यादा गहरी थीं, जिनमें काम के कम घण्टों का समर्थन मज़दूरों के स्वास्थ्य-सुधार चरित्र-सुधार तथा उनको शिक्षा के लिए अधिक समय प्रदान करने की दृष्टियों से किया गया था। इसके हामियों के मुताबिक ८ घंटे के दिन का उद्देश्य मज़दूरों के वेतन और हैसियत दोनों को बढ़ाकर समाज के वर्तमान गठन को बदलना और इस प्रकार शनैः-शनैः मालिक और मजदूर के बीच खाई को कम करते-करते "पूंजीपति और श्रमिक को एक कर देना था।"

८ घण्टे के दिन के लिए मुख्य आन्दोलनकारी बोस्टन का एक मशीन चालक तथा यूनियन का वफादार सदस्य इरा स्टीवर्ड था, जिसको यह गहरा विश्वास था कि उसके विचारों में मज़दूरों की सब समस्याओं का हितनिहित है और उन विचारों को उसे हर समय और हरेक स्थान पर प्रचारित करने से नहीं रोका जा सकता था, इसे वह अपना मिशन समझता था। 'अमेरिकन वर्कमैन' में एक लेखक ने लिखा; "सड़क पर चलते हुए आप किसी भी दिन उससे मिलिये; उस समय यदि आप कोई और बात उससे करेंगे तो वह कन्नी काट जाएगा...किन्तु जरा काम के घण्टों की बात छेड़कर देखिए और उसकी बात सुनने की इच्छा का इजहार कीजिए, तो वह रुक जाएगा और आपको अंधेरा होने तक अपनी बात समझाता रहेगा।"

८ घण्टे के दिन के बारे में उसने मज़दूरों की अनगिनत सभाओं में भाषण दिए, मैसाच्युसेट्स विधानमण्डल के समक्ष गवाही दी, मज़दूरों के अखबारों के लिए पैम्फलेट और लेख लिखे और पहले मज़दूर सुधार ऐसोसियेशन की और बाद में ग्रैण्ड एट अवर लीग आव मैसाच्युसेट्स की स्थापना की। उसके विचारों ने मज़दूरों के मस्तिष्क को जकड़ लिया। ८ घण्टे की लीगें सब कहीं कायम हो गईं और राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन उसके कार्यक्रम को

अपना कर मज़दूरों के काम के दिन में इस प्रस्तावित कमी में राष्ट्रव्यापी दिलचस्पी को प्रकट कर रही थी।

स्टीवर्ड का मूल सिद्धान्त स्पष्ट ही उन विचारों और आचरणों का आख्यान करता था, जिन्हें २० वीं सदी में और ज्यादा व्यापक रूप में स्वीकार कर लिया गया। उसका कहना था कि काम का दिन घटा कर ८ घण्टे कर देने से वेतनों की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। मज़दूर १० या १२ घण्टे काम करके जो मज़दूरी प्राप्त करते थे, कम से कम उतनी मज़दूरी तो वे ८ घण्टे के दिन में भी मांगेंगे और चूंकि यह मांग सर्वव्यापी होगी इसलिए मालिकों के पास इससे इन्कार करने का कोई युक्तियुक्त आधार न होगा।" इसका अगर मालिक प्रतिरोध करेंगे तो उसका यही अभिप्राय होगा कि संसार में प्रबलतम शक्ति के खिलाफ यानी आराम की आदतों, रीति-रिवाजों और विचारों के खिलाफ वे स्वयं 'हड़ताल' की बेवकूफी करेंगे।" जब मज़दूरों को खाली समय ज्यादा मिलेगा, तब वे ज्यादा आनन्द मनाने की स्थिति में होंगे, फलस्वरूप उद्योगों का माल ज्यादा तादाद में खरीदना चाहेंगे। इस तथ्य पर बल देते हुए कि "किसी वस्तु को बनाने की लागत उसकी बनाए जाने वाली संख्या पर निर्भर करती है," स्टीवर्ड ने कहा कि निर्माताओं को अपने बाजार के विस्तार से तुरन्त लाभ होगा, क्योंकि जो चीजें कभी ऐश्वर्य की निशानी रही होंगी उन्हें बड़ी संख्या में श्रमिकों को बेचा जा रहा होगा।

मुख्य बात, जिस पर स्टीवर्ड ने बल दिया, यह थी कि काम के घण्टे वेतन में कटौती किए बिना कम किए जा सकते हैं यह विचार एक लोकोक्ति बन गया, जिसे उसकी पत्नी का बताया जाता है :

> चाहे तुम प्रति वस्तु के आधार पर काम
> करो या दिहाड़ी पर, काम के घण्टे कम
> करने से तनख्वाह बढ़ती है।

यह एक बड़ा प्रश्नचिन्ह था कि क्या मालिक इस आशा से कि उनके माल के लिए क्रयशक्ति का निर्माण होगा, कानून द्वारा प्रतिपादित ८ घण्टे के दिन के लिए वस्तुतः पहले जितना वेतन देंगे या नहीं। किन्तु पूंजीवादी

का एक नया उत्साह पैदा हुआ और राष्ट्रीय मजदूर यूनियन ने इसका पूर्णतः समर्थन किया। १८४० के दशक की अपेक्षा इस आंदोलन से ज्यादा आशाएं की गई थीं। सहकारिताओं के प्रवर्तक ८ घण्टे के दिन के समर्थकों की भांति यही समझते थे कि उनकी योजनाओं से समाज का नव-निर्माण हो जाएगा। हर व्यवसाय में उत्पादकों की सहकारी संस्थाएं बनाकर श्रमिकों से आत्म-नियोजन की एक ऐसी प्रणाली अपनाने के लिये कहा गया, जिससे अन्ततो-गत्वा वेतन-प्रणाली खत्म हो जाए, उद्योग के लाभ के न्यायपूर्ण वितरण के लिए व्यावहारिक साधन उपलब्ध हों और जो मजदूरों को पूंजी के बन्धन से बिल्कुल मुक्त कर दे।

सिलविस ने आयरन मोल्डरों की सहकारी संस्थाएं बनाकर स्वयं इस आन्दोलन का नेतृत्व किया। उनकी स्थानीय यूनियनों ने न केवल ट्राय, रोचे-स्टर, शिकागो, क्लीवलैण्ड, लुईसविल और अन्य शहरों में अपनी फाउण्ड्रियां चलाईं किन्तु हड़ताल के अपने कड़वे अनुभवों के बाद राष्ट्रीय यूनियन १८६८ स्वयं एक सहकारी संस्था बन गई। अपना नाम यकायक आयरन मोल्डर्स इण्टरनेशनल को-आपरेटिव ऐण्ड प्रोटैक्टिव यूनियन रखकर इसने पिट्सबर्ग में १५,००० डालर की लागत से एक विशाल फाउण्ड्री लगाने का बड़ा काम शुरू किया। १८६८ में एक समय इस कार्यक्रम के प्रति सिलविस इतना उत्साही रहा कि वह इसको सफल बनाने के लिये सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार प्रतीत हुआ। उसने कहा: "समय आ गया है, जब हमें हड़तालों की समस्त परिपाटी को छोड़कर सहकारिता को अपने संगठन का आधार तथा अपने सब प्रयत्नों का प्रमुख लक्ष्य बनाना चाहिए।"

अन्य यूनियनों ने मोल्डरों का अनुकरण किया। मशीन चालकों ने ज्वाइण्ट स्टाक आधार पर कई वर्कशाप कायम किए, मोचियों ने उत्पादक तथा उप-भोक्ता दोनों की सहकारी संस्थाएं बनाईं, टीन की चद्दरों का काम करने वालों ने मिन्नीपोलिस में ८ कारखाने लगाए और बेकरों, मुद्रकों, हैट बनाने वालों, खातियों तथा जहाज बनाने वालों ने भी ऐसी ही परियोजनाएं चालू कीं।

कुछ समय तक तो ये सहकारी संस्थाएं सफल होती दिखाई दीं, किन्तु धीरे-धीरे एक-एक करके वे फेल हो गईं। व्यावसायिक समाज ने उन्हें "कम्यूनिज़्म के फ्रांसीसी सिद्धान्त" बताकर उनका कड़ा विरोध किया और उन्हें

गला-काट प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। किन्तु वास्तविक मुसीबत उनका अपना व्यवसाय चलाने का ढंग ही था। यूनियन के अधिकारियों में प्रबन्ध कुशलता नहीं थी और सहकारी संस्थाएं बड़ी अयोग्यता से और कभी-कभी बेईमानी से चलाई जा रही थीं जिससे उनकी कठिनाइयां बढ़ती चली गईं। इसके अतिरिक्त एक मूल बाधा यह थी कि उस ज़माने में जबकि किसी भी उत्पादक व्यवसाय के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी लगाना आवश्यक हो गया था, यूनियनों के पास पैसे की कमी थी और उन्हें ऋण मिलना वस्तुतः असम्भव था।

इसी कारण राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन ने अपना ध्यान मुद्रा-सुधार की ओर मोड़ा और उसे मज़दूरों की सहायता के लिए एक बुनियादी बात बताया। ऊपर से देखने पर यह आन्दोलन जो गृह-युद्ध में चलाई गई मुद्रा के वापस लेने के प्रस्ताव से उत्पन्न हुआ था इस मांग तक ही सीमित प्रतीत होता था कि गिरती हुई कीमतों को रोकने के लिए मुद्रा-प्रसार की नीति अपनाई जाए। जिन दिनों में मज़दूर द्रव्य को मंहगा बनाने की माँग किया करते थे, उनके मुकाबले आज की मांग एक विचित्र-सी मांग प्रतीत होती थी किन्तु मुद्रा सुधार के पीछे निहित सिद्धान्तों का महज़ मूल्य स्तर में परिवर्तन से कहीं गहरा तात्पर्य था। इस प्रश्न पर मज़दूर किसानों से मिल गए, क्योंकि इसमें समस्त वित्तीय और आर्थिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन के सब्ज़ बाग दिखाए गए थे। ८ घण्टे के दिन और सहकारिता के समान ही मुद्रा-सुधार का आंदोलन भी पूंजीवाद की जगह उत्पादकों का कामनवेल्थ स्थापित करने की आशा रखता था।

नई मुद्रा-प्रणाली के लिए अपने विचार अधिकांश में १८४८ में एडवर्ड केलोग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों से लेकर मुद्रा सुधारकों ने सार्वजनिक ऋण को ३ प्रतिशत ब्याज के बौण्डों में तब्दील कराने का अनुरोध किया जो सोने के बजाय देश की भौतिक सम्पदा के आधार पर खड़ी कानूनी मुद्रा में इच्छानुसार परिवर्तनीय हो। यह ख्याल किया गया कि इस कार्यक्रम से "गैर-जिम्मेदार बैंकिंग ऐसोसियेशनों" का एकाधिकार टूट जाएगा और "ब्याज की ऊँची दर से होने वाली लूट" बन्द हो जाएगी और आर्थिक प्रणाली सोने पर निर्भर रहने के बन्धन से मुक्त हो जाएगी, जिस बन्धन के कारण "मज़दूर की खून-पसीने की

का एक नया उत्साह पैदा हुआ और राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन ने इसका पूर्णतः समर्थन किया। १८४० के दशक की अपेक्षा इस आंदोलन से ज़्यादा आशाएं की गई थीं। सहकारिताओं के प्रवर्तक ८ घण्टे के दिन के समर्थकों की भांति यही समझते थे कि उनकी योजनाओं से समाज का नव-निर्माण हो जाएगा। हर व्यवसाय में उत्पादकों की सहकारी संस्थाएं बनाकर श्रमिकों से आत्म-नियोजन की एक ऐसी प्रणाली अपनाने के लिये कहा गया, जिससे अन्ततोगत्वा वेतन-प्रणाली खत्म हो जाए, उद्योग के लाभ के न्यायपूर्ण वितरण के लिए व्यावहारिक साधन उपलब्ध हों और जो मज़दूरों को पूंजी के बन्धन से बिल्कुल मुक्त कर दे।

सिलविस ने आयरन मोल्डरों की सहकारी संस्थाएं बनाकर स्वयं इस आन्दोलन का नेतृत्व किया। उनकी स्थानीय यूनियनों ने न केवल ट्राय, रोचेस्टर, शिकागो, क्लीवलैण्ड, लुईसविल और अन्य शहरों में अपनी फाउण्ड्रियां चलाईं किन्तु हड़ताल के अपने कड़वे अनुभवों के बाद राष्ट्रीय यूनियन १८६८ स्वयं एक सहकारी संस्था बन गई। अपना नाम यकायक आयरन मोल्डर्स इण्टरनेशनल को-आपरेटिव ऐण्ड प्रोटैक्टिव यूनियन रखकर इसने पिट्सबर्ग में १५,००० डालर की लागत से एक विशाल फाउण्ड्री लगाने का बड़ा काम शुरू किया। १८६८ में एक समय इस कार्यक्रम के प्रति सिलविस इतना उत्साही रहा कि वह इसको सफल बनाने के लिये सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार प्रतीत हुआ। उसने कहा : "समय आ गया है, जब हमें हड़तालों की समस्त परिपाटी को छोड़कर सहकारिता को अपने संगठन का आधार तथा अपने सब प्रयत्नों का प्रमुख लक्ष्य बनाना चाहिए।"

अन्य यूनियनों ने मोल्डरों का अनुकरण किया। मशीन चालकों ने ज्वाइण्ट स्टाक आधार पर कई वर्कशाप कायम किए, मोचियों ने उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों की सहकारी संस्थाएं बनाईं, टीन की चद्दरों का काम करने वालों ने मिन्नीपोलिस में ८ कारखाने लगाए और बेकरों, मुद्रकों, हैट बनाने वालों, खातियों तथा जहाज़ बनाने वालों ने भी ऐसी ही परियोजनाएं चालू कीं।

कुछ समय तक तो ये सहकारी संस्थाएं सफल होती दिखाई दीं, किन्तु धीरे-धीरे एक-एक करके वे फेल हो गईं। व्यावसायिक समाज ने उन्हें "कम्यूनिज़्म के फ्रांसीसी सिद्धान्त" बताकर उनका कड़ा विरोध किया और उन्हें

गला-काट प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। किन्तु वास्तविक मुसीबत उनका अपना व्यवसाय चलाने का ढंग ही था। यूनियन के अधिकारियों में प्रबन्ध कुशलता नहीं थी और सहकारी संस्थाएं बड़ी अयोग्यता से और कभी-कभी बेईमानी से चलाई जा रही थीं जिससे उनकी कठिनाइयां बढ़ती चली गईं। इसके अतिरिक्त एक मूल बाधा यह थी कि उस ज़माने में जबकि किसी भी उत्पादक व्यवसाय के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी लगाना आवश्यक हो गया था, यूनियनों के पास पैसे की कमी थी और उन्हें ऋण मिलना वस्तुतः असम्भव था।

इसी कारण राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन ने अपना ध्यान मुद्रा-सुधार की ओर मोड़ा और उसे मज़दूरों की सहायता के लिए एक बुनियादी बात बताया। ऊपर से देखने पर यह आन्दोलन जो गृह-युद्ध में चलाई गई मुद्रा के वापस लेने के प्रस्ताव से उत्पन्न हुआ था इस मांग तक ही सीमित प्रतीत होता था कि गिरती हुई कीमतों को रोकने के लिए मुद्रा-प्रसार की नीति अपनाई जाए। जिन दिनों में मज़दूर द्रव्य को मंहगा बनाने की माँग किया करते थे, उनके मुकाबले आज की मांग एक विचित्र-सी माँग प्रतीत होती थी किन्तु मुद्रा सुधार के पीछे निहित सिद्धान्तों का महज़ मूल्य स्तर में परिवर्तन से कहीं गहरा तात्पर्य था। इस प्रश्न पर मज़दूर किसानों से मिल गए, क्योंकि इसमें समस्त वित्तीय और आर्थिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन के सब्ज़ बाग दिखाए गए थे। ८ घण्टे के दिन और सहकारिता के समान ही मुद्रा-सुधार का आंदोलन भी पूंजीवाद की जगह उत्पादकों का कामनवेल्थ स्थापित करने की आशा रखता था।

कमाई पालने से लेकर कब्र तक रेहन ही रहती है।"

मजदूरों को उनके स्वाभाविक अधिकार दिलाने की यह अन्तिम अचूक दवा थी। राष्ट्रीय मजदूर यूनियन ने सुपरिचित वाक्यावलि में कहा : "इस से अनुत्पादक पूंजी तथा श्रम के बीच श्रम के उत्पादन का न्यायोचित वितरण होगा, मजदूरों को अपने श्रम का उचित मुआवज़ा मिलेगा और पूंजी को उचित पुरस्कार। इससे अत्यधिक श्रम की आवश्यकता भी जाती रहेगी और औद्योगिक वर्गों को सामाजिक तथा बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक समय और साधन उपलब्ध होंगे।"

एक बार फिर सिलविस जो बारी-बारी से ट्रेड यूनियनवाद, ८ घण्टे का आन्दोलन और सहकारिता में बहता रहा इस सुधार के आन्दोलन को ज़ोर-शोर से चलाने लगा। उसने लिखा : "अमरीका में लगभग ३००० मजदूर यूनियनें हैं। हमें उन्हें दिखाना चाहिए कि जब एक न्यायपूर्ण मुद्रा-प्रणाली कायम हो जाएगी तब ट्रेड यूनियन की आवश्यकता नहीं होगी।"

किन्तु इस कार्यक्रम को अपनाने से और मुद्रा-सुधार के राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने से ही राष्ट्रीय मजदूर यूनियन ट्रेड यूनियनिस्टों का सहयोग खो बैठी और १८७२ में एक राजनीतिक आन्दोलन का प्रयत्न करने के बाद खत्म हो गई। तो भी किसानों और मजदूरों दोनों में मुद्रा-सुधार के कट्टर पक्षपाती अब भी बचे रह गए थे और बाद के वर्षों में कानूनी टेण्डर-मुद्रा तथा परिवर्तनीय बाण्ड की मांग पर जोर देने के लिए सारे देश में स्थानीय मुद्रा सुधार पार्टियां बनीं। अन्ततोगत्वा इन दलों से मिलकर एक राष्ट्रीय मुद्रा सुधार मजदूर दल कायम हुआ और १८७८ के मध्यवर्ती चुनावों में उसे १० लाख से अधिक वोटें प्राप्त करने तथा १४ प्रतिनिधि कांग्रेस में भेजने में सफलता मिली।

इस पार्टी द्वारा डाले गये दबाव से ग्रीन बैक मुद्रा की ओर वापसी रुकने में तो सहायता मिली किन्तु जिन बुनियादी चीजों के लिए मुद्रासुधार के हिमायतियों ने आन्दोलन किया वे दरगुजर कर दी गईं। १८७८ के रिज़म्पशन ऐक्ट में बचे-खुचे नोट सोने में परिवर्तनीय बना दिए गए। इस कदम के उठाए जाने के बाद ग्रीन बैक मजदूर पार्टी जिसने अस्थायी रूप से मज़दूरों और किसानों को एक संयुक्त कार्यक्रम के लिए मिला दिया प्रतीत होता था, शीघ्र

लुप्त हो गई। मुद्रा-सुधार को मज़दूर नेताओं का तो समर्थन प्राप्त था किन्तु इसमें शक है कि सामान्य मज़दूरों में उससे कोई विशेष उत्साह पैदा हुआ हो। इसके परिणामों को वे समझ नहीं सकते थे। और इसका उन्होंने जितना भी समर्थन किया वह इस लिए कि मौजूदा परिस्थितियों के खिलाफ वे अपना असन्तोष जाहिर करना चाहते थे तथा ऐसे किसी भी प्रोग्राम को स्वीकार करने के लिए उत्सुक थे, जो उन्हें राहत प्रदान करने का वचन देता हो।

१८७२ में राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन के खात्मे के बाद एक ऐसा नया संगठन बनाने की कोशिशें की गईं, जो राजनीति से अछूता रह कर मज़दूरों को फिर से ट्रेड यूनियनवाद और आर्थिक कार्रवाई के सीधे रास्ते पर ले जाए। १८७३ और १८७५ के बीच अनेक औद्योगिक कांग्रेसें की गईं जिनके प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि "आज की सब से बड़ी जरूरत, ८ घण्टे के दिन की, मुद्रा सुधार की या अन्य सुधार की नहीं बल्कि उत्पादक जनसमूह के संगठन, शक्ति संचय और सहकारी प्रयत्न की है।" इन्ही सामान्य उद्देश्यों के लिए 'इण्डस्ट्रियल ब्रदरहुड' तथा 'सौवरेन्स आव इण्डस्ट्री' नाम से दो गुप्त सोसाइटियां भी बनाई गईं। किन्तु ये प्रयत्न कुछ नेताओं द्वारा मज़दूरों पर ऊपर से एक प्रकार का नियंत्रण थोपने की कोशिशें ही थीं और वस्तुतः उन्हें पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं था। बहस और विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करने के अलावा उनकी और कोई उपयोगिता नहीं थी।

इसके अतिरिक्त इस समय की आर्थिक परिस्थितियों ने एक बार फिर मज़दूर आन्दोलन के तले से ज़मीन खिसका दी थी और किसी प्रभावशाली कार्रवाई के मार्ग में अलंघ्य बाधाएं खड़ी कर दी थीं। १८७३ में देश में ऐसा आतंक फैला कि १८३० के दशक से भी ज़्यादा भीषण मन्दी का दौर-दौरा चला। गिरती हुई कीमतों, व्यवसाय के तरक्की न करने, उत्पादन और वेतनों में कटौती तथा बेकारी की वही पुरानी कहानी दोहरायी गई। खान, मिलों व कारखानों ने जैसे-जैसे अपना कारोबार घटाया या वे बन्द हो गए, वैसे ३० व्यक्ति बेकार हो गए। इस कठिन समय ने न केवल राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन तथा औद्योगिक कांग्रेसों जैसे मज़दूर-एकता के अस्पष्ट प्रयत्नों को एकदम खत्म कर दिया बल्कि विद्यमान राष्ट्रीय यूनियनों को बिलुल तहस-

नहस कर दिया। वेतनों में कटौती और बढ़ती हुई वेकारी के दारुण प्रहारों को वे उसी प्रकार नहीं सह सकीं, जैसे ४० वर्ष पूर्व की यूनियनें जिनसे बड़ी आशएँ थीं। १८३७ के आतंक के विध्वंसात्मक परिणामों को झेलने में असफल रहीं।

जब संकट आया तब कोई ३० राष्ट्रीय यूनियनें थीं। १८७७ में लेवर स्टैण्डर्ड ने सिर्फ ६ की सूची प्रकाशित की और यूनियन के सदस्य-मज़दूरों की कुल संख्या ३ लाख से घट कर शायद ५० हजार रह गई। एक के बाद दूसरी यूनियन का यही अनुभव रहा। 'दि नाइट्स आव सेण्ट क्रिस्पिन' जूता बनाने वालों का एक विलक्षण संगठन था, जो औद्योगिक आधार पर स्थापित किया गया था, जिसके जल्दी ही ५० हजार सदस्य बन गए और जो एक के बाद एक हड़ताल करके "बन्द कारखाना" पद्धति को लागू कराने में आश्चर्य-जनक रूप से सफल रहा। किन्तु जितने तेजी से यह उभरा था उतनी ही तेज़ी से बैठ भी गया और १८७८ तक बिल्कुल खत्म हो गया था। मशीन चालकों और लुहारों के दो-तिहाई और टीन का काम करने वाले श्रमिकों के तीन-चौथाई सदस्य खत्म हो गए। ज्यादा स्थिर नेशनल टाइपोग्रैफिकल यूनियन के भी आधे सदस्य जाते रहे और नव-निर्मित सिगार-निर्माता राष्ट्रीय यूनियन के सदस्य ६,००० से घटकर एक हजार से कुछ ही अधिक रह गए। ट्रेड यूनियनवाद बिल्कुल तो नहीं कुचला गया लेकिन मालिक जब इस कठिन समय का हर लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे थे, और मज़दूर अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे, तो यह वस्तुतः भूमिगत हो गया।

गृहयुद्ध के बाद की दशाब्दि में मज़दूर स्वयं को एक औद्योगिक समाज की नई परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढाल सके और मन्दी का सामना करने के लिए वे अन्तास्थ शक्ति प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसके नेता असंख्य विचार और कार्यक्रम रखते थे, किन्तु ट्रेड यूनियन गतिविधि, सुधार और राजनीति के प्रति फिसलती, बदलती मनोवृत्ति को विशाल श्रमिक समुदाय का पर्याप्त तथा व्यापक समर्थन नहीं मिला और न ही उसने एकता की कोई वास्तविक भावना उत्पन्न की। श्रम-सम्मेलनों की लम्बी-चौड़ी बहसों और मज़दूर अखबारों के लेखों और अपीलों के बावजूद मज़दूर आन्दोलन के मुट्ठी भर सक्रिय कार्यकर्ताओं तथा उनके नाम मात्र के अनुयायियों के बीच खाई बढ़ती

हुई प्रतीत हुई ।

राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन की गतिविधियों के पीछे अगर कोई निश्चित विचारधारा थी तो वह सुधार के इस सिद्धान्त पर आधारित थी कि किसी प्रकार उत्पादक आर्थिक प्रणाली को अपने कब्जे में ले ले और उसका नियंत्रण करे। अब तक भी यह बात व्यापक रूप में अनुभव नहीं की जाती थी कि मशीन, सामूहिक उत्पादन तथा बड़े पैमाने पर पूंजी विनियोग ने मज़दूरों के लिए उत्पादकों की सहकारिताओं जैसे आसान तरीकों से उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित करना असंभव बना दिया है। सुधारक आगे देखने के बजाय पीछे देख रहे थे। स्थायी रूप से मज़दूरी कमाने वालों का एक वर्ग वस्तुतः बन गया था जिसे स्वीकार करने में मज़दूर नेता अब भी हिचकिचा रहे थे। ८ घण्टे का आन्दोलन, मुद्रा-सुधार तथा सहकारिता समाज को पुनरुज्जीवित कर सकने के उपायों के बारे में मध्यम वर्ग के विचारों की उपज थे, उनका जन्म पूंजीवादी व्यवस्था में मज़दूरों की तात्कालिक आवश्यकताओं को वस्तुतः समझने के कारण नहीं हुआ था।

—:o:—

७ : उथल-पुथल का युग

१८७० के दशक की मन्दी से अमरीका के मज़दूर इतिहास में एक सबसे अधिक संभ्रमित युग का आविर्भाव हुआ। कठिन जमाने की अँधियारी पृष्ठ-भूमि में मजदूर "मालिकों के क्रूर शोषण के खिलाफ़" हिंसात्मक विरोध पर उतर आए। वेकारों द्वारा एक के वाद एक शहर में प्रदर्शन किए गए जिनमें प्राय: पुलिस को अपनी शक्ति से हस्तक्षेप करना पड़ता था। खनिकों की हड़ताल में रक्तपात और मारकाट हुई और १८७७ में रेलकर्मचारियों के सहज विद्रोह से इतने व्यापक दंगे हुए कि ऐसा लगता था, मानो देश को एक आम मज़दूर विद्रोह का सामना करना पड़ रहा हो।

इन उपद्रवों के शान्त हो जाने के वाद भी मज़दूरों में अशान्ति और असन्तोष भीतर ही भीतर खतरनाक रूप से सुलगता रहा और जव १८८० के दशक में पुन: मन्दी आई जिसमें कि वेतनों में कटौती और वेकारी का सामान्य चक्र पुन: चला तो इतनी अधिक हड़तालें हुई कि इस जमाने को ही "महान उथल-पुथल" के जमाने का नाम दिया गया। राष्ट्र को पहली वार यह अच्छी प्रकार महसूस हुआ कि औद्योगिक मजदूरों में, जो वदलते हुए अर्थतन्त्र की उपज थे, कितनी वड़ी विस्फोटक शक्ति निहित है।

यह आश्चर्य की वात नहीं थी कि जव ये उपद्रव हो रहे थे तो जनता और रूढ़िवादी व्यापारिक हितों ने महसूस किया कि देश खतरे में है। जो लोग वाहर से देश में आ रहे थे उनमें ऐसे विदेशी उग्रपन्थी भी थे जो उस समय यूरोप में व्यापक रूप से प्रचलित समाजवादी और यहाँ तक कि अराजकतावादी विचारों को अमरीका के मज़दूरों पर थोप देना चाहते थे। ये लोग सुधार की धीमी प्रक्रिया के वजाय उन्हें सीधी कार्रवाई के लिए उकसाते थे। उनके प्रभाव के भय ने वेकारों के प्रदर्शनों तथा हड़तालों की अनेक रिपोर्टों को भी दूषित कर दिया था और १८८६ के हेमार्केट स्क्वेयर के दंगे में यह भय वहुत वढ़ गया। समस्त मज़दूर आन्दोलन पर उग्रता और हिंसा का लाँछन लग गया। किन्तु कम्यूनिज़्म और अराजकता के खिलाफ़ चीख-पुकार मचाकर

कन्ज़र्वेटिव अमरीकी मजदूर की उग्रपन्थिता को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे थे। अपने वामपक्षी तत्वों के बावजूद मज़दूर मूलतः रूढ़िवादी ही थे। पूँजी-वाद का तख्ता उलटने के बजाय वर्तमान अवस्थाओं में सुधार ही अब तक भी मज़दूरों का लक्ष्य था। १८७० और १८८० के दशकों में मज़दूरों के उपद्रवों के लिए विदेशी उग्रपन्थियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उस समय के अखबारों और बाद के जमाने के अखबार भी कम वेतन और बेकारी के उन बुनियादी तत्वों की उपेक्षा कर रहे थे जो मज़दूरों के असन्तोष के लिए मूलतः जिम्मेदार थे।

१८७७ की महान रेल हड़ताल जैसे नाटकीय विद्रोह में जो हिंसा हुई उसे इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए कि चिरकाल से मन्दी का दौरदौरा चल रहा था, जिनके वेतनों में कटौती की गई थी या जो बिल्कुल बेकार थे उनके कष्ट दूर करने के लिए कोई सार्वजनिक प्रयत्न नहीं किया गया, रेलों के, जिन पर सिर्फ़ मुनाफ़ों में दिलचस्पी रखने वाले बैंकरों और महाजनों का नियन्त्रण था, बड़े-बड़े मालिकों का रवैया बड़ा कठोर था और अन्याय के विरुद्ध मज़दूरों के प्रतिरोध को प्रभावशाली रूप देने के लिए मज़दूरों का कोई संगठन नहीं था। रेलकर्मचारियों के भीतर सुलगती हुई असन्तोष की आग के खुले विद्रोह के रूप में भड़क उठने के लिये उग्रपन्थी आन्दोलन की चिन-गारी की ज़रूरत नहीं थी। जब वेतनों में लगातार कटौतियां किए जाने से मज़दूर हताश हो गए और उन्होंने कटुताभरी चुनौती देने के ख्याल से अन्धा-धुन्ध हड़तालें कर दीं तो यह आग अपने आप भभक उठी।

मज़दूरों में अशान्ति और संघर्ष के इस युग में 'नाइट्स ऑव लेबर' और उन राष्ट्रीय यूनियनों का शनैः-शनैः विकास हुआ जो बाद में 'नाइट्स' के साथ प्रतिद्वन्द्विता करते हुए अमेरिकन फैडरेशन आव लेबर के रूप में मिलकर एक हो गए। किन्तु बुनियादी तौर से ये महत्वपूर्ण घटनाएँ उस असंगठित हिंसा और उग्र आन्दोलन के सामने गौण हो गईं जिनमें एक पूँजीवादी समाज के अन्तर्गत मज़दूरों के बढ़ते हुए कष्टों की छाया दिखाई देती थी। इस पूँजी-वादी समाज में तब औद्योगिक सम्बन्धों में मानवीय तत्त्व की प्रायः उपेक्षा की जाती थी।

१८७३ के आतंक का प्रभाव जैसे-जैसे गहरा और व्यापक होता गया वैसे-

वैसे सारे देश के शहरों में अव्यवस्था के दृश्य दिखाई देने लगे। न्यूयार्क, शिकागो, वोस्टन, सिनसिनाटी और ओमाहा में वेकार मज़दूरों की भीड़ की भीड़ फैक्ट्रियों और कारखानों के वन्द होने से उत्पन्न असह्य परिस्थितियों के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शित करने के हेतु विशाल सभाएँ करने के लिए एकत्र होने लगीं। १९ वीं सदी के प्रथमार्ध के कम जटिल कृषि समाज की अपेक्षा औद्योगिक समाज में वेकारी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वेघर, भूखे और निराश मज़दूरों ने पुलिस द्वारा उनकी सभाएँ भंग किए जाने की कोशिशें करने पर तितर-वितर होने से इन्कार कर दिया। स्वतन्त्र रूप से सभाएँ करने के अपने तथाकथित अधिकार की रक्षा के लिए वे जमकर लड़े और अपनी माँगें पूरी करने के लिए उन्होंने समाज को चुनौती दी।

इनमें सवसे विख्यात उपद्रव १३ जनवरी, १८७४ को न्यूयार्क में टाम्पकिन्स स्क्वेयर में हुआ। नगर के अधिकारियों को राहत की आवश्यकता के प्रति सजग करने के लिए वेकारों की एक सभा वुलाई गई थी। इस सभा के लिए पूर्व स्वीकृति दे दी गई थी और मेयर ने इसमें भाषण करने का वचन दिया था। इस वात का पता लगते ही कि उग्र आन्दोलनकारी सभा में भाषण करने की तैयारी कर रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ की अमरीकी शाखा के सदस्यों ने इस सभा के इन्तज़ाम में भाग लिया है, अन्तिम क्षण सभा के लिए पुलिस का परमिट रद्द कर दिया गया। किन्तु पूर्वनिर्धारित समय पर टाम्पकिन्स स्क्वेयर मज़दूरों से खचाखच भर गया। उन्हें सभा के प्रति सरकारी रवैया वदल जाने का पता ही नहीं था। शीघ्र ही घुड़सवार पुलिस का एक दस्ता सभा-स्थल पर आ गया और विना किसी चेतावनी के जो कोई भी पकड़ में आया उसी पर अन्धाधुन्ध डण्डे वरसाने शुरू कर दिये। स्त्री-पुरुष व वच्चे जव डरकर भागे तो उनमें से अनेक कुचले गए और वीसियों निरपराध तमाशवीन पुलिस के हमले से अपना वचाव करने का प्रयत्न करते हुए जख्मी हो गए।

न्यूयार्क टाइम्स ने अगले दिन लिखा कि पुलिस ने अपने डण्डों का इस्तेमाल "अत्यधिक सख्ती से नहीं, वल्कि विवेक से किया है और अफसरों के आगे वढ़ने पर भीड़ में जो भगदड़ मची वह भी देखने लायक थी।" मज़दूरों में असन्तोष के मूल कारण तथा वेकारी के वदले में राहत पाने का जो थोड़ा-

बहुत अधिकार उनका था, उनकी उपेक्षा करते हुए अखबार ने यह रवैया अपनाया कि यह प्रदर्शन विदेशी उग्र-पंथियों की कारस्तानी थी। इसने अपने अग्रलेख में कहा : "कल जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए वे सब विदेशी—मुख्यतः जर्मन या आयरिश मालूम पड़ते हैं। कम्यूनिज़म स्वदेश की उपज नहीं है।"

एक युवा मज़दूर भी था जिसने यह सबक अच्छी तरह हृदयंगम कर लिया कि टाम्पकिन्स स्क्वेयर के दंगे से मालूम पड़ता है कि ट्रेड यूनियन द्वारा उग्र-पंथियों का नेतृत्व अपनाए जाने में कितन बड़ा खतरा है। जब पुलिस भीड़ पर हमले कर रही थी तब यह तरुण सेम्मुअल गाम्पर्स वहाँ मौजूद था और वह एक तहखाने में कूद कर बड़ी मुश्किल से अपना सिर पुलिस के डंडों से बचा पाया था।

वर्षों बाद अपनी आत्मकथा में उसने लिखा : "मैंने देखा कि किस प्रकार उग्रवादिता और सनसनीवाद ने समाज की सब बातों को मज़दूर आन्दोलन के खिलाफ एकत्र कर दिया और पहले से ही उसने सामान्य, आवश्यक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। मैंने देखा कि मज़दूर आन्दोलन का नेतृत्व सुरक्षित रूप से उन्हीं लोगों को सौंपा जा सकता है जिनके हृदय और मस्तिष्क दैनिक श्रम से रोटी कमाने के अनुभव से परिपक्व हो गए हों। मैंने देखा कि मज़दूरों के हित-साधन का काम मुख्यतः मज़दूरों को ही करना चाहिए।"

टाम्पकिन्स स्क्वेयर के दंगे और अन्य शहरों में बेकारी के प्रदर्शन के पश्चात् पूर्वी पेंसिलवेनिया की ऐन्थ्रसाइट कोयला खानों में हिंसात्मक उपद्रवों पर लोगों का ध्यान गया। इस उद्योग के मज़दूरों ने सौफ्ट कोयला खानों के मज़दूरों की "माइनर्स नेशनल ऐसोसियेशन की तरह अपनी एक यूनियन बना ली थी जिसका नाम था—'माइनर्स एन्ड माइन लेबरर्स बेनेवलेण्ट ऐसोसियेशन।' यह यूनियन एन्थ्रसाइट व्यापार बोर्ड के साथ एक समझौता करने में कामयाब हुई किन्तु दिसम्बर १८७४ में खान मालिकों ने निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी की राशि में भी मनमाने ढंग से कटौती कर दी। खनिक एकदम खानों से बाहर निकल आए और "लम्बी हड़ताल" चली। उन्होंने खान मालिकों को वेतनों में कटौती बहाल करने के लिये मजबूर करने की कोशिश

वैसे सारे देश के शहरों में अव्यवस्था के दृश्य दिखाई देने लगे। न्यूयार्क, शिकागो, बोस्टन, सिनसिनाटी और ओमाहा में बेकार मज़दूरों की भीड़ की भीड़ फैक्ट्रियों और कारखानों के बन्द होने से उत्पन्न असह्य परिस्थितियों के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शित करने के हेतु विशाल सभाएँ करने के लिए एकत्र होने लगीं। १६ वीं सदी के प्रथमार्ध के कम जटिल कृषि समाज की अपेक्षा औद्योगिक समाज में बेकारी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। बेघर, भूखे और निराश मज़दूरों ने पुलिस द्वारा उनकी सभाएँ भंग किए जाने की कोशिशें करने पर तितर-बितर होने से इन्कार कर दिया। स्वतन्त्र रूप से सभाएँ करने के अपने तथाकथित अधिकार की रक्षा के लिए वे जमकर लड़े और अपनी माँगें पूरी करने के लिए उन्होंने समाज को चुनौती दी।

इनमें सबसे विख्यात उपद्रव १३ जनवरी, १८७४ को न्यूयार्क में टाम्पकिन्स स्क्वेयर में हुआ। नगर के अधिकारियों को राहत की आवश्यकता के प्रति सजग करने के लिए बेकारों की एक सभा बुलाई गई थी। इस सभा के लिए पूर्व स्वीकृति दे दी गई थी और मेयर ने इसमें भाषण करने का वचन दिया था। इस बात का पता लगते ही कि उग्र आन्दोलनकारी सभा में भाषण करने की तैयारी कर रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ की अमरीकी शाखा के सदस्यों ने इस सभा के इन्तज़ाम में भाग लिया है, अन्तिम क्षण सभा के लिए पुलिस का परमिट रद्द कर दिया गया। किन्तु पूर्वनिर्धारित समय पर टाम्पकिन्स स्क्वेयर मज़दूरों से खचाखच भर गया। उन्हें सभा के प्रति सरकारी रवैया बदल जाने का पता ही नहीं था। शीघ्र ही घुड़सवार पुलिस का एक दस्ता सभा-स्थल पर आ गया और बिना किसी चेतावनी के जो कोई भी पकड़ में आया उसी पर अन्धाधुन्ध डण्डे बरसाने शुरू कर दिये। स्त्री-पुरुष व बच्चे जब डरकर भागे तो उनमें से अनेक कुचले गए और बीसियों निरपराध तमाशबीन पुलिस के हमले से अपना बचाव करने का प्रयत्न करते हुए जख्मी हो गए।

न्यूयार्क टाइम्स ने अगले दिन लिखा कि पुलिस ने अपने डण्डों का इस्तेमाल "अत्यधिक सख्ती से नहीं, बल्कि विवेक से किया है और अफसरों के आगे बढ़ने पर भीड़ में जो भगदड़ मची वह भी देखने लायक थी।" मज़दूरों में असन्तोष के मूल कारण तथा बेकारी के बदले में राहत पाने का जो थोड़ा-

बहुत अधिकार उनका था, उनकी उपेक्षा करते हुए अखबार ने यह रवैया अपनाया कि यह प्रदर्शन विदेशी उग्र-पंथियों की कारस्तानी थी। इसने अपने अग्रलेख में कहा : "कल जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए वे सब विदेशी— मुख्यतः जर्मन या आयरिश मालूम पड़ते हैं। कम्यूनिज़्म स्वदेश की उपज नहीं है।"

एक युवा मज़दूर भी था जिसने यह सबक अच्छी तरह हृदयंगम कर लिया कि टाम्पकिन्स स्क्वेयर के दंगे से मालूम पड़ता है कि ट्रेड यूनियन द्वारा उग्र-पंथियों का नेतृत्व अपनाए जाने में कितन बड़ा खतरा है। जब पुलिस भीड़ पर हमले कर रही थी तब यह तरुण सेम्मुअल गाम्पर्स वहाँ मौजूद था और वह एक तहखाने में कूद कर बड़ी मुश्किल से अपना सिर पुलिस के डंडों से बचा पाया था।

वर्षों बाद अपनी आत्मकथा में उसने लिखा : "मैंने देखा कि किस प्रकार उग्रवादिता और सनसनीवाद ने समाज की सब बातों को मज़दूर आन्दोलन के खिलाफ एकत्र कर दिया और पहले से ही उसने सामान्य, आवश्यक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। मैंने देखा कि मज़दूर आन्दोलन का नेतृत्व सुरक्षित रूप से उन्हीं लोगों को सौंपा जा सकता है जिनके हृदय और मस्तिष्क दैनिक श्रम से रोटी कमाने के अनुभव से परिपक्व हो गए हों। मैंने देखा कि मज़दूरों के हित-साधन का काम मुख्यतः मज़दूरों को ही करना चाहिए।"

टाम्पकिन्स स्क्वेयर के दंगे और अन्य शहरों में बेकारी के प्रदर्शन के पश्चात् पूर्वी पेंसिलवेनिया की ऐन्थ्रसाइट कोयला खानों में हिंसात्मक उपद्रवों पर लोगों का ध्यान गया। इस उद्योग के मज़दूरों ने सॉफ्ट कोयला खानों के मज़दूरों की "माइनर्स नेशनल ऐसोसियेशन की तरह अपनी एक यूनियन बना ली थी जिसका नाम था—'माइनर्स एन्ड माइन लेबरर्स बेनेवलेण्ट ऐसोसियेशन।' यह यूनियन एन्थ्रसाइट व्यापार बोर्ड के साथ एक समझौता करने में कामयाब हुई किन्तु दिसम्बर १८७४ में खान मालिकों ने निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी की राशि में भी मनमाने ढंग से कटौती कर दी। खनिक एकदम खानों से बाहर निकल आए और "लम्बी हड़ताल" चली। उन्होंने खान मालिकों को वेतनों में कटौती बहाल करने के लिये मजबूर करने की कोशिश

की। जब भूख और अभाव मजदूरों पर अपना असर दिखाने लगे और अनेक मज़दूर खानों में काम पर लौटने को विवश हो गए तो बाकी हड़तालियों तथा हड़ताल भंग करने वालों की रक्षा के लिए खान मालिकों द्वारा बुलाई गई पुलिस में खुलकर संग्राम हुआ।

इस उपद्रव-ग्रस्त स्थिति में एक और बात ऐसी हो गई जिसके बारे में यह निर्णय करना मुश्किल है कि इस लम्बी हड़ताल में उसकी क्या भूमिका रही। लेकिन उस समय अखबारों में इस आशय की सनसनीखेज रिपोर्ट छपी —कि खनिकों में 'ऐन्श्यन्ट आर्डर आव हाइबर्नियन्स नाम अथवा मौली मैगा-यर्स के अधिक लोकप्रिय नाम का एक गुप्त संगठन काम कर रहा है जिसने कोयला खानों में आतंक मचाया हुआ है और जो काम पर लौट आना चाहने वाले मज़दूरों को काम पर लौट आने से रोक रहा है। इस सोसाइटी के सदस्यों पर खान मालिकों को डराने-धमकाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया जैसा कि एक बार उन्होंने मौली मेगायर नाम की दुर्धर्ष विधवा के नेतृत्व में आयरिश जमींदारों को डराने-धमकाने की कोशिश की थी। इसी महिला के नाम पर उनके संगठन को मौली मैगायर कहा गया। खान मालिकों को आतंकित करने के लिये उन्होंने जो उपाय अपनाए, उनमें फोरमैन और सुपरिण्टेण्डेण्टों को हिंसात्मक धमकियां देना, खान की सम्पत्ति का विध्वंस और विनाश तथा एकदम हत्याएं कर देना शामिल था। बाद में पता चला कि इनमें से कुछ हमले स्वयं खान मालिकों ने करवाए जिससे उन्हें न केवल मौली मैगायर को बल्कि सारे यूनियन संगठन को ही कुचलने का अवसर मिल जाए। पूर्वी पेंसिलवेनिया में फैली इस हिंसा की विवेचना अव्यवस्था को दबाने के लिये उठाए गए कदमों से कम-से-कम आंशिक रूप में जरूर पुष्ट हो जाती है।

फिलाडेल्फिया और रीडिंग रेलवे के अत्यन्त कटु मज़दूर विरोधी अध्यक्ष ने जिनका कई खानों पर नियन्त्रण था, इस अभियान में पहल की। उसने जेम्स मैकपार्लन नाम के एक पिंकरटन जासूस को भाड़े पर रखकर उससे किसी भी कीमत पर मौली मैगायर्स की जरायम हरकतों का प्रमाण लाने के लिये कहा। स्वयं को अदालत की सजा से डर कर भागा हुआ बता कर मैकपार्लन ने उनका विश्वास प्राप्त किया, उनके षड्यन्त्रों में हिस्सा लिया और स्वयं भी

कुछ षड्यन्त्र रचाये, जिससे कि उसके आरोप सही निकलें और अन्त में १८७५ की पतझड़ में वह ऐसी साक्षी जुटाने में सफल हो गया जिसके आधार पर अधिकारियों ने अनेक गिरफ्तारियाँ कराईं। गवाह के कठघरे में उसकी व अन्य सरकारी गवाहों की साक्षियां यद्यपि संदिग्ध प्रतीत होती थीं तो भी उस मुकदमे में २४ मौली मैगायर दण्डित हुए जिनमें से १० को फांसी दे दी गई और बाकी को दो से ७ वर्ष तक की जेल की सज़ा दी गई। खानों में शान्ति और व्यवस्था कायम हो गई। इस गुप्त सोसाइटी का अगर कुछ प्रभाव था भी तो वह इस हमले से ख़त्म हो गया। किन्तु इसके साथ ही खान मालिक 'माइनर्स बेनवलेण्ट ऐंसोसियेशन' को तोड़ने और हड़तालियों को अपनी शर्तों पर काम पर वापस लेने में कामयाब हो गए। यह लम्बा संघर्ष मज़दूरों के लिए पूर्ण विफलता में और उनकी यूनियन के वस्तुत: ख़ात्मे के रूप में समाप्त हुआ।

किन्तु ऐन्थ्रसाइट कोयला खानों में बेकारी के ये दंगे और हिंसा १८७७ की रेल हड़तालों की भूमिका थे। जिनमें ऐसी अव्यवस्था और दंगे हुए कि उन्हें संघीय सेनाओं की बदौलत ही दबाया जा सका। पहले आम जनता को मज़दूरों से सहानुभूति थी। उनके वेतन मनमाने ढंग से कम कर दिए गए थे, जबकि गिरे हुए मूल्य के शेयरों पर ऊँचे-ऊँचे डिविडेण्ड दिए जा रहे थे और कुछ भी हो १८७० के दशक में रेलें बहुत ही अलोकप्रिय थीं। न्यूयार्क ट्रिब्यून ने लिखा: कि "इस तथ्य से आँखें मूंदना मूर्खता है कि जनमत प्राय: सब कहीं विद्रोहियों के साथ है।" किन्तु जब हिंसा अनियंत्रित रूप में जारी रही तो सिर्फ सिविल व्यवस्था और अराजकता के बीच ही विकल्प रह गया। यद्यपि 'नेशन्स' के इस बेलाग वक्तव्य से हर कोई सहमत नहीं था कि हड़तालियों को शुरू में ही प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा आतंकित और कुचला जाना चाहिए था तो भी यह महसूस किया गया कि सरकार सार्वजनिक व्यवस्था पुन: स्थापित करने की अपनी जिम्मेदारी को नहीं टाल सकती।

१८७७ की जुलाई के शुरू में वेतनों में कटौती के खिलाफ हड़तालें सहज उद्भूत थीं। पहली हड़ताल बाल्टिमोर तथा ओहायो में हुई और इसके बाद रेल कर्मचारियों की इसी प्रकार की हड़तालें पेंसिलवेनिया, न्यूयार्क सेण्ट्रल

तथा एरी में हुई। अल्पकाल में ही मिसीसिपी से पूर्व की सब रेल लाइनें इस हड़ताल से प्रभावित हुई और तब यह आन्दोलन मिसूरी पैसिफिक, सेण्ट लुई, कन्सास और नार्दर्न तथा अन्य पश्चिमी रेलों तक फैल गया। समूचे देश में रेल यातायात अव्यवस्थित हो गया और कहीं-कहीं तो बिल्कुल ठप्प हो गया। बाल्टिमोर और पिट्सबर्ग, शिकागो और सेण्ट लुई तथा सान-फ्रांसिस्को में भी जब दंगों ने खतरनाक रूप अख्त्यार कर लिया तो देश के सामने राष्ट्रव्यापी स्तर पर पहला औद्योगिक उत्पात फूट पड़ा। सेण्ट लुई रिपब्लिकन ने लिखा : "इसे हड़ताल कहना गलत है, यह एक मज़दूर क्रान्ति है।"

पहले पहल बाल्टिमोर और ओहायो के हड़तालियों का मार्टिन्सबर्ग, प० वर्जीनिया के अधिकारियों से संघर्ष हुआ और इन स्थानों पर शान्ति २०० संघीय सैनिक भेजे जाने के बाद ही कायम हो सकी। बाल्टिमोर में दंगे ज्यादा बड़े पैमाने पर हुए। वहां हड़तालियों ने सब ट्रेनें रोक दीं, उन्हें चलने से रोका और रेलवे की सम्पत्ति पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मैरीलैण्ड के गवर्नर द्वारा बुलाई गई मिलीशिया ने जब अपनी बारकों से रेलवे स्टेशन की ओर कूच किया तो मज़दूरों और उनसे सहानुभूति रखने वालों की एक भीड़ ने उन पर ईंट-पत्थरों और डण्डों से हमला कर दिया। सेनाओं ने गोली चलाई और वह स्टेशन की ओर निकल गई किन्तु दंगाइयों को खून का चसका लग गया था। उन्होंने आक्रमण जारी रखा तथा स्टेशन को आग लगादी जब पुलिस और आग बुझाने वाले पहुँचे तो भीड़ ने उन्हें कुछ समय तक आग बुझाने से रोके रखा किन्तु अन्त में वह हट गई। उपद्रव और दंगे उस सारी काली डरावनी रात में होते रहे और अगले दिन सवेरे संघीय सेनाओं के आने के बाद ही वस्तुतः कुछ शांति कायम हो सकी। तब तक ९ व्यक्ति मर चुके थे और बीस से अधिक (जिनमें से तीन बाद में मर गए) सख्त घायल हुए।

इस बीच पिट्सबर्ग में इससे भी भयावह उपद्रव फूट पड़ा। वहां भी हड़तालियों ने ट्रेनें रोकीं और रेलवे की सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया। यहां लोगों की सहानुभूति पूर्णतः रेल कर्मचारियों के साथ थी क्योंकि पेंसिलवेनिया की नीतियों से यहां के लोग बहुत नाराज़ थे। स्थानीय मिलीशिया खुल्लम-
हड़तालियों के साथ भाईचारा दिखा रही थी और उसने उनके खिलाफ

लूट का हिस्सा हो और बीसियों औरतें अपनी पोशाकों में आटा, अण्डे, सूखी चीजें इत्यादि भर-भर कर ले गईं। पुरुषों की छतरियाँ और औरतों की खूबसूरत छतरियाँ, मांस, सूअर की चरबी, कपड़े, कम्बल, गोटा, किनारी और आटे के बण्डल मजबूत पुरुषों की बाहों में समेट लिये गए या जल्दी-जल्दी में बनाई गई हथ-गाड़ियों में भर कर ले जाए गए।"

इस वहशियाना लूट के सप्ताहान्त तक चलते रहने के बाद ही जिसमें करीब ५० लाख से लेकर १ करोड़ डालर तक का नुकसान हुआ, पुलिस ने संशस्त्र नागरिकों के दलों के साथ मिलकर कुछ ऊपरी व्यवस्था स्थापित करना प्रारम्भ किया। इस बीच राज्य की सारी मिलीशिया लाम पर बुला ली गई और मंत्रिमण्डल की आपात कालीन बैठक के बाद राष्ट्रपति हेयेज ने अटलाण्टिक डिपर्टमेण्ट में उपलब्ध सब संघीय सेनाओं से संकट काल का मुकाबला करने के लिए कहा। अन्त में पिट्सबर्ग में नियमित सैनिकों के पहुँचने पर ही रेलवे की सम्पति को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जा सका।

अखबारों की सुर्खियों और अग्रलेखों में कहा गया कि हड़ताल की जड़ में कम्यूनिज़्म घुसा हुआ था और बाल्टिमोर, पिट्सबर्ग तथा देश के अन्य भागों में हिंसा के लिए वही जिम्मेदार है। इसे एक विद्रोह, एक क्रांति, समाज को सताने की कम्युनिस्टों और आवारा लोगों की चेष्टा, और अमरीकी संस्थाओं में पलीता लगाने का एक प्रयत्न कहा गया। न्यूयार्क ट्रिब्यून ने कहा: "अज्ञानी भूखे दुष्टजनों की इस भीड़ को ताकत ही दबा सकी।" टाइम्स ने हड़तालियों को दंगाई, नीच, शराबी, लुटेरे, धोखेबाज, चोर, आवारा गुण्डे, शोले, समाज के दुश्मन, डाकू, शैतान, बदमाश, हत्यारे और मूर्ख" कहा और हैरल्ड ने कहा कि यह भीड़ 'जंगली जानवर थी, जिसे गोली मार दी जानी चाहिए थी।' "पिटसबर्ग लूट लिया गया—शहर पर भेड़िया भीड़ का पूर्णत: कब्जा" और "शिकागो कम्युनिस्टों के कब्जे में" आदि शीर्षक पढ़कर जनता भयभीत हो उठी।

किन्तु जैसे-जैसे संघीय सेनाएं एक के बाद एक उपद्रव ग्रस्त शहरों में जाती रहीं वैसे-वैसे दंगे जिस प्रकार यकायक उभरे थे, वैसे ही शान्त हो गए। हड़तालियों ने न केवल रेलों के संचालन में और कोई बाधा डालने की कोशिश नहीं की, बल्कि धीरे-धीरे वे काम पर वापस आ गए। वे जानते थे कि वे

सम्बन्धी कानूनों को पुनर्जागृत किया, मज़दूरों को यूनियनों में शामिल होने से रोकने के लिए डराने धमकाने का प्रयत्न किया, बड़ी सख्त प्रतिज्ञाएँ उनसे कराईं और जहां कहीं भी उपद्रव की आशंका हुई हड़ताल भंजकों की सेवाएँ लीं। मज़दूरों ने इससे यह सबक सीखा कि उन्हें एक ऐसे संगठन और प्राधिकार की जरूरत है जो हड़तालों की भीड़ को अनियंत्रित कार्रवाई का रूप लेने से रोके, जिससे अन्य या राज्य और संघ की सेनाओं को दमन के लिए निमंत्रण मिलता है। औद्योगिक संघर्ष के इस प्रथम दौर में जीत पूँजीवाद की रही किन्तु भविष्य के प्रति वह भयभीत हो उठा। और मज़दूर हार गए किन्तु इस हार में भी उन्हें अपने अन्दर छिपी शक्ति का नया अहसास हुआ।

१८७० के दशक में बेकारी के विरुद्ध किए गए प्रदर्शनों और रेल कर्मचारियों के विद्रोह से जो हिंसात्मक काण्ड हुए उनकी अगले दशक में हड़तालों के एक अन्य दौर में पुनरावृत्ति हुई। किन्तु १८८६ में हेमार्केट स्क्वेयर के दंगे ने इन वर्षों के अन्य उपद्रवों की अपेक्षा जनता को अधिक भयभीत किया। इस दुखद स्थिति के लिए अराजकतावादी जिम्मेदार ठहराये गए और यद्यपि उनके हिंसात्मक "काम के द्वारा प्रचार" के ढंग से शिकागो के कुछ ही मज़दूर प्रभावित हुए, तो भी दंगे के परिणामों ने समस्त मज़दूर आन्दोलन पर असर डाला। यूनियनवाद के दुश्मनों ने श्रम संगठनों को बदनाम करने के लिए इस नाटकीय घटना को खूब तूल दिया और उस पर उग्र परिवर्तनवादी क्रांतिकारी और गैर-अमरीकी होने का लांछन लगाया।

मज़दूर आन्दोलन के भीतर वामपक्षी ग्रुप सदा की भांति इस काल में भी अपनी नातेदारियाँ बदलता रहा और नई पार्टियाँ संगठित करता रहा, जो क्रांतिकारी यूरोपीय वर्ग, जिससे ज्यादातर उसका विकास हुआ था, के ऊलजलूल विचारों को प्रतिक्षिप्त करता था। इण्टरनेशनल वर्किंगमेन्स ऐसोसियेशन की अमरीकी शाखा विदेश में अपनी पितृ-संस्था में फूट पड़ जाने के कारण, १८७८ में भंग कर दी गई और अमरीका में समाजवादी ताकतों ने मज़दूरों का एक नया दल बना लिया। यह कोई महत्वपूर्ण नहीं था, इसके ·ड़े से सदस्यों में ज्यादातर जर्मन और अन्य यूरोपीय-जन्मा आवासी थे

किन्तु १८७७ की रेल हड़ताल में यह सक्रिय रहा, हिंसा भड़काता रहा और इसने एक आम हड़ताल कराने की कोशिश की ।

और ज्यादा आंतरिक झगड़ों के कारण इसके सदस्यों में शीघ्र फूट पड़ गई । मार्क्सवादी समाजवादियों तथा लस्सालियनों में कटुताभरी प्रतिद्वन्द्विता हो गई । मार्क्सवादी समाजवादी क्रांतिकारी हरकतों के लिए जिनसे अन्ततोगत्वा पूंजीवादी समाज का तख्ता पलट दिया जाता, ट्रेड यूनियनिज्म का आधार बनाना चाहते थे और लस्सालियन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीधी राजनीतिक कार्रवाई को ज्यादा कारगर समझते थे । इन दो ग्रुपों के अलावा एक तीसरा ग्रुप अराजकतावाद के ज्यादा परिवर्तनकारी सिद्धान्तों से खिलवाड़ कर रहा था । इन सिद्धान्तों का पाठ इस देश में जोहन मोस्ट नाम का एक व्यक्ति पढ़ा रहा था जो लम्बे कद का काली दाढ़ी वाला एक जर्मन

से, जिनका समस्त जलूस में खूब प्रदर्शन किया गया था, सामने आ गया।"

१८८६ में जब ८ घण्टे के दिन के पक्ष में आम हड़ताल करने का आन्दोलन देश भर में फैला तब शिकागो के अराजकतावादी क्रांतिकारी हिंसा के अपने सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाने को तैयार थे। हड़ताल के लिए निश्चित दिन १ मई शांति से गुजर गया किन्तु दो दिन बाद शिकागो के मैक कौरमिक हार्वेस्टर प्लाण्ट में हड़तालियों और हड़ताल भंजकों में संघर्ष हो गया, जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और चार व्यक्ति मारे गए। यह एक ऐसा अवसर था जिसकी ब्लैक इण्टरनेशनल के सदस्य प्रतीक्षा कर रहे थे। उस रात शहर में पर्चे बाँट कर मजदूरों को अपने मृत साथियों की मौत का बदला लेने के लिए उकसाया गया था।

इस भड़काने वाली अपील में कहा गया: "मालिकों ने अपने शिकारी कुत्ते—पुलिस भेजी है। उसने आज तीसरे पहर आपके ६ भाइयों को मार डाला। इन अभागों को उसने इसलिए मार डाला क्योंकि आपके समान ही उन्होंने आपके मालिकों की सर्वोच्च इच्छा का अनादर करने का साहस किया था.......हम आपसे हथियार उठाने की अपील करते हैं।"

अगले दिन ४ मई की शाम को हेमार्केट स्क्वेयर में एक विरोध-सभा बुलाई गई और कोई ३ हज़ार व्यक्ति अराजकतावादी नेताओं के आवेशपूर्ण और भड़काने वाले भाषणों को सुनने के लिए एकत्र हुए। किन्तु इन सब प्रकार के भयों के बावजूद सभा बिल्कुल शान्ति से सम्पन्न हुई (स्वयं मेयर ने इसमें भाग लिया था और सारे वातावरण को इतना शान्त पाकर वह चले गये थे) और जब ठण्डी हवाओं ने स्क्वेयर पर पानी बरसाना शुरू कर दिया तो भीड़ शनैः-शनैः छँटने लगी। वस्तुतः सभा दो सौ पुलिसमैनों की टुकड़ी आने पर भंग हो गई और उनके कप्तान ने सख्ती से बचे हुए मजदूरों को तितर-बितर हो जाने का आदेश दिया। यकायक एक भीषण विस्फोट हुआ, किसी ने पुलिस वालों पर एक बम फेंक दिया जिससे एक पुलिसमैन तत्काल मर गया। पुलिस ने एकदम गोली चलाई और मजदूरों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। इस मुठभेड़ में कुल ७ पुलिसमैन मारे गये या सांघातिक रूप से घायल हुए और कोई ६७ जख्मी हुए, ४ मज़दूर मारे गए और ५० से ज्यादा घायल हुए।

बम फेंके जाने की इस घटना से शिकागो ही [illegible] हो उठा। इसका दोष तुरन्त ही अराजकतावादियों के मत्थे मढ़ा गया और सर्वत्र यह मांग की गई कि उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया जाए। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए शहर को छान मारा और अन्त में ८ सुपरिचित अराजकतावादी नेता गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर हत्या का अभियोग लगाया गया। एक उन्मत्तता के वातावरण में, जिसमें भय और बदले की इच्छा दोनों मिली हुई थीं, उन्हें शीघ्र ही दोषी करार दिया गया और उनमें से ७ को मृत्युदण्ड तथा एक को १५ वर्ष की जेल की सजा दी गई। ऐसी कोई गवाही प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे सिद्ध होता हो कि बम फेंके जाने की घटना से उनका सम्बन्ध था। उन्हें उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण, तथा हिंसा के लिए भड़काने के कारण, जिसे बम फेंके जाने की घटना का कारण समझा गया, दण्डित किया गया। सरकारी अभियोक्ता ने अनुरोध किया : "इन आदमियों को सजा दीजिये, इन्हें दूसरों के लिए सबक लेने लायक उदाहरण बनाइये, फांसी पर लटका दीजिये और तब आप हमारी संस्थाओं को बचा लेंगे......"।

दो सजायाफ्ताओं ने सरकार से दया की याचना की, उनकी मौत की सजा आजन्म कारावास में बदल दी गई। ६ वर्ष बाद गवर्नर जॉन पीटर आल्टगेल्ड ने उन्हें उस आठवें आदमी के साथ, जिसे १५ साल जेल की सजा दी गई थी, इस आधार पर माफ कर दिया कि उनके साथ मुकदमे में न्याय नहीं बरता गया। इतना समय बीत जाने के बाद भी अराजकतावादियों के खिलाफ लोगों की भावनाएं इतनी उग्र थीं कि इस क्षमादान के लिए आल्टगेल्ड की सारे देश में आलोचना की गई, यद्यपि अब हर कोई यह स्वीकार करता है कि उनका यह कार्य महज न्याय का एक काम था।

कोई सम्बन्ध, सहानुभूति या आदर का भाव नहीं है। अभियुक्तों पर जो आरोप लगाए गए उन्हें सिद्ध करने में इस्तगासे की पूर्ण विफलता को दरगुज़र करते हुए नाइट्स ने उन्हें सज़ा देने की माँग की। उन्होंने कहा "सात आदमियों को सात बार फाँसी पर लटका देना कहीं ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हमारी जमात पर विनाशक तत्व के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध होने का कलंक लगे।"

इस प्रकार के आक्रोश का कारण स्पष्ट था मज़दूरों के पूँजीवादी दुश्मन यह आरोप लगा कर कि नाइट्स आव लेबर तथा सामान्यतः यूनियनों में अराजकतावाद तथा कम्यूनिज़्म की भावना घुसी हुई है, "बदनामी की इस चक्की" को मज़दूर आन्दोलन के गले में लटका देना चाहते थे। भयभीत जनता इसे मानने के लिए भी तैयार थी। हेमार्केट स्क्वेयर में पुलिस दल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बम फैंके जाने से समस्त मज़दूर आन्दोलन पर कालिख पुत गई। यह बात कोई मायने नहीं रखती थी कि मज़दूर आन्दोलन के जिम्मेदार नेता तथा स्वयं मज़दूर अराजकतावाद और कम्यूनिज़्म के उतने ही खिलाफ़ थे, जितना समाज का अन्य कोई वर्ग। समस्त श्रमिक वर्ग को अपने बचाव पर विवश होना पड़ा।

ट्रेड यूनियनवाद जिस तरफ जा रहा था, उस पर इस सारी घटना का महत्वपूर्ण असर पड़ा किन्तु समग्र दृष्टि से मज़दूर आन्दोलन के विकास के अध्ययन के हमारे उद्देश्य से यह हमें दूर घसीट ले गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है १८८० के दशक में नाइट्स आव लेबर का अभ्युदय थोड़े से रैडिकल तत्व की गतिविधियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो मज़दूर आन्दोलन में सदा मौजूद रहती थी किन्तु उसकी मूल विचारधारा पर कभी गहरा असर नहीं डाल सकी।

— :o: —

८ : नाइट्स आव लेबर का उत्थान और पतन

हेमार्केट स्क्वेयर के दंगे से १७ वर्ष पहले और महान रेलवे-हड़ताल से ८ वर्ष पूर्व उस संगठन की स्थापना के लिए पहला कदम उठाया गया था जो बाद में "नोवल ऐण्ड होली आर्डर आव नाइट्स आव लेबर कहलाया। तो भी इन दोनों घटनाओं के बीच के वर्ष, जिनमें यह अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुँची श्रमिक अशांति तथा औद्योगिक संघर्ष के वर्ष थे। यद्यपि उस समय राष्ट्रीय यूनियनवाद भी धीरे धीरे फिर पनप रहा था। और सम्मुअल गाम्पर्स दृढ़ता से उन नीतियों का पक्षपोषण कर रहा था, जो अमेरिकन फेडरेशन आव लेवर की स्थापना के साथ फलीभूत हुईं तो भी १८८० के दशक के बीच के वर्षों में अमरीकी श्रमिक का भविष्य नाइट्स आव लेवर के हाथ में प्रतीत होता था। श्रमिकों का कोई संगठन पहली बार इतना मजबूत प्रतीत हुआ जो उद्योग को उसी के गढ़ में चुनौती दे सकता था। उस समय के एक लेखक ने दृढ़ता-पूर्वक लिखा : "यह एक ऐसा संगठन है जिसके हाथ में अब गणराज्य का भाग्य निहित है। इसने मज़दूरों में राष्ट्रीय संगठन की महान शक्ति का प्रदर्शन किया है।"

इस युग के उत्तेजनापूर्ण वातावरण में नाइट्स पर उग्र (रैडिकल) विचारों को उभारने का जिनका विदेशी आन्दोलनकारी प्रचार करते हैं, आरोप लगाया गया और हेमार्केट स्क्वेयर के दंगे ने उसकी ताकत को उतनी ही जल्दी क्षीण भी कर दिया, जितनी जल्दी वह बढ़ी थी। किन्तु वस्तुतः नोवल ऐण्ड होली आर्डर अमरीकी परम्परा को ही निवाह रहा था और इसकी अन्दरूनी विचार-धारा राष्ट्रीय मजदूर यूनियन की विचार धारा से बहुत भिन्न नहीं थी। इसके नेता अन्ततोगत्वा एक औद्योगिक कामनवेल्थ की स्थापना का स्वप्न लिये थे जिसकी रूपरेखा तो हमेशा कुछ धुंधली होती थी किन्तु बल सदा की पूर्ति के लिए सीधी कार्रवाई के बजाय शिक्षा प्रक्रिया अपनाने पर दिया जाता था। इस व्ी प्रणाली के अन्तर्गत काम करने के लिये तैयार थे

सभी हड़तालों का विरोध किया।

ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने दक्ष, अदक्ष सभी कर्मचारियों को एक ही संगठन में यूनियनें बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने हमारी उदीयमान पूंजीवादी प्रणाली में औद्योगिक मजदूरों की भूमिका का विशेष महत्व स्वीकार किया और उन्हें विश्वास हो गया कि अब तक जैसा ट्रेडयूनियनवाद चला आ रहा है उसे अधिक व्यापक आधार पर बनाए गए श्रम-संगठन को अपना स्थान देना होगा। यह मनोवृत्ति कुछ हद तक बाद में आने वाले औद्योगिक यूनियनवाद की पूर्व परिचायक थी, किन्तु अलग अलग यूनियनों का एक संघ या कांग्रेस बनाने के बजाय नाइट्स निरन्तर मजदूरों की एकता पर बल देते रहे और वे एक ऐसा केन्द्रीय संगठन स्थापित करने की आशा रखते थे जिसमें सब उद्योगों और व्यवसायों के मजदूर शामिल हों। मजदूरों में सर्वत्र एक व्यापक एकता का आदर्श—"एक की चोट सबकी चोट है"—बड़ा उच्च आदर्श था, किन्तु अगर वह पूरा हो जाता तो मजदूर वर्ग तथा सामान्य समाज के लिए उससे बड़ा खतरा पैदा हो जाता। अकेले एकजूट मजदूर संगठन के हाथ में शक्ति केन्द्रित हो जाने से लोकतंत्रीय संस्थाओं के सामने गम्भीर संकट पैदा हो जाता।

ये संभावित आशंकाएं सामने आती या न आतीं, नाइट्स आव लेबर को अपने उद्देश्य में सफलता ही नहीं मिली। अदक्ष श्रमिकों को संगठित श्रमिकों के दायरे में लाने के उनके प्रयत्न अस्थायी रूप से सफल हुए। अदक्ष मजदूरों के संगठन के बारे में सिद्धान्त की दृष्टि से उनकी बात कितनी भी सही रही हो, वे जमाने से आगे की बात कर रहे थे। इन मजदूरों की विशाल संख्या, जो ज्यादातर विदेशों से नए नए आए हुए लोग होते थे, जाति, भाषा और धर्म की करीब-करीब अलंघ्य बाधाओं से अलग-थलग रहती थी। मालिक लोग संघर्ष और कटुता बढ़ाने के हर अवसर का तत्परता से लाभ उठाते थे जिससे उनमें कभी वास्तविक सहयोग नहीं हो पाता था। इसके अलावा मजदूरों में सदा नवागन्तुकों की बाढ़ सी आती रहती थी और जो लोग यूनियन की हरकतों में जरा भी हिस्सा लेते थे उनके स्थान पर हड़ताल को नाकामयाब बनाने वाले सस्ते मजदूर सदा बड़ी संख्या में उपलब्ध रहते थे। १८८० के दशक में अदक्ष औद्योगिक मजदूरों में न तो एकता थी और न सौदेबाजी की

ताकत जिससे संगठित श्रमिक आन्दोलन में अपने सन्निवेश को वे उपयोगी बना पाते। मालिकों के कभी ढीले न पड़ने वाले विरोध के सामने औद्योगिक यूनियनवाद का, कोयला खानों जैसे उल्लेखनीय अपवादों को छोड़ कर, सफलतापूर्वक विकास तव तक नहीं हो पाया जव तक १९२० के दशक में आव्रजन पर अंकुश नहीं लगाया गया और सन् १९३० के दशक में सरकार ने श्रमिकों के संगठन को सहयोग प्रदान नहीं किया।

परम्परागत ट्रेडयूनियनों पहले के मिस्त्रियों और शिल्पियों की प्रतिरूप के सदस्यों ने १८८० के दशक में यह वात महसूस की और अदक्ष मजदूर जिनने कमजोर सावित हुए उतने कमजोर मित्रों के साथ अपने भाग्य का गठवंधन करने के लिए वे अधिकाधिक अनिच्छुक हो गए। उन्होंने विशुद्ध धन्धे के आधार पर अपना संगठन करके अपने हितों की रक्षा करने के लिए नाइट्स द्वारा सिखाए गए मज़दूरों की एकता के पाठ को तिलांजलि दे देने की मजबूरी महसूस की। राष्ट्रीय यूनियनों ने नाइट्स आव लेवर का दृढ़ता से मुकावला किया और अमेरिकन फेडरेशन आव लेवर नए यूनिवनवाद का प्रतीक बन गया जिसका सिर्फ अपने सदस्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं से ही सरोकार था।

९ क्षुद्र दर्जियों ने फिलाडेलफिया में अमेरिकन होज़ कम्पनी के भवन में एक सभा करके ९ दिसम्बर, १८६९ को नाइट्स आव लेवर की स्थापना की। एक स्थानीय गारमेण्ट कटर्स ऐसोसियेशन के, जिसे अपने कल्याण कार्यक्रम को जारी रखने के लिए धन की कमी के कारण स्वयं को भंग कर देना पड़ा था, इन सदस्यों ने एक नई ऐसोसियेशन बनाने का फैसला किया जो शुरू-शुरू में किसी भी अन्य शिल्प यूनियन से अगर कुछ भिन्न थी तो सिर्फ इसी वात में कि यह एक गुप्त संस्था थी और इसकी गतिविधियां एक लम्बे संस्कार पर केन्द्रित थीं। किन्तु एक ग्रुप की दृष्टि मज़दूर संगठन के वारे में कहीं ज्यादा व्यापक थी और उसके साथी सदस्य शीघ्र ही आदर्शवादी उत्साह से आकर्षित हुए। यह एक नई मज़दूर एकता का स्वप्न था जिससे राष्ट्रीयता, लिंग, धर्म या रंग के भेदभाव के बिना राष्ट्र के सभी मज़दूरों को एक ही सुगठित संगठन में शामिल करना सम्भव होता।

नाइट्स आव लेबर के संस्थापकों के मन में वर्ग-संघर्ष की कोई भावना नहीं थी। उद्योग के दुर्ग पर हमला करने की उनकी कोई योजना नहीं थी, "वाजिब व्यवसाय के साथ उनका कोई संघर्ष और आवश्यक पूंजी से उनका कोई विरोध नहीं था।" यद्यपि सम्पत्ति के उत्पादकों को दासता और वेतन की हानि सम्बन्धी गुलामी से पूर्ण छुटकारा दिलाने की वे आशा रखते थे तो भी इस उद्देश्य की पूर्ति वर्तमान आर्थिक प्रणाली की बुराइयों को दूर कर तथा उत्पादकों की सहकारी संस्थाएं स्थापित कर शनैःशनैः की जानी थी। तब यथा समय एक औद्योगिक कामनवेल्थ बनता, जिसमें व्यक्ति और राष्ट्र की महानता का पैमाना भौतिक सम्पत्ति नहीं, बल्कि नैतिक धरातल होता।

फिलाडेल्फिया में सभा करने वाले ६ दर्जियों का नेता और इन विचारों का मुख्य प्रवक्ता यूरिया एस० स्टीफेन्स था वह केप मे, न्यूजर्सी में १८२१ में पैदा हुआ और उसे पादरी बनाए जाने के ख्याल से शिक्षा दी गई। १८३७ के आतंक के बाद पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होकर वह एक दर्जी का अप्रैण्टिस बन गया और १८४० में फिलाडेल्फिया में अपना धन्धा करने लगा। कुछ अरसे बाद उसने, वेस्ट इण्डीज़, मैक्सिको और कैलिफोर्निया का व्यापक भ्रमण किया किन्तु गृहयुद्ध से पहले वह पुनः फिलाडेल्फिया में वापस आ गया। १८६१ में उसने मज़दूरों के युद्ध-विरोधी सम्मेलन में भाग लिया और अगले वर्ष गारमेण्ट कटर्स ऐसोसियेशन की स्थापना में मदद दी। ट्रेड यूनियनिस्ट का हम जो अर्थ लगाते हैं उसमें वह कभी ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं रहा, बल्कि वह यूनियनों को बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण और सीमित दायरों वाली मानता था। अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण स्टीफेन्स मजदूरों के विश्वभ्रातृत्व का वह नज़ारा अपने सामने रखता था जिसका प्रतीक नाइट्स आव लेबर का वह गुप्त संस्कार था।

वह अपने साथियों को सलाह देता : "मज़दूरों के महान् भाई-चारे के बीच मैत्री स्थापित करो, हर समझदार मजदूर की शख्सियत में उद्योग का आदर करना सीखो, अपने किन्तु उपयोगी कारीगर का सम्मान करके जीवन पर से कपटी आवरण को हटा दो; मेल-मिलाप करके संयुक्त कार्रवाई करो...इस भाईचारे ने जो काम अपने हाथ में लिया है वह विश्व के अब तक के इतिहास

में सबसे महान् है......यह ईश्वर के पितृत्व के अमिट आधार और मनुष्य के भाईचारे के तज्जन्य युक्तियुक्त सिद्धान्त पर बना है...।"

उसके सब लेखों और भाषणों का यही राग था। मज़दूरों की सब शाखाओं को मिलाकर एक करने को अपने अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसने अलग-अलग धन्धों और व्यवसायों को संगठित करने का विचार त्याग दिया और उसने बहिष्कार और हड़तालें भी खत्म कर दी होतीं, जिनके बारे में वह समझता था कि इनके लाभ "आंशिक तथा क्षणिक" होते हैं। उसके स्वप्नों में सारी मानव-जाति बसी हुई थी। उसने लिखा : "जाति, पार्टी और राष्ट्रीयता सिर्फ ऊपरी पोशाकें हैं और ये विश्वजनक परमात्मा के भक्तों तथा विश्व-बन्धु मानव के सेवकों के हृदयों को एक करने में बाधक नहीं हैं।"

नाइट्स आव लेबर की स्थापना में स्टीफेन्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और जब राष्ट्रीय आधार पर इसका संगठन किया गया तो वह इसका पहला ग्रैण्ड मास्टर वर्कमैन बना। तो भी वह इसमें ज़्यादा समय तक नहीं रहा। वह राजनीति की ओर मुड़ गया, जैसे कि इस सदी के अन्य बहुत-से मज़दूर नेता मुड़ गए थे, और मुद्रा-सुधार में दिलचस्पी लेकर १८७८ में उसने ग्रीन बैक टिकट पर कांग्रेस में चुने जाने का एक असफल प्रयत्न किया। इसके बाद वह नाइट्स में अपने पद से इस्तीफा देकर मज़दूर आन्दोलन से बिल्कुल अलग हो गया और आर्डर के असाधारण उत्कर्ष को देखे बिना ही सन् १८८२ में चल बसा। तो भी उसका प्रभाव बना रहा। नाइट्स के अखबार "दि जर्नल आव यूनियन लेबर" ने उसकी मृत्यु की घोषणा पर लिखा : "हमारे सभी विधि-विधानों में उसके मस्तिष्क की छाप तथा वर्तमान युग की महान् समस्याओं में उसकी पैनी दृष्टि की प्रेरणा मिलेगी।"

इस बीच नाइट्स आव लेबर के मूल फिलाडेलफिया संगठन का बहुत धीरे-धीरे विस्तार हुआ। गोपनीयता का, जो संस्कार और समारोह की रहस्यमय अपील में वृद्धि करने और सदस्यों को मालिकों की सम्भावित बदले की कार्रवाई से बचने के लिए अपनाई गई थी, सख्ती से पालन किया गया। एक सम्भावित नए सदस्य को ग्रुप की एक सभा में बुलाया जाता था और उसे बताया नहीं जाता था कि क्या मामला है; और "मज़दूरों के उत्थान" के विषय में पूछे गए अनेक विषयों पर उसके जवाब अगर सन्तोषजनक होते थे

तभी उसे "दीक्षा" दिए जाने योग्य समझा जाता था। यह दीक्षा मौखिक शब्दों के माध्यम से दी जाती थी और बाहर वालों के पास आर्डर के अस्तित्व तक का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था, उसके उद्देश्य का पता लगाना तो दूर की बात थी। सब दस्तावेज़ों और नोटिसों में संगठन का नाम ५ सितारों से जताया जाता था। अस्थायी सदस्यों की भर्ती से संगठन के विस्तार की व्यवस्था रखी गई। दर्जीगीरी के अलावा अन्य धन्धों के मज़दूर १ डालर की 'दीक्षा फीस' देकर सदस्य बन सकते थे। जब उनकी संख्या पर्याप्त हो जाती थी तो वे परस्पर मिलकर अपनी निजी सभा बना सकते थे। किन्तु दूसरी सभा वस्तुतः १८७२ में ही कायम हो सकी, जिसमें जहाज बनाने वाले खाती शामिल थे। इसके बाद विकास की गति बढ़ गई। अगले दो वर्षों में फिलाडेल्फिया और उसके आस-पास कोई ८० सभाएँ बनीं और १८७४ में इस क्षेत्र के बाहर न्यूयार्क में पहली सभा स्थापित हुई। इन सभाओं में से सब में अलग-अलग धन्धों के मज़दूर शामिल थे, जैसे पोशाकों का कटिंग करने वाले, जहाज़ बनाने वाले, खाती, टिन, प्लेट और लोहा कर्मचारी, शाल बुनने वाले, राज, मशीन-चालक, लुहार, घरों में काम करने वाले खाती, संगतराश और सोने के पत्रे बनाने वाले आदि।

नाइट्स के विकास में अगला कदम जो मज़दूर एकता के अंतिम लक्ष्य की ओर इंगित करता था—स्थानीय सभाओं के प्रतिनिधियों की ज़िला सभाएं बनाना था। इनमें से पहली इकाई १८७३ में फिलाडेल्फिया में स्थापित हुई। उससे अगले वर्ष पश्चिम पर अभियान के लिए पहले कदम के रूप में एक सभा कामडेन, न्यूजर्सी में और दूसरी पिट्सबर्ग में कायम हुई। शीघ्र ही ओहायो, वेस्ट-वर्जीनिया, इण्डियाना, इलिनौयस, पेंसिलवेनिया, न्यूयार्क तथा न्यूजर्सी में जिला सभाएं कायम हुई, जिनके सदस्यों में शिल्प मज़दूरों के अलावा दक्ष तथा अदक्ष दोनों प्रकार के श्रमिक शामिल थे।

जैसे-जैसे समय गुजरता गया, विभिन्न व्यवसायों के श्रमिकों की मिश्रित सभाओं के रूप में अनेक स्थानीय सभाएँ स्थापित हुईं। खनिक, रेल कर्मचारी तथा इस्पात कर्मचारी अधिकाधिक संख्या में नाइट्स में शामिल हुए और जहां किसी एक व्यवसाय में अलग सभा स्थापित करने के लिए पर्याप्त सदस्य [illegible] थे, विशेषकर कस्बों और गांवों में, वहां मिश्रित सभाएं बनाने की सामान्य

परम्परा बन गई। अन्ततोगत्वा मिश्रित सभाओं की संख्या किसी एक व्यवसाय की सभाओं से ज्यादा बढ़ गई, और उनमें अदक्ष श्रमिकों के भी शामिल होने से नाइट्स का एक अपना खास रूप सामने आया। जब १४ ज़िला सभाएं बन गईं, जिनके करीब ९ हज़ार सदस्य थे तब आन्दोलन के नेताओं ने निर्णय किया कि एक राष्ट्रीय संस्था बनाने के लिए एक बृहत् सम्मेलन बुलाया जाए।

यह सम्मेलन जनवरी, १८७८ में रीडिंग, पेंसिलवेनिया में हुआ, जिसमें ३३ प्रतिनिधि शामिल हुए। लम्बे विचार-विमर्श के बाद एक संविधान स्वीकार किया गया जिसमें नाइट्स की सर्वोच्च अधिकारी संस्था के रूप में एक बृहत्सभा कायम की गई, जिसका जिला व स्थानीय सभाओं दोनों पर नियंत्रण रखा गया। नया संगठन सिद्धान्ततः अत्यधिक केन्द्रीभूत था किन्तु ज़िला सभाओं को अपने अपने क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे और संविधान में सिद्धान्ततः लिखे रहने पर भी उन पर केन्द्रीय संगठन का कभी भी कड़ा नियंत्रण नहीं रहा। किन्तु आर्डर सच्चे मायनों में, एक राष्ट्रीय संगठन बन गया, जब कि इससे पूर्ववर्त्ती कोई भी संगठन इन मायनों में राष्ट्रीय नहीं बन सका था। इसमें उनसे यह भी विशेषता थी कि उसकी सदस्यता, सम्बद्ध यूनियनों के जरिए न होकर वैयक्तिक आधार पर कायम रही। जो मज़दूर इसके सदस्य बनना चाहते थे वे सिर्फ एक स्थानीय सभा की सदस्यता के लिए प्रार्थनापत्र देते थे, उन्हें बाकायदा दीक्षित किया जाता था, वे अपनी सदस्यता फीस देते थे, सभाओं में भाग लेते और इस प्रकार मान्यता प्राप्त नाइट आव लेबर बन जाते थे।

सदस्यता सभी मज़दूरी कमाने वालों और भूतपूर्व मज़दूरों के लिए खुली हुई थी (यद्यपि भूतपूर्व मज़दूरों की संख्या किसी भी स्थानीय सभा में कुल सदस्यों की एक-चौथाई से ज्यादा नहीं हो सकती थी। सिर्फ वकील, डाक्टर, बैंकर, और जो शराब बेचते या शराब बेचकर जीवन निर्वाह करते थे, इनमें शामिल नहीं हो सकते थे। बाद में इन अपवादों में स्टाक मार्केट के दलाल और पेशेवर जुआरी भी शामिल कर दिए गए। संविधान में बाद में की गई एक व्यवस्था में कहा गया: "यह सम्मानीय श्रम की सब शाखाओं को एक तह में एकत्र कर देता है।"

संविधान की भूमिका में, जिसके सामान्य सिद्धान्त पहले के इण्डस्ट्रियल ब्रदरहुड से लिए गए थे, हाल की विपज्जनक घटनाओं तथा संचित सम्पत्ति द्वारा की गई चोटों की ओर ध्यान खींचा गया था और कहा गया था "कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसका अनिवार्य परिणाम श्रमजीवी मज़दूरों की गरीबी और निराशाजनक अर्धःपतन होगा।" नाइट्स ने घोषणा की कि "मज़दूरों को सिर्फ एकता से ही अपने श्रम का फल मिल सकता है और यह एकता स्थापित करने के लिए ही सहकारी प्रयत्नों से औद्योगिक वर्ग की ताकत का संगठन और संचालन करने की दृष्टि से हमने * * * * * (पांच सितारों का चिन्ह) कायम किया है।"

स्वतः संविधान में ही संगठित मज़दूरों की बहुत सी परम्परागत मांगें रखी गई थीं और कुछ नए लक्ष्य सुझाए गये थे। इसमें बहुत कुछ राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन की तरह ही सहकारी संस्थाओं की स्थापना, सार्वजनिक भूमि को वास्तविक बसने वालों के लिए रिजर्व रखने, ८ घंटे के दिन तथा एक अधिकृत मुद्रा की मांग की गई थी। इसने जेल के मज़दूरों के लिए ठेका-प्रणाली की समाप्ति, बच्चों से मज़दूरी का काम लेने पर प्रतिबन्ध, स्त्री-पुरुष दोनों के लिए समान वेतन, श्रम सम्बन्धी आंकड़ों के लिए ब्यूरो की स्थापना, और बाद में एक संशोधन द्वारा रेलों और तार-प्रणाली पर सरकारी स्वामित्व तथा आयकर के एक क्रमिक स्केल की मांग की।

इन सब चीजों का प्रतिपादन या तो सुधारवादी था या राजनीतिक। जहाँ तक औद्योगिक कार्रवाई का ताल्लुक था, नाइट्स आव लेबर बहिष्कारों का समर्थन करता था, जो बाद में अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो गए किन्तु हड़तालों के बजाय, जिसके वह पहले बिल्कुल खिलाफ था, पंच-फैसले का प्रबल समर्थन करता था। यद्यपि बहुत सावधानी से निश्चित की गई कुछ संकट की परिस्थितियों में उपयोग के लिए अन्ततः एक प्रतिरोध कोष स्थापित किया गया तो भी यह व्यवस्था कर दी गई कि संचित कोष का सिर्फ ३० प्रतिशत ही सीधे किन्हीं हड़तालों के लिए उपयोग किया जा सकता है। ६० प्रतिशत सहकारी संस्थाओं के लिए और १० प्रतिशत शिक्षा के लिए रखा गया। नाइट्स को मानना पड़ा कि कभी हड़तालें भी ज़रूरी हो सकती हैं किन्तु वे तब तक उनका समर्थन करने को अनिच्छुक रहते थे जब तक उनका

कार्यकारी बोर्ड उस पर अपनी निश्चित मंजूरी नहीं दे देता था। बाद में १८८४ के संशोधित संविधान में कहा गया: "हड़तालें, बहुत हुआ तो सिर्फ अस्थायी राहत प्रदान करती हैं और सदस्यों को शिक्षा, सहकारिता और राजनीतिक कार्रवाई पर निर्भर रहना और इनके जरिए मजदूरी-प्रणाली के खात्मे पर निर्भर करना सिखाया जाना चाहिए।"

फूंक-फूंक कर कदम रखने के इस रवैये का आंशिक कारण १८७७ की रेल हड़ताल में प्राप्त किए गए अनुभव थे। इन हड़तालों ने जो अव्यवस्था की स्थिति पैदा की, जिसमें फिर संघीय सेनाओं को हस्तक्षेप करना पड़ा, उससे नाइट्स आव लेबर के नेताओं के मन में इस प्रकार की सीधी कार्रवाई की उपयोगिता में सन्देह पैदा हो गया था। किन्तु इस समस्या का उनके पास कोई हल नहीं था कि अगर मालिकों ने उनके प्रतिनिधियों से व्यवहार करने से इन्कार कर दिया तो पंच-फैसले को अमल में कैसे लाया जाएगा। इसलिए अपनी धारणाओं के बावजूद नाइट्स को हड़तालों में फंसना पड़ा और जब उद्योग द्वारा स्थानीय सभाओं से बदला लिए जाने का खतरा पैदा होता तो कार्यकारी बोर्ड उनकी सहायता करना अपना फ़र्ज समझता था।

हड़ताल के प्रश्न की तरह राजनीतिक मामलों पर भी नोबल और होली आर्डर के विचार अस्पष्ट थे। जिन सुधारों की उन्होंने कल्पना की थी वे कुछ मामलों में राष्ट्रीय मजदूर यूनियन से भी आगे बढ़े हुए थे तो भी नाइट्स एक राजनीतिक संगठन के बजाय मुख्यतः औद्योगिक संगठन ही रहना चाहता था। यद्यपि ये लाबींग किया करते थे और समय-समय पर राजनीति में सीधा चंचुपात भी करते थे तो भी उन्होंने एक मजदूर दल बनाने की कोई कोशिश नहीं की। १८८४ में वृहत्सभा ने घोषणा की कि "राजनीति का स्थान उद्योग से नीचे रखा जाना चाहिए", और यह स्पष्ट कर दिया कि "यह आर्डर किसी भी प्रकार अपने सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रकट किए गए विचारों से बंधा हुआ नहीं है।"

संक्षेप में नाइट्स आव लेबर की बुनियादी नीतियां शुरू में यूरिया स्टीफेन्स द्वारा प्रस्तुत नमूने पर कुछ अस्पष्ट आदर्शवादी और मानवतावादी रहीं और कभी-कभी वे अत्यधिक परस्पर-विरोधी मालूम पड़ती थीं। नाइट्स अपने औद्योगिक स्वरूप पर जोर देते थे तो भी सामाजिक सुधारों के एक

व्यापक कार्यक्रम के लिए आन्दोलन करते थे, वे राजनीतिक कार्रवाई की अपील करते थे पर साथ ही इस बात से इन्कार भी करते थे कि राजनीति से उनका कोई सीधा सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त यह आर्डर यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से अधिक केन्द्राभिमुखी था, जिससे कि उस पर ये आरोप लगाए जाते थे कि इसकी नीतियां मुट्ठीभर नेता तानाशाही ढंग से निर्धारित करते हैं, तो भी इसके सदस्य अपने मामले बहुत कुछ अपने ही हाथ में रखते थे और अपनी इच्छा से कार्य करते थे।

पहली वृहत्सभा ने आगे विस्तार के लिए आधार तैयार किया। एक वर्ष बाद सदस्य संख्या ९२८७ से बढ़कर २८१३६ हो गई और फिर १८८१ में घटकर १९४२२ रह गई। जो गोपनीयता पहले मालिकों के हमले से सदस्यों की रक्षा करती थी, वही अब समस्त आर्डर पर बुरा प्रभाव डालने लगी। लोग इसे माली मैगायर्स जैसा ही एक और गुप्त संगठन समझने लगे और कैथोलिक चर्च इसके प्रति शंकालु और शत्रुतापूर्ण हो गया कि कैथोलिकों को इसमें शामिल होने से मना कर दिया गया। फलतः आर्डर की गोपनीयता समाप्त करने के लिए कदम उठाए गए, दीक्षा की कार्रवाई में से शपथ ग्रहण उड़ा दिया गया और संस्कार में से सब शास्त्रीय उद्धरण निकाल दिए गए। कार्डिनल गिब्बन्स के माध्यम से, जिसे दिखाया गया कि संशोधित संस्कार में धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ़ कोई बात नहीं है, पोप को अपनी निन्दा वापस लेने और चर्च की रजामन्दी देने के लिए मनाया गया। गोपनीयता समाप्त करने के बाद सदस्यता फिर तेजी से बढ़ी। १८८२ में यह दुगनी होकर ४२००० से अधिक और अगले तीन वर्षों में एक लाख से अधिक हो गई।

वृहत्सभा के निर्माण के एक वर्ष बाद ही १८७९ में स्टीफेन्स के अवकाश-ग्रहण के पश्चात् टेरेंस वी० पाउडरली ग्रण्डमास्टर वर्कमैन के उच्च पद पर उसका उत्तराधिकारी चुना गया। यह युवक मजदूर आन्दोलनकारी उस समय सिर्फ़ ३० वर्ष का था और १८४९ में कारबॉण्डेल (पेंसिलवेनिया) में पैदा हुआ था। वह १८२० के दशक में इस देश में आकर बसे आयरिश कैथोलिक मां-बाप का पुत्र था। जब वह लड़का ही था, तब उसने स्थानीय रेलवे यार्ड में स्विच टेण्डर का काम किया था किन्तु शीघ्र ही उसने मशीनचालक बनने का फैसला कर लिया। १७ वर्ष की आयु में वह इस धन्धे में अप्रैण्टिस बन गया

और ३ वर्ष बाद स्क्रैण्टन में डेलावेयर ऐण्ड वेस्टर्न रेलरोड के वर्कशाप में उसे दिहाड़िये का काम मिल गया।

अगले कुछ वर्षों में वह क्रमश: मशीनचालकों व लुहारों की अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन में शामिल हुआ, औद्योगिक ब्रदरहुड का पेंसिलवेनिया में संयोजक बना और १८७४ में नाइट्स आव लेबर में दीक्षित किया गया। कुछ समय की "खामोशी" के बाद उसने २२२ नं० की सभा बनाई और उसका मास्टर वर्कमैन बना। साथ ही नं० ५ जिला सभा का वह पत्राचारी सचिव भी रहा। मजदूरों की राजनीति में ज्यादा और ज्यादा दिलचस्पी लेने के कारण उसने ग्रीन बैक लेबर पार्टी की गतिविधियों में भी भाग लिया और १८७८ में इसके टिकट पर वह स्क्रैण्टन का मजदूर मेयर चुना गया।

पाउडरली १८८४ तक मेयर बना रहा, यद्यपि इस बीच वह नाइट्स आव लेबर का ग्रैण्डमास्टर वर्कमैन चुना जा चुका था। वह सदा विविध और बहुत से विषयों में दिलचस्पी रखता था। उसने कानून पढ़ा और फिर वकालत की, एक ग्राम स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर काम किया, एक परचूनिये स्टोर का आंशिक मालिक व मैनेजर और आयरिश लैण्ड लीग का उपप्रधान बना। एक बार उसने वाशिंगटन में श्रमसांख्यिकी ब्यूरो के जो मुख्यत: नाइट्स आव लेबर के प्रयत्नों से स्थापित हुआ था, मुखिया पद के लिए असफल प्रार्थनापत्र दिया और १८९३ में जब आर्डर की अध्यक्षता अन्तिम रूप से उसके हाथ से जाती रही तब उसे आव्रजन ब्यूरो में एक सरकारी पद मिल गया। १९२४ तक जीवित रहता हुआ वह पहले कमीशनर जनरल और बाद में सूचना विभाग का मुखिया रहा और तब मजदूर नेता के रूप में उसके तूफ़ानी जीवन को १८८० के दशक के औद्योगिक संघर्ष की उथल-पुथल से बहुत दूर रहने वाली पीढ़ी ने करीब-करीब भुला दिया।

पाउडरली एक मजदूर नेता लगता नहीं था। वह दुबला और औसत से कम ऊँचा था, उसके घुँघराले भूरे बाल थे, सुन्दर झुकी मूँछें थीं और उसकी कोमल नीली आँखों पर चश्मा चढ़ा रहता था। वह प्रचलित ढंग के अच्छे कपड़े पहनता था। उसकी सामान्य पोशाक में डबलब्रेस्ट का सुन्दर काले कपड़े का कोट, खड़े कालर, सादी टाई, काली पतलून और छोटे तंग जूते शामिल थे। उसके तौर तरीक़े औपचारिकतापूर्ण व शिष्ट होते थे, जिनसे

प्रतीत होता था कि वह कुलीन और संस्कारी आदमी है। एक मज़दूर पत्रकार जॉन स्विण्टन ने लिखा है: "अंग्रेज उपन्यासकार पाउडरली की सी शक्ल के आदमियों को अपना कवि, नाव का खिवैया, दार्शनिक और प्रेम में पगे नायक चित्रित करते हैं किन्तु ऐसी शक्ल के किसी आदमी को आज तक किसी ने सींग सी मजबूत कलई वाले १० लाख मज़दूरों का नेता चित्रित नहीं किया है।"

अपने विचारों में वह बिल्कुल अकृत्रिम, करीब-करीब दकियानूसी था। शराब के व्यसन से मुक्त वह मयखानों के खिलाफ संघर्ष करता रहता था और जो शराब पीना चाहते थे उनके प्रति उसमें ज़रा भी सहिष्णुता नहीं थी। अपने अनुयायियों में जहां वह प्रेम और वफादारी की दोनों भावनाएं उत्पन्न करता था वहां वह आसानी से मिलता-जुलता नहीं था और मज़दूरों की सभाओं में जाकर वस्तुतः प्रसन्न नहीं होता था। हंसी मजाक का उसका अपना ही ढंग था, जो उसके आत्मचरित सम्बन्धी लेखों से स्पष्ट है किंतु उसमें ले-दे की स्वाभाविक भावना नहीं थी।

ग्रैण्डमास्टर वर्कमैन का पद सम्हालने के बाद नाइट्स आव लेबर की सदस्यता के निर्माण में उसमें घोर परिश्रम किया। वह धाराप्रवाह और अपनी बात दूसरे के हृदय में बैठा देने वाला वक्ता और अथक पत्र-लेखक था। तो भी उत्साह के इन प्रारम्भिक दिनों में भी वह मज़दूर आन्दोलन में विलियम सिलविस जैसे नेताओं की सी निष्ठा से सर्वात्मना नहीं जूझा। वह निरन्तर शिकायत किया करता था कि उसके अन्य कार्य उसे ग्रैण्डमास्टर वर्कमैन के पद के कार्य को पूरा समय नहीं देने देते और कभी-कभी आवेश-पूर्वक यह भी शिकायत किया करता था कि उसका स्वास्थ्य (जो वस्तुतः बहुत अच्छा नहीं था) उससे की जाने वाली आशाओं को पूरा करने लायक नहीं है। वह भाषण देने की सतत प्रार्थनाओं पर न केवल रोष प्रकट करता था, अपितु कभी कम न होने वाली अहंमन्यता की भावना से, वह यह आग्रह किया करता था, कि जब कभी वह भाषण दे तो उसके लिए परिस्थितियां आर्डर में उसके उच्च पद के अनुकूल होनी चाहिएँ।

'जर्नल आव युनाइटेड लेबर' में एक बार उसने गुस्से से लिखा: "मैं आमोद-विहारों (पिकनिकों) में भाषण नहीं दूंगा। मज़दूर सम्बन्धी प्रश्नों पर जब मैं भाषण दूं तो मैं चाहूँगा कि मेरा प्रत्येक श्रोता कम से कम दो

घण्टे तक मेरी बात ध्यान से सुने और इस दो घण्टे में भी मैं केवल संक्षेप में ही अपनी बात कह सकूंगा। पिकनिक में जहाँ लड़के-लड़कियां मिलकर शराब पीएंगे मैं नहीं बोल सकता......यदि मैंन सुना कि मेरे पिकनिकों में भाषण देने का विज्ञापन किया गया है तो मैं अपराधियों के खिलाफ आर्डर के प्रशासनिक मुखिया का उपहास करने का मुकदमा चलाऊंगा........"

इस अहंमन्यता की मनोवृत्ति के बावजूद और शायद इस कारण ही एक संयोजक के रूप में उसकी कुशलता से इन्कार नहीं किया जा सकता और इसके अतिरिक्त कैथोलिक चर्च के साथ झगड़े को जिस खूबी से उसने निबटाया उसी की बदौलत कार्डिनल गिब्बन्स ने पोप से नाइट्स की हिमायत की। वह मज़दूर-राजनीति का भी चतुर खिलाड़ी था और उसने एक निजी मशीन बना ली थी जिससे वह विकास और विस्तार के इन वर्षों में बृहत्सभा पर अपना निकट नियंत्रण कायम रख सका। ऐसे भी मौके आए, जब उसने कहा कि वह इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता कि वह अपना पद किसी दूसरे को सौंप दे, किन्तु इससे भी वह अपनी नीतियों के किसी भी विरोध का दृढ़ता से मुकाबला करने से बाज नहीं आता था, जबकि वह अपने विरोधियों पर तीव्र प्रहार करता और अपने पद के साथ दृढ़ता से चिपका रहता।

नाइट्स ग्राव लेबर ने अपने मूल प्रथम सिद्धान्तों में जो आधारभूत उद्देश्य प्रकट किए थे, पाउडरली के विचार और सिद्धान्त उनसे बहुत मेल खाते थे और इनका वही आदर्शवादी, मोटे तौर से मानवतावादी और प्रायः परस्पर विरोधी क्षेत्र था। वह सीधी आर्थिक कार्रवाई के बजाय शिक्षा में विश्वास करता था किन्तु यह सदा स्पष्ट नहीं होता था कि वह किस चीज़ के लिए आन्दोलन कर रहा है। वह बड़ी अस्पष्ट सामान्य सी बातें करता था जिन पर लफ्फाजी का मुलम्मा चढ़ा होता था।

एक मौके पर उसने कहा: "नाइट्स आव लेबर पार्टी से ऊंचा तथा महान है। दलगत विद्वेष और संघर्ष को देखते हुए जितना प्रतीत होता है, उससे ज्यादा उज्ज्वल इसका भविष्य है। उत्पीड़न और इजारेदारी, इन दो शैतानों के खिलाफ हमने जो जिहाद बोल रखा है, उसमें हम हर समाज, हर पार्टी और धर्म के व्यक्तियों तथा प्रत्येक राष्ट्र का सहयोग पाने के लिए प्रयत्न शील हैं और इस जिहाद में हमने अपने पीछे छोड़े हुए पुल जला दिए

हैं, हमारा लक्ष्य समस्त संसार में मानव के पूर्ण अधिकारों की स्थापना करना है।

सहकारिता वह साधन था, जिसके जरिये वह प्रत्यक्षतः इन आदर्शवादी लक्ष्यों की पूर्ति की आशा रखता था। कभी कभी वह किसी अन्य सुधार पर ज्यादा जोर देता प्रतीत होता था। १८८२ में उसने वृहत्सभा में कहा : "मेरी राय में आज का मुख्य और सबके ध्यान देने लायक प्रश्न जमान का प्रश्न है .....मुझे जमीन दो, तब तुम ८ घण्टे के दिन के कानून जितने मर्जी बना लेना फिर भी मैं उन सब को चकमा देकर उन्हें व्यर्थ कर दूंगा।" शराबखोरी बन्द करने के अपने उत्साह के कारण भी उसने इस आन्दोलन पर ज़ोर दिया। 'रम बेचने वाले' तथा रम पीने वाले पर समय-समय पर चोट करते हुए उसने लिखा : "कभी-कभी मैं सोचता हूं कि यह मुख्य सवाल है।" किन्तु देर-सवेर वह इसी मान्यता पर लौट आता कि सहकारिता ही मज़दूरों की समस्याओं का अंतिम हल है।

नाइट्स आव लेबर ने इन दिशाओं में अनेक सक्रिय कदम उठाए। बहुत सी जिला सभाओं ने उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों किस्म की कुल मिलाकर १३५ सहकारी संस्थाएं कायम कीं और राष्ट्रीय संगठन ने कैनेलबर्ग (इण्डियाना) में स्वयं एक कोयला खान खरीदी और उसका संचालन किया। किन्तु ये संस्थान चाहे वे खान उद्योग में, टीन-कनस्तर के उद्योग में, जूता बनाने, मुद्रण या अन्य उद्योगों में स्थापित किए गए हों उन्हीं कारणों से फेल हो गए, जिनसे इस प्रकार के पहले के अधिकांश परीक्षण फेल हो गए थे। निजी उद्योग से प्रतिस्पर्धा करने, अपने उद्योगों को विस्तार करने के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध करने या उनमें कुशल प्रबन्ध व्यवस्था स्थापित करने में नाइट्स आव लेबर राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन से ज्यादा सफल नहीं हुआ।

इन जोखिम के कामों में उनके कोष काफी खर्च हो गए और आर्डर की अंतिम समाप्ति में इनकी विफलता का महत्वपूर्ण योग रहा। तो भी पाउडरली अपने इस विश्वास पर जमा रहा कि मज़दूर सहकारिताओं के माध्यम से ही आत्मनियोजन स्थापित कर सकते हैं इसी में उनका अंतिम कल्याण निहित है।

१८८० में उसने वृहत्सभा में कहा : "संसार के पुरुष श्रमजीवियों और महिला श्रमजीवियों की आँखें सहकारिता पर ही टिकाई जानी चाहिएं, सहकारिता पर उनकी आशाएं केन्द्रित की जानी चाहिएं......कोई वजह नहीं कि मज़दूर सहकारिता के जरिये खान, फैक्ट्री और रेलों के मालिक बन कर उनका संचालन न कर सकें। सहकारिता के जरिये ही एक ऐसा समाज स्थापित किया जा सकता है जिसमें आदमी अधिक से अधिक व्यक्तियों की अधिक से अधिक भलाई करने के उद्देश्य से लोग परस्पर मिलकर काम करें और जो आदमी मेहनत करने के लिए तैयार हो उसे उसका उचित स्थान मिले। आन्दोलन की उसने क्रांति से तुलना की और जब नाइट्स इसका परित्याग कर चुके उसके बहुत देर बाद तक वह अन्ततोगत्वा सहकारी कामन-वेल्थ के निर्माण में अपना विश्वास प्रकट करता रहा। वर्षों बाद उसने आत्मचरित "द पाथ आई ट्रोड" में लिखा : "मेरा यह विश्वास अब भी कायम है कि सहकारिता एक दिन अवश्य वेतन प्रणाली का स्थान लेगी।"

ये दीर्घकालीन लक्ष्य ही यद्यपि उसकी वास्तविक चिन्ता के विषय थे, तो भी आर्डर के मुखिया होने के नाते उसे काम के कम घण्टे और अधिक वेतन जैसे तात्कालिक और व्यावहारिक मामलों को जिनमें नाइट्स की स्वयं अधिक दिलचस्पी थी हाथ में लेना पड़ता था। इससे हड़तालों का प्रश्न उठ खड़ा होता था। शाँति का आदर्शवादी व्यक्ति होने के कारण पाउडरली उनका विरोध करता था। १८८३ में उसने लिखा : "समय की पुकार हड़तालों को खत्म कर देना है। यह इलाज अनुभव से मालिक और मज़दूर दोनों के लिए मंहगा सिद्ध हुआ है।" बाद में उसने शेखी बघारी : "जनरल मास्टर वर्क-मैन के पद पर १४ वर्ष के अपने कार्यकाल में मैंने एक भी हड़ताल का आदेश नहीं दिया।" किन्तु १८८० के दशक के इस महत्वपूर्ण सवाल पर उसका यह रवैया ही शायद उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। जब नाइट्स आव लेवर अपने प्रशासनिक मण्डल की स्वीकृति से या उसके बिना ही बार-बार हड़तालों में उलझ गए तो ग्रैण्डमास्टर वर्कमैन की उन्हें सहयोग देने की जिम्मेदारी थी, जिससे वह बच नहीं सकता था। पाउडरली ने अपने इस विश्वास के बावजूद कि ये हड़तालें व्यर्थ हैं, कभी कभी इन हड़तालों को साहस पूर्ण सहयोग प्रदान किया, लेकिन कहीं-कहीं उसने इतना डरपोकपना

दिखाया कि वह मालिकों से कैसा भी समझौता करने के लिए तैयार हो गया। उसके ढुलमुल रवैये से प्राय: विभ्रम पैदा हो जाता था और मजदूरों का वह संयुक्त मोर्चा टूट गया जो किसी और के दृढ़ नेतृत्व में शायद हड़तालों को वस्तुत: सफल बना देता।

पाउडरली दिल से मानवतावादी था। वह सोचता था कि उत्पादक वर्ग को सामान्यत तत्कालीन समाज में एक ऊँचे स्तर पर उठा लिया जाए। बाद में उसने अपनी आत्मकथा में लिखा "अगर मुझे स्वयं को कोई नाम देने का हक है तो मैं समता स्थापित करने वाला कहूँगा।" तात्कालिक, अल्पकालिक उद्देश्यों के प्रति जिनमें मज़दूरी कमाने वालों की हैसियत को अधिकाधिक स्वीकार करने वाले अधिकांश मजदूरों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, उसकी अधीरता का इससे अच्छा चित्रण नहीं हो सकता था।

अपने पद पर स्वयं रहम खाते हुए एक बार उसने लिखा: "जरा सोचो तो, मैं हड़तालों का विरोध करता हुआ भी सदा हड़ताल करता रहता हूँ......जिन महान् चीजों के बारे में हम अपने लोगों को शिक्षित कर रहे हैं उनके लिए इस जमाने की प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में अपनी कलम से जूझते हुए भी छोटी-छोटी बातों के लिए अपनी सारी शक्ति से लड़ रहा हूं। हमारे आर्डर ने मुझे इस उच्च पद पर इसलिए रखा है क्योंकि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों पर ऊँची टेक लेकर मैंने राष्ट्र में सम्मान का स्थान प्राप्त किया है। तो भी हमारे आर्डर के मज़दूरों ने जिस मिट्टी को वे रौंदते हैं उसे फैंक-फैंक कर मुझे दीवार की नींव में ही व्यस्त रखा है।"

१८८० के दशक में जब पुन: कठिन समय आया और वेतनों में व्यापक कटौती तथा बेकारी का सामान्य चक्कर फिर चला तब नाइट्स आव लेबर ने वे हड़तालें कीं जिससे पहले तो उसका चाम्तकारिक विकास हुआ और तब शनै: शनै: ह्रास हो गया। पाउडरली की परीक्षा हुई और वह विफल रहा किन्तु नोबल ऐण्ड होली आर्डर का उत्थान और अन्तत: उसका पतन दोनों ही उन आर्थिक और सामाजिक ताकतों की वजह से हुए जिन पर उसका कोई बस नहीं था।

बेचैन मज़दूरों ने जब माल की लागत कम करने की कोशिश करने वाले

मालिकों की ज्यादतियों का मुकाबला करना चाहा तो १८८३-८४ में फॉल रिवर में काँच मज़दूर यूनियनों, तार-कर्मचारियों, तथा सूत कातने वालों ने, फिलाडेलफिया के जूते बनाने वालों तथा गलीचा बुनने वालों ने, पेंसिलवेनिया और हॉकिंग वैली (आहायो) के खनिकों ने और यूनियन पेंसिफिक की वर्कशाप के कर्मचारियों तथा ट्राय के लोहे की ढलाई करने वालों ने हड़ताल कर दी। नाइट्स आव लेबर ने इनमें से प्रत्येक हड़ताल में भाग लिया और चार हड़तालों में प्रमुख भूमिका अदा की। सबसे महत्व की बात तो यह थी कि मालिकों ने जहाँ और हड़तालों को कुचल दिया वहां जिन हड़तालों में नाइट्स ने भाग लिया वे सब, एक अपवाद को छोड़ कर, सफल रहीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हड़ताल रेलवे वर्कशाप के कर्मचारियों की थी जिसने यूनियन पैसिफिक को वेतनों में कटौती बहाल करने पर मजबूर कर दिया।

इस हड़ताल में मज़दूरों की विजय मुख्यत: जोसेफ आर. बुकानन के दुर्धर्ष नेतृत्व के कारण हुई। बुकानन एक उग्र मज़दूर आन्दोलनकारी था जो १८८२ में नाइट्स में शामिल हुआ था। कोलोरैडो में कभी खनिजों के अन्वेषक पद पर काम करने वाला यह व्यक्ति नए पश्चिम का प्रतीक—विशालकाय, दृढ़ और दब-दबे वाला आदमी था। वर्कशाप के कर्मचारियों का नेतृत्व करने में उसकी सफलता का मुख्य कारण था......यूनियन पैसिफिक एम्प्लायीज़ प्रोटैक्टिव ऐसोसियेशन की स्थापना करके और बाद में नाइट्स आव लेबर की स्थानीय सभाएं कायम करके मज़दूरों में एकता की भावना उत्पन्न करना।

यूनियन पैसिफिक की इस हड़ताल के एक वर्ष बाद तथाकथित साउथवेस्ट सिस्टम की रेलों—मिसूरी पैसिफिक, मिसूरी, कन्सास और टैक्सास तथा वाबाश की रेलों पर भी रेलवे वर्कशाप के कर्मचारियों की हड़ताल हुई। यकायक काम बन्द होने से इस हड़ताल के शुरू होते ही बुकानन पश्चिमी रेलवे पर नाइट्स आव लेबर की सभाओं के प्रतिनिधि के रूप में शीघ्र घटनास्थल पर पहुँच गया और साउथवेस्ट सिस्टम के असन्तुष्ट मज़दूरों का स्थानीय सभाओं में संगठन कर यूनियन पैसिफिक पर प्राप्त की गई सफलता को दोहराया। ट्रेन-कर्मचारियों के सहयोग से वर्कशाप के हड़ताली कर्मचारी इतना मजबूत मोर्चा कायम कर सके कि उन्होंने पुन: अपनी माँगें पूरी करा लीं।

इन विजयों ने जो १८७७ के रेल-हड़तालों के दु:खद अनुभवों के बाद

आश्चर्यजनक प्रतीत होती थीं, नाइट्स आव लेवर की कीर्ति में चार चाँद लगा दिए और उसकी प्रतिष्ठा वढ़ने लगी, यद्यपि हड़तालों में सिर्फ स्थानीय सभाओं ने भाग लिया था। किन्तु कुछ अरसे के वाद १८८५ में इससे भी वड़ी सफलता प्राप्त की गई जव नोवल एण्ड होली आर्डर की वावाश में और ज़्यादा झगड़ों की वदौलत समस्त साउथवेस्ट सिस्टम पर नियन्त्रण रखने वाले शक्तिशाली, चतुर और अच्छे-बुरे की परवाह न करने वाले महाजन जे गोल्ड से सीधी टक्कर हुई। वावाश रेलवे ने अप्रैल-मई में वर्कशाप में नाइट्स आव लेवर के सदस्य कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया जो स्थानीय यूनियनों को जान-बूझ कर तोड़ने का एक प्रयत्न प्रतीत होता था। गत वर्ष मोवरली (मिसूरी) में जो जिला-सभा आयोजित की गई थी उसने तुरन्त हड़ताल का आह्वान किया और राष्ट्रीय सदर मुकाम से सहायता की अपील की। प्रशासनिक वोर्ड की नीति अव भी हड़ताल के विरुद्ध थी किन्तु उसे यह मानना पड़ा कि रेल-कर्मचारियों के संगठन को इस चुनौती में आर्डर का अस्तित्व ही दाँव पर लगा हुआ है। जव वावाश ने कर्मचारियों की छटनी करने से साफ इन्कार कर दिया तव वोर्ड कार्रवाई करने पर मजवूर हुआ। नाइट्स आव लेवर के जो सदस्य तव भी वावाश में काम कर रहे थे, उन्हें हड़ताल की हिदायत की गई और साउथ-वेस्ट सिस्टम की अन्य रेलों पर तथा यूनियन पैसिफिक पर काम करने वालों से कहा गया कि वे वावाश का कोई काम न करें। मज़दूरों ने उत्साह से अपनी जिम्मेदारी निभाही। ट्रेनें रोक दी गईं, डिव्वे अलग कर दिए गए, इंजन वेकार कर दिए गए और समस्त साउथवेस्ट में व्यापक विध्वंसात्मक कार्रवाइयाँ हुईं जिनमें कभी-कभी उपद्रव और हिंसात्मक काम भी हुए।

अपनी समस्त परिवहन-प्रणाली पर जिसे मालूम होता था, कि नाइट्स विल्कुल वन्द कर देंगे, आए इस खतरे ने गोल्ड को समझौते पर विचार करने को मजवूर कर दिया। न्यूयार्क में अनेक वैठकें की गईं और सारा देश यह देखकर हैरान रह गया कि राष्ट्र की एक सवसे वड़ी रेल-प्रणाली के प्रवन्धक एक राष्ट्रवादी मज़दूर-संगठन के कार्यकारी वोर्ड के साथ समझौते की वातचीत कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा समझौता हो भी गया। जिन रेलों पर गोल्ड का नियन्त्रण था उन पर

नाइट्स आव लेबर के खिलाफ भेदभाव को ख़त्म करना उसने स्वीकार कर लिया और कहा जाता है कि उसने यहाँ तक कहा कि मैं मज़दूर यूनियनों में विश्वास करने लगा हूँ और चाहता हूँ कि मेरे सब रेल-कर्मचारी संगठित हों। पाउडरली ने हड़ताल उठा ली और वचन दिया कि रेलवे अधिकारियों के साथ आगे बात-चीत किए बिना भविष्य में काम बन्द करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

'लुई क्रानिकल' ने आश्चर्य से कहा : "बाबाश में नाइट्स की विजय हुई है। इस या अन्य किसी देश में पहले ऐसी कोई विजय प्राप्त नहीं की गई।"

राष्ट्र के मज़दूरों के लिए सामान्यतः गोल्ड का इस प्रकार घुटने टेक देना उस संगठन में शामिल होने के लिए आतुर हो उठने का संकेत था, जिसने स्वयं को इतना शक्तिशाली सिद्ध किया। अगले कुछ महीनों में नाइट्स आव लेबर की स्थानीय सभाएँ इतनी अधिक संख्या में बनीं जितनी पिछले १६ वर्षों में भी नहीं बनी थीं। नए सदस्य ज़्यादातर, रेलों, खानों तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखानों के अदक्ष और अर्धदक्ष मज़दूर बने जिससे विशेष रूप से तथाकथित मिश्र-सभाएँ ताकतवर हुईं। किन्तु इनमें सभी धन्धों और व्यवसायों का प्रतिनिधित्व था और कुछ ऐसे वर्ग के लोग भी शामिल थे जो मज़दूरों की श्रेणी में नहीं आते थे, जैसे क़िसान, दूकानदार और छोटे कार्य-नियोजक। इनके अतिरिक्त हज़ारों महिलाएँ और नीग्रो भी आर्डर में शामिल हुए। १ जुलाई, १८८५ तथा ३० जून, १८८६ के बीच स्थानीय सभाओं की संख्या १६१० से ५८६२ और सदस्य संख्या १ लाख से बढ़ कर ७ लाख से कुछ अधिक हो गई। एक मज़दूर अखबार के सम्पादक ने खुशी से कहा : "अब तक के सम्पूर्ण इतिहास में पहले कभी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला, जैसा कि आजकल आर्डर आव नाइट्स आव लेबर का कूच।"

नए सदस्यों की ऐसी भीड़ पड़ी और परेशान संयोजकों ने नए सदस्य इतनी शीघ्रता से बनाए कि स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो गई और कुछ देर के लिए उन्हें नई सभाएँ बनाना बन्द करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि आर्डर का विस्तार बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था। बाद में पाउडरली ने कहा : "कम-से-कम ४ लाख आदमी सिर्फ कौतूहलवश सदस्य बने और उनसे

नफा के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ।" तो भी १८८६ में ऐसा लगता था कि नाइट्स आव लेबर ने सारे मज़दूर आन्दोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है और वस्तुतः वह सर्वशक्तिमान बन गई है।

नाइट्स का जो आश्चर्यजनक विस्तार हुआ था उसे अफवाह उड़ाने वालों ने और भी बढ़ा-चढ़ा कर बताया। कहा गया है कि नाइट्स के २५ लाख सदस्य और एक करोड़ २० लाख डालर का हड़ताल-कोष हो गया है। रूढ़िवादी समाचार-पत्रों ने आर्डर का भयपूर्ण चित्रण किया कि देश पर उसका पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया है। भविष्यवाणी की गई कि अगले राष्ट्रपति को यही नामज़द करेगा और यह भी डर दिखाया गया कि यह समस्त सामाजिक व्यवस्था को उलट देगा।

'न्यूयार्कसन' में एक लेख में कहा गया : "इस देश में ५ आदमी ५ लाख मज़दूरों के मुख्य हितों को नियंत्रित करते हैं और किसी भी क्षण वे २५ लाख व्यक्तियों की आजीविका के साधन छीन सकते हैं। ये आदमी नाइट्स आव लेबर आव अमेरिका के पवित्र आर्डर के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं......वे तार पर काम करने वाले करीब करीब हर आदमी की चुस्त उंगलियों को रुकवा सकते हैं, अधिकांश मिलों व फैक्ट्रियों को बन्द कर सकते हैं और रेलों को पंगु कर सकते हैं। वे किसी भी तैयार माल के खिलाफ डिक्री जारी करके अपने सदस्यों को उसे खरीदने से रोक सकते हैं और दूकानदारों से उसका बेचा जाना रोक सकते हैं। वे पूंजी के खिलाफ मज़दूरों का मोर्चा लगवा सकते हैं जिसमें वे उन्हें शान्त और दृढ़तापूर्वक आत्मरक्षा के लिए या क्रोधपूर्ण संगठित प्रहार के लिए इच्छानुसार बचाव का या हमले का निर्देश दे सकते हैं।"

यह कहा गया कि इस शक्तिशाली संगठन के मुखिया के रूप में पाउडरली मज़दूरों का सर्वशक्तिमान जार बन गया है जो तानाशाही और गोपनीयता से अपने अनुयायियों पर शासन करता है। वस्तुतः वह आर्डर के अनियंत्रित विस्तार से अभिभूत हो गया और उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी। उसने हताश होकर कहा : "मैं जिस पद पर हूं, वह १० आदमियों के लिए भी बहुत बड़ा है, मेरे लिए तो यह निश्चय ही बहुत बड़ा है।"

किन्तु आम लोग नाइट्स को एक सुनियंत्रित और अनुशासित संगठन

समझते थे और उनका खयाल था कि मालिकों के खिलाफ जिस किसी भा संघर्ष को यह अपना सहयोग प्रदान कर देगा वही जीत जाएगा। इस समय नाइट्स आव लेबर अपनी प्रतिष्ठा के चरम शिखर पर था।

सब कहीं मजदूर गाते होते थे :
लाखों श्रमजीवी अब जाग रहे हैं—
उन्हें मार्च करते हुए देखो;
अपनी सत्ता की समाप्ति से पूर्व
अब सब आततायी कांप रहे हैं।

समूहगान

ऐ नाइट्स आव लेबर ! किले पर चढ़ दौड़ो,
हर पड़ौसी के लिए समान अधिकार
और आततायी कानूनों की समाप्ति के
अपने ध्येय की खातिर संग्राम करो।

किन्तु शुरू-शुरू की विजयों की इन संभावनाओं में ही संगठन के विघटन के बीज छिपे हुए थे। सफलता से नाइट्स का सिर फिर गया। यद्यपि जर्नल आव युनाइटेड लेबर ने उस खतरे की चेतावनी दी थी कि "अत्यधिक खुशी में हमारे सदस्य कहीं स्वयं को अजेय न समझने लगें, और कार्यकारी बोर्ड ने आलोचनात्मक ढंग से यह कहा था कि एक साथ आवश्यकता से अधिक हड़तालें हो रही हैं, तो भी सामान्य मज़दूरों ने संयम से काम नहीं लिया। आर्डर के विशाल संख्या में अनियंत्रित सदस्यों ने कोई अनुशासन और नियंत्रण नहीं माना और न कोई जिम्मेदारी की भावना दिखाई। जिसे वे उद्योग का कमज़ोर विन्दु समझते थे उसका पूरा लाभ उठाने की चेष्टा करते हुए मालिकों पर अपनी मांगें पूरी करने के लिए दबाव डालते रहे और आर्डर से सहयोग प्राप्ति की आशा करते रहे। इस स्थिति में उन्हें एक के बाद एक पराजय का सामना करना पड़ा जिनसे नाइट्स वैसे ही हताश हुए, जैसे अपनी शुरू की विजयों से उत्साहित हुए थे।

पहला धक्का साउथवेस्ट सिस्टम पर रेल कर्मचारियों की एक अन्य हड़ताल से लगा। मिसूरी पैसिफिक और मिसूरी, तथा कन्सास व टैक्सास के रेल कर्मचारी अब भी असन्तुष्ट थे। १८८५ में वाबाश के वर्कशाप के कर्मचारियों को सहयोग देने के लिए वे भी हड़ताल करने को तैयार थे और नाइट्स आव-लेबर की ताकत के मद में अगली वसन्त ऋतु में अधिक वेतन की मांग के लिए हड़ताल करने का बहाना ढूंढ़ रहे थे। जब टैक्सास और पैसिफिक रेलवे पर मज़दूरों में से एक फोरमैन को निकाल दिया गया तो नं० १ जिला सभा के मास्टर वर्कमैन ने, जिसका नाम मार्टिन आयरन्स था और जो एक स्थानीय नेता था, अधिकारियों की मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना ही तुरन्त हड़ताल का आह्वान किया। यह हड़ताल तेजी से टैक्सास और पैसिफिक से अन्य रेलवे लाइनों के कर्मचारियों तक फैल गई।

एक शेखीभरी अपील में कहा गया ! "दुनिया से कह दो गोल्ड साउथ-वेस्ट सिस्टम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हमने अपने लिए और सब कहीं अपने भाइयों के लिए न्याय की खातिर हड़ताल की है। १४००० आदमी हड़ताल पर हैं......अपनी शिकायतों का पुलिन्दा एक साथ ले आओ, सब मिलकर हड़ताल कर दो और तब तक उसे जारी रखो, जब तक तुम्हारी वे सब शिकायतें तुम्हारे लिए पूर्ण सन्तोषजनक ढंग से हल न हो जाएं। आओ हम अपने अधिकारों की मांग करें और शोषकों को उन्हें मानने के लिए मजबूर कर दें......"

गोल्ड और उसके नियंत्रण में चलने वाली रेलों के अधिकारियों को, यह विश्वास कराने के लिए ऐसी ही बढ़ी-चढ़ी माँगों की दरकार थी कि नाट्स आव लेबर को कुचल दिया जाना चाहिए। यह मानने का कोई कारण नहीं कि गोल्ड वस्तुतः रत्तीभर भी यूनियनों के पक्ष में रहा हो। १८८५ में वह सिर्फ इसीलिए पीछे हटा था कि १८८६ में प्रत्याक्रमण कर सके। पाउडरली ने वस्तुतः बाद में आरोप लगाया कि यह नई हड़ताल टैक्सास और पैसि-फिक के प्रवन्धकों ने ही उसकी इच्छा के विरुद्ध आइरन्स को मजबूर करके कर कराई। तथ्य कुछ भी हो, साउथवेस्ट रेलवे ने अब अपने पूरे हथियार इस्तेमाल करके हड़ताल से लोहा लिया। जब मज़दूरों ने डिब्बे पुनः किए, और इंजनों को नष्ट किया तब प्रवन्धकों ने हड़ताल भंजक

और पिंकरटन गार्ड किराये पर भरती कर लिए तथा राज्य के गवर्नरों से सैनिक संरक्षण की अपील की। इस बार उन्होंने कोई रियायत या समझौता न करने का पक्का निश्चय कर लिया था।

पाउडरली ने स्वयं को एक असंभव स्थिति में पाया। वह हड़ताल के पक्ष में नहीं था, और उसे कराने में उसका कोई हाथ नहीं था तो भी रेलवे के अधिकारियों ने उस पर अपना यह वचन तोड़ने का आरोप लगाया कि पहले विचार-विमर्श किए बिना वह किसी हड़ताल की मंजूरी नहीं देगा। उसने गोल्ड को तलाश करके एक ऐसा आधार खोज निकालने का प्रयत्न किया जिसे हड़ताली स्वीकार कर सकें। किन्तु रेलवे-बॉस का अब नाइट्स के साथ समझौते की बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था और बातचीत बिल्कुल बेकार रही।

इस बीच मज़दूरों को नुकसान पहुँच रहा था। गोल्ड रेल प्रणाली के ४८००० मज़दूरों में से वस्तुतः सिर्फ ३००० ने ही काम छोड़ा और हड़तालियों की जगह काम करने वाले लोगों के साथ संघर्ष में वे हार रहे थे। नेशन ने घोषणा की कि "वे वस्तुतः आधुनिक समाज में एक नया अधिकार स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं, अर्थात् उन लोगों द्वारा काम पर लगाए जाने का अधिकार जो तुम्हें नहीं चाहते और जो तुम्हें मुँह माँगा वेतन नहीं दे सकते।" "हड़तालियों द्वारा अपने सिवा किसी दूसरे से काम लिए जाने के जबरन विरोध" की सर्वत्र निन्दा की गई।

अन्त में जब कि रेलवे कोई भी रियायत देने से इन्कार कर रही थी, कांग्रेस की एक समिति हड़ताल की जाँच कर रही थी और लोकमत रेल-सर्विस भंग होने से और ज्यादा कुपित हो रहा था, तब पाउडरली ने इस सारे मामले से अपना हाथ खींच लिया। नोबल ऐण्ड होली आर्डर की प्रतिष्ठा के लिए वह संघर्ष के महत्व को स्वीकार करता था और गोल्ड के आगे घुटने टेक देने को अनिच्छुक था किन्तु उसे हड़ताल को सफल बनाने का कोई रास्ता नहीं सूझता था। ग्रैण्ड मास्टर वर्कमैन जब अपनी जिम्मेदारी से बच निकला, तब कार्यकारी परिषद् ने भी हार मान ली और मज़दूरों को काम पर लौटने का आदेश दिया। नाइट्स आव लेबर को पहली गम्भीर पराजय का सामना करना पड़ा और गोल्ड रेल प्रणाली के मज़दूरों में उसका संगठन खत्म

हो गया।

अभी और पराजय होनी थी क्योंकि गोल्ड का अनुसरण करते हुए अन्य मालिकों ने मज़दूरों के हर उभार को कुचल देने और नाइट्स की कमर को स्थायी रूप से तोड़ देने के लिए अपनी ताकतें जुटाईं। १८८६ के उत्तरार्ध में कोई एक लाख मज़दूर श्रम-विवादों में उलझ गए और इनमें से बहुत ज्यादा हड़तालों और तालाबन्दियों में वे बिकुल असफल रहे।

नाइट्स का शिकागो स्टाकयार्ड की हड़ताल में सब से ज्यादा नुकसान हुआ। मामला ८ घण्टे के दिन का था और ऐसोसियेटेड मीट पैकर्स ने न केवल इस माँग को मानने से इन्कार कर दिया, बल्कि घोषणा की कि अब वे आर्डर के किसी भी सदस्य को काम पर नहीं रखेंगे। तो भी हड़ताल ने पैंकिग हाउस में काम बिल्कुल ठप्प कर दिया और समझौते के कुछ आसार नजर आए। तभी अचानक और बिना चेतावनी दिए पाउडरली ने मज़दूरों को काम पर लौटने का हुक्म दिया और यह धमकी दी कि अगर वे नहीं लौटे तो उनका चार्टर छीन लिया जाएगा। पाउडरली पर मालिकों के हाथ बिक जाने तथा इस चाल में एक कैथोलिक पादरी द्वारा अनुचित रूप से प्रभावित हो जाने का आरोप लगाया गया। घटना के अपने विवरण में वह कहता है कि हड़तालियों की हार निश्चित थी इसलिए उन्हें और ज्यादा नुकसान तथा सम्भावित रक्त-पात से बचाने के लिए मैंने जैसा उचित समझा किया। कुछ भी हो, अपने नेताओं के डाँवाडोल रुख के कारण स्थिति पर से नाइट्स का नियन्त्रण जाता रहा। हड़ताल के विफल होने के साथ-साथ उनकी प्रतिष्ठा पर एक और असाध्य चोट लगी।

यह स्पष्ट था कि धारा का प्रभाव उलट चुका है। प्रत्येक अवसर का तुरन्त फायदा उठाने में दक्ष उद्योग के भीषण प्रत्याक्रमण ने मज़दूरों की पहले की उपलब्धियाँ भी खत्म कर दीं। १८८६ की जुलाई में ही लार्ड स्विण्टन ने कहा कि वर्ष के शुरू में स्वर्णिम युग जहाँ पकड़ में आया प्रतीत होता था वहाँ अब ऐसा लगने लगा था कि मज़दूर किसी "मृगमरीचिका" से धोखा खा गए हैं। अब वह यह पक्का विश्वास करने लगा था कि "पैसे की ताकत ने अपने सामने किसी को खड़ा नहीं रहने दिया और वरिष्ठता उसने इस कदर कायम कर ली है कि कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता।"

स्विण्टन ने आगे लिखा : "दुश्मन के जनरल जे. गोल्ड ने साउथवेस्ट के रेलवे हड़ताल को कुचल दिया और उसके बाद सैंकड़ों अन्य हड़तालें विफल हो गईं......यूनियन के सदस्यों का नाम सर्वत्र काली सूची में दर्ज कर दिया गया और अनेक बस्तियों में नाइट्स आव लेबर के खिलाफ विशाल षड़यंत्र का पता चला। हड़ताल के विरुद्ध क़ानूनों को तोड़ा-मरोड़ा गया। पिंकर्टन ठगों की भाड़े पर एक छोटी सी सेना बना ली गई......नागरिकों के सांविधानिक अधिकारों पर प्रहार किया गया, मज़दूरों की सभाएं भंग कर दी गईं और उनके अखबारों को धमकी दी गई या उन्हें कुचल दिया गया।"

उद्योगों का हमला और फलस्वरूप हड़तालों में हार की घटनाएं ही सिर्फ नाइट्स की शक्ति को घटाने वाली नहीं थीं। इसके नेता अधिक से अधिक गलतियां करते प्रतीत हो रहे थे। पाउडरली ने औद्योगिक संघर्ष को कम करने तथा सहकारिताओं की ओर ध्यान् मोड़ने की कोशिश की और वह स्वयं मज़दूरों का उत्तरोत्तर विश्वास खोता गया। उन्होंने महसूस किया कि अब वह उनके वास्तविक हित को नहीं समझता और मालिकों से की गई उनकी वाजिब माँगों का समर्थन नहीं करता।

उसकी साहस-हीनता के रवैये का एक उदाहरण वह नीति थी जो उसने तब अपनाई, जब पुनर्जीवित होती हुई राष्ट्रीय यूनियनें अमेरिकन फेडरेशन आव लेबर की पूर्वज फेडरेशन आव आर्गनाइज्ड ट्रेड्स ऐण्ड लेबर यूनियन्स से सम्बद्ध हो चुकी थीं। १८८६ में ८ घण्टे के दिन के लिए आम हड़ताल कराने की कोशिश की, जिसमें हेमार्केट स्क्वेयर के दंगे की पृष्ठ भूमि सामने दिखाई दे रही थी। यद्यपि नाइट्स आव लेबर ८ घण्टे के दिन का प्रबल समर्थक था, तो भी पाउडरली ने हड़ताल के आह्वान से आर्डर को अलग रखा। एक गुप्त परिपत्र में उसने कहा कि "कोई सभा यह समझ कर कि वह हैडक्वार्टर के आदेश का पालन कर रही है पहली मई को ८ घण्टे की परिपाटी के लिए हड़ताल न करे क्योंकि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया और न दिया जाएगा..." इस सीधी कार्रवाई के बजाय उसने सुझाव दिया कि स्थानीय सभाएं अपने सदस्यों से ८ घण्टे के दिन पर छोटे-छोटे निबन्ध लिखवाएं जो वाशिंगटन के जन्म दिवस पर अखबारों में एक साथ छपें। तो भी अनेक जिला सभाओं ने आम

हड़ताल के पक्ष में प्रस्ताव पास किए और पाउडरली द्वारा रोके जाने की परवाह नहीं की और जब १ मई आई तो नाइट्स के हज़ारों सदस्यों ने उद्योग पर अपनी मांगों की छाप अंकित करने के लिए राष्ट्र के कर्मचारियों की तरफ से किए गए पहले सामूहिक प्रदर्शन में भाग लिया।

यह सफल नहीं हुआ। ८ घण्टे के दिन के आन्दोलन में कोई ३,४०,००० मज़दूरों ने हिस्सा लिया और इसमें आधे से अधिक ने वस्तुतः १ मई को हड़ताल कर दी किंतु २ लाख कर्मचारियों ने यद्यपि अपने मालिकों से ८ घण्टे के दिन की मांग मनवा ली, तो भी उनकी यह मांग-पूर्ति क्षणिक ही रही। वर्ष की समाप्ति पर बताया गया कि मालिकों को अस्थायी रूप से मजबूर होकर जो रियायतें देनी पड़ी थीं, वे उन्होंने सिर्फ १५००० मज़दूरों को छोड़कर शेष सबसे वापस ले लीं। हेमार्केट स्क्वेयर काण्ड के बाद मज़दूरों के विरुद्ध जो भावना फैली, वह शायद इस पराजय का सबसे बड़ा कारण थी किंतु नाइट्स आव लेबर द्वारा शुरू में ही आन्दोलन का समर्थन न करना भी उसका एक महत्वपूर्ण कारण था।

१८८६ की पतझड़ में नाइट्स आव लेबर का जब फिर सम्मेलन हुआ, तब भी उसको देखने से ऐसा नहीं लगता था कि यह अन्दर से खोखला हो चुका है जिससे इसके दिन गिने चुने रह गए हैं। रिचमण्ड में आयोजित राष्ट्रीय सभा मज़दूरों की सबसे प्रभावशाली सभा थी, जैसी देश में अब तक नहीं हुई थी और ७०० प्रतिनिधियों का वर्जीनिया के गवर्नर ने बाकायदा स्वागत किया। किन्तु यह शक्तिशाली प्रदर्शन एक बाहरी दिखावट से ज्यादा कुछ नहीं था और सभा में बोलने वालों के जोशीले भाषणों में जिनमें उन्होंने "लाखों की पीठ पर" गिरने वाले "सोने के चाबुक" की निन्दा की, कुछ खोखलापन था। इतनी ज़्यादा हड़तालों की विफलता, ८ घण्टे के आन्दोलन की पराजय, अधिकांश सहकारी धन्धों के दुखद परिणामों और हेमार्केट स्क्वेयर के दंगे के बाद के परिणामों ने नेताओं व सदस्यों के बीच बढ़ती हुई खाई के साथ मिलकर नाइट्स आव लेबर को पतन की उस ढलान पर डाल दिया जिस पर फिसलने से वह बाद में रुक ही नहीं सका।

बहुत सी स्थानीय सभाएं तो भंग ही हो गईं और दक्ष कर्मचारियों की अन्य सभाएं उस आन्दोलन के पीछे हो लीं जो अमेरिकन फैडरेशन आव लेबर

का रूप ले रहा था। नाइट्स नए यूनियनवाद की उभरती हुई ताकतों के साथ निर्णायक संघर्ष में इस कदर उलझ गए कि उससे उनका पूर्णतः खात्मा हो गया। ७ लाख की सदस्यता दो वर्ष में ही २ लाख रह गई। १८९३ में यह और घटकर ७५००० रह गई। कंजर्वेटिव अखबार इस संगठन के विघटन पर खूब खुश हुए, जिसके बारे में कभी यह समझा जाता था कि गणराज्य का भाग्य उसके हाथ में है। एक सम्पादक ने चैन की सांस लेते हुए कहा : "आश्चर्य की बात तो यह है कि यह पागलपन इतने अरसे तक जारी रहा।"

नाइट्स आव लेबर के नेताओं ने औद्योगिक गति-विधियों के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों की ओर ध्यान देकर कुछ अरसे तक तो इस रुझान का मुकाबला करने की कोशिश की। पाउडरली ने मजदूरों से अनुरोध किया कि वे "उस दिन जो अमरीकी नागरिक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन है अर्थात् चुनाव के दिन" अपना तीव्र दबाव महसूस कराकर अपने हितों की रक्षा करें। १८८६ की पतझड़ में एक दर्जन शहरों में राजनीतिक पदों के लिए स्थानीय मज़दूर उम्मीदवारों को आर्डर ने अपना पूरा सहयोग दिया और न्यूयार्क के मेयर के चुनाव में खुद ग्रैण्डमास्टर वर्कमैन ने हेनरी जार्ज और उसकी एकमात्र कर पद्धति के पक्ष में जोरदार प्रचार किया ! क्योंकि पाउडरली यद्यपि अब भी तृतीय दल आन्दोलन में विश्वास नहीं रखता था फिर भी आर्थिक कार्रवाइयों में उत्तरोत्तर मिली असफलताओं से वह इतना निराश हो गया था कि वह अंतिम उपाय के रूपमें राजनीति की ओर अधिकाधिक मुड़ता गया। १८८९ में वह नाइट्स से अनुरोध कर रहा था, कि "हड़तालों, बहिष्कारों, ताला बन्दियों और ऐसी ही अन्य वाहियात चीजों को धत्ता बताओ और विधायक हथियार से एक ऐसी कड़ी चोट करने के लिए संगठित हो जाओ जिससे कि अमरीका पर हुकूमत करने की कम्पनियों की ताकत क्षीण हो जाए।"

नाइट्स आव लेबर के खात्मे के अंतिम दिनों में उसमें विद्यमान कृषि-तत्वों ने, जो किसानों को सदस्य बनाए जाने के कारण सदा उसमें मौजूद रहते थे, औद्योगिक मज़दूर के प्रभाव पर स्वयं छा जाना प्रारम्भ कर दिया। १८९३ में पाउडरली को निकाल बाहर किया गया और ग्रैण्ड मास्टर वर्कमैन का उसका पद आयोवा के जेम्स आर सौवरेन ने सम्हाल लिया जिसे सिर्फ सुधारों की राजनीति में दिलचस्पी थी।

१८९४ में आर्डर के कार्य की व्याख्या करते हुए सौवरेन ने कहा: "मज़दूरियों में हेरफेर के प्रश्न पर इसकी दीवार नहीं खड़ी है, वल्कि वेतन प्रणाली की समाप्ति और एक सहकारी औद्योगिक प्रणाली की स्थापना इसका आधार है। जब इसका वास्तविक उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तब गरीबी कम से कम रह जाएगी और हमारी जमीन शांतिमय सुखद घरों से चिन्हित होगी।"

इन शब्दों में सिल्विस, स्टीफेन्स के शब्दों की सुपरिचित गूंज सुनाई देती है; शायद पाउडरली ने भी ये शब्द कहे हों किन्तु सौवरेन यह भूल गया कि मज़दूरी प्रणाली की विकृति उसके अन्तिम खातमे की ओर एक कदम है और मज़दूर स्वयं ही आर्डर में शामिल होने के लिए जो टूटे पड़ते थे, उसके अस्पष्ट और आदर्शवादी चरम लक्ष्यों की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि वे समझते थे कि मज़दूरी और घण्टे से सम्बन्धित उनकी तात्कालिक मांगों का यह समर्थन करने को उद्यत है। और नाइट्स आव लेवर की ताकत ही उसके सदस्यों की उग्र भावनाएं थीं। अब जबकि एक के बाद एक सभा इस रास्ते से विचलित हो गई, तब आर्डर पुरानी मज़दूर कांग्रेस जैसी चीज ही बन कर रह गया। राजनीतिक विचारों के कुछ नेता कभी-कभी परस्पर मिलकर ऐसे कदम उठाए जाने का अनुरोध करते थे, जिनको लागू कराने में वे सर्वथा असमर्थ थे।

अपने दुखद अन्त के बावजूद नोवल एण्ड होली आर्डर ने मज़दूरों के संगठन को एक शक्तिशाली गति प्रदान की और उसकी सफलताएं और विफलतायें दोनों का ही समस्त मज़दूर आन्दोलन के लिए अब भी बहुत महत्व था। क्योंकि नाइट्स ने मज़दूरों में वह एकता कायम कर दी थी जो उनके अभ्युदय से पूर्व बिल्कुल धुंधले रूप में महसूस की गई थी और उन्होंने उद्योग की ताकत को वह चुनौती दी जिसने मज़दूरों की अन्तर्हित शक्ति को इस प्रकार सामने लाकर रख दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरकार २० वर्ष से भी कम समय में सात दिहाड़िये दर्जियों की एक छोटी सी गुप्त सोसाइटी से ७ लाख मज़दूरों का एक व्यापक राष्ट्रीय संगठन बन जाना स्वतः एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी।

विफलता के कई कारण रहे—सदस्यों में गैर-जिम्मेदारी की भावना और लड़खड़ाता नेतृत्व, ठीक ढंग से आयोजित न की गई और फलतः असफल हड़तालों में भाग लेना, सहकारी धन्धों में, जिनकी विफलता निश्चित थी, अपनी ताकत और कोष को गंवा देना और सबसे ज्यादा अदक्ष औद्योगिक मजदूरों को एक ही केन्द्रीय मजदूर संगठन में शामिल करने की अव्या-वहारिकता तथा उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा सहायता से हाथ खींच लेना।

अपनी अंतिम निवृत्ति से पूर्व पाउडरली ने यह अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि आर्डर अब अंतिम रूप से विघटित होने वाला है और उसका खयाल था कि इसके नेतृत्व के गुण-दोष कुछ भी रहे हों, आन्तरिक विरोधी बातों ने उसके भाग्य का सितारा डूबना अनिवार्य कर दिया था।

१८९३ में उसने लिखा : "महत्पूवर्ण और बहुत अधिक आवश्यक सुधारों का पाठ पढ़ाते हुए भी उसे अपनी सीख से विपरीत आचरण करना पड़ा! श्रम-विवादों में पहले कदम के रूप में पंच-फैसले व समझौते की वकालत करते हुए भी उसे अपने कन्धों पर पहले चोट करने की जिम्मेदारी वहन करनी पड़ी और जब पंच-फैसले और समझौते की आशा जाती रहती तब विपक्ष से उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी पड़ती, जो उसे सब पहले करनी चाहिए थीं। हड़तालों की मुखालफत करते हुए भी हम उनमें जूझे रहे। महत्वपूर्ण सुधारों की अपील करते हुए भी हमें अपना समय और ध्यान छोटे-छोटे झगड़ों पर देना पड़ा, जिससे हम एक ऐसी स्थिति में फंस गए जिसमें हमें कर्मचारियों और मालिकों दोनों ने बहुधा गलत समझा। राजनीतिक दल न होते हुए भी हमें राजनीतिक कार्रवाई करने जैसा रवैया अपनाना पड़ा......"

नाइट्स ग्राव लेबर विफल हो गए थे। तो भी यह सच था, जैसा कि पाउडरली ने आगे कहा कि आर्डर ने देश पर अपनी गहरी छाप डाली थी और अपने खात्मे में भी वह गलत रूप में समझी जाने वाली और पद्दलित मानवता के उद्देश्यों को सामने लाने में अपनी शानदार उपलब्धियों की ओर इंगित कर सकता था।

९ : अमेरिकन फेडरेशन आव लेबर (ए. एफ. एल.)

प्रश्न—तुम पहले घरेलू मामले सुधारने की कोशिश कर रहे हो ?

उत्तर—जी, हां, पहले मैं जिस यूनियन का प्रतिनिधित्व करता हूँ उसी के वारे में सोचता हूँ......जिन लोगों ने मुझे अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया है, उनके हित की वात सोचता हूँ ।

चेयरमैन—मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे अन्तिम लक्ष्य के वारे में पूछ रहा था।

गवाह—हमारा कोई अन्तिम उद्देश्य नहीं है। हम जो दिन आता है, उसी की वात सोचते हैं। हम सिर्फ तात्कालिक उद्देश्यों के लिए—उन उद्देश्यों के लिए जो कुछ ही वर्षों में प्राप्त किए जा सकें, संघर्ष करते हैं।

१८८५ में शिक्षा और श्रम पर नियुक्त सेनेट की समिति में अन्तर्राष्ट्रीय सिगार निर्माता यूनियन के अध्यक्ष ऐडल्फ स्ट्रासर की प्रायः उद्धृत की जाने वाली इस साक्षी में हमें उस विचारधारा का निचोड़ मिल जाता है जो ट्रेड-यूनियनों के पुनरुद्धार के पीछे विद्यमान थी और जिसने वाद में अमरीकी श्रम संघ (अमेरिकन फेडरेशन आव लेवर) के निर्माण की प्रेरणा दी। संगठित मज़दूरों के नए नेताओं को सहकारी कामनवेल्थ का निर्माण करके समाज में सुधार करने की कोई तमन्ना नहीं थी। यद्यपि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के मानवीयतायुक्त आदर्शवादी लक्ष्यों को बिल्कुल नहीं त्यागा तो भी उन्हें और सब चीजों को छोड़कर "व्यावहारिक आदमी" होने का गर्व था। उनको मौजूदा औद्योगिक प्रणाली के ढाँचे में ही अपनी ट्रेड यूनियनों के अनुयायियों के लिए वेतनों, काम के घण्टों तथा काम की हालतों में सुधार कराने की ही विशेष चिन्ता थी।

१८७० की दशक का मन्दी के अन्धकारपूर्ण दिनों में जहाँ पुरानी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनें करीब करीब बिल्कुल तहस-नहस हो गई थीं, तब उन्हीं वर्षों में जिनमें नाइट्स आव लेवर का चामत्कारिक उत्थान हुआ, शनैः-शनैः इन

यूनियनों में भी पुनः जान आने लगी। कुछ मामलों में तो वे राष्ट्रीय मज़दूर सभाओं के रूप में आर्डर में शामिल होकर नाइट्स के साथ सम्बद्ध थी, कुछ अन्य मामलों में वे बिल्कुल अलग रहीं और उन्होंने अपनी पूर्ण स्वाधीनता कायम रखी। दोनों हालतों में मज़दूर आन्दोलन में उनकी भूमिका १८८० के दशक के अधिकांश भाग में नाइट्स के सामने दबी रही। नोबल ऐण्ड होली आर्डर की प्रत्यक्ष एकता व शक्ति से प्रभावित हुई जनता यह सोच ही नहीं सकती थी कि भविष्य दक्ष और अदक्ष मज़दूरों की अनाड़ी भीड़ के हाथ में नहीं, जो पूर्णतः टेरेंस वी० पाउडरली के कहने में चलते थे, बल्कि ट्रेड यूनियनों के हाथ में था।

इन वर्षों में राष्ट्रीय यूनियनों का इतिहास किसी निश्चित ढंग का नहीं रहा। १८७० की दशाब्दि से बाद उनके पुनरुद्धार के समय में काफ़ी प्रतिद्वन्द्विता, संघर्ष और मज़दूर राजनीति की सब जटिल पैंतरेबाजियाँ रहीं। किन्तु नए यूनियनवाद का, जो स्ट्रासर के मन में बसी हुई थी और जिनके लिए वह तात्कालिक और व्यावहारिक लक्ष्यों पर जोर देता था, नाइट्स आव लेबर के कार्यक्रमों के विफल होने पर शनैः-शनैः एक रूप उभर आया।

मज़दूर समस्याओं के प्रति यह व्यावहारिक दृष्टिकोण कोई बिल्कुल नया नहीं था। आधी सदी पूर्व की मूल मज़दूर सोसाइटियों ने विशुद्ध शिल्पिक, धन्धे का संरक्षण और अधिक वेतन तथा काम के कम घण्टों जैसे साफ और सीधे लक्ष्यों के आधार पर संगठन बनाने पर जोर दिया था। १८६० के दशक के बाद के वर्षों और १८७० के दशक के प्रारम्भिक वर्षों की राष्ट्रीय यूनियनों ने इन्हीं लक्ष्यों को सामने रखा और जब विलियम सिलविस ट्रेड यूनियनवाद के सुधारों की ओर झुका, उससे पूर्व के दिनों में मोल्डर्स इण्टरनेशनल यूनियन के रूप में इस कार्यक्रम को तत्काल अमल में लाने वाला भी मिल गया। फिर भी इससे पूर्व के मन्दी के जमानों में राष्ट्रीय यूनियनों को जो दुखद अनुभव हुए थे उनको देखते हुए मज़दूरों के संगठन की मूल समस्या के प्रति कई मामलों में एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया।

पूर्णतः समाप्त होने से बच जाने वाली यूनियनों में एक अन्तर्राष्ट्रीय सिगार निर्माता यूनियन भी थी। तीन उत्साही नेताओं एडल्फ स्ट्रासर, फर्डिनेण्ड लारेल और विशेष रूप से सेम्युअल गौम्पर्स ने जब इसके पुनर्गठन

का काम हाथ में लिया तो इसके मुट्ठीभर सदस्य रह गए थे। इन तीनों नेताओं ने इसे पुनः अपने पैरों पर खड़ा करने और ठोस व अच्छी परिपाटियाँ अपनाने का निश्चय किया। १८७५ में एक न्यूयार्क लोकल स्थापित की गई जिसका अध्यक्ष गौम्पर्स बना और १८७७ में स्ट्रासर इंटरनेशनल का अध्यक्ष चुना गया। १८७७ में ही कम से कम वेतन पर अधिक से अधिक श्रम कराने की नीति के खिलाफ़ न्यूयार्क के सिगार-निर्माताओं की हड़ताल भयानक रूप से विफल रही किन्तु इस हार ने यूनियन के नए अधिकारियों के अपने कार्यक्रम को सफल बनाने और सिगार निर्माताओं को ऐसा संगठन प्रदान करने के, जो उनके हितों की प्रभावशाली ढंग से रक्षा कर सके, संकल्प को और मजबूत ही किया। जैसा कि गौम्पर्स ने लिखा : "काम की अच्छी हालतें प्राप्त करने के हेतु पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के लिये ट्रेड यूनियनवाद की स्थापना व्यावसायिक आधार पर करना निहायत जरूरी था।"

प्रवेश फीस और चन्दे की ऊँची दरें और उनके साथ बीमारी और मौत की हालत में लाभ प्रदान करने की एक प्रणाली अपनाई गई जिससे नई यूनियन में स्थिरता और स्थायित्व आ सके। ब्रिटिश ट्रेड यूनियनों की परम्परा से कोष के समानीकरण का सिद्धान्त लिया गया, जिसके द्वारा किसी मजबूत वित्तीय स्थिति वाली स्थानीय यूनियन को अपने जमा कोष का कुछ हिस्सा विपदा में फँसी किसी अन्य स्थानीय यूनियन को दे देने का आदेश दिया जा सकता था। एक अत्यन्त केन्द्रित नियन्त्रण की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन के अधिकारियों को सब स्थानीय यूनियनों पर वस्तुतः पूर्ण अधिकार प्राप्त था। यह इस बात की गारण्टी थी कि हड़ताल करने में सख्त अनुशासन से काम लिया जाए और जब अधिकारियों के आदेश से कोई हड़ताल हो तो उसे पर्याप्त समर्थन मिले। सिगार मेकर्स ने उत्तरदायित्व और कार्यकुशलता पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। किसी माँग को पूरा कराने के लिये वे जहाँ सबसे प्रभावशाली हथियार का सहारा लेने के लिये तैयार रहते थे, वहाँ यह भी था कि इस हथियार का प्रयोग तभी किया जाना होता था जब हड़ताल को सफल बनाने के लिये यूनियन के पास पर्याप्त साधन हों।

गौम्पर्स ने अपनी आत्मकथा में इन दिनों के बारे में लिखा है : "स्ट्रासर ... सन के साथ सिगार मेकर्स और अन्य सब ट्रेड यूनियनों के लिए एक

नया युग शुरू हुआ क्योंकि हमारे काम का असर बाद में बहुत व्यापक हुआ। अमरीका की इण्टरनेशनल सिगार मेकर्स यूनियन के लिए विकास, वित्तीय सफलता और ठोस विस्तार का युग शुरू हुआ, जिसमें एक से नियम, चन्दे की ऊँची दरें, यूनियन के लाभ, यूनियन का बिल्ला, बेहतर मज़दूरी और कम काम के घण्टे कायम किए गए।"

अन्य यूनियनों ने भी ये प्रक्रियाएं अपनाईं विशेष कर पीटर जे. मैकगायर के कुशल नेतृत्व में ब्रदरहुड आव कारपेण्टर्स ऐण्ड जौयनर्स ने किन्तु वास्तविक पायोनियर सिगार मेकर्स ही थे जिन्होंने अपना पुनर्गठन इतनी सफलता से किया कि वे नई यूनियनों के लिए आदर्श बन गए। उनके अनुभवों से यह स्पष्ट जाना जा सकता था कि वित्तीय स्थिरता और केन्द्रित अधिकार की दृढ़ भित्ति पर क्या कुछ किया जा सकता है। उत्पादकों के स्वयं-नियोजन, एक सहकारी कामनवेल्थ, या अन्य किसी दिवास्वप्न जैसी वाहियात बातें उनमें नहीं थीं। दृढ़तापूर्वक यह कहा गया : "आवश्यकता ने मज़दूर आन्दोलन को सबसे ज्यादा व्यावहारिक तरीके अपनाने के लिये बाध्य कर दिया है। वे अधिक वेतन और काम के कम घण्टों के लिए संघर्ष कर रहे हैं......कोई वित्तीय कार्यक्रम या कर लगाने की कोई योजना श्रम के घण्टे कम नहीं करा सकती।"

यह व्यावहारिक दृष्टिकोण सुधार के मध्य वर्गीय विचारों, जो अतीत में मजदूरों को इतनी ज्यादा अन्धी गलियों में भटकाते रहे और समाजवादी सिद्धान्तों, जिन्हें नई यूनियनों के नेता इन्हीं की भांति हानिकारक समझते थे, दोनों के विरुद्ध यह एक प्रकार का विद्रोह था और। स्ट्रासर और मैकगायर दोनों समाजवादी थे। गौम्पर्स कभी उनके प्रभाव में ,था। किन्तु पहले दोनों व्यक्ति समाजवादियों की प्रतिद्वन्द्विता और झगड़ों से ऊब गए और हमने देखा कि किस प्रकार गौम्पर्स के अपने अनुभवों ने उसे रैडिकल वाद के खिलाफ कर दिया। ऐसे किसी भी उपाय से मजदूरों की भलाई के काम में विफलता निश्चित जानकर ये नेता पुनः दृढ़ संकल्प के साथ "विशुद्ध और सरल" ट्रेड यूनियनवाद की ओर लौटे। उनके मन्तव्य वर्ग के प्रति सजगता के बजाय वेतन के प्रति सजगता पर आधारित थे। आर्थिक प्रणाली को बदलने का उनका कोई विचार नहीं था, उसे उलटने की कोशिश करना तो दूर की बात है।

कहने का यह तात्पर्य नहीं कि पुनर्गठित मजदूर आन्दोलन में कोई

रैडिकल नहीं थे। १८७० और १८८० की दशाब्दि के दंगों और उपद्रवों में जिन क्रांतिकारी तत्वों का हाथ था, वे अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। मार्क्सवादी और लासालीन दोनों प्रकार के समाजवाद के अनुयायी मज़दूरों को अपने अपने कैम्पों में लाने के उनके प्रयत्नों में "अन्दर-अन्दर से पलीता लगाते रहे" और अमेरिकन फेडरेशन आव लेवर से सम्बद्ध यूनियनों के सदस्यों में से अपने अनुयायी बनाने की चेष्टा करते रहे। किन्तु नई यूनियनों के जिम्मेदार नेताओं ने ऐसे सब तत्वों का दृढ़ता से और सफलता से सामना किया और आर्थिक तथा सामाजिक मामलों में उनका दृष्टिकोण अधिकाधिक रूढ़िवादी बनता गया।

अगर नई यूनियनों के पीछे प्रेरक शक्ति ज्यादातर इण्टरनेशनल सिगार मेकर्स रही तो सेम्युअल गौम्पर्स इसका सबसे योग्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय संगठन का, जिसने इसके मूल सिद्धान्तों को आगे बढ़ाया, मुख्य शिल्पी था। अमेरीकन फेडरेशन आव लेवर का वह न केवल प्रथम अध्यक्ष बना किन्तु सिर्फ एक वर्ष को छोड़कर १९२४ में अपनी मृत्यु तक वह इसी पद पर बना रहा। नाइट्स आव लेवर के अधःपतन पर मज़दूर आन्दोलन को नई दिशा प्रदान करना और १८९० की दशाब्दि की मंदियों को झेलने में ए. एफ. एल. को सफल बनाना इस मजबूत, व्यावहारिक और दृढ़ मज़दूर नेता का ही काम था जिसका चरित्र और सिद्धान्त पाउडरली के चरित्र और सिद्धान्त से इतने ज्यादा भिन्न थे।

गौम्पर्स १८५० में लन्दन की ईस्ट ऐण्ड बस्ती में पैदा हुआ था। डच-यहूदी जात का उसका पिता सिगार बनाता था और १० वर्ष की आयु में किशोर सेम्युअल को इस धन्धे की शिक्षा दी गई। १८६३ में जब परिवार अमरीका चला गया तो पहले तो गौम्पर्स ने न्यूयार्क की ईस्ट साइड बस्ती के एक मकान में सिगार बनाने में अपने पिता की सहायता की, किन्तु शीघ्र ही उसे अलग से काम मिल गया और १८६४ में वह एक स्थानीय यूनियन में शामिल हो गया।

उस समय के सिगार बनाने वाले कारखाने फैक्ट्री होने के अलावा राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं के स्कूल भी थे और उनका सबसे ज्यादा उत्साही विद्यार्थी लन्दन से आया हुआ यह नौजवान आव्रजक ही था जो

ब्रिटिश ट्रेड यूनियनवाद की पृष्ठभूमि का पहले से ही अच्छा जानकार था। अंधेरे और धूलभरे कमरे में अपनी बेंच पर बैठ कर कुशलता से सिगार वनाता हुआ वह समाजवाद और मज़दूरों से सम्बिन्धित सुधारों के वारे में अपने साथी मज़दूरों की वातचीत को वड़े ध्यान से सुनता रहता था। उसके साथियों में अधिकांश यूरोप में पैदा हुए थे और उनमें से अनेक इण्टरनेशनल वर्किंगमेन्स ऐसोसियेशन के सदस्य थे। उनमें से एक मजदूरों से सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाएं ऊँचे स्वर में पढ़कर सुनाया करता था (वीच वीच में वह रुक कर पुनः अपना काम करने लगता था, क्योंकि वरना वह अपनी मज़दूरी खो वैठता) और यह काम अक्सर गौम्पर्स को सौंपा जाता था।

लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मार्क्सवादी विचारधारा को खूब पढ़ने के वावजूद यह नौजवान सिगार निर्माता कोई सिद्धांतवादी व्यक्ति नहीं वना, इसके विपरीत लगता है कि इसने मज़दूर समस्याओं के प्रति उसके भावुकता रहित व्यावहारिक दृष्टिकोण को और पक्का कर दिया। अपने इस दृष्टिकोण को वनाए रखने में वह शायद फर्डिनेण्ड लारेल से ज्यादा प्रभावित हुआ जो एक कठोर तबियत का स्वीडिश आवासी था और जिसे रैडिकलवाद के सव स्वरूपों का अच्छा-खासा अनुभव था। लारेल ने उसे मार्क्स और एंजल्स पढ़ने के लिए तो जरूर कहा लेकिन यह चेतावनी भी दी कि उनकी सैद्धान्तिक विवेचनाओं में वह वह न जाए। उसने उसे समाजवादी दल में शामिल होने से मना किया। गौम्पर्स को उसने कहा : सैम अपने यूनियन कार्ड का अध्ययन करो और अगर कोई विचार उससे मेल नहीं खाए तो वह गलत है।''

इस पृष्ठभूमि के साथ गौम्पर्स, स्ट्रासर और लारेल के सहयोग से सिगार मेकर्स यूनियन के पुनर्निर्माण में जुट गया। इन दिनों के अनुभवों का सिंहावलोकन करते हुए गौम्पर्स उन्हें न केवल अपने व्यावसायिक जीवन के लिए, अपितु अमरीका के मज़दूर आन्दोलन के भावी पथ के लिए उत्तरदायी मानता था। जिन व्यक्तियों के साथ अनन्त विचार-विमर्श करके उसने अपने विचारों को परिपक्व किया था उनके वारे में उसने लिखा : "इस छोटे से ग्रुप की वदौलत वह उद्देश्य और पहल हमारे हाथ में आई जिसकी अंतिम परिणति वर्तमान अमरीकी मजदूर आन्दोलन के रूप में हुई......हमने अमरीकी ट्रेड यूनियन का निर्माण नहीं किया—वह विभिन्न ताकतों और परिस्थितियों की उपज है।

किन्तु हमने वे तौर-तरीके अपनाए और कुछ बुनियादी बातें तय कीं जिन्होंने ट्रेड यूनियनों को रचनात्मक नीतियों और उपलब्धियों का रास्ता दिखाया।"

इण्टरनेशनल सिगार मेकर्स यूनियन के पुनर्गठन के समय गौम्पर्स की आयु २६ वर्ष की थी और इस छोटी आयु से ही वह अविचलित भाव से एक ही मार्ग पर चलता रहा। सिलविस और पाउडरली के विपरीत वह अंत तक अपने लक्ष्य पर चिपटा रहा और कभी और किसी काम में दत्तचित्त नहीं हुआ। वह न तो कोई सुधारक था और न कोई बड़ा पंडित। वह ऐसे लोगों से घृणा करता था जो मज़दूरों को यह बताने का दुःसहास किया करते थे कि उन्हें किस मार्ग पर चलना चाहिए। जिन सिद्धान्तों को वह "औद्योगिक दृष्टि से असम्भव" समझता था उनके प्रति पूर्ण अविश्वास की भावना रखते हुए उसने स्वयं श्रम-सम्बन्धी किसी सिद्धान्त पर लेक्चरबाजी देने का प्रयत्न नहीं किया। नैतिक प्रभाव और अन्तर्ज्ञान के बारे में बातचीत करना उसे पसन्द न था किन्तु हर प्रश्न के प्रति उसका दृष्टिकोण सर्वथा व्यावहारिक रहता था।

उसके विचार संकीर्ण और सीमित से लगते थे और उसका कार्यक्रम निश्चित रूप से तात्कालिक अवसरवादिता का होता था। एक बार यद्यपि उसने वेतन प्रणाली की समाप्ति का कुछ अस्पष्ट शब्दों में समर्थन किया था तो भी शिल्पिक यूनियनों के दक्ष कर्मचारियों के लिए अधिक वेतन और काम के कम घण्टों से परे उसकी नजर नहीं गई। मुद्रासुधार भूमि-बसाव और सहकारिता जैसे रामबाण उपायों से, जिन्होंने राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन और नाइट्स आव लेबर को इतना छकाया था, बिल्कुल अलग रहकर उसने मज़दूर एकता का उनका लक्ष्य भी छोड़ दिया। गौम्पर्स का यथार्थवादी रवैया यह था कि कम से कम जहां तक दक्ष कर्मचारियों का ताल्लुक है, मज़दूर आन्दोलन को अब तक की अपेक्षा अधिक दृढ़ और स्थायी आधार पर रखा जाए। किन्तु उसमें व्यापक दृष्टिकोण के अभाव ने समग्रतः मज़दूरों के हित-साधन के कार्यों में अमेरिकन फैडरेशन आव लेबर के योगदान को बहुत सीमित कर दिया। उसने एक साथ ही एक तरफ तो ट्रेड यूनियन आन्दोलन को बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो जाने की सम्भावना से बचा लिया और दूसरी ओर उसे उस व्यापक रूपरेखा के आधार पर जो उसके पूर्ववर्तियों का अत्यन्त आदर्शवादी

 रहा है, विकसित करने का अवसर फेंक दिया।

पहले अपनी यूनियन और बाद में अमरीकी श्रम संघ के हितों की पूर्ति में उसका उत्साह असमाप्य लगने वाली शक्ति से और बढ़ गया। उसने कभी ऐसी शिकायतें नहीं कीं कि लोगों के लिए उसके पास समय नहीं है। गौम्पर्स अथक संगठन कर्ता व प्रशासक था, मज़दूरों के सभा-सम्मेलनों में भाषण देने के लिये समूचे देश में भ्रमण किया करता था। कभी जो "हकलाने वाला सैम" करके मशहूर था, उसने भाषण में कोई झिझक दिखाना बन्द कर दिया और अपने मन्तव्यों का खूब उत्साह से गरज-गरज कर बखान किया करता था। यह सच है कि उसके भाषण कभी कभी अस्पष्ट और उलझन भरे होते थे, क्योंकि वह वस्तुत: मौखिक भाषण देने में बहुत कुशल नहीं था। उसका तौर-तरीका प्राय: गम्भीर और पादरी का सा होता था। किन्तु अपनी नाटकीयता के स्वभाव के कारण जो बाद के एक नाटकीय मज़दूर नेता की भी विशेषता थी वह मंच को काबू में रखने का गुर अच्छी तरह जानता था।

प्लेटफार्म से दूर और सम्मेलन-कक्ष के बाहर गौम्पर्स मैत्रीपूर्ण, शान्त-प्रसन्न और निरभिमानी रहता था, स्वयं को एक मज़दूर ही मानता था। वह बड़ा प्रेमी जीव और खुले दिल का आदमी था। मयखानों, थियेटर, संगीत भवनों, फैशनेबल लड़कियों और अटलाण्टिक सिटी के समुद्रतट पर विहार करना पसन्द करता था। जब वह शाम को अपने कुछ मित्रों के साथ मयखाने के एक अंधेरे कमरे के सुखद वातावरण में एक काले सिगार को अपने दाँतों में दबाए और सामने मेज पर उठते हुए झागों वाले शराब का जाम लिए पूर्ण विश्राम की भावना के साथ एकत्र होता था। तो अपनी हैसियन को बिल्कुल भूल जाता था। उसका दूसरों के साथ मिलजुल कर भोजन करना, झिझक वाले पुराणपन्थी प्रतिद्वन्द्वि नाइट्स आव लेबर को चौंका देने वाला था। नाइट्स का जब अमरीकी मज़दूर संघ के साथ संघर्ष चल रहा था, तब जारी किए गए एक पर्चे में नाइट्स ने लिखा: "जनरल ऐक्जीक्यूटिव बोर्ड को गौम्पर्स को गम्भीर मुद्रा में देखने का कभी सौभाग्य नहीं मिला।" संयम के उत्साही वकीलों की यह टिप्पणी अनुचित थी किन्तु इसमें शक नहीं कि गौम्पर्स बीयर का खूब आनन्द लेता था।

गौम्पर्स देखने में कुछ दुर्बल पाउडरली की अपेक्षा ज़्यादा मज़दूर नेता सा लगता था। उसका छोटा, गठीला, मजबूत शरीर, जिसकी ऊँचाई सिर्फ ५ फुट

४ इंच थी उसकी इस शेखी को ठीक की सिद्ध करता प्रतीत होता था कि "गौम्पर्स बलूत की लकड़ी के बने होते हैं।" इसके अतिरिक्त चौड़े मस्तक के नीचे मजबूत जबड़ा उसके चरित्र की शक्ति और दृढ़ता को जाहिर करता था १८८० के दशक के प्रारम्भ में उसके काले अव्यवस्थित बाल थे, झुकी हुई दरियाई घोड़े की सी उसकी मूँछें थीं और ठोड़ी पर कहीं-कहीं बाल थे। बाद के वर्षों में वह दाढ़ी-मूँछ मुँडा कर रहने लगा; चमकदार चश्मा उसकी काली, जल्दी-जल्दी झपकने वाली आँखों को ढके रहता था। वह अच्छी पोशाक पहनता था और प्रायः महत्वपूर्ण अवसरों पर रेशमी हैट प्रिंस ऐल्बर्ट लगता था। उसके तौर-तरीके शान वाले होते थे। व्यवसायपति उसके प्रति कुछ पक्षपात के ढंग से उसे "बहुत भला आदमी" कहा करते थे।

बाद में बड़े आदमियों, उद्योगपतियों, वाल-स्ट्रीट के बैंकरों, सेनेटरों और राष्ट्रपतियों के साथ मेल-मुलाकात करते हुए भी उसने मज़दूरों के साथ अपना सम्पर्क खत्म नहीं किया और चाहता था कि उसे इन शब्दों में जाना जाए "जो मज़दूरों की श्रेणी से तो ऊँचा नहीं उठा हुआ है, किन्तु उनकी श्रेणी में रहने का जिसे गर्व है।" वह अत्यन्त वफादार था और जिस ध्येय के लिए वह काम करता था उसके लिए अपनी सब व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं को होम देने के लिये तैयार रहता था। निष्कलंक रूप से ईमानदार गौम्पर्स गरीबी की हालत में मरा और उसकी विधवा पत्नी को डब्लू०पी०ए० से काम मंजूर करना पड़ा।

उपर्युक्त कथन के किसी अंश का भी यह अभिप्राय नहीं कि गौम्पर्स महत्वाकाङ्क्षी नहीं था। वह समझता था कि वह नेतृत्व करने के लिए ही पैदा हुआ है और अमरीकी मज़दूर संघ के अध्यक्ष पद पर वह मज़बूती से चिपका रहा। उसने एक शक्तिशाली राजनीतिक मशीन तथा सुसम्बद्ध श्रम-नौकर शाही दोनों का निर्माण किया। अपनी नीतियों पर अमल कराने में वह तानाशाही से काम लेता था और समय के साथ वृद्ध हो जाने पर भी उसने अपेक्षाकृत युवा और अधिक प्रगतिशील नेतृत्व से हार नहीं मानी। किन्तु सत्ता तथा सार्वजनिक पद के लिए महत्वाकाङ्क्षा रखते हुए भी उसने कभी धन या राजनीतिक पद नहीं चाहा। ट्रेड यूनियनवाद और ए०एफ०एल० को अपने जीवन का कार्य बनाकर पूर्णतः सन्तुष्ट था।

अपनी आत्मकथा में उसने लिखा: "मैं ट्रेड यूनियन के लिए वर्षों के अपने काम का सिंहावलोकन करता हूँ और मुझे यह समझ कर खुशी होती है कि वास्तविक ट्रेड यूनियन आन्दोलन श्रमिकों को जीवन और काम का एक उन्नत स्तर प्रदान कराने के लिए एक महान साधन है।"

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय यूनियनों के मेल की तरफ जिसकी परिणति अमेरिकन फेडरेशन आव लेबर के रूप में हुई, पहला कदम १८८१ में पिट्सवर्ग में मज़दूर नेताओं के एक सम्मेलन में उठाया गया। इस सम्मेलन का जिसमें ट्रेड यूनियनों तथा नाइट्स आव लेबर दोनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, मूल उद्देश्य ऐसे ऐसोसियेशन की स्थापना करना था जिसमें सब मज़दूर शामिल हो सकें। सम्मेलन के लिए अपील में कहा गया। "हमारी असंख्य ट्रेड यूनियनें, मज़दूर सभाएँ या परिषदें, नाइट्स आव लेबर तथा अन्य अनेक स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय यूनियनें हैं। यद्यपि इन सब का कार्य महान रहा है किन्तु अगर इन सबका एक संघ बना दिया जाए तो इससे भी बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है।" किन्तु नई यूनियनवाद के पक्षपातियों तथा नाइट्स आव लेबर के नेताओं के बीच बढ़ती हुई प्रतिद्वन्द्विता के कारण ऐसा कोई लक्ष्य प्राप्त करना असम्भव हो गया और पिट्सवर्ग के सम्मेलन से संगठित व्यवसाय और मज़दूर यूनियनों का जो संघ बना उसका अस्तित्व बहुत कम समय तक रहा।

जैसा कि हमने देखा, यद्यपि कुछ राष्ट्रीय यूनियनें नाइट्स या मज़दूर सभाओं से सम्बद्ध थीं वे नोबल ऐण्ड होली आर्डर के सिद्धान्तों के अधिकाधिक खिलाफ़ होती जा रही थीं। कुछ तो उनसे बिल्कुल अलग हो रही थीं और वे अपने मामलों में दस्तंदाजी की कोशिश किए जाने पर या जिसे वे अपना अधिकार क्षेत्र समझती थीं, उसमें चंचुपात किए जाने पर स्वभावत: रुष्ट होती थीं। उनका रवैया कारपेण्टर्स के मैकगायर ने स्पष्ट प्रकट कर दिया। उसने कहा: "जहां किसी व्यवसाय की कोई राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन है, वहां उस व्यवसाय के कर्मचारियों को उसी के मातहत संगठित होना चाहिए......नाइट्स आव लेबर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"

तो भी नाइट्स ने हस्तक्षेप किया ही। ट्रेड यूनियनों में दक्ष श्रमिकों के

महत्व और मज़दूर जगत में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति को अंगीकार करते हुए आर्डर उनकी वफ़ादारी प्राप्त करने को उत्सुक था। उदाहरणार्थ पाउडरली ने नवगठित शिल्प यूनियन ऐमलगमेटेड ऐसोसियेशन आव आयरन, टिन ऐण्ड स्टील वर्कर्स को वचन दिया कि अगर वह नाइट्स में शामिल हो जाए तो वह अपना पृथक अस्तित्व और अपनी निजी शासन प्रणाली कायम रख सकती है। परन्तु इस तथा अन्य संगठनों के दक्ष कर्मचारियों ने देखा कि नाइट्स के नियंत्रण में आने के वाद वे अदक्ष मज़दूरों के स्तर पर ले आए गए हैं। उन्होंने घोषित किया कि "अमरीका के दक्ष कर्मचारियों को भिखारी वना दिए जाने से रोकने के लिए" सब वाह्य दवावों के खिलाफ़ वे अपनी स्वायत्तता कायम रखेंगे।

१८८१ में पिट्सवर्ग के सम्मेलन में गौम्पर्स ने सिगार मेकर्स के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और वह संगठन के वारे में नियुक्त समिति का अध्यक्ष वनाया गया। यद्यपि वह वस्तुतः नाइट्स आव लेवर का सदस्य था जिसमें वह १८७० के दशक में शामिल हुआ था, तो भी इसके मूल सिद्धान्तों का वह जो विरोध किया करता था उससे उसने प्रस्तावित नए संघ को विशुद्ध एक ट्रेड यूनियन संस्था वनाए रखने का भरसक प्रयत्न किया। लेकिन जोरदार वहस के वाद उसके प्रस्ताव गिर गए। एक प्रतिनिधि ने मंच पर कहा : "हम जिस प्रकार अपना आधार वदल रहे हैं वह कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है। इस कांग्रेस के बारे में व्यापक प्रचार किया गया था कि यह मज़दूर कांग्रेस है और अव हम ट्रेड यूनियनों की वात कर रहे हैं। नाइट्स आव लेवर को ही संघ का आधार क्यों न वनाया जाए ?" यद्यपि ऐसा किया नहीं गया, तो भी नए संगठन ने दक्ष तथा अदक्ष कर्मचारियों के बीच कोई भेद नहीं किया और सिद्धान्ततः उसमें जाति, रंग या राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना सब मज़दूर शामिल हो सकते थे।

फेडरेशन आव आर्गनाइज्ड ट्रेड्स ऐण्ड लेवर यूनियन्स नए यूनियनवाद के सीमित कार्यक्रम के प्रति मज़दूरों के झुकाव में कई तरह से एक संक्रमण-कालीन दौर का प्रतीक था। यद्यपि एकता का आदर्श कायम रखा गया तो भी फैडरेशन का मुख्य लक्ष्य आर्थिक प्रणाली में बुनियादी सुधार की अपेक्षा ऐसे तात्कालिक लाभों की प्राप्ति रखा गया जिनको मज़दूर पाने में समर्थ थे। इसके

विधि सम्बन्धी कार्यक्रम में, जिसके समर्थन के लिए उसने सब मज़दूर संस्थाओं
से विधानमण्डल में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का आग्रह किया, ट्रेड यूनियनों के
वैधानिक विलय, बच्चों से मज़दूरी कराने के रिवाज की समाप्ति, कानून
सम्मत ८ घण्टे के दिन का परिपालन, ठेका-मज़दूर प्रणाली की समाप्ति एक से
अप्रैण्टिस कानूनों की स्थापना षड़यंत्र सम्बन्धी कानूनों की समाप्ति की मांग
की गई।

किन्तु फेडरेशन को कोई सक्रिय समर्थन नहीं मिला। नाइट्स के प्रतिनिधि
तुरन्त उससे हट गए, और राष्ट्रीय यूनियनों में से अधिकांश ने उनका अनुसरण
किया। दूसरे वार्षिक सम्मेलन में सिर्फ १९ तथा तीसरे में सिर्फ २६ प्रतिनिधि
आए। १८८३ में गौम्पर्स उसका अध्यक्ष चुना गया किन्तु अगली बैठक में वह
शामिल तक नहीं हुआ। स्वयं मज़दूरों से सम्पर्क टूट जाने के कारण नया
संगठन शीघ्र ही पुराने राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन की तरह हो गया जिसका
वार्षिक सम्मेलन के अलावा और किसी तरह अस्तित्व का भान नहीं होता
था। इसका एकमात्र महत्वपूर्ण कार्य ८ घण्टे के दिन के लिए १ मई, १८८६
को हड़ताल कराना था किन्तु जैसा कि हमने देखा, अपने इस कार्यक्रम को
वह नाइट्स आव लेबर के सहयोग के बिना सफल नहीं बना सका।
संघ वस्तुतः १८८६ में इस दिखावे को बिल्कुल छोड़ देने वाला था।
राष्ट्रीय यूनियनों के नेताओं को विश्वास हो गया कि इससे उनकी समस्याएं
हल होने की कोई आशा नहीं है। नाइट्स आव लेबर द्वारा अपने संगठन के
स्वरूप पर निरन्तर किए जाने वाले आक्षेपों से, जो अपनी विजयों से गर्वोन्मत्त
होकर यह कहने लगे थे कि मज़दूर आन्दोलन में स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों का कोई
स्थान नहीं, अपने बचाव के लिए उन्होंने अधिक दृढ़ता से काम लेने का निर्णय
किया। फलस्वरूप १८ मई १८८६ को फिलाडेल्फिया में राष्ट्रीय यूनियनों का
एक और सम्मेलन बुलाया गया, जिसका उद्देश्य ही यह रखा गया कि "एक
तत्व के निन्दात्मक कार्यों से जो खुल्लमखुला यह शेखी बघारते हैं कि "ट्रेड
यूनियनों को नष्ट करना जरूरी है", अपने-अपने संगठनों की रक्षा की जाए।"
स्वयं सिगार मेकर्स इण्टरनेशनल यूनियन के मामलों में नाइट्स द्वारा टाँग
अड़ाए जाने से ट्रेड यूनियनिस्टों का गुस्सा विशेष रूप से भड़क उठा। न्यूयार्क
लोकल में आन्तरिक संघर्षों के फलस्वरूप, जो अदक्ष श्रमिकों को शामिल

करने और समाजवाद को अग्रसर करने के प्रश्नों पर उत्पन्न हुए थे, एक विद्रोही वर्ग ने पिट्ठ—संस्था से अलग होकर प्रोग्रेस्सिव सिगार मेकर्स यूनियन वना ली। स्ट्रासर ने इस कदम की कड़े शब्दों में निन्दा की और उसने विद्रोहियों को किसी भी रूप में मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया। उन्हें वह व्यंग से "किराये के मकान की गन्दगी" कहा करता था। इस स्थिति में नाइट्स आव लेबर की ४९ वीं जिला सभा संग्राम में आ कूदी। बड़ी उग्रता से विद्रोही यूनियन का उसने समर्थन किया और आर्डर में उसके प्रवेश के लिए आन्दोलन किया।

जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, तब कम से कम सिद्धान्त रूप में समझौते के एक ऐसा सामान्य आधार खोज निकालने का, जिसमें नाइट्स को राष्ट्रीय यूनियनों के प्रति शत्रुता खत्म कर देने के लिए मनाया जा सकता हो, एक और प्रयत्न किया गया। मज़दूर आन्दोलन के भीतर दोनों ग्रुपों के अलग अलग उद्देश्यों में तालमेल का और उनका झगड़ा खत्म करने के लिए एक "संधि" का प्रस्ताव किया गया। नाइट्स से यह मान लेने को कहा गया कि वे किसी ट्रेड यूनियनिस्ट को उसकी यूनियन की रजामन्दी के बिना, या ऐसे किसी भी मज़दूर को जो अपने धन्धे के लिए निर्धारित वेतन दर से कम पर काम कर रहा हो, आर्डर में शामिल नहीं करेंगे और उनसे यह भी कहा गया जिस धन्धे में कोई राष्ट्रीय यूनियन पहले से बनी हुई हो उसमें मज़दूरों द्वारा संगठित किसी भी स्थानीय सभा का चार्टर वापस ले लिया जाए।

क्या वस्तुतः यह कोई संधि थी ? इसकी एक पक्षीय शर्तें : राष्ट्रीय यूनियनों के सामने नाइट्स द्वारा घुटने टेक दिए जाने की मांग प्रतीत होती थी। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के कुछ प्रतिनिधि शायद यह समझते रहे हों कि उन्होंने अपनी टेक के बारे में एक वक्तव्य दिया है जिससे कि अगर आर्डर ने समझौते की भावना दिखाई तो वे पीछे हटने को तैयार रहेंगे। किन्तु इसमें कोई शक नहीं कि नए यूनियनवाद के अनुयायियों के मन में यह एक युद्ध घोषणा थी। उनका असली उद्देश्य एक अन्य संघ के लिए राष्ट्रीय यूनियनों का समर्थन प्राप्त करना था जो नाइट्स आव लेबर से बिल्कुल अलग हो जाए और अपना सारा ध्यान दक्ष शिल्प-कर्मचारियों के हितों की रक्षा पर केन्द्रित कर दे। गौम्पर्स यह काम ५ वर्ष पहले करना चाहता था, किन्तु तब इस का

समय नहीं आया था। अब नाइट्स और राष्ट्रीय यूनियनों की बीच बढ़ती हुई शत्रुता ने जो सिगार मेकर्स में दोहरे यूनियनवाद पर संघर्ष में तीव्र रूप में सामने आई, निर्णयात्मक कार्रवाई के लिए अवसर प्रदान कर दिया।

जो लोग बिल्कुल तोड़ा-टूटन चाहते थे, नोबल ऐण्ड होली आर्डर पूर्णतः उनके हाथों में खेल गया। जिन मामलों पर राष्ट्रीय यूनियनों के साथ उसका झगड़ा था, उनपर समझौता करने की कुछ इच्छा व्यक्त करते हुए भी प्रस्तावित संधि के बारे में अधिकृत रूप से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हड़तालों की विफलता और हे मार्केट स्क्वेयर के दंगे की प्रतिक्रिया यद्यपि नाइट्स की स्थिति को पहले से ही कमजोर कर रहे थे, तो भी वे अपने ही कार्यक्रमों से चिपटे रहना चाहते थे और रियायत करने की कोई जरूरत महसूस नहीं करते थे। अक्तूबर में रिचमौण्ड सम्मेलन में पाउडरली ने विचार के लिए कोई संधि प्रस्तुत तक नहीं की। नए राष्ट्रीय व्यावसायिक जिलों की स्थापना करके राष्ट्रीय यूनियनों को चुनौती दी गई, प्रोग्रेस्सिव सिगार मेकर्स को बाकायदा आर्डर में शामिल किया गया और उनके अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद को हल करने की कोई चेष्टा नहीं की गई।

इसके जवाब में राष्ट्रीय यूनियनों ने ८ दिसम्बर, १८८६ को अपना फिर सम्मेलन किया और इस सम्मेलन में उनके साथ समाप्त प्राय फेडरेशन आव आर्गनाइज़्ड ट्रेड्स ऐण्ड लेबर यूनियन्स का अब भी प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ मुट्ठी भर प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कुल मिलाकर २५ श्रमिक ग्रुपों के कोई ४२ प्रतिनिधि शामिल हुए। जिन राष्ट्रीय यूनियनों ने इसमें भाग लिया, उनमें आयरन मोल्डर्स माइनर्स ऐण्ड माइन लेबरर्स, टाइपोग्राफर्स, जर्नीमैन टेलर्स, जर्नीमैन बैकर्स, फर्निचर वर्कर्स, मैटल वर्कर्स, ग्रेनाइट कटर्स, कारपेण्टर्स और सिगार मेकर्स शामिल थीं। उनके कुल सदस्य लगभग १,५०,००० थे। अब प्रतिनिधियों का एकमात्र वास्ता यह रह गया कि जिस धन्धे का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उसके हितों को वे बढ़ाएं और अच्छी तरह विचार-विमर्श के बाद उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक नया संगठन बनाया और सेम्युअल गौम्पर्स को इसका पहला प्रधान चुना। इस प्रकार अन्त में यह अमरीकी मज़दूर संघ (अमेरिकन फेडरेशन आव लेबर) बना। इसके जन्म की तारीख बाद में पीछे १८८१ में धकेल दी गई जबकि फेडरेशन आव आर्गनाइज्ड ट्रेड्स ऐण्ड लेबर

यूनियन्स की स्थापना हुई थी। किन्तु यद्यपि ए० एफ० एल० ने अपने पूर्ववर्ती संगठन के कोष और कागज़ात को ले लिया था तो भी दोनों ग्रुप बिल्कुल भिन्न थे और अमरीकी मजदूर संघ का इतिहास वस्तुतः १८८६ में प्रारम्भ हुआ।

अपने जन्म की परिस्थितियों के कारण नए संगठन का पहला सिद्धान्त यह रखा गया कि "हर धन्धे की स्वायत्तता का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए।" राष्ट्रीय स्तर पर मामले निवटाने के लिए नियुक्त की गई कार्यकारी परिषद् को उन मामलों में जो सदस्य यूनियनों के अधिकार क्षेत्र में आते थे, हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। मज़दूरों में एकता शिक्षा और नैतिक प्रेरणा के ज़रिये स्थापित करने का निश्चय किया गया, केन्द्रीकृत नियंत्रणों के ज़रिये नहीं जैसा कि नाइट्स आव लेवर किया करते थे। फिर भी कार्यकारिणी परिषद् के महत्वपूर्ण काम थे। यह घटक यूनियनों के लिए चार्टर जारी करती थी, और दोहरे यूनियनवाद के खात्मे के लिए जिसे सारे मज़दूर आन्दोलन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला समझा गया, इसे अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी सब झगड़े निवटाने का हक प्रदान किया गया। एक वित्तीय कोष की स्थापना के लिए सब सदस्य यूनियनों पर प्रति व्यक्ति टैक्स लगाया गया, जिससे कि हड़ताल और तालाबन्दी की अवस्थाओं में ए०एफ०एल० ठोस सहायता दे सके और सब मज़दूर संगठनों का परम्परागत ढंग से एक विधि सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार किया गया। अन्त में मज़दूर सम्बन्धी कानूनों को पास कराने में और ज्यादा प्रभाव डालने के लिए कार्यकारिणी परिषद् के सामान्य अधिकार के मातहत नगर-संगठन और राज्य संघ दोनों का निर्माण किया गया।

ज़्यादा जोर निश्चित रूप से आर्थिक और औद्योगिक कार्रवाई पर दिया गया। आगे चलकर ए०एफ०एल० को मालिकों से मान्यता प्राप्त कराने के लिये राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय यूनियनों का समर्थन करना पड़ा, सामूहिक सौदे-बाजी के समझौते किए, और ऐसी स्थिति बनाए रखी, जिसमें अन्य उपाय विफल होने पर वे प्रभावशाली ढंग से हड़ताल कर सकें। विधि सम्बन्धी कार्यक्रम को जिसमें पुराने फेडरेशन आव आर्गनाइज्ड ट्रेड्स ऐण्ड

लेबर यूनियन्स के अधिकांश उद्देश्य शामिल थे अपने पूर्ववर्ती की नीति को स्पष्ट ही अपर्याप्त मानते हुए चोट करने की इस बुनियादी नीति के मुकाबले गौण कर दिया गया। इसके अतिरिक्त ए०एफ०एल० ने शुरू से राजनीति में सीधे भाग न लेने और किसी एक दल का समर्थन न करने का दृढ़ निश्चय कर रखा था। इसने किसी के राजनीतिक स्वरूप की परवाह किए बिना मज़दूरों के मित्रों को पुरस्कृत करने और उनके दुश्मनों को दण्डित करने के सिद्धान्त पर काम किया।

शुरू के वर्षों में अमरीकी मज़दूर संघ पूर्णतः मानो सेम्युअल गौम्पर्स ही था। उसके वफादार साथी थे किन्तु संगठन को जीवन और दिशा उसी ने प्रदान की। बाद में उसने इस जमाने की बाबत लिखा : "काम ज़्यादा, वेतन कम और सम्मान बहुत ही कम था किन्तु इन चीज़ों ने उसे हतोत्साह नहीं किया। सिगार मेकर्स द्वारा प्रदान किए गए १० फुट लम्बे और ८ फुट चौड़े एक कमरे में उसने अपना हैडक्वार्टर कायम किया, जिसमें एक किचन टेबल, कुर्सियों का काम देने वाले कुछ मूढ़ों और टमाटर की पेटियों के बनाए गए फाइल रखने के बक्स के अलावा और कोई फर्निचर नहीं था। इसी कमरे से उसने उत्साह, निष्ठा और अथक परिश्रम से, नए संगठन में प्राण फूंकने का बीड़ा उठाया और उसके इन्हीं गुणों की बदौलत यह संगठन जीवित भी रह सका। वह सारे देश में मज़दूर नेताओं को सदा अपने हाथ से असंख्य चिट्ठियां लिखा करता था; अपने आन्दोलन का प्रचार करने के साधन के रूप में कुछ समय तक "ट्रेड यूनियन ऐडवोकेट" का सम्पादन किया; यूनियन चार्टर प्रदान करता, फीस इकट्ठी करता और रोज़-मर्रा का सब काम करता था; सम्मेलनों का आयोजन करता और भाषण देने तथा संगठन करने के लिए यात्राएँ किया करता था और शनैः शनैः किन्तु निश्चय पूर्वक उसने अमरीकी मज़दूर संघ को एक विशुद्ध कागजी संगठन से उभार कर मज़दूरों के अधिकारों का उग्र और शक्तिशाली चैम्पियन बना दिया। वह समझता था कि उसके जिम्मे एक पवित्र काम है और जबसे ए०एफ०एल० अस्तित्व में आया, तभी से ३८ वर्ष बाद अपनी मृत्यु तक यही उसका समस्त जीवन रहा।

संघ का दीर्घकालीन संघर्ष यद्यपि उद्योग की ताकतों के साथ होना था, तो भी प्रारम्भिक वर्षों में नाइट्स आव लेबर के साथ उसके झगड़े चलते

रहे। १८८० की दशाब्दि के अन्त में और १८९० की दशाब्दि के प्रारम्भ में दोनों संगठनों में मेल कराने की और कोशिश की गई किन्तु ये भी बिल्कुल असफल रही। स्थिति करीब-करीब वैसी हो गई, जैसी आधी सदी बाद तब पैदा हुई जब स्वयं अमरीकी मजदूर संघ को विद्रोही यूनियनों ने, जिन्होंने एक औद्योगिक संगठनों की कांग्रेस बना ली थी, चुनौती दी। सिद्धान्त दाव पर लगे हुए थे किन्तु प्रतिस्पर्धी नेताओं की प्रतिद्वन्द्विता और महत्त्वाकाङ्क्षाओं के आगे वे प्रायः महत्वहीन हो जाते थे।

पाउडरली कालान्तर में राष्ट्रीय यूनियनों से पूर्णतः घृणा करने लगा। १८८९ में उसने एक साथी को लिखा : "मैं तुम से स्पष्ट कहूंगा कि राष्ट्रीय सभाएं, जितनी जल्दी खत्म हो जाएं मुझे उसकी चिन्ता नहीं है। वे औरों को हमारे पास आने से रोकती हैं और मैं उन्हें यह सलाह देने का लोभ संवरण नहीं कर सकता कि वे मैदान में आकर अकेले काम करके दिखाएं और तब तुम देखोगे कि किस प्रकार वे कुछ थोड़े से व्यक्तियों के लाभ के लिए, जो किसी न किसी चीज में अगुआ बनना चाहते हैं, संगठन के चक्र को पीछे घुमाने से भी नहीं चूकेंगे। "नाइट्स आव लेबर, उनके उद्देश्य और आकाङ्क्षाओं के बारे में सेम्युअल गौम्पर्स भी कम व्यंगबाण नहीं छोड़ता था। १८९७ में उसने कहा: "नाइट्स आव लेबर के साथ एकता की बात करना मूर्खता है। वे ट्रेड यूनियनों के उतने ही बड़े शत्रु हैं, जितना कोई मालिक हो सकता है, बल्कि उनमें बदले की भावना ज्यादा है। उन्हें खुश करने या उनके साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार तक करने से कोई लाभ नहीं।" इन परिस्थितियों में मजदूरों की एकता की सम्भावना लुप्त हो गई और धीरे-धीरे एक तरह नाइट्स की शक्ति कम होती गई और दूसरी ओर अमरीकी मजदूर संघ जोर पकड़ता गया। संघ की तरक्की चामत्कारिक नहीं रही। १॥ लाख की सदस्यता ६ वर्ष बाद सिर्फ २॥ लाख पर पहुँच सकी। इन वर्षों में सब यूनियनों पर उद्योग के उग्र प्रत्याक्रमण ने सरकार व अदालतों के आमतौर से दमनात्मक रवैये ने और अन्त में १८९३ की मन्दी के कठिन समय ने किसी भी संगठन को अपनी शक्ति बनाए रखना बहुत मुश्किल कर दिया, उसके विकास और विस्तार की तो बात ही अलग है। किन्तु गौम्पर्स अपने ।र्य में दृढ़ता से लगा रहा उसने संघ को उसके तात्कालिक और व्यावहारिक

उद्देश्यों से भटकने नहीं दिया और १८६३ के वार्षिक सम्मेलन में, जो कुछ अब तक हासिल किया जा चुका था, उस पर वह गर्व अनुभव कर सका।

एकत्रित प्रतिनिधियों से उसने कहा कि "पिछले प्रत्येक औद्योगिक संकट में ट्रेड यूनियनें जहां वस्तुतः कुचल दी जाती थीं और उनका अस्तित्व खत्म हो जाता था, वहां मौजूदा यूनियनों ने न केवल अपनी प्रतिरोध की शक्ति, बल्कि स्थिरता और स्थायित्व का भी प्रदर्शन कर दिया है।

नए यूनियनवाद के व्यावहारिक पहलुओं को अग्रसर करने में ए०एफ०एल० के महत्व से यह तथ्य दरगुजर नहीं कर दिया जाना चाहिए कि १६ वीं सदी की समाप्ति और बाद के वर्षों दोनों कालों में पुनरुज्जीवित मज़दूर आन्दोलन का वास्तविक आधार राष्ट्रीय यूनियनें ही रहीं। वे ए०एफ०एल० के बिना रह सकती थीं किन्तु उनके बिना ए०एफ०एल० का कोई मतलब नहीं था। उनकी स्वायत्तता पूरी थी और स्थानीय यूनियनों पर जिनसे वस्तुतः मज़दूरों की ताकत बनती थी, उन्हीं का नियंत्रण था। उनका काम स्थानीय यूनियनों की गतिविधियों का दिशादर्शन, जो व्यवसाय या उद्योग उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके जरिये यूनियन संगठन का विस्तार करना; सामूहिक सौदे-बाजी और हड़तालों में (जिनके लिए आम रक्षाकोष के निमित्त प्रतिव्यक्ति टैक्स लगाया जाता था) यथा सम्भव सहायता देना और ए०एफ०एल० के अधिक सामान्य कार्यक्रम में हिस्सा लेना था।

समय के साथ-साथ मूल शिल्पिक यूनियनों ने अपना अधिकार क्षेत्र काफी बढ़ा लिया और उनके नाम प्रायः इस विस्तार के इतिहास को प्रतिक्षिप्त करते हैं। इसके बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं किन्तु इस रुझान का प्रतीक एक उदाहरण "इण्टरनेशनल ऐसोसियेशन आव मार्बल, स्लेट ऐण्ड स्टोन पालिशर्स रबर्स ऐण्ड साय्यर्स, टाइल ऐण्ड मार्बल सेटर्स हेल्पर्स ऐण्ड टेराजो हेल्पर्स" नाम है। नए तौर तरीकों और आर्थिक परिवर्तनों के कारण अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी समस्याओं का निपटारा ए०एफ०एल० के लिए अपनी स्थापना के शुरू से ही एक बड़ी समस्या बन गया।

यूनियनों का एक महत्वपूर्ण ग्रुप जो ए०एफ०एल० से सम्बद्ध नहीं हुआ, रेलवे ब्रदरहुडों का था। रेल कर्मचारियों का संगठन एक निराले ही ढंग पर

हुआ था और शिल्पिक रूप रेखा पर आधारित होने पर भी कुछ विशिष्ट कारणों से अन्य मामलों में दूसरे कर्मचारियों के संगठनों से भिन्न था। लोकोमोटिव इंजीनियर्स का संगठन काफी पहले १८६३ में, उसके ५ वर्ष बाद रेलवे कण्डक्टर्स का, १८७३ में ट्रेनमेन का और उसके १० वर्ष बाद फायरमैन का संगठन बना। यद्यपि इन्होंने १८७७ की हड़ताल में भाग लिया था, तो भी बाद के वर्षों में ये चारों ब्रदरहुड ज़्यादा कंजरवेटिव हो गए और अपने सदस्यों के खतरों से भरे काम के कारण उनके यूनियन कार्यक्रमों में बीमा व कल्याण की अन्य बातों का विशेष महत्व रहा। अन्य रेल कर्मचारियों का स्थायी संगठन ज़्यादा धीरे-धीरे 'विकसित हुआ। १८९० के दशक में यूजीन वी० डेब्स द्वारा सब अमरीकी रेल कर्मचारियों की एक यूनियन बनाने की कोशिश किए जाने के बाद, जिसकी चर्चा हम आगे चल कर करेंगे, वर्कशाप कर्मचारियों, स्विचमैनों, यार्डमास्टरों, सिगनलमैनों, तार भेजने वालों तथा रेलवे और स्टीमशिप क्लर्कों की अलग-अलग यूनियनें बनाई गई और उन्हें चारों ब्रदरहुडों के स्वतन्त्र रहने के बावजूद ए०एफ०एल० से सम्बद्ध कर दिया गया।

अन्तर्राज्यीय यूनियनों द्वारा १८९० की दशाब्दि की मन्दी को झेल लेने का यह मतलब नहीं कि मज़दूर जो चाहते थे, प्राप्त कर लेते थे, और बहुत शक्तिशाली यूनियनें मालिकों के साथ समानता के आधार पर ठहर पाती थीं। इस दशक में मज़दूरों के वेतन कम और काम के घण्टे ज़्यादा रहे और अदक्ष कर्मचारी तो मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाते थे। मज़दूरों को अब भी सस्ती से सस्ती कीमत पर खरीदा जाने वाला माल समझा जाता था और उनका संगठित होने और सामूहिक सौदे-बाजी का अधिकार स्वीकार नहीं किया गया था। उद्योग चूंकि काली सूची में नाम दर्ज करके सौगन्ध खिला-कर, तथा हड़ताल भंजकों और पिंकरटन जासूसों के जरिये यूनियनों की ताकत को तोड़ देने के लिए प्रयत्नशील था और हड़तालों का सामना करने के लिये कानून व व्यवस्था के संरक्षण के नाम पर राज्य की मिलीशिया और संघीय सेनाओं को बुला सकता था इस लिए मज़दूर समझते थे कि वे अब भी अत्य-धिक विपरीत परिस्थियों से जूझ रहे हैं।

अमरीकी मज़दूर संघ का ओज भविष्य के लिए आशा बंधाता था। गौम्पर्स के आशावाद के बावजूद १८९० के दशक की लगातार मन्दी ने

राष्ट्र के मज़दूरों पर बहुत बुरा असर डाला और इन वर्षों के संघर्ष में उन्हें कुछ बहुत निर्णयात्मक पराजयों का सामना करना पड़ा।

—:o:—

१० : होमस्टेड और पुलमैन

१८६० के दशक में मज़दूर आन्दोलन के इतिहास की खास बात यद्यपि यह रही कि अमरीकी मज़दूर संघ ने नाइट्स आव लेवर पर विजय पाई और नए यूनियनवाद की शक्ति का प्रदर्शन किया तो भी इस दशाब्दि की खूबी इसकी महान् हड़तालें थीं। इससे पहले कभी भी मज़दूर और पूँजी में ऐसा योजनाबद्ध निजी युद्ध नहीं हुआ जैसा १८६२ में होमस्टेड में हुआ और न ही आम जनता औद्योगिक संघर्ष के खतरों पर पहले कभी इतनी भयभीत हुई थी जितनी दो वर्ष बाद पुलमैन की हड़ताल के दौरान हुई। ये दोनों हड़तालें १८७७ की रेल कर्मचारियों की हड़ताल से मुख्यतः इस बात में भिन्न थीं कि ये हड़तालें विद्रोह की आकस्मिक अभिव्यक्ति के बजाय शक्तिशाली यूनियनों द्वारा की गई थीं किन्तु इनमें हिंसा और रक्तपात पहले जैसा ही हुआ। १८६० के दशक में मज़दूर समस्या की गम्भीरता को इससे ज़्यादा जोरदार ढंग से व्यक्त नहीं किया जा सकता था।

इसके अलावा इन हड़तालों में औद्योगिक श्रमिकों में व्याप्त जिस सामान्य असन्तोष का इजहार हुआ उसकी १८६० की दशाब्दि की मन्दी ज्यादा गंभीर हो जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ हुईं और पौपुलिज्म के उत्थान के रूप में शहरों की अशान्ति किसानों के विद्रोह से मिल गई। मध्य-पश्चिम के किसानों और पूर्व के मज़दूरों में गठबन्धन मजबूत न हो सकने का आंशिक कारण यह था कि ए० एफ़० एल० सीधी राजनीतिक हरकतों में भाग नहीं लेना चाहता था किन्तु १८६६ में कंजरवेटिव लोगों में यह भय छा गया था कि चुनाव में पौपुलिस्टों के क्रांतिकारी सिद्धान्तों की जीत से पूँजीवादी प्रणाली का विध्वंस हो जाएगा।

६ जुलाई, १८६२ की भोर में दो नावें शनैः-शनैः होमस्टेड, पेंसिलवेनिया की तरफ मोनोंगा हेला नदी के ऊपरी भाग की ओर खींच कर लाई जा रही थीं। कारनेगी इस्पात कम्पनी के स्थानीय कारखाने में हड़ताल थी। होमस्टेड

के दक्ष मज़दूरों ने, जो ऐमलगमेटेड ऐसोसियेशन आव आयरन, स्टील ऐण्ड टिन वर्क्स के सदस्य थे, वेतनों में नई कटौतियों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था और बाकी मज़दूर उनकी पीठ पर थे। इस पर कम्पनी के जनरल मैनेजर हेनरी क्लेफ्रिक ने जो कठोर हृदय और अत्यन्त मज़दूर विरोधी था, तुरन्त ही सारा कारखाना बन्द कर दिया और यूनियन के साथ आगे कोई बातचीत करने से इंकार कर दिया। कम्पनी की सम्पत्ति की रक्षा के लिए विशेष डिप्टी शेरिफ तैनात किए गए और कारखाने के चारों ओर तख़्तों का बाड़ा लगा दिया गया, जिनके ऊपर कँटीले तार लगा दिए गए। किन्तु ताला-बन्दी से बाहर खदेड़े गए मज़दूरों ने उन्हें यह समझकर शहर से बाहर भगा दिया कि ये तैयारियाँ हड़तालभंजकों के इस्तेमाल की द्योतक हैं। यह फ्रिक के अधिकार को चुनौती थी जिसे उसने खुशी से स्वीकार किया। उसको ऐमलगमेटेड को सदा के लिए कुचल देने का मौका मिला था। मोनोगाहेला नदी के ऊपर जो दो नावें खींच कर लाई जा रही थीं उनमें विंचेस्टर रायफलों से लैस ३०० पिकरटन जासूस थे।

इस्पात कम्पनी की यह निजी सेना जैसे ही होमस्टेड के किनारे आकर उतरने की तैयारी करने लगी वैसे ही उन नावों तथा तट के बीच एकदम गोलियाँ चलने लगीं। मज़दूरों ने इस्पात की छड़ों की ओट में मोर्चे सम्हाल लिए थे और जब पिकरटनों ने कारखाने पर कब्जा करने की कोशिश की तो नदी के साथ जूझते हुए संग्राम में उन्हें पीछे धकेल दिया गया। उस दिन सारे समय, प्रातः ४ बजे से लेकर तीसरे पहर के बाद ५ बजे तक गोलियाँ चलती रहीं। हड़तालियों ने रेलवे के सलीपरों के ढेर की आड़ में एक तोप लगा दी और नौकाओं पर सीधी गोलाबारी की। जब वे उन्हें नहीं डुबा सके तो उन्होंने तेल के पीपे नदी में उड़ेल दिए और तेल में आग लगा दी। पिकरटन, जिनके तीन आदमी मारे जा चुके थे और इससे बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, फँस गए। जो टग उन्हें नदी की धार पर खींच कर लाया था, वह भी उन्हें छोड़ गया। अब वे असहाय होकर नावों में भीड़ लगाए हुए थे और ये नावें किनारे से बहुत दूर थीं। अंत में उन्होंने सफेद झण्डी दिखा दी और आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। शहर से सुरक्षित बाहर निकालने की गारण्टी के बदले में उन्होंने अपने हथियार और गोलाबारूद सौंपना स्वीकार कर लिया।

किन्तु होमस्टेड में, जहां ७ व्यक्ति मारे गये थे, उत्तेजना बहुत फैल रही थी, जिससे आसानी से व्यवस्था पुनः स्थापित नहीं हो सकी। जब पिकरटन किनारे पर उतरे तो इन पर फिर हमला किया गया और पिट्सबर्ग के लिए ट्रेन पर सवार होने से पूर्व उन्हें पत्थरों और डण्डों से लैस क्रुद्ध स्त्री-पुरुषों की एक भीड़ को चीरकर पार आना पड़ा। इस प्रकार जब होमस्टेड के मज़दूर पहले दौर में विजयी होकर कम्पनी के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब इस छोटे से नगर पर एक बेचैनीपूर्ण शान्ति छा गई।

अगली घटना ६ दिन बाद घटी। तब १२ जुलाई को राज्य की मिलीशिया ने, जिसकी तादाद फ्रिक की अपील पर पेंसिलवेनिया के गवर्नर ने ८००० कर दी थी, मार्शला के मातहत होमस्टैड को अपने कब्जे में लेने के लिए कूच किया। इस प्रकार का संरक्षण प्राप्त करके कारनेगी कम्पनी ने दूसरे कर्मचारी काम पर बुलाने शुरू कर दिए—जिनके बारे में तालाबन्दी से बाहर निकाले हुए कर्मचारी जानते थे कि उन्हें उनका काम सौंपा जा रहा है—और पिंकरटनों पर हमले के लिए हड़तालियों के नेताओं के खिलाफ़ दंगे और हत्याओं के आरोप लगाने शुरू कर दिये। मिलीशिया के संरक्षण में कारखाना फिर चालू किया गया और गैर यूनियन व्यक्तियों को ऐमलगमेटेड के सदस्यों का काम दे दिया गया। जब नवम्बर में हड़ताल अधिकृत रूप से वापस ली गई तब दो हज़ार हड़तालभंजक लाए जा चुके थे और होमस्टैड के ४००० मूल-कर्मचारियों में से सिर्फ ८०० को पुनः काम पर लिया गया।

शुरू के संघर्ष के बाद एक और हिंसात्मक काण्ड हुआ। २३ जुलाई को रूस में पैदा हुआ हुआ एक अराजकतावादी अलेग्जेण्डर बर्कमैन, जिसका हड़तालियों से कोई सम्बन्ध नहीं था, किन्तु जो कार्नेगी कम्पनी द्वारा पिकरटनों का इस्तेमाल किए जाने से बहुत क्रुद्ध था, पिट्सबर्ग में फ्रिक के दफ्तर में जबर्दस्ती घुस आया और उसकी हत्या करने की कोशिश की। फ्रिक के यद्यपि गोली भी लगी और छुरा भी लगा तो भी वह सांघातिक रूप से घायल नहीं हुआ और हमलावर पकड़ा गया। हमले की योजना बर्कमैन और उसकी महिला साथिन ऐम्मा गोल्डमैन ने मिलकर बनाई थी। ऐम्मा भी "काम के जरिये प्रचार" के सिद्धान्त की कम उत्साही वकील नहीं थी और जैसा कि ~ में उसने अपनी आत्मकथा में बताया कि सिर्फ़ धन की कमी के कारण ही

वह बर्कमैन के साथ उसके मिशन पर नहीं जा सकी। बर्कमैन को हत्या के इरादे से हमला करने के अभियोग में २१ वर्ष की जेल की सजा मिली और १३ वर्ष बाद जेल से छूटने पर उसे ऐम्मा गोल्डमैन के साथ रूस निर्वासित कर दिया गया।

इन खतरनाक घटनाओं ने देश को १८८० के दशक की महान उथल-पुथलों से या एक दशाब्दि पूर्व की रेल हड़ताल से भी अधिक क्षुब्ध कर दिया। क्योंकि होमस्टेड की घटना असंगठित मज़दूरों का आकस्मिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह एक बहुत आधुनिक कम्पनी तथा देश में उस वक्त की सब से शक्तिशाली यूनियन के बीच एक युद्ध था। प्रत्येक विवादग्रस्त पक्ष ने कानून अपने हाथ में ले लिया था। शिकागो ट्रिब्यून ने ७ जुलाई को अपने सारे मुख-पृष्ठ पर इस युद्ध का वर्णन छापते हुए लिखा : "यह एक ऐसा संग्राम था, जिसमें इतनी रक्त-पिपासा और साहस का प्रदर्शन किया गया, जितना किसी वास्तविक युद्ध में भी नहीं किया जाता।"

होमस्टेड की हड़ताल से पहले तक कारनेगी कम्पनी और यूनियन के बीच सम्बन्ध अच्छे थे और दक्ष श्रमिकों के लिए ३ वर्ष का एक करार करके काम की हालतें निश्चित कर दी गई थीं। इसमें इस्पात की छड़ों के मूल्य के अनुसार घटते-बढ़ते वेतन दर की व्यवस्था की गई थी। कारनेगी स्वयं को यूनियनों का पक्षपाती कहा करता था। कुछ वर्ष पूर्व 'फोरम' में उसने लिखा था कि मज़दूरों का अपना संगठन बनाने का अधिकार निर्माताओं के अपना संगठन बनाने से कम पवित्र नहीं है और उन्होंने हड़ताल भंजकों के उपयोग से जिन कर्मचारियों का रोज़गार खतरे में पड़ जाता था, उनके प्रतिवास्तविक सहानुभूति प्रदर्शित की। उन्होंने लिखा : "जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए अपनी दैनिक मज़दूरी पर निर्भर करने वाले व्यक्ति से यह आशा करना कि दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका स्थान लिए जाने पर वह
रहेगा, उससे बहुत अधिक आशा करना है।"
साथ जब पुराना करार खत्म हुआ तो
पूर्णतः फ्रिक के साथ में थी।

अगर कारनेगी घटनास्थल पर
भिन्न ही होता। तो भी यह बात

दे दी थी और यह नहीं माना जा सकता कि उसे यह पता न होगा कि उसके जनरल मैनेजर का रवैया मज़दूर-विरोधी है। वस्तुतः हड़ताल के दौरान उसने एक रिपोर्टर से कहा : "कम्पनी जिस तरह मामले को सुलझा रही है, उसे मेरा पूर्ण समर्थन प्राप्त है।" और ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ग्लैडस्टोन को एक पत्र में उसने लिखा कि उसकी फर्म ने मज़दूरों के सामने उदार शर्तें रखी हैं और "वह इतनी दूर तक गई है, जितनी मैं चाह सकता था।" तो भी इसी पत्र में उसने लिखा कि अपनी शर्तें मनवाने के लिए होमस्टेड कारखाने को नए आदमियों से चलवाने का फ्रिक ने गलत कदम उठाया है। ग्लैडस्टोन को उसने लिखा : "इससे मुझे को कष्ट हुआ है वह दिन पर दिन बढ़ रहा है। कारखाना मानव रक्त की एक बूंद जितना भी कीमती नहीं है। मैं चाहता हूं कि सब डुबा दिया जाता तो अच्छा होता।"

तथापि नियंत्रण फ्रिक के हाथ में था और उसने हड़ताल भंजक और पिंकरटन गार्ड, जिनकी व्यवस्था वेतन की बातचीत टूट जाने से पहले ही कर ली गई थी, बुलाए ही इसलिए गए थे कि यूनियन को कुचल दिया जाए। और वह कामयाब हो गया। होमस्टेड में तो उसका ख़ातमा ही हो गया और पिट्सबर्ग क्षेत्र की अन्य इस्पात मिलों में, जहां मज़दूरों द्वारा सहानुभूति में हड़ताल किये जाने पर मालिकों ने तुरन्त बदला लिया था, यह यूनियन बहुत कमज़ोर हो गई। एमलगमेटेड ने इस्पात कर्मचारियों को संगठित करने की पुनः कोशिश की किन्तु कारनेगी कम्पनी और उसकी उत्तराधिकारी युनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन के निरन्तर विरोध के सामने उसकी शक्ति क्षीण ही होती गई। इसके ४० वर्ष बाद तक कोई प्रभावशाली इस्पात यूनियन नहीं बन सकी, जबकि १९३० के दशक में औद्योगिक यूनियनवाद के पुनरुत्थान के साथ इस्पात कर्मचारियों की संगठन समिति का निर्माण हुआ।

ऐमलगमेटेड अमरीकी मज़दूर संघ के साथ सम्बद्ध था। गौम्पर्स ने हड़तालियों के साथ बड़ी सहानुभूति दिखलाई और जिन पर पिंकरटनों पर हमला करने का अभियोग था उनके बचाव के लिए धन संग्रह में मदद की। किन्तु फेडरेशन कोई प्रभावशाली सहायता नहीं दे सका और गौम्पर्स की गर्वपूर्ण उक्तियों से मज़दूरों को क्या सन्तोष मिल सकता था।

कहा जाता है कि 'पिट्सबर्ग लीडर' मे उसने लिखा : "होमटेस्ड के

इस्पात कर्मचारियों ! अगर कोई गुलाब खिल रहा है तो यह तुम्हारी कृति है, अगर संसार में कोई ऐसी चमकीली चीज है जो होमस्टेड को कीमती बनाती है तो यह तुम्हारी कृति है। तुमने इस चामत्कारिक तानाशाह के आगे सिर झुकाने से इन्कार कर दिया और इसका उसने पहला जवाब यह दिया कि तुम्हें अपने सामने झुकने को मजबूर करने के लिए और अन्ततोगत्वा तुम्हें अपने शांतिपूर्ण घरों से खदेड़ने के लिये इस शान्तिपूर्ण नगर में भाड़े के टट्टू ले आया। मुझे नहीं मालूम कि ६ जुलाई के उस स्मरणीय दिवस की प्रातः पहली गोली किसने चलाई किन्तु मैं यह जानता हूँ कि अमरीकी जनता का हृदय होमस्टेड के बहादुर आदमियों के साथ एकता और सहानुभूति से स्पन्दित हो रहा था ! मैं शांति का आदमी हूँ और शांति से प्रेम करता हूँ किन्तु मैं उस महान व्यक्ति पैट्रिक हेनरी के समान हूँ, मैं एक अमरीकी नागरिक की तरह पुकारता हूँ 'मुझे आजादी दो या मौत'।"

संरक्षणात्मक तटकर के विरुद्ध थे, इस अवसर का लाभ उठाकर यह दिखाने के लिए प्रयत्नशील थी कि अमरीकी मज़दूरों के वेतनों की सुरक्षा के नाम पर ऊंचे तटकर लगाने का दावा पेश करते हुए भी इस्पात उद्योग मज़दूरियां घटा रहा है और अपने कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। उन्होंने पिंकरटन भड़ैतों के उपयोग की निन्दा की और तालाबन्दी के कारण बाहर निकाले हुए मज़दूरों से सहानुभूति प्रकट की। कुछ रिपब्लिकन अखबारों ने तटकर का मामला उठाये जाने पर नाराज़ होकर डैमोक्रैटिक पार्टी के अभियोगों का खण्डन करने के लिए कारनेगी कम्पनी से अधिक नरम रुख अपनाने का अनुरोध किया। किन्तु सामान्यतः प्रेस ने यह रवैया अख्तियार किया कि यद्यपि होमस्टेड के कर्मचारी उनको दिए जाने वाले वेतनों पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो भी दूसरों को उस वेतन पर काम करने से रोकने का उन्हें कोई हक नहीं है। "इण्डिपेण्डेण्ट" ने कहा : "लोग जब यह कहते हैं कि होमस्टेड में मज़दूरों ने ठीक किया तो वे अराजकतावादियों या पागलों की तरह बात करते हैं" इस्पात कम्पनी जिस किसी को काम पर लगाना चाहे उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के उसके अधिकार को स्वीकार किया गया।

'क्लीवलैंड लीडर' ने लिखा : "अगर सभ्यता और सरकार नाम की कोई चीज़ है तो हर आदमी का यह अधिकार कि वह जिसके लिए चाहे काम करे, सुरक्षित रखा जाना चाहिए और रखा जाएगा। नार्थ अमेरिकन रिव्यू में एक लेख में जार्ज टिकनर कर्टिस ने इस बारे में और आगे कहा : "कानून बनाने के अधिकार का पहला कर्त्तव्य मज़दूर को अपनी जमात के अत्याचारों से मुक्त कराना है। व्यक्तिगत मज़दूर को अपनी आजादी अपने साथियों के नियन्त्रण में सौंप कर अपनी नैतिक आत्महत्या नहीं करने देनी चाहिए।" मज़दूर किन शर्तों पर व्यक्तिशः अपनी सेवाएँ बेच सकता है, इसका निर्णय करने के भ्रामक अधिकार की रक्षा के लिए सामूहिक सौदेबाजी के निमित्त मज़दूर के दूसरों के साथ मिलने का अधिकार मंजूर नहीं किया गया। कंजरवेटिव मालिकों के मज़दूर-विरोधी रवैये को इससे अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

इन अन्धकारपूर्ण दिनों में, जब नए उद्योगवाद की ताकतें मज़दूरों के

सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं के लिए भी अधिक शुल्क लिया जाता था।" "जहन्नुम में जाए", स्पष्टवादी मार्क हान्ना ने अपने साथी उद्योगपति के सामन्ती साम्राज्य के बारे में टीका करते हुए कहा : 'आदर्श—जाओ पुलमैन में जाकर रहो और देखो कि पुलमैन उन गरीब भूखों को पानी और गैस १० फी सदी ज़्यादा शुल्क पर बेच कर कितना कमाता है ?"

१८९३ में मन्दी आने पर पुलमैन भी संकट में पड़ गई और अपने ५,८०० कर्मचारियों में से ३००० की छटनी कर देने के बाद भी उसने बचे हुए कर्मचारियों के वेतनों में २५ से ४० प्रतिशत तक कटौती कर दी और कम्पनी के क्वार्टरों के किराए में तदनुरूप कमी नहीं की। परिणाम भयंकर हुए। कम्पनी द्वारा अपनी सेवाओं का खर्चा काट लेने के बाद एक कर्मचारी को मुश्किल से ही ६ डालर प्रति सप्ताह मिल पाते थे। एक मामले में तो ऐसा भी हुआ कि एक कर्मचारी का वेतन मकान का किराया काटे जाने के बाद सिर्फ २ सेण्ट बाकी रहा। पुलमैन मैथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के पादरी डब्लू० एच० कारवारडीन ने बताया कि "उसने यह रकम कभी ली ही नहीं।" एक तरफ जब ऐसी घटनाएँ घट रही थीं तब भी पुलमैन कम्पनी ने डिवीडेण्ड देना जारी रखा। कारोबार की हालत सुधरने पर भी, जब कि कम्पनी ने छँटनी किए हुए कर्मचारियों में से २००० को काम पर वापस ले लिया, वेतनों में कटौती को बहाल करने या किराये कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

अन्त में मई, १८९४ में कर्मचारियों की एक समिति ने अपनी शिकायतों पर कुछ विचार किए जाने की मांग की। पुलमैन ने वेतनों के हेरफेर के प्रश्न पर विचार करने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि कम्पनी को अब भी नुकसान हो रहा है और उसने किराये कम करने से भी इन्कार कर दिया। उसने बड़े हलकेपन से यह बात कही कि कार्य-नियोजक और जायदाद-मालिक के रूप में कम्पनी के दो रूपों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। इस आश्वासन के बावजूद कि शिकायत समिति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस मुलाकात के लगभग तुरन्त बाद ही इसके तीन सदस्यों को तुर-फुरत बर्खास्त कर दिया गया।

कठिनाई और कष्ट के इस वर्ष में पुलमैन के कर्मचारियों ने अमरीकी

रेलवे यूनियन की स्थानीय शाखाओं में अपना व्यापक संगठन किया। अन्य सब मजदूर-संघों से स्वतन्त्र इस नए ऐसोसियेशन की स्थापना यूजीन वी० डेब्स ने एक वर्ष पहले ही एक औद्योगिक यूनियन के रूप में की गई थी, जिसमें रेलों के सब गोरे कर्मचारी शामिल हो सकते थे। शिकायत समिति के तीन सदस्यों की, जो अमेरिकन रेलवे यूनियन के भी सदस्य थे, बर्खास्तगी पर पुलमैन के स्थानीय संगठनों ने हड़ताल के लिए आह्वान किया। जब कम्पनी ने सब कर्मचारियों को काम से हटाकर और कम्पनी को बन्द करके हड़ताल का जवाब दिया तो राष्ट्रीय सम्मेलन से सहायता के लिए अपील की गई। विवादग्रस्त मामलों को पंच-फैसले के सुपुर्द करने की कोशिश की गई। किन्तु समझौते की इन चेष्टाओं का जब पुलमैन ने यह कह कर कि "पंच-फैसले के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है", टका-सा जवाब दे दिया तो अमरीकी रेलवे यूनियन ने सीधी कार्रवाई की तैयारी की। २१ जून को एक प्रस्ताव स्वीकार कर उसने कहा कि अगर पंच-फैसले की बात ५ दिन के अन्दर-अन्दर स्वीकार नहीं की गई तो उसके सदस्यों से कह दिया जाएगा कि वे पुलमैन की किसी कार को हाथ न लगाएं।

कर लिया है। हम इस टेक पर कायम हैं कि मज़दूरों को अपने श्रम के फल का एक उचित हिस्सा प्राप्त करने का हक है......" किन्तु कुछ क्षेत्रों में जहां हड़तालियों से सहानुभूति प्रकट की गई, मार्क हान्ना ने पुनः पुलमैन द्वारा पंच-फैसले को अस्वीकार किए जाने पर निजी रूप से अपनी नापसन्दगी जाहिर की, वहाँ कंजरवेटिव प्रेस ने दृढ़ता से जनरल मैनेजर्स ऐसोसियेशन का समर्थन किया। शिकागो हैरल्ड ने कहा : "आवश्यकता इस बात की है कि हड़तालियों को हराया जाए और न्यूयार्क वर्ल्ड ने लिखा : "यह सरकार और समाज के विरुद्ध एक संग्राम है"।

रेल कर्मचारियों के विद्रोह का नेतृत्व करने के कारण डेब्स रातों-रात राष्ट्र-भर में विख्यात हो गया। अमरीकी रेलवे यूनियन को बने सिर्फ एक ही वर्ष हुआ था तो भी उसके चतुर और योग्य नेतृत्व में उसके कोई १।। लाख सदस्य बन चुके थे, जिन की संख्या चारों रेलवे ब्रदरहुडों से अधिक थी और जो क्षीण होते जाने वाले नाइट्स आव लेबर और शनैः शनैः उदीयमान अमरीकी मज़दूर संघ, दोनों का प्रतिद्वन्द्वी था। प्रबन्धक और यूनियनें दोनों ही इस बात से डरते थे कि अगर इसने हड़ताल में सफलता प्राप्त कर ली तो औद्योगिक यूनियनवाद का सिद्धान्त जीत जाएगा और भविष्य में फिर ऐसी ही यूनियनें बना करेंगी।

डेब्स फ्रांसीसी अल्सेशियन आव्रजकों की, जो टेरे हौटे (इण्डियाना) में आकर बस गए थे, सन्तान था। उसके पिता यहां परचून की दूकान करते थे। १८५५ में जन्म लेकर १४ वर्ष की आयु में वह एक रेलवे यार्ड में काम करने चला गया और १६ वर्ष की आयु में एक इंजीनियर बन गया। कुछ अरसे तक वह यार्ड का काम छोड़कर एक परचूनिया क्लर्क बन गया और राजनीतिक गोटें चलाना सीखने लगा किन्तु १८७८ में वह मज़दूर आन्दोलन में लौट आया और दो वर्ष बाद २५ वर्ष की आयु में ब्रदरहुड आव लोकोमोटिव फायरमैन का राष्ट्रीय खंजाची-सचिव और लोकोमोटिव फायरमैन्स मैगजीन का सम्पादक चुना गया। यह ज्यादातर उसके प्रयत्नों का ही परिणाम था कि अगले १२ वर्षों में यह यूनियन एक फलता फूलता और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ संगठन बन गया।

किन्तु डेब्स को इस बात की अधिकाधिक चिन्ता रहने लगी कि ब्रदरहुड

किसी से मेल ही नहीं रखना चाहता और इसके सदस्यों और अन्य रेल कर्मचारियों में सहयोग का नितान्त अभाव है। उसका यह विश्वास था कि राष्ट्रीय रेलों पर सब कर्मचारियों का एक ही संगठन बनाकर ही मज़दूरों के इस महत्वपूर्ण वर्ग के हितों को सफलतापूर्वक बढ़ाया जा सकता है। १८९२ में उसने ब्रदरहुड आव लोकोमोटिव फायरमेन में अच्छे खासे वेतन वाला अपना पद छोड़ दिया और अकेले ही अमरीकी रेलवे यूनियन बनाने का बीड़ा उठाया।

डेब्स एक चतुर और व्यावहारिक संगठनकर्ता था। वह बड़ा ज़ोरदार और प्रभावशाली वक्ता था और जिस बात में विश्वास रखता था उसमें सर्वस्व होम देने के लिए तत्पर रहने वाला आदर्शवादी था। जीवन भर उसे आश्चर्य-जनक सम्मान और वफ़ादारी प्राप्त रही। पुलमैन की हड़ताल के दौरान उसके बारे में इतनी बुरी-बुरी और कड़वी बातें कही गईं, जितनी शायद ही किसी को कही गयी हों। उसे मजदूर तानाशाह, मुजरिम, अराजकतावादी, पागल और प्रलापी कहा गया किन्तु कुछ समय बाद उसके विचारों की निन्दा करने वाले भी उसका सम्मान करने लगे। १८९० की दशाब्दि में एक उग्र मजदूर नेता के रूप में या बाद में अमरीकी समाजवाद के एक प्रवक्ता के रूप में उसकी अविचल और ईमानदारी से इंकार नहीं किया जा सकता। हमारे राष्ट्रीय जीवन में अन्य संघर्षकारी अवाम के साथ अन्य कोई व्यक्ति इतना घुलमिल कर नहीं रहा और न ही कोई शोषितों का उससे ज्यादा दृढ़ संरक्षक रहा।

डेब्स ने एक बार अपने बहुधा उद्धृत वक्तव्य में कहा: "जब तक कोई निचली श्रेणी है तब तक मेरा स्थान उसी में है। जब तक कोई मुजरिम तत्व मौजूद है, तब तक मैं भी उसका एक हिस्सा हूं और जब तक कोई भी आत्मा जेल में बन्द है तब तक मैं आजाद नहीं हूं।"

डेब्स लम्बा और दुबला था, पुलमैन हड़ताल के समय ३९ वर्ष की आयु में भी करीब-करीब गंजा हो गया था; ऊँचे माथे और निष्कपट आंखों वाले डेब्स के तौर-तरीके शान्त और सरल थे। उसमें कोई ऐसी चीज थी जो न केवल विश्वास उत्पन्न करती थी बल्कि प्रेम पैदा करती थी। क्लेरेंस डैरो ने लिखा: "शायद किसी समय कहीं, डेब्स से ज्यादा दयालु, भद्र और उदार

आदमी रहा हो, किन्तु मुझे उसका पता नहीं।"

डेब्स उस हड़ताल के पक्ष में नहीं था जो पुलमैन के कर्मचारियों की अपील पर अमरीकी रेलवे यूनियन पर लाद दी गई थी। यद्यपि इस यूनियन ने ग्रेट नार्दर्न रेलवे पर एक हड़ताल में आश्चर्यजनक विजय प्राप्त की थी तो भी वह जानता था कि उसका युवासंगठन अभी इतना ताकतवर नहीं है कि वह संयुक्त रेलवे कार्पोरेशनों से इतनी बड़ी टक्कर ले सके। किन्तु जब पुलमैन ने पंच-फैसले की बात मानने से इन्कार कर दिया तब उसने महसूस किया कि अगर यूनियन हड़ताल से अलग रही तो यह पुलमैन के कर्मचारियों को धोखा देना होगा। उनका समर्थन करने के लिए बाध्य होकर भी डेब्स ने नरमी और संयम की सलाह दी। उसने रेल कर्मचारियों को हिदायत की कि वे सर्वथा शान्त रहें, रेलवे की सम्पति को कोई नुकसान न पहुँचाएं और हड़ताल के पहले दौर में उसके इन आदेशों का सख्ती से पालन किया गया।

किन्तु जनरल मैनेजर्स ऐसोसियेशन शांत हड़ताल को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने शीघ्र ही कनाडा से हड़ताल भंजकों को बुलाना शुरू कर दिया और उन्हें गुप्त रूप से हिदायत की कि वे डाकगाड़ियों को पुलमैन की गाड़ियों में जोड़दें जिससे कि हड़ताली जब उनमें से पुलमैन की गाड़ियां काटेंगे तो उन पर डाक में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया जा सके।

हिंसा के जिस खतरे की अभी आशंका भी नहीं थी उसके आधार पर उसने रेल कम्पनियों के पक्के दोस्त अटार्नीजनरल ओलनी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह ३,४०० आदमियों को, जिन्हें वस्तुतः रेल कम्पनियों ने भर्ती किया था और वही उनको भुगतान कर रही थीं ट्रेनों को चलाने में सहायता देने के लिए विशेष सहायक (डिपुटी) के रूप में काम पर रख लिया जाए। ये तरकीबें सफल हो गईं। हड़तालियों तथा डिपुटियों में जगह-जगह संघर्ष हो गया, दंगे फूट पड़े और रेलवे की सम्पति को नुकसान पहुँचा। मैनेजर्स ऐसोसियेशन ने तुरन्त यह फतवा देकर कि इस प्रकार की हिंसा बेकाबू हो गई है राष्ट्रपति क्लीवलैण्ड से अपील की कि वे शांति और व्यवस्था फिर से स्थापित करने के लिये संघीय सेनाएं भेजें, डाक और अन्तर्राज्यीय वाणिज्य की हिफाजत करें। १५वीं पदाति सेना की ४ कम्पनियां शिकागो भेजी गईं।

गवर्नर आल्टगेल्ड ने तुरन्त ही इस कदम का विरोध किया। उन्होंने

राष्ट्रपति को तार दिया कि स्थिति अभी वेकाबू नहीं हुई है स्थानीय अधिकारी उसे संभालने में पुर्णतः समर्थ हैं। उन्होंने कहा : "संघ सरकार से अपील उन लोगों ने की है जिनका राज्य सरकार की उपेक्षा करने में राजनीतिक स्वार्थ है। फिलहाल हमारी कुछ रेलें पंगु हो गई हैं, इसलिए नहीं कि कुछ लोग बाधा डाल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि रेलों को अपने कार्यसंचालन के लिए आदमी नहीं मिल रहे......इलिनौयस राज्य के गवर्नर के रूप में आपसे अनुरोध करता हूँ कि संघीय सेनाएँ इस राज्य में सक्रिय सेवा से तुरन्त वापस बुला ली जाएँ।" किन्तु आल्टगेल्ड के विरोध की कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने हाल में ही हेमार्केट स्क्वेयर के दंगे के अराजकतावादी मुजरिमों की सजा माफ़ कर दी थी और अखबारों ने उन्हें "अव्यवस्था का मित्र और चैम्पियन" बनाकर उनपर कड़े आक्षेप किए थे। क्लीवलैण्ड ने यद्यपि इससे पूर्व कांग्रेस को दिए अपने एक संदेश में वेतन सम्बन्धी झगड़ों की जाँच पड़ताल और पंच-फैसले की अपील की थी किन्तु इस मौके पर उनकी दृष्टि व्यवस्था फिर से कायम करने की आवश्यकता से आगे नहीं गई। जो टेक उन्होंने अपना ली थी उसकी उन्होंने दृढ़ता से वकालत की और राज्य सरकार के अधिकार हड़पने के आरोपों के बावजुद इस आधार पर संघीय सेनाओं के प्रयोग को उचित ठहराया कि डाक गाड़ियाँ चालू रखने की उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है।

बताया जाता है कि उन्होंने कहा : "शिकागो में चिट्ठी यथा स्थान पहुँचाने के लिए अगर मुझे खजाने के एक-एक डालर और अमरीका के एक एक सैनिक का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है तो भी वह चिट्ठी जरूर पहुँचाई जाएगी।"

तो भी हड़ताल भंजकों, विशेष डिपुटियों और सेना के बावजूद हड़तालो डटे रहे और शिकागो में रेलों का तीन-चौथाई काम ठप्प हो गया। इतना ही नहीं, हड़ताल और भी फैल रही थी। पूर्व और सुदूर पश्चिम, दोनों जगह बहुत सी लाइनों पर इंजन चालकों, फायरमैनों, मरम्मत करने वालों, सिगनल देने वालों, यार्डमास्टरों तथा अन्य कर्मचारियों ने सहानुभूति में हड़ताल कर दी। साथ ही हिंसात्मक कार्य भी बढ़ रहे थे। जब संघर्ष तेज हो गया तो डेब्स अपनी शांतिपूर्ण अपीलों से हड़तालियों को ज्यादा देर तक

संयम की डोर में बांधे नहीं रख सका। सेनाओं के संरक्षण में जब ट्रेनें चलने लगीं तो क्रुद्ध भीड़ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आवारा और गुण्डे शीघ्र ही स्थिति का फायदा उठासे लगे, जैसा कि उन्होंने १८७७ की रेलवे हड़ताल में किया था। रेलवे स्टोर लूट लिए गए, माल तथा सवारी के डिब्बे जला दिए गए और अन्य सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया।

जैसे-जैसे अव्यवस्था फैलने लगी, पत्र-पत्रिकाओं ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि समाज खतरे में है। न्यूयार्क ट्रिब्यून ने कहा : "यह हड़ताल पूंजी तथा श्रम के बीच अमरीका में अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है।" सबने एक स्वर से मांग की कि अन्य किसी चीज की परवाह किए बिना "इस विद्रोह को कुचल दिया जाए।" रेल कर्मचारियों तथा हड़ताल के लिए उकसाने वालों के बीच फर्क करने की कोशिश की गई। कर्मचारियों को "स्वार्थी, क्रूर और गुस्ताख नेताओं का शिकार" बताया गया और सब ईमानदार श्रमिकों से स्वयं को ऐसे "असह्य अत्याचार" से मुक्त करने की अपील की गई। न्यूयार्क टाइम्स ने डेब्स को खुला छूटा हुआ कानून भंजक, मानव जाति का शत्रु" बताया मौर शिकागो हैरल्ड ने कहा : "इस लापरवाह, शोर मचाने वाले दुराग्रही, निर्लज्ज शेखीखोर से छुटकारा दिलाया जाना चाहिए......"

भीड़ की हरकतों तथा पुलिस व सेना के साथ उसकी भिड़न्त के बारे में अखबारों में भयावह समाचार छपने लगे। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी सुर्खियों में चीख-पुकार मचाई "शिकागो दाहक की टार्च की दया पर है।" लोगों के दिल पर ऐसी छाप अंकित करने की कोशिश की गई मानों सारा शिकागो क्रांति और अराजकता का शिकार हो गया है। किन्तु न्यूयार्क हैरल्ड के एक संवाद-दाता ने इस अतिशयोक्ति पूर्ण डरावने वातावरण में भी अपना संतुलन कायम रखते हुए ९ जुलाई को अपने पत्र में रिपोर्ट दी कि कारोबार सामान्य गति से जारी है, दूकानों में खरीदारों की भीड़ रहती है और "शहर के मुख्य भाग में भी भीड़, दंगे या हड़ताल का कोई चिह्न नहीं है।"

किन्तु रेल कम्पनियां तुर्प का पत्ता पहले ही खेल चुकी थीं। उन्होंने अटार्नी जनरल ओलनी को सीधे हस्तक्षेप करने के लिए मना लिया था और २ जुलाई को संघीय जिला अदालत के न्यायाधीश पीटर जे० ग्रौसकप से

एक निषेधादेश प्राप्त कर लिया गया, जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति अन्तर्राज्यीय व्यापार में डाक तथा अन्य रेल सामग्री के परिवहन में बाधा न डाले और रेल कर्मचारियों को अपना सामान्य कामकाज करने से मना न करे। जब सरकार और अदालतों की सारी शक्ति उसके खिलाफ लाकर खड़ी कर दी गई तो डेब्स हताश हो गया। कुछ अरसे तक तो उसे आम हड़ताल के लिए मज़दूरों से समर्थन प्राप्त होने की आशा रही किन्तु अमरीकी मज़दूर संघ ने उसे साफ अंगूठा दिखा दिया। गौम्पर्स ने इस मामले पर मज़दूरों का एक सम्मेलन बुलाने की तो मजबूरी महसूस की किन्तु वह हड़ताल के एकदम विरुद्ध था। वस्तुतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जो संगठन औद्योगिक यूनियनवाद के विरोध में कायम हुआ वह अमरीकी रेलवे यूनियन को अपना सहयोग देने में आनाकानी कर दहा था।

१३ जुलाई को गौम्पर्स ने एक वक्तव्य जारी करके कहा कि "सम्मेलन की यह राय है कि इस समय आम हड़ताल करना अयुक्तियुक्त, अबुद्धिमत्ता पूर्ण और मज़दूरों के हितों के विरुद्ध होगा। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि अमरीकी मज़दूर संघ के जिन सदस्यों ने सहानुभूति में हड़ताल कर रखी है वे काम पर लौट जाएं और जो सहानुभूति में हड़ताल करने का इदादा कर रहे हैं उनको सलाह दी जाती है कि वे काम करते रहें।"

जब किसी तरफ से सहायता नहीं मिली तब डेब्स ने इस शर्त पर हड़ताल और बहिष्कार को वापस लेने का प्रस्ताव रखा कि कम्पनी बिना किसी भेद-भाव के सब कर्मचारियों को काम पर वापस ले ले। अदालतों का दण्डचक्र घूमते हुए रेलों को क्या चिन्ता थी। उन्होंने डेब्स के शाँति प्रस्तावों को साफ ठुकरा दिया: "अराजकतावाद को अब और प्रश्रय नहीं दिया जाएगा।"

न्यायाधीश ग्रासकप ने अब इन अभियोगों की सुनवाई करने के लिए जूरी बैठाई कि डाक में बाधा डालकर हड़ताली नेताओं ने षड़यन्त्र रचने का अपराध किया है और अदालत की हिदायत पर डेब्स तथा इसके तीन साथियों पर तुरन्त अभियोग लगा दिए गए। उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, जमानत पर रिहा कर दिया गया और एक सप्ताह बाद पहले निषेधादेश का पालन न करने का अभियोग लगाते हुए अदालत की मानहानि करने के जुर्म में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें जेल भेज दिया गया। अन्य

निषेधादेश अलग-अलग कर्मचारियों के खिलाफ लागू किए गए और संघीय अभियोगों पर करीब २०० को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके अतिरिक्त कई सौ को स्थानीय पुलिस ने जेलों में डाल दिया। नेतृत्व तथा दिग्दर्शन से वंचित, सर्वथा हताश रेल कर्मचारियों ने व्यर्थ से प्रतीत होने वाले संघर्ष को तिलांजलि दे दी और शनैः शनैः काम पर वापस आगए। २० जुलाई को सेनाएं हटा ली गईं। निषेधादेश के जरिए सरकार ने पुलमैन की हड़ताल को बिल्कुल कुचल कर पहली विजय प्राप्त की।

कुछ अरसे बाद डेब्स के खिलाफ़ अदालत की मानहानि के आरोप सरकिट कोर्ट में इस आधार पर पुष्ट किए गए कि हाल में बने शर्मन ट्रस्ट विरोधी अधिनियम के मातहत हड़ताल के नेताओं ने अन्तर्राज्यीय व्यापार में बाधा डालने के लिए षड़यन्त्र रचा। अगली वसन्त ऋतु में उच्चतम न्याया-लय ने शर्मन अधिनियम की सार्थकता पर कोई राय प्रकट किए बिना निचली अदालत के फैसले को कायम रखा। यह कहा गया कि संघ सरकार को अन्तर्राज्यीय व्यापार या डाक के परिवहन में किसी भी बाधा को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है।

डेब्स को ६ महीने के लिए वुडस्टाक, इलिनौयस की जेल भेज दिया। अदालतों की कार्रवाई ने उसे शहीद बना दिया था और अपनी सजा की समाप्ति के बाद जब वह शिकागो लौटा तो १ लाख से अधिक प्रशंसकों की भीड़ ने उसका तुमुल स्वागत किया। एक विशाल सभा में, हेनरी डेमारेस्ट लायड ने उसे आज के महत्वपूर्ण लोगों में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति और अदालती लिंच कानूनों का शिकार" बताकर उसका स्वागत किया, जेल में रहते हुए डेब्स का यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि पूंजीवाद में मज़दूरों का हित-साधन असम्भव है। वह समाजवादी हो गया और तब से उसने अपना सारा जीवन उस प्रणाली के खिलाफ़ संघर्ष करने में लगा दिया जिसकी बदौलत मालिक अपने आदेश का पालन कराने के लिये सरकार का आह्वान कर सकते हैं। यह आदेश है—"हम आपको जो कुछ देना चाहते हैं, उसी पर काम कीजिए, वरना भूखों मरिये।" १९२६ में अपनी मृत्यु तक वह समाज-वादी झण्डे के नीचे मज़दूरों के अधिकारों के लिए निरन्तर संघर्ष करता रहा और अपने दल की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए ५ बार उम्मीदवार

खड़ा हुआ ।

मज़दूरों तथा उनसे सहानुभूति रखने वालों ने पुलमैन हड़ताल में संघीय
सेनाओं के हस्तक्षेप तथा निषेधादेशों के प्रयोग की तीव्र निन्दा की किन्तु
अन्य क्षेत्रों में सरकार की नीति का जोरदार समर्थन किया गया । सेनेट और
प्रतिनिधि सभा दोनों ने राष्ट्रपति क्लीवलैण्ड की कार्रवाई के समर्थन में
प्रस्ताव पास किए । सार्वजनिक नेताओं ने अपने असंख्य वक्तव्यों में स्थिति को
सम्हालने में दिखाई गई चतुरता के लिए राष्ट्रपति की सराहना की और
कंजरवेटिव प्रेस ने "डेब्स के विद्रोह" को तत्परता से दबा देने के लिए उन्हें
राष्ट्रवीर कहा । सरकार की सत्ता का सिक्का असंदिग्ध रूप से जमा दिया
गया था इतिहासज्ञ जेम्स फोर्ड र्होड्स ने लिखा : "न्यायपूर्ण निर्णयों के लिए
प्रसिद्ध इस देश में एक बेशकीमती परिपाटी के लिए हम 'क्लीवलैण्ड और
ओलनी के ऋणी हैं ।"

शायद पुलमैन की हड़ताल का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि
मज़दूरों की मांग का मुकाबला करने में अदालत के निषेधादेश से उद्योग के
हाथ में आई हुई ताकत का पता चला । मजदूरों के मालिक जब इतनी
आसानी से अदालतों में जाकर हड़तालों और बहिष्कारों के खिलाफ निषेधा-
देश प्राप्त कर सकते थे और जब सरकार विवाद ग्रस्त मामलों में ठीक और
गलत का ख्याल किए बिना अपनी सब ताकत मज़दूरों के खिलाफ झोंक देने
को तैयार थी तो बेचारे मज़दूरों के लिए क्या गुंजायश हो सकती थी । उनके
हाथ बिल्कुल बंधे हुए प्रतीत हुए । निषेधादेश के जरिये हकूमत करने के
खिलाफ तुरन्त एक आन्दोलन चल पड़ा और यद्यपि अमरीकी मज़दूर संघ ने
अमरीकी रेलवे यूनियन की हड़ताल में कोई सहयोग नहीं किया था तो भी
इस आन्दोलन को उसने उसी दिन से मज़दूरों के लिए एक मुख्य चिन्ता का
विषय स्वीकार किया । १८९० की दशाब्दि की भांति सन् १९४० की दशाब्दि
तक भी यह एक मुख्य विषय बना रहा ।

होमस्टैड और पुलमैन की हड़तालों को जबर्दस्ती कुचल दिए जाने से
मज़दूरों में असन्तोष बढ़ने लगा परन्तु उससे भी ज्यादा निराशा बेकारी ने
उत्पन्न की । देश भर में "औद्योगिक फौजें" राहत की मांग करने के लिए

वाशिंगटन को जाने वाली सड़कों पर कूच करने लगीं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कौक्सी की फौज थी जो वस्तुतः राजधानी पहुंची और ह्वाइट हाउस के लॉन में अनधिकृत प्रवेश पर उसके नेता की गिरफ्तारी के बाद उसे तितर-बितर कर दिया गया। किन्तु चिथड़े पहने गरीब मजदूरों के और भी ग्रुप कूच कर रहे थे। समस्त देश में भीड़ की कार्रवाई के निरन्तर मौजूद खतरे का सामना करने के लिए अधिकारियों को इन प्रदर्शनों को भंग करने की हिदायत दी गई।

इस बीच राष्ट्र के किसानों में भी असन्तोष बढ़ रहा था और विद्रोह की चिनगारी फैल रही थी। कीमतें गिरते जाने से; जिसके कारण उनके द्वारा पैदा किए गए माल की आधी कीमत रह गई थी, ने भी परेशान थे। पौपुलिज़्म खेतों में छा गया और जहां यह क्षोभ मध्य-पश्चिम और दक्षिण के किसानों तक ही सीमित रहा वहां पूर्व के मज़दूर जो यह महसूस करते थे कि सरकार के हाथ सब जगह उनका गला दबोचने को तत्पर हैं, इससे आकर्षित हुए बिना न रह सके। पौपुलिज़्म संगठित सम्पदा द्वारा शासन की समस्त प्रणाली को ही चुनौती देता था। बहुत कुछ जैक्सनी लोकतंत्र की तरह इसने जन सामान्य को वह राजनीतिक सत्ता फिर से प्राप्त कराने की कोशिश की, जिसके बारे में समझा जाता था कि उसे व्यापारी वर्ग ने हथिया लिया है।

पौपुलिस्ट पार्टी ने, जिसका १८९२ में बाकायदा संगठन किया गया, इस विचार को अपना मूल आधार बना लिया कि सम्पत्ति उनकी है जो उसे पैदा करते हैं, और राष्ट्र के श्रमजीवी वर्ग से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपील की। औद्योगिक श्रमकों को इस सिद्धान्त का अनुगामी बनाने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया। चाँदी के स्वच्छन्द और असीमित सिक्के ढालने की माँग जहाँ किसानों के असन्तोष की परिचायक थी वहाँ अन्य माँगें सर्वथा औद्योगिक थीं।

पौपुलिस्ट मंच से कहा गया : "शहरी मज़दूरों को आत्मरक्षा के लिए संगठित होने का अधिकार नहीं प्रदान किया जाता, बाहर से लाए गए गरीब मज़दूर उनकी मज़दूरी में कटौती कराने का कारण बनते हैं, उन्हें गोली का शिकार बनाने के लिए किराये की टट्टू एक स्थायी सेना रखी जाती है जिसकी कानून इजाजत नहीं देता और तेजी से यूरोप की सी बुरी हालत होती जा रही है।" इस स्थिति का सामना करने के लिये पौपुलिस्टों ने मुद्रा व अन्य प्रकार के

सुधारों के अपने कार्यक्रम में राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन, नाइट्स आव लेबर तथा अमरीकी मज़दूर संघ की परम्परागत माँगों को भी शामिल कर लिया। उन्होंने आव्रजन पर अंकुश लगाने, सरकारी परियोजनाओं पर ठेका विरोधी मज़दूर कानून पर अमल किए जाने तथा ८ घण्टे के दिन की, श्रमिक विवादों में अदालती निषेधादेशों का प्रयोग बन्द करने और "पिंकरटन प्रणाली के रूप में विख्यात भाड़े के टट्टुओं की सेना" को गैर कानूनी करार दिए जाने की माँग की।

नाइट्स आव लेबर अपनी क्षीण हुई शक्ति को पौपुलिस्ट के समर्थन में झौंक देने को तैयार थे। १८९२ के एक सम्मेलन में उसके ८२ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मज़दूरों के जो ग्रुप एक ही कर लिए जाने के हेनरी जार्ज के आन्दोलन का और समाजवादी सुधारों के उद्देश्य वाली राष्ट्रीय क्लबें स्थापित करने के ऐडवर्ड बेलामी के आन्दोलन का समर्थन करते थे, वे वाकायदा पीपल्स पार्टी से सम्बद्ध हो गए। यूजीन वी० डेब्स ने, जो पुलमैन की हड़ताल की विफलता पर अब भी अफसोस किया करता था, समाजवादी बन जाने से तरोताजा होकर तहे-दिल से उस कार्यक्रम का समर्थन किया जिसके बारे में उसका विश्वास था कि वह आम लोगों को पैसे की ताकत के खिलाफ़ एक-जूट होने का आधार प्रदान करता है। सिर्फ़ अमरीकी मज़दूर संघ ही सेम्यु-अल गौम्पर्स के प्रभाव को पुनः प्रकट करता हुआ उससे अलग रहा।

संघ के अन्दर जो समाजवादी तत्त्व थे, उनके द्वारा एक प्लेटफार्म पर, जिसमें यह मांग की गई कि उत्पादन और वितरण के सब साधनों पर सब लोगों का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, संघ को तीसरे मज़दूर दल की स्थापना के पक्ष में करने का प्रयत्न कुछ ही समय पहले ठुकरा दिया गया था। गौम्पर्स जीता किन्तु इस प्रयत्न में १८९४ में अध्यक्ष पद के चुनाव में हार गया। यूनाइटेड माइन वर्क्स का जॉन मैकब्राइड इस पद पर चुना गया और संघ का हैडक्वार्टर इंडियानापोलिस ले जाया गया। किन्तु गौम्पर्स का सितारा कुछ ही देर तक डूबा रहा। अगले सम्मेलन में न केवल उसे पुनः अध्यक्ष वना दिया गया, अपितु समाजवाद के खिलाफ़ जो टेक उसने ली थी उसका दढ़ता से समर्थन किया गया। अमरीकी मज़दूर संघ से जब पौपुलिज़्म को सहयोग देने की माँग की गई तो इसके पुनर्निर्वाचित अध्यक्ष ने संघ को राजनीति में

सीधा भाग न लेने देने का और भी दृढ़ निश्चय कर लिया। अमरीकी मज़दूर संघ स्वच्छन्द चाँदी की पार्टी का समर्थन करने को तैयार नहीं था। गौम्पर्स ने मजदूरों के लिए अपनी सब शक्तियाँ यूनियनवाद की समस्याओं पर केन्द्रित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा : "मध्यम वर्ग के मामले उनका ध्यान उनके अपने मामलों से हटाते हैं।"

१८९६ में जब डैमोक्रैटों ने न केवल रिपब्लिकनों को बल्कि अपनी पार्टी में मौजूद कंजरवेटिव तत्वों को चुनौती देते हुए पौपुलिस्टों का कार्यक्रम अपने हाथ में ले लिया तब भी औद्योगिक श्रमिकों में उन्हें काफी समर्थन प्राप्त रहा। दोनों पार्टियाँ मज़दूरों के वोट के महत्व को समझती थीं। विलियम जेनिंग्स ब्रायन ने तो एक भाषण में यहाँ तक कहा कि अगर वह राष्ट्रपति चुना गया तो वह गौम्पर्स को अपने मन्त्रिमण्डल का एक सदस्य बना लेगा। किन्तु उनके इस प्रस्ताव का ए० एफ० एल० के अध्यक्ष पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। रिपब्लिकन हाईकमाण्ड ने, जबकि मार्क हान्ना पार्श्व से विलियम मैकिनली के आन्दोलन का संचालन कर रहे थे, एक दूसरा मार्ग अपनाया। मज़दूरों के वेतनों के लिफ़ाफ़ों में नोटिस रखकर चेतावनी दी गई कि डैमोक्रैटिक पार्टी की जीत का मतलब होगा और ज़्यादा कारखानों का बन्द होना तथा और ज़्यादा बेकारी। इस प्रकार की खतरनाक भविष्यवाणियाँ कर कि "यदि ब्रायन, आल्टगेल्ड और डेब्स के नेतृत्व में समाजवादी और क्रान्तिकारी ताकतें जीत गईं तो महान् आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा", मज़दूरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई।

अन्ततः पूंजीवाद की संगठित ताकतों ने, जिसका प्रतिनिधित्व रिपब्लिकन पार्टी कर रही थी, डैमोक्रैटिक झण्डों के नीचे आन्दोलन करने वाले किसानों और मज़दूरों के प्रहार को पीछे धकेल दिया। मैकिनली चुन लिया गया। यह गठबंधन इतना शक्तिशाली या एकजूट नहीं था कि एक ऐसी किसान-मज़दूर पार्टी कायम की जा सकती जो आर्थिक और सामाजिक सुधारों के कार्यक्रम को सफल बना देती। सेम्युअल गौम्पर्स ने अपने संगठन को राजनीति से बाहर रखा और इस प्रकार संभवतः उसे पहले के मज़दूर संगठनों की भांति दलबन्दी की चट्टान पर टकराकर टूट-फूट जाने से बचा लिया। किन्तु १७९६ के [illegible]नावों में उस सामाजिक व्यवस्था के रक्षक कंजरवेटिवों की जीत हुई जो

हड़तालों को तोड़ने, पिंकरटन जासूसों के उपयोग और निषेधादेश द्वारा शासन चलाने के हामी थे।

जब १८९६ के आन्दोलन की हलचल शान्त हुई तो मजदूरों ने अपनी स्थिति का सिंहावलोकन कर उसे निराशाजनक पाया। मंदी से पहले वेतनों में जो लाभ प्राप्त किए गए थे, वे सब के सब खत्म हो गये। निर्माण उद्योग के कर्मचारियों की औसत वार्षिक आय ४०६ डालर से अधिक नहीं थी। अत्यन्त दक्षतापेक्षी धन्धों को छोड़ बाकी में काम का समय ८ घण्टे से कही ज्यादा था, जब कि इसके लिए मजदूर इतने अरसे से संघर्ष करते चले आ रहे थे। काम का समय सामन्यता ५४ से ६३ घण्टे प्रति सप्ताह था। इस्पात कारखनों, कपड़ा मिलों और पोशाक की फैक्ट्रियों में काम के घण्टे इससे भी ज्यादा थे जहां स्त्रियां और बच्चे बहुत थोड़े से पैसों के लिए इतनी देर तक काम करते थे कि काम का समय समाप्त होता दिखाई नहीं देता था। औद्योगिक श्रमिकों के लिए कहीं भी आर्थिक सुरक्षा नहीं थी।

यद्यपि मजदूरों के सम्बन्ध में कानून बनने शुरू हो गए थे तथापि १८६० की दशाब्दि के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय मजदूर यूनियन ने पहले पहल जो लक्ष्य रखे थे उनकी पूर्ति में भी वस्तुतः कोई प्रगति नहीं हुई। संघ सरकार ने श्रम सम्बन्धी आंकड़ों के लिए एक ब्यूरो स्थापित कर दिया था और ३२ राज्यों ने भी ऐसे ही ब्यूरो कायम किए थे, एक विदेशी ठेका मजदूर कानून बनाया जा चुका था, चीनियों को बाहर रखने के अधिनियम भी बन चुके थे और १८९८ में राष्ट्रपति मैकिनली ने एक औद्योगिक कमीशन स्थापित करने की भी सिफारिश की। औद्योगिक गतिविधियों के कुछ पहलुओं को नियमित करने के लिए राज्य सरकारों ने भी कानून बना दिए थे और खानों व फैक्ट्रियों में मजदूरों की हालत सुधारने की आशा की जा रही थी। किन्तु इन मामूली लाभों के मुकाबले यूनियनों की ताकत सामान्यतः कमजोर हो गई थी। वस्तुतः व्यापार में अड़चन डालने के लिए संगठन बनाने पर प्रतिबन्ध के शर्मन अधिनियम को यूनियनों पर लागू करके और हड़तालों तथा बहिष्कारों को कुचलने में निरोधा देशों का इस्तेमाल करके पुराने षड्यंत्र कानूनों को फिर से सजीव कर दिया गया था।

इतना ही नहीं, संगठित श्रमिकों की संख्या १८८० के दशक के चरम शिखर से नीचे आ गई थी। लगभग १० लाख से घटकर ३॥ लाख के करीब रह गई थी। यद्यपि गोम्पर्स १८९३ में गर्व पूर्वक यह कह सका कि राष्ट्रीय यूनियनें पहली बार मंदी के आघातों को सह सकी हैं, तो भी १८९७ में अमरीकी मज़दूर संघ के सिर्फ २,५०,००० सदस्य थे और रेलवे ब्रदरहुडों तथा अन्य असम्बद्ध यूनियनों में १ लाख सदस्य और थे। शुरू के वर्षों की अपेक्षा यह ज्यादा गठा हुआ और अधिक प्रभावशाली केन्द्र विन्दु था किन्तु यूनियन की कुल ताकत उससे कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, जितनी मज़दूर १८३० के दशक में या १८६० की दशाब्दि के अंतिम वर्षों में दावा करते थे।

अदक्ष औद्योगिक मज़दूरों की विशाल संख्या असंगठित ही रही। उनके मालिक चूंकि आव्रजकों की आजस्र धारा में से कितनों को ही उनके स्थान पर लगा सकते थे और सरकार तथा अदालतों से उन्हें हड़तालों को तोड़ने में पूरा सहयोग मिलता था इसलिए काम के लम्बे घण्टों, कम वेतन, और मनमानी बर्खास्तगियों से बचाव का उनके पास कोई उपाय नहीं था। होमस्टेड और पुलमैन दोनों हड़तालों में कड़ी हार ने यह कटु पाठ पढ़ा दिया था कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए औद्योगिक श्रमिकों के संगठित होने के प्रयत्नों को कुचल डालने के लिए कितनी ज्यादा ताकत जुटाई जा सकती है। मज़दूरों को सामान्यत: यही आशासूत्र दिखाई देता था कि ए. एफ. एल. की छत्र-छाया में एकत्र लाई गई पुराने ढंग की ट्रेड यूनियनों को और मजबूत किया जाए।

—: ० :—
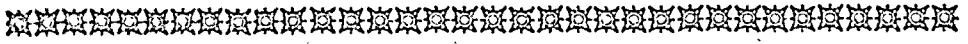
११ : प्रगतिशील युग

प्रगतिशील युग में जो १९०१ में थियोडोर रूज़वेल्ट के राष्ट्रपति बनने से लेकर १६ वर्ष बाद प्रथम विश्व-युद्ध में हमारे प्रवेश तक चला, सारे अमरीका में उदारता की एक लहर व्याप गई। व्यावसायिक प्रभुत्व के प्रति लोगों का असन्तोष, जो १८९६ के अभियान में प्रकट हुआ था, ब्रायन की पराजय के साथ ठण्डा नहीं पड़ा था। इसने एक अधिक सामान्य तथा कम क्रान्तिकारी आन्दोलन में नई अभिव्यक्ति पायी, जिसने दोनों बड़ी पार्टियों के जरिए राजनीतिक और सामाजिक सुधार प्राप्त किए। अधिक सामाजिक न्याय प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर राष्ट्र ने "अदृश्य सरकार" की समाप्ति तथा किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार के खात्मे की माँग की। अगर उदार उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त नहीं भी हुए तो भी अनेक क्षेत्रों में प्रभावशाली प्रगति की गई और "देश की नैतिक भावना" मज़बूत की गई, जिसने इस प्रगतिशील युग को १८९० या १९४० के दशकों में विद्यमान लोकमत के मुकाबले एक विशेष स्वरूप प्रदान किया।

राष्ट्रीय स्तर पर ट्रस्टों को नियन्त्रित करने, रेलों को नियमित करने, मुद्रा-प्रणाली को सुधारने और तटकर को कम करने की भरसक कोशिश की गई और साथ ही राज्य सरकारों ने आर्थिक व सामाजिक सुधार के व्यक्तिगत कार्यक्रम लागू किए, जिनका उद्देश्य गन्दी बस्तियों की सफाई, उद्योगों में स्त्री बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, और सामान्यतः फैक्ट्री में काम की हालतों में सुधार करना था। १९वीं सदी के स्वच्छन्द और उन्मुक्त अर्थतन्त्र की जगह सामाजिक जिम्मेदारी की भावना घर करने लगी जो उद्योगीकरण और शहरों के विकास की बढ़ती हुई समस्याओं का सामना करने के लिए सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता स्वीकार करती थी। इसके अतिरिक्त ये लाभ शांति और वैभव की पृष्ठभूमि में प्राप्त किए गए जिससे जीवन-स्तर काफी उन्नत हुआ। लोकतन्त्रीय पूँजीवाद में लोगों की आस्था और विश्वास, जो १८९० की दशाब्दि के मध्यवर्ती वर्षों में डगमगा गया था, उल्लासमय आशावाद के

बीच फिर जाग उठा।

इन सामान्य लाभों में मज़दूरों को भी हिस्सा मिला और अन्ततः उन्हें कांग्रेस और राज्यों दोनों के सुधार-सम्बन्धी कानूनों से काफी लाभ हुआ। किन्तु फिर भी सामष्टिक दृष्टि से राष्ट्र ने इस युग में जितनी प्रगति की, उसके अनुरूप मजदूरों की एक विशाल संख्या की हालत नहीं सुधरी। औद्योगिक मज़दूरों का वास्तविक वेतन यानी उसकी क्रय-शक्ति पहले से घट गई। इसके अलावा एक तरफ मज़दूरों की बचत करने वाली मशीनों के प्रयोग से और दूसरी ओर आव्रजन के बढ़ते रहने से मज़दूरों की बहुतायत की हालत निरन्तर बनी रही। इससे न केवल वेतन कम मिलते रहे बल्कि कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई जिनके सिर पर बेकारी का भूत सवार रहता था।

और नए कानून के बावजूद अधिकांश मज़दूरों की वास्तविक काम की हालतों में चिरकाल तक कोई असली परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। फैक्ट्री-नियम अब भी अपर्याप्त थे और प्रायः बड़े ढीले-ढाले ढंग से अमल में लाए जाते थे। कोयला-खानों, इस्पात-मिलों और पैकिंग-गृहों में; अब भी हृदय-हीनता से स्त्रियों व बच्चों से काम लेने वाली कपड़ा-मिलों और शहरी कपड़ा-उद्योग की फैक्ट्रियों में जहाँ चिरकाल तक बहुत ही कम मजदूरी पर काम कराया जाता था, जीवन की कठोर परिस्थितियाँ देश द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले ऐश्वर्य पर एक दुःखद टिप्पणी थी।

जहाँ तक स्वयं मजदूर-संगठन का सम्बन्ध था, इन वर्षों के लाभ घटते-बढ़ते और कुछ द्वयर्थक रहे। कुछ समय तक तो ऐसा लगा कि औद्योगिक सम्बन्धों का एक नया युग प्रारम्भ हो गया है जिसमें मजदूरों के शांत रहने की प्रबल आशा है किन्तु जैसे-जैसे यूनियनों की शक्ति बढ़ी, उद्योगों की तरफ से किए गए प्रत्याक्रमण से और ज़्यादा संघर्ष पैदा हो गए और मज़दूरों को अदालतों में तथा कारखानों में धरना देने के काम में बड़ी असफलताओं का मुँह देखना पड़ा। सिर्फ इस काल की समाप्ति आने पर ही पहले की गई प्रगति फिर से जारी की जा सकी, जिसमें यूनियन की सदस्यता काफी बढ़ी और सौदेबाजी की शक्ति में भी वृद्धि हुई।

संगठित मज़दूर आन्दोलन पर प्रायः अमरीकी मज़दूर संघ का ही प्रभुत्व —आई. डब्लू. डब्लू. के अचानक आविर्भाव का उल्लेख हम बाद में करेंगे—

और इसको मुख्य चिन्ता अब भी अपनी सम्बद्ध यूनियनों के कल्याण और हैसियत की थी, जिनके सदस्य ज़्यादातर दक्ष या अर्धदक्ष कर्मचारी थे। आगामी वर्षों में यह चीज़ बहुत महत्त्वपूर्ण रही। कोयला-खानों, पोशाक-उद्योग और कपड़ा-कारखानों में ए. एफ. एल. की यूनियनों का स्वरूप जहाँ औद्योगिक रहा वहाँ अन्यों में कुछ अदक्ष श्रमिक भी शामिल थे। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगों में बहुत अधिक कर्मचारी—जिनमें ज्यादातर विदेशों में जन्मे, अज्ञानी और अमरीकी संस्कृति में न पले हुए लोग थे—यूनियनों से बाहर ही रहे। प्रगतिशील युग में संगठित मज़दूरों के कार्य पर दृष्टिपात करते हुए यह याद रखना चाहिए कि इससे राष्ट्र के सिर्फ १० प्रतिशत मज़दूरों का सीधा सम्बन्ध था।

हमारे विदेश मन्त्री जोन हे ने जिसे स्पेन के साथ "हमारी शानदार छोटी-सी लड़ाई" कहा, उसके बाद राष्ट्रीय यूनियनों तथा मालिकों के बीच सम्बन्ध इतने अच्छे रहे कि १८९८ से १९०४ तक के युग को "पूँजी और श्रम का सुहागराती जमाना" कहा जाता है। हड़तालें कभी-कभी इसमें रंग-भंग भी कर देती थीं किन्तु कम-से-कम १८९० के दशक के क्षुब्ध औद्योगिक संघर्ष के मुकाबले स्थिति में काफी सुधार था। अनेक उद्योगों में लगता था कि मालिकों और मज़दूरों दोनों ने यह संकल्प कर लिया है कि वे अपनी समस्याएँ शान्ति से ही हल करेंगे। जिम्मेदार मज़दूर नेताओं को पुलमैन जैसी हड़तालों के संघर्ष की निश्चित विफलता का विश्वास हो गया था और बहुत से उद्योगपति भी हड़तालों को सफलतापूर्वक कुचल दिए जाने पर भी उनके खतरनाक राजनीतिक और आर्थिक परिणामों को समझने लगे थे। सामान्यत: देश ही, पिछले अनुभवों से सबक लेकर इस बात की अधिकाधिक माँग कर रहा था कि औद्योगिक झगड़े शान्त करने का कोई ऐसा उपाय निकाला जाये जिससे सार्वजनिक हित की सुरक्षा हो सके।

मज़दूर समस्याओं के प्रति इन नए दृष्टिकोण का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व नेशनल सिविक फेडरेशन ने किया। पहले १८९६ में शिकागो में इसकी स्थापना हुई थी किन्तु सदी की समाप्ति पर वह राष्ट्रीय स्तर पर काम करने लगा था और उसका उद्देश्य था कि औद्योगिक शांति रखने के संयुक्त अभियान में श्रम,

पूँजी और जनता को एक मंच पर लाया जाए। १८९० की दशाब्दि के प्रचलित रवैये के खिलाफ, जिसमें मज़दूरों के सब आन्दोलनों को अराजकता समझा जाता था, इसकी स्थापना इस मन्तव्य के आधार पर हुई थी कि "संगठित मज़दूरों को यदि नष्ट करने की कोशिश की गई तो अवाम का पतन अवश्यम्भावी है" यूनियन विरोधी मालिकों को भी राष्ट्रीय स्थिरता का उतना ही बड़ा शत्रु घोषित किया गया, जितना रैडिकल या समाजवादी मज़दूर नेताओं को। नेशनल सिविक फेडरेशन न यूनियनों के निर्माण और उनके द्वारा किए गए समझौतों को मूल सिद्धान्त स्वीकार किया और मालिक और मज़दूर जब कभी भी अपने झगड़ों को पंच-फैसले के लिए सुपुर्द करने को राजी होते थे तब वह "उनके बीच ठीक प्रकार के सम्बन्ध" स्थापित करने के लिए अपनी सेवाएँ देने को उद्यत रहता था।

इस आन्दोलन के नेता थे—मार्क हान्ना और सेम्युअल गोम्पर्स और उनके साथ नेशनल सिविक फेडरेशन में प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों का एक ग्रुप था। इसमें गवर्नर क्लीवलेण्ड, हारवार्ड के प्रेजीडेण्ट इलियट और आर्कबिशप आयरलैण्ड जनता के; जॉन डि राकफेलर जूनियर, चार्ल्स एम. श्वाब और ऑगस्ट बेलमोण्ट मालिकों के तथा युनाइटेड माइन वर्कर्स के जॉन मिचेल, मशीनचालकों के जेम्स ओ' कोनेल और ग्रेनाइट कटर्स के जेम्स डंकन मज़दूरों के प्रतिनिधि थे। सदस्यों की सूची बड़ी प्रभावकारी थी और कुछ अरसे तक नेशनल सिविक फेडरेशन का जो असर रहा वह श्रम और पूँजी के सहयोग के लिए बहुत आशाप्रद था।

मालिकों के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रुपों ने परस्पर स्वीकार्य राजीनामों के आधार पर यूनियनों से समझौता कर लिया। नेशनल फाउण्डर्स ऐसोसियेशन तथा मशीन-चालकों ने अन्तर्राज्यीय एसोसियेशन के साथ करार किए गए। न्यूज़पेपर्स पब्लिशर्स ऐसोसियेशन तथा इण्टरनेशनल टाइपोग्रैफिकल यूनियन ने अनेक समझौते किए। रेलवे कम्पनियों ने ब्रदरहुडों को मान्यता दी और इनसे समझौते की बातचीत की। औद्योगिक शांति की तरफ उस प्रत्यक्ष प्रगति में और सामूहिक सौदेबाजी को स्वीकार कर लेने में निःसन्देह कुछ अपवाद भी थे। उदाहरणार्थ ऐमलगमेटेड आयरन ऐण्ड स्टीलवर्कर्स की तरफ से इस्पात उद्योग के कर्मचारियों को संगठित करने का

अंतिम प्रयत्न सर्वथा विफल हो गया जब कि युनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन ने १६०१ में की गई जबर्दस्त हड़ताल को कुचल दिया। इसके निर्देशक मंडल ने मज़दूरों की यूनियनों के विस्तार का विरोध करने के पक्ष में गुप्त रूप से एक प्रस्ताव पास किया था। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हार थी किन्तु व्यावसायिक समझौतों की बढ़ती हुई संख्या से, जो ए. एफ. एल. की नीतियों और कार्यक्रमों का परिणाम थीं, ऐसा लगता था कि मालिकों के आम रवैये में परिवर्तन हुआ है और इससे मज़दूरों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। गोम्पर्स ने खुशी से कहा: "यह वर्षों के संगठन का परिणाम है जो अब फल देने लगा है।"

इन परिस्थितियों में यूनियनें फली-फूलीं और देश के अनेक हिस्सों में उन्हें नई महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हुई। जिन धन्धों में मज़दूर-हलचलों का लम्बा इतिहास रहा था, उनमें यूनियनें सबसे मज़बूत थीं और उन्होंने लाभ भी सबसे ज्यादा प्राप्त किये। अमरीकी मज़दूर संघ से सम्बद्ध यूनियनों में खनिकों, मुद्रकों, सिगार-निर्माताओं, खातियों, ढलाई का काम करने वालों, खलासियों, शराब खींचने वालों और मशीन-चालकों की यूनियनें अग्रणी रहीं और इनमें से प्रत्येक के सदस्यों की संख्या काफ़ी बढ़ी।

कीचड़ उछालने वालों का भण्डाफोड़ होने से जो इन वर्षों में औद्योगिक जीवन के हर पहलू को कुरेदते रहे थे, सौदेबाज़ी के लिये अपनी स्थिति सुधारने के मज़दूरों के प्रयत्नों के प्रति लोगों में कुछ सहानुभूति उत्पन्न हुई। १६०२ में स्प्रिंग-फील्ड रिपब्लिकन ने लिखा: "पूँजी को संगठित मज़दूरों के साथ अपनी पटरी बैठाने का निश्चय कर लेना चाहिए। अब ये संगठन स्थायी हो गये हैं और कानून अब मज़दूर यूनियनों को गैरकानूनी करार देने के बजाय सम्भवतः उनका निर्माण अनिवार्य कर देगा। इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लिया जाए, उतनी ही जल्दी देश एक स्थायी औद्योगिक शान्ति की राह पर अग्रसर होने लगेगा।" कई वर्ष बाद नए प्रगतिवाद के प्रवक्ता हर्बर्ट क्रोली ने भी मज़दूरों के संगठन बनाये रखने की जोरदार वकालत की। 'दि प्रामिस आव अमेरिकन लाइफ' में उन्होंने लिखा: "मज़दूर यूनियनों का पक्ष लिया जाना चाहिए क्योंकि मज़दूर वर्ग की आर्थिक और सामाजिक हालत को सुधारने के लिये अभी इससे अच्छी कोई मशीनरी नहीं बन सकी है।"

लोगों का रवैया बदल रहा है यह बात इन वर्षों की सबसे महत्त्वपूर्ण

हड़तालों में सरकार की कार्रवाइयों से भी पता चलती थी। क्योंकि जब ऐन्थ्रसाइट कोयला खनिक १६०२ में खान मालिकों के साथ एक कठिन संघर्ष में जूझ रहे थे तब राष्ट्रति रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति क्लीवलैंड की तरह जिन्होंने १८६४ में शिकागो में संघीय सेनाएँ भेज दी थीं, अपने प्रभाव का उपयोग हड़तालियों को कुचलने में नहीं, बल्कि पंच-फैसला कराने में किया। यद्यपि उनका मुख्य लक्ष्य कोयले के संभावित अकाल को रोकना था तो भी इससे मज़दूरों की उचित शिकायतों के प्रति उन्होंने अपनी आँखें नहीं मूँदीं।

१८७० के दशक की लम्बी हड़तालों और मौली मैगायर्स के विक्षोभकारी जमाने से लेकर अब तक मज़दूरों द्वारा अपनी काम की हालतों में सुधार के लिए संघर्ष किये जाने पर कोयला खानों में समय-समय पर हड़तालें हो चुकी थीं। किन्तु १८६० में जब तक यूनाइटेड माइन वर्कर्स का निर्माण नहीं हुआ तब तक वे खान मालिकों की संयुक्त शक्ति के खिलाफ़ एक मज़बूत मोर्चा नहीं लगा सके। किन्तु यह नई यूनियन पेंसिलवेनिया, ओहायो, इंडियाना और मिशीगन की कोयला खानों में मज़दूरों को संगठित करने में कामयाब हुई और एक समझौते के द्वारा, जिसमें वेतन और काम के घण्टे दोनों निश्चित कर दिये गये थे, मालिकों से पूरी मान्यता प्राप्त की। इस विजय से तरोताज़ा होकर इसने १८६० की दशाब्दि के अन्त में पूर्वी पेंसिलवेनिया की कोयला-खानों में भी अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया।

यहाँ इसका काम ज्यादा कठिन था। यहाँ खानों के मालिकों का रेलवे कम्पनियों के मातहत एक ट्रस्ट बना हुआ था और वे यूनियनों को मान्यता देने के सख्त खिलाफ़ थे। इसके अतिरिक्त वहाँ के मज़दूरों में पोलों, हंगेरियनों, स्लोवाकों, इटालियनों तथा अन्य नवागन्तुकों की इतनी बहुतायत थी कि उनको एक सूत्र में बाँधनेवाली कोई चीज़ नहीं थी। एकता के इस अभाव का खान मालिकों ने पूरा लाभ उठाया और उनमें आपसी झगड़े बढ़ाने की उन्होंने हरचन्द कोशिश की।

इन बाधाओं के होते हुए युनाइटेड माइन वर्कर्स ने बहुत आहिस्ता-आहिस्ता प्रगति की, किन्तु यद्यपि इस कोयला क्षेत्र में उनकी सदस्य संख्या १० हजार से भी कम थी, तो भी सन् १६०० में हड़ताल की पहली पुकार पर

उसमें इससे १० गुना लोग शामिल हुए। खान मालिक इस 'हमले' का सामना करने को तैयार थे किन्तु मार्क हान्ना ने हस्तक्षेप करके उन्हें लम्बा संघर्ष टालने के लिए राज़ी कर लिया। हान्ना का ध्येय पूर्णतः राजनीतिक था। १९०० में रिपब्लिक पार्टी समृद्धि के मंच पर, रात्रि-भोज का पूरा भरा पात्र जिसका प्रतीक था, चुनाव आन्दोलन कर रही थी और कोयले की हड़ताल दल के व्याख्याताओं के राग में स्वर भंग उत्पन्न कर देती। खान मालिकों ने खनिकों के साथ अनिच्छा से एक मौखिक समझौता कर लिया जिसका मतलब उनकी यूनियन को मान्यता देना नहीं था किन्तु वेतन में १० प्रतिशत वृद्धि कर उसकी तात्कालिक माँगों की आंशिक पूर्ति करना था।

किन्तु यह एक विराम संधि थी, समझौता नहीं। हड़तालियों का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था और खान मालिकों को भी जरा सी भी रियायतें दे देने का अफसोस था। अवस्था में जब कोई वास्तविक सुधार नहीं हुआ तो युनाइटेड माइन वर्कर्स ने १९०२ में और माँगें रखीं और इस बार खान मालिकों ने निश्चय कर लिया कि किसी भी राजनीतिक दबाव से संघर्ष को स्थगित नहीं होने देंगे। उन्होंने खनिकों के नए प्रस्तावों पर विचार करने या यूनियन के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार रखने से स्पष्ट इंकार कर दिया। तब दूसरी हड़ताल बुलाई गई और १॥ लाख खनिक काम छोड़ कर खानों से बाहर आ गए।

मजदूरों की शिकायतें बिल्कुल वाजिब थीं। किसी भी पैमाने से देखने पर भी तनख्वाहें बहुत कम थीं, दिन में काम के घण्टे कठिन और खतरनाक थे और बार-बार काम से हटा दिए जाने के कारण रोजगार स्थायी न रहने से मज़दूर की औसत वार्षिक आय सिर्फ ३०० डालर रह जाती थी। दुर्घटनाएँ सामान्य बात थी, जिनसे १९०१ में ४४१ व्यक्ति मरे और खान मालिकों ने सुरक्षा की अधिक अच्छी व्यवस्था करने अथवा चोटों के लिए अपने कर्मचारियों को मुआवज़ा देने के लिए कुछ नहीं किया। किन्तु कम वेतन और काम की खराब हालतों से भी ज्यादा भयावह बात कम्पनी के नगरों पर नियंत्रण के द्वारा खान मलिकों द्वारा चलाई जा रही सख्त सामन्ती प्रणाली थी। बाद में सेम्युअल गोम्पर्स ने लिखा : "मज़दूरों के जन्म के समय कम्पनी के डाक्टर ही उनकी देखभाल करते थे, कम्पनी के फ्लैट या झोंपड़ी में ही उन्हें

रहना पड़ता था, कम्पनी की दूकानों से ही सामान खरीदना पड़ता था और कम्पनी के कब्रिस्तान में ही उन्हें दफनाया जाता था।"

९ मई, १९०२ की हड़ताल हो जाने पर खान मालिकों ने तुरन्त ही ३००० पुलिस और उसके साथ १००० विशेष डिपुटी उस क्षेत्र में झोंक दिए। और वे हड़ताल-भंजकों को भी लाने लगे, उन्होंने झूठ-मूठ ही मज़दूरों के खिलाफ़ हिंसा, विध्वंस और दंगों के आरोप गढ़े और राज्य की मिलीशिया से भी संरक्षण की मांग की। हड़ताल को सम्पत्ति के अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ एक और अराजकतावादी और क्रांतिकारी विद्रोह बता कर उसका सामना करने की योजना बनाई गई।

इस प्रकार की उत्तेजना के बावजूद हिंसा का प्रायः बिल्कुल ही आश्रय नहीं लिया गया। यह सामान्यतः इतनी शांत हड़ताल रही जितनी कोयला खानों में पहले कभी नहीं हुई थी। मज़दूर खानों के बाहर रहे और उन्होंने बिल्कुल निष्क्रिय रवैया अपनाया। हड़ताल से उनके परिवारों को जो कष्ट झेलने पड़े उसके बावजूद मज़दूर डटे रहे। आखिर तक के संग्राम के लिए भी वे तैयार थे। अपनी मांगें पूरी होने तक खानों से कोयला न निकालने का उनका दृढ़ निश्चय था।

यह एकता और व्यवस्था मुख्यतः युनाइटेड माइन वर्कर्स के अध्यक्ष के कुशल संचालन और मज़दूरों पर उनके अच्छे प्रभाव के कारण कायम रह सकी। १८९८ से इस पद पर जॉन मिचेल काम कर रहा था। जब वह १२ वर्ष का लड़का था तभी से उसने खानों में काम करना शुरू कर दिया था। यूनियन के अत्यन्त अंधकारपूर्ण दिनों में वह उसके साथ रहा और ज्यादातर खानों में काम करने वाले अनेक राष्ट्रीयताओं वाले मज़दूरों के संगठन स्थापित करने के कारण २८ वर्ष की ही आयु में इसका नेता बन गया। पतले और मज़बूत, अपनी भूरी आँखों और साँवले चेहरे से ईटालियन-सा प्रतीत होने वाला मिचेल नरम स्वभाव का, यहां तक कि शर्मीला था। उसकी शक्ति इस बात में निहित थी कि यूनियन की राजनीति में तथा मालिकों के साथ सम्बन्धों दोनों में नरम रवैया रखता था और बड़े मामलों को छोड़कर बाकी सब मामलों पर बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार रहता था।

अपने सामाजिक और राजनीतिक विचारों में उस समय का कोई दूसरा

मजदूर नेता उससे ज्यादा रूढ़िवादी नहीं था, पंच-फैसले को स्वीकार करने के लिये उससे अधिक उत्सुक और रैडिकलवाद और हिंसा का उससे अधिक विरोध करने वाला नहीं था। १६०२ में पहले उसने हड़ताल का विरोध किया था, ऐन्थ्रूसाइट (लपट न छोड़ने वाला कोयला) कोयला खानों में खनिकों की हड़ताल के समर्थन में बिटुमिनस (लपट छोड़ने वाला कोयला) खनिकों की हड़ताल बुलाने से वह लगातार इन्कार करता रहा क्योंकि बिटुमिनस खनिकों ने खान मालिकों के साथ एक करार पर दस्तख़त कर रखे थे और किसी भी समय विवादग्रस्त मामलों को पंच-फैसले के लिए एक निष्पक्ष निकाय को सौंपने के लिये तैयार था। उसने सुझाव दिया नेशनल सिविक फेडरेशन ५ व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त कर दे या आर्क विशप आयरलैण्ड, विशप पौटर उनकी पसन्द के एक तीसरे व्यक्ति की समिति बना दी जाए।

उसने कहा कि "अगर वे यह निर्णय देंगे कि ऐन्थ्रूसाइट खनिकों का औसत वार्षिक वेतन इतना पर्याप्त है कि खनिक माने हुए अमरीकी स्तर तथा अमरीकी नागरिकता के अनुरूप अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं और उन्हें निश्चित कर सकते हैं तो हम अधिक वेतन और अधिक न्यायोचित काम की हालतों की अपनी माँगों को वापस ले लेंगे, बशर्ते कि ऐन्थ्रूसाइट खानों के मालिक अपने कर्मचारियों की आय और उनकी काम की हालतों के बारे में इस समिति की किन्हीं भी सिफारिशों को मानने का वचन दें।"

एक तरफ मिचेल का यह नरम रुख था तो दूसरी ओर खान मालिकों के सख्त-दिमाग प्रवक्ता जार्ज एफ. बेअर का रवैया बड़ा निष्ठुरतापूर्ण था। मिचेल के प्रस्तावों पर उसका जवाब था कि "ऐन्थ्रूसाइट खानों से कोयला निकालना एक व्यावसायिक कारोबार है, धार्मिक, भातृकतापूर्ण ज़बानी जमाख़र्च नहीं।" वह किसी भी लागत हर यूनियन को तोड़ने पर आमादा था। उसने यह स्पष्ट कह देने में कभी संकोच नहीं किया कि किसी भी झगड़े को कभी भी बाहरी ग्रूप को नहीं सौंपा जाएगा, यूनियन से सीधी बातचीत तो दूर की बात थी। खान मालिकों के पितृवत् नियंत्रणों में उसका पूर्ण विश्वास था। इस अपील के जवाब में कि अपने क्रिश्चियन कर्तव्य के नाते उसे हड़ताल खत्म करानी चाहिए, उसने उन शब्दों में अपनी स्थिति स्पष्ट की जो 'न्यूयार्क टाइम्स' को भी बहुत कुछ ईश्वर-निन्दा प्रतीत हुई।

वेग्रर ने पत्रप्रेपक को लिखा : "मैं प्रार्थना करता हूँ, आप निराश न हों। मज़दूरों के अधिकारों और हितों की रक्षा मज़दूर आन्दोलनकारी नहीं वल्कि वे ईसाई व्यक्ति करेंगे जिन्हें ईश्वर ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता से इस देश की सम्पत्ति का नियंत्रण सौंपा है...।"

हड़ताल लम्बी चलने पर जव कोयले की कमी पड़ी और कीमतें चढ़ने लगीं तो आम लोगों को भी अधिक चिन्ता होने लगी और वे समझौते की माँग करने लगे। आम लोगों की सहानुभूति जहाँ पहले खनिकों के साथ थी वहाँ कंजरवेटिव अखवार खुल्लमखुल्ला उत्पादन में रुकावट के लिए मज़दूरों को ही दोप देने लगे और कोयला खानों में जव कभी किसी उपद्रव की ख़बर मिलती तो ये उसे वहुत वढ़ा-चढ़ाकर छापते थे। 'जर्नल आव कामर्स' में सुपरिचित स्वर में कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वह "हड़ताल नहीं, विद्रोह है" और न्यूयार्क इवनिंग पोस्ट ने हड़ताल का दमन करने के लिए "कठोर कदमों" की माँग की।

किन्तु खान मालकों ने जव समझौते की तरफ एक भी कदम नहीं वढ़ाया तव लोगों का समर्थन पुनः खानकर्मचारियों के पक्ष में हो गया। वेग्रर ने जव अपने "दैवीय अधिकारों" का वखान किया तो अग्रलेखों और कार्टूनों में उसकी कड़ी निन्दा की गई और अनेक क्षेत्रों में दुराग्रहपूर्ण हठ-धर्मिता के लिए उसकी अधिकाधिक आलोचना की गई। किन्तु देश को मुख्य दिलचस्पी न तो खनिकों में थी और न खानमालिकों में। उसे तो कोयला चाहिए था। उस समय का लोकमत शायद 'न्यूयार्क हैरल्ड' के एक कार्टून में ज्यादा अच्छी तरह व्यक्त हुआ जिसमें जनता को विध्वंस के एक ढेर पर पड़ा दिखाया गया था, जिसको एक सिरे से खान मालिक और दूसरे सिरे से खनिक खींच रहे थे और उसके परिचय में कहा गया था : "पीड़ित को इससे सरोकार नहीं कि पहले कौन हटता है।"

राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कोयलाखानों में शांति की इस माँग के वल को अनुभव किया। श्रम संवंधी मामलों में उनका अपना मन्तव्य कुछ द्वयर्थक था किन्तु अव उन्हें इस वात की चिन्ता थी कि खानों को चलाया जाए। सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए वह कार्रवाई करने के लिए वाध्य हुए, क्योंकि जैसा कि उनके पत्र-व्यवहार से पता चलता है कि उन्हें कोयले के अकाल की राजनीतिक

प्रतिक्रिया का डर था। उनका कार्यक्रम हड़ताल को कुचलना नहीं, बल्कि पंच-फैसले के लिए मजबूर करना था, यद्यपि खान मालिक शर्मन अधिनियम के मातहत व्यापार में बाधा डालने के एक षड्यंत्र के रूप में यूनाइटेड माइन वर्कर्स के खिलाफ एक निरोधादेश की माँग कर रहे थे। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति ने खानमालिकों तथा हड़ताली नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया जो ३ अक्तूबर को ह्वाइट हाउस में हुआ था।

मिचेल जहाँ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी कमीशन के फैसले को मानने के लिए तैयार था वहाँ बेअर ने एक बार पुनः पंचफैसले से कोई सरोकार रखने से साफ इन्कार कर दिया। खनिक नेता के नरम रुख के मुकाबले उसके सख्त और अड़ंगेबाजी के रवैये ने राष्ट्रपति को क्रुद्ध कर दिया। बेअर ने न केवल हड़तालियों पर आक्षेप किए, बल्कि राष्ट्रपति को भी इस बात के लिए गुस्से से झिड़क दिया कि वह "अराजकता तथा कानून को चुनौती देने की भावना भड़काने वालों से" समझौता वार्ता करने का यत्न कर रहे हैं। सम्मेलन में बड़ा गुलगपाड़ा मचा। बेअर के बारे में रूज़वेल्ट ने कहा बताते हैं कि "अगर मैं इस उच्च पद पर न होता तो मैंने उसे शरीर के निचले भाग और गर्दन से पकड़कर खिड़की के बाहर फेंक दिया होता।"

अब भी कोई भी कोयला खानों से नहीं निकाला जा रहा था। हड़ताल भंजकों की रक्षा के लिए यद्यपि उस क्षेत्र में १० हज़ार सैनिक भेज दिये गए थे तो भी कोई भी खनिक काम पर वापस नहीं आ रहा था। जनता अधिकाधिक बेचैन हो उठी और अनुदार अखबारों ने भी अब कहना शुरू कर दिया कि खान मालिक लोकमत का समर्थन पाने का दावा गँवा बैठे हैं और उन्हें यूनाइटेड माइन वर्कर्स के साथ बातचीत के आधार पर हड़ताल का निबटारा कर लेना चाहिए। 'शिकागो इवनिंग पोस्ट ने लिखा : "और जनता बहुत देर तक' प्रतीक्षा भी नहीं करेगी......।"

रूज़वेल्ट ने और भी ज्यादा सीधा हस्तक्षेप करने का निर्णय किया। उन्होंने घटना-स्थल पर सेना भेजने की गुप्त रूप में एक योजना बनाई, जिसके कमाण्डर को यह आदेश था कि वह खान मालिकों से खानों की मिल्कियत छीनकर एक रिसीवर के तौर पर उन्हें चलाए और युद्धमंत्री रूट को खान मालिकों के पीठ पीछे की वास्तविक ताकत जे. पी. मार्गन को यह सूचित करने के लिये भेजा कि

अगर 'पंचफैसले से अब भी इन्कार किया गया तो राष्ट्रपति की यह वैकल्पिक योजना है। सरकार के इस सीधे दवाव के नीचे अन्ततः खान मालिकों को झुकने के लिए राज़ी कर लिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति से एक पंच-फैसला आयोग नियुक्त करने की प्रार्थना की किन्तु इस स्थिति में भी उन्होंने मामले को निवटाने में राष्ट्रपति के प्रयत्नों में वाधा डालना वन्द नहीं किया और कहा कि वे आयोग में किसी मजदूर सदस्य को स्वीकार नहीं करेंगे। वातचीत तव तक अधर में लटकी रही जव तक राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने इस अंतिम अड़चन को भी ग्रैण्ड चीफ आव रेलवे कण्डक्टर्स को मज़दूरों के प्रतिनिधि के वजाय "एक प्रमुख समाजशास्त्री" की हैसियत से आयोग का सदस्य वनाकर दूर नहीं कर दिया। २३ अक्तूवर को ५ महीने से भी अधिक समय पश्चात् जिसमें मज़दूर अपने संकल्प पर दृढ़ रहे, खनिक काम पर लौट गए।

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग ने मार्च १९०३ में दिए गए अपने पंच फैसले में वेतनों में १० प्रतिशत वृद्धि प्रदान की, विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए काम के घण्टे कम करके ८-९ घण्टे कर दिए और आगामी तीन वर्षों में जव तक यह पंचाट लागू रहना था, उठने वाले झगड़ों को निवटाने के लिए एक विशेष वोर्ड नियुक्त कर दिया। खनिकों की यूनियन को मान्यता नहीं मिली। उन्हें अपने पूरे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई और उन्होंने पंचाट को अनमने भाव से स्वीकार किया। किन्तु खान मालिकों के चट्टान की तरह कठोर विरोध के सामने उन्होंने वास्तव में वड़े महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए जिससे ऐन्थ्रूसाइट क्षेत्र में युनाइटेड माइन वर्कर्स की स्थिति वहुत मज़वूत हो गई।

२०वीं सदी के शुरू में जो लाभ प्राप्त किए गए उनके, और यूनियनों की कुल सदस्य संख्या १९०० में ८,६८,५०० से १९०४ में २० लाख हो जाने और कोयला हड़ताल में जनता द्वारा सामान्यतः अधिक सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाए जाने के वावजूद संगठित श्रमिकों के लिए आगे मुसीवत के दिन थे। मालिक, जो कुछ अरसे तक यूनियनों को मान्यता देते हुए से प्रतीत हुए थे, यूनियनों की बढ़ती हुई ताकत से चौकन्ने हो गए। मूलतः नेशनल सिविक फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक शांति के कार्यक्रम को लगभग धत्ता बताकर ९०३ में वे संगठित रूप से मज़दूरों को और ज्यादा लाभ प्राप्त करने से

रोकने में लग गए।

वे 'येलो डॉग करारों'* को प्रोत्साहन देकर मज़दूरों को यह वचन देने पर ही काम पर रखने लगे कि वे किसी यूनियन में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने आप्रजक मज़दूरों में स्वाभाविक प्रतिद्वन्द्विता को बढ़ावा दिया जिससे वे मिल कर कोई काम न कर सकें, मज़दूर आन्दोलनकारियों के बारे में सूचनाएँ देने के लिए मज़दूर गुप्तचर रखे, जिनकी रिपोर्ट पर बाद में उन्हें तुरन्त बरखास्त कर दिया जाता था और क्रांतिकारी विचारों वाले मज़दूरों की काली सूची का आदान-प्रदान किया गया। इस नए यूनियन-विरोधी अभियान में बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ बहुत क्रूरता से काम ले रही थीं और षड्यन्त्र सम्बन्धी अभियोगों और निरोधादेशों में सहयोग देने के लिए अदालतों से सफलतापूर्वक अपील करके उन्होंने अपनी ताकत काफी बढ़ा ली।

मशीनरी और धातु के व्यवसाय में पहले किए गए समझौते भंग हो गए क्योंकि इन दोनों में मालिकों की ऐसोसियेशन अपने पहले के मज़दूर विरोधी रवैये पर लौट आयीं। युनाइटेड स्टेट्स स्टील कम्पनी द्वारा यूनियन मज़दूरों के साथ किसी भी हालत में कोई व्यवहार रखने से इन्कार कर देने पर लोहे का ढांचा बनाने वाले उद्योग में खुला संग्राम छिड़ गया जिसमें मज़दूरों ने हिंसा और डाइनामाइट का आश्रय लिया। खाद्य पदार्थ पैक करने वाले कारखानों ने एक हड़ताल को दबा दिया जिसमें उसके कर्मचारियों ने सामूहिक सौदेबाजी की कोशिश की थी; शिकागो की डिलीवरी फर्मों ने मान्यता के लिए टीमस्टर्स की हड़ताल को कुचल डालने के लिए अपनी ताकत एकजुट कर ली। करीब-करीब हर क्षेत्र में संगठित मज़दूरों को धक्का सा लगता प्रतीत हुआ जबकि मालिकों ने, जो कुछ वर्ष पूर्व मज़दूरों के साथ सौदेबाजी के लिए उद्यत प्रतीत होते थे, अब वैसा करने से इन्कार कर दिया।

स्वतः नेशनल सिविक फेडरेशन का दिल बदल गया जब उसने देखा कि व्यापारिक समझौते एक के बाद एक टूटते जा रहे हैं तो यूनियनों के निर्माण के लिए उसका पहले का उत्साह जाता रहा। इसके मालिक-सदस्य मज़दूरों

---

* 'येलो डाग करार', कर्मचारी के साथ किया गया वह करार होता है जिसमें वह यह घोषित करता है कि वह किसी यूनियन का सदस्य नहीं है और भविष्य में भी जब तक वह काम करेगा, किसी यूनियन में शामिल नहीं होगा।

के प्रति अपनी मित्रता का वखान तो अव भी करते थे किन्तु उनकी शक्ति मुख्यतः समाजवाद और 'वन्द शाप'* का मुकावला करने में लगी हुई थी। गौम्पर्स, जो समाजवाद का उनसे कम विरोधी नहीं था, उनके साथ काम करता रहा किन्तु उसके द्वारा नेशनल सिविक फेडरेशन के कार्यों की वकालत किए जाने पर भी औद्योगिक झगड़ों में उसकी निष्पक्षता पर से मज़दूरों का विश्वास उठ गया।

सब प्रकार के मज़दूर संगठनों के विरुद्ध ये औद्योगिक संस्थान थे जिन्होंने १९०३ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन कर नागरिकों का औद्योगिक ऐसोसियेशन कायम किया। लोकमत को मज़दूरों के विरुद्ध करने में उसकी हलचलें व प्रचार काफी सफल रहा। १९०६ में एक सम्मेलन के वाद जिसमें मालिकों के करीव ४६८ ऐसोसियेशनों के लगभग इतने ही प्रतिनिधियों ने भाग लिया, अध्यक्ष सी. डब्लू. पोस्ट ने उत्साहपूर्वक वताया कि संस्था कैसी प्रगति कर रही है। उसने कहा कि "दो वर्ष पूर्व अखवार और औपदेशिक मंच मज़दूरों के उत्पादन के वारे में उपदेश झाड़ रहे थे। अव यह सव कुछ वदल गया है क्योंकि यह देखा गया है कि विशाल श्रमिक ट्रस्ट स्वतंत्र मज़दूर और सामान्य अमरीकी नागरिक को सवसे ज्यादा सताता है। लोगों की आँखें खुल गई हैं और अव वे सतर्क हैं......"

इसी समय इससे भी ज्यादा जोर मज़दूर-विरोधी अभियान निर्माताओं के राष्ट्रीय ऐसोसियेशन ने चलाया, जिसकी स्थापना तो १८९५ में हुई थी किन्तु संगठित श्रमिकों पर वास्तविक हमले उसने १९०३ में शुरू किए। इसका नारा और युद्ध-घोष था 'ओपनशाप' अर्थात् कोई व्यक्ति यूनियन का सदस्य हो या न हो, उसे काम पाने के अधिकार की गारण्टी हो। किन्तु व्यक्तिगत स्वाधीनता के नाम पर की गई इस अपील के पीछे यूनियन की मान्यता और सामूहिक सौदेवाजी दोनों के विरुद्ध प्रच्छन्न रूप से एक तीव्र आन्दोलन चलाया जा रहा था। निर्माताओं के राष्ट्रीय ऐसोसियेशन का कहना था कि वेतन और काम की हालतों के निश्चय का एकमात्र अधिकार उद्योग को है।

* 'वन्दशाप' वह संस्थान होता है जिसमें मालिक सिर्फ यूनियन के सदस्यों को ही काम पर रखता है, लेकिन जब यूनियन सदस्य न मिलें तो गैर-यूनियन सदस्य को भी काम पर ले सकता है। किन्तु इसे भी काम शुरू करने से पूर्व यूनियन का सदस्य वनना पड़ता है।

१९०३ के वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्ष पैरी ने प्रतिनिधियों से कहा कि चूँकि संगठित मजदूरों के सिद्धान्त और माँगें व्यक्तिवादी सामाजिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को बिल्कुल भी मान्य नहीं हैं इसलिए नरमी के रवैये का मतलब होगा अपनी बुनियादी आस्थाओं के साथ सौदेबाजी करना......"महानतम खतरा यूनियन को मान्यता देने में है।" निर्माताओं के राष्ट्रीय ऐसोसियेशन ने पहले जारी किए गए एक पैम्फलेट में, जिसका स्कूलों, गिरजाघरों, अखबारों और औद्योगिक पत्रों तक में प्रचार किया गया, स्पष्ट यह कहा गया कि "अगर भाषण और लेखन की स्वाधीनता के बारे में गौम्पर्स-डेब्स के आदर्शों को हावी होने दिया गया तो न तो हमारी सरकार ही टिक सकती है और न उसकी स्वतन्त्र संस्थाएँ कायम रह सकती हैं।"

'ओपनशाप' के सिद्धान्त का, प्रायः इतनी दृढ़ता से समर्थन किया जाता था, जितनी विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से जरूरत नहीं थी, और इसका यूनियनों को कुचलने के लिए उठाए गए अत्यन्त कठोर कदमों को दर-गुज़र करने या उन्हें उचित ठहराने के लिए उपयोग किया जाता था। इसका शायद सबसे सजीव चित्रण १९१३ में कोलोरेडो फ्युएल ऐण्ड आयरन कम्पनी के कर्मचारियों की हड़ताल को कुचले जाते समय देखने को मिला। इस मामले में वास्तविक विवाद युनाइटेड माइन वर्कर्स को मान्यता देने के बारे में था, जिसने इस क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि भेज दिए थे। यह रियायत देने के बजाय कम्पनी ने किराये के जासूसों, विशेष डिपुटियों और राज्य की मिलीशिया की सहायता से हड़तालियों से जमकर लोहा लिया।

कोलोरेडो के खान क्षेत्रों में खुला संग्राम महीनों तक जारी रहा और अंत में अपनी खूनी चरमावस्था पर जा पहुँचा जबकि मिलीशिया ने लुडलो में हड़तालियों की एक बस्ती पर हमला किया। काफी देर तक मशीनगनों से अन्धाधुन्ध गोलियाँ बरसाए जाने के बाद उन तम्बुओं पर, जिनमें मज़दूरों के परिवार रह रहे थे, तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। आग की लपटों से बचने के लिए स्त्री-बच्चे खान में भाग निकले और एक अग्निकाण्ड में ११ बच्चे और दो स्त्रियाँ जलकर या दम घुटकर मर गईं। इस हत्याकाण्ड से राष्ट्र दहल उठा किन्तु फिर भी कोलोरेडो फ्युएल ऐण्ड आयरन कम्पनी ने हड़ताल

खत्म करने के लिये यूनियन से वार्ता के प्रश्न पर विचार करने से इंकार कर दिया ।

कम्पनी पर राकफेलर के हितों का नियन्त्रण था और जब खानों व खनन पर प्रतिनिधि सभा की एक समिति ने हड़ताल की जांच की तो जॉन डी० राकफेलर जूनियर को गवाह के रूप में मंच पर बुलाया गया। उससे जब पूछा गया कि "लोगों की हत्या और बच्चों को गोली मार दिए जाने के बाद" क्या उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि औद्योगिक शांति की पुनःस्थापना के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिएँ, तो राकफेलर ने जवाब दिया कि "खनिकों की बात मानने के बजाय उनकी कम्पनी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हड़ताल का निबटारा करने का एकमात्र उपाय सब खानों का यूनियनीकरण है, किन्तु हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते क्यों कि "मज़दूरों के हितों में हमारी दिलचस्पी इतनी गहरी है और हमारा दृढ़ विश्वास है कि उस दिलचस्पी का यह तकाज़ा है कि कैम्प खुले कैम्प रहें और हम किसी भी हालत में अपने अफसरों का समर्थन करेंगे ।" उन्हें विशेष गुस्सा इस बात पर था कि बाहर के लोग आकर उन लोगों को उभाड़ने की कोशिश करें जो "अपने काम की हालतों से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं।" इस बारे में कोई आत्म-समर्पण नहीं किया जा सकता । राकफेलर ने कहा कि "इसी प्रकार के एक सिद्धान्त पर क्रांति की लड़ाई लड़ी गई थी। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किस्म का महान् राष्ट्रीय प्रश्न है।"

कर्मचारियों के संगठनों के निर्माण के कड़े विरोध का यह अकेला उदाहरण नहीं है और रोज़गार के लिए यूनियन से अलग रहने की शर्त रखने में अदालतों ने मालिकों का पक्षपोषण किया ।

१८९८ में कांग्रेस ने एक एर्डमैन अधिनियम पास किया था जिसमें अन्तर्राज्यीय रेलों द्वारा यूनियन की सदस्यता के कारण कर्मचारियों के खिलाफ भेद-भाव करने की मुमानियत की गई थी। १० वर्ष बाद अडेयर बनाम यूनाइटेड स्टेट्स के मामले में सुप्रीमकोर्ट ने एर्डमैन अधिनियम की इस धारा को व्यक्तिगत स्वाधीनता तथा सम्पत्ति के अधिकार दोनों पर चोट करने वाली बता कर उसे अवैध करार दिया। १९१५ में कौपेज बनाम कंसास के एक अन्य मामले में ऐसे ही एक अन्य कानून को भी सुप्रीमकोर्ट ने अवैध घोषित

कर दिया और उसके बाद वेस्ट वर्जीनिया में हिचमैन कोल ऐण्ड कोक कंपनी की प्रार्थना पर दिए गए एक निरोधादेश को बहाल रखा जिसमें युनाइटेड माइन वर्कर्स को "येलो डॉग करार" के मातहत यूनियन में शामिल न होने के लिए मजबूर किए गए कर्मचारियों को संगठित करने से मना किया गया था।

यूनियन के निर्माण में कानूनी बाधाओं की आलोचना सुप्रीमकोर्ट में भी हुई। न्यायाधीश ओलिवर वेण्डल होम्स ने इन बाधाओं से तीव्र असहमति व्यक्त की। कौपेज के मामले में उन्होंने कहा "वर्तमान अवस्थाओं में एक मज़दूर स्वभावतः यह समझ सकता है कि यूनियन से सम्बद्ध होकर ही वह अपने लिए एक न्यायोचित करार पा सकता है...। अगर कोई युक्तियुक्त आदमी यह विश्वास करता है तो मुझे लगता है कि उन पार्टियों को जिनमें करार की स्वाधीनता की शुरूआत होती है, समान स्थिति में लाने के लिए कानूनन इस पर अमल कराया जा सकता है। अन्ततोगत्वा इस प्रकार का कानून बनाना मज़दूरों के हित में होगा या नहीं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। किन्तु मेरा यह दृढ़ मत है कि अमरीका के संविधान में इसको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं है .....।" किन्तु सुप्रीमकोर्ट में उनके अन्य भाई उनकी युक्तियों से प्रभावित नहीं हुए। 'येलो डॉग' करारों को लागू करने के निर्णय तब तक कायम रहे जब तक कि १९३२ में नौरिस ला गार्दिया कानून बनने के साथ सरकार की नीति अन्ततः उलट नहीं गई।

यूनियनों द्वारा किए जाने वाले बहिष्कारों पर प्रत्याक्रमणों में भी अदालतों ने मालिकों का साथ दिया। अमरीकी मज़दूर संघ ने यूनियनों को मान्यता दिलाने में इस हथियार को बड़ा कारगर पाया था। अपने सदस्यों को यह कह कर कि वे उन मालिकों का माल न खरीदें जहाँ यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है, बहुत-से अक्खड़ मालिकों को सीधा कर दिया गया था। इस स्थिति का सामना करने के लिए एक अमेरिकन बायकाट विरोधी ऐसोसियेशन की स्थापना की गई जो मालिकों को इस आधार पर अदालतों में जाने में सहयोग देती थी कि इस प्रकार के बहिष्कार-व्यापार में रुकावट डालने वाले षड्यन्त्र हैं और सम्पत्ति के अधिकारों की "सम्भावित आशाओं" में 'द्वेषपूर्ण' बाधा डालने के कारण उन पर निरोधादेश लागू

किया जा सकता है। दो महत्त्वपूर्ण मामले जिनमें ये प्रश्न उलझे हुए थे, १६०२ और १६१६ के बीच अदालतों में खिचते रहे किन्तु जब उनका निर्णय हुआ तो दोनों में मज़दूरों की पूरी हार हुई।

१६०२ में युनाइटेड हैटर्स ने मान्यता प्राप्त करने के लिए एक स्थानीय यूनियन की हड़ताल के समर्थन में डैनवरी (कनेक्टिकट) की डी. इ. लोवे ऐण्ड कम्पनी के टोपों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी बहिष्कार घोषित किया था। कम्पनी ने तुरन्त ही युनाइटेड हैटर्स पर शर्मन अधिनियम की धाराओं को तोड़-कर व्यापार में बाधा उत्पन्न करने के षड्यंत्र का आरोप लगा कर मुकद्दमा चला दिया और स्थानीय यूनियन के हड़ताल करने वाले सदस्यों से व्यक्तिशः तिगुने हर्जाने का दावा किया। काफी अरसे तक कानूनी दाँव-पेंच चलते रहने के बाद १६१६ में कम्पनी की जीत हुई और उसका २,५२,००० डालर का हर्जाना स्वीकार किया गया। यूनियनों के सदस्यों का बैंकों में जो हिसाब था, वह कुर्क कर लिया गया; उनके मकानों को गिरवी से न छुटा सकने की प्रक्रिया जारी की गई किन्तु अन्त में जुर्माना राष्ट्रीय यूनियन और ए. एफ. एल. के चन्दों से अदा कर दिया गया।

डैनबरी हैटर्स के मामले से मज़दूरों में क्रोध की लहर फैल गई क्योंकि इससे गौण बहिष्कार भी शर्मन अधिनियम की पाबन्दी के अन्तर्गत आ गए और सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से हर्जाना लिया जा सकता था। किन्तु अमरीकी मज़दूर संघ अभी जब अदालतों की भूल-भुलैया में से अपना रास्ता निकाल रहा था तब वह स्वयं ही एक अन्य झगड़े में उलझ गया जिसके इससे भी व्यापक परिणाम हुए। १६०६ में सेण्ट लुई की बक्स स्टोव और रेंज कम्पनी के धातु पर पालिश करने वाले कर्मचारियों ने ६ घण्टे के दिन के लिए हड़ताल कर दी और सहायता की अपील की। ए. एफ. एल. ने अमेरिकन फेडरेशनिस्ट में कम्पनी को "हम इसका माल नहीं खरीदते" की सूची में रखकर और यूनियन के सब सदस्यों को उसके माल का बहिष्कार करने का आह्वान कर उसकी मदद की। बक्स स्टोव ऐण्ड रेंज कम्पनी तथा अमरीकी निर्माताओं के ऐसो-सियेशन दोनों के अध्यक्ष जे. डब्लू. वान क्लीव ने, जो सब यूनियनों का पक्का दुश्मन था, तुरन्त ही निरोधादेश प्राप्त कर लिया, जिसमें न केवल ए. एफ. एल. के अधिकारियों और सदस्यों को उसकी फ़र्म को "हम इसका माल नहीं

खरीदते" सूची में से निकाल देने का आदेश दिया गया बल्कि यह भी कहा
गया कि धातु पर पालिश करने वालों की हड़ताल की तरफ कुछ लिख कर या
मुँहज़बानी भी लोगों का ध्यान न खींचा जाए।

ए. एफ. एल. ने अदालत के इस व्यापक आदेश को मानने से इन्कार कर
दिया। गौम्पर्स ने कम्पनी का नाम यद्यपि सूची में से हटा लिया तो भी वह
यह कहता रहा कि यूनियन के सदस्यों को बक के स्टोव और रसोई का सामान
खरीदने को मजबूर नहीं किया जा सकता। इस पर उसे अदालत की मानहानि
करने का अपराधी पाया गया और एक वर्ष कैद की सजा दी गई। फेडरेशन
के दो अन्य अधिकारियों को भी अपराधी घोषित कर हलकी सज़ाएँ दी गईं।
किन्तु गौम्पर्स ने यह सजा कभी भुगती नहीं। वान क्लीव की मृत्यु के बाद
और मूल निरोधादेश वापस ले लिए जाने के बाद भी अदालती कार्रवाई चलती
रही किन्तु अन्त में केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके फलस्व-
रूप ए. एफ. एल. के नेता यद्यपि जेल जाने से बच गए तो भी उनका दण्डित
किया जाना एक बड़ा धक्का था जिसने निरोधादेश सम्बन्धी कानून के खिलाफ
मज़दूरों को पहले से भी ज्यादा उभार दिया। गौम्पर्स उस स्थिति को सहन नहीं
कर सका जब उसके रूढ़िवादी, मालिकों के दोस्त और मजदूर-क्रांति का
कट्टर दुश्मन होते हुए भी सरकार ने उस पर ऐसे आक्षेप किए मानो वह कोई
क्रांतिकारी या अराजकतावादी हो।

इन तथा अन्य निर्णयों से, जिसमें मालिकों को खूब खुलकर निरोधादेश
दिए गए, मज़दूरों को ऐसा लगा कि पुराने षड्यंत्र विरोधी कानून, जिनके
खिलाफ वे प्रायः संघर्ष करते रहे थे, फिर से जीवित किए जा रहे हैं। जो
सिद्धान्त दाँव पर लगे हुए थे उनका १९वीं सदी के प्रारम्भ के कानूनी मामलों
से बहुत सादृश्य था। मज़दूरों ने महसूस किया कि वे संगठन बनाने और हड़-
ताल करने के अपने बुनियादी अधिकारों के लिए अदालतों के खिलाफ लड़
रहे हैं जो यूनियन सम्बन्धी गतिविधियों को व्यापार में बाधा डालने वाली
बताकर उन पर प्रतिबन्ध लगाते हुए पूर्णतः मालिकों के कैम्प में चली गई हैं।
एक समय स्वीकृत इस सिद्धान्त का कि हड़तालों और बहिष्कारों के ज़रिये
सम्पत्ति के अधिकारों की संभावित क्षति काम की हालतों में सुधार करने के
मज़दूरों के वाजिब उद्देश्य की मात्र आनुषंगिक चीज़ है, उन परिस्थितियों में

प्रतिवाद किया जा रहा था जो यूनियनों के अस्तित्व तक को खतरे में डालने वाली प्रतीत हो रही थीं।

अमरीकी मज़दूर संघ ने इन प्रतिबन्धों से कानूनी राहत पाने की कोशिश करना जरूरी समझा। यह अब भी सीधा राजनीति में भाग नहीं लेना चाहता था और आर्थिक प्रणाली में सुधार की कोशिश करने का भी उसका कोई इरादा नहीं था। उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व का अपना कार्यक्रम अपनाए जाने के फिर से रखे गए समाजवादियों के प्रस्ताव को ठुकराते हुए गोम्पर्स ने १९०३ में कहा : "आर्थिक दृष्टि से तुम्हारी बात लाभदायक नहीं, सामाजिक दृष्टि से तुम गलत हो, औद्योगिक दृष्टि से तुम्हारी बात असंभव है।" और गोम्पर्स के इस कथन की २१४७ वोट के मुकाबले ११२८२ वोटों से पुष्टि कर दी गई। किन्तु यूनियनों को जिन बन्धनों में जकड़ दिया गया था उनसे किसी तरह उन्हें मुक्त करना था। संगठन बनाने, सामूहिक सौदेबाजी करने, हड़ताल व बहिष्कार करने तथा धरना देने के अधिकारों की रक्षा तात्कालिक चिन्ता का महत्त्वपूर्ण विषय बन गई।

इस प्रकार के उद्देश्यों के समर्थन में ज्यादा कारगर राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश में पहला कदम १९०६ में उठाया गया जबकि ए. एफ. एल. ने राष्ट्रपति और कांग्रेस को एक शिकायत-पत्र प्रस्तुत किया। इसमें वे अधिकांश परम्परागत मांगें शामिल थीं जो मज़दूर गृहयुद्ध के बाद से पेश करते आ रहे थे और देश भर में प्रगतिशील लोग जिन चीजों को बढ़ावा दे रहे थे, उनकी इसमें वकालत की गई थी। किन्तु इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण मांगें थीं—मज़दूर यूनियनों पर शर्मन अधिनियम लागू न किया जाए और निरोधादेश से राहत प्रदान की जाए, जिसे न्यायपालिका द्वारा विधानमण्डल के हड़पे जाने का प्रतीक बताया जाता था। शिकायत-पत्र में अन्त में कहा गया था : "हमने अपनी शिकायतें दूर करने के लिए चिरकाल तक व्यर्थ में प्रतीक्षा की है .... अब मज़दूर आप से अपील करते हैं और आशा करते हैं कि यह व्यर्थ नहीं जाएगी। किन्तु अगर किसी वजह से आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया तो हम समर्थन के लिए अपने साथी नागरिकों की अन्तरात्मा से अपील करेंगे।"

कांग्रेस ने मज़दूरों के प्रवक्ताओं की बात अनसुनी कर दी। मज़दूर जो

बिल पेश कराना चाहते थे, उन्हें दरगुजर कर दिए जाने या धत्ता बता दिए जाने पर ए. एफ. एल. ने १६०६ के कांग्रेस के चुनावों में सक्रिय भाग लिया। इसने न केवल यह अपील की कि मज़दूरों की आकाङ्क्षाओं के प्रति सद्भावना रखने वाले कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया जाए बल्कि जहाँ किसी भी दल ने कोई स्वीकार्य 'उम्मीदवार खड़ा' नहीं किया था वहाँ इसने एक ट्रेड्यूनियनिस्ट को खड़ा करने की सलाह दी। दो वर्ष बाद गौम्पर्स ने समर्थन के लिये दोनों पार्टियों के सम्मेलन से अपील की। रिपब्लिकनों ने तो उसकी पूर्णतः उपेक्षा कर दी किन्तु डेमोक्रैटों ने अपने कार्यक्रम में निरोधादेशो को हटवाना शामिल कर लिया। तब अमेरिकन फेडरेशनिस्ट ने विलियम होवार्ड टैफ्ट का, जिनपर निरोधादेश जारी करने वाला जज कहकर आक्षेप किया जाता था, खुल्लमखुल्ला विरोध करने का अगला कदम उठाया और निश्चित रूप से विलियम जेनिंग्स ब्रायन का समर्थन किया। जब टैफ्ट चुन लिये गये और रिपब्लिकन मज़दूरों की उपेक्षा करते रहे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि श्रमिकों ने डेमोक्रैटों का और ज्यादा समर्थन करना शुरू कर दिया है। १६१२ के चुनावों में यद्यपि ए. एफ. एल. टैफ्ट पर आक्षेप करता रहा तो भी रूज़वेल्ट और विल्सन के बीच उसने बड़ी सावधानी से तटस्थता का रवैया बनाए रखा।

गौम्पर्स ने इन राजनीतिक पैंतरेबाज़ियों की जोरदार वकालत की और कहा कि मज़दूरों के दोस्तों को पुरस्कृत करने और उसके दुश्मनों को दण्डित करने की ए. एफ. एल. की जो परम्परागत नीति चली आ रही है वह इनसे किसी भी प्रकार भंग नहीं होती। उसके कथनानुसार यूनियनों को वर्तमान प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए कानून की जरूरत है और इस विषय में रिपब्लिकनों की अपेक्षा डेमोक्रैटों का रवैया ज्यादा सहृदयता और सहानुभूति का रहा है। ए. एफ. एल. के मुखिया ने १६०८ में कहा : "इस समय एक राजनीतिक दल के समर्थन का अपने पवित्र कर्त्तव्य का निर्वाह करते हुए मज़दूर किसी एक पार्टी की तरफदारी नहीं बल्कि एक सिद्धान्त की तरफदारी कर रहे हैं।"

विल्सन की सरकार से पूर्व इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियाँ सफल रही हों, यह बहुत संदिग्ध है। राज्यों के विधानमण्डलों ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिनसे औद्योगिक श्रमिकों की, विशेषकर स्त्रियों व बच्चों की हालत

काफी सुधरी किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये कदम संगठित मज़दूरों के राजनीतिक दवाव के वशीभूत होकर नहीं वल्कि इस प्रगतिशील युग में सामाजिक दायित्व की भावना से प्रेरित होकर उठाए गए थे। ये मानवता की दृष्टि से उठाए गए थे। मज़दूरों के अधिकारों—यूनियन की मान्यता और सामूहिक सौदे-वाजी—से उतना सरोकार नहीं था जितना एक औद्योगिक-समाज के सामान्य पहलुओं से, जो इतनी अधिक गरीवी, वीमारी और जुर्मों को प्रश्रय देता है।

इसके अलावा मज़दूर यद्यपि इन सुधारों के समर्थक थे तो भी ए. एफ. एल. और गौम्पर्स की विचारधारा के अनुसार उनकी उन्हें बहुत चिन्ता नहीं थी। राज्य के प्रति शंकालु गौम्पर्स मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। उद्योग में स्त्री व बाल मज़दूरों की रक्षा के लिए वह कानून वनाए जाने का पक्षपाती था किन्तु वह नहीं चाहता था कि यूनियन के सदस्यों के लिए काम के घण्टे और वेतन कानून द्वारा निश्चित किए जाएँ। उसकी राय में मज़दूरों की काम की सामान्य हालतों में सुधार का एकमात्र उपाय संगठित श्रमिकों का आर्थिक दवाव था। राज्य से उसकी यही आकांक्षा थी कि वह इस प्रकार का दवाव डालने का मज़दूरों का अधिकार स्वीकार करें।

वस्तुतः अनुदार औद्योगिक नेताओं में स्वछन्द अर्थव्यवस्था का ए. एफ. एल. के मुखिया से वड़ा हिमायती और कोई न था। १९१५ में अमरीकन फेडरेशनिस्ट के एक अग्रलेख में गौम्पर्स ने इसकी जोरदार वकालत की और जिस वाक्यावली का उसने इस्तेमाल किया वह १९३० के दशक की राजनीतिक वहसों के प्रकाश में सुपरिचित सी प्रतीत होती है।

उसने सवाल किया : "हम किधर भटके जा रहे हैं ? अगर कपास के लिए कोई बाजार नहीं है तो कपास उगाने वाले कानून की माँग करते हैं। अगर वेतन कम हैं तो उसके लिए कानून या कमीशन का इलाज प्रस्तुत किया जाता है। इस मनोवृत्ति का परिणाम सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि लोगों का नैतिक चरित्र कमजोर हो जाए। जहाँ अपने जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने के किए जिम्मेदारी वहन करने की इच्छा का अभाव है वहीं एक दृढ़, ओजस्वी मेहनत माँगने वाली आजादी और संकल्प शक्ति नहीं

रह सकती...हम अमरीका के मजदूरों के जीवन, आचरण और आजादी की छानबीन, और नियम के लिए सरकार के हाथ में ज्यादा ताकत नहीं सौंपना चाहते।"

तो भी इस प्रगतिशील युग में किए गये आर्थिक और सामाजिक सुधार महत्त्वपूर्ण थे और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उससे मजदूरों को बहुत लाभ पहुँचा। १९१२ तक कोई ३८ राज्यों में बाल-श्रम के सम्बन्ध में कानून पास किए गए, जिनमें काम पर रखते समय बच्चों की आयु, उनके लिए काम के घण्टे और उनके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की देखभाल के नियम तय कर दिए गए और २८ राज्यों में महिला श्रमिकों के लिए काम के अधिकतम घण्टे नियत कर उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। १९१५ तक कम-से-कम ३५ राज्यों में मज़दूरों के लिए मुआवजे के कानून बना दिए गये जिनमें औद्योगिक दुर्घटनाओं की हालत में अनिवार्य मुआवज़े की व्यवस्था थी। ये उत्तरवर्ती कदम प्रायः अपर्याप्त थे और उन पर सदा कारगर ढंग से अमल नहीं होता था तो भी ये खानों व कारखानों में मज़दूरों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए मालिकों की जिम्मेदारी निश्चित करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति के द्योतक थे।

सामान्य अधिकतम घण्टे का कानून पास करने की भी शुरूआत हुई। राज्यों द्वारा इस प्रकार का कानून बनाए जाने की माँग पर, जो १८४० और फिर १८६० के दशक में खूब ज़ोरों से उठाई गई थी, मज़दूरों ने उतना ज़ोर नहीं दिया था, जितना इस पहले के जमाने में दिया गया था। काम के घण्टे कम करने के लिए यूनियनों ने कानून के बजाय सामूहिक सौदेबाजी पर ज्यादा निर्भर किया। किन्तु मज़दूर आन्दोलनों की वजह से नहीं बल्कि प्रगतिशीलता की भावना से कोई २५ राज्यों ने इस जमाने में ऐसे कानून बनाए जिनके द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिए काम के घण्टे सीमित कर दिए गए। अधिकतम घण्टों के पहले कानून से ये कानून इस चीज में बहुत भिन्न थे कि "विशिष्ट करारों" को मुक्त रखने की धारा अंतिम रूप से निकाल दी गई। राज्यों के काम के घण्टों से संबन्धित कानून पहली बार अमल में लाए जा सके।

शुरू में अदालतों ने मजदूर सम्बन्धी अधिकांश कानूनों को पास होने से रोक दिया था। उनकी दलील थी कि राज्य अपनी पुलिस-सत्ता का उपयोग

इस हद तक नहीं कर सकती कि या तो वह मालिक के सम्पत्ति के अधिकार में दस्तंदाजी करे या अपनी इच्छानुसार कैसा भी करार करने की मज़दूर की व्यक्तिगत स्वाधीनता में बाधा डाले। सन् १९०५ में लोकनर बनाम न्यूयार्क केस में, जिसमें बेकरी कर्मचारियों के लिए काम के अधिकतम घण्टों के नियमन को अवैधानिक करार दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि १४वें संशोधन की उचित प्रक्रिया सम्बन्धी धारा में दी गई स्वाधीनता की गारण्टी से इस प्रकार का कानून बनाए जाने पर प्रतिबन्ध है। किन्तु अदालत ने शनैः-शनैः वैधानिक संरक्षणों की अधिक उदार व्याख्या करनी शुरू कर दी और अन्त में उसने पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिए काम के अधिकतम घण्टों के नियमन को उचित ठहराया और मज़दूरों को मुआवज़ा दिए जाने के नए कानून को भी स्वीकार कर लिया। किन्तु इसके बाद जब न्यूनतम वेतन सम्बन्धी कानून बनाने की कोशिश की गई तब सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के कानून की वैधानिकता के बारे में बराबर वजन के दो मत हो गए और सात राज्यों में जिस रूप में ये कानून पास किए गये उसकी वैधानिकता संदिग्ध बनी रही। यह मामला फिर १९२३ तक निर्णय के लिए नहीं आया और तब ऐडकिन्स बनाम चिल्ड्रन्स हौस्पिटल के मामले में कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वेतनों पर पाबन्दियाँ करार की स्वाधीनता से मेल नहीं खातीं। यह निर्णय १९३७ तक कायम रहा जब कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्ततः यह स्वीकार कर लिया कि रोजगार की वर्तमान परिस्थितियों में करार की स्वाधीनता एक काल्पनिक चीज है और वह काम के घण्टे या वेतन निश्चित करने के बारे में मज़दूर की व्यक्तिगत स्वाधीनता की किसी भी प्रकार रक्षा नहीं करती।

सामान्यतः औद्योगिक कर्मचारियों के पक्ष में राज्यों के कानून यद्यपि वृद्धावस्था की पेंशन और बेकारी के बीमे के मामले में समकालीन यूरोपीय परीक्षणों से अब भी बहुत पीछे थे फिर भी रूज़वेल्ट और टैफ्ट के प्रशासन में उन्होंने पर्याप्त उपलब्धियाँ हासिल कीं। जैसा कि कहा जा चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर सन्तोष नहीं किया जा सकता था। १९०६ में ए० एफ० एल० ने जो शिकायत-पत्र प्रस्तुत किया था उस पर लगता था कि प्रतिनिधि-सभा और सेनेट दोनों में विरोधी रुख रखने वाली समितियों ने विचार करना सदा के लिए मुल्तवी कर दिया था। यूनियन की सुरक्षा के लिए इसमें सुझाई गई

सामान्य बातों को कानूनी रूप देने में कोई प्रगति नहीं हुई। जैसा कि अनेक मामलों में की गई कार्रवाई से जाहिर हुआ, शर्मन अधिनियम के अन्तर्गत निरोधादेश और यूनियनों का उत्पीड़न मजदूरों के दुश्मनों के हाथ में उत्तरोत्तर शक्तिशाली हथियार बनते चले गए। १९१० में चुनी गई डैमोक्रैटिक प्रतिनिधि-सभा का रवैया मजदूरों के प्रति अधिक अनुकूल रुख का पहला संकेत था। अन्त में सरकारी कार्यों में ८ घण्टे के दिन का कानून पास किया गया, "औद्योगिक स्थिति में असन्तोष के मूल कारणों की जाँच के लिए" एक औद्योगिक सम्बन्ध आयोग स्थापित किया गया और एक श्रम-विभाग की स्थापना की व्यवस्था की गई जिसका उद्देश्य विशेष रूप से मजदूरों के हितों को बढ़ावा देना था। किन्तु राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिक व्यापक कानून बनाए जाने का जहाँ तक सवाल है, वास्तविक मोड़ बिन्दु सन् १९१२ के चुनाव तक नहीं आया।

विलसन ने "नई स्वाधीनता" में मालिकों और कर्मचारियों के आपसी सम्बन्धों के बारे में प्रचलित कानूनों को "गए-बीते और असम्भव" बताकर उनकी निन्दा की। कांग्रेस में उनके उद्घाटन भाषण में ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता पर और बल दिया गया जो न केवल मजदूरों के जीवन को सुरक्षा प्रदान करने वाला, उनके काम की हालतों में सुधार करने वाला और काम के युक्तियुक्त और सह्य घण्टे नियत करने वाला हो, बल्कि उन्हें "अपने हित में कार्य करने की स्वाधीनता" देने वाला भी हो। उन्होंने प्रतिवाद किया कि इस प्रकार के कानून को 'वर्गीय' कानून कहा जा सकता है और बताया कि वे समस्त लोगों के हित में है। अपनी स्थिति की इस प्रकार से वकालत किए जाने पर मजदूरों को खुशी हुई और विश्वासपूर्वक वे यह आशा करने लगे कि निरोधादेशों और षड्यन्त्र सम्बन्धी अभियोगों के बारे में सुधार करने वाले कुछ कानून पास होंगे जिनके लिए वे चिरकाल से असफल प्रयत्न करते आ रहे थे। गौम्पर्स ने कहा : "हम अब जंगल में नहीं भटक रहे। अब हम सिर्फ पौध लगाने की मौसम में नहीं हैं, हम फसल काटने की मौसम में हैं।"

कुछ अरसे तक तो यह आशावाद फलीभूत होता दिखाई दिया। १९१४ में कांग्रेस ने क्लेटन अधिनियम पास किया जिसने पहले के ट्रस्ट विरोधी कानूनों को मजबूत किया और मजदूरों के अधिकारों से सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण

धाराएँ शामिल कीं। इसमें विशेष रूप से घोषित करते हुए कि "मनुष्य का श्रम सौदे की वस्तु नहीं है," कहा गया कि ट्रस्ट विरोधी कानून में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह यूनियन बनाने से मना करता है, यूनियनों को अपने वाजिब कार्य करने से "कानूनन" रोकता है या उन्हें वाणिज्य में बाधा डालने वाला गैरकानूनी साँठ-गाँठ समझता है। इससे भी बढ़ कर इसमें मालिकों और कर्मचारियों के झगड़े में निरोधादेश का प्रयोग गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया, "बशर्ते कि सम्पत्ति के अधिकार की अपूरणीयक्षति को जिसकी पूर्ति के लिए कानून में कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, रोकने के लिए निरोधादेश जारी करना जरूरी न हो।"

गौम्पर्स ने इस कानून को मजदूरों का 'महाधिकार-पत्र' कहकर और संगठन करने, सामूहिक सौदेबाजी करने, हड़ताल करने, बहिष्कार करने, और घरना देने के मज़दूरों के अधिकारों की अंतिम गारण्टी कहकर इसका स्वागत किया। नए कानून की प्रभावशालिता के बारे में अन्यों की राय भिन्न थी। वाल स्ट्रीट जर्नल ने यद्यपि कांग्रेस को..."मज़दूर अधिपति द्वारा अपना अंगूठा झुकाए जाने की प्रतीक्षा करते हुए डरपोक कायरों की समवेत भीड़" बताया तो भी अनेक अखबारों के अग्रलेखों में, और राजनीतिक नेताओं तथा कुछ मज़दूर प्रवक्ताओं के वक्तव्यों में भी यह बताया गया कि क्लेटन अधिनियम की सावधानतापूर्ण शब्दावली जाहिर करती है कि मजदूरों ने वस्तुतः कोई नए अधिकार प्राप्त नहीं किए हैं और निराधादेशों को वाकई गैरकानूनी घोषित नहीं किया गया है। किन्तु गौम्पर्स इन सब व्यावहारिक व्याख्याओं की उपेक्षा कर उसे मज़दूरों की एक महान् विजय कहता रहा और इस खुशखबरी को सर्वत्र फैलाता रहा। शायद अपनी अब तक की नीतियों का औचित्य ठहराने और ए. एफ. एल. की प्रतिष्ठा के निर्माण के लिए वह यूनियनों द्वारा सिद्धान्ततः प्राप्त की गई पूर्ण स्वाधीनता में किसी भी सन्देह को मानने के लिए तैयार नहीं था।

किन्तु जिन्हें शंका थी, वे शीघ्र ही ठीक साबित हो गए क्लेटन अधिनियम जब अदालत की कसौटी पर कसा गया तो उसमें दी गई गारण्टी मृग मरीचिका ही सिद्ध हुई। ट्रस्ट विरोधी कानूनों से यूनियन की काल्पनिक मुक्ति में छलछिद्र निकाले गए; निरोधादेश के उपयोग के बारे में की गई व्यवस्थाओं की इस

ढंग से व्याख्या की गई कि वस्तुतः कोई राहत न मिले। 'मजदूर कोई सौदे की वस्तु नहीं है', इस सिद्धान्त का बखान कायम रहा और लोगों का रवैया तबदील करने में वस्तुतः इसका महत्त्व था किन्तु मालिक-कर्मचारियों के सम्बन्धों पर उसका कोई क्रियात्मक प्रभाव नहीं हुआ।

तो भी विल्सन की हुकूमत में मज़दूरों ने पर्याप्त लाभ प्राप्त किए और क्लेटन अधिनियम की बाद में की गई व्याख्याओं के बावजूद इन वर्षों में संगठित मज़दूर अनेक मोर्चों पर आगे बढ़ रहे थे। तीन महत्त्वपूर्ण मामलों पर उन्हें विधानमण्डल का सहयोग प्राप्त हुआ। १९१५ में ला फोलेट सीमेंस ऐक्ट पास होने से नाविकों की भरती में बहुत सी गड़बड़ियाँ दूर हो गयीं और अमरीकी व्यापारिक जहाजों में डेक पर काम करने वाले लोगों की हालत में अपरिमित सुधार हुआ। अगले वर्ष ऐडम्सन ऐक्ट द्वारा सब अन्तर्राज्यीय रेल-कर्मचारियों के लिए ८ घण्टे का दिन तथा ड्यौढ़ा ओवरटाइम नियत करके काम के कम घण्टों की रेल-कर्मचारियों की माँग पूरी कर दी गई और १९१७ में यूरोपीय आव्रजकों की साक्षरता की परीक्षा के लिए कांग्रेस द्वारा बनाया गया कानून आव्रजन को मर्यादित करने की नीति की ओर जिसकी मजदूर इतने अरसे से माँग कर रहे थे, पहला कदम था।

मजदूर यूनियनों का विकास नई सदी की पहली दशाब्दि में १९०४ में जारी किए गए औद्योगिक प्रत्याक्रमण से अस्थायी रूप से रुक गया था। अमरीकी मजदूर संघ के सदस्यों की संख्या १९०५ में घट गई और अगले ५ वर्ष तक उतनी ही रही। १९१० में इसके सदस्यों की संख्या ६ वर्ष पूर्व १६,७६,००० के मुकाबले सिर्फ १५,६२,००० थी। किन्तु १९१० और १९१७ के बीच ए. एफ. एल. के ८ लाख नए सदस्य बने और ट्रेड यूनियनों के सदस्यों की कुल संख्या ३० लाख हो गई। सदी के प्रारम्भ के मुकाबले यह करीब चौगुनी थी।

अन्य समयों की भांति इस समय में भी यूनियनों में शामिल होने की प्रेरणा सिर्फ सामूहिक सौदेबाजी के ज़रिये आर्थिक स्थिति सुधारने की आशा से ही नहीं मिली 'मुझे अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी, मेरे साथ अच्छा बर्ताव होगा और मनमाने अनुशासन से मुझे संरक्षण मिलेगा', इस प्रकार की आशाएँ भी

बहुत महत्त्वपूर्ण थीं किन्तु व्यक्तिगत रूप से मजदूरों की यह प्रच्छन्न अभिलाषा भी रही कि औद्योगिक समाज में वह अपनी वैयक्तिक कीमत तथा महत्त्व को और बढ़ाए। मशीनें मज़दूर को उस प्रक्रिया में अधिकाधिक एक पुर्जा मात्र बनाती जा रही थीं जिस पर मजदूर का कोई प्रभाव या नियंत्रण नहीं था। कम्पनी-कारोबार में जब वैयक्तिक सम्पर्क बिल्कुल जाता रहा और प्रबन्धक कर्मचारियों से बहुत दूर-दूर रहने लगे तो मज़दूर की वैयक्तिक हैसियत और खत्म हो गई। वह मज़दूर यूनियन जैसे सार्थक सामाजिक संगठन में सदस्य बनकर सन्तोष पा सकता था जो उसे हज़ारों व्यक्तित्वहीन कर्मचारियों के बीच प्राप्य नहीं था। इस प्रगतिशील युग में किसी ग्रुप की गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा बहुत प्रबल थी। इस ज़माने में सामाजिक क्लबों, निवासों और भ्रातृमण्डलों का तेजी से विकास हुआ। यूनियनें, जिनमें भ्रातृनिवासों की कुछ विशेषताएँ शामिल थीं, सामूहिक सौदेबाजी के लिए सहयोग देने के अलावा इस दूसरी आवश्यकता को भी पूरा करती थीं।

कुछ भी हो यूनियनों की सदस्य संख्या में वृद्धि दोनों प्रकार से हुई, पुरानी यूनियनों के सदस्य बढ़े तथा नई यूनियनें कायम हुईं। युनाइटेड माइन वर्कर्स के ३,३४,००० सदस्य हो गए थे और वह देश में सबसे शक्तिशाली यूनियन थी। इमारती व्यवसाय में यूनियन सदस्य, जिनमें खाती, पेण्टर, राज और मिस्त्री शामिल थे, ३ लाख से अधिक थे और संगठित श्रमिकों में एक महत्त्वपूर्ण योग पोशाक कर्मचारियों की यूनियन का हुआ था।

न्यूयार्क के शर्टवेस्ट (कमर तक की कमीज) बनाने वालों में "२० हज़ार के विद्रोह" से इस उद्योग में यूनियन सम्बन्धी गतिविधियों को बहुत प्रोत्साहन मिला। १६०६ की पतझड़ में यह हड़ताल मजदूरों से बहुत थोड़ी मज़दूरी पर अत्यधिक काम लिए जाने वाली दूकानों में असह्य परिस्थितियों को इतने सनसनीखेज ढंग से सामने लाई कि लोगों की सहानुभूति पूर्णतः हड़तालियों के पक्ष में हो गई। इण्टरनेशनल लेडीज़ गारमेण्ट वर्कर्स के नेतृत्व में 'बन्दशाप' के अलावा वे अपनी सब माँगें मनवाने में कामयाब हुए। किन्तु यह हड़ताल अगले वर्ष होने वाले एक अन्य संघर्ष की भूमिका थी। यह संघर्ष चोगा व सूट उद्योग में पैदा हुआ, जहाँ काम की हालतें और भी ज्यादा खराब थीं। ये ज्यादातर असंगठित थे किन्तु इन्टरनेशनल लेडीज़ गारमेण्ट वर्कर्स यूनियन ने इसका नेतृत्व

किया। लुई डी. ब्रैण्डीज़ की, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के सह-न्यायाधीश बने, मध्यस्थता में पुन: एक अनुकूल समझौता कर लिया गया। पोशाक कर्मचारियों ने न केवल अपनी वेतन और घण्टे की माँगें मनवालीं बल्कि मालिकों से एक 'दस्तूर' भी मनवा लिया जिसके मातहत भावी झगड़ों को शांति से निबटाने के लिये एक मशीनरी कायम कर दी गई। इण्टरनेशनल लेडीज़ गारमेण्ट वर्कर्स देश की एक सबसे मजबूत तथा अध्यवसायी यूनियन बन गई। इसमें ज़्यादा-तर आव्रजक लोग थे और उनमें भी स्त्रियों की संख्या अधिक थी। इसका दृष्टिकोण कुछ-कुछ समाजवादी था और उसे अपने व्यक्तिगत सदस्यों के कल्याण की बहुत चिन्ता थी।

पुरुषों के कपड़े बनाने वाले कर्मचारियों की मुख्य यूनियन चिरकाल तक युनाइटेड गारमेण्ट वर्कर्स रही। १९१४ में आन्तरिक झगड़ों की वजह से इसके अधिकांश सदस्य ए. एफ. एल. से अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र यूनियन ऐमलगमेटेड क्लोदिंग वर्कर्स बनाली। इस यूनियन की शक्ति भी शनैः-शनैः बढ़ती रही और उद्योग के सब बड़े केन्द्रों में यह निर्माताओं के साथ समझौते करने में कामयाब रही। इण्टरनेशनल लेडीज़ गारमेण्ट वर्कर्स यूनियन की तरह यह भी सिद्धान्ततः समाजवादी थी किन्तु इसकी दैनिक नीति रचनात्मक व उदार नेतृत्व के मातहत मालिकों से उत्तरोत्तर अधिक सहयोग करने की थी।

युनाइटेड माइन वर्कर्स, इण्टरनेशनल लेडीज़ गारमेण्ट वर्कर्स यूनियन और ऐमलगमेटेड क्लोदिंग वर्कर्स औद्योगिक यूनियनें थीं, जिनके सदस्यों में उन सब उद्योगों के कर्मचारी शामिल थे जिनका वे प्रतिनिधित्व करती थीं। किन्तु ये मज़दूर संगठन के सामान्य नियम की अपवाद ही रहीं। इस्पात, मोटरगाड़ी, कृषि-मशीन, बिजली का सामान, सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं, तम्बाकू तथा मांस पैक करने के उद्योगों में कोई जरा भी महत्त्व की यूनियन नहीं थी। देश के आर्थिक विकास में जो उद्योग महत्त्वपूर्ण बनते जा रहे थे, और जिनमें अधिकांश औद्योगिक कर्मचारी काम कर रहे थे, वे इन वर्षों की मज़दूर हलचलों से अप्रभावित रहे क्योंकि इन हर नियंत्रण रखने वाले कार्पोरेशन यूनियनों के सख्त खिलाफ थे और इतने शक्तिशाली थे कि उनके कर्मचारियों को संगठित करने के हर प्रयत्न की विफलता निश्चित थी।

सामूहिक उत्पादन के इन उद्योगों में मजदूरों के लिए कम वेतन और काम के अधिक घण्टे बने रहना ही इस प्रगतिशील युग में मजदूरों की उपलब्धियों के एकसार न होने का सबसे बड़ा कारण था। इस वक्त के सामाजिक कानूनों ए. एफ. एल की यूनियनों के दक्ष कर्मचारी सदस्यों की वेतन-वृद्धि और यूनियनों के प्रति जनता के रुख और नीति में परिवर्तन का हर्षोत्पादक रिकार्ड असंगठित औद्योगिक कर्मचारियों की, जिनकी संख्या अब भी कुल मजदूरों की ९० प्रतिशत थी, विशाल भीड़ की दुःखदायी परिस्थितियों के कारण बहुत आकर्षक दिखाई नहीं देता था।

—:o:—

१२ : वाम-पक्षियों का गर्जन-तर्जन

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय यूनियनों में मजदूर जहाँ उस आर्थिक प्रणाली को स्वीकार करने के लिए सामान्यतः इच्छुक थे जिसके अन्दर वे शनैः-शनैः किन्तु निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करते प्रतीत हो रहे थे, वहाँ इस प्रगतिशील युग में ट्रेड यूनियनों से बाहर के मजदूरों में गहरे असन्तोष की चिन्ताजनक लहरें हिलोरें ले रही थीं। औद्योगिक लाइनों पर या सब मज़दूरों को शामिल करने वाली यूनियनों के निर्माण की, जैसी कि नाइट्स आव लेबर थी, नए सिरे से मांग की जाने लगी; समाजवाद के अनुयायियों की ताकत बढ़ी, और उन्होंने एक प्रभावशाली राजनीतिक दल बनाने के प्रयत्न दुगने जोर से शुरू कर दिए। विस्तृत होते जाने वाले अर्थतन्त्र में उठाए गए लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त करने के हेतु सीधी कार्रवाई के लिए असंगठित मज़दूरों में क्रान्तिकारी आन्दोलन पनपने लगा।

रूज़वेल्ट ने सन् १९०६ में कुछ आतंकित होकर हेनरी कैवट लाज को एक पत्र में लिखा : "मजदूर बहुत अभद्र हैं और कोई नहीं कह सकता कि यह असन्तोष कहाँ तक फैलेगा। पिछले ६-८ वर्षों में मजदूरों में समाजवादी और क्रान्तिकारी भावना बढ़ी है और मजदूर नेता अपना नेतृत्व छिन जाने के भय से इस या उस का राग आलापते फिरते हैं।"

जिस जमाने में देश की भावना स्फूर्तिमान विश्वास की हो और लोगों की सामान्यतः इतनी तरक्की होने जा रही हो उसमें, क्रांतिकारी भावनाओं का उभार कुछ असंगत-सी बात लगती है। किन्तु यह इस चीज का सीधा परिणाम था कि अदक्ष मजदूरों के हितों की किस हद तक उपेक्षा की जा रही थी। ए. एफ. एल. ने जब औद्योगिक संगठन की उपेक्षा की और हर क्रान्तिकारी आन्दोलन का उसने वैसे ही दृढ़ता से मुकाबला किया जैसा स्वयं उद्योग का तो असन्तोष के शोले और भी जोर से भड़के। क्रान्तिकारी एजन्टों के लिए, जिनका उद्देश्य, वेतन-प्रणाली की तुरन्त समाप्ति और पूँजीवाद का पूर्ण विनाश था, एक उपयुक्त आधार मिल गया। कुछ समय

तक लगा कि यह आन्दोलन समस्त मज़दूर-आन्दोलन की स्थिरता और रूढ़िवादिता को ख़तरा पैदा कर देगा। इसमें सबसे अग्रणी था 'इण्डस्ट्रियल वर्कर्स आव दि वर्ल्ड'।

पश्चिम में खनिक, काष्ठ श्रमिक और फसल काटने वाले खानाबदोश इस नई ऐसोसियेशन की स्थापना के लिए पूर्व के असंगठित कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व के समाजवादी ग्रुपों से मिल गए। आई. डब्लू. डब्लू. ने इस बात को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि श्रमिकों और मालिकों के बीच मेल खाने वाली कोई चीज़ है। ए. एफ. एल. और समस्त ट्रेड यूनियनवाद की नीतियों पर घोर आक्षेप करते हुए उन्होंने मज़दूरों को उत्पादन की मशीनों पर अपना अधिकार कर लेने के लिए आह्वान किया।

'उचित दिन के काम के लिए उचित दिन का वेतन' के रूढ़िवादी नारे के बजाय उनके घोषणा-पत्र में यह नारा दिया गया: "हमें अपने झण्डे पर 'वेतन प्रणाली का उन्मूलन' यह क्रान्तिकारी नारा अंकित करना चाहिए। पूँजीवाद का खात्मा करना मज़दूरों का ऐतिहासिक मिशन है।"

आई. डब्लू. डब्लू. (इण्डस्ट्रियल वर्कर्स आव दि वर्ल्ड) का जन्म १९०५ में शिकागो में एक गुप्त सभा में हुआ जिसमें मज़दूर आन्दोलन के सब क्रान्तिकारी और विद्रोही तत्त्व शामिल हुए। ये उग्र पश्चिमी खनिक, विभिन्न विचारों के समाजवादी, औद्योगिक यूनियनवाद के हिमायती और सीधी कार्रवाई के अराजकतावादी व्याख्याता अपने मतभेद दूर करके पूँजीवाद पर सीधा हमला करने के लिए एक हो गए। बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध किया कि ए. एफ. एल. के कार्यक्रम और तौर-तरीकों से घृणा करने के अलावा वे अन्य किसी बात में एक नहीं थे। किन्तु इस वर्ग-संघर्ष को अपना प्रारम्भिक कार्य-बिन्दु स्वीकार करके उन्होंने एक ऐसे आर्थिक संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य मज़दूरों की अन्तिम मुक्ति के लिए राजनीतिक व औद्योगिक दोनों मंचों पर काम करना था।

आई. डब्लू. डब्लू. के पीछे सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रुप वेस्टर्न फेडरेशन आव माइनर्स का था। पहले कभी यह ए. एफ. एल. से सम्बद्ध था किन्तु मज़दूरों ध्येय के साथ दुर्बल पूर्व की गद्दारी से कुपित होकर १८९७ में उससे अलग

और गौम्पर्स को जब तब "मज़दूरों को धोखा देने वाला," "एक जाल में फंसा ठग" और "वाल स्ट्रीट का चिकना औजार" कहा करता था। किन्तु समाजवादी कैम्प में एकता सम्भव नहीं थी और १६०० में इसके सदस्यों में फूट पड़ जाने से अन्य अनेक पार्टिया बन गई जो किसी न किसी रूप में समाजवादी विचारों पर बल देती थीं। इस वर्ग ने, जिसे सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी के नाम से पुकारा जाता था, अपने किसी भी पूर्ववर्ती की अपेक्षा अपना ज्यादा प्रभाव डाला और प्रगतिशील युग के राष्ट्रपति के चुनावों में यूजीन वी. डेब्स के नेतृत्व में उसने भारी संख्या में वोट प्राप्त किए। सोशलिस्ट लेबर पार्टी तथा सोशलिस्ट पार्टी में स्वभावतः संघर्ष रहता था किन्तु इसकी वजह से नेताओं का शिकागो आना नहीं रुका।

यद्यपि अमेरिकन लेबर यूनियन, यूनाइटेड मैटल वर्कर्स और यूनाइटेड ब्रादरहुड ऑव रेलवे एम्पलायीज़ समेत अन्य स्वतंत्र रैडिकल यूनियनों का सम्मेलन में प्रतिनिधित्व था तो भी आई. डब्लू. डब्लू. की स्थापना के लिए संगठनों के वजाय व्यक्ति मुख्य रूप से जिम्मेदार थे और उनके विभिन्न व्यक्तियों में संघर्ष से सम्मेलन में जान आ गई थी। डिलियोन और डेब्स के अतिरिक्त सम्मेलन में आए अन्य प्रतिनिधियों में वेस्टर्न फेडरेशन आव माइनर्स के विलियम डी. हेवुड, एक बड़ी, काली दाढ़ी वाले कैथोलिक पादरी फादर टी. जे. हैगर्टो जो अमेरिकन लेबर यूनियन के मुखपत्र के सम्पादक और औद्योगिक यूनियनवाद के प्रबल हिमायती थे, समाजवादी विद्वान् तथा इण्टर नेशनल सोशलिस्ट रिव्यू के सम्पादक ए. एम. साइमन्स, यूनाइटेड मेटल वर्कर्स के महामंत्री चार्ल्स ओ. शेरमान, यूनाइटेड ब्रीवरी वर्कर्स के रैडिकल नेता तथा इसके जर्मन भाषा के-पत्र के सम्पादक विलियम ई. ट्राउटमान और एक तेजस्वी, अविचल, ७५ वर्ष की छोटे कद की घुँघराले सफेदबालों वाली, राखी रंग की दयालु आँखों वाली मदर जोन्स नाम की एक महिला, शामिल थी। आन्दोलनकारी के रूप में इस महिला के उत्साह ने उसे करीब आधी सदी तक मज़दूरों के मोर्चे की अगली पंक्ति में रखा।

इन विविध और आकर्षक व्यक्तियों में सबसे ज्यादा ध्यान हेवुड पर जाता था। विशालकाय, झुके कन्धों वाला, दैत्याकार, एक आँख जाते रहने से ...वना-सा प्रतीत होने वाला 'बिग बिल' हेवुड सीमान्त भावना का शक्ति-

शाली और आक्रामक प्रतीक था। वह चरवाहा, मकान बनाने वाला और खनिक रह चुका था किन्तु सदी की समाप्ति तक सिल्वर क्रीक (इदाहो) की खानें छोड़ कर मज़दूरों और सोशलिस्ट पार्टी का सक्रिय संगठनकर्ता बन गया था। "आदिमकालीन स्वभाव का गट्ठर" कलाए जाने वाला हेवुड हिंसा को मज़दूर संघर्ष का आवश्यक अंग मानता था। वह स्पष्टतः सीधी कार्रवाई के पक्ष में था। आइ. डब्लू. डब्लू. को पहला सम्मेलन बुलाने के लिए कहे जाने पर हेवुड ने उसमें भाषण देते हुए उसे "मज़दूरों की महाद्वीपीय कांग्रेस" बतलाया और शुरू से ही उसने यह स्पष्ट कर दिया कि उसे वास्तविक दिलचस्पी भुलाए-बिसराए अदक्ष श्रमिकों और विशेषकर पश्चिम के खानाबदोश मज़दूरों—"आवारा" और "जीवट वाले लांछित" लोगों का संगठन करने में है। हेवुड ने ऊँचे स्वर में कहा: "हम मज़दूरों के विशाल समुदाय तक पहुँच कर उन्हें एक अच्छे जीवनस्तर तक लाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं।"

हेवुड को छोड़कर सम्मेलन के अन्य प्रतिनिधि आई. डब्लू. डब्लू. में अपने बहुत थोड़े से ही अनुयायियों को शामिल करा सके। वे सिर्फ अपना ही प्रतिनिधित्व करते थे और श्रम संबन्धी नीति पर उनका व्यक्तिवादी रुख सम्मेलन की बहस के रोमांच में बेमेल प्रतीत होता था। इसे 'अमरीकी मज़दूरों का विभाजन' (अमेरिकन सेपरेशन आव लेबर) कहकर इसका खुला विरोध करने के बावजूद वे आइ. डब्लू. डब्लू. के सामान्य कार्यक्रम पर सहमत हो गए।

गौम्पर्स वामपक्षियों की इन चालों से और फिर से एक ऐसा मज़दूर संगठन कायम करने की कोशिश से, घृणा करता था जिसकी वह "हेत्वाभासपूर्ण हानिकारक और प्रतिक्रियावादी" कहकर घोर निन्दा किया करता था। उसने विशेष रूप से अपने पुराने शत्रु डि लियोन पर प्रहार किया जिसके बारे में वह आशा करता था कि उसके अनुयायी आई. डब्लू. डब्लू. में शामिल होने वाले अन्य लोगों का 'आत्मा को आनन्द प्रदान करेंगे"। उसने लिखा: "इस प्रकार बाहर से ट्रेड यूनियनों के प्रहारकर्त्ता और हिंसात्मक हड़ताल करने वाले और "अन्दर से छेद करने वाले" फिर हाथ मिला रहे हैं, 'डाकुओं' और 'कंगारूओं' का अपने अपने शिकार पर खुश होकर परस्पर गले मिलने का क्या ही सुखद दृश्य है।"

उसका यह विश्वास कि ये विचित्र साथी ज्यादा देर तक साथ-साथ काम नहीं कर सकते, शीघ्र ही सच्चा निकलता दिखाई दिया। दलबन्दी और विवाद से आइ. डब्लू. डब्लू में करीब-करीब तुरन्त ही फूट पड़ गई। १६०६ के सम्मेलन में अपेक्षाकृत अधिक नरम तत्वों, जिनमें मुख्य सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे और सीधे क्रांति कर देने के हामियों में संघर्ष पैदा हो जाने से सब दक्षिण-पन्थी इस संगठन से अलग हो गए। अगले वर्ष स्वयं वेस्टर्न फेडरेशन आव माइनर्स इससे अलग हो गया और आइ. डब्लू. डब्लू. के सदस्य ६००० से भी कम रह गए और १६०८ में राजनीतिक या आर्थिक कार्रवाई के बुनियादी मामले पर अंतिम संघर्ष छिड़ गया। पहली नीति के समर्थक ग्रुप का नेता डि लियोन और दूसरी नीति के समर्थक ग्रुप का नेता ट्राडटमान था। किन्तु सम्मेलन में निर्णायक तत्त्व पश्चिमी विद्रोहियों—"ओवर आल्स ब्रिगेड" का एक प्रतिनिधिमण्डल था जो माल के डिब्बों में सवार होकर शिकागो आया था और जिसे सैद्धान्तिक विवादों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी।

इस दल ने डि लियोन के अनुयायियों को बाहर निकाल दिया, जिन्होंने तुरन्त एक दूसरा सम्मेलन बुलाकर एक नया संगठन बना लिया और तब वह शिकागो संविधान को अपनी इच्छानुसार बदलने लगा। राजनीति के अस्त्र का प्रयोग करने का ख्याल बिल्कुल छोड़ दिया गया। सीधी आर्थिक कार्रवाई से पूंजीवाद को उलट देने का लक्ष्य रखा गया। सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में क्रांतिकारिता को, हड़ताल, विध्वंस और हिंसा को अपना कर आई. डब्लू. डब्लू. ने मज़दूरों के दुश्मनों के साथ शांति कभी भी स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा की।

अब यह घोषणा की गई कि सभी व्यवसायों की एक बड़ी यूनियन बनाकर ही मज़दूर वर्ग संघर्ष में तगड़ा मोर्चा ले सकते हैं। ए. एफ. एल. ने मज़दूरों के साथ दग़ा किया है और वह मालिकों के पूर्ण प्रभुत्व में है।

आइ. डब्लू. डब्लू. के सदस्य गाते: "उन्हें बांध दो"

पुराने ए. एफ. एल. के भाइयों से हमारी कोई लड़ाई नहीं
किन्तु हम तुमसे कहते हैं कि जो तथ्य हम तुम्हें बताएँ
उन पर तुम अक्ल से सोचो

वाम-पक्षियों का गर्जन-तर्जन

तुम्हारी कारीगरी एक प्रकार की सम्पत्ति के लिए
संरक्षण है।
क्या तुम देखते नहीं कि तुम् अपनी दक्षता
खो रहे हो
मशीनों में सुधार तुम्हारी दक्षता और औजारों
को हर लेगा
और किसी दिन तुम भी सामान्य गुलामों में
शामिल हो जाओगे
हम जो बातें कह रहे हैं उनके बारे में हमें
पूर्ण विश्वास हैं
तब उस रास्ते पर चलने से क्या लाभ ? जिस पर
चल कर तुम जीत नहीं सकते

उन्हें बाँध दो, उन्हें बाँध दो, यही जीत
का मार्ग है
संघर्ष छिड़ने तक मालिकों को कोई
सूचना मत दो
तोपचियों, हड़तालभंजकों और ऐसे ही लोगों
को कोई मौका मत दो
आपको ज़रूरत है 'एक बड़ी यूनियन' और
'एक बड़ी हड़ताल' की

किसी भी समय और कहीं भी हड़ताल करने के अधिकार को छोड़ने से इन्कार करने वाली आइ. डब्लू. डब्लू. ने मजदूर समझौतों को पसन्द नहीं किया। वेतनों और काम के घंटों के लिए आए दिन के संघर्ष आक्रमण की सिर्फ पहली पंक्ति थी, अन्तिम प्रहार के लिए डेक साफ रखनी जरूरी थी। औद्योगिक यूनियनों को "पुराने खोल के भीतर नए समाज का ढाँचा" प्रदान करना था और पूँजीवादी समाज में "मालिक वर्ग के हितों की देखभाल के लिए तैनात सिर्फ एक समिति" का स्थान मजदूरों की सरकार को लेना था।"

आई. डब्लू. डब्लू. सबसे ज्यादा अपील पश्चिम के खनिकों, निर्माण कार्यों में लगे मज़दूरों, काष्ठ-श्रमिकों और खानाबदोश कृषि मज़दूरों को करती थी जिनको राजनीतिक कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्योंकि उन्हें वोट हासिल नहीं था। कम वेतन पाने वाले, गृहहीन, अविवाहित, एक काम से दूसरा काम करने वाले, समाज के सामान्य बंधनों से ज्यादातर अलग ये लोग समझते थे कि वे उनका शोषण करने के उद्देश्य से ही बनाई गई एक आर्थिक प्रणाली के शिकार हैं। वे "आकाश में लटके वन के" काल्पनिक स्वप्न के लिए नहीं बल्कि उत्पादन के साधनों के प्रत्यक्ष स्वामित्व के लिए हड़ताल करने, हिंसात्मक कार्य करने और खुला संग्राम करने के लिए तैयार थे। इस्पात मिलों, खाद्य-पदार्थ पैक करने के कारखानों और कपड़ा मिलों में आव्रजक मज़दूरों को भी उन्होंने अपना अनुयायी बना लिया। आइ. डब्लू. डब्लू. इनकी सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। यह ग्रुप पश्चिम के विद्रोहियों की तरह सख्त और लड़ने-मरने को सदा तैयार नहीं रहता था। पूर्व के फैक्ट्री कर्मचारियों ने आइ. डब्लू. डब्लू. कार्यक्रम के क्रांतिकारी फलितार्थों को अनिवार्यतः स्वीकार नहीं किया था। फिर भी वे अपनी हड़तालों में आइ. डब्लू. डब्लू. द्वारा दिए गए सहयोग के लिए कृतज्ञ थे।

आइ. डब्लू. डब्लू. के सदस्य कभी भी बहुत ज्यादा नहीं रहे, अपने उच्चतम शिखर पर भी उनकी संख्या शायद ६० हज़ार से ज्यादा नहीं हुई। कई लाख यूनियन कार्ड जारी किए गए किन्तु कभी-कभी काम पर आने वाले लोग ज्यादा दिन तक सदस्य नहीं रहते थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है आइ. डब्लू. डब्लू. का महत्त्व उसके क्रांतिकारी नेतृत्व में था। इसके सदस्य जिन्हें पश्चिम में वौबली कहा जाता था प्रायः हिंसा का स्वागत करते. लड़ाई को लड़ाई के लिए पसन्द करते प्रतीत होते थे और विवादग्रस्त मामलों की युक्तियुक्तता की बहुत परवाह किए बिना उन्होंने कानून और व्यवस्था की ताकतों से लोहा लिया। सान डियागो ट्रिब्यून ने १९१२ में गुस्से से लिखा : "उनके लिए फाँसी भी बहुत दुरुस्त चीज़ नहीं है। बेहतर है, वे मर जाएँ क्योंकि मानव अर्थतंत्र में वे बिल्कुल बेकार हैं, वे सृष्टि का मलबा हैं जिसे विस्मृति के गड्ढे में लुढ़का कर अन्य किसी विष्ठा की भाँति सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए।" किन्तु इस वर्ग के मजदूरों के बिना, चाहे वे कितने ही

झगड़ालू हों, 'पश्चिम' इतनी तेज़ी से विकास नहीं कर सकता था। भद्दा और भारी काम वही करते थे; लकड़ी काटते थे, फसल काटते थे, खानें खोदते थे। और उनके विचार कितने भी गलत रहे हों, समाज के विरुद्ध उनका अन्धा संघर्ष उनके लिए कितना भी निराशाजनक रहा हो, उनमें वह उत्साह और जोश था जो आकर्षण और रोमांच पैदा करने वाला था।

इनकी भावना आइ. डब्लू. डब्लू. के गीतों में अभिव्यक्त होती थी जो यूनियन की सभाओं व फसल शिविरों में और धरना देने के समय गाए जाते थे : "क्या तुम एक बौबली हो ?" "मालिकों को अपनी पीठ से उतार फैंको" "उन पर लाल रंग पोत दो" "हम क्या चाहते हैं ?" "लाल झण्डा" और "हालेलुजा मैं आवारा हूँ।"

ओह ! मैं अपने मालिक को पसन्द
करता हूँ

वह मेरा अच्छा दोस्त है
और यही कारण है कि मैं
फैक्टरी पर धरना देता हुआ भूखों
मर रहा हूँ।

हालेलुजाह ! मैं एक आवारा हूँ
हालेलुजाह ! आवारा हूँ
हालेलुजाह हमें पुनर्जीवित
करने के लिए एक हैण्ड-आउट दो।

आइ. डब्लू. डब्लू. की तरफ से उत्तर-पश्चिम की खानों में, लकड़ी के कारखानों में, निर्माण शिविरों में, प्रशान्तसागर के तटवर्ती डिब्बा बन्द करने के कारखानों, पूर्वी कपड़ा मिलों, मध्य पश्चिम की इस्पात व पैंकिंग संयन्त्रों में तथा स्ट्रीटकार कर्मचारियों, खिड़की साफ करने वालों और खलासियों की हड़ताल कराई गई। आइ. डब्लू. डब्लू. के नेता और विशेष कर 'बिग बिल' हेवुड जो वेस्टर्न फेडरेशन आव माइनर्स के हट जाने पर भी आइ. डब्लू. डब्लू. से अलग नहीं हुआ, कहीं भी, किसी भी समय असंगठित कर्मचारियों की

सहायता करने को तत्पर रहते थे। वे हड़ताल सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करते थे, धरना देने वालों में शामिल होते थे, मज़दूरों के परिवारों को सहायता प्रदान करते थे और इतने अन्धे जोश के साथ संगठन करते और आन्दोलन करते थे कि उसके सामने ए. एफ. एल. के तौर तरीके बिल्कुल मुर्दा प्रतीत होते थे।

जब स्थानीय अधिकारियों ने आइ. डब्लू. डब्लू. की हरकतों का दमन करने की कोशिश की और इसके नेताओं को जेल भेज दिया तो वल्ला-वल्ला (वाशिंगटन) से लेकर न्यू बेडफोर्ड (मैसाच्युसेट्स) तक "भाषण स्वातंत्र्य" के लिए लड़ाइयाँ फूट पड़ीं। जैसे ही किसी शहर में गिरफ्तारियों की खबर मिलती थी, वैसे ही वौबली सैंकड़ों की संख्या में अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करने तथा पुलिस को चुनौती देने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। जब पहली टुकड़ी को जेल भेज दिया जाता था तो दूसरी उसका स्थान ले लेती थी। अन्त में परेशान अधिकारियों को समाज पर इतना अधिक दबाव महसूस हुआ कि उनके पास अपने कैदियों को छोड़ देने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा। वौबली अपनी जीत से मदमाते जेल से छूटकर आते और आन्दोलन करने, धरना देने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को पुनः तैयार रहते थे।

वौबलियों द्वारा कराई गई सबसे ज्यादा चामत्कारिक हड़तालें और लड़ाइयाँ पश्चिम में हुई किन्तु उनकी एक सबसे बड़ी विजय १९१२ में लारेंस (मैसाच्युसेट्स) की कपड़ा मिल के कर्मचारियों की हड़ताल में हुई। किन्तु पूर्व में सीमान्त की हिंसा के घुस आने के भय के बावजूद यह हड़ताल बहुत ही अनुशासनपूर्ण रही। इस केस में आइ. डब्लू. डब्लू. ने कर्मचारियों के लिए जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के महत्त्व को समझा और व्यवस्था कायम रखने के लिए भरसक कोशिश की। क्रांतिकारी हलचलों के सब विचार तात्कालिक उद्देश्य के सामने गौण कर दिए गए। अन्य यूनियनों से कोई सहयोग न पाने के कारण जो पूर्वी शहरों में उनके पदाक्रमण से क्षुब्ध थी, लारेंस में आइ. डब्लू. डब्लू. के नेताओं ने अपनी सारी शक्ति हड़तालियों का संयुक्त मोर्चा बनाये रखने में लगाई जिसने अन्ततोगत्वा मालिकों को

घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया।

लारेंस कपड़ा मिलों के ३०००० कर्मचारियों के, जिन में करीब आधे अमेरिकन वूलेन कम्पनी में काम करते थे, वेतनों में कटौती हड़ताल का कारण बनीं। इन कर्मचारियों की जिनमें ज्यादातर इटालियन, पोल, लिथुआनियन और रूसी थे, औसत साप्ताहिक आय ६ डालर से कम थी—और मिलें पूरे समय चल रही थीं। कम वेतन और काम के लम्बे घण्टों के अलावा अत्यधिक दवाव और तनातनी की अवस्थाओं में काम की गति तेज करने के लिए एक प्रीमियम प्रणाली चालू की गई थी। वेतनों में कटौती अंतिम तिनका सिद्ध हुई। १२ जनवरी, १९१२ को कुछ मजदूरों ने सम्मिलित विरोध में, जिसमें शीघ्र ही २० हजार स्त्री-पुरुष शामिल हो गए, एक साथ वाकआउट कर दिया और टाउनहाल की खतरे की घंटिया वज उठीं।

मिलों में कुछ यूनियन सदस्य भी थे। कुछ थोड़े से ए. एफ. एल. से सम्बन्धित यूनियन यूनाइटेड टैक्सटाइल वर्कर्स से सम्बन्ध रखते थे और १००० के करीब आइ. डब्लू. डब्लू. के सदस्य थे। बाकी सब असंगठित थे। हड़ताल की संभावना को देखते हुए आइ. डब्लू डब्लू. के सदस्यों ने अपने हैडक्वार्टर से सहायता पाने के लिए आदमी भेज दिए थे और सामान्य प्रशासनिक बोर्ड के एक सदस्य जोसेफ जे. ऐट्टर लारेंस दौड़े। आए शीघ्र ही आइ. डब्लू. डब्लू. का एक अन्य नेता आर्तुरो गियोवान्निती भी उससे आमिला। इन दोनों व्यक्तियों ने हड़ताल का नियंत्रण तुरन्त ही अपने हाथ में ले लिया। इसका पूर्ण यथार्थवादी आधार पर संगठन किया और कड़ा अनुशासन लागू कर दिया। ऐट्टर ने हड़तालियों को संगठित रखने के लिए बड़ी-बड़ी सभाएँ कीं, कारखानों पर धरना दिए जाने की व्यवस्था की और इस बात का ध्यान रखा कि दुःख में पड़े जरूरतमन्द परिवारों को, जिनकी आय का स्रोत हड़ताल के कारण एकदम सूख गया था सहायता प्रदान की जाए। वस्तुतः सहायता देने का यह कार्य उसके लिए सबसे बड़ा सिर दर्द था क्योंकि शहर की ८५००० की आबादी में से आधे से अधिक या तो हड़ताली थे या उनपर आश्रित व्यक्ति। सप्लाई के वितरण, सूप की किचन चलाने और अन्य सहायता देने के लिए प्रत्येक पृथक् राष्ट्रीय ग्रुप के लिए अलग-अलग आम समितियां बना दी गईं।

कानून भंग की पहली घटना शहर के बहुत से भागों में लगाए गए डायनामाइटों की खोज थी, जो अखवारों में मोटों-मोटी सुर्खियों में जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से छापी गई। आइ. डब्लू. डब्लू. पर तुरन्त ही अपने आतंकवादी तरीके अपनाने का आरोप लगाया गया और हड़तालियों के प्रति लोगों में जो कुछ थोड़ी सी-सहानुभूति थी वह क्रोध में वदल गई। न्यूयार्क टाइम्स ने अपने अग्रलेख में लिखा : "जव हड़ताली डायनामाइट का प्रयोग करने को उद्यत हैं तो वे मानवीयता का एक ऐसा शैतानी अभाव दिखा रहे हैं, कि उन्हें, जव तक वे पश्चात्ताप न करलें धर्म का सुख प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।"

हड़तालियों ने तुरन्त ही विरोध प्रदर्शित किया और कहा कि डायनामाइट उन्होंने नहीं लगाए। वाद की घटनाओं ने उन्हें पूर्णतः सच्चा सावित किया। हड़ताल समाप्त होने से पूर्व यह सिद्ध हो गया कि एक स्थानीय उद्योगपति ने हड़तालियों को और विशेपकर आइ. डब्लू. डब्लू. को वदनाम करने के लिए डायनामाट लगा दिए थे और इस दुरभिसंधि में मिल मालिकों के निकट सम्वन्ध रखने वाले व्यक्ति भी शामिल थे। इस षड्यंत्र में शामिल होने के अभियोग में अमेरिकन वूलेन कम्पनी के मुखिया की गिरफतारी के साथ अत्यधिक कंजरवेटिव अखवारों ने भी झूठ-मूठ के वमकाण्डों में मज़दूरों को फँसाने की कोशिशों की कड़ी निन्दा की। आयरन ऐज ने लिखा : "यह सामान्यतः मालिकों के हितों के साथ दगा करना है।" और न्यूयार्क इवनिंग-पोस्ट ने इसे "पूँजीवाद का एक ऐसा अपराध वताकर जो मजदूर यूनियनों द्वारा कभी भी किए गए खराव से खराव काम से भी ज्यादा वढ़ा-चढ़ा है", इसकी निन्दा की।

इस वीच अमेरिकन वूलेन कम्पनी ने, जो मजदूरों की माँगों पर विचार करने से अव भी इन्कार कर रही थी, अपनी मिलों को फिर से चालू करने की कोशिश की। उसके इस कदम से हड़तालियों तथा पुलिस में हिंसात्मक संघर्ष हो गया जिसमें एक इटालियन महिला को गोली दाग कर मार डाला गया। अधिकारियों ने तुरन्त मार्शल ला लागू कर दिया, सार्वजनिक सभाओं और वातचीत को रोकने के लिए मिलीशिया की २२ कम्पनियाँ सड़कों पर गश्त लगाने के काम पर तैनात कर दी गई और ऐट्टर तथा

गियोवान्नित्ती को हत्या में शरीक होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया।

इन घटनाओं से न तो हड़ताल समिति और न आइ. डब्लू. डब्लू. प्रतिहिंसा के लिए भड़कीं और न ही हड़ताल को सफल बनाने का उनका संकल्प ढीला पड़ा। ऐट्टर और गियोवान्नित्ती की गिरफ्तारी के बाद "बिग बिल" हेवुड ने चार्ज ले लिया और अपनी निजी तथा आइ. डब्लू. डब्लू. की क्रांतिकारी नीतियों के बावजूद वह शांत प्रतिरोध के रुख पर जोर देता रहा। इस संयम के साथ मजदूर डटे रहे। काम पर लौटने की इच्छा रखने वाले मजदूरों को मिलीशिया जो संरक्षा प्रदान करती थी उसके बावजूद हड़ताली मजदूरों की एकजूटता भंग नहीं हुई। एक मिल को देखने के बाद एक अखबार के रिपोर्टर ने लिखा : "कताई के कक्ष में हरेक पटा चल रहा था, हर तरफ मशीनों की आवाज़ आ रही थी; तो भी कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं था और कोई भी मशीन सूत का एक भी तकुआ नहीं ले सकी।"

किन्तु हड़तालियों के भरण-पोषण का काम अधिकाधिक कठिन हो गया और फरवरी के शुरू में समिति ने एक योजना बनाई जिसके दो उद्देश्य थे— एक तो तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति और दूसरी उनके प्रति नाटकीय ढंग से जनता का ध्यान खींचना। अन्य शहरों में मज़दूरों से सहानुभूति रखने वालों से कहा गया कि वे हड़तालियों के बच्चों को अस्थायी आश्रय प्रदान करें। इस अपील का तत्काल असर हुआ और कई सौ बच्चे अन्य शहरों में भेज दिए गए। इस कदम के परिणामों से भयभीत होकर जिसकी युनाइटेड टैक्सटाइल वर्कर्स के मुखिया ने "आन्दोलन को चालू रखने, आइ. डब्लू. डब्लू. के प्रचार को बढ़ाने वाला" बताकर सबसे ज्यादा निन्दा की। लारेंस के अधिकारियों ने कहा कि अब और ज्यादा बच्चों को शहर से नहीं जाने दिया जाएगा। जब हड़ताल समिति ने बच्चों का एक अन्य ग्रुप बाहर भेजने की कोशिश की तो पुलिस ने ऐसी परिस्थितियों में हस्तक्षेप किया जो अन्य किसी भी चीज की अपेक्षा हड़तालियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने में ज्यादा सफल हुई।

बच्चों की देख-भाल का काम अपने हाथ में लेने वाली फिलाडेलफिया की

महिला समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया : "स्टेशन को पुलिस और मिलीशिया ने घेर लिया था। जब जाने का समय आया तो दो-दो की लम्बी कतार लगाए बच्चे पास खड़े अपने माता-पिताओं की देख-रेख में व्यवस्थित ढंग से ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हुए, तभी पुलिस ने दरवाज़े के दोनों तरफ तैनात होकर अपने दाएँ-बाएँ अन्धाधुन्ध डण्डे बरसाने शुरू कर दिए। बच्चों का कोई ख़याल नहीं रखा जिनके बारे में यह डर था कि कहीं वे भगदड़ में कुचले जाकर मारे न जाएँ। माताओं और बच्चों को सामूहिक रूप से धकेला गया और जबर्दस्ती घसीटकर एक सैनिक ट्रक में लाद दिया गया, उसमें भी उन्हें डण्डों से पीटा गया और भयभीत स्त्री-बच्चों की चीख़-पुकार की कोई परवाह नहीं की गई।

हड़ताल में शायद यह एक मोड़-बिन्दु सिद्ध हुआ। देश के प्रत्येक हिस्से से विरोधपत्रों की जो बाढ़ आई उसे न तो लावेल के अधिकारी ही सह सके और न मिल मालिक। हड़तालियों पर और हमले हुए और गिरफ्तारियाँ भी हुईं—दो महीने की हड़ताल में २९६ गिरफ्तारियाँ हो चुकी थीं—किन्तु जब धरना देने वाले डटे रहे तो अमेरिकन वूलेन कम्पनी ने आख़िरकार पराजय स्वीकार कर ली और १२ मार्च को जो पेशकश की, उसमें मजदूरों की करीब-करीब सब माँगें स्वीकार कर ली गई। वेतन ५ से २५ प्रतिशत तक बढ़ा दिए गए, सवाया ओवर टाइम निश्चित किया गया, प्रीमियम प्रणाली में उचित फेर-बदल किया गया और हड़तालियों को फिर से काम पर लगाते हुए कोई भेद-भाव न करने का वचन दिया गया। लारेंस कामन में आयोजित एक विशाल सभा में हेवुड ने इस पेशकश को स्वीकार करने की सलाह दी और मिल कर्मचारी काम पर लौटने को राजी हो गए।

अंतिम घटना ऐट्टर और गियोवान्नित्ती पर चलाया गया मुकदमा था। कुछ समय तक तो लगा कि उनके मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी और हत्या में शामिल होने का उन पर जो अभियोग लगाया गया है, उसको सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण न होने पर भी उन्हें सज़ा दे दी जाएगी। आइ. डब्लू. डब्लू. ने ६०,००० डालर एकत्र करके एक बचाव समिति कायम की और लारेंस के मज़दूरों ने यह घोषणा कर कि अगर जेल के दरवाज़े नहीं खोले गए। तो वे मिल के दरवाज़े बन्द कर देंगे, १५००० की संख्या में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर दी। अंतिम फैसले में दोनों व्यक्तियों को निर्दोष घोषित

किया गया और रिहाई के बाद खुशी से नाचती हुई भीड़ ने उनका स्वागत किया। ये लोग समझते थे कि लारेंस कपड़ा मिल के कर्मचारियों की हड़ताल को सफल बनाने में इनका नेतृत्व कम ज़िम्मेदार नहीं है।

मुकदमा खत्म होने से पूर्व दोनों अभियुक्तों ने जूरी के सामने वक्तव्य दे कर अपनी स्थिति स्पष्ट की, जिसमें उन्होंने आइ. डब्लू. डब्लू. के क्रांतिकारी उद्देश्यों को स्पष्ट स्वीकार किया और कहा कि वे पुलिस से नहीं डरेंगे। गियोवान्नित्ती का, जो अपने अधिकार से ही एक कवि थे और जिनकी क्रांतिमय कविताएँ बहुत ही पद्यावलियों में पाई जाती हैं, भाषण बड़ा ओजस्वी और मार्मिक था।

उन्होंने कहा: "मैं आप से साफ कहता हूँ कि इस कामनवेल्थ तथा अमरीका में अन्य किसी भी स्थान पर पहली जो भी हड़ताल फूट पड़ेगी और जहाँ कहीं भी जोसेफ जे-एट्टर और आर्तुरो गियोवान्नित्ती के काम, मदद और सूझबूझ की जरूरत होगी, वहीं हम किसी धमकी या भय की परवाह किए बिना दुबारा जाएँगे। हम फिर से अपने विनम्र प्रयत्नों की ओर, संसार के मज़दूरों की शक्तिशाली सेना के अज्ञात व गलत रूप में समझे जाने वाले योद्धाओं के बीच, लौट जाएँगे जो अतीत की छाया और अधिकार में से मानव जाति की स्वतंत्रता के और इस भूमण्डल पर हर स्त्री-पुरुष के लिए प्रेम, भाईचारा व न्याय की स्थापना के निर्दिष्ट उद्देश्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।"

आइ. डब्लू. डब्लू. ने लारेंस में आश्चर्यजनक विजय प्राप्त की। कपड़ा कर्मचारियों में इस की सदस्य संख्या रातों-रात १८,००० हो गई और इस नए जीवन से उसके और भी विकास की संभावना दिखाई देने लगी। हड़ताल में इसके आक्रामक तौर-तरीकों के भावी विकास को लेकर ए. एफ. एल. में हलचल मच गई और इससे भी ज्यादा व्यापारी वर्ग में अमरीकी मजदूरों में क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के संभावित प्रसार का भय व्याप गया। 'सर्वे' में एक लेख में कहा गया: "क्या हम आशा करें कि सम्मानपूर्वक खेल खेलने के बजाय, अथवा स्पष्टतः अव्यवस्थित ढंग के दंगे कराने के बजाय, जिनसे निपटना हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, मजदूर एक सूक्ष्म अराजकतावादी विचार-

धारा के वशीभूत हो जाएँगे जो 'सीधी कार्रवाई,' 'हड़तालों के जरिए मज़दूरों के हाथ में सत्ता लाने,' 'आम हड़ताल' और 'हिंसा' जैसे अजीब-अजीब सिद्धान्तों को दिमाग में ठूँसकर कानून और व्यवस्था के बुनियादी विचार को चुनौती दे रही है ?...... हम समझते हैं कि सम्पत्ति और जीवन की पवित्रता के बारे में हमारी सादी विद्यमान नैतिकता इसमें दांव पर लगी हुई है।"

ये भय शीघ्र ही बेबुनियाद सिद्ध हुए। आइ. डब्लू. डब्लू. अपनी शक्ति और प्रभाव के उच्चतम शिखर पर पहुँच चुकी थी। जैसा कि पुराने नाइट्स आव लेबर के साथ हुआ इसकी महानतम विजय भीषण पराजयों और पतन की पूर्व परिचायक थी जिससे कुछ ही वर्षों में इसका वस्तुतः खात्मा हो गया। आइ. डब्लू. डब्लू. इतना ज्यादा क्रान्तिकारी था कि वह अमरीकी मजदूर की मूलतः रूढ़िवादी ताकतों का समर्थन प्राप्त नहीं कर सकता था और इसके प्रचार की तीव्रता के बावजूद क्रान्ति के रूप में इसकी सफलता के बारे में सन्देहशील था। यह सिर्फ इसी बात में सफल हुआ कि इसने लोगों में हिंसा का इतना ज़्यादा भय उत्पन्न कर दिया कि लारेंस के अपेक्षाकृत शान्तिमय तौर तरीकों से भी वह दूर नहीं हुआ।

अगली महत्त्वपूर्ण हड़ताल, जिसमें आइ. डब्लू. डब्लू. ने भाग लिया इसका पतन कराने वाली सिद्ध हुई। पैटर्सन (न्यूजर्सी) के रेशम के कारखानों में १९१३ में गड़बड़ हुई और वौबलियों के अन्य नेताओं के अलावा एट्टर तथा हेवुड ने इसमें पुनः प्रमुख भाग लिया। यह संघर्ष बहुत लम्बा और कटुतापूर्ण रहा। पैटर्सन के अधिकारी आइ. डब्लू. डब्लू. के क्रांतिकारी खतरे को मटियामेट कर देने के लिए कृतसंकल्प थे और आइ० डब्लू० डब्लू० समझता था कि इस हड़ताल के परिणाम पर इतना कुछ निर्भर करता है कि वह हार नहीं मान सकता। हड़तालियों को किसी भी बहाने गिरफ्तार कर लेने में, प्रतिरोध करने पर उन्हें डण्डे मार-मार कर बेहोश कर देने में और उनकी धरना देने वाली पंक्ति को छिन्न-भिन्न कर देने में पुलिस ने अत्यन्त बदनामी पूर्ण पाशविकता से काम लिया फिर भी हड़ताल जारी रही। रेशम कर्मचारियों के लिए जिन अन्य लोगों की सहानुभूति प्राप्त की गई उनमें हार्वार्ड में शिक्षित नौजवान क्रांतिकारी जॉन रीड भी था जिसने 'टेन डेज़ दैट शूक द वर्ल्ड' (वे दस दिन जिन्होंने दुनिया को दहला दिया) पुस्तक लिखी और जिसे क्रेमलिन की

सार्वजनिक प्रतिक्रिया यह हुई कि लोग आइ० डब्लू० डब्लू० को देशभक्ति रहित, जर्मन पक्षपाती और गद्दार कहकर उसकी निन्दा करने लगे। युद्धोन्माद के वातावरण में लोगों की भावनाएँ सब कहीं "साम्राज्यी विल्हेल्म के योद्धाओं" के खिलाफ खूब उभार दी गई। और मालिकों ने भी यह देखकर कि अब उनके लिए आइ० डब्लू० डब्लू० को हमेशा के लिए कुचल देने का मौका है। अखबारों के उत्साहपूर्ण सहयोग से उन सुलगते शोलों पर तेल छिड़कने का हर सम्भव प्रयत्न किया। शिकागो ट्रिब्यून ने लिखा : "पश्चिम में आइ० डब्लू० डब्लू० का गुस्सा दिलाने वाला उभार विद्रोह से कम नहीं है।" क्लीवलैण्ड न्यूज ने लिखा : "देश जब युद्ध में ग्रस्त है तब आइ० डब्लू० डब्लू० के सदस्यों को एकमात्र जेलखाने की दीवारों के पीछे ही कमरा दिया जा सकता है।"

इन भावनाओं ने मूर्त रूप भी ग्रहण किया। १९१७-१८ में एक के बाद एक राज्य ने जरायम सिंडिकलिजम (हड़तालों के जरिये सत्ता हथियाने का प्रयत्न) कानून पास किए जिनमें आइ० डब्लू० डब्लू० को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इन कानूनों के अन्तर्गत असंख्य गिरफ्तारियाँ की गई। राष्ट्रीय सरकार ने भी राजद्रोह और जासूसी अधिनियम पास किए। युद्ध-प्रयत्नों में बाधा डालने के अभियोगों में संघीय अधिकारियों ने आइ० डब्लू० डब्लू० के १६० सदस्यों को सजा दिलाई। शिकागो के लिए सामूहिक मुकदमे में हेवुड तथा ९४ अन्य व्यक्तियों को राजद्रोह का अभियुक्त ठहराया गया और उन्हें २० साल तक की जेल की सजाएँ दी गई। सरकार के खिलाफ षड्यन्त्र करने के अभियोग कई मामलों में इतने लचर थे कि हंसी आती थी किन्तु देशभक्ति का जोश प्रथम विश्व युद्ध में प्रायः भाषण और सभा की स्वतंत्रता के वैधानिक अधिकारों के खयाल से संयत नहीं हो पाता था।

जब अधिकारियों नें बहुत तत्परता से कार्रवाई नहीं की तो लायलटी लीग और स्थानीय सुरक्षा समितियाँ प्रायः ही कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेती थी अनेक शहरों में क्रूरता से डण्डे बरसाये गए, घोड़ों को पीटने के चाबुक लगाये गये ! ऐसे कई केस हुए जिनमें आइ० डब्लू० डब्लू० के आन्दोलनकारियों को पकड़कर अव्यवस्थित भीड़ ने लिंच कर दिया। १९१७ में बिसबी (एरिजोना) में कोई १२०० हड़ताली खनिकों को

जिनमें से आइ. डब्लू. डब्लू. के सदस्य वस्तुतः आधे से भी कम थे, स्थानीय लायल्टी लीग के कहने पर नगर अधिकारी द्वारा तैनात एक पुलिस पार्टी ने जबर्दस्ती शहर से निकाल दिया। उन्हें पशुओं की गाड़ियों में भरकर राज्य की सीमा के बाहर ले जाया गया और रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। जब भोजन और पानी के बिना उन्हें ३६ घण्टे हो गये तब संघीय अधिकारियों ने उन्हें बचाया तथा कोलम्बस (न्यू मैक्सिको) के एक नजरबन्दी शिविर में ले गए।

युद्ध के इन वर्षों में आइ. डब्लू. डब्लू. की शक्ति ज़्यादातर उसके अपने कथनानुसार "वर्ग संघर्ष के कैदियों" का बचाव करने की कोशिशों में लगी रही। इसमें सफलता न मिलने के कारण यह शीघ्र ही नेता-विहीन हो गया और अन्ततोगत्वा हेवुड स्वयं जमानत की परवाह न करता हुआ रूस भाग गया। स्वतः संगठन भंग नहीं हुआ—बाद में इसमें पुनः कुछ ताकत-सी-भी आई—किन्तु युद्ध-पूर्व की अपनी आतंककारी शक्ति को यह फिर कभी प्राप्त नहीं कर सका।

पश्चिम की बदलती हुई परिस्थितियों ने, जिनमें खेतों में मशीनों का अधिक उपयोग किया जाने लगा था और मोटर परिवहन का बहुत विकास हो गया था, खानाबदोश कर्मचारियों की संख्या कम कर दी थी और यही आइ. डब्लू. डब्लू. के सबसे महत्त्वपूर्ण सदस्य थे। बहुत से क्रांतिकारी समाजवादियों को १९१९ में थर्ड इण्टरनेशनल की शाखा के रूप में आयोजित कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी ओर खींच लिया। अन्त में आइ. डब्लू. डब्लू. में जो बचे, वे पुराने नेताओं के अभाव में बहुत कम उग्र रह गए। अब उत्पादन के साधनों पर कब्ज़ा करने के लिए क्रांतिकारी साधन अपनाने के बजाय इन पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने की तैयारी पर बल दिया जाने लगा। युद्ध के बाद 'न्यूयार्क वर्ल्ड' के एक रिपोर्टर ने बेकारी पर आयोजित एक सम्मेलन की बाबत लिखा : "वौबलियों ने क्रांति, वर्ग-चेतना, शोषण या पूँजीवादी प्रणाली को अनिवार्यतः उलटने की बात नहीं कही, बल्कि 'निर्बाध उत्पादन' और 'औद्योगिक प्रक्रियाओं में समन्वय' की बातें कहीं..." १९२० की दशाब्दि के मध्य तक पुराना लड़ाकू आइ. डब्लू. डब्लू. एक कहानी बन चुका था।

आइ. डब्लू. डब्लू. की सदस्यता या उसकी अनियमित हड़तालों की गतिविधियों के बजाय मज़दूर आन्दोलन पर उसका प्रभाव ज्यादा महत्त्व की बात थी। पश्चिम की खानों, काष्ठ-गृहों और कभी कभी पूर्व के कारखानों में काम की हालतों में सुधार के प्रत्यक्ष परिणामों के अलावा इस क्रांतिकारी आन्दोलन ने विशेषतः अदक्ष श्रमिकों की विशाल संख्या की अत्यन्त ज़रूरी आवश्यकताओं पर लोगों का ध्यान केन्द्रित किया और औद्योगिक यूनियनवाद को एक नई गति प्रदान की जिसकी ए. एफ. एल. भी बिल्कुल उपेक्षा नहीं कर सकता था। वर्ग संघर्ष के क्रांतिकारी सिद्धान्त ने कम-से-कम कुछ समय के लिए रूढ़िवादी मज़दूर नेताओं की शिथिलता को झकझोर दिया जो परम्परागत ट्रेड यूनियनवाद की सीमाओं से परे देखना ही नहीं चाहते थे।

तो भी आइ. डब्लू. डब्लू. अपने उद्देश्य में विफल रहा। वर्ग संघर्ष भड़काकर वेतन-प्रणाली खत्म करने के अपने लक्ष्य में उसने उससे ज्यादा प्रगति नहीं की, जितनी नाइट्स आव लेबर ने शिक्षा और आन्दोलन के अपने हलके कार्यक्रम के जरिए की थी। अमरीकी मज़दूरों की एक बहुत बड़ी संख्या आइ. डब्लू. डब्लू. की विचारधारा के मूलतः उतनी ही खिलाफ थी, जितने उनके मालिक या सामान्यतः मध्यम वर्ग। अमरीकी मज़दूर संघ, जो अपने क्रांतिकारी प्रतिद्वन्द्वी को बदनाम करने या उस पर चोट करने का कोई मौका नहीं चूकता था, मज़दूर आन्दोलन पर अपना प्रभुत्व जमाये रहा और क्रांतिकारी यूनियनवाद ने कामकाजी यूनियनवाद के मुकाबले कोई वास्तविक प्रगति नहीं की। आइ. डब्लू. डब्लू. वामपक्षीय भावनाओं की नाटकीय अभिव्यक्ति थी किन्तु इसका कोई अनुयायी नहीं बना। अमरीकी मज़दूर को यह विश्वास नहीं कराया जा सका कि श्रमिकों का ऐतिहासिक कार्य पूँजीवाद का खात्मा कर देना है।

—:o:—

१३ : प्रथम विश्व-युद्ध और उसके बाद

आगामी युद्ध की छाया जब अमरीका पर पड़ने लगी और घटनाएँ तेज़ी से देश को यूरोपीय युद्ध की ओर घसीट ले चलीं तो अमरीकी मज़दूरों के सामने एक गम्भीर समस्या आ खड़ी हुई। क्या यह ऐसा युद्ध है जिसमें मज़-दूरों का कोई हित दाँव पर लगा हुआ है? क्या युद्ध-प्रयत्नों में सहयोग दिया जाए अथवा मज़दूर राष्ट्रीय-संकट का लाभ उठाकर अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा दें? आइ. डब्लू. डब्लू. ने १९१४ में इन विकल्पों में से अपना चुनाव कर लिया था और उस पर वह दृढ़ता से कायम रहा। समाजवादियों में दो मत हो गए और यूजीन वी. डेब्स अपने मन्तव्यों के मुताबिक इसे पूँजीवादियों का युद्ध कहकर इस पर आक्षेप करता रहा और जेल चला गया। किन्तु अम-रीकी मज़दूर संघ ने, राष्ट्र के बहुत अधिक मज़दूर जिसके साथ थे, सरकार और उसके युद्ध-प्रयत्नों के प्रति पूर्ण वफ़ादारी की घोषणा की और उस पर अमल किया। मज़दूरों के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में गौम्पर्स से बढ़कर देशभक्ति किसी सार्वजनिक नेता ने नहीं दिखाई और न ही कोई विल्सन सरकार का उससे बड़ा वफ़ादार निकला।

मज़दूरों की यह जीत श्रम सम्बन्धों के क्षेत्र में सरकारी अधिकार क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण विस्तार की प्रतीक थी। यह सच है कि कांग्रेस ने यह ऐक्ट रेलवे हड़ताल के आसन्न खतरे को देखते हुए, जिससे राष्ट्र के युद्ध प्रयत्नों में बाधा पहुँचती, यह ऐक्ट पास किया था और रेलवे ब्रदरहुडों द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों पर काफी व्यापक रोष था। किन्तु तो भी सरकार द्वारा मज़दूरों के हितों की रक्षा करने का दायित्व अपने ऊपर ले लेना बहुत महत्त्वपूर्ण बात थी।

सत्ता और ज़िम्मेदारी दोनों की भावनाओं के साथ लगभग तीस लाख मज़दूरों के प्रवक्ताओं ने युद्ध के प्रति मज़दूरों का रुख निश्चित करने का काम अपने हाथ में लिया। यह मामला युद्ध छिड़ने से लगभग १ मास पूर्व, किन्तु जब युद्ध बहुत निकट प्रतीत होता था, एक सम्मेलन में उठाया गया था, जिसमें ७६ अन्तर्राज्यीय यूनियनों, रेलवे ब्रदरहुडों और ए. एफ. एल. की कार्यकारिणी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन की समाप्ति पर इन्होंने "शांति और युद्धकाल में अमरीकी मज़दूरों का मन्तव्य" शीर्षक से एक वक्तव्य जारी किया जिसमें देश के जर्मनी से सीधा युद्ध में उलझने पर सब मज़दूर संगठनों के पूर्ण सहयोग का वचन दिया गया था।

यह कोई बिना शर्त प्रतिज्ञा नहीं थी। संगठित मज़दूरों का संकल्प था कि हाल के वर्षों में जो लाभ प्राप्त किए जा चुके हैं, युद्धकाल में भी उनकी रक्षा की जाए और विल्सन सरकार के समर्थन का वचन देते हुए भी इसने अपनी नव-प्राप्त हैसियत को पूर्ण मान्यता दिए जाने का आग्रह किया। सरकार से माँग की गई कि वह मज़दूरों का सहयोग यूनियनों के माध्यम से ही प्राप्त करे और राष्ट्रीय-रक्षा से सम्बन्धित सब बोर्डों में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। मज़दूरों को संगठित होने के अधिकार का प्रयोग करने की छूट दी गई और सब प्रकार से संयम रखने की बात स्वीकार करते हुए भी उन्होंने हड़ताल के हथियार को छोड़ देने की बात नहीं मानी। जिस प्रकार के उद्देश्यों के लिए राष्ट्र युद्ध में कूदने को तैयार हो रहा था, उन्हें देखते हुए मज़दूरों के असहयोग के लिए इन शर्तों को आवश्यक बताया गया।

मज़दूर नेताओं ने कहा कि "इस गणराज्य की सुरक्षा के साथ ही लोकतंत्र के आदर्श बंधे हुए हैं। यह एक ऐसी विरासत है जो हमारी जनता ने इस देश में आज़ादी को जीवित रखने के लिए संघर्ष करने वाले अपने पूर्वजों से

हासिल की है—एक ऐसी विरासत जिसे कायम रखना है और आगे आने वाली हर पीढ़ी को पूर्ण शक्ति और उपयोगिता के साथ प्रदान करना है।"

सरकार इस आधार पर मज़दूरों के साथ सहयोग करने को तैयार थी और युद्ध में हमारे वास्तविक प्रवेश के बाद उसने औद्योगिक सम्बन्धों में हड़तालों को रोकने की नीति पर चलने का प्रयत्न किया। अमरीकी मज़दूर संघ के साथ किए गए समझौतों में सब सरकारी करारों में ट्रेड यूनियन स्टैण्डर्ड को लागू करने की व्यवस्था की गई। सब उपयुक्त सरकारी एजेंसियों में मज़दूरों के प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए गए और गौम्पर्स को राष्ट्रीय रक्षा-परिषद् के परामर्शदाता आयोग का सदस्य बना दिया गया। नवम्बर, १९१७ में ए. एफ. एल. के सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा : "जब हम स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं तो हमें अन्य बातों के अलावा यह भी देखना है कि मज़दूर स्वतंत्र हों.... ।"

किन्तु १९१७ में औद्योगिक शांति कायम रखना बहुत आसान नहीं रहा। युद्ध काल की खरीदारी के कारण जब कीमतें चढ़ीं और उसके हिसाब से मज़दूरी की दर नहीं बढ़ी तो मज़दूरों में असन्तोष पैदा हो गया और वेतन में वृद्धि की आम माँग की जाने लगी। जब ये पूरी नहीं की गई तो युद्ध-पूर्व की अपेक्षा भी अधिक बड़े पैमाने पर हड़तालें होने लगीं। १९१७ की समाप्ति से पूर्व ही इनकी संख्या ४,४५० तक जा पहुँची जिनमें १० लाख से अधिक मज़दूरों ने भाग लिया।

बहुत-सी हड़तालें आइ. डब्लू. डब्लू. ने कराईं। इसके क्रान्तिकारी नेतृत्व में उत्तर-पश्चिम के काष्ठ-गृहों में, प्रशान्त महासागर के तट पर जहाजी घाट के कर्मचारियों में और ऐरिजोना की ताम्बे की खानों में खतरनाक हड़तालें हुईं। किन्तु मजदूरों में यह असन्तोष सिर्फ उसके क्रान्तिकारी तबके तक ही सीमित नहीं था। ए. एफ. एल. से सम्बन्धित बहुत-सी रूढ़िवादी और देशभक्त यूनियनों ने भी युद्धकाल में माँगें रखना और उनकी पूर्ति के लिए हड़ताल करना, जिनसे रक्षा-उद्योगों के उत्पादन में गम्भीर अड़चन पैदा हुई, उचित समझा।

१९१८ के शुरू में इस स्थिति से समुद्रपार युद्ध सामग्री की सप्लाई खतरे में पड़ती प्रतीत हुई। श्रम सम्बन्धी झगड़ों को यद्यपि वेतनों में हेर-फेर के

लिए विशेष वोर्डों के ज़रिये और राष्ट्रपति विल्सन द्वारा अगस्त, १६१७ में नियुक्त कमीशन की मध्यस्थता से हल करने की कोशिशें की जाती रहीं तो भी सरकार ने आवश्यक औद्योगिक उत्पादन को कायम रखने के लिए और ज्यादा हस्तक्षेप की ज़रूरत महसूस की। संगठित मज़दूरों के प्रति सरकार की मित्रता और समय की माँग दोनों का यह तकाज़ा था कि हड़तालों को बलपूर्वक दवाने के वजाय मज़दूरों का सहयोग प्राप्त करने की नीति अख्त्यार की जाए। फलस्वरूप एक युद्ध-श्रम सम्मेलन वोर्ड में मज़दूरों और प्रवन्धकों दोनों के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए जब उसने सर्वसम्मति से भविष्य के लिए श्रम-सम्वन्धों के वारे में अपनाए जाने वाले सिद्धान्त तय कर दिए तव अप्रैल, १६१८ में इसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति ने एक नेशनल वार लेवर वोर्ड कायम किया जिसे उन सव औद्योगिक झगड़ों के निवटारे के लिए, जिन्हें और किसी उपाय से हल न किया जा सका हो, एक अन्तिम अपीलीय न्यायालय का काम करना था। इसमें ५-५ प्रतिनिधि मज़दूरों और मालिकों के रखे गए और दो संयुक्त चेयरमैन रखे गए जो जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। ये थे भूतपूर्व राष्ट्रपति टैफ्ट और औद्योगिक सम्वन्धों के कमीशन के भूतपूर्व चेयरमैन फ्रैंक पी. वातश। कुछ समय वाद फ्रैंक फर्टर की अध्यक्षता में वार लेवर पालिसीज़ वोर्ड की एक और एजेंसी कायम की गई। जिसने युद्ध-सम्वन्धी उद्योगों में वेतन और काम के घण्टों से सम्वन्धित विभागीय मज़दूर नीतियों में समन्वय करने के लिए क्लियरिंग हाउस का काम किया।

नेशनल वार लेवर वोर्ड ने जिन आम सिद्धान्तों पर काम किया वे मज़दूरों के प्रति सरकार की नई नीति के प्रतीक के रूप में वहुत महत्त्वपूर्ण थे। ये न्यू डील के अन्तर्गत वाद में वनने वाले श्रम-कानूनों का पूर्वाभास भी देते थे। युद्ध-काल में अव और हड़तालें तथा तालावन्दियाँ नहीं होंगी इस आम वायदे के प्रत्युत्तर में विल्सन सरकार वस्तुतः मज़दूरों की सव परम्परागत माँगों की पूर्ति में उन्हें सहयोग देने को तैयार थी। "निर्वाचित प्रतिनिधियों" के ज़रिये संगठित होने और सामूहिक सौदेवाजी के अधिकार को निश्चित रूप से स्वीकार किया गया मालिक इसमें कोई कटौती नहीं कर सकते थे और न ही उसे प्रदान करने से इन्कार कर सकते थे। यूनियन अथवा ओपन-शाप के वारे में सव मौजूदा समझौते युद्ध-पूर्व की स्थिति के आधार पर कायम रखने, ८ घण्टे के

दिन का यथासम्भव पालन करने, उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निश्चय किया गया और सामान्य मज़दूरों समेत सब श्रमिकों का जीवनयापन के लायक जिससे मज़दूर और उसका परिवार स्वास्थ्य तथा उपयुक्त सुख-सुविधाओं के वातावरण में अपनी ज़िन्दगी बसर कर सके, वेतन प्राप्त करने का हक पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया।

इन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजीनामों के साथ हड़तालें कम होने लगीं और जो झगड़े उत्पन्न भी होते थे, उनका जल्दी ही निबटारा कर दिया जाता था। इनसे युद्धोत्पादन के कार्य में कोई विशेष रुकावट उत्पन्न नहीं हुई इसलिए संकट काल के लिए आवश्यक मनुष्यशक्ति रिजर्व में रखने, अनिवार्य पंच-फैसले और हड़ताल-विरोधी कानूनों जैसे सख्त कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मजदूरों ने अपनी इच्छा से जो करार किया था उसमें अपने से सम्बन्धित शर्तों का उन्होंने पूर्णतः पालन किया और युद्ध मंत्री बेकर ने एक बार तो यह भी कहा कि "मजदूर पूँजीपतियों की अपेक्षा अपने वचन का अधिक अच्छी तरह पालन कर रहे हैं।"

मजदूरों के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में गौम्पर्स हर संभव तरीके से युद्ध-प्रयत्नों में सहयोग देता रहा और ए. एफ. एल. को हमारी विदेशनीति से पूर्णतः एकात्म करने में सफल हुआ। उसने सब शांतिवादियों और संदिग्ध जर्मन पक्षपाती ग्रुपों की कड़ी आलोचना की और शांति के लिए समाजवादियों के आन्दोलन के मुकाबले में श्रमिकों व लोकतंत्र के लिए अमरीकी गठ-बन्धन (अमेरिकन अलाएन्स फॉर लेबर ऐण्ड डिमोक्रेसी) नाम से एक संगठन कायम किया और अमरीकीवाद की जोर-शोर से हिमायत की। राष्ट्रपति विल्सन ने उसे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा : "उसके देशभक्तिपूर्ण साहस, उसकी व्यापक दृष्टि और क्या करना है उसके बारे में उसकी राजनीतिज्ञतापूर्ण सूझ का मैं कायल हूँ।" १९१८ की पतझड़ में गौम्पर्स अन्तर-मित्रराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश चला गया और शांति-वार्ताओं के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कानून कमीशन के एक सदस्य के रूप में वह पेरिस में मौजूद था।

श्रम नीति की झांकी मजदूरों के युद्धकालीन लाभों तथा यूनियनवाद

के विकास में देखी जा सकती थी। वेतन धीरे-धीरे बढ़ते रहे जब तक कि वे निर्माण, परिवहन तथा कोयला खानों में १००० डालर से अधिक नहीं हो गए और १९१९ में यूनियनों की सदस्य संख्या १९१६ से १० लाख से अधिक कुल ४१,२५,००० हो गई। जब सरकार ने रेलों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया तो जो मान्यता पहले सिर्फ रेलवे ब्रदरहुडों को मिली हुई थी वह वर्कशाप के कर्मचारियों, यार्ड के कर्मचारियों, पटरी का रख-रखाव करने वाले कर्मचारियों, रेलवे क्लर्कों तथा तार भेजने वालों को भी प्राप्त हो गई। जिन उद्योगों में यूनियनवाद तरक्की नहीं कर पा रहा था, उनमें खाद्यपदार्थों को पैक करने वाले कर्मचारियों, नाविकों, बन्दरगाह पर माल चढ़ाने-उतारने का काम करने वाले कर्मचारियों, विद्युत्, कर्मचारियों यथा मशीन-चालकों में महत्त्वपूर्ण प्रगति की गई। युद्ध ने महान् अवसर ला खड़े किए थे और अमरीकी मजदूरों ने उनका अधिक से अधिक लाभ उठाया।

युद्ध की समाप्ति ने एकदम नई परिस्थितियां पैदा कर दीं। युद्धकालीन प्रतिबन्ध हटा दिए जाने और नेशनल वार लेबर बोर्ड जो लगाम लगाए रखता था, सरकार द्वारा उन्हें हटा दिए जाने के बाद श्रमिक और उद्योगपति अपने ऐतिहासिक संघर्ष को अनिवार्यतः फिर से शुरू करने के लिए सन्नद्ध हो गए। युद्धकालीन नाजुक संधि खत्म हो गई थी। मजदूरों का न केवल युद्ध-काल में प्राप्त किए गए लाभों को कायम रखने का बल्कि अपने लिए और ज्यादा अधिकार प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय था और उद्योग भी स्वयं को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने, यूनियनवाद को और प्रगति करने से रोकने तथा अपनी शक्ति का फिर से प्रदर्शन करने के लिए कम कृतसंकल्प नहीं थे। १९१९ में जब पहले किसी भी समय की अपेक्षा बड़े पैमाने हर हड़तालें फूट पड़ीं तो इन दोनों विरोधी पक्षों में से किसी ने कोई कसर नहीं रखी। उस वर्ष राष्ट्रव्यापी हड़तालें हुईं और राष्ट्र के पुनः शांतिकालीन स्थिति में आने की सारी प्रक्रिया पर चौथाई सदी बाद की तरह सीधा और खतरनाक प्रभाव डाला।

इन में से बहुत में झगड़ों का तात्कालिक कारण वेतन था। वस्तुओं के मूल्यों में युद्धकालीन वृद्धि १९१९ में भी बे-रोक-टोक जारी रही—रहन-सहन

का खर्चा अन्ततः युद्ध-पूर्व के स्तर से दूना हो गया—और मजदूर, यद्यपि अब भी उन्हें ऊँची तनख्वाहें मिल रही थीं, उसका कष्ट महसूस करने लगे। किन्तु वेतनों में हेर-फेर के मुकाबले यूनियन सुरक्षा का मूल प्रश्न आसानी से हल नहीं होता था। बहुत से मालिक वेतन सम्बन्धी माँगों को पूर्णतः या आंशिक रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार थे किन्तु सामूहिक सौदेबाजी के विस्तार में उन्हें अपने निजी व्यापार के प्रबन्ध पर खतरा दिखाई दिया। उन्होंने यूनियन प्रवक्ताओं को मान्यता देने से इन्कार कर दिया और युद्ध के दबाव में आकर जो रियायतें दी गई थीं वे ज्यादातर वापस ले ली गईं।

यूनियन मान्यता के प्रश्न का महत्त्व विलसन सरकार द्वारा युद्ध के बाद एक मामले में प्रबन्धकों और मज़दूरों के बीच मतभेद दूर करने की कोशिशों के फलस्वरूप सामने आया। विरामसंधि के बाद श्रम सम्बन्धी झगड़ों का निबटारा करने वाली विविध एजेंसियाँ तुरन्त खत्म कर दी गईं, किन्तु जब हड़तालों की संख्या बढ़ने लगी तो राष्ट्रपति ने एक राष्ट्रीय औद्योगिक सम्मेलन बुलाया, जिसमें इस बार मज़दूर, उद्योग और जनता के प्रतिनिधि थे और उससे आशा की कि यह श्रम सम्बन्धी शांति का कोई आधार ढूँढ सकेगा। सामूहिक सौदेबाजी के स्वरूप और जो उसके अपने कर्मचारी नहीं हैं उन व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के प्रति मालिक के दायित्व के बारे में तुरन्त ही बुनियादी मतभेद खड़े हो गए। मज़दूरों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय यूनियनों की मान्यता हासिल करने के एकमात्र उपाय के रूप में "बिना किसी भेदभाव के संगठन करने के अधिकार" का आग्रह किया और जब जनता के प्रतिनिधियों ने, जिनमें किसी प्रकार जॉन डि रौकफेलर जूनियर और युनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन के चेयरमैन ऐल्बर्ट एच. ग्रे भी शामिल हो गए थे, इस रियायत को न देने में उद्योग का साथ दिया तो सम्मेलन भंग हो गया।

इस बीच १९१९ में हड़तालों की संख्या और स्वरूप जनता को अधिकाधिक भयभीत करने लगा। उन्होंने महसूस किया कि ये हड़तालें न केवल शांतिकालीन अवस्था में लौटने में बाधक बन रही हैं बल्कि अमरीकी संस्थाओं की स्थिरता को संकट में डाल रही हैं। बहुत से लोगों के रवैये पर रूस में बोलशेविक क्रांति हो जाने से कम्यूनिज़्म के प्रसार के उन्मादपूर्ण भय

का भी असर पड़ा था। वस्तुतः १९१९ में हुई हड़तालों के प्रति लोकमत के निर्माण में कम्यूनिज़्म के भूत के डर ने प्रमुख भाग लिया। अमरीका में अव्यवस्था उत्पन्न करने में मास्को की काल्पनिक भूमिका का हिस्टीरिया लोगों में फैल जाने के कारण ज्यादातर जनता यही समझने लगी कि अधिकांश हड़तालें क्रेमलिन के सीधे आदेश पर कम्युनिस्टों ने ही करायी हैं। वोल्शेविज़्म को समस्त मज़दूर अशांति का कारण वनाने की भयपूर्ण धुन में मज़दूरों के वाजिव अधिकार और उनकी उचित शिकायतें भुला दी गई। मालिकों ने सव हड़तालियों को कम्युनिस्ट वताने का निरन्तर आन्दोलन करके जनता के उस भय का पूरा लाभ उठाया। युद्ध से उत्पन्न वड़ी-वड़ी आशाओं के वाद मज़दूरों ने सव कहीं अपने आप को प्रतिरक्षात्मक स्थिति में पाया; उन्हें अपनी विद्यमान स्थिति को कायम रखना मुश्किल हो रहा था, उसमें सुधार की तो दूर की वात थी।

जनता के रवैये के लिए कुछ उपयुक्त आधार भी थे। कम्युनिस्ट इण्टर-नेशनल विश्व-क्रांति का पाठ-पढ़ाती थी और उसके अनुयायी अमरीका में भी थे। १९१९ में वनी स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी में मज़दूर आन्दोलन के बहुत से क्रांतिकारी तत्त्व, जो पहले आई. डब्लू. डब्लू. से सम्वद्ध थे, और अन्य वामपक्षी ग्रुप शामिल हो गए थे। इसके सदस्य अनेक यूनियनों में चोरी-छिपे दाखिल हो गए, उनका प्रभाव उनकी वास्तविक संख्या के अनुपात से कहीं ज्यादा था, अनेक हड़तालें कराने में उनका हाथ था और हिंसात्मक कार्यों के लिए वे लोगों को भड़काते थे। किन्तु जैसा कि पहले होता आया था, भयभीत जनता को मज़दूरों की हड़तालों से—१८७७ में रेल हड़तालों, पुलमैन हड़ताल और १९०२ की कोयला हड़ताल—जव समाज पर क्रांति-कारी खतरा दिखाई देता था तो कम्युनिस्ट प्रभाव को बहुत वढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता था।

इसके अलावा समस्त मज़दूर आन्दोलन पर वोल्शेविज़्म के कलंक का टीका लगाने का रूढ़िवादी मालिकों का प्रयत्न वास्तविकता से बहुत दूर था। ए. एफ. एल. के नेता भी कम्युनिज़्म के उतने ही उग्र विरोधी थे, जितना राष्ट्रीय निर्माता संघ का प्रशासनिक निकाय। कम्युनिस्टों के खिलाफ जिहाद बोलने वालों में जो इस ज़माने में उन्मादपूर्ण असहिष्णुता उत्पन्न करने में

सहायता दे रहे थे, गौम्पर्स उनमें सबसे आगे था। वस्तुतः बोल्शेविज़्म पर लगातार आक्षेप करके मजदूर आन्दोलन को क्रांतिकारी और विध्वंसक हरकतों के उद्योग के आरोपों से मुक्त करने का उसका प्रयत्न एक प्रकार से स्वयं को ही नुकसान पहुँचाने वाला सिद्ध हुआ। जिस ग़ैर-जिम्मेदारी से उसने कम्युनिस्टों के खतरे को बढ़ा-चढ़ा कर बताया, उससे सामाजिक संघर्ष बढ़ने के बारे में जनता का भय बढ़ गया और फलस्वरूप वह हड़तालों का बलपूर्वक दमन करने की माँग करने लगी।

कुछ भी हो, हड़ताल की हलचलों के बारे में अखबारी रिपोर्टों से, अग्रलेख की टिप्पणियों से, कार्टूनों और सार्वजनिक नेताओं के वक्तव्यों से, सबसे यह जाहिर होता था कि जैसे समय गुजरता जाता है, मजदूरों के प्रति जनता का रवैया कठोर हो गया है। प्रगतिशील जमाने की अधिक सहानुभूतिपूर्ण भावना हवा हो गई और उसका स्थान राष्ट्रपति विल्सन की 'नई स्वाधीनता' की समस्त कल्पना के खिलाफ प्रतिक्रियावादिता ने ले लिया। मजदूर जब अधिक वेतन की माँग कर रहे थे तो इस बात की मजाक उड़ायी जाती थी कि फैक्ट्री मजदूर काम करने अपनी कारों में जाएँगे। अपने लिए रेशमी कमीजें और अपनी पत्नियों के लिए रेशमी जुराबें खरीदेंगे! एक अखबार ने लिखा कि हड़तालों की जीवन के हर क्षेत्र के लोग सपाट निन्दा कर रहे हैं। दूसरे ने कहा कि राष्ट्र एकमात्र उसी बड़ी यूनियन को सहन करेगा, "जिसका चिन्ह सितारे और धारियाँ होंगी।"

आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के नाम पर हड़तालों के दमन की राष्ट्रीय नीति अपनाए जाने की लोग ज्यादा ज़ोर से माँग करने लगे। लिटरेरी डाइजेस्ट ने बताया कि १९१९ की समाप्ति तक एक के बाद एक हड़तालें विफल हो रही थी क्योंकि लोकमत की शक्ति मजबूती से और निश्चित रूप से मालिकों के पक्ष में और मजदूरों के विरोध में संघीय, राज्यीय तथा स्थानीय पुलिस के हस्तक्षेप के पक्ष में हो गई थी।

को लेकर यह पनपी और सब मज़दूरों को उसमें शामिल करने की कोशिशों से ही राष्ट्र इतना चिन्तित हो गया कि उस पर बोल्शेविज्म से प्रेरित होने के आरोप लगाए जाने लगे।

यह हड़ताल सिएटल में जहाजी घाट के कर्मचारियों द्वारा अधिक वेतन की माँग किए जाने के कारण हुई। जब उनके मालिकों ने इस माँग को एकदम ठुकरा दिया तो मज़दूरों ने काम छोड़ दिया। इस समय सिएटल में केन्द्रीय मज़दूर समिति पर जेम्स ए. डंकन नाम के एक ऐसे आक्रामक और क्रांतिकारी आन्दोलनकर्ता का नियंत्रण था, जिसने आइ. डब्लू. डब्लू. द्वारा समस्त उत्तर-पश्चिम में पैदा किए गए कटुतापूर्ण औद्योगिक संघर्ष के फलस्वरूप सत्ता प्राप्त की थी। वह ए. एफ. एल. की रूढ़िवाद मज़दूर नीतियों का मुखर विरोधी था। उसने युद्ध में हमारे प्रवेश का सख्त विरोध किया था। उपद्रव खड़ा करने का अवसर पाकर उसने सिएटल में सब कर्मचारियों को हड़ताल का आह्वान किया। ६०,००० ने उसका साथ दिया और ५ दिन तक शहर का औद्योगिक जीवन करीब-करीब ठप्प रहा और नागरिकों को अधिकांश सामान्य सेवाओं से वंचित रहना पड़ा।

आम हड़ताल अमरीका में एक नई चीज़ थी और उत्तर पश्चिम तथा समस्त देशों में लोकमत के बढ़ते हुए विरोध ने इनमें शामिल होने वाली यूनियनों को यह महसूस करा दिया कि इस प्रकार के तौर-तरीकों से वे जनता की सम्पूर्ण सहानुभूति खो रही हैं। उन्होंने केन्द्रीय मजदूर समिति से अपने सहयोग का हाथ खींच लिया और हड़ताल का कचूमर निकल गया। किन्तु इस बीच मेयर ओल हैन्सन के इस सनसनीखेज़ वक्तव्य को राष्ट्र के समाचार-पत्रों ने बड़ी मोटी-मोटी सुर्खियों में छापा कि यह समस्त घटना बोल्शेविकों का षड्यन्त्र थी जिसे सिर्फ उसके साहसपूर्ण उपायों से ही कुचला जा सका है।

इससे भी ज्यादा क्षुब्धकारी हड़ताल कुछ महीने बाद बोस्टन पुलिस की हुई। अपने कम वेतन और काम की अन्य हालतों से, जिसे वह अन्यायपूर्ण समझती थी, असन्तुष्ट होकर पुलिस ने एक यूनियन बना ली थी, जिसे बोस्टन सोशल क्लब कहा जाता था और ए. एफ. एल. से चार्टर दिए जाने की माँग की। पुलिस कमिश्नर कर्टिस ने तत्काल यह घोषणा कर दी कि किसी भी ... को यूनियन में शामिल नहीं होने दिया जाएगा और यूनियन में

शामिल होने वाले ऐसे १६ व्यक्तियों को मुअत्तिल कर दिया और यूनियन की गतिविधि जारी रहने पर उनका स्थान लेने के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती शुरू कर दी। इस प्रकार की अनधिकृत और मनमानी कार्रवाई से क्रुद्ध होकर पुलिस ने मामला अपने हाथ में ले लिया और ९ सितम्बर को उसने अचानक हड़ताल कर दी। उस रात बोस्टन में पुलिस का संरक्षण बिल्कुल भी नहीं रहा और उसके घबराए नागरिक परेशान थे, कि जाने क्या अपराध और हिंसात्मक कार्य हो जाएँ। इन परिस्थितियों में गुण्डों ने काफी दंगे किए भी किन्तु ऐसी आम अव्यवस्था नहीं फैली, जितनी आशंका थी। अगले दिन स्वयंसेवकों तथा स्टेट गार्डों ने पुलिस का काम सम्हाल लिया और पूर्ण व्यवस्था फिर से कायम हो गई।

अत्यधिक जटिल विवादग्रस्त मामलों का निबटारा इतना आसान नहीं था। हड़ताल की जिम्मेदारी के लिए और स्वयंसेवक दल को जिसे इसी प्रकार के आपात काल में सेवा के लिए बनाया गया था, तुरन्त ही ड्यूटी पर तैनात न कर सकने के लिए आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए। पुलिस कमिश्नर और मेयर में विवाद चल रहा था। पुलिस कमिश्नर ने जहाँ उन शिकायतों पर विचार करने से इन्कार कर दिया, जिनके कारण हड़ताल हुई थी या जिन लोगों ने इसमें भाग लिया था उन्हें पुनः अपने पदों पर बहाल करने से मना कर दिया था, वहाँ मेयर ने हड़तालियों से काफी अधिक सहानुभूति दिखाई और आरोप लगाया कि सारे मामले को ठीक तरह से नहीं सम्हाला गया। ए. एफ. एल. के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कमिश्नर को विवाद हल करने के बजाय मजदूरों को बदनाम करने की कोशिश करने में ज्यादा दिलचस्पी है और वस्तुतः उन्होंने स्वयं पुलिस को हड़ताल के लिए भड़काया है।

पुलिस के समर्थन में चाहे कुछ भी कहने की कोशिश की गई हो, लोगों ने सामान्यतः अपने पद से अलग होने के लिए उसकी निन्दा की और उन्हें फिर से काम पर लेने में पुलिस कमिश्नर कर्टिस की इन्कारी का समर्थन किया। "सभ्यता के खिलाफ अपराध" यह थी हड़ताल पर राष्ट्रपति विल्सन की तीखी टिप्पणी और एक भावी राष्ट्रपति ने इसके लिए इससे भी ज्यादा कड़े शब्द इस्तेमाल करके राष्ट्रव्यापी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। गीम्पर्स ने

मैसाच्युसेट्स के गवर्नर कालविन कूलिज से पुलिस कमिश्नर को हटाने की प्रार्थना की। उन्होंने इन्कार कर दिया। उनका संक्षिप्त तार था : "सार्वजनिक सुरक्षा के खिलाफ हड़ताल करने का किसी को, कहीं भी, किसी समय कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता।" जनता इस प्रकार की भावनाओं पर खुश थी, बोस्टन की पुलिस को पुनः काम पर नहीं लिया गया और कूलिज व्हाइट-हाउस के पथ पर अग्रसर हो चले।

यद्यपि सिएटल की आम हड़ताल और बोस्टन की पुलिस हड़ताल पर सारे राष्ट्र का ध्यान गया तो भी ये स्थानीय मामले ही थे। राष्ट्रीय और उद्योग-व्यापी परिणामों की दृष्टि से इस्पात और कोयला उद्योगों में हड़तालें उनसे कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण थीं। १९१९ की परिस्थितियों में उन्हें विफल कर दिया गया किन्तु उनसे औद्योगिक संघर्ष के एक नए नमूने की जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद काफी तेज हो गया, झाँकी मिली। इस्पात की हड़ताल विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण थी। अगर यह हड़ताल सफल हो जाती तो १९२० के दशक का समस्त मजदूर इतिहास बिल्कुल दूसरे प्रकार का होता। किन्तु हड़ताल के दमन के फलस्वरूप अगले १८ वर्ष तक इस बुनियादी उद्योग में मज़दूरों का प्रभावशाली संगठन स्थगित हो गया।

इस्पात मिलों में काम की हालतों से सर्वत्र असन्तोष फैला हुआ था और मज़दूर नेता जो यह कहा करते थे कि अगर मज़दूर अपनी शिकायतों पर कुछ गौर किए जाने की आशा करते हैं तो उन्हें यूनियन बनानी होगी, उसकी उनसे पुष्टि होती थी। युद्धकालीन प्रगति के बावजूद वेतन कम रहे और रहन-सहन का खर्चा निरन्तर बढ़ते जाने से वे और भी पिछड़ते जा रहे थे। आधे से अधिक मज़दूरों के लिए काम के घण्टे सप्ताह के छहों दिन अब भी १२ और सप्ताह में काम के औसत घण्टे ६९ से कुछ ही कम थे। अधिकांश कर्मचारी बाहर से आए हुए अलग ग्रुपों के लोग थे और उनकी रहन-सहन की हालत अधिक सुख-सुविधापूर्ण जीवन के वायदे पर, जिससे आकर्षित होकर वे इस 'अवसरों के देश' में आए थे, एक कटु विडम्बना थी।

अन्य उद्योगों में मजदूरों ने जो संगठनात्मक प्रगति की, वैसा इस्पात उद्योग में कोई उदाहरण न था। १९०१ और १९१० में पुरानी ऐमलगमेटेड [illegible] आव आयरन, स्टील ऐण्ड टिन वर्कर्स की हड़तालों के दमन के

बाद से इन उद्योगों में यूनियन बनाने के और प्रयत्न नहीं किए गए। । यद्यपि ऐमलगमेटेड का अस्तित्व अब भी था, तो भी यह एक छोटी सी शिल्प यूनियन रह गई थी जिसे अदक्ष मज़दूरों के विशाल समुदाय से कोई सरोकार नहीं था।

हड़ताल की ओर पहला कदम १९१८ की गर्मियों में उठाया गया जबकि इस्पात उद्योग पर अधिकार क्षेत्र वाली २४ यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक संगठन समिति बनाई गई। इसका उद्देश्य न केवल मिलों में काम की हालतों में सुधार करना बल्कि यूनियन मज़दूरों द्वारा इस कुंजी उद्योग को हथियाना भी था। इसके लिए अनुप्राणित करने वाला व्यक्ति था विलियम जेड. फौस्टर, जो सीधी आर्थिक कार्रवाई का क्रांतिकारी प्रवक्ता था, जिसने औद्योगिक संघर्ष में अपने प्रारम्भिक अनुभव आइ. डब्लू. डब्लू. में रहकर प्राप्त किए थे और जो बाद में एक प्रमुख कम्युनिस्ट बन गया। उसकी संगठन शक्ति कमाल की थी और ऐसोसियेटेड यूनियन समिति के सचिव-कोषाध्यक्ष के रूप में "अमरीका के इस्पात कारखानों में संगठन के लिए" एक विशाल अभियान करने का काम उसके सुपुर्द कर दिया गया।

इस्पात कारखानों में संगठित श्रमिकों की संख्या एक वर्ष के अन्दर ही एक लाख हो गई और युनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन के चेयरमैन गैरी के साथ एक श्रमिक समझौते के लिए वार्ता चलाने की कोशिश की गई। जब उसने इस प्रार्थना की बिल्कुल उपेक्षा कर दी तो एक हड़ताल-मत लिया गया और इस्पात कर्मचारियों की तरफ से यूनियन समिति ने सामूहिक सौदेबाजी, ८ घंटे के दिन और वेतनों में वृद्धि की माँग की। इन माँगों पर विचार के के लिए बातचीत करने के और प्रयत्नों का गैरी ने असंदिग्ध शब्दों में टका-सा जवाब दिया, "हमारा कार्पोरेशन और उसकी सहायक संस्थाएँ यद्यपि वे इस प्रकार मज़दूर यूनियनों को मुँह नहीं लगातीं, उनके साथ कोई विचार-विमर्श करने से इन्कार करती हैं।" तब १२ सितम्बर को हड़ताल करने का बाकायदा निश्चय कर लिया गया और महीने के अन्त तक कई राज्यों में ३५,००,००० व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया।

इस्पात-उद्योग विश्व में सबसे शक्तिशाली पूँजीवादी ताकत—इस चुनौती का सामना करने को उद्यत थी और हड़ताल तोड़ने के दृढ़ संकल्प में उसे

स्थानीय, राज्य और यहाँ तक कि संघीय अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग मिला। हज़ारों हड़ताल-भंजक विशेषकर नीग्रो ले आए गए। मिलों में के भिन्न-भिन्न प्रकार के विदेशी तत्त्वों के बीच दुश्मनी और जातीय वैर-भाव पैदा करने के लिए मजदूर गुप्तचर रखे गए, और स्थानापन्न गार्डों, स्थानीय पुलिस, राज्य की पुलिस ने धरना देने वालों की पंक्तियों को तहस-नहस कर दिया और नागरिक-स्वाधीनता के कानूनों की परवाह न करते हुए हड़तालियों की सभाएँ भंग कर दीं। अनेक बस्तियों में मार्शल ला लगाकर हिंसा पर काबू पाने का यत्न किया गया, मेजर जनरल वुड की कमान में गैरी (इण्डियाना) में सेनाएँ भेजी गईं किन्तु फिर भी हड़ताल खत्म होने तक कोई २० व्यक्ति मारे गए, जिनमें १८ मज़दूर थे।

इस्पात कम्पनियों ने मज़दूरों को हतोत्साह करने और लोकमत को यह विश्वास कराने के लिए यह सब काण्ड अमरीकी पूँजीवाद को उलट देने के लिए मास्को में पकाया हुआ एक षड्यन्त्र है, अखबारों में इश्तिहारों के जरिये धूँआधार प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि हड़ताल-श्रमिकों और मालिकों के बीच नहीं बल्कि क्रान्तिवादियों और अमरीका के बीच है। यह सफल नहीं हो सकती क्योंकि "आई. डब्लू. डब्लू. वाद या अन्य कोई भी वाद हो जो, संविधान को फाड़ डालना चाहता है, अमरीका बोल्शेविज्म के 'लाल' शासन का कभी हामी नहीं बनेगा।" यह अफवाह भी उड़ाई गई कि "हड़ताल को भड़काने में तोड़-फोड़ करने वालों" का भी हाथ है जो औद्योगिक प्रगति को रोकने की आशा करते हैं।

इन परिस्थितियों में इतनी ज्यादा उत्तेजना और विवाद उत्पन्न हुआ कि प्रोटैस्टैण्ट चर्चों के संगठन इण्टर चर्च वर्ल्ड मूवमेण्ट ने हड़ताल की पड़ताल करने के लिए एक जाँच कमीशन नियुक्त किया। इसको ऐसे शैतानीपूर्ण षड्-यंत्रों का कोई प्रमाण नहीं मिला, जिनका इस्पात कम्पनियों ने पता लगाने का दावा किया था और कहा कि मज़दूरों के विद्रोह को "बोल्शेविज्म की निराधार उत्तेजना की चकाचौंध" के बजाय औद्योगिक इतिहास के प्रकाश में देखना ज्यादा लाभदायक है। किन्तु हड़ताल के क्रांतिकारी अराजकतावाद और कम्यु-निस्टी पहलुओं पर बार-बार दिया गया जोर फौस्टर के वामपक्षी विचार

इस्पात कर्मचारियों के प्रति आम जनता की सहानुभूति को खत्म करने में सफल हो गए, यद्यपि मिलों में काम की कठोर हालतों के विषय में जो तथ्य सामने आए थे, उनका किसी ने प्रतिवाद नहीं किया था। जनता बोल्शेविज़्म को सक्रिय मानने के लिए तैयार बैठी थी। इसी तथ्य को कि इस्पात कर्मचारियों में से इतने ज्यादा लोग 'पूर्व-मध्य यूरोप के हुंकी' स्पेनिशिया इटालियन 'डैगी' और 'वौप' थे। इस बात का पर्याप्त प्रमाण मान लिया गया कि वे अमरीका-विरोधी, क्रांतिकारी और मास्को द्वारा नियन्त्रित हैं।

हड़ताल समिति को इस प्रचार का सफलतापूर्वक मुकाबला करने का कोई उपाय नज़र नहीं आया। संयोजक यूनियनों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, ए. एफ. एल. ने फौस्टर के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया और स्वयं हड़तालियों में निराशा छाने लगी। फलस्वरूप नवम्बर के आखीर में यूनियन समिति ने इण्टरचर्च कमीशन से मध्यस्थता करने के लिए कहा और झगड़े को समाप्त करने के लिये उसकी किसी भी योजना को स्वीकार करने को उद्यत हो गई। गैरी ने किसी भी शांति-प्रस्ताव पर ध्यान देने से इन्कार कर दिया। उसने कहा : "हड़ताली चाहते हैं—बन्दशाप, सोवियत, सम्पत्ति का जबरन वितरण...मामला है ही कोई नहीं।" हड़ताल खिचती रही किन्तु निराश मज़दूर अब काम पर लौटने लगे। जनवरी १९२० में नेताओं ने हार मान ली। हड़ताल वापस ले ली गई और इस बीच जिन मज़दूरों के नाम काली सूची में दर्ज नहीं किए गए थे, वे एक भी रियायत पाये बिना काम पर लौट आए।

इण्टरचर्च कमीशन ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में लिखा कि "यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन इतना विशाल है कि ३००००० मज़दूर उसे परास्त नहीं कर सकते। इसके पास इतनी ज्यादा फालतू नकदी है, अन्य व्यवसायों में इसके इतने अधिक दोस्त हैं, स्थानीय व राष्ट्रीय सरकारी अफसरों का उसे इतना अधिक सहयोग प्राप्त है; प्रेस और उपदेश मंच जैसी सामाजिक संस्थाओं पर उसका इतना ज्यादा प्रभाव है, और हमारे प्रदेश पर अत्यधिक फैला होने पर भी वह इतना पूर्ण केन्द्रीय नियन्त्रण कायम रखे हुए है—कि उसे अनेक विचारों और आशंकाओं वाले और विभिन्न 'वज़न की जेबों वाले' बहुत ज्यादा बिखरे हुए मज़दूर अपेक्षाकृत दुर्बल नेतृत्व में कभी नहीं

हरा सकते ।"

अगर मज़दूरों को अन्य बड़े पैमाने के उद्योगों में यूनियनें बनानी थीं, जिनमें उनके यूनियन बनाने पर प्रतिबन्ध था तो इस्पात उद्योग में संगठन करना उनके लिए निर्णायक बात थी। व्यावसायिक और वित्तीय वर्ग ने ओपनशाप और औद्योगिक यूनियन के बीच निर्णयात्मक संघर्ष के रूप में सन् १६१६ की हड़ताल के महत्त्व को पूर्णतः समझ लिया था। यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन का भरपूर साथ दिया गया। जे. पी. मार्गन ने गेरी की इस बात का पूर्ण समर्थन किया कि वह यूनियनों से कोई सरोकार नहीं रखेगा। मज़दूरों की माँग पर विचार करने तक से इन्कार कर देने का औचित्य जताने के लिए बोल्शेविज़्म के हौए का सफल प्रयोग किया गया। हड़ताल का परिणाम यह हुआ कि न केवल पुनः १२ घण्टे का दिन कायम हो गया बल्कि देश के सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग में अनियन्त्रित पितृ-भाव और यूनियन-विरोधिता कायम हो गई।

इस्पात की हड़ताल समाप्त होने से पूर्व ही बिटुमिनस कोयला खानों में हड़ताल हो गई। यूनाइटेड माइन वर्कर्स ने युद्ध-काल में खान-मालिकों के साथ एक करार किया था और १६१६ में कीमतें चढ़ने के बाद वेतनों में हेर-फेर किए जाने की माँग की, जो सन् १६१७ के बाद से बढ़ाई नहीं गई थी। उसने वेतनों में ६० प्रतिशत वृद्धि की और ईंधन के लिए युद्ध-कालीन आवश्यकता समाप्त हो जाने के कारण बढ़ी हुई बेकारी का सामना करने के लिए ३० घण्टे के सप्ताह का प्रस्ताव किया किन्तु मालिकों ने खनिकों की माँगों पर, जो वस्तुतः बहुत ज्यादा थीं न केवल विचार करने से इन्कार कर दिया, बल्कि इस बात पर जोर दिया कि चूँकि युद्ध अभी बाकायदा समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए पुराना करार ही कायम रहेगा। तब एक नवम्बर से हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसमें ४,२५,००० श्रमिकों ने भाग लिया।

कोयले की खानों में काम रुक जाने से राष्ट्रीय अर्थतन्त्र को जो नुकसान हो सकता था, जैसा कि १६१६ से पहले और बाद में भी अन्य अवसरों पर देखने में आया, उससे आम जनता को बड़ी बेचैनी हुई। सरकार पहले ही यह चेतावनी दे चुकी थी कि कोयला-उद्योग के बारे में एक युद्धकालीन कानून के

मातहत यह हड़ताल गैर-कानूनी होगी। न केवल यूनाइटेड माइन वर्कर्स बल्कि सामान्यत: सभी अमरीकी मज़दूर यह देख कर स्तब्ध रह गए कि जो विल्सन सरकार कभी उनके प्रति मैत्रीपूर्ण रुख रखती थी, उसी ने अब इण्डियानापोलिस की संघीय जिला अदालत के जज ऐल्बर्ट वी. ऐण्डर्सन से निरोधादेश प्राप्त करने का सख्त कदम उठाया। इस आदेश के द्वारा यूनियन अधिकारियों को आगे कोई हड़ताल-सम्बन्धी गतिविधि करने से मना कर दिया गया और उन्हें हड़ताल का आदेश रद्द कर देने को कहा गया।

मजदूर यह समझते थे कि सरकार ने यह वचन दे रखा है कि वह हड़तालों का दमन करने के लिए अपने युद्धकालीन अधिकारों का उपयोग नहीं करेगी इसलिए अब उसके हस्तक्षेप करने पर विरोध का तूफान खड़ा हुआ। ए. एफ. एल. ने निरोधादेश को "क्रोध उत्पन्न करने वाली कार्रवाई" और "न्याय और स्वाधीनता की नींव पर प्रहार करने वाला" कह कर उसकी निन्दा दी। उसने खनिकों से अपील की कि वह सरकारी दबाव के आगे झुकें नहीं, और संघर्ष जारी रखने की हालत में उन्हें अपने पूर्ण सहयोग का वचन दिया।

१९१९ में यूनाइटेड माइन वर्कर्स का कार्यवाहक अध्यक्ष एक ४० वर्षीय मज़दूर नेता था, जो युद्धकाल में यूनियन का मुख्य सांख्यिक था और जिसको जनता बिल्कुल नहीं जानती थी। किन्तु जॉन एल. लेविस अपने एक कार्य से घर-घर चर्चा का विषय बन गया। उसने हड़ताल वापस ले ली। यद्यपि उसने निरोधादेश के लिए राष्ट्रपति विलसन की तीव्र निन्दा की तो भी वह ए. एफ. एल. की उग्रतापूर्ण सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं था, और यद्यपि बाद के वर्षों में उसका यह कार्य बड़ा अस्वाभाविक सिद्ध हुआ, उसने घुटने टेक देने की सलाह दी। मज़दूरों के नेतृत्व के इस पहले दौर में लेविस ने पत्र-प्रतिनिधियों के समक्ष कहा : "हम अमरीकी हैं, अपनी सरकार से हम नहीं लड़ सकते।"

स्वयं खनिकों ने, जो एक असाधारण बात लगती थी, उसका आदेश मानने से इन्कार कर दिया। हड़ताल का आदेश रद्द कर दिए जाने के बावजूद वे खानों में काम करने नहीं गए। इससे पूर्व कि उन्हें लौटने के लिए मनाया जा सके, वाशिंगटन में और बैठकें हुईं और एक राज़ीनामा हुआ जिसमें मालिकों ने वेतनों में तुरन्त १४ प्रतिशत वृद्धि करना स्वीकार कर लिया और वेतन

सम्बन्धी तथा अन्य विवादग्रस्त मामलों का अंतिम निबटारा एक बिटुमिनस कोल कमीशन के हाथ में सौंपना मान लिया। अंतिम फैसले के अनुसार वेतनों में २७ प्रतिशत वृद्धि की गई जो खनिकों की मूल मांग से करीब आधी थी किन्तु उसमें ३० घण्टे के सप्ताह की दूसरी मांग की बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई।

हड़ताल सरकारी कार्रवाई से खत्म हुई। यद्यपि खनिकों ने काफी लाभ प्राप्त किए, किन्तु महत्त्वपूर्ण प्रश्न निरोधादेश के कानून का प्रयोग करना था। एक महत्त्वपूर्ण परिपाटी कायम कर दी गई थी। किन्तु सरकार का आदेश मानने की उत्सुकता जाहिर करके लेविस ने दिखा दिया कि ए. एफ. एल. के नेताओं की अपेक्षा वह इस चीज़ को ज्यादा अच्छी तरह समझता था कि हड़तालों को दमन करने में लोकमत कहाँ तक जाने को तैयार था। इस्पात की हड़ताल के बारे में जितना रोष व्यक्त किया गया था, अब कोयला खनिकों की हड़ताल में, जिससे जाड़े आने पर देश के समक्ष ईंधन का संकट उपस्थित हो गया था, उससे भी ज्यादा रोष प्रकट किया जा रहा था।

राष्ट्रपति विल्सन ने कोयला हड़ताल को "नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से गलत" घोषित किया। कांग्रेस ने उनके कथन की पुष्टि की, देशभर के समाचार-पत्रों के अग्रलेखों में निरोधादेश प्रयोग की सराहना की गई। 'चैम्बर्सबर्ग पब्लिक ओपीनियन' की टिप्पणी थी : "न तो खनिकों को और न अन्य किसी संगठित अल्पसंख्यक वर्ग को देश को आर्थिक व सामाजिक विनाश में ढकेलने का कोई हक है......मज़दूर तानाशाही भी उतनी ही खतरनाक है, जितनी पूँजीवादी तानाशाही।" फिलाडेल्फिया पब्लिक लेजर ने कहा : "जब मज़दूरों के विशाल संगठन देश का गला पकड़कर किसी उद्योग के मालिकों को अपनी माँगें मानने के लिए मजबूर करने को जान बूझ कर राष्ट्रव्यापी योजना बनाते हैं तब वे गैरकानूनी षड्यंत्र रचते हैं। और शिकागो डेली न्यूज़ ने साफ-साफ लिखा : "लोग औद्योगिक संघर्ष से थक गए हैं। अब वे अपनी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं।"

निस्सन्देह बोल्शेविज़्म का प्रश्न फिर उठाया गया सेनेटर पायनडेक्सटर ने कहा कि "अराजकतावादी और हत्यारे कम्युनिस्टों" के प्रति सरकार ने जो जरूरत से ज्यादा नरमी दिखाई है, यह हड़ताल उसी का नतीजा है। इस

समझौते के बाद न्यूयार्क ट्रिब्यून ने कहा कि अन्ततोगत्वा सरकार ने जो दृढ़ नीति अपनायी वह एक उदाहरण भी है और चेतावनी भी। "रूस में इसका डंका बजा दो, मास्को की गलियों पर इसकी घोषणा कर दो और स्वदेश के सब विध्वंसकारियों के मन में इसे पैठा दो।"

यद्यपि १९१९ की हड़तालों से मज़दूरों को बहुत धक्का लगा और उन्होंने समझा कि विल्सन सरकार ने उन्हें धोखा दिया है और उनके मन में उससे वितृष्णा पैदा हुई तो भी यूनियनों द्वारा युद्धकाल में की जाने वाली प्रगति रुकी नहीं। पराजयों के बावजूद मज़दूरों का जोश ठण्डा नहीं हुआ था। अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में वह वेतन बढ़वाने में कामयाब हुआ और यूनियनों की सदस्य संख्या बढ़ती रही। ए. एफ. एल. से सम्बद्ध ११० यूनियनों में से मशीन-चालकों, संचालनकार्य से इतर रेलवे कर्मचारियों, टैक्सटाइल कर्मचारियों और जहाज़ी नाविकों की यूनियनों ने महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए और खाना व कपड़ा जैसे उद्योगों में अदक्ष और अर्धदक्ष दोनों प्रकार के कर्मचारियों का संगठन किया जा रहा था।

तो भी ए. एफ. एल. के सामने कठिनाइयाँ बढ़ती गईं। व्यावसायिक यूनियनवाद के अपने कार्यक्रम पर अमल करने में जिस सरकारी सहयोग की उसने आशा की थी, उसकी जगह निरोधादेश कानून का फिर से आश्रय लिया जाने लगा और फलस्वरूप उसपर ज्यादा आक्रामक तरीके अपनाने के लिए दबाव पड़ने लगा। किन्तु संघ के नेताओं ने अब भी किसी राजनीतिक कार्रवाई में भाग लेने से इन्कार कर दिया और मज़दूर दल की स्थापना के नए सुझाव को ठुकराते हुए ए. एफ. एल. के परम्परागत गैर-राजनीतिक उद्देश्यों की नीति पर पुनः बल दिया। १९१९ के एक सम्मेलन में "मज़दूरों के एक नए अधिकार-पत्र की घोषणा की गई जिसमें यूनियन को मान्यता दिए जाने, जीवन-यापन के लायक वेतन दिए जाने और निरोधादेशों के प्रयोग को मर्यादित करने की माँग की गई किन्तु इससे आगे जाने से फेडरेशन ने इन्कार कर दिया।

परिस्थितियों ने इस प्रकार के कार्यक्रम को पहले से भी कठिन बना दिया। अगले वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही देश में यकायक भारी मन्दी आ गई। युद्धकाल में जो व्यावसायिक तेजी आई थी, उसके युद्ध के बाद ठप्प हो

जाने से कीमतें लुढ़क पड़ीं, कारोबार फेल हो गए, उद्योगों ने तरक्की करनी बन्द कर दी। सब जगह वेतनों में कटौतियां हुईं और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। १९२१ के मध्य ग्रीष्म तक ५० लाख व्यक्ति बेकार हो गए। उद्योग ने इन परिस्थितियों का तुरन्त लाभ उठाकर यूनियनों के खिलाफ अपना जिहाद तेज़ कर दिया। निरोधादेश और गिरफ्तारियों ने नाविकों की एक हड़ताल तोड़ दी और बाद में मज़दूरों की जो काली सूची बनाई गई उससे इस यूनियन की ताकत युद्ध काल की अपेक्षा २० प्रतिशत से भी कम रह गई। खाद्य पदार्थ पैक करने के उद्योग के कर्मचारियों की इतनी बुरी हार हुई कि उद्योग पुनः ओपनशाप पर आ गया और १९२२ में रेलवे वर्कशाप के कर्मचारियों को, जिनपर सब ओर से आक्षेप किए जा रहे थे और भी बुरी तरह मात खानी पड़ी।

यह हड़ताल तब हुई जब कि १९२० में रेलों का स्वामित्व फिर से निजी हाथों में सौंप दिए जाने पर कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध निश्चित करने के लिए नियुक्त रेलवे लेबर बोर्ड ने युद्ध-काल में किए गए समझौते मंसूख कर दिए, ओवरटाइम खत्म कर दिया और वेतनों में कुल ६ करोड़ डालर की कटौती का अधिकार दे दिया। वेतनों में इस कटौती का रेलवे ब्रदरहुडों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और पटरी की देखभाल करने वाले कर्मचारियों ने पंचफैसला स्वीकार कर लिया किन्तु वर्कशाप कर्मचारियों की ६ शिल्प यूनियनों के सदस्य बोर्ड द्वारा मालिकों के दबाव के आगे प्रत्यक्षतः झुक जाने से क्रुद्ध हो गए। हड़ताल का आह्वान किया गया और १ जुलाई १९२२ को वर्कशाप के ४००००० कर्मचारियों ने काम बन्द कर दिया।

उन्हें शुरू से ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। रेलवे लेबर बोर्ड ने हड़ताल को गैरकानूनी घोषित कर दिया। ब्रदरहुडों ने रेलों को चलाने में मालिकों को सहयोग देने का प्रस्ताव किया। राष्ट्रपति हार्डिंग ने डाक में कोई हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेतावनी दी और लोगों की सहानुभूति सर्वथा कर्मचारियों के खिलाफ हो गई। लोकमत शायद इस तथ्य से सबसे अच्छी तरह प्रकट हुआ कि विशेष गार्डों और मिलीशिया के संरक्षण में लाए गए हड़ताल भंजकों में सैकड़ों कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे। किन्तु यहीं इति नहीं थी। १ सितम्बर को जब हड़ताल कैसे भी विफल होने को थी तो अंतिम

प्रहार सरकार ने किया। अटार्नी जनरल डौहर्टी ने शिकागो में संघीय जिला अदालत के जज जेम्स एच. विल्करसन से एक निरोधादेश ले लिया जिसे "अब तक के किसी श्रम-विवाद में लिया गया सबसे व्यापक निरोधादेश" कहा जाता था।

इसमें किसी भी प्रकार का धरना देने, हड़ताल के सम्बन्ध में सभाएँ करने, जनता के नाम वक्तव्य जारी करने, हड़ताल जारी रखने के लिए यूनियन कोष खर्च करने तथा इसके संचालन के लिए नेताओं द्वारा किसी भी संचार साधन के प्रयोग पर पाबन्दी लगा दी गई। किसी को भी "पत्रों, तारों, टेलीफोनों या मुँह से कोई शब्द निकाल कर भी हड़तालियों को मदद देने की और मज़ाक उड़ा कर, प्रार्थना करके, युक्ति-प्रत्युक्ति करके, आग्रह करके, प्रलोभन देकर अथवा अन्य किसी भी प्रकार से किसी को काम करना बन्द करने की प्रेरणा देने की इजाजत नहीं दी गई।" डौहर्टी का किसी भी लागत पर हड़ताल को तोड़ देने का इरादा था। उसने प्रेस प्रतिनिधियों को कहा : "मैं जब तक और जिस हद तक अमरीकी सरकार की तरफ से बोल सकता हूँ, तब तक और वहाँ तक मैं प्राप्त शासनाधिकार का उपयोग देश की मज़दूर यूनियनों को ओपनशाप नष्ट करने से रोकने के लिए करूँगा।"

इस कठोर कदम से देश भर में तीव्र विवाद छिड़ गया। न केवल मज़दूरों से सहानुभूति रखने वाले अखबारों ने बल्कि अन्य बहुत से अखबारों ने भी बहुत से मामलों में शायद दलीय भावना से प्रेरित होकर निरोधादेश को सर्वथा अनधिकृत और भाषण-स्वातंत्र्य पर कुठाराघात बताया। 'न्यूयार्क इवनिंग पोस्ट' ने लिखा कि यह हड़ताल की आसन्न विफलता को इसी दृष्टि से देख रहा था कि यह बहुत उचित ही है किन्तु यह नियमों के प्रतिकूल "कमर से नीचे किया गया प्रहार" है। "नेवार्क न्यूज" ने निरोधादेश को "मुँह बन्द करने वाला कानून" बताया और न्यूयार्क वर्ल्ड ने इसे "एक भद्दा कदम" कह कर इसकी निंदा की। दूसरी ओर कंजरवेटिव रिपब्लिकन अखबारों ने सरकार की नीति का पक्ष-पोषण करने की कोशिश की। न्यूयार्क ट्रिब्यून, फिलाडेल्फिया इन्क्वायरर, द बोस्टन ट्रान्सक्रिप्ट और शिकागो डेली न्यूज़ ने यह कहा कि यह निरोधादेश कितना भी व्यापक हो, लेकिन समस्त रेल-परिवहन को खतरे में डालने वाले वर्कशाप कर्मचारियों की कानून का पालन न करने की प्रवृत्ति से ज्यादा

व्यापक नहीं है। मज़दूरों के दुश्मनों की ओर से अंतिम शब्द शायद मैन्यू-फैक्चरर्स रिकार्ड ने कहे। इसने कहा कि निरोधादेश कर्मचारियों को सिर्फ इस बात का हुक्म देता है कि वे "अव्यवस्था के साथ अपना व्यभिचारपूर्ण सहवास बन्द कर दें।"

रेलवे वर्कशाप के कर्मचारियों के लिए सरकार का हस्तक्षेप अंतिम तिनका था। उन्होंने अलग-अलग रेलों से अलग-अलग समझौता करने के बाल्टीमोर और ओहायो के प्रेज़ीडेण्ट विलर्ड के प्रस्ताव को उत्सुकतापूर्वक लपक लिया और जितना अच्छा समझौता वे कर सकते थे, उन्होंने किया। कुल रेलवे लाइनों के मित्रतापूर्ण रुख के कारण वे कोई २,२५००० कर्मचारियों के लिए अपना यूनियन संगठन कायम रख सके, किन्तु १,७५,००० को कम्पनी यूनियनों में शामिल होना पड़ा। सरकारी हस्तक्षेप ने पलड़ा मालिकों के पक्ष में कर दिया था और रेलवे मज़दूरों को एक भीषण आघात सहना पड़ा।

१९२१-२२ की मन्दी में सारा मज़दूर आन्दोलन क्षीण होता गया और जब निरोधादेश कानून का बल पाकर पूंजीपतियों का जवाबी हमला जोर पकड़ने लगा तो वह बेकारी के पस्त हिम्मत कर देने वाले प्रभाव के कारण अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं जुटा सका। कुछ यूनियनें बिल्कुल कुचल दी गईं, अन्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध से मज़दूर बहुत संगठित होकर निकले थे, अपने लाभों को बढ़ाने का उनका दृढ़ संकल्प था और उसे विश्वास था कि मैत्रीपूर्ण सरकार की संरक्षा में वह सब अमरीकी मज़दूरों के जीवन-स्तर को उन्नत कर सकेगा। किन्तु १९२० और १९२३ के बीच यूनियनों की समग्र संख्या ५० लाख से कुछ अधिक की चरम संख्या से घट कर लगभग ३५ लाख रह गई।

—:o:—

१४ : मज़दूर पीछे हटे

१९२२ से १९२९ के ७ वर्षों में उत्पादन बढ़ा, आर्थिक शक्ति और ज़्यादा केन्द्रित हुई, राष्ट्रीय आय बढ़ती रही और अर्थतंत्र में १९वीं सदी के स्वच्छन्द कारोबार के सिद्धान्त पर वापस आ गए। सरकार पर ज्यादातर उद्योगपतियों का प्रभुत्व था और युद्ध-पूर्व के प्रगतिशील लोगों ने आर्थिक और सामाजिक सुधारों की जो पगडण्डी तैयार की थी उस पर आगे कोई प्रगति नहीं हुई। समृद्धि और ऊँचे उठते हुए स्टाक मार्केट, सट्टा और हर गराज में दो कारें, इन्हीं सब बातों का महत्त्व प्रतीत होता था। अपनी स्थिति से सन्तुष्ट लोगों ने १९२८ में राष्ट्रपति हूवर की यह विश्वासपूर्ण घोषणा खुशी से स्वीकार कर ली कि "अमरीका में हम लोग गरीबी पर अंतिम विजय प्राप्त करने के इतने निकट आ गए हैं जितना किसी देश के इतिहास में लोग पहले कभी नहीं आ सके।"

१९२० की दशाब्दि "आश्चर्यजनक बेहूदगी" का ज़माना भी थी। नौजवान पीढ़ी ने विद्रोह कर दिया था। शराब की गैर-कानूनी दूकानों, मदिरा के तस्कर व्यापार और गिरोह बांध कर जुर्म करने का बोलबाला था। अखबारों की सनसनीखेज़ ढंग से खबरें देने की प्रवृत्ति से लोगों का ध्यान एक लाख डालर इनाम की लड़ाइयों, बहुत दूरी की लम्बी दौड़ों, स्कोप्स मंकी ट्रायल, लिण्डबर्ग की अटलाण्टिक के आर-पार की उड़ान और स्नानसौन्दर्य प्रतियोगिताओं पर टिका रखा था। अमरीका का सारा नज़ारा ही सजीव, रंगीन और रोमांचक था।

देश के कोई ३ करोड़ गैर-कृषि जीवी मज़दूरों ने इस राष्ट्रीय विकास में अपना पूर्ण योग दिया और सामान्यतः इस बढ़ती हुई समृद्धि में हाथ बँटाया। वेतन बढ़े और यद्यपि हर गराज में कारों की बात एक सुदूर स्वप्न ही रही तो भी खाना, मकान और कपड़े के खर्च के बाद अब मज़दूर की जेब में पहले किसी भी समय की अपेक्षा ज्यादा पैसा बच रहा था। मोटरें, वैक्यूम क्लीनर, कपड़ा धोने की मशीनें और बिजली के रेफ्रिजरेटर किश्तों में खरीदने की

भव्वड़ में मज़दूर भी सामान्य जनता के साथ शामिल थे। और मनोरंजन तथा आमोद-प्रमोद के लिए १० अरब डालर के खर्च में उनका भी अपना हिस्सा था। कभी-कभी स्टाकमार्केट में भी उन्होंने पैसा लगाया और विलियम ग्रीन ने वालस्ट्रीट की विनियोग फर्म हैलर्स स्टुअर्ट ऐण्ड कम्पनी के लिए "मज़दूर और उसका पैसा" विषय पर ब्राडकास्ट भी किया।

एक उत्साही फ्रांसीसी यात्री आन्दे सीगफ्रिड ने १६२७ में लिखा : "एक मज़दूर को संसार के अन्य किसी भी प्रदेश की अपेक्षा अमरीका में कहीं ज्यादा पैसा मिलता है और उसका जीवनस्तर बहुत ही उन्नत है। यह फर्क जो युद्ध से पहले भी दिखाई देता था, तब से बहुत बढ़ गया है और अब पुराने और नए महाद्वीप में मुख्य फर्क बन गया है...।"

अमरीकी नज़ारे पर समग्रतः दृष्टिपात करने पर वास्तव में यह दिखाई देता था कि अधिकाधिक मज़दूर मध्यम वर्ग में शुमार होते जा रहे हैं। अब जब कि उन्हें न केवल ऊँची तनख्वाहें मिल रही थीं, जिनकी बदौलत वे कभी स्वप्न सी दिखाई देने वाली सुख-सुविधाओं का उपभोग कर रहे थे, अपितु काम के घण्टे कम हो जाने से जीवन के अन्य पहलुओं का आनन्द लेने को उन्हें खाली समय भी अधिक मिल रहा था। तब मज़दूरों की पहले के समान कोई अलग श्रेणी नजर नहीं आती थी। उनके मनोरंजन और आमोद-प्रमोद अधिकाधिक राष्ट्रव्यापी ढंग के होते चले गए। देश की सड़कों पर हर रविवार को जो मोटरें निकल पड़ती थीं; सिनेमाओं में हर सप्ताह जो विशाल भीड़ लगती थी; रेडियो प्रसारण सुनने के लिए जितनी संख्या में लोग एकत्र होते थे, वे सब अधिक एकरस समाज के उद्भव के प्रतीक थे। अगर फैक्ट्री कर्मचारी वही कपड़े नहीं पहनते थे जो ज्यादा वेतन पाने वाले लोग पहनते थे तो भी उनके डिजाइन एक से होते थे। समाजशिक्षा के सदी पुराने स्वप्न की लगभग पूर्ति में मज़दूरों के लड़के-लड़कियाँ महान् राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते थे। बीसियों तरीकों से मज़दूर आम लोगों के रीति-रिवाजों और आकाङ्क्षाओं को अपना रहे थे। सामाजिक लोकतंत्र ने अमरीकी जीवन-पद्धति के रूप में एक नई सार्थकता प्राप्त कर ली प्रतीत होती थी।

आव्रजन में कटौती कर दिए जाने से इस प्रक्रिया में सहायता मिली। ।गक मज़दूर की हालत सदैव खराब रहने का एक बड़ा कारण हर वर्ष

अज्ञानी, दरिद्र और अदक्ष आव्रजकों का आगमन रहा है। १९२० के दशक के मध्य में कोटा पद्धति अपना लिए जाने से, आव्रजकों की संख्या ५० लाख वार्षिक से गिरकर १॥ लाख वार्षिक रह गई। इसका न केवल मजदूर की आर्थिक दशा पर बल्कि सामाजिक अवस्था पर भी गहरा असर पड़ा। परम्परागत फालतू मजदूरों का आगमन बन्द कर दिए जाने से प्रगति के नए रास्ते खुल गए। जरूरी नहीं कि ये रास्ते मजदूरों को मालिक वर्ग में ले जाने वाले हों तो भी इससे हमारे विकासमान समाज में उसका स्थान अधिक सुरक्षित हो गया।

किन्तु १९२० की दशाब्दि में इस बात की ज्यादातर उपेक्षा कर दी गई कि मजदूरों के बीच इन भौतिक और सामाजिक लाभों के वितरण में अब भी बहुत विषमता से काम लिया जाता था जैसा कि देश भर में समृद्धि के इस वितरण में विषमता दिखाई देती थी। आर्थिक विस्तार से उत्पन्न बाहुल्य की इस दावत में अनेक तबकों के मजदूरों को शामिल होने का न्यौता नहीं दिया गया और जिन मजदूरों को वेतन-वृद्धि से सबसे ज्यादा लाभ हुआ था वे भी यह महसूस करते थे कि इस समृद्धि में मिलने वाला उनका हिस्सा उद्योग-पतियों के मुनाफों के मुकाबले अनुपात की दृष्टि से बहुत कम है।

इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि बेकारी को देश-निकाला नहीं दिया जा सका। कई क्षेत्रों में वह बहुत ज्यादा थी। तकनीकी प्रगति के कारण जो उद्योग को अपेक्षाकृत कम मजदूरों से अधिक सामान पैदा करने में निरन्तर सहायता दे रही थी, बहुत से बुनियादी उद्योगों में वेतन भोगी मजदूरों की संख्या बहुत घट गई। सिर्फ सड़क बनाने के काम में, कपड़ा उद्योग, रबड़ उद्योग और बिजली का सामान बनाने वाले कारखानों में ही नई मशीनों और मजदूरों की बचत करने वाले यंत्रों के उपयोग से विद्यमान उत्पादन को बनाए रखने के लिए २५ से ६० प्रतिशत मजदूरों की छँटनी कर दी गई। हिसाब

मनुष्य-दिवसों के हिसाब से मज़दूरों की कुल उपलब्धि की १० से १३ प्रतिशत रही। १९२८ में कम से कम २० लाख मज़दूर बेकार थे।

इन परिस्थितियों में मज़दूर को अपने काम के बारे में असुरक्षा की जो भावना होती थी उसकी काम से लगे रहने पर ऊँचे वेतनों से पूरी भरपाई नहीं होती थी। मिडलटाउन का अध्ययन कर के लिण्ड्स इस परिणाम पर पहुँचे कि मज़दूरों के जिन परिवारों से उन्होंने साक्षात्कार किया था, वे यद्यपि समृद्धवर्ग के थे तो भी उन्हें बेकार हो जाने का डर हमेशा सताता रहता था। वेतन और घण्टों की अपेक्षा काम की स्थिरता में उन्हें ज्यादा दिलचस्पी थी। रोजगार के सम्बन्ध में आँकड़े कुछ भी कहते हों, जिस आदमी का काम छूट जाता था उसे अपनी अल्प-बचत सर्वथा समाप्त हो जाने से पूर्व ही कोई और काम तलाश करने की कोशिश करनी पड़ती थी, जिसकी संभावना बहुत कम होती थी।

आम मज़दूरों के बजाय जहाँ तक संगठित मज़दूरों की स्थिति का सवाल है, १९२० के दशक में उनकी दशा विरोधाभास से परिपूर्ण थी। राष्ट्रीय समृद्धि के हर पिछले युग में इसका जो रिकार्ड रहा है उसके विपरीत मज़दूर आन्दोलन ने अब क्षति ही उठाई। बड़े पैमाने के उद्योगों में अदक्ष मज़दूरों को संगठित करने में न केवल कोई प्रगति नहीं की गई बल्कि वर्तमान ट्रेड यूनियनों की सदस्य संख्या भी घटती चली गई। हमने देखा कि १९२१ में मन्दी के फलस्वरूप अमरीकी यूनियनों की कुल सदस्य संख्या ५० लाख से कुछ अधिक से घटकर लगभग ३६ लाख रह गई। किन्तु इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह थी की आगामी वर्षों में वे इस क्षति को पूरा नहीं कर सकीं। १९२९ में वैभव के शिखर पर यूनियनों के कुल सदस्य ३४,४३,००० रह गए थे। यह संख्या १९१७ के बाद के किसी भी वर्ष से कम थी।

अच्छा समय जारी रहने के सुखद वातावरण में और जो काम पर लगे हुए थे उनकी तनख्वाहें बढ़ते रहने पर लोगों को इस बात की कोई परवाह प्रतीत नहीं होती थी। काम की असुरक्षा ने भले ही कुछ कर्मचारियों को मालिकों की इच्छा के विपरीत यूनियनों में शामिल होने से रोका हो किन्तु उनमें से बहुत से प्रत्यक्षतः यह महसूस करते थे कि यूनियन अब पहले की

तरह जरूरी नहीं रही है। वे यह सोचते थे कि जब वेतन का लिफाफा खुद-बखुद ज्यादा मोटा होता जा रहा है, गरीबी पर अंतिम विजय की तरफ हमारे कदम तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुतायतपूर्ण जीवन निश्चित रूप से आया जान पड़ता है तब हड़तालों और सामूहिक सौदेबाजी के लिए अन्य प्रकार के आन्दोलन करने से क्या लाभ ?

इन दिनों के शान्त वातावरण में मज़दूरों के पास यह देखने का कोई साधन नहीं था कि क्षितिज पर एक और मन्दी उभर रही है जो १८३०, १८७० और १८९० के दशकों की मन्दी से भी अधिक भीषण और चिरस्थायी होगी, जिसमें १॥ करोड़ असहाय मज़दूर स्वयं को सड़कों पर प्रक्षिप्त, कोनों पर सेब बेचते हुए, सूप के लिए लाइन लगाते और रोटी प्राप्त करने के लिए लगाई गई पंक्तियों में भीड़ करते पाएँगे। किन्तु इसकी घुमड़ती छाया ने १९२० के दशक की "सुनहरी चमक" को शीघ्र ही बुझा दिया और मज़दूरों की स्थिति का प्रच्छन्न दुर्बलता को आश्चर्यजनक रूप से जाहिर कर दिया। नई आर्थिक व्यवस्था के यकायक ढुलक जाने से जहाँ सारे देश को क्षति पहुँची वहाँ मन्दी का सबसे ज्यादा प्रभाव एक बार फिर मज़दूरों पर पड़ा।

१९२१ की संक्षिप्त मन्दी के बाद जो आर्थिक उत्थान आया उसमें उद्योग ने यह निश्चय कर लिया कि वह मज़दूरों को युद्ध के दौरान प्राप्त की गई स्थिति को पुनः हासिल नहीं करने देगा। १९१९ ने पुनरुज्जीवित किए गए यूनियन विरोधी आन्दोलन को तेज़ कर दिया गया और ओपनशाप पद्धति को जारी रखने पर नए सिरे से जोर दिया जाने लगा। सिद्धान्त रूप से ओपनशाप का अब भी इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं था कि मालिक को किसी भी मज़दूर को काम पर रखने का हक है चाहे वह यूनियन का सदस्य हो या न हो। किन्तु १९०० के प्रारम्भ की तरह इसका न केवल यह तात्पर्य था कि यूनियन सदस्यों के साथ प्रायः दुर्भांत की जाती थी बल्कि किसी भी यूनियन को मान्यता देने से इन्कार कर दिया जाता था, भले ही अधिकांश मज़दूर उसके सदस्य क्यों न हों। कहने का मतलब यह है कि ओपनशाप मालिक और कर्मचारी के सम्बन्धों में सामूहिक सौदेबाजी की सारी प्रक्रिया से इन्कार करने का एक मान्य तरीका बन गया।

यूनियनों के खिलाफ आन्दोलन को तेज करने के लिए १९२० के दशक में देश भर में ओपनशाप ऐसोसियेशनें बनाई गई, जैसी कि उद्योगों के प्रत्याक्रमण के पहले अवसरों पर बनाई गई थीं। न्यूयार्क में मालिकों के ऐसे ५० ग्रुप, मैसाच्युसेट्स में १८, कनैक्टिकट में २०, इलिनौयस में ४६, ओहायो में १७ और मिशीगन में २३ ग्रुप बनाए गए। स्थानीय वाणिज्य मण्डलों, निर्माता एसोसियेशनों और नागरिक संगठनों ने इस आन्दोलन को और मज़बूत किया तथा उनके पीछे नेशनल ऐसोसियेशन आव मैन्युफैक्चरर्स, नेशनल मैटल ट्रेड्स ऐसोसियेशन और लीग फार इण्डस्ट्रियल राइट्स की ताकत लगी हुई थी। इन युद्धोत्तरकालीन वर्षों में अभिवृद्ध राष्ट्रीयता के कारण उत्पन्न प्रेरणा से इन विभिन्न ऐसोसियेशनों द्वारा १९२१ में शिकागो में आयोजित एक सम्मेलन में ओपनशाप को बाकायदा 'अमरीकी योजना' नाम दिया गया। परिश्रमी व्यक्तिवाद के परम्परागत मूल्यों की विध्वंसक समूहवाद की विदेशी विचार-धारा से तुलना की गई। अमरीकी योजना के प्रवर्तकों ने घोषित किया : "प्रत्यके व्यक्ति अपने कल्याण की योजना स्वयं बनाए और अपने संगठन की जंजीरों से बँधकर अपना नुकसान न करे।"

यूनियनों के भ्रष्ट नेतृत्व और रुपया-पैसा एँठे जाने के किसी भी संकेत का मजदूरों और आम जनता दोनों को यह विश्वास दिलाने में पूरा लाभ उठाया गया कि उन्हें सामूहिक सौदेबाजी के कल्पित लाभों के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। और १९२० के दशक के तूफानी दिनों में कुछ यूनियनों में भ्रष्टाचार और रुपये-पैसे की ठगी के उदाहरण मिल भी गए। न्यूयार्क, शिकागो और सानफ्रांसिस्को के मकान-निर्माण उद्योगों और सर्विस उद्योगों में यूनियन के नेताओं और मालिकों के बीच गैर-कानूनी साँठगाँठ, मज़दूर नेताओं द्वारा रुपये-पैसे की छीना-झपटी और सीधे रिश्वतखोरी के मामलों का भण्डाफोड़ किया गया। कुछ/मामलों में अपराधी गिरोहों ने जब यह देखा कि चोरी से शराब बेचने के बजाय ज्यादा मुनाफे के अवसर उन्हें उपलब्ध हैं तो वे यूनियनों में दाखिल हो गए और धमकियों तथा हिंसा के बल पर मालिकों और कर्मचारियों दोनों की हजामत बनाई। किन्तु मज़दूर यूनियनों पर अनुदार व्यक्तियों द्वारा जो आक्षेप किए रहे थे उनमें भ्रष्टाचार और समाज विरोधी हरकतों के इक्के-दुक्के

उदाहरणों तथा बहुत अधिक यूनियनों में उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्व के सामान्य नजारे के बीच कोई फर्क नहीं किया गया। जब मज़दूर नेताओं को क्रांति के खिलाफ़ षड्यन्त्र करने वाले बोल्शेविक कहकर बदनाम करना बन्द कर दिया गया था तब उन्हें अपनी निजी सत्ता और सम्पत्ति के लिए हर सम्भव तरीके से यूनियन के सदस्यों का लाभ उठाने वाले क्रूर लुटेरे कहा जा रहा था।

नेशनल ऐसोसियेशन आव मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष जॉन इ. एड गर्टन ने १९२५ में बड़े आलंकारिक शब्दों में कहा : "मज़दूरों के महल से दिखाई देने वाले मन्दिर, जिनके सुनहरी कलश समस्त राष्ट्र में अपनी दिव्य आभा से चमकते हैं, और हर वर्ष लोभ के रत्नजटित हाथों से मज़दूरों की जेब से निकाले गए और बाद में मोटी-मोटी तनख्वाहों के रूप में बाँटे गए करोड़ों डालर ऐसी दासता की दयनीय कहानी कह रहे हैं, जैसी इस देश ने पहले कभी नहीं देखी।" राष्ट्र के कर्मदाताओं (मालिकों) को "मज़दूरों की कलाइयों को जकड़ने वाली हथकड़ियों को तोड़ने और अपने कर्मचारियों को मज़दूरों के दोस्त के प्रच्छन्न वेष में फिरने वाले स्वार्थी लुटेरों के झूठे नेतृत्व" से मुक्त करने का कर्तव्य निभाने के लिए बुलाया गया।

यूनियनों का विरोध करने और ओपन-शाप प्रचलित करने के लिए सिर्फ प्रचार का ही आश्रय नहीं लिया गया। बहुत से मालिक अपने कर्मचारियों पर यूनियन में शामिल न होने की शर्त लादते रहे, अपने कारखानों में भेदिये रखते रहे, अवांछनीय यूनियन सदस्यों की काली सूची का विनिमय करते रहे और मज़दूरों को काम पर रखने में खुल्लमखुल्ला अत्यन्त भेद-भाव अपनाते रहे। यह आतंक और ज़ोर जबर्दस्ती की पुरानी कहानी थी और जब इन सब सावधानियों के बावजूद कोई उपद्रव हो जाता था तो उपद्रवियों को पीटने के लिए सख्त कदम उठाए जाते थे और अबुद्धिमत्तापूर्ण हड़तालों को स्थानीय अधिकारियों के संरक्षण में हड़तालभंजक लाकर कुचल दिया जाता था।

उदाहरणार्थ कोयला खानों में यूनियनों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अपने सदस्यों में फूट और दलबन्दी हो जाने से वह स्वयं को मालिकों के हमले से बचाने में असमर्थ हो गई। कोयला एक रुग्ण उद्योग था, शक्ति के अन्य साधनों के साथ प्रतियोगिता में पिछड़ जाने के कारण देश की आम समृद्धि में हिस्सा नहीं बटा सका और खान मालिकों ने मज़दूरों पर कठोर

निकाल कर उत्पादन की लागत कम करने की समस्या को हल करने का दोहरा निश्चय कर रखा था। खनिकों के साथ वेतन सम्बन्धी विद्यमान समझौतों को भंग करने की उन्होंने कोशिश की और उत्पादन को केन्द्रीय बिटुमिनस खानों से हटाकर वेस्ट वर्जिनिया, केण्टकी, टेनेस्सी और अलाबामा जैसे राज्यों की यूनियन रहित खानों में ले जाने लगे जहां वे वेतनों और काम के घण्टों के बारे में यूनियनों की अड़ंगेबाजी से मुक्त होकर काम कर सकते थे। यह यूनियनों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बात थी।

यूनाइटेट माइन वर्कर्स के सामने कठिन समस्या आ खड़ी हुई। यूनियन विहीन कोयला खानों में जब हड़तालें फूट पड़ीं तो सहायता की बार-बार माँग की गई। अब दुविधा यह थी कि क्या यूनियन सहानुभूति में केन्द्रीय बिटुमिनस कोयला खानों में हड़ताल करके अपने करारों को भंग करे अथवा चुपचाप निष्क्रिय होकर बैठ जाए और यूनियन विहीन खानों में हालत बिगड़ने दे और अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण उद्योगों को हानि पहुँचने दे। जॉन एल. लेविस ने करार के समझौतों के पालन का आग्रह किया। उसने ऐसी किसी भी हड़ताल को सहायता देने से इन्कार कर दिया जिसके लिए यूनियन ने मंजूरी न दी हो और यूनियन-विहीन खानों की समस्या को दक्षिण में मज़दूरों का संगठन कर और उन्हें अनुशासित नियंत्रण में लाकर हल करने का सुझाव रखा।

उसका कार्यक्रम फेल हो गया। युनाइटेड माइन वर्कर्स ने यद्यपि खान-मालिकों के साथ और भी समझौते किए तथा उनका पालन किया तो भी यूनियन वाली कोयला खानों में उसकी शक्ति क्षीण होती गई और यूनियन विहीन खानों में संगठन करने में कोई प्रगति नहीं हुई। यूनियन के एजेण्टों का जिस तरह से स्वागत हुआ वह अतिथि-सत्कार की परम्परा के प्रतिकूल था। उन्हें बदनाम किया गया कम्पनी द्वारा नियंत्रित खानों के शहर से खदेड़ दिया गया, सशस्त्र गारद ने उन्हें पीटा और कभी-कभी उनकी हत्या भी कर दी गई। हड़तालों की संख्या बढ़ने और अव्यवस्था फैलने से खान वाले कुछ शहरों में वस्तुतः गृह-युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे हिंसा, गोलाबारी और हत्याओं का बोल-बाला था।

यूनाइटेड माइन वर्कर्स के अधिक क्रांतिकारी तत्त्व इस बात पर बहुत क्रुद्ध थे कि लेविस ने गैर-यूनियन खनिकों की सहायता के लिए आम हड़ताल क्यों

नहीं बुलाई। उन्होंने इस नीति के खिलाफ, जो उनके मत में असंगठित मज़दूरों से दगा कर रही थी और स्वतः यूनियन को नष्ट कर रही थी, असन्तोष पैदा करने में मदद दी। उसके अपने लेफ्टिनेण्टों ने विद्रोह कर दिया और यूनियन के सदस्यों ने भी गैर कानूनी हड़तालें कीं। जब लेविस ने बदले में अपने विरोधियों को कम्युनिस्ट कह कर उन पर तीव्र आक्षेप किए, अपने आदेश को पूर्णतः शिरोधार्य किए जाने का आग्रह किया और अनधिकृत हड़ताल कराने वाले स्थानीय नेताओं को यूनियन से निकाल दिया तो यूनियन के सदस्यों में व्यापक असन्तोष फैला जो यह समझते थे कि करारों को कायम रख कर लेविस यूनियन-विरोधी खान मालिकों के सामने सिर्फ घुटने टेक रहा था।

इस कठिन समय में लेविस ने यूनियन का नियंत्रण अपने हाथ से नहीं जाने दिया किन्तु इसमें बुरी तरह फूट पड़ गई थी और खान क्षेत्रों में उसका वह प्रभाव नहीं रहा जो पहले था। खान मालिक पहले की राष्ट्रीय हड़तालों में प्राप्त किए गए लाभों में कटौती करने में कामयाब हो गए और गैर-यूनियन खानों में जो पस्त-हिम्मती पैदा हुई वह केन्द्रीय विटुमिनस कोयला खानों के क्षेत्र में भी फैल गई। १९२२ में यूनाइटेड माइन वर्कर्स ने अपनी शक्ति ५ लाख सदस्यों की बना ली थी जो समस्त कोयला खनिकों की ७० प्रतिशत थी। इसके पतन की कहानी इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से और कैसे बताई जा सकती है कि आगामी १० वर्षों में उसके सदस्य सिर्फ १,५०,००० रह गए।

कोयला खानों में या अन्यत्र कहीं भी मालिकों के यूनियन-विरोधी अभियान का मुकाबला करने में मज़दूर सरकार या अदालतों से कोई सहायता अथवा समर्थन पाने की आशा नहीं कर सकते थे। यूनियन में शामिल न होने की शर्त पर काम देने (येलो डॉग) के करारों को, जो दक्षिण की कोयला खानों में व्यापक रूप से प्रचलित थे, अब भी वैध करार दिया गया; यूनियन सदस्यों के साथ भेद-भाव को दूर कराने का कोई कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं था और अदालतों के एक के बाद एक निर्णयों ने निरोधादेश कानून के खिलाफ क्लेटन ऐक्ट की कल्पित सुरक्षितताओं को सर्वथा अवैध ठहरा दिया।

सन् १९२१ के प्रारम्भ में डूप्ले प्रिंटिंग प्रेस बनाम डीयरिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि कानून सहानुभूति में की जाने वाली हड़तालों की इजाज़त नहीं देता और वाणिज्य में रुकावट डालने का षड्यंत्र करने के अभि-

योग में प्राप्त किए गए निरोधादेशों से यूनियनों की रक्षा नहीं करता। बाद में उसी वर्ष 'ट्रू ऐक्स बनाम कौरिगन' के प्रसिद्ध केस में मजदूरों के लिए कोई कानूनी राहत पाने की आशा और भी धूल में मिल गई। ऐरिज़ोना ने श्रम-सम्बन्धी विवादों में निरोधादेश की प्राप्ति को सर्वथा खत्म कर देने को एक कानून पास किया था किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने इसे वस्तुतः असांवधानिक घोषित कर दिया। उसने फैसला किया कि मालिक को निरोधादेश प्राप्त करने से रोक कर राज्य सरकार ने उससे संरक्षण पाने का साधन ही छीन लिया और इस प्रकार बिना किसी कानून के उसे संपत्ति से वंचित कर दिया। इससे उत्साहित होकर मालिकों ने क्लेटन ऐक्ट पास होने के पहले की भी अपेक्षा अधिक संख्या में निरोधादेश का प्रयोग करना शुरू कर दिया। १९२८ में ए. एफ. एल. ने पिछली दशाब्दी में संघीय अथवा राज्य न्यायालयों द्वारा किए गए ३८९ निरोधादेशों की सूची प्रस्तुत की किन्तु यह भी सूची स्पष्टतः अधूरी थी, क्योंकि निचली अदालतों में प्राप्त किए गए बहुत से निरोधादेशों का तो कोई रिकार्ड ही नहीं रखा गया था।

इस काल के अदालती निर्णयों में से शायद सबसे ज्यादा रोशनी डालने वाला निर्णय १९२३ में 'ऐडकिन्स बनाम चिल्ड्रन्स हौस्पिटल' के मामले में दिया गया। इसमें न्यूनतम वेतन सम्बन्धी कानून को करार की आजादी के सांविधानिक संरक्षण को भंग करने के कारण अवैध घोषित करके, न केवल इस प्रकार के कानून का पक्षपोषण करने के पहले के सम्मान को उलट दिया गया बल्कि "मज़दूर एक माल है" इस पुरानी धारणा को पुनः बल प्रदान करने के कारण इसको और भी महत्त्वपूर्ण समझा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि "हर स्त्री-पुरुष मज़दूर का जीवन-यापन के लायक मज़दूरी पाने का नैतिक अधिकार" स्वीकार किया तो भी कहा कि मालिक यह वेतन देने के लिए मजबूर नहीं हैं और कानून द्वारा इसकी व्यवस्था करने का राज्य को कोई हक नहीं है। अदालत ने कहा कि "चूंकि श्रम बेचने और माल बेचने में सिद्धान्ततः कोई फर्क नहीं हो सकता" इसलिए किसी मालिक को एक निश्चित वेतन देने के लिए मजबूर करना "एक नग्न, तानाशाही सत्ता की ऐसी स्पष्ट उपज है कि उसे अमरीका के संविधान के अन्तर्गत कायम नहीं रहने दिया जा सकता।"

मुख्य न्यायाधीश टैफ्ट तक ने जिन्हें 'निरोधादेश न्यायाधीश' कहा

जाता था उक्त नतीजा निकाले जाने का विरोध किया और कहा कि कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से मालिकों के साथ समानता के आधार पर करार कर सकने की स्थिति में नहीं हैं और विशेषत: कठोर तथा लालची मालिकों की चालबाजियों के शिकार हैं। सहकारी न्यायाधीश होम्स ने भी असहमति प्रकट की और अदालत द्वारा "करार की आजादी के सिद्धांत" के एकपक्षीय समर्थन की तीव्र आलोचना की।

यद्यपि सरकार और अदालतें दोनों सिद्धान्त रूप से मज़दूर यूनियनों की उपयोगिता को स्वीकार करती थीं और राष्ट्रपति हार्डिंग ने भी यह घोषणा की थी कि मज़दूरों का संगठन करने का अधिकार प्रबन्धकों अथवा पूँजी के अधिकार से "जरा भी कम नहीं है" तो भी वे जिन गतिविधियों के लिए यूनियनें बनाई गई थीं उन पर लगातार अंकुश लगाते जा रहे थे। १९२० के दशक में इन दमनात्मक नीतियों का एक अपवाद १९२६ में रेलवे लेबर ऐक्ट का पारित और स्वीकृत होना था। इस ऐक्ट में "बिना किसी दस्तंदाजी, प्रभाव या जोर-जबर्दस्ती के" रेल कर्मचारियों में यूनियन बनाए जाने की व्यवस्था थी और रेलों में श्रम सम्बन्धी सब झगड़ों के निबटारे के लिए एक विशेष मशीनरी नियुक्त की गई। इस कानून की प्रामाणिकता की घोषणा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "अगर चुनाव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करके आवेदन को व्यर्थ कर दिया गया तो कर्मचारियों की तरफ से की गई सामूहिक कार्रवाई की वैधानिकता एक मज़ाक बन जाएगी। किन्तु रेल कर्मचारियों के जो अधिकार स्वीकार किए गए, उन्हें १९३० के दशक तक अन्य कर्मचारियों को प्रदान नहीं किया गया।

यूनियन की गतिविधियों पर कानूनी अंकुश लग जाने और अदालतों के विरोधी निर्णयों के समक्ष संगठित मज़दूरों ने १९०६ की भाँति, जब उन्होंने "शिकायत-पत्र" प्रस्तुत किया था, पुन: यह महसूस करना शुरू कर दिया कि अगर मज़दूरों को मलिकों के यूनियन विरोधी अभियान में कार्य की स्वाधीनता प्राप्त करनी है तो अधिक सीधा राजनीतिक दबाव डालना होगा। सुप्रीम कोर्ट का रवैया अब और भी स्पष्ट हो जाने पर एक मज़दूर दल की स्थापना का अभियान, जोर पकड़ने लगा जो पहले-पहल १९१९ में, जबकि "श्रमिकों

का अधिकार-पत्र" तैयार किया गया था, शुरू हुआ था। ए. एफ. एल. भी किसी-न-किसी प्रकार की संगठित राजनीतिक कार्रवाई के लिए डाले जाने वाली दवाव का पूरी तरह सामना नहीं कर सका।

यह आन्दोलन पहले १९२२ में सामने आया जबकि कृषि, श्रम व अन्य उदार ग्रुपों के कोई १२८ प्रतिनिधियों ने शिकागो में एकत्र होकर 'प्रगतिशील राजनीतिक कार्रवाई के लिए सम्मेलन" का निर्माण किया। शक्तिशाली इण्टरनेशनल ऐसोसियेशन आव मशीनिस्ट का एच. जोन्स्टन इस आन्दोलन का प्रमुख व्यक्ति था। रेलवे ब्रदरहुडों ने, जो पुराने नेशनल लेवर वोर्ड के प्रतिवन्धों और निरोधादेश कानून के पुनरुज्जीवन से कराह रही थीं, इसका जोरों से समर्थन किया और १८ राष्ट्रीय यूनियनों, ८ राज्य श्रम संघों, मध्य-पश्चिम की कई किसान पार्टियों, महिलाओं की ट्रेड यूनियन लीग और समाजवादियों ने भी इसका समर्थन किया। दो वर्ष वाद जव रिपब्लिकन और डेमोक्रैट दोनों पार्टियों ने अत्यन्त अनुदार कालविन कूलिज और जॉन डब्लू. डेविस को अपना उम्मीदवार चुना तो इन प्रगतिशील तत्त्वों ने एक तीसरे स्वतंत्र उम्मीदवार विस्कोंसिन के ला फौलेट का नाम प्रस्तुत किया। इस शर्त पर कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के अलावा जिसके लिए मोण्टाना के सेनेटर ह्वीलर को उम्मीदवार वनाया गया, अन्य किसी पद के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। ला फोलेट ने नामज़दगी स्वीकार कर ली और प्रगतिशील राजनीतिक कार्रवाई के लिए सम्मेलन ने १९२४ में वाकायदा चुनाव-आन्दोलन शुरू कर दिया।

आन्दोलन का मंच, जिससे यह घोषणा की गई कि देश के सामने मुख्य प्रश्न निजी एकाधिकार द्वारा सरकार और उद्योग पर नियन्त्रण स्थापित कर लेने का है. ज्यादातर युद्ध-पूर्व के प्रगतिशील सिद्धान्तों का ही अवशेष था। इसमें राष्ट्र की जल-शक्ति तथा रेलों पर सार्वजनिक स्वामित्व की, राष्ट्रीय सम्पदा के संरक्षण की, किसानों को सहायता दिए जाने, साधारण आमदनी पर टैक्स कम किए जाने, सरकारों में कमी करने तथा श्रम-सम्बन्धी कानूनों में त्रुटियाँ दूर करने की माँग की गई। कहा गया कि "श्रम-सम्बन्धी झगड़ों में हम निरोधादेश को खत्म कर देने के हक में हैं"; संगठित होने, अपनी पसन्द के प्रतिनिधियों के जरिये सामूहिक सौदेबाजी करने और बिना किसी रोक-

टोक के सहकारी उद्योगों के संचालन के किसानों और औद्योगिक मज़दूरों के अधिकार की घोषणा करते हैं।"

अमरीकी मज़दूर संघ पहले "प्रगतिशील राजनीतिक कार्रवाई के लिए सम्मेलन" का विरोधी था किन्तु जब दोनों बड़ी पार्टियों ने मज़दूरों की मांग की उपेक्षा कर दी, तब इसने ला फौलेट की उम्मीदवारी का समर्थन कर अभूतपूर्ण कदम उठाया। इसकी कार्यकारी परिषद् ने कहा कि रिपब्लिकन और डैमोक्रैटिक दोनों परिषदों ने "मज़दूरों की इच्छा का अनादर" किया है और वे "नैतिक रूप से दिवालिया हो गई हैं जो हमारे देश और उसकी संस्थाओं के लिए संकट व ख़तरे की बात है।" बड़ी पार्टियों पर इस आक्षेप के बावजूद ए. एफ. एल. ने १९२४ के प्रगतिशील तत्वों के साथ मिलने बहुत सावधानी से काम लिया। युद्ध-पूर्व के वर्षों की राजनीतिक हलचलों में अपनायी गई अपनी नीति के अनुरूप ही गॉम्पर्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि ए. एफ. एल. सिर्फ इसी आन्दोलन में "मज़दूरों का मित्र" होने के नाते ला फौलिट का समर्थन करने के लिए वचनबद्ध है, वह तीसरे दल की स्थापना का विचार नहीं रखता। मज़दूरों को निरोधादेश जैसे कानूनों से मुक्त करने के लिए विधान की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए भी उसने यह कह कर कि "हम सरकार को जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं मानते", "स्वैच्छिकता" में पुनः अपना विश्वास प्रकट किया।

इन शर्तों और सफाई के बावजूद ए. एफ. एल. के बहुत से नेताओं ने कार्यकारी परिषद् का निर्णय मानने से इन्कार कर दिया। कार्पेण्टर्स यूनियन के जॉन एल. लेविस तथा विलियम हचिसन ने कूलिज का समर्थन किया और मुद्रण-कर्मचारी यूनियन के जार्ज एल. बेरी अन्तिम क्षण जान. डब्ल्यू. डेविस की तरफ हो गए। यद्यपि ए. एफ. एल. ने अपनी परम्परागत नीति को छोड़ खुल्लमखुल्ला एक तीसरे दल के राष्ट्रपतीय उम्मीदवार का समर्थन किया था तो भी उसने यह काम पूरे मनोयोग से नहीं किया और चुनाव-आन्दोलन के लिए सिर्फ २५ हजार डालर एकत्र किए गए।

विस्कौंसिन ने ही उसका साथ दिया। मज़दूरों के वोट उसे पर्याप्त संख्या में नहीं मिले और प्रगतिशील तत्वों की विफलता मजदूरों की विफलता समझी गई। सिएटल टाइम्स के वाशिंगटन स्थित संवाददाता ने लिखा कि "इस वर्ष का क्रान्तिकारी आन्दोलन संगठित मज़दूरों का अपने प्रशासनिक निकायों के जरिये राजनीतिक कार्रवाई करने का पहला प्रयत्न है। इस की विफलता ने आगामी अनेक वर्षों के लिए इस बात की सम्भावना खत्म कर दी है कि मजदूर राष्ट्रपति पद के लिए तीसरी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून ने चुनाव-परिणामों का विश्लेषण करते हुए लिखा : "मज़दूरों का वोट जैसी कोई चीज़ नहीं थी" और वाशिंगटन स्टार ने यह माना कि "इस देश के मज़दूर परम्परागत पार्टियों के खिलाफ विद्रोह में शामिल नहीं हुए।" अधिक संक्षेप और बोल-चाल की भाषा में फिलाडेल्फिया बुलेटिन ने सिर्फ यह कहा कि "राजनीति में मज़दूरों का प्रवेश व्यर्थ सिद्ध हुआ"।

ए. एफ. एल. भी चुनाव के बारे में प्रत्यक्षतः इसी नतीजे पर पहुँचा। इसने बड़ी तत्परता से प्रगतिशील राजनीतिक कार्रवाई के लिए सम्मेलन से अपने सहयोग का हाथ खींच लिया और तीसरी पार्टी का फिर से विरोध करने लगा। सारा आन्दोलन ठप्प हो गया। बाद के वर्षों में मजदूर यद्यपि निरोधादेशों से राहत पाने के लिए ज़ोर देते रहे तो भी इसके बाद राजनीति में कोई और सीधी कुदान नहीं भरी गई। जब समाजवादियों के वोट भी बहुत कम हो गए तो शेष देश के समान मज़दूर भी रूढ़िवादी राजनीतिक ढाँचे को स्वीकार करने के लिए उद्यत प्रतीत हुए जो न्यूडील के आने तक राष्ट्रीय रंग-मंच का स्वरूप निर्धारित करता रहा।

१९२४ में इस असफल अभियान के बाद ही ए. एफ. एल. का पितामह सेम्युअल गोम्पर्स ७४ वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गया। बाद के वर्षों में उसके लिए काम चलाना मुश्किल हो गया था। किन्तु ४० वर्ष पूर्व जब फेडरेशन की स्थापना हुई थी तभी से जो सत्ता उसे प्राप्त थी उसे स्वयं उसके हाथ से मौत ही छुड़वा सकी। १९२१ में जब लेविस अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ था तब क्षणिक तौर पर उसके हाथ से नियंत्रण जाता प्रतीत हुआ था किन्तु इस अवि-... विद्रोह को अन्यों की भाँति उसने दबा दिया। संगठित श्रमिकों का वह

सर्वमान्य नेता था और इस क्षेत्र में उसका कोई वास्तविक प्रतिद्वन्द्वी नहीं था। ए. एफ. एल. की सफलताएँ और विफलताएँ दोनों ही उसकी रूढ़िवादी व्यावहारिक विचारधारा को ही जिसे उसने निरंतर कायम रखा था, ज्यादातर प्रतिक्षिप्त करती हैं।

उसकी मृत्यु पर मज़दूरों ने ही नहीं उद्योगपतियों ने भी शोक प्रकट किया। अखबारों में जो अग्रलेख निकले वे इस विषय में दिलचस्प टिप्पणियों से परिपूर्ण थे कि उसकी नरम नीतियों ने कितना विश्वास प्राप्त कर लिया था और उन्हें राष्ट्र के मज़दूरों की अधिक क्रांतिकारी प्रवृत्तियों की रोकथाम करने वाला स्वीकार किया गया था। कहा जाता है कि गौम्पर्स विशुद्ध अपने व्यक्तित्व के बल पर ट्रेड यूनियनवाद को एक सीधे गैर-राजनीतिक मार्ग पर ले गया और श्रम तथा पूँजी के बीच की खाई को पाटने की निरन्तर कोशिशों के लिए सामान्यत: उसकी सराहना की गई। उसकी मृत्यु अमरीका के लिए एक क्षति बतायी गई, मुख्यत: इसलिए कि उसके जाने के बाद ए. एफ. एल. में फूट पैदा होने की सम्भावना पैदा हो गई थी, जिसमें उग्रतावादी तत्व सत्तारूढ़ हो सकते थे।

किन्तु फेडरेशन का नया अध्यक्ष जब विलियम ग्रीन को चुना गया तो व्यापारिक समाज ने चैन की साँस ली। क्योंकि ग्रीन भी श्रमिक-राजनीति में रूढ़िवादिता का हामी था और उसके बारे में यह विश्वास प्रेस को तत्काल दिए गए उसके एक वक्तव्य से और भी गहरा हो गया। इस वक्तव्य में उसने कहा: "गौम्पर्स ने ट्रेड यूनियनवाद के जिन बुनियादी सिद्धान्तों का इतनी योग्यता से प्रतिपादन किया है उन पर चलते रहने का मेरा दृढ़ निश्चय है।" देश ने तुरन्त यह अनुभव किया कि ए. एफ. एल. के परम्परागत कार्यक्रम के समाजवादी हो जाने या तीसरी पार्टी की स्थापना के पक्ष में हो जाने का कोई खतरा नहीं है। ग्रीन के चुनाव पर एक प्रतीकात्मक टिप्पणी करते हुए 'रिचमण्ड टाइम्स डिस्पैच' ने लिखा: "उसके नेतृत्व में मज़दूर सुरक्षित हैं। पूँजी को डरने का कोई कारण नहीं है और जनता का यह सौभाग्य है कि नागरिकों के इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रुप का प्रवक्ता विलियम ग्रीन है।"

ग्रीन का जन्म कोशोक्टन (ओहायो) में १८७३ में हुआ था। बहुत से अन्य अमरीकी मज़दूर नेताओं की तरह वह एक दूसरी पीढ़ी का अमरीकी,

एक वेल्श आव्रजक का पुत्र था और जब लड़का ही था तभी अपने पिता की तरह ओहायो की कोयला खानों में काम किया करता था। यूनाइटेड माइन वर्कर्स में शामिल होने के बाद वह १९०६ में एक उप-जिला यूनियन का अध्यक्ष चुना गया और धीरे-धीरे संगठित मज़दूरों की उच्च परिषद् की सीढ़ी पर चढ़ता चला गया। ओहायो में खनिकों के नेता के नाते ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि के रूप में उसे राज्य विधान मण्डल में भेजा गया और तब अपनी निष्ठापूर्ण सेवाओं के पुरस्कार के रूप में यूनाइटेड माइन वर्कर्स का सचिव कोषाध्यक्ष चुना गया। १९१३ में जब गौम्पर्स ने निश्चय किया कि ए. एफ. एल. की कार्यकारी परिषद् में खनिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए तो उसकी नजर ग्रीन पर गई और उसे ८वां उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। जब मृत्यु ने उनसे ऊपर के अधिकारियों को एक-के-बाद-एक हटा दिया तब ग्रीन धीमे-धीमे ऊपर उठ कर तीसरा उपाध्यक्ष बन गया। लेविस का समर्थन पाकर इस पद से वह ए. एफ. एल. की अध्यक्षता की चोटी पर पहुँच गया।

१९२४ में वह कोई विलक्षण व्यक्तित्व प्रतीत नहीं होता था। उसमें गौम्पर्स, मिचेल या लेविस के शक्तिशाली नाटकीय गुण नहीं थे। शांत-गम्भीर—युवावस्था में रविवार को लगने वाले धार्मिक स्कूल में वह पढ़ाया करता था और शुरू में उसका पादरी की ट्रेनिंग लेने का इरादा था—वह गौम्पर्स की तरह लड़कों के साथ शराब नहीं पीता था। उसका नशे से परहेज़ रखना टेरेंस पाउडरली की याद दिला देता था। श्रममंत्री परकिन्स ने बाद में उसे "अत्यन्त मृदु और नम्र स्वभाव का व्यक्ति" बताया और कहा कि उसका स्थूल शरीर, गोल, हास्यविहीन चेहरा, कोमल वाणी और शान्त मुद्रा कोई बहुत आकर्षक व्यक्तित्व नहीं बनाती थीं किन्तु उसमें चुम्बकीय शक्ति कमाल की थी। एल्क, आड फैलो और मेज़न (विशिष्ट जनसमुदाय) सभी उसे अपना समझते थे। उसके आनन्दप्रद भले तौर-तरीकों और सामान्य मैत्रीभाव ने उसे लोकप्रिय बना दिया था। अपनी असंदिग्ध ईमानदारी, सदाचार और यूनियन मज़दूरों के हितों के प्रति परिश्रमपूर्ण निष्ठा के लिए भी उसका आदर किया जाता था।

यूनाइटेड माइन वर्कर्स में अपने अनुभवों के फलस्वरूप, १९१७ में ग्रीन ने को पूर्णतः औद्योगिक यूनियनवाद का पक्षपोषक घोषित किया था और

यह भी एक कारण था जिससे लेविस ने उसे अपना समर्थन प्रदान किया था। ग्रीन ने कहा था : "शिल्प के बजाय उद्योग को इकाई मानकर मज़दूरों का संगठन करने से उसमें ज्यादा पूर्णता आती है, अधिक सहयोग हो पाता है... यह ज्यादा और ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है कि अगर अदक्ष श्रमिकों को कम वेतनों पर लम्बे घण्टों तक काम करने को मजबूर किया जाता है तो उससे दक्ष श्रमिकों के हितों पर भी खतरा निरन्तर बना रहता है।" किन्तु नए पद पर आकर उसने यह सब भुला दिया। औद्योगिक यूनियनवाद के बजाय शिल्प-यूनियन ही ए. एफ. एल. की बुनियादी नीति रही और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगों के अदक्ष कर्मचारियों की यूनियनों को मान्यता दिलाने का १९२० की दशाब्दी में कोई वास्तविक प्रयत्न नहीं किया गया।

स्वयं को गौम्पर्स के समान ही रूढ़िवादी सिद्ध करने के प्रयत्न में ग्रीन ए. एफ. एल. की नीति में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप तब्दीलियों की संभावित आवश्यकता को स्वीकार करने में अपने पूर्ववर्ती से ज्यादा उत्सुक प्रतीत नहीं हुआ। वह स्वैच्छिकता के उस विचार का समर्थन करता रहा जिसकी गौम्पर्स ने "मजबूत, स्फूर्तिमान, परिश्रममय स्वाधीनता" पर जोर देते हुए इतनी दृढ़ता से वकालत की थी, और जिसकी स्वयं राष्ट्रपति हूवर भी वकालत कर सकते थे। अन्ततोगत्वा १९३२ में ही, जब कि मन्दी के प्रभाव ने ए. एफ. एल. के अनेक सिद्धान्तों को छिन्न-भिन्न कर दिया था, ग्रीन ने वृद्धावस्था के लिए पेंशन और बेकारी का बीमा जैसे रूपों में सरकार के हस्तक्षेप का विरोध करना बन्द किया।

ए. एफ. एल. की अगर भीरुता ने नहीं तो रूढ़िवादिता ने १९२० के दशक में मालिकों के यूनियन-विरोधी अभियान के मुकाबले समस्त संगठित मज़दूरों को कमज़ोर कर दिया। किन्तु यूनियनों के निर्माण में 'येलो डॉग' करार और निरोधादेश ही केवल-मात्र बाधक नहीं थे। उदारता के कारण भी मज़दूर आन्दोलन को क्षति पहुँच रही थी। उद्योग जहाँ एक तरफ आक्रामक ढंग से ओपन-शाप को लागू कर रहे थे, वहाँ उन्होंने मज़दूरों के लिए अनेक कल्याण-कार्यक्रमों पर भी अमल किया। इन्होंने काम की हालतों को इतना अच्छा बना कर यूनियनवाद को हतोत्साह करने का यत्न किया कि मज़दूर यूनियनों

को लाभदायक मानना ही वन्द कर दें; साथ ही मज़दूरों और प्रवन्धकों में निकट सहयोग के ज़रिये उत्पादन तथा औद्योगिक कार्य-कुशलता वढ़ाई।

इसके वाद से उद्योगों ने औद्योगिक प्रवन्ध में "वैज्ञानिकन" की प्रक्रिया से प्रति-मज़दूर उत्पादन में वहुत अधिक वृद्धि करने, मज़दूरों की आवश्यकता कम करने और सामान्यत: टैकनिकल स्तर को उन्नत करने की कोशिश की। प्रगतिशील युग में फ्रेडरिक डब्लू. टेलर द्वारा वनाए गए एक कार्यक्रम को व्यापक रूप में स्वीकार किया जाने लगा। समय तथा गति सम्वन्धी अध्ययन, काम की मात्रा के विचार का विकास, हिस्सों को जोड़कर तैयार माल की उत्पादन वृद्धि और कर्मचारियों के साथ सम्वन्धों में "वैज्ञानिक" हेरफेर, इन विपयों पर सव कहीं परीक्षण किए जाने लगे। उत्पादन की लागत कम करने की सतत धुन में युद्धोत्तर काल में "टेलरवाद" पर और भी ज्यादा व्यापक ध्यान गया। औद्योगिक कार्यकुशलता के इस कार्यक्रम में ट्रेडयूनियनवाद का कोई स्थान नहीं था, किन्तु मालिक ऐसी किसी स्थानापन्न चीज़ की आवश्यकता महसूस करते थे जो उद्योग और मज़दूर के आपसी हित के हक में सहयोगपूर्वक काम करते हुए 'एक वड़े परिवार' की भावना को उत्पन्न करने में सहायक हो। उनका खयाल है कि यह चीज़ उन्हें, कारखाना परिपदों, कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की योजनाओं तथा विशेप रूप से कम्पनी यूनियनों के रूप में प्राप्त हो गई है। १९१४ में लुडलो की हड़ताल के वाद जिसकी परिणति खूनी हत्याकाण्ड में हुई, इस कार्यक्रम को अपनाने में कोलैरेडो फ्युएल एण्ड आयरन कम्पनी ने पहल की। रौकफेलर संस्थानों ने युनाइटेड माइन वर्कर्स को मान्यता देने से इंकार कर दिया था और उसकी जगह एक कम्पनी यूनियन की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य संगठित मज़दूर आन्दोलन के साथ किसी प्रकार के साहचर्य के खतरनाक परिणामों के विना ही एक 'औद्योगिक लोकतन्त्र' की व्यवस्था करना था। रॉकफेलर के परीक्षण का अन्य वहुत से कार्पोरेशनों ने अनुकरण किया। युद्धकाल में १२५ ने किसी न किसी प्रकार की कम्पनी यूनियन कायम की और युद्ध के वाद के वर्षों में ओपन-शाप अभियान के कारण वाहर की यूनियनों के स्थान पर मालिकों द्वारा नियंत्रित यूनियनों की स्थापना की परिपाटी पर और ज्यादा जोर दिया जाने लगा। १९२६ तक कम्पनी यूनियनों संख्या ४०० से अधिक हो गई थी जिनके १३,६९,००० अथवा ए.एफ.एल.

से सम्बद्ध यूनियनों के सदस्यों के करीब ५० प्रतिशत सदस्य थे।

कर्मचारियों का प्रबन्ध करने वालों ने जब मज़दूर समस्या का और अध्ययन किया (युद्ध के बाद पहले ५ वर्षों में इस विषय पर लगभग ३००० पुस्तकें छपीं) तब कम्पनी यूनियनों के कार्य को मजबूत करने और उनके प्रति मज़दूरों की निष्ठा प्राप्त करने के लिए और भी कदम उठाए गए। बीसियों और उसके बाद सैकड़ों कार्पोरेशनों ने मुनाफ़े में हिस्सा बँटाने वाली योजनाएँ चालू कीं, कम्पनी के शेयरों के रूप में बोनस दिए या अन्य तरीकों से कम्पनी की गति-विधियों में मज़दूरों की सीधी आर्थिक दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की। १९२८ में अनुमान लगाया गया कि १० लाख से अधिक मज़दूरों ने, जिन कम्पनियों में वे काम कर रहे थे, उनके एक अरब डालर से ज्यादा कीमत के शेयर खरीद रखे थे। ग्रुप बीमा पालिसियाँ भी जारी की गईं, जो कर्मचारी द्वारा नौकरी बदल लिए जाने पर जब्त हो जाती थीं, और १९२६ तक इस तरह की योजनाओं के अन्तर्गत कोई ५० लाख मज़दूरों का बीमा किया गया। साथ ही बुढ़ापे में पेंशन देने के कई कार्यक्रम चालू किए गए, स्वास्थ्य अच्छा रखने में सहायता देने के लिए मुफ्त औषधालय खोले गए, और कर्मचारियों के लिए कैन्टीनों तथा भोजनालयों की व्यवस्था की गई। कम्पनी यूनियनों के कर्मचारी विभागों के निर्देशन में कारखानों के कर्मचारियों के लिए पिकनिक, क्लब, नृत्य, खेल आदि मनोरंजक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई और सैकड़ों पत्र-पत्रिकाएँ मज़दूर और प्रबन्धक के बीच सद्भावना तथा मैत्रीपूर्ण मानवीय सम्बन्धों का गुणगान कर रही थीं।

कल्याणकारी पूँजीवाद के विस्तार की कोई सीमा नहीं थी और यह काम की हालत सुधारने तथा अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी की आमदनी बढ़ाने में बहुत हद तक सफल हुआ। तो भी सारा कार्यक्रम कार्पोरेशन के संचालक के नियंत्रण के आधीन था और इन परिस्थितियों में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व असली रूप नहीं ले पाया। यह कोई महत्त्वहीन बात नहीं थी कि जिन कम्पनियों ने मज़दूरों के कल्याण-कार्यक्रमों की जितनी अधिक उदारता से व्यवस्था की उनकी बुनियादी नीति उतनी ही ज्यादा यूनियन विरोधी थी। अगर समृद्धि की जगह उनकी मन्दी आ जाए तब कल्याणकारी पूँजीवाद और विशेषकर शेयरों में हिस्सा देने का उसका कार्यक्रम कितनी जल्दी ढह सकता है, यह उस समय अज्ञात

नहीं किया गया था। कम्पनी यूनियनों का शायद ही कोई सदस्य इस बात को समझता हो कि यूनियन-मान्यता तथा वास्तविक सामूहिक सौदेबाजी के लाभों के बदले में जो कृपा उन्हें मिल रही है उससे वे अपने मालिकों पर कितने निर्भर हो गए हैं।

यह सबक १९२० में सीखा गया, किन्तु इस बीच कल्याणकारी पूंजीवाद ने अनेक विजयें प्राप्त कीं। नेशनल एसोसियेशन ग्राव मैन्युफैक्चरर्स की ओपन-शाप समिति के चेयरमैन एस. बी. पेक ने कहा : "यह बात ताल ठोक कर कही जा सकती है कि अधिकांश यूनियनों की सदस्य-संख्या घटने और अपने और अपने सदस्यों को एकजूट रखने में अनुभव की जाने वाली उनकी महान् कठिनाइयों का एकमात्र कारण यह है कि मालिक और विशेषकर जिन्हें कभी 'अन्तरात्मा रहित कार्पोरेशन' कहा जाता था, मज़दूरों के कल्याण के लिए यूनियनों से ज्यादा काम कर रहा है।" ७६वीं कांग्रेस की शिक्षा और श्रम-सिमिति ने १९२६ में रिपोर्ट दी कि यूनियनवाद का मुकाबला करने में एन. ए. एम. ने इतना अच्छा काम किया है कि वह "समृद्धि के वर्षों में अपने प्रयत्नों के फल के शांतिमय उपभोग" का सरंजाम कर सका।

वास्तविक ट्रेड यूनियनों के दमन और कम्पनी-यूनियनों तथा कल्याण-कारी पूंजीवाद के लाभों के जरिए कर्मचारियों की वफादारी प्राप्त करने के दुधारे कार्यक्रम के फलस्वरूप न केवल ए. एफ. एल. की सदस्य-संख्या में कमी हुई, बल्कि देश में इतनी औद्योगिक शांति कायम रही, जितनी अनेक वर्षों से नहीं रही थी। इसका यह मतलब नहीं कि हड़तालें हुई ही नहीं। उदाहर-णार्थ दुःखी कपड़ा मिल कर्मचारियों ने निरन्तर हड़तालें कीं, जमकर मोर्चा लिया और हिंसा और रक्तपात भी हुआ। गैस्टोनिया और मेरियन (नार्थ कैरोलिना) और एलिज़ाबेथन (टेनेसी) जैसे दक्षिण के कारखाना-नगरों में हड़तालियों और राज्य की सेनाओं के बीच मठभेड़ों में बहुत-से लोग मारे गए। किन्तु समग्र चित्र श्रम-विवादों की संख्या घटते जाने का रहा। युद्धकाल में औसतन ३००० से अधिक हड़तालें प्रति वर्ष होती थीं, जिनमें १० लाख से अधिक मज़दूरों ने भाग लिया होता था। १९२० के दशक के मध्य तक ये संख्याएँ आधी रह गईं। दशाब्दी के अन्त में हड़तालों की वार्षिक संख्या ८०० ...९ रह गई, जिनमें कोई ३ लाख कर्मचारियों ने या समस्त श्रमिक-संख्या

काम के घण्टों का जहां तक सम्बन्ध है, स्थिति में आम सुधार हुआ। सामान्यतः ८ घण्टे का दिन था और अनुमान लगाया गया कि सदी के प्रारम्भ के बाद से काम के घण्टों में १५ से ३० प्रतिशत तक कमी हो गई थी। किन्तु जब उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तो बड़ी विषमता दिखाई देती है। मकान बनाने के व्यवसाय में औसत सप्ताह जहाँ ४३.५ घण्टे का था वहाँ इस्पात मिलों में धमन भट्ठी के कर्मचारियों से अब भी सप्ताह में ६० घण्टे काम लिया जा रहा था।

अन्य वर्षों की भाँति इन वर्षों में भी मजदूरी की दर तथा काम के घण्टों के अलावा अन्य बातों ने भी राष्ट्र के मज़दूरों की खुशहाली पर प्रभाव डाला। औद्योगिक प्रक्रियाओं में तेजी आ जाने से मेहनत और स्नायविक खिचाव बढ़ गया जिसमें मशीनें चलाने वाले और हिस्सों को जोड़कर तैयार माल बनाने वाले मज़दूरों को निरन्तर काम करना पड़ता था। बहुत से फैक्टरी कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत दक्षता से काम लेने के बजाय पूर्ण यांत्रिक प्रक्रिया अपनाया जाना नीरसता उत्पन्न करने वाला था, जिसकी भरपाई सदा ही अधिक वेतन और काम के कम घण्टों से नहीं हो पाती थी। यद्यपि उद्योगीकरण के इतिहास में यह कोई नई बात नहीं थी, तो भी १९२० के दशक में यह बहुत महत्त्व रखती थी।

मशीन के मार्च के साथ-साथ मज़दूर के सिर पर काम छूट जाने के भय की तलवार लटकी रहती थी। फलस्वरूप देश के औद्योगिक श्रमिक सुरक्षा और खुशहाली की उस मंजिल को प्राप्त करने से अभी बहुत दूर थे जो संगठित श्रमिकों का लक्ष्य थी। सामाजिक आँकड़े भले ही दूसरी तसवीर पेश करें, जो लाभ प्राप्त किए गए थे उनके खो जाने का बड़ा खतरा था, विशेषकर इसलिए कि जो कल्याणकारी पूँजीवाद द्वारा प्रदान किए गए थे, उनके जारी रहने के बारे में किसी करार का संरक्षण प्राप्त नहीं था। वास्तविक सामूहिक सौदेबाजी के स्थान पर मज़दूर प्रबन्धक सहयोग को स्वीकार करके जिस हद तक संगठनात्मक शक्ति तथा उग्र ट्रेड यूनियनवाद की बलि दे दी गई थी वहाँ तक मज़दूरों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए मुश्किल से प्राप्त की गई अपनी शक्ति पर गंभीर रूप से कुठाराघात किया था। वे पूर्णरूप से मालिक द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार करते रहने की इच्छा और सामर्थ्य पर निर्भर

रह गए।

१९२९ में शेयर बाज़ार के यकायक ढुलक जाने के बाद जब शनैः-शनैः देश में मन्दी आई, तब यही स्थिति थी। कहानी बहुत परिचित है। शेयरों में से जब अरबों डालर की कीमत उड़ गई तो राष्ट्र के विश्वास को धक्का लगा। चिल्ला-चिल्ला कर कहा गया कि स्थिति बुनियादी तौर से मज़बूत है और हमारी औद्योगिक प्रणाली में दरारें जैसे-जैसे चौड़ी होती गईं व्यवसाय धीरे-धीरे ठप्प होता गया और सारा ढाँचा ढुलकता प्रतीत हुआ। यह मन्दी आर्थिक चक्र में एक और ऐतिहासिक मोड़ थी, किन्तु इससे पहले की अन्य किसी मंदी की अपेक्षा, समाज पर ज्यादा प्रभाव पड़ा।

मन्दी समाप्त होने से पहले कृषि-उपज की कीमतें अपने पिछले स्तर से ४० प्रतिशत गिर गई थीं। निर्यात पहले के अधिकतम स्तर से एक-तिहाई गिर गया था, औद्योगिक उत्पादन करीब-करीब आधा हो गया और कम्पनी उद्योगों की बैलेंस शीट में ५ अरब ६५ करोड़ डालर का घाटा दिखाया गया। तीन वर्षों में ८२,८८,५०,००००० डालर की राष्ट्रीय आय गिर कर ४०,०७,४०,००,००० डालर रह गई। इससे भी ज्यादा बड़ी और ज्यादा विपज्जनक बात यह हुई कि बेकारी १९३० की समाप्ति तक ७० लाख से ऊपर जा पहुँची और अन्य दो वर्षों में १॥ करोड़ हो गई।

किन्तु ये आँकड़े इस भीषण मन्दी का धुँधला-सा ही चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसने लाखों मध्यमवर्गीय परिवारों को जिस कंजूसी और बचत के लिए मजबूर किया, निम्न आय वर्ग के लोगों को जो कष्ट उठाने पड़े और बेकार मज़दूरों और उनके परिवारों पर विधाता ने जो क्रूर उपहास खेला उसको ये आँकड़े चित्रित नहीं कर सकते। रोटी के लिए लगी कतारें, असंख्य शहरों के आस-पास आवारा लोगों के जंगल, जिन्हें कटाक्षपूर्वक हूवरविल कहा जाता था और काम-धन्धे की निराशाजनक तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने वाले पुरुषों और युवकों की सेना गरीबी का खात्मा करने वाले युग की चमकती मृगमरीचिका पर एक विषादमय टिप्पणी थी।

मन्दी के कारण जब उत्पादन में कटौती और सामान्य व्यापार ठप्प हो गया और उससे बहुत से कारखाने, खानें व वर्कशाप एकदम बन्द हो गए तो

देश के मज़दूर असहाय से खड़े देखते रहे। १९३० के प्रारम्भ में वाशिंगटन में कई सम्मेलन किए गए जिनमें उद्योगपतियों ने वेतन और रोज़गारों को कायम रखने का वचन दिया। मज़दूरों ने सहज विश्वास के साथ ये वायदे स्वीकार कर लिए। शेष देश की तरह उन्हें भी यह विश्वास नहीं होता था कि समृद्धि यकायक गायव हो गई है और उन्हें अब भी आशा थी कि स्थिति शीघ्र ही फिर संभलने वाली है। किन्तु वेतन दरों का पालन कराने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों—इस्पात, मोटर, विजली का सामान आदि में—सामूहिक सौदे-वाज़ी के कोई समझौते नहीं थे। वेतनों के चेकों में पहले तो धीरे-धीरे कटौती की गई और फिर यकायक उनके स्थान पर वर्खास्तगी के नोटिस आ गए।

समृद्धि के सुखद दिनों में वेतन वृद्धि के स्थान पर जो आनुषंगिक लाभ प्रदान किए गए थे उन्हें वापस लेने के लिए जव मालिक वाध्य हो गए तो कल्याणकारी पूंजीवाद का सारा कार्यक्रम ही छिन्न-भिन्न हो गया। मुनाफे में हिस्सा देने की योजनाओं, शेयरों की मिल्कियत कर्मचारियों को भी देने की तजवीज़ों, औद्योगिक पेंशनों और मज़दूरों के स्वास्थ्य तथा मनोरंजन सम्वन्धी परियोजनाओं को तुरत-फुरत तिलांजलि दे दी गई। छंटनी के लिए परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया था, किन्तु वहुत से मामलों में यह छंटनी मज़दूरों के हितों को वलि देकर की गई, जबकि साधारण शेयरों पर अब भी पूरा लाभांश दिया जा रहा था। कम्पनी यूनियनें अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने में विल्कुल असमर्थ थीं। कल्याणकारी पूंजी का आश्रय एक भ्रम सावित हुआ।

संगठित मज़दूर विल्कुल पस्त-हिम्मत हो गए लगते थे। राष्ट्रीय यूनियनों ने स्थिति में सुधार कराने के लिए सरकार पर कोई सीधा दबाव डालने की चेष्टा तक नहीं की और कल्याणकारी पूंजीवाद के सामने प्रत्यावर्तन में उनकी शक्ति इतनी क्षीण हो गई थी कि राष्ट्रव्यापी वेकारी के सामने से आर्थिक ढंग से सम्मिलित कार्रवाई कर सकने का सवाल ही नहीं था। हड़तालें कम से कम हो रही थीं और १९३० में उनकी संख्या इतनी कम रही कि उन सब में २ लाख से भी कम श्रमिकों ने भाग लिया। १९३३ तक संगठित श्रमिकों की कुल संख्या ३० लाख से भी कम रह गई, दूसरे शब्दों में १९१७ के स्तर पर आ गई।

कई तरह से मन्दी के इन वर्षों की सबसे आश्चर्यजनक बात बेकारी के आँकड़े शनैः-शनैः बढ़ने और रोटी के लिए लगी कतारें लम्बी होते जाने पर भी औद्योगिक मज़दूरों की उपेक्षा-वृत्ति थी। जिस आर्थिक प्रणाली ने उन्हें इस प्रकार ठग लिया था उसके प्रति उनमें कोई विद्रोह की भावना नहीं थी। १८७७ की भद्दी रेल-हड़तालों या १८९४ के डेब्स के विद्रोह जैसी कोई घटना नहीं घटी। पार्क एवेन्यू के ड्राइंग रूमों और वाल स्ट्रीट के दलालों के कार्यालयों में तो "आगामी क्रांति" की काफी चर्चा रहती थी किन्तु स्वयं बेकार इतने उत्साहहीन और निर्जीव थे कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी।

१९३२ की ग्रीष्म-ऋतु में 'हार्पर्स' में लिखते हुए जार्ज सोल ने बताया कि बुद्धिजीवी लोगों का स्पष्ट सम्मान जहाँ क्रांतिकारी कैम्प की ओर जा रहा था और कम्युनिज़्म में उनकी दिलचस्पी बढ़ रही थी, वहाँ मज़दूरों में इस प्रकार का कोई रुझान देखने में नहीं आया। उसने लिखा : "ठीक है, कि अवाम बहुत निराश हालत में हैं किन्तु उनके जरा भी कुपित होने का कोई संकेत नहीं मिला है। वे बस घर में बैठते हैं और दारूबन्दी को कोसते हैं .. रिपब्लिकन सरकार की तरह सम्पत्ति की वापसी के बजाय किसी कठोर कदम की प्रतीक्षा नहीं कर रहे।" इसी पत्र में एक अन्य लेख में एलमर डेविस ने भी "जिन नीतियों से गरीबी का उन्मूलन किया जाना था उन पर अमल किए जाने से अपने रोज़गार व अन्य सब कुछ गँवा देने वाले व्यक्तियों द्वारा स्थिति को चुपचाप स्वीकार कर लिये जाने पर" आश्चर्य से टिप्पणी की।

एक अप्रत्याशित अवसर ऐसा आया था, जब लिटररी डाइजेस्ट के शब्दों में ग्रीन ने ए. एफ. एल में भाषण देते हुए 'अपने मृदु स्वभाव' को छोड़कर ओहायो खान में जहाँ वह कुदाल चलाया करता था, कोयला गिरने जैसी गरजपूर्ण आवाज में वाग्बाणों की झड़ी लगायी। ताली बजाते हुए श्रोताओं से उसने कहा कि रोज़गार बढ़ाने के लिए अगर स्वेच्छा से कम काम का दिन और कम काम का सप्ताह नहीं अपनाया गया, "तो हम किसी न किसी जोर-ज़बर्दस्ती से इसे प्राप्त करेंगे।" रिपोर्टरों ने जब उससे पूछा कि ज़ोर-ज़बर्दस्ती से उसका क्या मतलब है तो उसने तुरन्त कहा कि उनका अभिप्राय आर्थिक ताकत से है। किन्तु मज़दूरों की उग्रता के इस अस्पष्ट संकेत से भी बेचैनी फैल गई। बोस्टन ट्रांसक्रिप्ट ने पूछा : "औद्योगिक संघर्ष के लिए क्या यही

समय है ?" "हड़ताल के तरीकों से उद्योग को मजबूर करने" के किसी भी ख्याल पर वाशिंगटन पोस्ट ने सख्त अफसोस ज़ाहिर किया। हैरल्ड ट्रिब्यून ने फतवा दे दिया कि ग्रीन "स्नायविक आघात" से पीड़ित है।

किन्तु यह विक्षोभ अमरीकी मज़दूर संघ की सामान्यतः सावधानतापूर्ण मनोवृत्ति में एक अपवाद था। १९३२ के अन्त तक भी बेकारी-बीमे का सख्त विरोध करते हुए इसने, मन्दी को दूर करने या बेकारी कम करने के लिए सरकार से इससे ज्यादा ठोस कार्रवाई की मांग नहीं की कि कम काम का सप्ताह लागू कर रोजगार बढ़ाने के उसके कार्यक्रम को अपना कर "उद्योग में स्थिरता" लाए।

प्रेस ने इस रवैये की तारीफ की। क्लीवलैण्ड प्लेन डीलर ने लिखा: "आज मज़दूर धैर्यवान और आशावान है......पहले की कभी कोई मन्दी मज़दूर संघर्ष से इतनी मुक्त नहीं रही। बेकारी ने उसे परेशान किया, बन्द कारखानों ने उसकी रोजी छीन ली। किन्तु अत्यन्त कठिनाई के समय में भी मज़दूरों ने अपनी उत्कृष्ट नागरिकता और सबल अमरीकी जीवट का प्रदर्शन किया। मज़दूर सलाम किये जाने के पात्र हैं।" रोजगारों के स्थान पर इस उदारतापूर्ण सलाम से क्या मज़दूर सन्तुष्ट हो गए यह विवादास्पद है। फिलाडेल्फिया रिकार्ड ने प्लेन डीलर की अपेक्षा ज्यादा यथार्थ रुख अख्त्यार करते हुए कहा कि बेकारी बीमे के खिलाफ फेडरेशन का मन्तव्य एक भयानक मज़ाक है। उसने पूछा, "भूखे मरने की आज़ादी ? क्या ग्रीन इसी के लिए संघर्ष कर रहा है ?"

सरकार और मजदूर संगठनों की निष्क्रियता के परिणाम हर गुजरते महीने के साथ राज्य या निजी व्यक्तियों की खैरात पर गुजर करने वाले बेकार मज़दूरों की संख्या में वृद्धि के रूप में स्पष्ट परिलक्षित हो रहे थे। उपलब्ध काम को अधिक से अधिक लोगों में फैला देने के शेखी भरे अभियान का इसके सिवाय कोई परिणाम प्रतीत नहीं हुआ कि मजदूरों की आय तो कम हो गई किन्तु जो बेकार हो गए थे, उन्हें काम मिलने का कदाचित् ही कोई अवसर आता था।

कुछ राज्यों ने काम की हालतों में सुधार करने के लिए कानून पास करने की कोशिश की। कई जगह मज़दूरों को मुआवज़ा दिए जाने के नए कानून पास

किए गए । १४ राज्यों ने बुढ़ापे की पेंशनें मंजूर कीं और विस्कौंसिन ने मज़दूरों के लिए बुनियादी अधिकार निश्चित करके और बेकारी का बीमा चालू करके एक नया मार्ग प्रशस्त किया । मार्च, १९३२ के प्रारम्भ में कांग्रेस द्वारा नोरिस-ला गार्दिया ऐक्ट पास किए जाने के साथ संगठित मज़दूरों ने सामान्यतः एक बहुत महत्त्वपूर्ण विजय प्राप्त की । इस कानून ने अन्ततोगत्वा सरकार की यह नीति घोषित कर दी कि मज़दूरों को मालिकों के हस्तक्षेप के बिना संगठन बनाने की पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए, 'येलो-डॉग' करार ग़ैर-कानूनी घोषित कर दिए गए और संघीय न्यायालयों के लिए श्रम सम्बन्धी विवादों में कुछ निश्चित परिस्थितियों को छोड़कर निरोधादेश जारी करने से रोक दिया गया। यद्यपि कम से कम कांग्रेस के एक सदस्य ने खड़े होकर कहा कि यह बिल "मास्को की दिशा में एक लम्बा कदम है" तो भी प्रतिनिधि सभा और सेनेट दोनों जगह इसे तगड़ा समर्थन मिला और आम जनता ने भी इसका समर्थन किया । न्यू डील की मज़दूर-नीतियों की तरफ मार्गदर्शन करने में नोरिस-ला गार्दिया ऐक्ट ने चाहे कितना भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया हो, तो भी इससे राष्ट्र के मज़दूरों की तात्कालिक समस्याएँ हल नहीं हुई । इससे बेकारी का कोई समाधान नहीं हुआ ।

१९३२ की ग्रीष्म ऋतु में जब परिस्थितियाँ अपने चरम शिखर पर पहुँचीं तब राष्ट्रपति के चुनाव-आंदोलन ने मन्दी का भली-भांति सामना करने में हूवर सरकार की असफलता के खिलाफ राजनीतिक विरोध प्रकट करने का पहला व्यावहारिक मौका प्रदान किया । डैमोक्रैटिक उम्मीदवार फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट ने देश के विशाल मज़दूर-समुदाय और "आर्थिक पिरामिड की तली में विद्यमान विस्मृत व्यक्ति" के लिए अपनी सहानुभूति स्पष्टतः प्रकट की । उन्होंने प्रत्यक्ष सहायता दिये जाने की परम आवश्यकता पर बार-बार ज़ोर दिया और बेकारी-बीमे की ज़ोरदार वकालत की । तो भी ए. एफ. एल.

चुनाव आन्दोलन की समाप्ति के बाद मजदूर-समस्याओं के बारे में और कोई घटना नहीं घटी। ए. एफ. एल. ने ३० घण्टे के सप्ताह तथा सरकारी काम-काज बढ़ाने की मांग की, अन्त में उसने बेकारी के बीमे को भी समर्थन दिया। किन्तु इस प्रकार के उपाय अपनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। देश के अन्य लोगों की भांति मजदूर भी इस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे कि नए राष्ट्रपति क्या करते हैं ?

— :o: —

१५ : न्यू डील

"......बेकार नागरिकों की एक विशाल संख्या के समक्ष जीवन-यापन की विषम समस्या मुँह बाए खड़ी है और इतनी ही विशाल संख्या नगण्य पारिश्रमिक पर काम कर रही है। कोई मूर्ख ही समय की अन्धकारपूर्ण परिस्थितियों से इन्कार कर सकता है......हमारा सबसे बड़ा पहला काम लोगों को काम पर लगाना है।"

मार्च, १९३३ में जब रूजवेल्ट पदारूढ़ हुए तो उनके आन्दोलित कर देने वाले उद्घाटन भाषण में राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए कुछ करने का वचन दिखाई दिया जिससे समस्त राष्ट्र में आशा और विश्वास की नई भावना का संचार हुआ। अन्ततोगत्वा सरकार कृषि, श्रम तथा उद्योग को वह सहायता देने को उद्यत हुई, सिर्फ जिससे ही हमारा बिगड़ा हुआ अर्थतंत्र दुरुस्त हो सकता था। जब राष्ट्रपति ने भावपूर्ण शब्दों में घोषणा की : "एकमात्र चीज़ जिससे हमें डरना है वह स्वयं डर ही है" तो देश ने महसूस किया कि उसे वह नेतृत्व मिल गया जिसके बिना वह मन्दी के गहरे दलदल में निःसहाय होकर धँसता जा रहा था।

रूजवेल्ट के तात्कालिक कार्यक्रम में लोगों को काम देने के वायदे के अलावा सीधा मजदूरों के लिए और कुछ नहीं था। बेकारी और बुढ़ापे के बीमे के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रश्न विचाराधीन था किन्तु जब वह पदारूढ़ हुए तो वागनर ऐक्ट और फेयर लेबर स्टैण्डर्ड्स ऐक्ट जैसे श्रम सम्बन्धी कानूनों की, जो राष्ट्रीय पुनरुत्थान प्रशासन की संहिता में लिखे गए, कल्पना भी नहीं की गई थी। उनका शनैः-शनैः समय की आवश्यकता के अनुसार निर्माण हुआ। किन्तु तो भी न्यू डील* (नया बर्ताव) की उभरती हुई विचारधारा में मजदूरों के अधिकारों के प्रति बुनियादी जागरूकता और सहानुभूति प्रच्छन्न रूप में विद्यमान थी।

---

* न्यू डील : सरकार के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बुनियादी तौर से पुनर्मूल्यांकन, जिनका दूरगामी और सामान्यतः समाज में उदारता लाने वाला प्रभाव हो।

इतिहास में पहली बार एक राष्ट्रीय सरकार ने औद्योगिक मजदूरों के कल्याण-कार्य को सरकार का उत्तरदायित्व कबूल किया और इस सिद्धान्त पर काम किया कि एक पूंजीवादी समाज में श्रम और पूंजी के बीच उपयुक्त संतुलन कायम करने के लिये संगठित पूंजी के साथ समान आधार पर सिर्फ संगठित श्रम ही खड़ा हो सकता है। अब से पहले मजदूर यूनियनों को बर्दाश्त किया जाता था, अब से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाने लगा।

इस प्रकार न्यू डील का आगमन मजदूर आन्दोलन के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण विभाजक रेखा साबित हुआ। युगों पुरानी परम्पराएँ तहस-नहस हो गईं, नई और गतिशील ताकतें उभरीं। हमारे इतिहास के पिछले किसी भी काल की अपेक्षा मजदूरों ने ज्यादा लाभ प्राप्त किए और मजदूरों की आर्थिक व राजनीतिक दोनों प्रकार की ताकत अपरिमित रूप से बढ़ गई। एक सदी के संघर्ष, कठिनाइयों और पराजयों की परिणति मजदूरों के ऐतिहासिक उद्देश्यों की पूर्ण उपलब्धि की सम्भावना में होती प्रतीत हुई।

मजदूरों के प्रति न्यू डील की नीति जिस कल्पना पर आधारित थी, उसे संगठित करने के उनके अधिकार की मान्यता के रूप में नोरिस-ला गार्दिया ऐक्ट में पहले ही लिखित रूप दे दिया गया था। रूज़वेल्ट सरकार ने जब अन्तर्राज्यीय वाणिज्य का नियमन करने के लिए कांग्रेस के कुछ संदिग्ध अधिकार पर आधारित राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम के आर्थिक नियंत्रण का समूचा परीक्षण किया तो प्रसिद्ध या कुछ क्षेत्रों की धारणा के मुताबिक बदनाम—खण्ड ७ (ए) में संगठन बनाने के इस अधिकार को अमली रूप देने के लिए पहला कदम उठाया गया।

मज़दूरों के हितों का समर्थन करने के लिए यह महत्त्वपूर्ण कदम अत्यन्त जटिल चालों का अन्तिम परिणाम था। १९३३ के मार्च महीने में सेनेटर ब्लैक तथा प्रतिनिधि सभा के कौनेरी ने बेकारी दूर करने के उद्देश्य से काम को फैलाने के लिए ३० घण्टे के सप्ताह की ए. एफ. एल की मांग की पूर्ति के लिये कांग्रेस में एक बिल पेश किया। रूज़वेल्ट को इस बिल की उपयोगिता में तब तक सन्देह था जब तक उसमें वेतनों की दर कायम रखने की कोई व्यवस्था कर दी जाती। इसलिए राष्ट्रपति की तरफ से श्रममंत्री पर्किन्स ने इसमें

कुछ संशोधनों का सुझाव दिया जिससे काम के घण्टे कम होने के साथ-साथ न्यूनतम वेतन भी निश्चित हो जाते। नए विल में अन्तर्हित-नीति १८६० के दशक में इरा स्टीवर्ड द्वारा प्रस्तुत विचारधारा से बहुत भिन्न नहीं थी। सिर्फ यही फर्क था कि काम के घण्टे घटाये जाने के साथ वेतनों में वृद्धि के बजाय इसमें वेतनों के स्थिरीकरण की बात कही गई थी। इससे आगे जाने का अभी कोई विचार नहीं था। श्रममंत्री पर्किन्स ने लिखा है कि "अप्रैल, १९३३ में जब मैंने राष्ट्रपति से बातचीत की तब वे राष्ट्रीय पुनरुत्थान अधिनियम के बारे में उतने ही अबोध थे, जितना कोई बच्चा हो सकता है।"

न्यूनतम वेतन के विचार का व्यापारी वर्ग ने तीव्र विरोध किया और मज़दूरों ने भी कोई बहुत उत्साह से उसका समर्थन नहीं किया। मन्दी की समस्या को इतने सीमित ढंग से हल करने की बजाय दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सरकार अपनी दृष्टि और ऊँची करके अधिक व्यापक कार्य-क्रम तैयार करे। यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर आव कामर्स ने प्रस्ताव किया कि वाणिज्य को ट्रस्ट-विरोधी कानूनों से मुक्त किया जाए और अपनी भलाई का मार्ग उसे स्वयं ढूँढने दिया जाए। मज़दूरों के प्रवक्ता के रूप में जॉन एल. लेविस ने कहा कि कोयला खानों में जहाँ पर वह उत्पादन, मूल्य तथा वेतनों पर नियंत्रण की माँग करते रहे हैं उसे समस्त उद्योगों पर लागू किया जाए। कांग्रेस के अन्दर और बाहर ऐसी बीसियों योजनाओं पर अधिकाधिक दिल-चस्पी ली गई, राष्ट्रपति के सलाहकारों की कई स्वतन्त्र टोलियाँ विशिष्ट कदमों का रूप निश्चित करने में लग गईं। किन्तु कोई वास्तविक प्रगति नहीं की जा सकी और राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने हस्तक्षेप का निर्णय किया। ब्लैक-कौनेरी बिल से सरकार का समर्थन वापस लेकर, जिसमें कि उनकी दिलचस्पी पहले ही बहुत कम थी राष्ट्रपति ने अपने सलाहकारों को एक सामान्य कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश किया और कहा कि जरूरत हो तो वे तालाबन्द कमरे में भी बैठें किन्तु कोई न कोई सर्वसम्मत निर्णय जरूर हो जाना चाहिए।

अन्तिम रूप से स्वीकार की गई और राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधि-नियम में शामिल की गई योजना के अनुसार उद्योग को अपनी प्रतियोगिता के तौर-तरीके खुद ईजाद करने की इज़ाजत दे दी गई किन्तु साथ ही उद्योग को दी गई इस खुली छूट के बदले में मज़दूरों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किए

गए। नए कानून के खण्ड ७ (ए) में, जो आंशिक रूप में १९२६ के रेलवे मज़दूर अधिनियम से लिया गया था, कहा गया था कि औद्योगिक संहिताओं में निम्न तीन महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएँ होनी चाहिएँ : कर्मचारियों को संगठन बनाने और अपनी पसन्द के प्रतिनिधियों के जरिये सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार होना चाहिए, उसमें मालिक कोई बाधा, रोक या जबर्दस्ती न करें; रोजगार के इच्छुक किसी व्यक्ति को कम्पनी यूनियन में शामिल होने को मजबूर न किया जाए और अपनी पसन्द के मज़दूर संगठन में शामिल होने से रोका न जाए; और मालिक वर्ग काम के अधिकतम घण्टों, न्यूनतम वेतन तथा काम की अन्य हालतों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत नियमों पर अमल करें। नए कानून को अगर समग्र दृष्टि से देखा जाए, तो इसमें चैम्बर आव कामर्स के कार्यक्रमों की बातों, यूनियनों की मान्यता के लिए मज़दूरों की परम्परागत माँग तथा ब्लैक-कौनेरी बिल की कुछ संशोधित व्यवस्थाओं का एक ही व्यापक कानून में समावेश कर लिया गया और इस व्यापक योजना में एक अलग मुद्दे के अन्तर्गत ३,३०,००,००,००० डालर के खर्च का एक विशाल सार्वजनिक कार्यक्रम और जोड़ दिया गया।

राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम जिस रूप में जून, १९३३ में पास हुआ उसका उद्देश्य राष्ट्रपति के शब्दों में "लोगों को पुनः काम पर लगाना था।" इसका लक्ष्य अनुचित प्रतियोगिता तथा संकटकारी अधिक उत्पादन को रोक कर उद्योग को उचित मुनाफा दिलवाना तथा काम के घण्टे कम करके उपलब्ध रोज़गार को अधिक से अधिक श्रमिकों में बाँट कर मज़दूरों को जीवन यापन के लायक मज़दूरी दिलवाना था। रूज़वेल्ट ने इस कानून को "अमरीकी कांग्रेस द्वारा तब तक पास किए गए किसी भी कानून से अधिक महत्त्वपूर्ण और दूरगामी बताया।"

इससे पूर्व सुप्रीमकोर्ट इसे अन्ततः ग़ैर-कानूनी ठहराती यह कानून आन्तरिक खिंचाव और दबाव से ही मृतप्राय हो गया और न्यू डील के प्रारम्भिक जोश का ऐसा शिकार बना जिस पर सामान्यतः किसी ने आँसू नहीं बहाए। किन्तु फिर भी मज़दूरों के लिए इसके परिणामों ने रूज़वेल्ट के वक्तव्य को काफी हद तक उचित सिद्ध किया। कानून को अमल में लाते हुए उसमें जो त्रुटियाँ ... दीं उनके बावजूद काँग्रेस की कार्रवाई के द्वारा प्राप्त सामूहिक सौदे-

वाज़ी की गारण्टी और वेतनों तथा काम के घण्टों पर नियन्त्रण इतने अग्रिम कदम थे जितने औद्योगिक सम्बन्धों में आज तक किसी सरकार ने नहीं उठाए थे और एन. आर. ए. की जब अन्य धाराएँ असांविधानिक घोषित कर दी गई तब भी इन कदमों को पीछे नहीं हटाया गया। न्यू डील ने खण्ड ७ (ए) के छिन्न-भिन्न तारों को पुनः सावधानी से वागनर ऐक्ट तथा फेयर लेवर स्टैण्डर्ड्स एक्ट के रूप में एकसूत्र में बाँध दिया। रूज़वेल्ट के शासन में औद्योगिक मज़दूरों के हितों की रक्षा करने में की गई इस प्रगति से पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं था।

जून १९३३ में एन. आर. ए. का सारे देश में सोत्साह स्वागत किया गया। यह सच है कि 'मैन्युफैक्चरर्स रिकार्ड' जैसे कंज़रवेटिव अख़बार ने, जो मज़दूरों को दी गई किसी भी रियायत को लाल-पीली आँखों से देखता था, तुरन्त यह टिप्पणी की: "मज़दूर आन्दोलनकारी........ इस देश में एक मज़दूर तानाशाही कायम करने की कोशिश कर रहे हैं।" किन्तु आलोचना का यह राग नए पुनरुत्थान कार्यक्रम की हर्षमय स्वीकृति के समवेत स्वर में खो गया। अपने प्रारम्भ की उज्जवल अरुणिमा में एन. आर. ए. देशभक्तिपूर्ण वक्तव्यों और लोकप्रिय प्रदर्शनों के साथ जनरल ह्यू जॉन्सन के गतिशील नेतृत्व में अमल में आना शुरू हुआ। संहिता की स्वीकृति के संकेत के रूप में इस पार से उस पार समस्त प्रदेश में "नीली चीलों" का गर्वपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था।

मज़दूरों ने खण्ड ७ (ए) का उल्लासपूर्वक स्वागत किया। विलियम ग्रीन ने कहा : "समस्त राष्ट्र में दसियों लाख मज़दूर अपने जीवन में पहली बार औद्योगिक स्वाधीनता का चार्टर ग्रहण करने के लिए खड़े हुए।" मन्दी की उत्साहहीनता में से रातोंरात असंख्य यूनियनें उठ खड़ी हुईं। कानून के संरक्षण पर भरोसा करते हुए संगठनकर्त्ता ठप्प पड़ी हुई स्थानीय शाखाओं की क्षीण हुई शक्ति को फिर से एकत्र करने में, नई यूनियनें बनाने में और जिन स्थानों पर उन्हें नहीं जाने दिया जाता था उनमें जाकर यूनियन बनाने में जुट गए। कोयला खानों में खान के गड्ढों पर गाड़े गये तख्तों पर लिखा था : "राष्ट्रपति चाहते हैं कि आप यूनियन में शामिल हों।" स्वयं मज़दूरों

ने बहुत स्थानों पर हैड क्वार्टर से ए. एफ. एल. के प्रतिनिधि के आगमन की प्रतीक्षा नहीं की अपितु अपनी स्थानीय यूनियनें खुद बना लीं और तब पितृ-संगठन से चार्टर प्राप्त करने के लिए अर्जी दे दी। इस समय मज़दूरों में जैसी हल-चल फूट पड़ी वैसी पहले कभी दिखाई नहीं दी सिवाय शायद तब के, जब कि आधी सदी पूर्व नाइट्स आव लेबर का नाटकीय विकास हुआ था।

अक्तूबर में जब ए. एफ. एल. का वार्षिक सम्मेलन हुआ तब अध्यक्ष ग्रीन ने विश्वासपूर्वक यह घोषणा की कि एक अनधिकृत गिनती से जाहिर होता है कि १५ लाख नए सदस्य बने जिससे एक दशाब्दी की क्षति पूरी हो गई और सदस्यों की कुल संख्या ४० लाख के करीब जा पहुँची। तब वह १ करोड़ सदस्यों का और अन्ततः ढाई करोड़ सदस्यों का स्वप्न लेने लगा।

सबसे ज्यादा सदस्य तथाकथित औद्योगिक यूनियनों में बने, विशेषकर उनमें जिनको मन्दी में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। कुछ ही महीनों में यूनाइटेड माइन वर्कर्स ने ३ लाख सदस्यों की भरपाई कर ली और केण्टकी और अलाबामा के भूतपूर्व गैर-यूनियन कोयला क्षेत्रों में नए समझौते किए गए; इण्टरनेशनल लेडीज गारमेण्ट वर्कर्स यूनियन के १ लाख सदस्य बढ़ गए, न्यूयार्क तथा देश के अन्य भागों में उठाकर ले जाए गए कारखानों में जो क्षति उसने उठाई थी उसकी भरपाई हो गई और ऐमलगमेटेड क्लोदिंग वर्कर्स ने ५०,००० की नई भर्ती से पहले की क्षति की भरपाई कर ली। किन्तु यहीं इति नहीं थी। खण्ड ७ (ए) की स्फुरणा के अन्तर्गत ए. एफ. एल. "बड़े पैमाने के उद्योगों में असंगठितों का संगठन बनाओ" के नए नारे के साथ उस प्रदेश पर भी छापा मारने को तैयार प्रतीत हुआ जिससे पहले उसे दूर रखा गया था। मोटर उद्योग में करीब १ लाख मजदूरों का, इस्पात में ९०,०००, लम्बरयार्ड और आरा मिलों में ९०,००० तथा रबड़ उद्योग में ६०,००० मज़दूरों का संगठन किया गया।

किन्तु शीघ्र ही यह पता चला कि असंगठित मजदूरों में यह तीव्र हलचल बहुत खतरनाक आधार पर स्थित थी और अध्यक्ष ग्रीन की गर्वोक्ति १६ आने उचित नहीं थी। औद्योगिक यूनियनवाद के प्रति ए. एफ. एल. की परम्परागत लु मनोवृत्ति ने, जो मज़दूर आन्दोलन पर अपना नियंत्रण कायम रखने के

पुराने ढंग की शिल्प-यूनियनों के नेताओं के दृढ़-निश्चय से और प्रबल हो गई थी, बड़े पैमाने के उद्योगों में मज़दूरों को औद्योगिक आधार पर संगठित करने के किसी भी अभियान को खण्डित कर दिया। जब तक अधिकार क्षेत्र संबन्धी समस्याओं का निबटारा नहीं कर लिया गया और इस्पात, मोटर व रबड़ उद्योगों में नए यूनियन सदस्यों को आहिस्ता-आहिस्ता विद्यमान यूनियनों में खपा नहीं लिया गया तब तक ए. एफ. एल. से सीधे सम्बद्ध तथाकथित संघीय यूनियनों के निर्माण का ढंग ही स्वीकार किया गया। १९३२ और १९३४ के बीच के फेडरेल यूनियनों की संख्या ३०७ से १७९८ हो गई। किन्तु इस प्रकार के संगठनों से अदक्ष मज़दूरों की वास्तविक आवश्यकताएँ पूरी नहीं हुईं और बड़े पैमाने के उद्योगों में बढ़ी हुई हलचल बहुत शीघ्र ही घटने लगी।

विफलता के इन प्रमाणों के कारण ए. एफ. एल. के अन्दर अधिक प्रगतिशील नेता तौर-तरीकों में परिवर्तन की जोरदार माँग करने लगे। उन्होंने असंगठित मज़दूरों को यूनियनों में लाने के लिए अधिक जोरदार अभियान किया तथा मोटर, इस्पात, रबड़, ऐल्युमीनियम तथा रेडियो उद्योग में तुरन्त ही औद्योगिक यूनियन चार्टर दिए जाने की माँग की। जब ए. एफ. एल. के रूढ़िवादी शासकों ने इन माँगों को ठुकरा दिया तो शिल्प यूनियनों तथा औद्योगिक यूनियनों के हामियों के बीच बढ़ती हुई खाई ने मज़दूर वर्ग में फूट पैदा कर दी। इसके महानतम अवसर के समय इसकी एकता नष्ट हो गई। विद्रोही मज़दूरों ने उन परिस्थितियों में, जिनका हम आगे चलकर उल्लेख करेंगे, अपनी निजी औद्योगिक संगठन समिति (कमेटी आव इण्डस्ट्रियल आर्गनाइज़ेशन) बना ली और मज़दूर इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ।

इस बीच पुरानी यूनियनों ने भी यह देखा कि स्वाधीनता के लए चार्टर से जो ऊँची-ऊँची आशाएँ उन्होंने बाँधी थीं वे और संघर्ष किए बिना पूरी नहीं होंगी। एन. आर. ए. की औद्योगिक संहिता को स्वीकार किये जाने तक सब मालिकों को राष्ट्रपति के पुनः कार्यनियोजन समझौते का पालन करने की हिदायत की गई, जिसमें ४९ घण्टे के सप्ताह की, १५ डालर साप्ताहिक या ४० सेण्ट प्रति घण्टा न्यूनतम वेतन की व्यवस्था की गई थी और १६ वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम लेने पर पाबन्दी लगाई गई थी। तब वाणिज्य संगठनों ने ज्यादा स्थायी समझौतों की रूप-रेखा तैयार की जिनमें यह माना

गया कि मजदूरों के हितों की रक्षा हर उद्योग में एक श्रम सलाहकार बोर्ड करेगा। किन्तु अन्ततोगत्वा इन वाणिज्य संगठनों ने सामान्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य किया और स्थायी नियमों के निर्माण में कर्मचारियों का वस्तुतः कोई हाथ नहीं था। अधिकांश समझौतों में ४० घण्टे का सप्ताह, तथा १२ से १५ डालर साप्ताहिक न्यूनतम वेतन निश्चित किया गया किन्तु अन्ततः जहाँ राष्ट्र के ९५ प्रतिशत औद्योगिक मजदूरों को यह संरक्षण प्रदान किया गया वहां अन्य मामलों में उनके अधिकारों की उपेक्षा कर दी गई। सामूहिक सौदे-बाजी के बारे में संरक्षण या तो निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किए गए या धीरे-धीरे उनमें कटौती कर दी गई। उदाहरणार्थ मोटर निर्माता अपने करार में एक ऐसी धारा रखवाने में सफल हो गए जिससे वे "व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर" अपने कर्मचारियों को छांट सकें, काम पर बनाए रख सकें या तरक्की दे सकें। इस प्रकार के सिद्धान्त से कोई इन्कार नहीं कर सकता किन्तु यूनियन विरोधी मालिकों को इससे किसी भी सुविधाजनक बहाने पर यूनियन सदस्यों के साथ भेदभाव करने का साधन मिल गया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने बाद में आदेश किया कि खण्ड ७ (ए) की व्याख्या किसी कोड (संहिता या करार) में शामिल न की जाए। उन्होंने कहा कि मालिक जिस किसी को भी काम पर लगाना चाहे उसके इस अधिकार में यह बाधा नहीं डालता किन्तु कर्मचारी को यूनियन में शामिल होने से रोकने के एक उपाय के रूप में इस अधिकार का इस्तेमाल करने से स्पष्ट रोकता है।

जब उद्योगों में फिर से जान आने लगी और भयभीत मालिक मन्दी की अंधेरी गुफा से सतर्कतापूर्वक बाहर निकल रहे थे तो उत्पादन को नियंत्रित करने तथा कीमतें निश्चित करने के बारे में प्रबन्धकों को दी गई खुली छूट के बदले मजदूरों को प्रदान की गई रियायतों पर और ज्यादा रोष प्रकट किया गया। 'आयरन एज' ने इसे "सामूहिक दण्ड-प्रहार" कह कर इसके खिलाफ चेतावनी दी और 'स्टील' ने कहा कि संगठित मजदूर जब अपने "दाँत निपोर रहे हैं" तब ओपनशाप को कायम रखने की हर कोशिश की जानी चाहिए। ए. एफ. एल. के १,००,००,००० सदस्यों की भयजनक संभावनाओं को देखते हुए 'कमर्शियल एण्ड फाइनेंशियल क्रानिकल' ने कहा कि तब देश में "एक संगठित संघटन अथवा वर्ग होगा जो राज्य से भी ज्यादा शक्तिशाली

होगा। इसका मतलब होगा स्वाधीनता की समाप्ति और अन्त में सब कहीं उत्पीड़न फैल जाएगा......।" इन भयानक चेतावनियों पर कान न देकर कुछ मालिकों ने संहिताओं की मजदूर सम्बन्धी व्यवस्थाओं का पालन करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और अन्यों ने अक्षरों का नहीं तो भावना का उल्लंघन करने का हर संभव प्रयत्न किया।

खण्ड ७ (ए) के स्पष्ट इरादे का उल्लंघन करने का एक मुख्य हथियार कम्पनी यूनियन था। कर्मचारियों के इस प्रकार के संगठनों में शामिल होने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता था किन्तु इसे वांछनीय बनाने के लिए मालिकों को हर किस्म का दबाव उन पर डालने की छूट प्राप्त थी और यह काम इतने प्रभावशाली ढंग से किया गया कि कम्पनी यूनियनों में सदस्य संख्या शीघ्र १२,५०,००० से २५,००,००० हो गई। एन. आर. ए. ने यह कह कर कि सरकार ने "किसी विशेष प्रकार के संगठन का समर्थन नहीं किया है", न केवल इस प्रकार की यूनियनों पर अपनी प्रच्छन्न स्वीकृति प्रदान की बल्कि सामूहिक सौदेबाज़ी में उन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहन भी प्रदान किया। जब किसी कारखाने में कोई राष्ट्रीय यूनियन अधिकांश मजदूरों को अपना सदस्य बना लेती थी, तब भी उसे समस्त मजदूरों का प्रवक्ता स्वीकार नहीं किया जाता था और प्रबन्धक मजदूरों के अन्य किसी भी वर्ग से व्यवहार कर सकते थे। कानून की इस व्याख्या की मजदूरों ने यह कह कर आलोचना की कि इससे सामूहिक सौदेबाज़ी का समस्त सिद्धान्त ही बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। एन. आर. ए. की बहुत भद्दे ढंग से मजाक उड़ाई गई और कहा गया कि नीली चील एक गिद्ध में परिवर्तित हो गई है।

जब औद्योगिक संघर्ष अपने पुराने ढर्रे पर फिर तेज हो चला तो एन. आर. ए. ने स्वयं को दो अग्नियों के बीच पाया : एक तरफ बहुत से मालिकों का इन्कारी का रवैया था और दूसरी ओर मजदूरों की उग्रतापूर्ण माँगें थीं। बढ़ते हुए औद्योगिक झगड़ों को निबटाने के लिए पहले एक राष्ट्रीय मजदूर बोर्ड, तब कुछ उद्योगों में विशेष बोर्ड और अन्त में जुलाई, १९३४ में एक

ज़ोर देता था। इसके द्वारा बहुमत-प्रतिनिधित्व, गुप्त चुनाव और वास्तविक सामूहिक सौदे-बाज़ी का समर्थन तथा इसके साथ ही कम्पनियों के प्रभुत्व में स्थापित यूनियनों को मान्यता देने से इन्कार ने इसी नाम से बाद में स्थापित किए गए बोर्ड की नीतियों के लिए आधार प्रदान किया। मूल एन. एल. आर. बी. (नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड) के कार्य में एन. आर. ए. (नेशनल रिकवरी ऐडमिनिस्ट्रेशन) से रुकावट पड़ती थी और उसके पास अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कोई अधिकार नहीं था।

अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मज़दूरों को हड़तालों का अधिकाधिक आश्रय लेना पड़ा। १९३३ के उत्तरार्द्ध में हड़तालों की संख्या एकदम बढ़ गई। ६ महीने में ही इतनी हड़तालें हुई, जितनी १९३२ के सम्पूर्ण वर्ष में; और अगले वर्ष उनकी संख्या १८५६ तक जा पहुँची। करीब १५ लाख मज़दूरों ने—कुल मज़दूरों के करीब ७ प्रतिशत ने इनमें भाग लिया। इस्पात, मोटर, कपड़ा उद्योगों, प्रशान्त सागर के तट के बन्दरगाहों के गोदी कर्मचारियों में, उत्तर-पश्चिम के काष्ठ कर्मचारियों में और बीसियों अन्य उद्योगों में हड़तालों की या तो धमकी दी गई या वस्तुतः १९२० के दशक के समान बड़े पैमाने पर हड़तालें फूट पड़ीं। इनमें से बहुत-सी हड़तालें वेतन-वृद्धि के लिए थीं किन्तु इनमें से बहुत काफी कम से कम एक तिहाई यूनियन-मान्यता के लिए थीं।

इस अशांति को दूर करने के लिए सरकार ने यथासंभव सब कुछ किया। विशेष सलाहकार बोर्ड तथा मध्यस्थता कमीशन कायम किए जिन्होंने हड़तालियों को पुनः काम पर लौटाने की कोशिश की और सम्बन्धित उद्योगों में हालतों की छानबीन की गई। इस्पात तथा मोटर कारखानों में हड़तालों को अंतिम क्षण राष्ट्रीय पैमाने पर फैलने से रोका गया; सानफ्रांसिस्को में संक्षिप्त आम हड़ताल के बाद मध्यस्थता के ज़रिये गोदी कर्मचारियों की हड़ताल का निबटारा किया गया। किन्तु मज़दूर सरकार की नीति के बारे में असन्तुष्ट और शंकालु होकर ही काम पर वापस गए।

सबसे गम्भीर और हिंसात्मक हड़ताल कपड़ा कर्मचारियों की रही। मालिकों ने व्यापक रूप से नियमों का उल्लंघन किया और काटन कोड अथारिटी ने उन्हें लागू करने की कोई कोशिश नहीं की। १२ डालर की न्यूनतम वेतन दर में कमी किए बिना ३० घण्टे के सप्ताह की; मज़दूरों को अतिरिक्त

वेतन दिए बिना उन पर काम का ज्यादा बोझ डालने की परम्परा की समाप्ति; तथा यूनाइटेड टैक्सटाइल वर्कर्स को मान्यता दिये जाने का योग करते हुए अगस्त, १९३४ में मिल कर्मचारी सामूहिक रूप से कारखानों से बाहर निकल आए। मैसाच्यूसेट्स में १,१०,००० ने, रहोड आइलैण्ड में ५०,००० ने, जार्जिया में ६०,००० ने और अलाबामा में २८,००० ने काम बन्द कर दिया। महीने की समाप्ति तक २० राज्यों में कोई ४-५ लाख स्त्री-पुरुष मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। तब तक के मज़दूर इतिहास में यह अकेली सबसे बड़ी हड़ताल थी। दक्षिण में जहाँ "उड़न दस्ते" एक मिल से दूसरी मिल में जाकर मज़दूरों को हड़ताल करने या धरना देने का आह्वान कर रहे थे, पुलिस तथा नगर अधिकारियों के साथ अनिवार्यतः भिड़न्तें हुईं। संघर्ष जब अपनी चरम सीमा पर था तो ८ राज्यों में कोई ११००० रक्षक दल के सैनिक व्यवस्था कायम रखने के लिए हथियार-बन्द होकर तैनात थे।

राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के हस्तक्षेप करने और उद्योग में परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक नए कपड़ा मज़दूर सम्बन्ध बोर्ड की नियुक्ति का वचन दिए जाने के बाद ७ सितम्बर को यूनियन नेताओं ने हड़ताल वापस ले ली। क्या यह नीतिमय प्रत्यावर्तन था या आत्म-समर्पण? इस बारे में रायें भिन्न थीं और कपड़ा कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश देने के लिए श्रम-नीति के निर्माताओं की प्रशंसा भी की गई और आलोचना भी की गई। किन्तु यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि उद्योग में वास्तविक शांति स्थापित नहीं हुई। मालिक यूनियन सदस्यों के साथ भेद-भाव करते रहे, दक्षिण के नगरों में लौटने वाले हड़तालियों को मिलों में घुसने से रोक दिया गया और मज़दूरों में और ज्यादा पस्त-हिम्मती फैली।

एन. आर. ए. के प्रारम्भिक दिनों में मज़दूरों ने जो लाभ प्राप्त किए थे व लुप्त होते प्रतीत हुए। कोड की व्यवस्थाओं को स्वीकार करने के लिए या सही सामूहिक सौदे-बाजी को कार्यान्वित करने के लिए अनिच्छुक मालिकों की हठधर्मिता ने, हड़ताल के निबटारों में मज़दूरों के हितों की रक्षा करने में सरकार की विफलता ने और बड़े पैमाने के उद्योगों में कर्मचारियों के उनके प्रभावशाली संगठन के लायक समर्थन प्रदान करने में ए. एफ. एल. की असमर्थता अथवा अनिच्छा ने मिलकर मज़दूरों की बड़ी-बड़ी आशाओं पर तुषार-

घात कर दिया। यद्यपि यूनियन सदस्यों की संख्या १९३५ में दो वर्ष पूर्व की अपेक्षा १० लाख ज्यादा थी तो भी यह ४० लाख से कम ही थी, यद्यपि ग्रीन ने १९३३ की समाप्ति पर अकेले ए. एफ. एल. के ही इतने सदस्य हो जाने की गर्वपूर्ण घोषणा की थी। लाखों नए सदस्य यूनियनों को छोड़ गए और कोई ६०० संघीय यूनियनें भंग हो गईं। मोटर कर्मचारियों की संगठित शक्ति सिर्फ १०,००० रह गई; ऐमलगमेटेड ऐसोसियेशन आव आयरन, टिन ऐण्ड स्टील वर्कर्स की सदस्य संख्या केवल ८६०० रह जाने पर इस्पात उद्योग की गतिविधियों में आया हुआ उभार बैठ गया और कपड़ा हड़ताल के दौरान यूनाइटेड टैक्सटाइल वर्कर्स में शामिल कई लाख मजदूरों में से सिर्फ ८० हजार ही यूनियनों में रह गए। खण्ड ७ (ए) को स्वीकार किए जाने बाद प्रारम्भ हुआ आन्दोलन अपना वेग खो चुका था।

१९३५ के शुरू में न केवल मजदूर सम्बन्धों की समस्या को हल करने में, बल्कि एक सफल व्यावसायिक संगठन प्रदान करने में भी एन. आर. ए. की विफलता और ज्यादा छिपाई नहीं जा सकती थी। कवायदों और झंडियां लहराने के जिस जोश-ओ-खरोश के साथ इसका स्वागत किया गया था, उसके मुकाबले अब उस पर सब तरफ से आक्षेप किए जाने का दुख:दायी दृश्य देखने में आया। पुनरुत्थान को पहला धक्का जरूर दे दिया गया था किन्तु उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव खत्म हो चला था। बड़े उद्योग प्राय: मजदूर संहिता के खिलाफ उठ खड़े हुए और छोटे उद्योग यह महसूस करने लगे कि वे एक अधिकार के पुनरुज्जीवन और यूनियनों की मांग के दो पाटों के बीच पिस गए हैं। मजदूर समझते थे कि उनके साथ दगा किया गया है। आन्तरिक विरोधों के कारण जब सारा कार्यक्रम अवरुद्ध हो गया तो देश आर्थिक नियन्त्रणों की उस प्रणाली का समर्थन करने के मूड में नहीं रहा जिसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता और जो उपभोक्ताओं के लिए सब से ज्यादा हानिकारक प्रतीत होता था। मई, १९३५ में इस घोषणा पर कि प्रसिद्ध स्केक्टर पोल्ट्री केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम को असांविधानिक घोषित कर समस्त ढांचे पर ही आखिरी प्रहार कर दिया है लोगों ने आंसू बहाने के बजाय चैन की सांस ली।

खण्ड ७ (ए) में मज़दूरों को जो संरक्षण प्रदान किए गए थे, इस फैसले से सब ख़त्म हो गए। किन्तु रेलवे लेबर ऐक्ट में एक संशोधन से वे रेल कर्मचारियों को निश्चित रूप से प्राप्त हुए और अन्य कर्मचारियों को भी उन्हें ज्यादा निश्चित रूप में प्राप्त कराने का आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका था। बहुत शीघ्र ही, यहाँ तक कि मार्च १९३४ में उन त्रुटियों को दूर करने के लिए सेनेटर वागनर ने बिल पेश किया जिन के कारण उद्योग कम्पनी यूनियनों की स्थापना करके और अन्य किसी ग्रुप से सामूहिक सौदेबाजी से इन्कार करके उद्योग मज़दूरों की ताकत को पंगु बनाए दे रहे थे। वर्तमान कानूनों की ओर परख करने की राष्ट्रपति की दलील पर उन्होंने अस्थायी रूप से अपना यह बिल वापस ले लिया था किन्तु १९३५ के शुरू में इसे फिर पेश किया। एन. आर. ए. के असांविधानिक घोषित होने के ठीक ११ दिन पहले यह सेनेट में पास हो चुका था।

वागनर बिल का मज़दूरों ने प्रबल समर्थन किया और एन. आर. ए. का खात्मा हो जाने से स्वभावतः ही प्रतिनिधि सभा द्वारा इसे शीघ्र स्वीकार कर लिए जाने की माँग तेज हो गई। ग्रीन ने असाधारण रूप से उग्र मुद्रा में कांग्रेस की एक समिति के समक्ष गवाही देते हुए कहा : "मुझे आप से यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अमरीकी मज़दूरों की आत्मा जाग उठी है, वे सामूहिक रूप से सौदेबाज़ी करने का कोई न कोई तरीका निकालेंगे...मज़दूरों का भी इस दुनिया में कोई स्थान होना ही चाहिए। जब तक वागनर बिल को कानून नहीं बनाया जाता और उस पर अमल नहीं किया जाता तब तक हम मजदूरों से निरन्तर धैर्य रखने के लिए न तो कह सकते हैं और न कहेंगे।"

इस बिल के निर्माण में रूज़वेल्ट का कोई हाथ नहीं था और मंत्री पर्किन्स तथा रेमण्ड मोले दोनों की साक्षी के मुताबिक जब उनके सामने इसका खुलासा किया गया तो उन्होंने इसे बहुत पसन्द नहीं किया। यह सेनेटर वागनर का ही काम था। किन्तु जैसा कि मोले ने बताया है एन. आर. ए. के ख़ात्मे के बाद राष्ट्रपति ने "अपने हाथ फैला दिए" और यकायक इसका स्वागत किया। मज़दूरों को बिल्कुल पिसने नहीं दिया जा सकता था और जहाँ तक सामूहिक सौदेबाज़ी का सम्बन्ध है, वागनर बिल खण्ड ७ (ए) की व्यवस्थाओं

को फिर अधिक शक्तिशाली रूप में कानूनी रूप देने के लिए एक अच्छा साधन था। सरकारी समर्थन के कारण बिल प्रतिनिधि सभा में शीघ्र पास हो गया और ५ जुलाई को रूज़वेल्ट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए।

यद्यपि वागनर ऐक्ट या जिसे सरकारी तौर पर नेशनल लेबर रिलेशन्स ऐक्ट (राष्ट्रीय मज़दूर सम्बन्ध अधिनियम) कहा जाता था, में निहित सामान्य नीति एन. आर. ए. खण्ड ७ (ए) में मौजूद थी तो भी नए कानून में यह बहुत स्पष्ट था कि मज़दूरों के प्रति सरकार की नीति में बुनियादी परिवर्तन हुआ है। न केवल औद्योगिक सम्बन्धों में उन्मुक्तता के पुराने विचारों की उपेक्षा की गई बल्कि रूज़वेल्ट सरकार ने संगठन बनाने का मज़दूरों का अधिकार स्वीकार करते हुए यह ज़रूरी नहीं समझा कि एन. आर. ए. की तरह इसके बदले प्रबन्धकों को भी रियायतें दी जाएँ। उद्योग चाहे कुछ भी दावे पेश करें, उनके मुकाबले मज़दूरों की सौदेबाज़ी की ताकत को मज़बूत करने और फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रीय आय का अधिक हिस्सा प्राप्त कर सकने लायक बनाने की दृष्टि से यह तैयार किया गया था। इसके पीछे औचित्य यह था कि हमारे उद्योग-प्रधान समाज में सिर्फ सरकार के समर्थन से ही मज़दूर प्रबन्धकों के साथ समान आधार पर खड़े हो सकते थे और समय आ गया था जब पलड़े को, जो हमेशा उद्योग के पक्ष में बहुत झुका रहता था, मज़दूरों के पक्ष में झुकाया जाता। वागनर ऐक्ट में जिन अनुचित तौर-तरीकों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था, वे सब मालिकों पर लागू होते थे और यूनियनों पर उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था।

रूज़वेल्ट ने घोषणा की कि कानून का उद्देश्य मज़दूरों और प्रबन्धकों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना है, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इसका एकपक्षीय होना स्वीकार किया। उन्होंने कहा : "मज़दूर की आज़ादी को नष्ट कर सकने वाले तौर-तरीकों की रोकथाम करके इस कानून के दायरे में आने वाले प्रत्येक मज़दूर के लिए चुनाव और कार्य की वह स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश की गई है जो न्यायतः उसकी है।"

इस प्रकार की आज़ादी की गारण्टी करने के लिए न केवल मज़दूर के संगठन करने के अधिकार पर ही स्पष्ट ज़ोर दिया गया बल्कि मालिकों की तरफ से सब प्रकार के हस्तक्षेप की स्पष्ट मनाही कर दी गई। मज़दूर को

अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकना अथवा उसके साथ जोर-जबर्दस्ती करना, किसी मज़दूर संगठन की सहायता के लिए उसे धन देना या किसी संगठन को अपने प्रभुत्व में लाने की कोशिश करना, काम पर रखने या काम से हटाने में भेदभाव करके यूनियन की सदस्यता को प्रोत्साहन देना या हतोत्साहित करना अथवा सामूहिक सौदेबाज़ी से इन्कार करना मालिकों के लिए अनुचित तौर-तरीके घोषित कर दिये गए। इसके अतिरिक्त यह विधान कर दिया गया कि किसी निर्दिष्ट यूनिट में चाहे वह मालिक, शिल्प या कारखाना यूनिट हो, सामूहिक सौदेबाज़ी के लिए अधिकांश कर्मचारियों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों को ही समस्त कर्मचारियों के लिए सौदेबाज़ी का अधिकार होगा। अर्थात् नए कानून ने कम्पनियों द्वारा प्रभावित यूनियनों को, जो एन. आर. ए. के मातहत फल-फूल रही थीं, ग़ैर-कानूनी बना देने और सच्चे यूनियनवाद को प्रोत्साहन देने का पक्का निश्चय कर लिया।

वागनर ऐक्ट का प्रशासन तीन सदस्यों के एक नए नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड के हाथों में सौंप दिया गया और कौन सी यूनिट सौदेबाज़ी कर सकती है, इसका निश्चय करने का और उन चुनावों का निरीक्षण करने का, जिनमें कर्मचारी मालिकों से व्यवहार के लिए अपने विशिष्ट प्रतिनिधि चुनते थे, उसे एकमात्र अधिकार प्रदान किया गया। बोर्ड श्रम सम्बन्धी अनुचित तौर-तरीकों के खिलाफ शिकायतें सुन सकता था और जहाँ उसे ये शिकायतें वाजिब मालूम देतीं वहाँ "बन्द करो और बाज़ आओ" आदेश जारी कर सकता था और अपने आदेशों पर अमल कराने के लिए अदालतों से दरख्वास्त कर सकता था। एन. एल. आर. बी. को वेतन और काम के घण्टों के बारे में होने वाले विवाद के गुणावगुण से अथवा काम की हालतों पर असर डालने वाले अन्य किसी मामले से कोई सरोकार नहीं था। उसका काम तो सिर्फ सामूहिक सौदेबाज़ी को क्रियात्मक दृष्टि से प्रोत्साहन देना और उसे आसान बनाना था।

इस प्रशासनिक एजेन्सी के अर्ध-न्यायिक कार्यों का स्पष्टीकरण करते हुए राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने कहा : "यह साफ़-साफ़ समझ लिया जाना चाहिए कि श्रम सम्बन्धी झगड़ों में यह मध्यस्थ अथवा मेल कराने वाले का काम नहीं करेगा। इस अधिनियम के मातहत मध्यस्थता का काम श्रममंत्री का और

श्रम-विभाग की मेल कराने वाली सर्विस का ही रहेगा.....यह बहुत महत्त्व-पूर्ण है कि न्यायिक कार्य और मध्यस्थता के कार्य में घुटाला न किया जाए। बीच के समझौते का, जो मध्यस्थता का सार है, कानून की व्याख्या अथवा परिपालन में कोई स्थान नहीं है।"

वागनर ऐक्ट के पारित होते समय उसे व्यापक समर्थन मिला। व्यापारी वर्ग में से पुराणपन्थी तत्त्व के कानून ने एकतरफा होने की आलोचना की, खुल्लमखुल्ला घोषणा की कि इसके अन्तर्गत यूनियनें ग़ैर-ज़िम्मेदार हो जाएँगी और प्रबन्धकों के नियंत्रण पर उसे खतरा जान वे उस पर बहुत भयभीत थे। किन्तु लोकमत ने उन दिनों मज़दूरों की आकांक्षाओं के प्रति बार-बार सहानुभूति दिखाई। यह आम भावना और विश्वास था कि प्रबन्धकों को हानि पहुँचने पर भी मज़दूर सरकार का संरक्षण पाने के हकदार हैं और वे अपने नए अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

नए कानून के अंग-प्रत्यंग कैसे भी हों इसके परिणाम बहुत दूरगामी थे। क्लेटन ऐक्ट, नोरिस-ला गार्दिया ऐक्ट और नेशनल इण्डस्ट्रियल रिकवरी ऐक्ट में संगठन करने के मज़दूरों के अधिकार को अक्षुण्ण रखने की भावना आखिरकार साकार हुई। मज़दूर अपनी गतिविधियों में रुकावट डालने वाले कानूनी बन्धनों से छुटकारा पाने के लिए एक सदी से अधिक समय तक लड़े थे। इसने साज़िश सम्बन्धी कानूनों व येलो-डॉग करारों पर अमल करने के खिलाफ, आज़ादी की उस अदालती व्याख्या के विरुद्ध, जो वस्तुतः व्यक्तिगत मज़दूर की आज़ादी को कुण्ठित करती थी, और निरोधादेशों के मनमाने उप-योग के खिलाफ संघर्ष किया था। वागनर ऐक्ट ने यूनियन सम्बन्धी गति-विधियों पर न केवल पिछली सब रुकावटें हटा दीं, बल्कि मज़दूरों की आर्थिक शक्ति के पूर्ण संगठन के लिए मालिकों द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए जाने के मार्ग में काफी बाधाएँ खड़ी कर दीं।

किन्तु नए कानून के पूरे लाभ उठाने के लिए संघर्ष करना अभी बाकी था। बहुत से मालिक जहाँ इस कानून की व्यवस्थाओं को स्वीकार करने और ईमानदारी से अपने कर्मचारियों के साथ सामूहिक सौदेबाज़ी करने के लिए तैयार थे, वहाँ कुछ मालिक यूनियनों के इतने सख्त

ख़िलाफ थे कि उन्होंने किसी भी कीमत पर अपना प्रतिरोध जारी रखने का निश्चय कर रखा था। अनेक क्षेत्रों में मज़दूरों को अपना संगठन बनाने के लिए उतने ही घोर विरोध का सामना करना पड़ा जितना पहले करना पड़ता था। सरकार की गारण्टियों के बावजूद जब बहुत-सी कम्पनियों ने यूनियनों को मान्यता प्रदान नहीं की तब उसे हासिल करने के लिए मज़दूरों को पुनः हड़ताल का आश्रय लेना पड़ा।

सामूहिक सौदेबाज़ी के लिए नई कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति से इन्कार करने के लिए प्रायः यह बहाना किया जाता था कि वागनर ऐक्ट असांविधानिक है। अपने वकीलों से यह सलाह पाकर कि सुप्रीमकोर्ट इस कानून को अन्तर्राज्यीय व्यापार पर, जिस पर इस कानून की व्यवस्थाएँ आधारित हैं काँग्रेस के अधिकार से परे बता कर निश्चित रूप से असांविधानिक घोषित कर देगी, यूनियन-विरोधी मालिकों ने कानून का उल्लंघन करने में कोई संकोच नहीं किया और नेशनल लेबर रिलेशन्स ऐक्ट द्वारा इस कानून पर अमल को रोकने के लिये बीसियों निरोधादेश प्राप्त करने की अर्जियाँ दीं। उन्होंने मज़दूरों के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य इस्पात, मोटर, रबड़ तथा बड़े पैमाने के अन्य उद्योगों में यूनियनों के निर्माण को रोकना था। कम्पनी यूनियनों पर अब भी उन्होंने अपना नियंत्रण कायम रखने की कोशिश की। यूनियन सम्बन्धी हरकतों का कोई भी प्रमाण हासिल करने के लिए, स्वयं मज़दूरों में परस्पर अविश्वास और सन्देह के बीज़ बोने के लिए और जिनको आन्दोलनकारी कहा जा सके उनसे छुटकारा पा सकने के लिये आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए मज़दूर जासूस और भड़काने वाले एजेण्ट रखे गए। कुछ मामलों में अधिक ज़ोर-ज़बर्दस्ती के तरीकों से यूनियन की सदस्यता को अनुत्साहित करने के लिए मारपीट करने वाले दल रखे गए, बाहर से आए संगठनकारियों को पीटा गया, शहर से भगा दिया गया और धमकी दी गई कि अगर वे फिर कभी लौटकर आए तो उनकी खैर नहीं है।

१९३३ और १९३७ के बीच औद्योगिक सम्बन्धों में कानूनी और सांविधानिक अधिकारों की कितनी अवहेलना की गई यह ला फौलेट नागरिक स्वाधीनता समिति की रिपोर्ट में बड़े खौफनाक रूप में प्रकट हुआ। इस

रिपोर्ट की पहली किश्त में जो दिसम्बर, १९३७ में प्रकट की गई, बताया गया कि कोई २,५०० कम्पनियां (सूची अमरीकी उद्योगों की नीली किताब-सी प्रतीत होती थी) औद्योगिक जासूसी में विदग्ध एजेंसियों से चिरकाल से मजदूर-जासूस किराये पर ले रही थीं। पिंकर्टन ऐण्ड बर्न्स एजेंसीज, रेलवे ऐण्ड आडिट इन्स्पेक्शन कम्पनी और कार्पोरेशन्स आग्जिलियरी कम्पनी जैसी फर्मों के रिकार्डों से पता चला कि उन्होंने विचाराधीन तीन वर्ष की अवधि में यूनियन सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट देने, कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ाने और मजदूर संगठनों के काम में सामान्यत: बाधा डालने के लिए ३,८७१ एजेण्ट प्रदान किए। अपनी गुप्त हलचलों के लिये इन एजेण्टों ने व्यक्तिश: ९३ यूनियनों से सम्पर्क कायम किया और एक-तिहाई पिंकर्टन जासूस यूनियन के अधिकारी बनने में सफल हो गए। यह भी बताया गया कि कुछ चुनींदा कम्पनियों ने १९३३ से १९३६ तक गुप्तचरों, हड़ताल-भंजकों और शस्त्रास्त्रों पर ९४,४०,००० डालर खर्च किए। अकेले जनरल मोटर्स कार्पोरेशन ने ही ८,३०,००० डालर का बिल चुकाया।

ला फौलेट कमेटी ने निष्कर्ष निकाला कि "जनता औद्योगिक जासूसी की इस चुनौती को दरगुजर नहीं कर सकती। इसके जरिये प्राइवेट कम्पनियां अपने कर्मचारियों पर प्रभुत्व जमाए रहती हैं, उनको सांविधानिक अधिकारों से वंचित रखती हैं, अव्यवस्था और फूट उत्पन्न करती हैं तथा सरकार की सत्ता तक को व्यर्थ कर देती हैं।"

इसी समिति ने जब १९३७ की लिटल स्टील स्ट्राइक की छानबीन की तो औद्योगिक संघर्ष के लिए एकत्र हथियारों का प्रकट हो जाना औद्योगिक जासूसी से भी ज्यादा स्तब्धकारी था। यंगसटाऊन शीट ऐण्ड ट्यूब कम्पनी के पास ८ मशीनगनें, ३६९ रायफलें, १९० शाटगनें और ४५० रिवाल्वर, ६९५० कारतूस और ३००० गैस-कारतूसों समेत १०९ गैस-बन्दूकें थीं। रिपब्लिक स्टील कार्पोरेशन के पास भी इतने ही शस्त्रास्त्र थे बल्कि इसके अलावा उसने ७९,००० डालर की आंसू और रोग गैस खरीद रखी थी और अमरीका में उसे इस गैस का सबसे बड़ा खरीदार बताया गया था। कानून का पालन करने वाली सरकारी एजेंसियों के पास भी इतनी गैस नहीं थी। ला फौलेट ने कहा कि इन दो कम्पनियों के अस्त्र-शस्त्र "एक छोटे युद्ध के लिए

पर्याप्त होंगे ।"

यूनियनवाद का विरोध करने के लिए औद्योगिक तौर-तरीकों का एक और खास बदनाम उदाहरण प्रकट हुआ। पहले-पहल रेमिंगटन रैण्ड कम्पनी ने उसे ईजाद किया था और तब मोहाक वैली फार्मूला के नाम से नेशनल ऐसोसियेशन आव मैन्युफैक्चरर्स ने इसका व्यापक प्रचार किया। इस फार्मूले की रूपरेखा यह थी, कि इसमें यूनियन के सब संगठनकर्त्ताओं को खतरनाक आन्दोलनकारी बताकर उन्हें बदनाम करने का, कानून और व्यवस्था के नाम पर समाज को मालिकों के पक्ष में करने का, सभाएँ भंग करने के लिए स्थानीय पुलिस की सेवाएँ लेकर हड़तालियों को आतंकित करने का, गुप्त रूप से "वफादार कर्मचारियों" का संगठन कर "काम पर लौटने" के आन्दोलनों को प्रोत्साहित करने का और हड़ताल वाले कारखाने को फिर से चालू करते हुए रक्षा समितियों की स्थापना करने का बाकायदा एक अभियान शुरू किया गया। मोहाक वैली फार्मूले का अन्तर्हित उद्देश्य यूनियन नेताओं को विध्वंसक बताकर और यह धमकी देकर लोकमत का समर्थन प्राप्त करना था कि अगर स्थानीय व्यावसायिक हित खड़े-खड़े देखते रहे और उन्होंने क्रान्तिकारी आन्दोलनकारियों को, वैसे मालिकों के साथ सहयोग के लिए उद्यत और उत्सुक कर्मचारियों पर हावी होने दिया तो वे सम्बद्ध उद्योग को उस इलाके से उठा ले जाएँगे।

ला फौलेट समिति द्वारा प्रकट की गई इस साक्षी से औद्योगिक संघर्ष की अब तक छिपाकर रखी गई कुछ बातें सामने आ गईं। अत्यधिक कंज़र्वेटिव अखबारों ने भी, यह कहते हुए भी कि समिति की छानबीन एक-तरफ़ा रही है और उसकी रिपोर्ट में अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, यह तसलीम किया कि इस स्थिति पर चुप नहीं रहा जा सकता और उन्होंने मजदूरों की नागरिक स्वाधीनताओं की रक्षा की वकालत की। इस रहस्योद्घाटन ने अनेक कम्पनियों को यह विश्वास कराने में, कि जो तौर-तरीके अब ज़माने के लायक नहीं रहे उन्हें छोड़ देने में ही अक्लमन्दी है, बहुत महत्त्वपूर्ण काम किया।

इस बीच मजदूर इस यूनियन विरोधी अभियान का अपने ही ढंग तौर-तरीकों से सामना कर रहे थे। जिस अवधि में वागनर ऐक्ट के मूल सिद्धान्त और

पर लगे रहे उस सबमें औद्योगिक अशांति व्यापक रूप से जारी रही। १९३७ में हड़तालों की संख्या १९३४ से भी ज़्यादा जा पहुँची। कुल ४७२० हड़तालें हुईं, जिनमें २० लाख श्रमिकों ने भाग लिया।

अशान्ति की इस नई लहर की चरम परिणति जब जनरल मोटर्स के कारखाने में "बैठे रहो" हड़ताल के रूप में हुई तब भी वागनर ऐक्ट की सांविधानिकता का निर्णय नहीं हुआ था, किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने अन्ततः १२ अप्रैल, १९३७ को कार्रवाई की। अनेक निर्णयों में, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड बनाम जोन्स ऐण्ड लाफलिन स्टील कम्पनी के मामले में दिया गया, इस कानून की पुष्टि की गई। न्यू डील और संगठित मज़दूरों के लिए यह एक चामत्कारिक विजय थी और अदालत के रवैये में परिवर्तन की परिचायक थी जिसने वर्ष के शुरू में राष्ट्रपति रूज़वेल्ट द्वारा मज़दूरों के पुनर्गठन के मामले पर शुरू किए गए संघर्ष को नाटकीय ढंग से परिणति पर पहुँचा दिया। अन्तर्राज्यीय वाणिज्य पर प्रभाव डाल सकने वाले श्रम-सम्बन्धों के नियमन को वाणिज्य धारा के अन्तर्गत स्पष्टतः कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में घोषित किया गया और इस दलील को कि ऐक्ट की व्यवस्थाएँ मालिक या कर्मचारी के अधिकारों पर आघात करती हैं, एकदम ठुकरा दिया गया।

एन. एल. आर. बी. बनाम जोन्स ऐण्ड लाफलिन के केस में मुख्य न्यायाधीश ह्यूजेज़ ने ४ के विरुद्ध ५ न्यायाधीशों का निर्णय सुनाते हुये कहा कि "जिस प्रकार वादी को अपने व्यवसाय का संगठन करने और उसके लिए अपने अफसर और एजेण्ट चुनने का अधिकार है, उसी प्रकार कर्मचारियों को भी कानून-सम्मत उद्देश्य के लिए संगठित होने तथा अपने प्रतिनिधि चुनने का हक है। आत्म-संगठन और प्रतिनिधि-निर्धारण के अपने अधिकार को मज़दूरों द्वारा स्वतन्त्रता से उपयोग किए जाने से रोकने के लिए भेदभाव और ज़ोर-ज़बर्दस्ती का व्यवहार योग्य विधायक प्राधिकार द्वारा निन्दनीय है। बहुत साल पहले हम मज़दूर संगठनों का औचित्य जता चुके हैं। हमने कहा था कि वे समय की आवश्यकताओं के कारण संगठित हैं, अकेला कर्मचारी मालिक से व्यवहार करने में असहाय है; साधारणतः वह अपने तथा अपने

परिवार के जीवन-यापन के लिये दैनिक मज़दूरी पर निर्भर करता है; यद्यपि

मालिक मज़दूर को उसकी समझ के मुताबिक उचित वेतन देने से इन्कार करता है, तो भी मजदूर काम छोड़ने में असमर्थ है और मनमाने तथा अनुचित व्यवहार का प्रतिरोध करता है; और यूनियन मज़दूरों को मालिक के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करने का अवसर प्रदान करती है......।" नेशनल रिलेशन्स लेबर बोर्ड का सिक्का बैठ जाने के बाद यह अन्त में उस हालत में आया जब कानून को प्रभावशाली ढंग से अमल में ला सकता था। इसने इस धारा का व्यापक भाष्य किया कि मालिक द्वारा मजदूरों को अपने अधिकारों के प्रयोग में बाधा डालना, रोकना या जोर-जबर्दस्ती करना श्रम सम्बन्धी अनुचित कार्य है। न केवल येलो डाग करार, काली सूची में नाम दर्ज करना और अन्य प्रकार के स्पष्ट भेद-भाव मूलक कार्यों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया बल्कि मज़दूर-गुप्तचरों के उपयोग और यूनियन विरोधी प्रचार की मनाही कर दी गई। कम्पनी-प्रभावित यूनियनें भग कर दी गई, यूनियन शाप और बन्द-शाप दोनों को कायम रखा गया और शान्तिपूर्ण धरने में हस्तक्षेप करना वर्जित कर दिया गया।

श्रम सम्बन्धी अनुचित तौर-तरीकों के जितने मामले बोर्ड के सामने आए उनमें से अधिकांश का निबटारा वस्तुतः यह ख्याल रखते हुए किया गया कि उद्योग के हितों को नुकसान न पहुँचे। यह निस्सन्देह सच था कि प्रायः सर्वथा अनुचित आरोप लगाए जा सकते थे और प्रबन्धक मज़दूरों द्वारा अनुचित तरीके अपनाए जाने की कोई शिकायत नहीं कर सकते थे किन्तु प्रायः शत्रुतापूर्ण प्रेस ने जिसने मजदूरों के प्रति कल्पित पक्षपात के लिए बोर्ड पर आक्षेप करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जैसा चित्र खींचा, एन. एल. आर. बी. का रिकार्ड उससे बिल्कुल भिन्न रहा।

१९३५ से १९४५ तक ३६००० मामले जिनमें अनुचित तौर-तरीके बरतने के आरोप लगाए गए थे और कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित ३८,००० मामले हाथ में लिए गए। इनकी सम्मिलित संख्या में से २९·५ प्रतिशत बिना कोई कार्रवाई किए वापस ले लिए गए, ११·९ प्रतिशत को प्रादेशिक डाइरेक्टरों ने बर्खास्त कर दिया, ४६·३ प्रतिशत में अनौपचारिक प्रक्रियाओं से आपस में समझौता करा दिया गया और सिर्फ १५·९ प्रतिशत मामलों में अधिकृत सुनवाई की आवश्यकता पड़ी। बाद के इन मामलों में किए गए फैसलों के

फलस्वरूप कोई २००० कम्पनी यूनियनें भंग कर दी गई और जहाँ मालिक असली यूनियन सदस्यों के खिलाफ भेदभाव करने के दोषी पाए गए उनमें ६० लाख डालर के बकाया वेतन दिलाने के साथ ३ लाख कर्मचारी काम पर बहाल कराये गए।

अनुचित तौर-तरीकों के इस्तेमाल की शिकायतों की सुनवाई करने और शिकायत ठीक पाई जाने पर "बन्द करो और बाज़ आओ" आदेश जारी करने के अलावा नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड ने १९३५ से १९४५ तक के अरसे में सामूहिक सौदे-बाज़ी की अधिकारी यूनियन का निश्चय करने के लिये कोई २४००० चुनाव कराए जिनमें ६० लाख मज़दूरों ने भाग लिया। इन चुनावों में से सी. आइ. ओ. ने ४० प्रतिशत, ए. एफ. एल. ने ३३·४ प्रतिशत, स्वतंत्र यूनियनों ने १०·५ प्रतिशय चुनाव जीते; १६·१ प्रतिशत चुनावों में सौदे-बाज़ी के लिए कोई भी यूनियन नहीं चुनी गई। यह ध्यान रहे कि बोर्ड को वेतन और काम के घण्टों से सम्बन्धित झगड़ों से कोई सरोकार नहीं था, किन्तु जिन मामलों को हाथ में लेने का उसे अधिकार था उनमें इसकी गतिविधियों ने औद्योगिक सम्बन्धों को स्थिरता प्रदान करने में बहुत सहायता दी।

संगठन करने और सामूहिक सौदेबाज़ी के लिए मज़दूरों के अधिकार को दिया गया संरक्षण न्यू डील के अन्तर्गत सामान्यत: अपनाई गई मजदूर पक्षपाती नीति का सबसे महत्त्वपूर्ण दौर था। एक बार अपने रास्ते पर चल पड़ने के बाद रूज़वेल्ट सरकार यूनियन के विकास को प्रोत्साहन देने तथा हमारे राष्ट्रीय अर्थतंत्र के विकास में मज़दूरों का बुनियादी रोल स्वीकार करने में पिछली अन्य किसी भी सरकार से आगे निकल गई। परन्तु न्यू डील के अन्तर्गत वागनर ऐक्ट मज़दूरों की सहायता करने तथा औद्योगिक श्रमिकों की सुधरी हालत में योग देने वाला अकेला कदम नहीं था।

राष्ट्रपति ने अपने पद पर आरूढ़ होने के बाद शुरू से ही जो इस बात पर बल दिया कि बेकारी और राहत की बुनियादी समस्याओं से सीधे निबटने का सरकार का उत्तरदायित्व है, उसने राष्ट्र के मज़दूरों की आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैये को स्पष्ट जाहिर कर दिया जो अमरीकी लोकतंत्र के अत्यन्त प्रगतिशील सिद्धान्तों के अनुरूप था। नेशनल इण्डस्ट्रियल रिकवरी में शामिल सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योगों में प्राण

फूँकना था किन्तु सिविलियन कंजरवेंशन कोर तथा फेडरेल एमर्जेंसी रिलीफ ऐडमिनिस्ट्रेशन दोनों का सीधा उद्देश्य बेकारों की विशाल सैन्य को राहत प्रदान करना था। ये मानवीय आवश्यकताओं की महत्त्वपूर्ण समस्या के प्रति एक नए दृष्टिकोण के प्रतीक थे जो राष्ट्रपति हूवर के दृष्टिकोण से बहुत भिन्न था। राष्ट्रपति हूवर प्रत्यक्ष राहत को व्यक्ति की पहल करने की क्षमता और आत्म-सम्मान को चोट पहुँचाने वाली समझ कर उसका चिरकाल तक विरोध करते रहे। रूज़वेल्ट प्रशासन ने जब तक उद्योग पुनः समर्थ होकर रोज़गार के लिए अधिक अवसर प्रदान न कर सकें तब तक बेकारों की समस्या को और सरकारी सहायता की आवश्यकता को समझने में अधिक यथार्थवादिता से काम लिया।

यह बात एक और कार्यक्रम से भी प्रकट हुई जिसकी परिणति वर्क्स प्रोग्रेस ऐडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हुई। इस एजेंसी की स्थापना न केवल बेकारों की सहायता करने के लिए, अपितु उन्हें काम देने के लिए भी हुई, जिससे वे अपने आत्म-सम्मान की रक्षा कर सकें। पुनरुत्थान की धीमी प्रगति और १९३७ में आई मन्दी के कारण सरकार इस कार्यक्रम में इतनी ज़्यादा उलझ गई जितनी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। तो भी संभावित किफायत की अपेक्षा मज़-दूरों की खुशहाली को ज़्यादा महत्त्वपूर्ण समझा गया और अत्यधिक खर्चा करने की समस्त आलोचनाओं के बावजूद प्रशासन अपने मार्ग पर दृढ़ रहा। एक और ज़्यादा दूरगामी कदम जिसे रूजवेल्ट "अपने प्रशासन का आधार-स्तम्भ" मानते थे, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम था, जिसमें बेकारी का बीमा, बुढ़ापे का बीमा तथा जरूरतमन्दों के लिए अन्य प्रकार की सहायता की व्यापक व्यवस्था की गई थी। जैसा कि हमने देखा, इस कानून में निहित सिद्धान्त का ए. एफ. एल. ने तब तक विरोध किया जब तक १९३२ के सम्मेलन में बेकारी के बीमे पर अपनी परम्परागत नीति को उसने उलट नहीं दिया। तब इसने सरकारी कार्रवाई का समर्थन किया। लेकिन राष्ट्रपति के अपने हित ने सामाजिक सुरक्षा के अभियान को बहुत प्रभावशाली ढंग से पुष्ट किया। मंत्री पर्किन्स ने लिखा: "उनकी अपनी समझ से यह उनका अपना कार्यक्रम था।"

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सर्वोत्तम उपायों का रूज़वेल्ट ने १९३३ के प्रारम्भ में अध्ययन करवाना शुरू किया; अपने कथन के अनुसार "पालने

घण्टों, न्यूनतम वेतन और करीव-करीव आखिरी मिनट में जोड़े गए बाल-श्रम की समाप्ति की, जिसका विधान पहले एन. आर. ए. के नियमों में करने की कोशिश की गई थी, व्यवस्था करने का विल पेश करने के लिए हरी झण्डी दे सके।

'फेयर लेवर स्टैण्डर्ड्स विल' का (जिस नाम से यह मशहूर हुआ) जोरदार विरोध किया गया जो अंशतः अदालती संघर्ष से उत्पन्न मनमुटाव का प्रतीक था और पहले मजदूरों ने भी इसका एक स्वर से समर्थन नहीं किया। ए. एफ. एल. के वहुत से रूढ़िवादी नेता वेतनों के बारे में कानून बनाने के अब भी विरुद्ध थे। उन्हें डर था कि न्यूनतम वेतन अधिकतम वेतन वन कर न रह जाएँ और ग्रीन ने अपने ख्याल से सरकार के प्रस्तावों में महत्त्वपूर्ण कमियों के खिलाफ मजवूती से मोर्चा लिया। जब ए. एफ. एल. और एन. ए. एम. के प्रवक्ताओं का संदिग्ध गठबन्धन हो गया तो न्यूडील के कानूनों पर अमल ज्यादा कठिन हो गया।

रूज़वेल्ट ने कांग्रेस को दिए गए अपने भाषणों तथा देश के साथ संलापों, दोनों में बिल के महत्त्व पर बार-बार बहुत जोर दिया। मई, १९३७ में उन्होंने कहा कि "एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी लोकतंत्र बाल-श्रम के औचित्य को सिद्ध नहीं कर सकता, मज़दूरों के वेतनों में कटौती करने या काम के घण्टे वढ़ाने का कोई उपयुक्त आर्थिक कारण नहीं बता सकता।" किन्तु मज़दूरों के साथ न्याय करने के अलावा प्रस्तावित बिल की व्यवस्थाओं का इसलिए भी समर्थन किया गया कि उसे राष्ट्र की क्रयशक्ति को बनाए रखने तथा उसे मज-बूत करने का एक आवश्यक साधन समझा गया।

इस दृष्टि से ऊँचे वेतनों का महत्त्व कोई नया विचार नहीं था। मज़दूर सदा से यह कहते आए थे कि जब मज़दूरों को इतना पर्याप्त वेतन मिलेगा कि वे अपने उद्योगों का तैयार माल खरीद सकें तभी हमारी आर्थिक प्रणाली सफ-लतापूर्वक कार्य कर सकती है। इस सिद्धान्त का निदर्शन १९२७ में ही मैके-निक्स यूनियन आव ट्रेड ऐसोसियेशन ने, वेतन, खपत और उत्पादन पर दिए गए एक वक्तव्य में कर दिया था। किन्तु इस युक्ति ने बहुत ही धीमे प्रगति की और १९३० के दशक के प्रारम्भ में इसे आहिस्ता-आहिस्ता ही स्वीकार जा रहा था जब कि अब यह सामान्य-सी बात समझी जाती है। ऊँचे

वेतनों के पक्ष में क्रयशक्ति के सिद्धान्त का सदा इस प्रत्युक्ति से विरोध किया जाता रहा कि ऊँचे वेतन उत्पादन की लागत को बढ़ाकर तैयार माल के लिये बाज़ार को सीमित कर देते हैं और फलस्वरूप उत्पादन की गति को मन्द कर देते हैं।

१९३७ की ग्रीष्म ऋतु में जब कांग्रेस ने फेयर लेबर स्टैण्डर्ड्स बिल पर कार्रवाई नहीं की तो रूजवेल्ट ने पुनः एक व्यापक मोर्चे पर अभियान शुरू कर दिया और नवम्बर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाकर उन्होंने इसे शीघ्र स्वीकार किए जाने की माँग की।

उन्होंने कहा : "सामान्य औद्योगिक परिस्थिति में मन्दी लाने वाले तत्त्वों के खिलाफ अगर हमें वेतनों में वृद्धि और राष्ट्र की क्रयशक्ति को कायम रखना है तो मैं समझता हूँ कि समग्र देश कांग्रेस द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता को महसूस करता है। मन्दी के समय में बाल-श्रम का शोषण और गरीब-से-गरीब मजदूरों के वेतनों में कटौती तथा काम के घण्टों में वृद्धि का क्रयशक्ति पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। यदि हम अमरीकी उद्योगों की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देते हैं तो देश को अन्ततोगत्वा क्या मिलेगा जब तक कि हम इस बात की व्यवस्था न करें कि हमारे मज़दूरों की आमदनी भी इतनी बढ़ जाए कि तैयार माल का अधिक उत्पादन भी बाजारों में खप सके।"

लगातार विलम्ब, मजदूरों की आपत्तियाँ दूर करने के लिए बिल के मसविदे में हेरफेर किए जाने तथा अत्यधिक सरकारी विलम्ब के सामने आखिर विरोध ने घुटने टेक दिए। जून, १९३८ में फेयर लेबर स्टैण्डर्ड्स बिल पास हो गया। इसने २५ सेण्ट प्रति घण्टे की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जिसे सात वर्ष में ४० सेण्ट कर देने का निर्देश किया, ४८ घण्टे का सप्ताह नियत किया गया जिसे तीन वर्ष में ४० घण्टे का कर देने को कहा गया और अन्तर्राज्यीय वाणिज्य में बिकने वाला माल तैयार करने वाले उद्योगों में १६ वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने की मुमानियत कर दी। वह आन्दोलन, जिसका बीज एक सदी पूर्व मज़दूरों की १० घण्टे के दिन की माँग के साथ पड़ा था, अब फल ले आया था। वेतन तथा काम के घण्टों पर राज्य ने सीधा इतना व्यापक नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसे मन्दी से पहले संभव भी नहीं

माना जा सकता था। यह उतनी ही महत्त्वपूर्ण घटना थी जितनी सामूहिक सौदेबाजी को सरकार का समर्थन। स्वच्छन्द अर्थ तंत्र के सिद्धान्तों का, जिनका सेम्युअल गोम्पर्स और विलियम ग्रीन जैसे मजदूर नेताओं ने भी अत्यधिक रूढ़िवादी पूंजीपतियों की अपेक्षा कम दृढ़ता से समर्थन नहीं किया, कोई और इतना प्रत्यक्ष उल्लंघन नहीं कर सकता था। किन्तु अब अधिकतम घण्टे और न्यूनतम वेतन के कानून को अधिकांश लोगों ने आवश्यक समझ कर सामान्यतः स्वीकार कर लिया था।

सरकार ने मजदूरों के हितों का समर्थन करना शुरू कर दिया था और ऐसे ही अदालतों ने भी। जिन मामलों में वागनर ऐक्ट, सामाजिक सुरक्षा और फेयर लेबर स्टैण्डर्ड्स ऐक्ट को वैध करार दिया गया, उनमें अदालतों के पहले के निर्णयों को उलट दिया गया था और इसने न्यू डील की नीतियों पर स्वीकृति की अंतिम मुहर लगा दी। जब सुप्रीमकोर्ट ने यह कहा कि "जब कोई नियमन अपने विषय की दृष्टि से युक्तियुक्त हो और समाज के हित में अपनाया गया हो" तब उसे ५वें या १४वें संशोधन की उचित कानूनी प्रक्रिया वाली धारा का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता, तब यह विचार छोड़ दिया गया कि यूनियन-सदस्यता को प्रभावित करने वाले अथवा न्यूनतम वेतन निर्धारित करने वाले कानून करार की स्वाधीनता की सांविधानिक गारण्टी का हनन करते हैं।

इसके अतिरिक्त अदालतों ने अब यूनियनों को ट्रस्ट-विरोधी कानूनों के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाए जाने से मुक्त कर दिया और शनैः-शनैः हड़ताल, बहिष्कार तथा धरना देने के अधिकार को स्वीकार करके अन्य प्रतिबन्धात्मक नीतियों को उलट दिया। प्रगतिशील युग में भी जहाँ मजदूरों ने यह देखा कि उनके कथित गारण्टी प्राप्त अधिकारों को भी सुप्रीमकोर्ट बार-बार काट रही है वहाँ अब उसकी स्थिति अनुकूल निर्णयों से निरन्तर पुष्ट की जा रही थी। उदाहरणार्थ थौर्न हिल बनाम अलाबामा के एक मशहूर केस में शांतिपूर्ण धरना देने को संविधान के अन्दर गारण्टी प्राप्त भाषण-स्वातन्त्र्य का उचित प्रयोग घोषित कर दिया गया।

वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक चली गई कि १९४५ में 'हण्ट बनाम ...' के मामले में उसने बहुमत से यूनियन को अत्यन्त जटिल परिस्थितियों

में उस फर्म के खिलाफ बहिष्कार के अधिकार को उचित ठहराया जो इस निर्णय के फलस्वरूप खत्म ही हो गई। न्यायाधीश जैक्सन को इस केस ने मज़दूरों के प्रति अदालतों की नीति की महत्त्वपूर्ण समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया।

अपनी ज़ोरदार विमतसूचक टिप्पणी में उन्होंने कहा: "इस निर्णय के साथ मजदूर आन्दोलन एक पूरा चक्कर घूम गया है। मज़दूरों ने चिरकाल तक संघर्ष किया है, संघर्ष खतरनाक और घृणापूर्ण रहा है किन्तु अब मज़दूरों को सिर्फ इसलिए अपनी आजीविका से वंचित नहीं किया जा सकेगा कि उनके मालिक यूनियनों का विरोध करते हैं और वे समर्थन करते हैं। मज़दूरों ने अन्य अधिकार भी प्राप्त किए हैं, जैसे-बेकारी का मुआवजा और बुढ़ापे की पेंशन और सबसे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण और अन्य सब लाभों का आधार यह मान्यता प्राप्त कर ली है कि उनका समर्थन प्राप्त करने का अवसर सिर्फ व्यक्ति के लिए ही चिन्ता का विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसी समस्या है जिसका जीवित रहने के इच्छुक सब संगठित समाजों को सामना करना है और उस पर विजय प्राप्त करनी है। यह अदालत अब एक यूनियन के इस दावे को पुष्ट कर रही है कि सिर्फ इसलिए कि यूनियन अपने मालिक से घृणा करती है, उसे अपने मालिक को आर्थिक जगत में भाग न लेने देने का अधिकार है। यह अदालत कर्मचारियों को उनके नियंत्रण के आर्थिक क्षेत्र में वही मनमाना प्रभुत्व प्रदान कर रही है जिसके बारे में मज़दूर चिरकाल से दृढ़तापूर्वक और उचित ही यह कहते आ रहे हैं कि वह किसी आदमी को नहीं मिलना चाहिए।"

न्यायाधीश जैक्सन के विचारों में कुछ भी सार्थकता हो और कभी कभी मज़दूरों द्वारा अपने अधिकारों के स्वेच्छाचारी प्रयोग के कारण बाद में कुछ भी समस्याएं खड़ी हुई हों, मज़बूत यूनियनों के विकास को प्रोत्साहन देने, और वैसे भी संगठित मज़दूरों की स्थिति को मज़बूत करने के न्यू डील के सामान्य कार्यक्रम की १९३० की दशाब्दी के मध्य में राष्ट्र ने आमतौर से सराहना ही की। जनता की राय जानने के लिए बार-बार जो सर्वे किया गया उसमें १९३३ और १९३८ के बीच कांग्रेस द्वारा उत्तरोत्तर पास किए गए

मज़दूर सम्बन्धी कानूनों के प्रति लोगों का दृढ़ समर्थन ही प्रकट हुआ। राष्ट्रपति रूज़वेल्ट का इस समय यह विश्वास प्रकट करना निस्सन्देह उचित ही था कि अधिकांश लोग इस बात पर प्रसन्न ही हैं कि "हम धीरे-धीरे मज़दूरों को अधिक अधिकार दिला-रहे हैं और साथ ही उनपर ज्यादा जिम्मेदारियाँ भी डाल रहे हैं।"

इन वर्षों में निरन्तर जारी रहने वाली और विशेषकर १९३७ की हड़तालों ने यह स्पष्ट ज़ाहिर कर दिया कि औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में कोई अन्तिम समाधान प्राप्त नहीं हुआ है और न्यू डील की मजदूर-पक्षपाती नीतियों की शीघ्र ही ज़ोरदार प्रतिक्रिया होने वाली है। किन्तु मज़दूरों के उपद्रवों तथा वागनर ऐक्ट में संशोधन की अधिकाधिक माँग किये जाने पर भी रूज़वेल्ट का यह विश्वास दृढ़ बना रहा कि यूनियनों की बढ़ी हुई ताकत से कुछ समय बाद अधिक औद्योगिक स्थिरता आ जाएगी। सामूहिक सौदेबाज़ी के सिद्धान्त में उनका पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा कि "इसे हमेशा के लिए औद्योगिक सम्बन्धों की नींव बने रहना है।" वह मज़दूरों को न केवल उनके लाभ कायम करने में बल्कि उनमें और वृद्धि करने के लिए भी सहयोग देने के लिये तत्पर थे।

१९४० में इण्टरनेशनल ब्रदरहुड आव टीम्स्टर्स के सम्मेलन में एक महत्त्वपूर्ण भाषण देते हुए उन्होंने कहा : "सिर्फ आज़ाद प्रदेश पर आज़ाद यूनियनें पनप सकी हैं। जब इस प्रकार के सम्मेलन में मज़दूर आज़ादी के साथ सम्मिलित होते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि अमरीकी लोकतन्त्र में कोई बिगाड़ नहीं आया है; इसे आज़ाद बनाए रखने के हमारे दृढ़ संकल्प का यह एक प्रतीक है।"

उनकी राय में मज़दूरों को अब भी बहुत-सी तकलीफ़ें थीं और वे समझते थे कि अधिक जिम्मेदार नेताओं का उभरना लाज़िमी है जिससे उतने ही जिम्मेदार प्रबन्धकों के साथ अधिक सहयोग सम्भव हो सकेगा। जब एक बार उन्हें यह चेतावनी दी गई कि होश्यार ! यूनियनें बहुत ताकतवर हो सकती हैं तो उन्होंने जवाब दिया बताते हैं, "बहुत ताकतवर, किस चीज़ के लिए ?" उनका मत था कि उनकी शक्ति बड़े व्यवसाय की शक्ति से सन्तुलन करने वाली सिद्ध होगी। मज़दूरों और स्वतन्त्र मज़दूर यूनियनों के

अत्यधिक महत्त्व में उनका विश्वास डिगने वाला नहीं था।

न्यू डील कार्यक्रम का बुनियादी महत्त्व इस बात में नहीं था कि मज़दूरों ने तात्कालिक लाभ प्राप्त किए या क्या हानियाँ उठाईं, बल्कि इस मान्यता में था कि मज़दूरों की काम की हालतों का सारा प्रश्न अब मालिकों व कर्मचारियों का ही मामला नहीं है अपितु सारे समाज का है। लोकतन्त्रीय पूँजीवाद जीवित रहने की आशा मुश्किल से ही कर सकता था, जब तक कि मज़दूरों की विशाल सेना को सम्मिलित प्रयत्नों के ज़रिये वह आज़ादी और सुरक्षा न मिल जाती जिस की वे एक औद्योगिक समाज में व्यक्तिगत रूप से रक्षा करने में असमर्थ थे। न्यू डील की नीति मज़दूर-पक्षपाती ज़रूर थी किन्तु यह चिरकाल से मालिकों के पक्ष में झुके चले आ रहे पलड़े को बराबर करने के लिए मज़दूर-पक्षपाती बनाई गई थी। इसका उद्देश्य मुख्यतः मज़दूरों की भलाई करना था किन्तु साथ ही इसका यह विश्वास भी था कि इनकी भलाई में ही सारे देश की भलाई निहित है।

—:o:—

१६ : सी. आई. ओ. का अभ्युदय

संगठित मज़दूर न्यू डील के जमाने में जहां इतने निश्चित लाभ प्राप्त कर रहे थे, वहाँ इसमें आपस की फूट ने इसकी पहले की सापेक्षिक एकता को ध्वस्त कर दिया। ए. एफ. एल. में औद्योगिक बनाम शिल्प यूनियन पर विवाद से जब विद्रोही उठ खड़े हुए और उन्होंने औद्योगिक संगठन समिति (सी. आई. ओ.) कायम कर ली तो निरन्तर प्रतिद्वन्द्विता के लिए आधार तैयार हो गया जिसने कुछ हद तक तो यूनियनों के विकास को प्रोत्साहन दिया किन्तु आन्तरिक झगड़ों के कारण मज़दूरों की शक्ति को छितरा भी दिया।

इन विवादग्रस्त मामलों की तुलना उन मामलों से की जा सकती है जब आधी सदी पूर्व ए. एफ. एल. ने नाइट्स आव लेबर को चुनौती दी थी। क्या यूनियन संगठन मुख्यतः दक्ष कर्मचारियों के हित में चलाया जाए या उसका उद्देश्य अदक्ष कर्मचारियों के विशाल समुदाय को भी प्रभावशाली ढंग से शामिल करना भी होना चाहिए ? नाइट्स ने इस समस्या को सर्व-निवेशी यूनियन बनाकर हल करने की कोशिश की किन्तु आर्थिक परिस्थितियों ने ए. एफ. एल. के नये यूनियनवाद का पक्ष लिया। जिसमें ज्यादा अनुशासित शिल्पों पर ज़ोर दिया गया था। १८८० की दशाब्दि में औद्योगिक यूनियन-वाद का किसी भी रूप में सफलता पूर्वक विकास नहीं किया जा सका क्योंकि अदक्ष कर्मचारियों की जिनकी संख्या आव्रजन के कारण फिर-फिर बढ़ती रहती थी, सौदे-बाज़ी की क्षमता बहुत तुच्छ थी। किन्तु १९३० की दशाब्दि की परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों ने सर्वथा औद्योगिक यूनियनों के निर्माण को महत्व तथा व्यावहारिकता दोनों पर बल दिया। बड़े पैमाने के उद्योगों में असंगठित कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में विफलता ने मज़दूर आन्दोलन को बहुत कमज़ोर कर दिया था और अब सरकारी समर्थन के कारण तथा आव्रजन कम हो जाने से सौदे-बाज़ी की सम्भावित क्षमता काफी जाने के कारण उन्हें संगठित करने का पहले किसी भी समय की अपेक्षा

अधिक अच्छा अवसर उपलब्ध था।

किन्तु ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. के आपसी झगड़े में जिसमें दोनों वर्ग सत्ता-प्राप्ति के लिए जद्दो-जहद कर रहे थे और उनके नेताओं में प्रतिद्विन्द्विता बढ़ रही थी शिल्प यूनियनवाद अथवा औद्योगिक यूनियनवाद का विवाद अधिकाधिक गौण हो गया। इन विवाद ग्रस्त मामलों का स्थान राजनीति की भीषण पैंतरे-बाजियों तथा महत्वाकाङ्क्षी व्यक्तियों की भिड़न्त ने ले लिया।

ग्रीन ने लिखा: "सब मज़दूरों की हालत को बेहतर बनाने के हमारे सामान्य प्रयत्नों के बीच एक आदमी आगे आया जिसके कुछ और ही उद्देश्य थे। व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा से भरपूर इस व्यक्ति ने अपना नेतृत्व ठुकरा दिए जाने के बाद लोकतंत्रीय प्रक्रिया को धत्ता बता दिया। उसने द्वित्व और फूट की आवाज़ उठाई, ऐसी आवाज़ जो एकता का बहाना करती हुई भी विध्वंस के लिए प्रयत्नशील थी, लोकतंत्रीय आदर्शों की घोषणा करते हुए भी तानाशाही स्थापित करना चाहती थी।"

बदले में लेविस ने ए. एफ. एल. के 'अड़चनकारी' रवैये और इसके नेताओं की अन्ध रूढ़िवादिता पर तीव्र प्रहार किए। फेडरेशन के संगठन सम्बन्धी प्रयत्नों को उसने "अनवच्छिन्न विफलता के २५ वर्षों" का प्रतीक बताया और इसके अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि या तो वह राष्ट्रीय अर्थतंत्र की वर्तमान परिस्थितियों को समझने में अथवा समय की मांग के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हैं। १९३६ में जब ये शाब्दिक कंकड़, एक-दूसरे पर फैंके जा रहे थे तो लेविस ने रिपोर्टरों से कहा: "बेचारे ग्रीन पर मुझे अफसोस है। मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वह चाहता है कि "ओ टैम्पोरा ओ मोरेस" के मन्द-मन्द गान में उसका साथ दूं।"

औद्योगिक यूनियनवाद के अभियान को अपने हाथ में लेकर और ए. एफ. एल. के शासकवर्ग को सीधी चुनौती देकर लेविस ने स्वयं को अमरीका में अब तक का सबसे आक्रामक और आकर्षक मज़दूर नेता जाहिर किया। न्यू डील के प्रारम्भिक दिनों में युनाइटेडमाइन वर्कर्स की सदस्य संख्या को १॥ लाख से बढ़ा कर ४ लाख तक पहुंचा देने में उसने जो

चामत्कारिक सफलता प्राप्त की उस पर सारे राष्ट्र का ध्यान गया। "फोर्चून" पत्रिका ने चिढ़ कर टिप्पणी की "वह सारे मज़दूर ग्रान्दोलन जितना शोर करता है।" और कुछ समय बाद यह शोर कान के पर्दे फाड़ने लगा। इस समय में लेविस के प्रति आम लोगों के रवैये की यह विशेषता थी, कि दुश्मन हो या दोस्त, हर कोई उसे सदा अत्यधिक बढ़े-चढ़े रूप में प्रस्तुत करता था। या तो उसे बे-मिसाल नायक बताया जाता या घृणित शैतान।

फिलिप मर्रे ने जो उनके बाद सी. आई. ओ. का अध्यक्ष बना, कहा कि कम्यूनिज़्म के साथ संयुक्त मोर्चे के दिनों में वह "समस्त अमरीका में अपना सानी नहीं रखता था" अर्ल ब्रोडर ने उसे न केवल महानतम अमरीकी मज़दूर नेता ही बल्कि "विश्व लोकतंत्र का एक नेता" बताया और ह्यू लोंग उसकी इससे ज्यादा बड़ी प्रशंसा नहीं कर सका कि उसे "मज़दूरों का लोंग्यू ग" बताया। दूसरी ओर निन्दा का स्वर युद्ध के दिनों में अपने उच्चतम शिखर पर पहुँचा। १९४३ में जब "फोर्चून" ने इस विषय में लोकमत का सर्वे किया कि अमरीका में सबसे हानिकारक व्यक्ति कौन है तो ७० प्रतिशत लोगों ने अपनी पर्चियों पर जॉन एल. लेविस का नाम लिखा।

लेविस की पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रारम्भिक जीवन दोनों का ही मज़दूर आन्दोलन से निकट सम्बन्ध रहा। विलियम ग्रीन के समान उसके माता-पिता भी वेल्स की खानों में काम करने वाले लोगों में से थे और जब १८७५ में उसके पिता अमरीका चले आए तो उनका परिवार ल्यूकास (आयोवा) के एक छोटे से कोयला-नगर में आकर बस गया। यहाँ आकर लेविस के पिता शीघ्र नाइट्स आव लेबर में शामिल हो गए। जॉन लेविस का जन्म १८८० में हुआ और १२ वर्ष की आयु में खानों में काम करने लगा। एक किशोर तथा युवक की आयुओं में अनेक राज्यों की खानों में बेचैनी से घूमते-फिरते रहने के बाद १९०९ में उसने मज़दूर-राजनीति में पदार्पण किया। पनामा (इलिनोयस) में पहले युनाइटेड माइन वर्कर्स की स्थानीय शाखा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद वह यूनियन का राज्य विधायक ऐजेण्ट बना, उसके बाद ए. एफ. एल. का क्षेत्रीय प्रतिनिधि और अनन्तर क्रमशः युनाइटेड वर्कर्स का मुख्य सांख्यिक, प्रथम उपाध्यक्ष और अन्त में अध्यक्ष चुना। जैसा कि हमने देखा कि १९१९ के कोयला संकट में जब उसने सरकार

के खिलाफ़ खान-मज़दूरों की हड़ताल कराने से इन्कार कर दिया था तो उसका नाम राष्ट्र के पत्रों में मोटी-मोटी सुर्खियों में छापा गया था। बाद के वर्षों में जब कोयला खानों के मालिकों ने उसकी यूनियन पर चोटें कीं, क्रांतिकारी तत्त्वों ने उसके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया और युनाइटेड माइन वर्कर्स की ताकत घटती चली गई तो लेविस को रक्षात्मक संघर्ष में जूझना पड़ा। एन. आर. ए. द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उसने स्वयं को और अपनी यूनियन को उबारने में जिस तत्परता से लाभ उठाया उसने पहले-पहल यह दिखा दिया कि उसमें कितनी चतुराई, अवसर से लाभ उठाने की योग्यता और साथ ही चुनौती भरा साहस है जिसने उसे एक राष्ट्रीय नेता बना दिया।

१९३३ के बाद जब वह उद्योग-जगत को दृढ़ता से चुनौती देते हुए ("वे मेरे नितम्ब और जाँघों पर हमला कर रहे हैं......में बहुत खुशी से उनके प्रहारों का जवाब दूँगा") मज़दूर आंदोलन में अपने दुश्मनों को बदनाम करते हुए, अपने आक्रमण की भूमि में परिवर्तन के अनुसार, गठजोड़ करते और उन्हें तोड़ते हुए और अपनी महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये सरकार को चुनौती देते हुए अपने तूफानी जीवन-पथ पर बढ़ा चला जा रहा था तो अमरीका के लोग राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के अलावा अन्य किसी सार्वजनिक व्यक्ति को उससे ज़्यादा नहीं जानते थे। उसके द्वारा कभी पूछे गये एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिये असंख्य लेख लिखे गये "मुझ को प्रेरणा देने वाली क्या चीज़ है ? क्या वह सत्ता है, जिसके पीछे मैं पागल हूँ, या में दूसरे रूप में सेण्ट फ्रांसिस हूँ, या और कुछ ?" जॉन लेविस क्या था—एक कुदरती ताकत, एक कुशल स्वांग-रचियता, एक निष्ठावान नेता या एक आत्माभिमुखी अवसरवादी ?...... अगर इसका उत्तर था—सेण्ट फ्रांसिस तो स्वाँग इससे ज़्यादा परिपूर्ण नहीं हो सकता था। व्यंग्य-चित्रकारों को मज़दूरों के इस शक्तिशाली हिमायती के आगे की ओर निकले हुए जबड़ों, क्रुद्ध त्यौरियों और घनी, खड़ी भ्रूहों को चित्रित करने में बड़ा मज़ा आता था।

उसके जीवन की कष्टदायक घुमरघेरी में कोई एक-सी विचारधारा नहीं थी। एक बार उसने "रचनात्मक औद्योगिक राजनीतिज्ञता" के लिये हर्बर्ट हूवर की प्रतिभा की बहुत सराहना की थी, १९३६ में उसने न्यू डील ने

आतुरता से आलिगन किया और अपने प्रभाव का पूरा वजन रूज़वेल्ट के पलड़े में डाल दिया और ४ वर्ष बाद राष्ट्रपति से नाटकीय ढंग से अलग हो कर वेण्डल विल्की के चुनाव के प्रश्न पर सी॰ आई॰ ओ॰ की अध्यक्षता को दाँव पर लगा दिया। अनिश्चित स्वभाव के इस व्यक्ति के लिए, जिसका एकमात्र निश्चित लक्ष्य प्रायः जॉन एल. लेविस का स्वार्थ ही प्रतीत होता था, राजनीति और मजदूर आन्दोलन में "अब यह, अब वह, अब यहाँ, अब वहाँ" ये मामूली बातें थीं। वह उन्मुक्त और नियंत्रित अर्थतंत्र में से किस में विश्वास करता था, यह पता करना मुश्किल है किन्तु इसमें कोई शक नहीं कि अपने में उसका सदा विश्वास रहता था।

१९३६ और १९३७ में उसके साथ राष्ट्रीय समस्याओं पर बातचीत करने के लिए इण्टरव्यू लेने आने वालों से वह औद्योगिक लोकतंत्र के बारे में बड़ी शान से बातचीत किया करता था किन्तु इस शब्द का अभिप्राय कभी स्पष्ट नहीं कर सका। सिर्फ इतना प्रत्यक्ष हुआ कि मौजूदा आर्थिक पद्धति को उलटने या उसमें गड़बड़ करने की कोशिश करने का उसका कोई विचार नहीं है। उसका कोई दीर्घकालीन कार्यक्रम या अंतिम लक्ष्य नहीं था और इस दृष्टि से उसकी नीति टेरेंस वी. पाउडरली अथवा नाइट्स आव लेबर के सुधारवादी उत्साह के बजाय सेम्युअल गोम्पर्स और ए॰ एफ. एल. की परम्परागत अवसरवादिता से मिलती थी। वह समझता था कि मजदूरों को सरकार के मामलों में ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए किन्तु तीसरे दल की स्थापना के उसके विचारों के पीछे प्रेरक शक्ति इस प्रकार के किसी निश्चित कार्यक्रम की पूर्ति उतनी नहीं थी, जितनी जॉन एल. लेविस को आगे बढ़ाने की इच्छा। मजदूरों के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर उसके उत्तर अस्पष्ट और शब्दजाल मात्र होते थे। एक प्रश्नकर्त्ता रिपोर्टर से उसने कहा : "ऐसा चित्र खींचना अबुद्धिमत्तापूर्ण होगा जिससे कल के हमारे दुश्मन भयभीत हो जाएँ और न ही मैं कल के मजदूर आन्दोलन के इरादों की शुद्धता और प्रशासनिक भद्रता की गारण्टी कर सकता हूँ।"

मंच पर सार्वजनिक सभाओं में और रेडियो पर लेविस ऐसी नाटकीयता [illegible]प्रदर्शन करता था जो बरबस जनता का ध्यान खींचती थी। नाटक रचने [illegible] योग्यता को वह खूब जानता था (एक बार उसने कहा था : "मेरा

जीवन बस एक मंच है") और वह एक-से आत्मविश्वास के साथ कभी मज़ाक उड़ाता, कभी निन्दा करता, कभी धमकी देता और कभी उपदेश देता था। अपने महत्त्व के प्रति उसकी चेतना बड़ी शानदार थी।

यूनाइटेड माइन वर्कर्स का संगठन करने और सी. आई. ओ. के निर्माण करने में उसने बड़े पराक्रम का परिचय दिया। मज़दूर उसके बहुत ऋणी थे। किन्तु सत्ता की उसकी अतृप्त भूख ने ट्रेड यूनियन की एकता को भंग करने में मदद दी और दूसरे विश्व-युद्ध में सरकार को दी गई उसकी चुनौती जनता की सहानुभूति को, जो न्यूडील के प्रारम्भ में मज़दूरों को प्राप्त थी खो बैठने का एक बड़ा कारण बनी। किन्तु जनता की सहानुभूति प्राप्त करने में अथवा मज़-दूरों का सहयोग हासिल करने में उसने कुछ भी क्षति उठाई हो, लेविस की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अपनेख निकों के ठोस समर्थन से जो उसके ताना-शाही नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उसने उन्हें प्राप्तियाँ करायी थीं, वह मज़दूर-राजनीति में एक प्रमुख भाग अदा करता रहा।

ए. एफ. एल. की लड़खड़ाती नीतियों के प्रति असन्तोष, जिसने लेविस को औद्योगिक यूनियनवाद का नेतृत्व करने का मौका दिया, १९३४ में सान फ्रांसिस्को में फेडरेशन के वार्षिक सम्मेलन में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। कपड़ा, इस्पात, रबड़ तथा मोटर उद्योगों में मज़दूरों द्वारा यूनियनों को तिलां-जली दिए जाने के कारण संघीय चार्टरों की बजाय औद्योगिक चार्टर दिए जाने की मांग ज्यादा जोर पकड़ने लगी। ए. एफ. एल. के अन्दर औद्योगिक यूनियनों के नेताओं ने उस नीति की निन्दा की जिसमें नई यूनियनों को मौजूदा शिल्प यूनियनों के अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी दावों के आगे गौण कर दिया गया। उन्होंने दृढ़ता से अपना यह विश्वास दोहराया कि अकेली उद्योग-व्यापी यूनियनों में दक्ष व अदक्ष सभी प्रकार के मज़दूरों का संगठन ही सामूहिक उत्पादन के उद्योगों में मज़दूरों की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है।

पुराने ढंग के शिल्प-यूनियन नेताओं ने यह बात नहीं मानी। उनके सामने जब यह तथ्य रखा गया कि पिछले वर्षों में मौजूदा औद्योगिक यूनियनों की सदस्य संख्या १२० प्रतिशत बढ़ गई है जबकि शिल्प यूनियनों में सिर्फ १० प्रति-शत सदस्य ही बढ़े हैं तो उन्होंने इसका यही अर्थ लगाया कि नए औद्योगिक चार्टर देने में जिनकी असन्तुष्ट वर्ग मांग कर रहा है, कितना खतरा है, उन्होंने कहा कि

परम्परागत कार्यप्रणाली में भिन्नता लाने से ए. एफ. एल. द्वारा डाली गई नींव हिल जाएगी। यह बात पुनः कही गई कि अपनी-अपनी "राष्ट्रीय और अन्त-र्राष्ट्रीय यूनियनों में जहाँ अधिकार-क्षेत्र कायम कर दिया गया है, मजदूरों को लाए बिना उनका सफलतापूर्वक संगठन नहीं किया जा सकता।"

सान फ्रांसिस्को में यह विवाद दोनों पक्षों के नरम लोगों के समझौता-प्रयत्नों से अस्थायी रूप से हल हो गया। यह मान लिया गया कि मोटर, रबड़, सीमेण्ट, रेडियो और ऐल्यूमीनियम उद्योगों में यूनियनों के लिए चार्टर दिए जाएंगे और इस्पात उद्योग में संगठन करने के लिये जोरदार अभियान शुरू किया जाएगा किन्तु विद्यमान शिल्प-यूनियनों के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रखे जाएंगे और अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी सब विवाद एक कार्यकारिणी परिषद् को सौंप दिए गए और परिषद् में औद्योगिक यूनियनों के प्रतिनिधियों को शामिल कर उसका विस्तर कर दिया गया।

असन्तुष्ट वर्ग के लिए कम से कम यह आंशिक सफलता और मजदूरों के लिए आशामय शकुन था। किन्तु बाद के वर्षों में इस समझौते का पालन करने के लिये कुछ नहीं किया गया। वस्तुतः ए. एफ. एल. के नेता अपने शिथि-लतापूर्ण रूढ़िवाद से जागे नहीं थे। शिल्प-यूनियन के नेताओं ने विशेषकर इमारती व्यवसाय में, औद्योगिक यूनियनवाद की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया था। मजदूर आन्दोलन के आधार को चौड़ा करने में उन्हें अब भी अपने हाथ में विद्यमान सत्ता के छिन जाने का खतरा दिखाई देता था। जिस कार्य-क्रम के बारे में कहा जाता था कि वे मान गए हैं, उसे अमल में लाना वे स्थ-गित ही करते रहे। १९३५ में अटलाण्टिक सिटी में फेडरेशन का अगला सम्मेलन बड़े पैमाने के उद्योगों में यूनियनों के मामले में बढ़ते हुए उत्साह-हीनता के वातावरण की पृष्ठ-भूमि में हुआ जिसमें कार्यकारिणी परिषद् की यह रिपोर्ट पढ़ी गई कि "इस्पात उद्योग में हम संगठन का अभियान शुरू करना उचित नहीं समझते।"

लेविस कार्रवाई की मांग करता हुआ अटलाण्टिक सिटी आया। उसके लिए इस्पात उद्योग में स्थिति विशेष रूप से चिन्तनीय थी। इस उद्योग की कोयला खानों में, जहाँ हालत बहुत खराब थी, उसने मजदूरों का संगठन बनाने सफलता प्राप्त की किन्तु उसका विश्वास था कि नई यूनियन के किले की

जब तक रक्षा नहीं की जा सकती जब तक इस्पात कर्मचारी भी संगठित न हों। औद्योगिक यूनियन के पक्षपाती अन्य नेताओं के साथ उसका इस बार पक्का विश्वास था कि वह कार्यकारिणी को या तो अपने वायदे पूरे करने के लिए मजबूर कर देगा...या...।

सम्मेलन की प्रस्ताव समिति ने अपनी बहुमत रिपोर्ट और अल्प-मत रिपोर्ट में मामला न्यायोचित ढंग से सम्मेलन में रखा। बहुमत रिपोर्ट में घोषणा की गई कि "शिल्प के आधार पर संगठित सब यूनियन के कार्य-क्षेत्र सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा करना चूँकि ए. एफ. एल. का मुख्य उत्तरदायित्व है इसलिए औद्योगिक चार्टर फेडरेशन और उससे सम्बन्ध शिल्प-यूनियनों के बीच सदा से चले आ रहे समझौतों को तोड़ देंगे। अल्प-मत रिपोर्ट में आग्रह किया गया था कि किसी भी उद्योग में जहाँ अधिकांश मज़दूरों द्वारा किया गया काम एक से अधिक शिल्प-यूनियन के अधिकार क्षेत्र में आता है वहाँ औद्योगिक संगठन ही मज़दूरों को स्वीकार्य होगा या वही उनकी आवश्यकताओं को भली-भाँति पूर्ण कर सकेगा।"

इस कटु विवाद के एक तरफ थे—प्रारम्भ में औद्योगिक यूनियनवाद वकालत करने के बावजूद गौम्पर्स द्वारा छोड़ी गई नीतियों का सावधानी से पालन करने वाला विलियम ग्रीन; कठोर तथा कड़ा प्रहार करने वाला खातियों का मुखिया विलियम एल हचिसन जिसका सब कर्मचारियों को अपनी निजी यूनियन के सुविधाजनक दायरे में रखने का दृढ़ संकल्प था, ड्राइवरों का लड़ाकू नेता डेनियल जे. टोबिन जो सामूहिक उत्पादन के उद्योगों में काम करने वाले अदक्ष मज़दूरों को घृणा से "गन्दगी" कहा करता था; फोटो-ब्लाक बनाने वालों का मैथ्यू वोल, जिसकी रूढ़िवादिता पुराने और समाप्त प्राय: नेशनल सिविक फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किए गए कामों से प्रकट होती थी; और ए. एफ. एल. के धातु-व्यवसाय विभाग के मुखिया ज्ञान और गरिमायम जॉन पी फ्रे। ये लोग औद्योगिक यूनियनवाद का अपनी सारी शक्ति से सामना करने के लिये तैयार रहते थे।

लेविस विद्रोहियों के नेता थे और उस ज़माने के अत्यन्त प्रगतिशील तथा ज़ोरदार मज़दूर नेताओं का उनको समर्थन प्राप्त था। इनमें थे—टाइपोग्रैफिकल यूनियन के शान्त, प्रभावशील मुखिया और अल्पमत रिपोर्ट के वास्तविक लेखक

चार्ल्स पी. होवार्ड; कुछ संकोचशील और मृदु स्वभाव वाले किन्तु अत्यन्त योग्य और यूनाइटेड माइन वर्कर्स में लेविस के अत्यन्त गहरे दोस्त फिलिप मर्रे; लिथुआनिया में पैदा हुए दर्जियों के नेता सिडनी हिलमैन जिसके शान्त तौर-तरीकों के नीचे भारी स्नायु-शक्ति और महत्त्वाकाङ्क्षा एकत्र थी और जिसने हाल में पहले की स्वतंत्र ऐमलगमेटेड क्लोदिंग वर्कर्स यूनियन को ए. एफ. एल. में शामिल कराया था, और एक अत्यन्त चतुर ट्रेड यूनियनिस्ट और उग्र इण्टरनेशनल लेड़ीज़ गारमेण्ट वर्कर्स के अध्यक्ष डेविड डुबिन्स्की।

इन सरदारों के बीच ए. एफ. एल. की नीति पर बहस कई दिन तक जारी रही। सम्मेलन में आरोप-प्रत्यारोपों से मामला तूल पकड़ गया। इसकी चरम अवस्था तब पहुँची जब लेविस ने उन तौर-तरीकों पर चलते हुए जिसका परिणाम नई यूनियनों के लिए शरद्ऋतु की धूप में मुरझाती घास की तरह मरने के समान हुआ" पिछले सम्मेलन में किए गए वायदों से मुकर जाने पर तीव्र आक्षेप किए।

उसने गरज कर कहा : "सानफ्रांसिस्को में उन्होंने मुझे लुभावने शब्दों से भ्रष्ट कर दिया किन्तु अब मैं यह जान कर कि उन्होंने मुझे भ्रष्ट कर दिया है, क्रुद्ध हूँ और मैं प्रतिनिधि वोल समेत अपने भ्रष्टकारियों के अंग-अंग को तार-तार कर देने के लिए तैयार हूँ। मेरा यह कथन निस्सन्देह अलंकारिक है।" उसने प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने कम भाग्यशाली भाइयों की खुशहाली में योग दें, मैसिडोनिया से आने वाली उनकी चीख-पुकार पर ध्यान दें, असंगठितों का संगठन बनाएँ और मानवता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए फेडरेशन को अब तक का सबसे महान साधन बनाएं। और उसने गम्भीरता से यह चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने यह अवसर हाथ से जाने दिया तो मज़दूरों के दुश्मनों का हौसला बढ़ेगा "और शक्तिशालियों की खाने की मेज़ों पर शराब का खूब दौर-दौरा चलेगा।"

अपने ज़ोरदार भाषण, अपीलों और चेतावनियों के बावजूद लेविस प्रतिनिधियों को परम्परागत नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता का बोध नहीं करा सका। आलंकारिक रूप में भी अंग-अंग काटे जाने की धमकी :। क : प्रतिनिधि अप्रभावित ही रहे। मैसिडोनिया की समस्त चीख पर उन्होंने अपने कान बन्द कर रखे थे। शक्तिशालियों के भोज में

शराब के दौर-दौरों के चित्रण से वे विक्षुब्ध नहीं हुए। जब अंतिम वोट लिया गया तो औद्योगिक यूनियनवाद का कार्यक्रम १०,६३३ के मुकाबले १८०२४ वोट शिल्प यूनियनों के पक्ष में दिये जाने से पराजित हो गया।

इसके कुछ ही देर पश्चात् एक ऐसी घटना घटी जो इस नाजुक वोट के समय पैदा हुई फूट की प्रतीक थी इसका विवरण कुछ धुंधला सा है। किन्तु कार्यविधि के वारे में और विवाद होते रहने पर हचिसन ने सभा की शिष्टता को भंग कर लेविस को एक ऐसा शब्द कहा जिसे दर्शकों ने "गंवारू" की संज्ञा दी। खनिकों के सरदार ने इसका जवाव अपने २२५ पौण्ड के वजन की पूरी ताकत से एक थप्पड़ मार कर दिया जो खातियों के उतने ही विशालकाय जार के जवड़े पर तड़ाक से वजा। गुत्थमगुत्था होने वाले इन दोनों सरदारों को अलग कर दिया गया और सौभाग्य से सव के वीच खुल कर लड़ाई होने से वच गई किन्तु इस झगड़े से भी दोनों कैम्पों की, जिनमें मज़दूर वँटे हुए थे, जल्दी भड़क उठने वाली भावनाएं शान्त नहीं हुईं।

ए. एफ. एल. सम्मेलन के तुरन्त वाद औद्योगिक यूनियनवाद के पक्षपातियों ने अमली कार्रवाई पर विचार करने के लिये एक सभा की। ये लोग ऐसा कोई निर्णय मानने को तैयार नहीं थे जिससे सामूहिक उत्पादन के उद्योगों में प्रभावशाली संगठन वनाने का काम दुवारा स्थागित हो जाए इसलिए ६ नवम्वर, १६३५ को उन्होंने अपनी निजी औद्योगिक संगठन समिति (कमेटी फ़ार इण्डस्ट्रियल आर्गनाइजेशन) के निर्माण के लिए पहला कदम उठाया। मूलतः इसमें लेविस, होवार्ड, हिलमैन और डुविन्स्की, युनाइटेड हैटर्स के कैंप और मिलिनरी विभाग मैक्स जारिस्की, युनाइटेड टैक्सटाइल वर्क्स के टामस एफ. मैकमोहन माइन, मिल ऐण्ड स्मेल्टर वर्क्स के टामस एच. ब्राउन और ऑयलफ़ील्ड गैसवेल ऐण्ड रिफाइनिंग वर्कर्स के हार्वे सी फ्रेमिंग थे। यह घोषणा की गई कि एक स्वतंत्र संगठन स्थापित करने के वजाय समिति का इरादा ए. एफ. एल. के ढांचे के अन्तर्गत ही काम करना है। इसका काम सामूहिक उत्पादन के उद्योगों में "आधुनिक सामूहिक सौदेवाजी" को स्वीकृति और मान्यता दिलाने की कोशिश करने के लिए "शिक्षात्मक और परामर्शात्मक था।" किन्तु इस प्रकार के वक्तव्यों के वावजूद सी आई. ओ. के नेताओं पर ग्रीन ने तुरन्त ही ए. एफ. एल. सम्मेलन के वहुमत निर्णय के खिलाफ जाने

का आरोप लगा दिया। उसने बार-बार कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य अपने दृष्टिकोण को स्वीकार कराना है। लेविस ने इसका उत्तर कार्यकारिणी परिषद् को और ज्यादा चुनौती देकर दिया।

२३ नवम्बर को उसने ग्रीन को लिखा: "प्रिय महोदय और भाई! आज की तारीख से मैं ए. एफ. एल. के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ।"

सी. आई. ओ ने तुरन्त ही अपने संगठन अभियान की योजनाएँ बनाना शुरू कर दीं और जनवरी, १९३६ के प्रारम्भ में और ए. एफ. एल. का कार्यकारिणी में अंतिम बार इस्पात, मोटर, रबड़ तथा रेडियो में औद्योगिक चार्टर दिए जाने की की पुरानी माँग दोहराई किन्तु पुराने नेताओं में कोई फूट नहीं पड़ी। नयी कमेटी के आक्रामक तौर-तरीकों का ए. एफ. एल. में शिल्प यूनियनों की जमी हुई स्थिति पर क्या असर होगा इससे भयभीत कार्यकारिणी के सदस्यों ने सी. आई. ओ को तुरन्त भंग किए जाने का आदेश जारी कर उस भय को दूर करना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विद्रोह फैलाना है और "कुछ थोड़े से स्वार्थी व्यक्तियों" के हित-साधन के लिए प्रतिद्वन्द्वी संगठन कायम किया गया है।

अगले कुछ महीनों तक ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ के नेताओं में भीषण रोष भरा विवाद चलता रहा और मज़दूरों में फूट की खाई चौड़ी होती चली गई। ग्रीन ने विद्रोहियों को वापस लाइन में लाने के लिए कभी उन्हें मनाने की कोशिश की और कभी धमकियाँ दीं। किन्तु लेविस अक्खड़ता से अपने ही रास्ते पर चलता रहा। अन्त में ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के दिनों में ए. एफ. एल. की कार्यकारिणी ने तब तक सी.आई.ओ. से सम्बद्ध हुई १० यूनियनों को मुअत्तिल कर दिया। किन्तु लेविस ने अनुशासन के आगे सिर झुकाने के बजाय यह कहा कि कार्यकारिणी ने अनधिकृत काम किया है। ग्रीन के अभियोगों के उत्तर में उसने एक बार कहा: "मैं उसकी धमकियों से उतना ही डरता हूँ जितना उसके वायदों में मेरा विश्वास है।" जब १९३६ में टम्पा (फ्लोरिडा, में ए. एफ. एल. का सम्मेलन हुआ तो सी. आई. ओ. यूनियनों के प्रतिनिधि गैर-हाजिर रहे। इसके बदले में ए. एफ. एल. ने भारी किन्तु बेकार बहुमत से यह निर्णय किया कि ये ... तब तक मुअत्तिल रहें "जब तक मनमुटाव दूर न हो जाए और कार्य-

कारिणी के मत के अनुसार उचित शर्तों पर उसमें हेरफेर न कर लिया जाए।"

सी. आई. ओ. अपने संगठन कार्यक्रम पर आगे बढ़ता रहा। इस्पात, मोटर, काँच, रबड़ तथा रेडियो उद्योगों की नई यूनियनें मूल सदस्यों में शामिल हो गईं। इससे और ज्यादा भयभीत होकर ए. एफ. एल. ने पुनः इस आन्दोलन की यह कह कर निन्दा की कि यह मज़दूर संघ के समस्त आकार को ही नष्ट किए दे रहा है और इसके नेताओं पर यूनियन सम्बन्धी ध्येय के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया। मार्च, १९३७ में इस्पात तथा मोटर उद्योग दोनों में संगठन स्थापित करने के आन्दोलन से उत्पन्न राष्ट्रीय रोमांच के बीच कार्यकारी परिषद ने समस्त सी. आई. ओ. यूनियनों को ए. एफ. एल. के राज्य तथा नगर-संघों से निकाले जाने का आदेश देने का निर्णयात्मक कदम उठाया।

१९३७ की समाप्ति के दिनों में पुनः दोनों कैम्पों के नरम नेताओं के प्रभाव में शाँति का कोई आधार ढूँढ़ने के लिए विलम्बित प्रयत्न किए गए। किन्तु उनकी विफलता निश्चित थी। ए. एफ. एल. ने प्रस्ताव किया कि मूल सी आई. ओ. यूनियनें ए. एफ. एल. में लौट आएँ और इसकी नई यूनियनें ए. एफ. एल. की यूनियनों में मिल जाएँ। सी. आई. ओ. ने माँग की कि उसकी समस्त यूनियनों को जिनकी संख्या अब तक ३२ हो गई थी मतदान के पूर्ण अधिकार के साथ शामिल किया जाए। प्रत्येक संगठन किसी भी प्रस्तावित विलय में प्रभुत्व पाने की चेष्टा कर रहा था और दोनों संगठनों में से किसी के भी नेता ऐसी कोई रियायत देने को तैयार नहीं थे जिससे वे मिल कर काम कर पाते। औद्योगिक यूनियन बनाम शिल्प यूनियन अगर कभी इनमें विवाद का विषय था भी तो अब नहीं रहा था। अब तो सत्ता के लिए होड़ लग रही थी। मजदूरों का कल्याण ज़िद्दी स्वार्थी महत्त्वाकाँक्षा की पूर्ति के लिए आयोजित प्रतिद्वन्द्विताओं पर बलि चढ़ा दिया गया।

अनेक प्रेक्षकों की राय में यही वह समय था जब लेविस ने सीमा से आगे बढ़ कर 'खेल' खेला, वरना शायद वह संयुक्त मज़दूर आन्दोलन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता था। क्योंकि सी. आई. ओ. के सदस्य ए. एफ. एल. से ज्यादा हो गए थे। १९३७ की समाप्ति के समय इसके ३७ लाख सदस्य थे

जबकि ए. एफ. एल. के ३४ लाख थे और विलय की कुछ भी शर्तें होतीं पुनर्गठित ए. एफ. एल. पर औद्योगिक यूनियनों का हावी होना लाज़िमी था। किन्तु सी. आई. ओ. की बढ़ती हुई ताकत से लेविस यह समझ बैठा कि वह जिम्मेदारी ओढ़े बिना इससे भी ज्यादा बड़ी विजयें प्राप्त कर सकता है और जिद्दीपन से अपने ही मार्ग पर चलता रहा। मज़दूरों की एकता को फिर से कायम करने के लिए ऐसा स्वर्णावसर फिर कभी नहीं आया।

१९३७ के पतझड़ में इन शांतिवार्ताओं की विफलता के बाद ए. एफ. एल. ने लेडीज़ गारमेण्ट वर्कर्स को छोड़ कर जो शीघ्र ए. एफ. एल. में लौट आई, सी. आई. ओ. की बाकी सब सदस्य यूनियनों को निकालने के कार्यकारी परिषद् के निर्णय पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। तब मई, १९३८ में लेविस और उसके लेफ्टिनेण्टों ने पहले जो सिर्फ एक संगठन समिति थी उसे औद्योगिक संगठनों की एक स्थायी कांग्रेस बना देने के लिए अंतिम कदम उठाया। समझौते के लिए अब तक के कदम सिर्फ औपचारिकताएं ही थीं। मज़दूरों के घर में फूट पहले ही पूर्णता को पहुँच चुकी थी।

सी. आई. ओ. औद्योगिक यूनियनवाद का विकास करता रहा और अदक्ष मज़दूरों के विशाल समुदाय के हितों की रक्षा करता रहा किन्तु वस्तुतः ए. एफ. एल. से यह बहुत भिन्न नहीं था। इस पर जो आक्षेप किये जा रहे थे और कम्यूनिज्म को प्रोत्साहन देने का जो आरोप लगाया जा रहा था, उसके बावजूद बुनियादी सिद्धान्तों के मामले में यह अपने पितृ-संगठन से कम रूढ़िवादी नहीं था। शिल्प यूनियनवाद के पहले के विरोधियों—नाइट्स आव लेबर, सोशलिस्ट ट्रेड ऐण्ड लेबर अलाएंस और आई. डब्लू. डब्लू. से विपरीत सी. आई. ओ. लोकतंत्रीय पूंजीवाद के विद्यमान ढांचे के अन्दर पूर्णतः सामूहिक सौदेबाजी के जरिये मज़दूरों का हित-साधन करने के लिए वचन-बद्ध था। यह राजनीतिक कार्रवाई पर ए. एफ. एल. से अब तक की अपेक्षा ज्यादा जोर देने को तैयार था किन्तु मजदूर सम्बन्धों के नियमन में सरकार जो रोल अदा कर रही थी यह उसी का स्वाभाविक परिणाम था हमारी राजनीतिक पद्धति में परिवर्तन करने के लिए कोई क्रांतिकारी माँग नहीं की गई।

सी. आई. ओ. की रचना भी ए. एफ. एल. से बहुत भिन्न नहीं थी; सिर्फ यही भिन्नता थी कि इसमें विशेष विभाग नहीं थे। ए. एफ. एल. ने बहुत

पहले ही बिल्डिंग ऐण्ड कन्स्ट्रक्शन ट्रेड्स डिपार्टमेण्ट, मैटल ट्रेड्स डिपार्टमेण्ट रेलवे एम्पलायीज डिपार्टमेण्ट तथा यूनियन लेबल ट्रेड्स डिपार्टमेण्ट कायम करने की आवश्यकता महसूस कर ली थी, किन्तु सी. आई. ओ. की बड़ी यूनियनें चूँकि औद्योगिक थीं इसलिए उसे इस प्रकार के विभाजनों की जरूरत नहीं थी। किन्तु इसने ए. एफ. एल. के राज्य मजदूर संघों और नगर केन्द्र-संगठनों के अनुरूप इसने राज्य तथा नगर औद्योगिक यूनियन परिषदें कायम कीं। सदस्य यूनियनों के साथ व्यवहार करते हुए सी. आई. ओ. का अधिकार ए. एफ. एल. की अपेक्षा व्यवहार में अधिक व्यापक पाया गया और स्थानीय यूनियन मामलों में इसकी कार्यकारी परिषद् ने ज्यादा बार हस्तक्षेप किया।

सामान्यत: कहा जाए तो सी. आई. ओ. यूरोपीय मजदूरों की कक्षागत परम्पराओं के बजाए अमरीकी मजदूर की संस्थापित परम्पराओं के ज्यादा अनुरूप था। मजदूर आन्दोलन पर इसके स्तब्धकारी प्रभाव का मुख्य कारण यह था कि यह अदक्ष मजदूरों की आवश्यकताओं के प्रति ए. एफ. एल. से ज्यादा सजग था और उनकी पूर्ति के लिए ज्यादा सक्रिय तथा आक्रामक साधनों से काम लेता था।

औद्योगिक यूनियनवाद के लिए सी. आई. ओ. के जोरदार अभियान का, जो १९३५ में ए. एफ. एल. की विलम्बकारी चालों के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया गया था, तत्काल राष्ट्रव्यापी असर हुआ। सामूहिक उत्पादन के उद्योगों में मजदूरों की विशाल संख्या इसी की प्रतीक्षा कर रही थी और उन यूनियनों में जो उनकी आवश्यकताएँ पूरी करती थीं और संघीय यूनियनों के भेद-भावकारी नियंत्रणों से मुक्त करती थी उनके झुण्ड के झुण्ड शामिल हो जाते थे। सी. आई. ओ. के नए हैडक्वार्टर से जब संगठनकर्ता खनिकों, दर्जियों व अन्य कर्मचारियों की सहानुभूति रखने वाली यूनियनों के चन्दों से संस्थापित कोष का आश्रय लेकर संगठन करने के लिये निकल पड़े तो उनका उत्साह से स्वागत किया गया। लेविस, मरे, हिलमैन और डुबिन्स्की के स्फूर्तिमय चतुर नेतृत्व में दिन-दूनी रात चौगुनी प्रगति होने लगी।

राष्ट्र के इस्पात मजदूरों में सी. आई. ओ. का मुख्य अभियान जून, १९३६ में इस्पात कर्मचारियों की संगठन समिति (स्टील वर्कर्स आर्गनाइज़िंग कमेटी) की स्थापना से प्रारम्भ हुआ। मरे के निर्देशन में इसने जब समाप्तप्राय

ऐमलगमेटेड ऐसोसियेशन आव आयरन, स्टील ऐण्ड टिन वर्कर्स को अपने हाथ में लिया, पिट्सबर्ग, शिकागो और बरमिंघम में जिला-कार्यालय स्थापित किए और शीघ्र ही उसके ४०० संगठनकर्ता मैदान में आ गए जो पेंसिलवेनिया, ओहायो, इलिनॉयस और अलाबामा के इस्पात नगरों में यूनियन का साहित्य वितरित करते थे, जन सभाएँ आयोजित करते और घर-घर जाकर मज़दूरों को यूनियन में शामिल होने के लिये राजी करते थे। अन्य उद्योगों में १५०० डालर वार्षिक के न्यूनतम वेतन के मुकाबले इसमें वेतन औसतन ५६० डालर जितना कम होने के कारण उन्हें अपने प्रचार के लिए उपजाऊ भूमि मिल गई। इस्पात उद्योग जिसका यूनियन-विरोधी दुराग्रह होमस्टेड से लेकर १९१९ की विशाल इस्पात हड़ताल तक चला आया था, इस नई चुनौती के महत्त्व को पूरी तरह समझता हुआ इसका सामना करने को तैयार था। देश भर के समाचार पत्रों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन निकलवा कर आयरन ऐण्ड स्टील इंस्टिट्यूट ने कहा कि कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की कम्पनी की अपनी योजनाएँ मज़दूरों की आवश्यकता को पूर्णतः पूरी कर देती हैं और सी. आई. ओ. उन्हें अपनी यूनियन में मिलाने के लिए जोर-जबर्दस्ती कर रहा है, तथा क्रांतिकारी और कम्यूनिस्ट प्रभाव पुनः सक्रिय हो रहे हैं।

लेविस ने राष्ट्रव्यापी रेडियो-प्रणाली पर इस्पात उद्योग के इस प्रचार-युद्ध का जवाब दिया और न केवल इस्पात उद्योग को बल्कि समस्त उद्योगों को यह चेतावनी दी कि औद्योगिक श्रमिकों की यूनियन बनाने के सी. आई. ओ. के आन्दोलन को कोई नहीं रोक सकता।

दिग्दिगन्त में उसने चिल्ला कर कहा : "कोई भी, चाहे वह आर्थिक 'जार' हो या गन्दा भाड़े का टट्टू, मानवीय भावनाओं के इस शक्तिशाली उभार के, जो अब औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना और इसके प्राप्य फलों में हिस्सा बँटाने के लिए आतुर ३ करोड़ मज़दूरों के हृदयों में घनीभूत हो रहा है, विरुद्ध अपनी ताकत को आज़मा ले। वह पागल या मूर्ख है जो यह समझता है कि मानवीय भावनाओं की इस नदी को रुकावटों की मनमानी बाधाएँ खड़ी करके बाँधा जा सकता है या रोका जा सकता है।"

कुछ ही महीनों के अन्दर जिस उद्योग ने यूनियनवाद को इतनी बार पछाड़ा था, स्वयं को अब रक्षात्मक पेंतरे पर पाया। हज़ारों मज़दूर स्टील

वर्कर्स आर्गनाइजिंग कमेटी (इस्पात मज़दूर संगठन समिति) में शामिल होने के लिये एकत्र होने लगे। बहुत से मामलों में भूतपूर्व कम्पनी यूनियनें रातों-रात नई यूनियन की स्थानीय शाखाओं में बदल गईं और जब प्रबन्धकों ने महँगाई के मुताबिक वेतन वृद्धि का वचन देकर उन पर अपना नियंत्रण रखने की कोशिश की तो उनके सदस्यों ने इन समझौतों को स्वीकार करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। १९३६ की समाप्ति तक एस. डब्लू. ओ. सी. १ लाख से अधिक सदस्यों की कोई १५० यूनियन इकाइयाँ स्थापित करने पर गर्व कर सकती थी। यह मान्यता तथा सामूहिक सौदेबाजी की माँग करने के लिये पर्याप्त शक्तिशाली हो गई थी, और यदि इस्पात उद्योग मज़दूरों की माँगों पर ध्यान देने से इन्कार कर दे तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल करा सकती थी।

किन्तु अभी जब हड़ताल के लिए तैयारियाँ जारी ही थीं तब १ मार्च, १९३७ को एक अप्रत्याशित और नाटकीय घोषणा की गई। लेविस तथा यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन के निदेशक मण्डल के चेयरमैन माइरोन सी. टेलर के बीच कुछ समय से जो गुप्त वार्ता हो रही थी उसके फलस्वरूप एक समझौता हो गया था जिसमें "बिग स्टील" ने एस. डब्लू. ओ. सी. को अपने सदस्यों के लिए सौदे-बाज़ी का एजेण्ट स्वीकार किया, १० प्रतिशत वेतन-वृद्धि प्रदान की तथा ८ घण्टे का दिन और ४४ घण्टे का सप्ताह स्वीकार किया। कम्पनी ने टैकनिकल दृष्टि से यद्यपि अब भी 'ओपन-शाप' नीति कायम रखी तो भी यह यूनियनवाद की एक महान् विजय थी और ऐसी विजय जिसका दृष्टांत संगठन मज़दूर आन्दोलन के समस्त इतिहास में नहीं मिलता था। सी. आई. ओ. के हमले में एक किला फतह हो गया था और यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन द्वारा घुटने टेक दिया जाना सामान्यतः सामूहिक उत्पादन के सभी उद्योगों में नए मजदूर सम्बन्धों के प्रतीक के रूप में प्रकट हुआ।

खयाल किया जाता था कि "बिग स्टील" ने बैंक मालिकों के दबाव में आकर घुटने टेक दिए, जिन्होंने वागनर ऐक्ट के पास हो जाने के बाद से ही अब साफ-साफ यह देख लिया था कि दीवार पर क्या लिखा है? कम्पनी के अधिकांश कर्मचारी (किन्तु वस्तुतः इसके मुख्य अंग कारनेगी इलिनोयस स्टील कम्पनी के अधिकांश कर्मचारी) जब एस. डब्लू. ओ. सी. के झण्डे तले जमा हो गए थे तब उन्होंने भाँप लिया था कि मज़दूर हड़ताल कर देंगे और वह भी

ऐसे समय जबकि कम्पनी अपनी पुरानी उत्पादन-गति पर फिर से अभी आई ही थी और नए आर्डर कम्पनी की किताबों में जमा हो रहे थे । जिस कार्पोरेशन ने कभी यूनियन मज़दूर के खिलाफ अपनी अमिट विरोध की घोषणा की थी उसे शांति से उस सम्मान को स्वीकार करने के लिये मना लिया गया जिसका अब सफलता से मुकाबला नहीं किया जा सकता था। प्रबुद्ध आत्म-कल्याण की भावना ने कठोर विद्वेष पर विजय पाई।

१०० से अधिक स्वतन्त्र कम्पनियों ने यूनाइटेड स्टेट्स स्टील के नेतृत्व का अनुकरण किया । मई तक एस. डब्लू. ओ. सी. के ३ लाख से अधिक सदस्य हो गए किन्तु अब भी कुछ महत्त्वपूर्ण किले फतह करने बाकी रह गए थे। 'लिट्ल स्टील' कही जाने वाली कम्पनियों—रिपब्लिक, यंग्सटाउन शीट ऐण्ड ट्यूब, इनलैण्ड स्टील एण्ड बेथलहेम ने एस. डब्लू. ओ. सी. से समझौता करने से इन्कार कर दिया और यूनियन के इससे ज्यादा दबाव का सामना करने के लिये अपनी शक्तियाँ जुटानी शुरू कर दीं। इसके कठोर, प्रतिक्रियावादी, भयानक रूप से यूनियन विरोधी अध्यक्ष टाम. एम. गर्डलर के नेतृत्व में मोर्चेबन्दी की रेखाएँ खींच ली गईं।

एस. डब्लू. ओ. सी. की तरफ से इसका जवाब था—हड़ताल का आह्वान और मई तक 'लिट्ल स्टील' के कोई ७५००० मज़दूर अपनी यूनियन को मान्यता दिलाने के लिये एक साथ काम छोड़कर बाहर आ गए। कम्पनियों ने डटकर मोर्चा लिया और इस्पात नगरों पर उनके सख्त नियंत्रण के कारण वह सफल भी रहा। आंतक तथा हिंसामय जोर-जबर्दस्ती के अभियान को मजबूत करने के लिए नागरिकों की समितियाँ बनाई गईं; स्थानीय पुलिस तथा स्पेशल डिपुटियों के सहयोग से 'काम पर वापस जाओ' आन्दोलन संगठित किये गए और धरना देने वालों पर किये गए हमलों से यूनियन के मुख्य कार्यालयों पर आँसू गैस छोड़ने, हड़तालियों के नेताओं की गिरफ्तारी से और हड़ताल-भंजकों की रक्षा के लिये मिलीशिया के उपयोग से शनैः-शनैः मज़दूरों की हिम्मत टूट गई।

बीस के करीब इस्पात नगरों में हिंसा भड़क उठी और रिपब्लिक स्टील कम्पनी के दक्षिण शिकागो नर्कशाप में खूनी संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। ३० मई को ३०० व्यक्तियों की धरना-पंक्ति को पुलिस ने रोक

लिया, कुछ ईंट-पत्थर फेंके गए और पुलिस ने गोली चला दी। निहत्थे मज़दूर लाइन छोड़-छोड़ कर गोलियों की बौछारों से बचने के लिये भाग पड़े किन्तु उनमें से १० सड़क पर मरे पाये गये और १०० से अधिक ज़ख्मी हुए। उपद्रव में करीब २० सिपाही भी ज़ख्मी हुए, किन्तु कोई ऐसा नहीं था, जिसे सख्त ज़ख्मी कहा जा सके।

"स्मृति दिवस के हत्याकाण्ड ने", जैसा कि यूनियन मज़दूरों ने इसे एक वार कहा था, हड़तालियों के पक्ष में लोगों की व्यापक सहानुभूति उत्पन्न कर दी। बाद की तहकीकात ने, जिसमें घटना की ली गई फिल्मों का सावधानी से अध्ययन भी शामिल था, स्पष्ट ज़ाहिर कर दिया कि हमले के लिए मज़दूरों ने कोई उत्तेजना प्रदान नहीं की किन्तु स्वयं इस्पात-नगरों में लोगों की भावना अब भी घोर यूनियन विरोधी थी और उनके समर्थन से इस्पात कम्पनियों की स्थिति इतनी मज़बूत हो गई थी कि मज़दूर टिक नहीं पाए। प्रचार, ताकत और आतंक ने हड़ताल तोड़ दी और सी. आई. ओ. को पहली हार का सामना करना पड़ा।

किन्तु 'लिटल स्टील' के लिए भी यह विजय अन्ततः कड़वी ही साबित हुई। ४ वर्ष बाद नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड ने सम्बन्धित कम्पनियों को तत्कालीन यूनाइटेड स्टील वर्कर्स आव अमेरिका को मान्यता देने का, हड़ताल में भाग लेने अथवा यूनियन की सदस्यता के कारण काम से हटाए गए सब कर्मचारियों को वापस काम पर लेने का और सामूहिक सौदेबाज़ी को स्वीकार करने का हुक्म दिया गया। मज़दूरों के दबाव का अन्तिम क्षण तक दृढ़ता से मुकाबला करने वाली 'लिटल स्टील' को अन्ततोगत्वा सरकार के हस्तक्षेप के आगे झुकना पड़ा। तब—१९४१—तक सी. आई. ओ. ६ लाख इस्पात-कर्मचारियों को संगठित करने में कामयाब हुई और करीब-करीब समस्त उद्योग में यूनियन-करार सम्पन्न किए गए।

इस बीच मोटर उद्योग में इससे भी नाटकीय और हिंसामय क्रांति हो गई थी। एन. आर. ए. के सूत्रपात और १९३४ की अविवेकपूर्ण हड़तालों की विफलता के बाद से इसके कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष था। प्रति घण्टा वेतन-दर ऊँची होने के बावजूद समय-समय पर काम से हटा दिए जाने के कारण औसत

वेतन १००० डालर से भी कम बैठता था जबकि एक और शिकायत असेम्बल करने वाले कर्मचारियों से जल्दी काम कराने की थी। उस कर्मचारी के लिए, जिसे सामने से गुजरते चेसिस पर एक पहिया ही लगाना होता था, एक फेण्डर जड़ना होता था या सिर्फ तक बोल्ट ही कसना होता था, भारी दबाव में काम करने का खिंचाव कभी-कभी असह्य हो उठता था। किन्तु सम्मिलित विरोध से इन परिस्थितियों में सुधार कराने के हर प्रयत्नों को प्रबन्धकों ने दबा दिया। मोटर उद्योग ने अपनी जासूस-प्रणाली इतनी व्यापक बना रखी थी कि यूनियन की हल-चल प्रारम्भ होने से पूर्व ही अवरुद्ध नज़र आती थी।

तो भी यूनियनों के निर्माण का काम रुका नहीं। मूलतः ए. एफ. एल. द्वारा स्थापित संघीय यूनियनों का विलय करके यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स की स्थापना की गई, और इसके संगठनकर्ता बहुत सक्रिय थे। काम अब भी धीरे चल रहा था। फेडरेशन के विलय-समर्थन से अधिक असन्तुष्ट होकर नई यूनियन १९३६ में ए. एफ. एल. से अलग होकर सी. आई. ओ. में मिल गई। होमर एस. मार्टिन इसका अध्यक्ष चुना गया और नए जोश के साथ संगठन अभियान फिर प्रारम्भ किया गया जिसके फलस्वरूप अन्ततोगत्वा देश की सबसे बड़ी यूनियन यूनाइटेड ऑटोमोबाइल, एयर क्राफ्ट ऐग्रिकल्चरल इम्प्लिमेण्ट वर्कर्स का निर्माण हुआ।

मार्टिन नौजवान और आदर्शवादी था, कार्यकर्ता या यूनियन सदस्य के रूप में उसे कोई अनुभव नहीं था। मिसूरी में एक छोटे से कालेज से स्नातक होने के बाद वह बैप्टिस्ट गिरजे में दाखिल हुआ और १९३२ में कन्सास सिटी के एक उपनगरीय छोटे गिरजाघर में पादरी बन गया। मज़दूर के प्रति उसकी प्रकट सहानुभूति के कारण उसे शीघ्र अपने काम से हटना पड़ा। तब उसने शेवरोलेट फैक्ट्री में काम कर लिया और वहाँ धर्म-प्रचारक के से उत्साह के साथ यूनियनवाद का प्रचार करने लगा। वहाँ से उपद्रवकारी घोषित करके काम से निकाल दिए जाने के बाद उसने अपना सारा समय यूनियन के कार्य में लगाया और संघर्षरत यू. ए. डब्लू. का उपाध्यक्ष बन गया। सहृदय, शांत और ऐनक लगाने वाले मार्टिन ने, जिसे शक्ल-सूरत और तौर-तरीकों में वाई. एम. सी. ए. का सचिव जैसा बताया जाता था, अध्यक्ष चुने जाने के बाद [illegible]न का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और उसमें नई भावना भरी।

अपनी अनुभव की कमी को वह अपने जोश से पूरा कर देता था। उसकी प्रेरणास्पद अपीलों से, जो यूनियन की सभाओं को बहुत कुछ पुराने ढंग की धार्मिक पुनर्जागरण सभाओं में बदल देती थीं, प्रभावित होकर मोटर कर्मचारी अधिकाधिक संख्या में यूनियन में शामिल हुए।

सन् १९३६ की ग्रीष्म ऋतु में इक्की-दुक्की हड़तालें हुई और पतझड़ के आखिरी समय तक कोई ३०००० की ताकत वाली यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स उद्योग दिग्गजों—जनरल मोटर्स, क्रिसलर और फोर्ड—से मान्यता की मांग मन्जूर कराने के लिये लोहा लेने को तैयार थी। "हम खदेड़े जाना नहीं चाहते, "हम नहीं चाहते कि हम पर कोई जासूसी करे" यह मज़दूरों की नई रट थी। किन्तु कम्पनियाँ वागनर ऐक्ट को चुनौती देती हुई अभी कोई रियायत देने को तैयार नहीं थीं। जब मार्टिन ने सामूहिक सौदेबाज़ी पर जनरल मोटर्स के अधिकारियों से सम्मेलन करने के लिये कहा तो उपाध्यक्ष विलियम एस. कुण्डसेन ने सिर्फ यह कहा कि अगर मज़दूरों को कुछ शिकायतें हैं तो उन्हें वे स्थानीय कारखाना प्रबन्धकों से निबटा लेनी चाहिएँ। यूनियन ने इसका जवाब हड़ताल से दिया जो जनवरी, १९३७ में फ्लिण्ट (मिशीगन) में कम्पनी के फिशर बाडी प्लाण्ट में प्रारम्भ हुई और तब धीरे-धीरे डेट्रायट, क्लीवलैण्ड, टोलेडो और देश के अन्य स्थानों पर फैल गई। १,५०,००० कर्मचारियों में से १,१२,००० के हड़ताल में भाग लेने से जनरल मोटर्स में उत्पादन ठप्प हो गया।

यह हड़ताल संसार में अपने निराले ढंग की थी। फ्लिण्ट में इसने 'बैठे रहो' का रूप ले लिया। इस क्रांतिकारी तरीके का पहले भी उपयोग किया गया था, विशेषकर ऐकरोन के रबड़ कर्मचारियों में किन्तु इसका व्यापक रूप में इस्तेमाल वस्तुतः पहलेपहल जनरल मोटर्स में ही किया गया। मोटर कर्मचारियों ने कारख़ाना ख़ाली करने से इन्कार कर दिया। वे अपनी काम करने की बेंचों पर बैठे रहे। यह कोई हिंसात्मक कार्य नहीं था, बल्कि शांत प्रतिरोध था जो इस कारण दुगना प्रभावशाली था कि इस प्रकार की हड़ताल को, कर्मचारियों को कारखाने से जबर्दस्ती निकाल कर ही तोड़ा जा सकता था।

फ्लिण्ट और पास के डेट्रायट में बहुत उत्तेजना फैली जनरल मोटर्स के प्रबन्धकों तथा कम्पनी द्वारा प्रवर्तित कथित वफ़ादार कर्मचारियों के गैंग-

सियेशन ने बैठे रहो हड़ताल को सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकारों पर गैरकानूनी हमला बताकर हड़तालियों को तुरन्त निकाल बाहर करने की माँग की। मार्टिन ने इसके जवाब में आरोप लगाया कि जनरल मोटर्स मजदूरों के सम्पत्ति अधिकारों पर हमला करना चाहता है।

उसने माँग की : "आज संसार में आदमी के काम करने के अधिकार से ज्यादा पवित्र और कौन सा सम्पत्ति का अधिकार है। इस सम्पत्ति-अधिकार में अपने बच्चों व परिवार का भरण-पोषण, भूख को दरवाजे से दूर रखना शामिल है। यह अमरीकी गृहस्थ की आधारशिला है, अमरीका में सबसे पवित्र, सबसे बुनियादी सम्पत्ति सबन्धी अधिकार है।"

सी. आई. ओ. ने पहले हड़ताल को आशंका की दृष्टि से देखा और 'बैठ-रहो' के प्रति उसमें उत्साह नहीं था। इस्पात उद्योग के संगठन कार्य में जिसकी सफलता को औद्योगिक यूनियनवाद के समस्त कार्यक्रम के लिए बुनियादी चीज़ समझा जाता था, अत्यन्त व्यस्त रहने के कारण मोटर उद्योग में हड़ताल उसके लिए बड़ी परेशानी पैदा करने वाली थी। किन्तु समर्थन से इन्कार नहीं किया जा सकता था और सी. आई. ओ. ने जनरल मोटर्स के कर्मचारियों की मदद के लिए यथासंभव सब कुछ किया। लेविस ने कहा, "आप लोग निस्संदेह ऐसा वीरतापूर्ण संघर्ष कर रहे हैं जैसा किसी औद्योगिक विवाद में हड़तालियों ने पहले कभी नहीं किया। अमरीका की सारी जनता का ध्यान आप पर केन्द्रित है। .. ..."

उसके इस वक्तव्य का अन्तिम अंश निस्सन्देह सच था और तब और भी ज्यादा सच हो गया जब फ्लिण्ट में हिंसा फूट पड़ी और हड़तालियों ने 'अधिकृत' कारखानों से टस से मस न होने का दृढ़-संकल्प दिखाया। यद्यपि कड़ाके की सर्दी में कारखाने को गरम रखने की व्यवस्था काट दिए जाने का भी कोई असर नहीं हुआ। जब पुलिस ने फिशर बाडी प्लाण्ट नं० २ में घुसने की कोशिश की तो उस पर मजदूरों ने जो कुछ हाथ में आया वही फेंककर मारा जैसे काफी के प्याले, शराब की बोतलें, लोहे की ढिबरियाँ, मोटरों के भारी दरवाज़ों के कब्जे आदि। जब पुलिस ने लौटकर आँसू गैस के बमों से हमला किया तो हड़तालियों ने कारखाने के पानी के पाइप से उन पर पानी की तेज़ [illegible]र डालकर बदला लिया। अन्त में पुलिस को जल्दबाज़ी में उस संघर्ष

से पीछे हटना पड़ा जिसे प्रसन्न मज़दूरों ने "दौड़ते साँड़ों की लड़ाई" का नाम दिया।

हड़ताल को जारी रहते हफ्ते पर हफ्ता बीतता चला गया और जनरल मोटर्स के कर्मचारी 'बैठे-रहो' हड़ताल पर दृढ़ रहे। उनके लिए रसद धरना-पंक्तियों के जरिये पहुँचाई जा रही थी। अनुशासन बहुत कड़ा था। उस समय के एक यूनियन संगठनकर्ता ने इस घटना का विवरण इस प्रकार लिखा: "अत्यन्त तेज़ प्रकाश से दीप्तिमान इस विशाल कारखाने में हड़तालभंजकों तथा अन्य अनधिकृत प्रवेशकों को घुसने से रोकने तथा इमारत व उसके अन्दर की चीज़ों की रक्षा के लिए अन्दर व बाहर दोनों तरफ से रक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। इन हड़तालियों ने कम्पनी के साँचों की विशेष रूप से रक्षा की। कारखाने के अहाते में किसी को शराब लाने की अनुमति नहीं दी गई, कारखाने के अन्दर धूम्रपान की सख्त मनाही थी। कारखाने के अन्दर ४५ व्यक्तियों को पुलिस की तरह चौकसी करने का काम सौंपा गया था, उनकी जबान ही कानून था।"

अब कम्पनी तथा फ्लिण्ट अलाएंस दोनों ने यह माँग की कि पुलिस के असफल रहने पर हड़तालियों को कारखाने से बाहर निकालने के लिए राज्य की मिलीशिया बुलाई जाए। किन्तु मिशीगन के गवर्नर मर्फी ने, जिसे हड़ताली ऑटोमोबाइल कर्मचारियों से सहानुभूति थी और निश्चित रूप से होने वाले रक्तपात का डर था, यह कदम उठाने से इन्कार कर दिया। किन्तु अन्त में जनरल मोटर्स ने अदालत से आदेश प्राप्त किया जिसमें हड़ताली मजदूरों को हुक्म दिया गया था कि वे ३ फरवरी को तीसरे पहर तीन बजे तक कारखाना ख़ाली कर दें वरना उन्हें कैद और जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ेगी। किन्तु हड़ताली अब भी अविचलित रहे। उन्होंने गवर्नर को तार दिया: "हम मज़दूरों को 'बैठे-रहो' हड़ताल करते हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है, जिस बीच जनरल मोटर्स कार्पोरेशन को कानून का पालन कर सामूहिक सौदेबाज़ी में भाग लेना चाहिए था। चूँकि हम निहत्थे हैं इसलिए हथियार बन्द मिलीशिया, शेरिफ या पुलिस को लाने का मतलब निहत्थे लोगों का ख़ून करना होगा... हमने कारखाने में बैठे रहने का ही निश्चय किया है।"

यह समझते हुए कि हड़तालियों के इस वक्तव्य का क्या अभिप्राय है,

मर्फी ने हवड़-दवड़ में एक शांति सम्मेलन बुलाया। जॉन एल. लेविस डेट्रायट भागा गया और उपाध्यक्ष कुण्डसेन से वार्ता शुरू कर दी जिसे गवर्नर मर्फी ने लेविस से बातचीत करने को मना लिया था। किन्तु ३ फरवरी का प्रातःकाल बिना कोई समझौता हुए ही आ गया। कारखानों में बैठे रहो हड़ताल करने वालों की सुरक्षा के लिए वाड़े लगा दिये गए थे, वे लोहे की ढिवरियों और दरवाज़ों के कब्जों से लैस थे और हलकी कपड़े की नकाब देकर प्रत्याशित आँसू तथा उलटी की गैस से सुरक्षित कर दिये गए थे। घिरे हुए संयंत्रों से बाहर सहानुभूति रखने वाले हजारों मज़दूरों और महिलाओं की आपातकालीन ब्रिगेड के सदस्य परस्पर भिड़ रहे थे, जबकि ट्रकों पर लगाये गए लाउडस्पीकरों से "एकता हमेशा के लिए" का नारा बुलन्द किया जा रहा था।

नियत समय आया और गुज़र गया। गवर्नर मर्फी ने राष्ट्रीय रक्षक दल को अदालत के आदेश पर अमल करने का हुक्म देने से इन्कार कर दिया। बढ़ते हुए दबाव के बावजूद वह ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे न जाने कितने बड़े पैमाने पर हिंसा फूट पड़ती।

अगले दिन गवर्नर मर्फी के साथ राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने भी बातचीत जारी रखने की प्रार्थना की और लेविस कुण्डसेन-वार्ता फिर प्रारम्भ हो गई जिसमें जनरल मोटर्स तथा हड़तालियों दोनों के अन्य प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। पूरे एक सप्ताह तक जब तक कि हड़ताली अपने किले के अन्दर दृढ़ता से डटे रहे, सम्मेलन चलता रहा और अन्त में श्रान्त और क्लान्त गवर्नर यह घोषणा कर सका कि समझौता हो गया है। जनरल मोटर्स ने यूनाइटेड ऑटोमोवाइल वर्कर्स को अपने सदस्यों के लिए सामूहिक सौदे-बाज़ी के एजेण्ट स्वीकार करना, हड़तालियों के खिलाफ निरोधादेश की कार्रवाई को रद्द करना, यूनियन सदस्यों से साथ किसी किस्म का कोई भेदभाव न करना और काम जल्दी कराये जाने तथा अन्य प्रकार की शिकायतों पर विचार करना मंजूर कर लिया।

यह यूनियन की पूरी विजय नहीं थी। यू. ए. डब्लू. ने जनरल मोटर्स के सभी कर्मचारियों के लिये एकमात्र सौदेबाज़ी के अधिकार की, एक-से न्यूनतम वेतन तथा ३० घण्टे के सप्ताह की माँग की थी। किन्तु "बिग स्टील" के साथ एस. डब्लू. ओ. सी. के समझौते की तरह एक और यूनियन विरोधी किले पर कर लिया गया था। समस्त मोटर उद्योग के पूर्ण यूनियनीकरण की

तरफ संगठित मज़दूरों ने पहला कदम उठा लिया था। बैठे-रहो हड़ताल की वैधानिकता या नैतिकता के बारे में कुछ भी कहा जाए, इसके परिणाम इसकी प्रभावशालिता के साक्षी थे।

जनरल मोटर्स में मोटर कर्मचारियों की सफलता से देश के सब हिस्सों में यूनियनों द्वारा बैठे-रहो हड़ताल करने का रिवाज फैल गया। क्रिसलर कार्पोरेशन के कर्मचारियों ने शीघ्र ही इसका अनुगमन किया और जनरल मोटर्स में ४४ दिन की बैठे-रहो हड़ताल के मुकाबले में यहाँ कुछ ही दिनों की बैठे-रहो हड़ताल में वे यूनियन को मान्यता दिलाने तथा जनरल मोटर्स के जैसी ही सामूहिक सौदे-बाज़ी का समझौता प्राप्त करने में सफल हुए। मोटर कम्पनियों में वस्तुतः सिर्फ फोर्ड ही और चार वर्ष तक यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स के संगठन करने के प्रयत्नों का सफलतापूर्वक मुकाबला करती रह सकी।

मज़दूरों के इस नए हथियार का प्रभाव अन्य उद्योगों पर भी पड़ा। सितम्बर, १९३६ और जून १९३७ के बीच लगभग ५ लाख मज़दूरों ने बैठे-रहो हड़तालें कीं। रबड़, कांच व कपड़ा कर्मचारी अपनी बैंचों पर बैठे रहे। वूलवर्थ के हड़ताली क्लर्क अपने काउण्टरों के पीछे बैठे रहते और ग्राहकों से कोई पूछताछ नहीं करते थे; पाई (एक प्रकार का पकवान) पकाने वालों, ऐनक बनाने वालों, पोशाक बनाने वालों और बंगलों के चौकीदारों ने बैठे-रहो हड़ताल कर दी। इस तरह की सबसे लम्बी हड़ताल फिलाडेल्फिया में १८०० बिजली कर्मचारियों की थी। इसमें दो नव-विवाहित पुरुषों की सुहागरातों के दिन गुजर गए और ६ अन्य विवाहित कर्मचारियों की पत्नियों ने अपने घर लौटते हुए पतियों का नव-जात शिशुओं से स्वागत किया।

समस्त देश में जब मज़दूरों ने यूनियन-विरोधी मालिकों को 'सीधा' करने के लिये इस उग्र तरीके को अपनाया तो वे विद्रोह का एक गीत बड़े उत्साह से गाते थे :

जब वे किसी यूनियन सदस्य को काम से हटा दें
तब बैठ जाओ! बैठ जाओ!

भले ही वे उसे वर्खास्त कर दें, पर वे उसे वापस लेंगे
बैठ जाओ ! बैठ जाओ !
जब तेजी से काम करने को कहा जाए तो अपने अंगूठे चटका दो
बैठ जाओ ! बैठ जाओ !
जब मालिक बात नहीं करे तो चलो नहीं
बैठ जाओ ! बैठ जाओ !

इन हड़तालों ने लोगों में रोप उत्पन्न कर दिया। सम्पत्ति के अधिकारों पर इतने निधड़क प्राक्रमण की अनुदार-पंथी अखबारों ने जी खोल कर निंदा की और किसी भी क्षेत्र में बैठे-रहो हड़ताल का समर्थन नहीं किया गया। अप्टन सिक्लेयर ने कैलीफोर्निया से भले ही यह लिखा हो कि "७५ वर्षों से बड़े उद्योगपति अमरीकी लोगों पर बैठे हुए थे अब इस प्रक्रिया को उलटते देख कर मुझे खुशी है।" किन्तु मज़दूरों से सहानुभूति रखने वालों में से भी शायद ही किसी ने इस भावना की दाद दी हो। ए. एफ. एल. ने साफ-साफ विरोध किया और यद्यपि सी. आई. ओ. ने इसका समर्थन किया तो भी बैठे रहो हड़ताल के आम प्रयोग के लिए अधिकृत स्वीकृति कभी नहीं दी गई। गरमागरम और कटुतापूर्ण बहस के बाद सेनेट ने निश्चय किया कि ऐसी हड़तालें "गैर-कानूनी और सार्वजनिक नीति" के खिलाफ हैं और अदालतों ने भी उन्हें अन्ततः निजी सम्पत्ति पर अतिक्रमण बतला कर कानून के खिलाफ घोषित कर दिया।

१९३७ के प्रथमार्ध में इस बैठे-रहो हड़ताल ने यद्यपि बड़ी उथल-पुथल मचाई तो भी यह अस्थायी चीज़ साबित हुई और जितनी जल्दी इसे स्वीकार किया गया उतनी ही जल्दी इसे छोड़ भी दिया गया। यूनियनवाद-विरोधी गढ़ों में मान्यता के लिए संघर्ष करने और मालिकों द्वारा वागनर ऐक्ट की व्यवस्थाओं का पालन करने से इन्कार किए जाने से उत्पन्न कटुता के कारण ही नए और अधीर यूनियन सदस्यों ने इस प्रकार की हड़ताल को शीघ्रता से अपनाया था। जब वागनर ऐक्ट पर अमल कराया गया और एन. एल. आर. बी. ने सामूहिक सौदे-बाज़ी की इकाइयों के लिए चुनाव करवाने का अधिकार प्रदान [किया] तो बैठे-रहो हड़तालों का परित्याग कर दिया गया।

किन्तु इससे पूर्व ही १९३७ की हड़तालों ने लोकमत को काफी क्षुब्ध कर दिया था और मज़दूरों को बैठे-रहो के कारण लोक-निंदा सबसे ज्यादा सहनी पड़ी। गैलपपील की रिपोर्टों से जाहिर हुआ कि जिन लोगों से पूछ-ताछ की गई। उनमें से अधिकांश ने मज़दूरों के इस नए हथियार का विरोध किया जब कि ७० प्रतिशत ने यह कहा कि यूनियनों पर अंकुश लगाने के लिए नए कानून बनाने की ज़रूरत है। बैठे-रहो हड़तालें उससे ज्यादा गैर-कानूनी नहीं थीं जितनी उद्योग द्वारा एन. एल. आर. बी. 'के बन्द करो और बाज आओ' आदेशों को मानने से इन्कार कर देना किन्तु इससे जो आशंका और भय उत्पन्न हुआ वह आसानी से शान्त नहीं हुआ।

तथापि समस्त १९३७ में सी. आई. ओ. की गतिविधियों का तात्कालिक प्रभाव था समस्त सम्बद्ध यूनियनों के लिए अत्यधिक लाभों की प्राप्ति। जहाँ इस्पात और मोटर उद्योगों में प्राप्त नाटकीय विजयें सामूहिक उत्पादन के उद्योगों पर आम चढ़ाई के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण फल थे वहाँ अन्य घटनाएं भी घटीं, जिन्होंने मज़दूर-जगत में क्रांति लाने में अपना भाग अदा किया। अन्यों के अलावा रबड़ कर्मचारियों, रेडियो और बिजली कर्मचारियों, लकड़ी का काम करने वालों और गोदी कर्मचारियों में संगठित अभियानों के ज़रिये शक्तिशाली यूनियनों का निर्माण हुआ। सिडनी हिलमैन के कुशल प्रबन्ध में नई कपड़ा कर्मचारी संगठन समिति का अभियान इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था कि यह बहुत-सी दक्षिणी मिलों में संगठन कायम करने में सफल हुई जब कि ए. एफ़. एल. वहाँ कोई भी प्रगति करने में कामयाब नहीं हुआ था। यूनियन के हजारों सदस्य उन कम्पनी नगरों में बनाए गए, जहाँ पहले मज़दूर संगठनकारियों को आने का साहस भी नहीं हुआ था और एक वर्ष के अन्दर ही यूनियन ने समस्त उद्योग में सामूहिक सौदे-बाज़ी के सैकड़ों समझौतों पर दस्तखत किए।

सन् १९३७ में सी. आई. ओ. की वास्तविक शक्ति से भी महत्त्वपूर्ण बात संगठित मज़दूरों के लिए सामान्यतः वह व्यापक आधार था जो इसके अभियान ने अन्ततः प्राप्त किया था। उस समय इसके सदस्यों में ६ लाख खनिक, ४ लाख मोटर कर्मचारी, ३,७५,००० इस्पात कर्मचारी, ३ लाख टैक्सटाइल कर्मचारी, २५०,००० महिला पोशाक कर्मचारी, १,७६,००० कपड़ा कर्मचारी, तथा एक लाख कृषि व पैकिंग कर्मचारी थे। सी. आई. ओ. ने अदक्ष कर्म-

चारियों की औद्योगिक यूनियनें सफलतापूर्वक बना ली थीं और ए. एफ. एल. द्वारा पोषित शिल्प यूनियनवाद की संकीर्ण सीमाओं को भंग कर डाला था। इसने रंग, लिंग अथवा राष्ट्रीयता का कोई खयाल किए बिना आव्रजकों, नीग्रो और महिलाओं सभी का स्वागत किया, जैसा कि ए. एफ. एल. ने कभी नहीं किया था।

इसके अलावा सी. आई. ओ. का प्रभाव समस्त मजदूर मोर्चे पर फैला हुआ था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है ए. एफ. एल. ने शीघ्र ही यह भाँप लिया कि वह अदक्ष कर्मचारियों की उपेक्षा नहीं कर सकता जब कि उसके प्रतिद्वन्द्वी ने उनका संगठन करने में इतनी प्रगति की है। किन्तु ऐसा उसने सर्वात्मना कभी नहीं किया। मशीन और हिस्से को जोड़ने के काम में तरक्की हो जाने से दक्ष, अर्धदक्ष और अदक्ष कर्मचारियों के बीच विभाजक रेखा इतनी धुँधली हो गई थी कि ए. एफ. एल. की बहुत सी यूनियनों में ये सब शामिल थे। जैसा कि हमने कोयला खनिकों और पोशाक उद्योग के कर्मचारियों में संगठन के विकास पर दृष्टिपात करते हुए देखा फेडरेशन में औद्योगिक यूनियनें सदा रहीं किन्तु इस्पात मोटर तथा सामूहिक उत्पादन के अन्य उद्योगों में जो कुछ हासिल कर लिया गया था उसको देखकर ए. एफ. एल. को यूनियन बनाने के सब अवसरों का लाभ सी. आई. ओ. को उठाने से रोकने के लिये अपने निज के संगठन का विस्तार करने की आवश्यकता महसूस हुई। हजारों कर्मचारी जिनकी दक्षता औद्योगिक यूनियनों में आम मजदूरों की दक्षता से किसी कदर ज्यादा नहीं थी, इस प्रकार की बहुशिल्पीय या अर्ध-औद्योगिक ए. एफ. एल. यूनियनों में शामिल हुए—जैसे मशीन चालकों, ब्वायलर निर्माताओं, मांस काटने वालों, भोजनालय कर्मचारियों, तसला उठाने वाले तथा अन्य सामान्य मजदूरों तथा ड्राइवरों की यूनियनें। पहले से ज्यादा मेहनत से काम करते हुए जहाँ कहीं संभव हुआ, नए सदस्य भर्ती किए, अगरचे उसका विकास इतना नाटकीय नहीं हुआ जितना सी. आई. ओ. का, तो भी ए. एफ. एल. के सदस्यों की संख्या भी काफी बढ़ी। बहुत-सी यूनियनों के ए. एफ. एल. में से निकल कर प्रतिद्वन्द्वी सी. आई. ओ. में चले जाने पर भी जैसा कि हमने देखा, १९३७ के अन्त में ए. एफ. एल. के १९३३ की अपेक्षा १० लाख अधिक थे।

ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. दोनों ही एक दूसरे से मुकाबले की भावना से अपनी ताकत बढ़ाते रहे। ए. एफ. एल. ने इस होड़ में औद्योगिक यूनियनें बनानी शुरू कर दीं और सी. आई. ओ. ने शिल्प-यूनियनों के निर्माण में संकोच नहीं किया। जब मजदूर नेताओं ने अधिकाधिक यह महसूस कर लिया कि संगठन बनाने के लिये कोई एक फार्मूला नहीं है और काम की विभिन्न परिस्थितियों के कारण यूनियन संबन्धी समस्याओं पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है तब पुराने प्रश्नों पर विवाद, जिनके कारण मज़दूर आन्दोलन में फूट पड़ी थी सिर्फ खयाली विवाद ही रह गए। सामूहिक उत्पादन के उद्योगों में जहाँ अधिकांश औद्योगिक यूनियनें सी. आई. ओ. की थीं और ए. एफ. एल. में अब भी शिल्प यूनियनों का अनुपात ज्यादा था, वहाँ पुराने भेद प्रायः छिन्न-भिन्न हो गए और दोनों संगठन, एक-दूसरे के साथ अधिक समता प्राप्त करते हुए सब आगन्तुकों का स्वागत करने को तैयार थे।

इन घटनाओं का एक दुःखद परिणाम दोनों प्रतियोगी यूनियनों में अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी झगड़ों का होना था। ए. एफ. एल. के खाती सी. आई. ओ. के लकड़ी पर काम करने वालों से झगड़ पड़े, सी. आई. ओ. के मोटर कर्मचारी ए. एफ. एल. के मशीनचालकों से जूझ पड़े। गोदी कर्मचारियों, टैक्सटाइल मजदूरों, बिजली कर्मचारियों, खाद्य सामान पैक करने वाले कारखानों के कर्मचारियों तथा खुदरा क्लर्कों में ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. के सदस्य अन्धाधुन्ध भिड़ पड़े। यूनियन पर हमला करने, हड़तालियों की जगह काम करने और आपस में धोखेबाजी के आरोपों से आकाश गुंजायमान हो उठा। इस आपसी विवाद की कटुता प्रायः श्रम-पूंजी के झगड़ों से भी बढ़ जाती थी। दोनों संगठनों के एक-दूसरे पर द्वेषपूर्ण आक्षेप और ए. एफ. एल. अथवा सी. आई. ओ. के अन्दर कभी-कभी होने वाले संघर्ष अनेक बार उद्योगों पर मज़दूरों के आक्षेपों से ज्यादा उग्र होते थे। सिर्फ अधिकार-क्षेत्र के मामले पर ही बार-बार हड़तालें होने लगीं जिससे उनसे सबसे निकट रूप से सम्बद्ध मज़दूरों की और सामान्यतः समस्त संगठित मज़दूर आन्दोलन की अपार क्षति हुई।

अपनी-अपनी यूनियनों के लिए मान्यता प्राप्त करने के हेतु ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. अपने संघर्ष में नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड को भी घसीट लाए। इस एजेंसी का लक्ष्य इस बात के लिए निष्पक्षता से चुनाव कराना था

कि कौन-सी यूनियन कर्मचारियों की तरफ से सामूहिक सौदेबाजी करने की हकदार है किन्तु इसके काम में उद्योग द्वारा नहीं बल्कि मज़दूरों द्वारा किए गए आक्षेपों से बार-बार रुकावट पड़ी। दोनों मज़दूर कैम्पों में इसकी सख्त आलोचना हुई, यही बात शायद उसकी निष्पक्षता के सफल होने का सबूत थी किन्तु इस प्रकार की आलोचना से उन लोगों को मसाला मिल गया जो इस पर अपने अधिकार-क्षेत्र का उल्लंघन करने और उद्योग-विरोधी भावना जाहिर करने के व्यापक आधार पर इस पर चोट कर रहे थे। मज़दूरों का आन्तरिक कलह न केवल उनकी अपनी शक्ति को खत्म कर रहा था बल्कि यूनियनों को मान्यता दिलाने के लिए स्थापित सरकारी एजेंसी के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न कर रहा था।

१९वीं सदी के मज़दूर नेताओं का एकता का उज्जवल स्वप्न बिखर गया। यह कहा जा सकता है कि अगर मज़दूर आन्दोलन में बहुत ज्यादा एकता होती तो ज्यादा केन्द्रीभूत प्राधिकार और तानाशाही नेताओं द्वारा जो शायद लोकतंत्री प्रक्रियाओं की उपेक्षा कर देते, मज़दूरों पर राष्ट्रव्यापी नियंत्रण का खतरा उत्पन्न हो जाता। मज़दूरों के संगठन में विविधता इस खतरनाक संभावना के विरुद्ध एक आश्वासन है। फिर भी संगठित मज़दूर की स्थिति अपने या लोकमत के दृष्टिकोण से इतनी सबल नहीं थी, जितनी कि हो सकती थी, बशर्ते कि शिल्प बनाम औद्योगिक यूनियनवाद पर मूल झगड़े में अथवा बाद में ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. के विलय के प्रयत्नों में समझदारी से काम लिया गया होता। १९३० की दशाब्दी की समाप्ति पर यह व्यापक रूप से अनुभव किया जाने लगा कि जब तक फिर से अधिक एकता स्थापित नहीं हो जाती तब तक संगठित मज़दूर जिम्मेदारी से काम नहीं कर सकते जो कि, अगर उन्हें हमारी आर्थिक प्रणाली की स्थिरता को कायम रखने और सामाजिक लोकतंत्र का आधार व्यापक करने में अपना पूरा भाग अदा करना है, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

—:०:—

१७ : मज़दूर और राजनीति

न्यू डील के आगमन के साथ ही राजनीति में मज़दूरों के रोल का नया महत्त्व सामने आया। औद्योगिक सम्बन्धों में जब सरकारी हस्तक्षेप इतने व्यापक स्तर पर हुआ, तब मज़दूरों की आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति रखने वाले राष्ट्रीय-प्रशासन तथा कांग्रेस को शासनारूढ़ रखना पहले से ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो गया। जब सेम्युअल गोम्पर्स न्यूनतम वेतन, बुढ़ापे की पेंशन तथा बेकारी के बीमे का उन्हें "लोगों की नैतिक शक्ति को क्षीण करने वाला" बता कर विरोध किया करता था, उन दिनों में ए. एफ. एल. की लाबी हरकतों से पूर्ण किए जाने वाले उद्देश्यों से अब राष्ट्र के मज़दूरों की आवश्यकता पूरी नहीं होती थी। विशेषकर नई औद्योगिक यूनियनें न्यू डील कानूनों द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण पर निर्भर करती थीं। फलतः वे वाशिंगटन में मज़दूर-पक्षपाती सरकार कायम रखने के लिए यथाशक्ति सब कुछ करने को उद्यत थीं।

किन्तु राजनीति में पहले से अधिक भाग लेने के इस स्पष्ट रुझान का सिर्फ यही कारण नहीं था कि नए मज़दूर-कानूनों को प्रभावशाली ढंग से अमल कराने की इच्छा थी। रूज़वेल्ट कार्यक्रम में निहित बड़े मानवों को लोग ज्यादा समझ रहे थे। मज़दूर सामान्यतः महसूस करते थे कि न्यू डील अमरीकी लोकतन्त्र में प्रगतिशील ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है जो जनसामान्य के हित में लोकप्रिय सरकार की जैक्सन के दिनों की परम्परा को निबाह रहा है। न्यू डील का समर्थन करते हुए लोकतन्त्रीय पूंजीवाद के सब फलितार्थ स्वीकार किए गए। मज़दूर औद्योगिक कामनवेल्थ या एक समाजवादी राष्ट्र की बात नहीं सोचते थे। इसका उद्देश्य हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन में उन परिस्थितियों को लाना था जिनमें स्वतन्त्र व्यवसाय-प्रणाली अधिक-से-अधिक सामाजिक न्याय के साथ काम कर सके।

यह स्वाभाविक ही था कि इस राजनीतिक हलचल में सी. आई. ओ. ए. एफ. एल. से ज्यादा उग्र रहती। इसकी उदार और विद्रोही भावना को, जो

औद्योगिक यूनियनवाद की वकालत में इसकी खास बात रही, सामाजिक सुधारों की प्रगति में काम में लाया गया। यद्यपि मज़दूरों के दोस्तों को पुरस्कृत करने और इसके दुश्मनों को दण्डित करने की पुरानी परिपाटी का वस्तुतः तिलांजलि नहीं दी गई तो भी इस नीति को कार्यरूप देने में सी. आई. ओ. बहुत आगे तक बढ़ गया। ए. एफ. एल. के विपरीत, जो राष्ट्रपति के चुनावों में निष्पक्षता अपनाए रहा, यह राष्ट्रपति रूज़वेल्ट का जोरों से समर्थन करने को तैयार था।

ए. एफ. एल. की मजबूती से जभी शिल्प यूनियनों की अपेक्षा सी. आई. ओ. की सदस्य औद्योगिक यूनियनें भी यह ज्यादा अच्छी तरह समझती थीं कि किस हद तक सभी मजदूर सरकार पर निर्भर हो गए हैं। मन्दी के अनुभव ने उन्हें विश्वास करा दिया था कि राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर अभी और नियन्त्रणों की आवश्यकता है।

सामूहिक उत्पादन के उद्योगों के बारे में लेविस ने लिखा कि "संगठन करने के अधिकार की गारण्टी के साथ इस प्रकार के उद्योगों में यूनियनें स्थापित की जा सकती हैं किन्तु दूसरी ओर उनके सदस्य मज़दूरों के लिए बेहतर जीवन-स्तर, काम के कम घण्टों, और रोजगार की सुधरी हुई हालतों की तब तक आशा नहीं की जा सकती जब तक आर्थिक आयोजन, मूल्य, उत्पादन तथा मुनाफा-नियन्त्रण के लिए कानूनी या अन्य व्यवस्थाएँ नहीं कर दी जातीं। इन बुनियादी परिस्थितियों के कारण औद्योगिक मज़दूरों के सामने यह स्पष्ट है कि मज़दूर आन्दोलन को न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी स्वयं को संगठित कर अपना प्रभाव डालना चाहिए...।"

इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सी. आई. ओ. के नेताओं ने १९३६ में मज़दूरों की एक नान-पार्टिजन लीग कायम की और न्यूयार्क में एक अमरीकी मज़दूर दल कायम किए जाने का समर्थन किया। इन कदमों का मुख्य उद्देश्य रूज़वेल्ट को जिताना था और इसके लिए ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. यूनियन का सहयोग प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया गया। नान-पार्टिज़न लीग का पहला अध्यक्ष ए. एफ. एल. से सम्बद्ध प्रिंटिंग प्रेस यूनियन का जार्ज एल-बेरी था। किन्तु बहुत-से राज्य मज़दूर-संघों तथा सदस्य यूनियनों ने जहाँ लीग से सहयोग किया, वहाँ ए. एफ. एल. का

अधिकृत तौर पर उससे कोई सम्बन्ध नहीं था। कार्यकारी परिषद् राजनीतिक मामलों पर विभक्त हो गई। रिपब्लिकन लेवर कमेटी के अध्यक्ष विलियम हचेसन तथा डैमोक्रैटिक लेवर कमेटी के अध्यक्ष डेनियल टोबिन थे ग्रीन ने यद्यपि स्वतः रूज़वेल्ट का समर्थन किया, तथापि उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में सी. आई. ओ. को द्वैध आन्दोलन बताने के समान राजनीति में नान-पार्टिजन लीग को द्वैध आन्दोलन बताकर उसकी निन्दा की।

किन्तु सी. आई. ओ. तथा नई औद्योगिक यूनियनों की स्थिति के बारे में कोई सन्देह नहीं था। नान-पार्टिजन लीग के अभियान-कोष में भारी चन्दे दिए गए। अकेले यूनाइटेड माइन वर्कर्स ने ही ५ लाख डालर दिए और लेविस ने न्यू डील के असंदिग्ध समर्थन का आह्वान किया। उसने कहा : "अब तक अन्य किसी भी राष्ट्रपति की अपेक्षा रूज़वेल्ट के शासन में मज़दूरों ने ज़्यादा लाभ प्राप्त किए हैं। स्पष्ट ही मज़दूरों का यह कर्त्तव्य है कि आगामी चुनाव में वे रूज़वेल्ट का १०० प्रतिशत समर्थन करें।"

डैमोक्रैटों ने मज़दूरों के समर्थन की अपील की थी और उनके लिए इसकी आशा करना उचित भी था। रूज़वेल्ट प्रशासन ने मन्दी से उत्पन्न समस्याओं को प्रत्यक्षतः हल करने की कोशिश की और लोगों को वापस काम पर लगाने, वेतन बढ़वाने तथा यूनियनों के संगठन के प्रति मुख्य रूप से अपनी चिन्ता प्रदर्शित की। डैमोक्रैटिक मंच से वायदा किया गया, "हम मज़दूर की और मज़दूरी कमाने वाले और उपभोक्ता के रूप में उसके अधिकारों की रक्षा करते रहेंगे।" रिपब्लिकनों ने भी संगठन करने के अधिकार की रक्षा करने का वचन दिया किन्तु उनका न तो पिछला रिकार्ड और न सामान्य रवैया इस बात का विश्वास दिला सकता था कि मज़दूरों के व्यापक लक्ष्यों को उनसे वह समर्थन प्राप्त होगा जो उसे न्यू डील के अन्तर्गत प्राप्त रहा है।

१९३६ का चुनाव-संघर्ष बड़ा कड़ा रहा। अमरीकी समाज में जो मत-विभेद उत्पन्न हो गए थे उन्होंने पार्टी लाइन की परवाह नहीं की और एक वर्ग को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जैसा कि उसके बाद से नहीं हुआ था जब कि ४० वर्ष पूर्व पोपुलिज़्म ने प्रभुत्व-सम्पन्न व्यावसायिक वर्ग के रूढ़िवादी शासन को चुनौती दी थी। भूतपूर्व राष्ट्रपति हूवर तथा लिबर्टी लीग ने जहाँ आरोप लगाया कि सरकार "

समाजवाद और फासिज़्म के विदेशी सिद्धान्तों को अमरीकी समाज में स्थान दे रही है", वहाँ रूज़वेल्ट ने भी यह प्रत्यारोप लगा कर कि "आर्थिक अधिपति" सरकार को अपने मामलों का सिर्फ एक पुछल्ला समझते हैं, कम तेज़ी से प्रत्याक्रमण नहीं किया। उन्होंने कहा कि "संगठित पूँजी की सरकार" संगठित भीड़ की सरकार से कम खतरनाक नहीं है।

१९३६ का चुनाव जीतने में ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. दोनों मज़दूर-संगठनों के सदस्यों के वोटों ने रूज़वेल्ट की बड़ी मदद की। पुनरुत्थान और सुधार के एक सजीव कार्यक्रम के प्रति राष्ट्रव्यापी सहयोग में मज़दूर देश के अन्य उदार तत्त्वों के साथ मिल गए थे। मज़दूर औद्योगिक सम्बन्धों तथा सामाजिक सुरक्षा की नई व्यवस्था के अलावा किसानों को राहत दिए जाने और व्यावसायिक सुधारों का भी समर्थन कर रहे थे; यह आर्थिक पुनरुत्थान के एक कार्यक्रम का भी जो वर्धमान व्यावसायिक हलचल तथा ज़्यादा कृषि-आय में प्रतिक्षिप्त हो रहा था, वैसा ही समर्थन कर रहे थे जैसा बेकारी कम करने और वेतन बढ़ाए जाने का।

नौन-पार्टिज़न लीग की चुनाव-अभियान सम्बन्धी हलचलें और न्यूयार्क में अमरीकी मज़दूर दल द्वारा रूज़वेल्ट के पक्ष में प्राप्त किए गए वोट राजनीति में मज़दूरों की सीधी कारंवाई के महत्त्व को ज़ाहिर करते प्रतीत होते थे। सी. आई. ओ. ने एक व्यापक विधि-सम्बन्धी कार्यक्रम बनाया और नौन-पार्टिजन लीग ने उद्देश्यों की एक नई घोषणा करते हुए कहा कि भावी चुनावों में वह इस बात का प्रयत्न करेगी कि मज़दूरों का तथा अन्य प्रगतिशील विधि-विधानों का समर्थन करने का वचन देने वाले उम्मीदवारों की ही नामज़दगी हो और वही चुने जाएँ। वह ऐसे हर किसी प्रगतिशील ग्रुप के साथ काम करने को तैयार थी 'जिसका उद्देश्य उदार और मानवतावादी कानून बनवाना हो।"

नौन-पार्टिज़न लीग ने अगले कुछ वर्षों में पेंसिलवेनिया में डैमोक्रैटिक पार्टी पर नियन्त्रण स्थापित करने की कोशिश करते हुए न्यूजर्सी की राजनीति में सक्रिय भाग लेते हुए, और डेट्रायट में मज़दूर-प्रशासन स्थापित करने के आन्दोलन का समर्थन करते हुए कई राज्यों में स्थानीय चुनाव लड़े। न्यूयार्क में अमरीकी मज़दूर दल ज़्यादातर सिलाई-मज़दूरों की यूनियन के समाजवादी विचारों वाले सदस्यों का था, किन्तु इसे मज़दूरों के बाहर उदार विचार

वाले बहुत से अन्य लोगों का भी समर्थन मिला, जिससे वह १९३७ में मेयर ला गार्दिया के पुर्ननिवाचन में ५ लाख वोट प्राप्त कर सका। राष्ट्रीय स्तर पर न्यू डील संबन्धी कानूनों का, सुप्रीम कोर्ट के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के कार्यक्रम का और इन्हीं के अनुरूप अन्य सुधार-कार्यक्रमों का समर्थन किया जाता रहा। नान-पार्टिज़न लीग १९३८ के कांग्रेस के चुनावों में कूद पड़ी और न्यू डील के समस्त विरोधियों को हराने और पार्टी लेवल की परवाह किए बिना अपने अनुयायियों को जिताने की उसने पूरे जोर से कोशिश की।

१९३० की दशाब्दी के आखिरी हिस्से की इस राजनीतिक गतिविधि में एक महत्त्वपूर्ण भाग सिडनी हिलमैन ने अदा किया, यद्यपि सन् १९४४ में सी. आई. ओ. की राजनीतिक कार्रवाई समिति के निर्माण के साथ उसने और भी महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया। मज़दूर और प्रबन्धकों के बीच "रचनात्मक सहयोग" का जबर्दस्त समर्थन करते हुए वह मज़दूरों से व्यापक पैमाने पर राजनीति में भाग लेने का भी अनुरोध किया करता था जिससे उपरोक्त सहयोग को संभव बनाने के लिए बुनियादी हालात पैदा किए जा सकें। शायद ही कोई और यूनियन राजनीतिक दृष्टि से इतनी जागरूक हो जितनी उसकी ऐमलगमेटेड क्लोदिंग वर्कर्स यूनियन। कभी-कभी जिसे "सामाजिक सुधार करने वाले" यूनियन नेतृत्व का अवतार कहा जाता था और एक साथ ही अत्यन्त व्यावहारिक तथा आदर्शवादी हिलमैन उस वक्त का एक अत्यन्त कुशल मज़दूर नेता था जो यह विश्वास करता था कि अमरीका में एक व्यापक दृष्टिकोण वाले समाज का निर्माण किया जा सकता है।

१९३८ के एक यूनियन सम्मेलन में उसने कहा: "कल के स्वप्नों की पूर्ति कर लेने के बाद अब हमें भविष्य के नए स्वप्नों की पूर्ति में लग जाना चाहिए जहाँ कोई बेकारी नहीं होगी और हर स्त्री-पुरुष आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित तथा राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होगा।"

इस समय में मज़दूरों द्वारा राजनीति में नॉन-पार्टिज़न लीग से भी ज्यादा सक्रिय भाग लेने के प्रश्न पर बहस की गई। मज़दूर दल बनाने का पुराना सवाल, जो अतीत में अनेक बार उठाया जा चुका था, फिर उठाया गया। लीग को कुछ क्षेत्रों में एक ऐसे आन्दोलन का संभावित केन्द्रबिन्दु समझा गया जिसमें मज़दूरों, किसानों तथा अन्य उदार तत्त्वों को एक मंच पर जुटाया जा

सके और तब जो या तो डैमोक्रैटिक दल की मशीन पर कब्जा कर ले या अगर वांछनीय हो तो एक तीसरा स्वतंत्र दल बना ले।

किन्तु इन विचारों ने कोई वास्तविक प्रगति नहीं की। ए. एफ. एल. तो इनमें से किसी से कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहता था और सी. आई. ओ. ने भी आर्थिक सुरक्षा के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम की बार-बार पुकार मचाते हुए भी स्वतंत्र राजनीतिक कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। तीसरा दल स्थापित करने के आन्दोलन के बारे में अतीत के अनुभव इस दिशा में और परीक्षण करने के लिए उत्साह को भंग कर देते थे और कुछ भी हो मज़दूरों के प्रति न्यू डील के मित्रतापूर्ण रवैये ने इसे अवांछनीय बना दिया था। मज़दूर ग्रीन के इस कथन की पुष्टि कर रहे प्रतीत होते थे कि मज़दूर कोई वर्ग य जमात नहीं है किन्तु राष्ट्र के इतने अधिक विभिन्न हितों वाले लोगों का एक अंश है कि मज़दूर दल की कोई वास्तविक सार्थकता नहीं हो सकती। समस्त १९वीं सदी की तरह समाजवाद या अन्य किसी विध्यात्मक विचारधारा में सामान्य विश्वास जैसी कोई परस्पर एक सूत्र में पिरोने वाली चीज़ नहीं थी। किन्तु मज़दूर अगर यह समझें कि वे अपने मूल उद्देश्यों के प्रति समर्थन पाने के लिए बड़े दलों पर और विशेषकर डैमोक्रैटिक पार्टी पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं तो तीसरे दल के निर्माण का खतरा पृष्ठभूमि में सदा बना रहता था।

तीसरी पार्टी बनती या न बनती, रूढ़िवादी और न्यू डील विरोधी ताकतें १९३० की दशाब्दी के आखिरी दिनों में मज़दूरों द्वारा डाले जाने वाले राज-नीतिक दबाव के असर पर अधिकाधिक भयभीत हो उठीं। इन प्रभावों का मुकाबला करने के लिये सी. आई. ओ. के कार्यक्रम को क्रांतिकारी और अमरीका और अमरीका विरोधी घोषित किया गया। आरोप लगाए गए कि नौन-पार्टिजन लीग पर पूरी तरह वामपक्षियों का नियंत्रण है जो उसे कम्युनिस्ट दिशा में ले जा रहे हैं। नेशनल ऐसोसियेशन आव मैन्युफैक्चरर्स तथा मालिकों के अन्य ग्रुपों ने इस प्रकार के आक्षेपों के लिए हर अवसर का लाभ उठाया। अनेक यूनियन-विरोधी ग्रुपों द्वारा प्रचारित किए गए एक पर्चे का ध्यानाकर्षक शीर्षक था : "सी. आई. ओ. में भरती होवो और सोवियत अमरीका के निर्माण

में सहायता दो।" नान-पार्टिज़न लीग तथा अमरीकी मज़दूर दल के सक्रिय नेताओं पर, जिनमें हिलमैन और लेविस को भी शामिल किया गया, कम्युनिज़्म के साथ सहानुभूति रखने और मास्को से निर्दिष्ट नीतियों पर अमल करने की इच्छा रखने के आरोप लगाए गए।

कुछ धधकते शोले थे भी जहाँ सी. आई. ओ. के विरोधियों को धुएँ के घने बादल दिखाई देते थे। मज़दूर आन्दोलन में क्रांतिकारी तत्त्व हमेशा मौजूद रहते थे और अतीत में जिनका प्रतिनिधित्व शिकागो-अराजकतावादियों, वामपक्षी समाजवादियों तथा आई. डब्लू. डब्लू. ने किया था, वे अब सामान्यत: कम्युनिस्ट कैम्प में भरती हो गए थे। उनका मज़दूर मोर्चा पहले ट्रेड यूनियन एजुकेशन लीग था जिसे १९१९ में इस्पात हड़ताल की विफलता के बाद विलियम जेड फौस्टर ने कायम किया था और बाद में ट्रेड यूनियन यूनिटी लीग हो गया जिसकी स्थापना १० वर्ष बाद ए. एफ. एल. से स्वतंत्र रूप में औद्योगिक-यूनियनवाद का विकास करने के लिये की गई थी। १९३० की दशाब्दी के मध्य में मास्को पार्टी की लाइन बदल जाने से, जिसके बाद कम्यु-निस्ट फासिज़्म के खिलाफ संयुक्त लोकतंत्रीय मोर्चे का समर्थन करने लगे, द्वैध यूनियनवाद का परित्याग कर दिया गया और अन्दर से तोड़-फोड़ करने के पुराने समाजवादी तौर-तरीकों पर लौट आए। कम्युनिस्ट औद्योगिक यूनियनवाद को प्रोत्साहन देने की भरसक कोशिश कर रहे थे और सी. आई. ओ. तथा उसकी राजनीतिक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने अथवा कम से कम उस पर हावी हो जाने की आशा कर रहे थे।

सी. आई. ओ. तथा नान-पार्टिजन लीग का निर्माण करने में लेविस ने उनके अनुभवों तथा संगठन-प्रतिभा का लाभ उठाने में संकोच नहीं किया। उसे हर क्षेत्र से मदद की ज़रूरत थी। उसने कहा : "हमारे पास जो कुछ है, हमें उसी से काम करना है।" यद्यपि वह यह अच्छी तरह समझता था कि कम्युनिस्ट नई यूनियनों का उपयोग अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिए करेंगे तो भी वह सोचता था कि जब तक औद्योगिक यूनियनवाद को आगे बढ़ाने में वे उसे सहयोग दे रहे हैं तब तक वह उनकी राजनीति की उपेक्षा कर सकता है। इस आतिथ्य के फलस्वरूप कम्युनिस्टों अथवा उनके अनुयायियों ने कुछ यूनियनों में और यहाँ तक कि सी. आई. ओ. की उच्च परिषदों में भी

महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिए। वामपंथी और रूढ़िवादी वर्ग जब सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने लगे तो यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स में सदा कलह रहने लगा और कम्युनिस्टों से सहानुभूति रखने वाले लोग इलैक्ट्रिकल रेडियो ऐण्ड मशीन वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, मैरिटाइम यूनियन, दि स्टेट, काउण्टी ऐण्ड म्युनिसिपल वर्कर्स, दि फर ऐण्ड लैदर वर्कर्स और वुड वर्कर्स आव अमेरिका यूनियनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में बहुत कुछ सफल हो गए। संसदीय तौर-तरीकों तथा संगठन सम्बन्धी कार्यों में उनके उत्साह तथा अध्यवसाय ने और स्थानीय चुनावों में गुण्डों के आतंककारी दलों द्वारा डाले गए दबाव ने उन्हें अपनी वास्तविक संख्या के अनुपात से कहीं ज्यादा प्रभाव प्रदान कर दिया था।

अधिकांश यूनियन सदस्यों की, चाहे वे ए. एफ. एल. से सम्बद्ध हों या सी. आई. ओ. से, बुनियादी रूढ़िवादिता तथा वफादारी का पहले से ज्यादा अब कोई सवाल नहीं था। किसी यूनियन के नेताओं के कम्युनिस्ट होने का यह मतलब नहीं था कि इसके सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को मानते हैं; बल्कि सिर्फ यही था कि वे किसी के भी ऐसे निर्देश को मानने को तैयार हैं जिससे कोई परिणाम हासिल हो। जिस प्रकार २५ वर्ष पूर्व क्रांति-विरोधी मज़दूरों ने आई. डब्लू. डब्लू. के संगठनकर्त्ताओं की सहायता स्वीकार की थी, उसी प्रकार १९३० की दशाब्दी के हड़ताली मज़दूर कम्युनिस्टों की सहायता स्वीकार करने को तैयार थे। सी. आई. ओ. का हाई कमाण्ड कम्युनिस्टों पर अविश्वास करता था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वे पार्टी के हित को सबसे आगे रखते हैं किन्तु जब तक वे मज़दूरों के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देने के लिए उद्यत थे तब तक वह उनकी सहायता का लाभ उठाता रहा। अगर लेविस उनके साथ निकट गटबन्धनपूर्वक नहीं तो कभी-कभी बहुत खतरनाक रूप से उनके साथ सहयोगपूर्वक काम करता प्रतीत होता था तो सी. आई. ओ. के अन्य नेता मर्रे और हिलमैन उनके प्रभाव को मिटाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। वे यह अच्छीतरह महसूस करते थे कि मज़दूर आन्दोलन में कम्युनिस्टों का पुट चाहे कितना भी थोड़ा हो तो भी वह इतना अधिक आबद्ध और अनुशासित था कि वह लोकतन्त्रीय यूनियन-वाद के लिए सदैव एक ख़तरा बना रहता था।

संयुक्त मोर्चे के कार्यक्रम के एक अंग के रूप में वामपक्ष रूज़वेल्ट और न्यू डील को जो राजनीतिक सहयोग देने को तैयार था, उसने मज़दूर क्षेत्र में और ज्यादा विभ्रम पैदा कर दिया। न्यू डील विरोधी ताकतों ने रूज़वेल्ट को कम्युनिस्टों के समर्थन का पूरा-पूरा लाभ उठाकर उनकी तथाकथित समाजवादी और क्रांतिकारी नीतियों पर चोटें कीं। किन्तु यद्यपि राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने कम्युनिस्टों के समर्थन का प्रतिवाद किया तो भी उन्हें संगठित मजदूरों की जरूरत बनी रही। इसलिए यह उनके बहुत हित में ही था कि कम्युनिस्टों को निकाल बाहर करने के लिए, क्रांतिकारी अल्पमत पर प्रभाव जमाए रखने के लिये और राष्ट्र की प्रगतिशील ताकतों द्वारा स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियों का पृष्ठपोषण कराने के लिए एक पर्याप्त शक्तिशाली संयुक्त आन्दोलन हो। इन्हीं विचारों को लेकर उन्होंने १९३७ से ही लगातार ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. में मेल की आवश्यकता पर बल दिया और १९३९ में एक बार पुनः दोनों संगठनों से अपने मतभेद दूर करने की कोशिश करने का आग्रह किया।

रूज़वेल्ट के आग्रह पर उस वर्ष शांति वार्ता पुनः प्रारम्भ की गई और ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. के प्रतिनिधियों ने परस्पर मिलने का यत्न किया। जैसा कि हमने देखा शिल्प यूनियनवाद बनाम औद्योगिक यूनियनवाद चिरकाल से अपनी यथार्थता खो चुका था किन्तु पिछले वर्षों के संघर्ष से सत्ता प्राप्ति की होड़ तेज हो गई थी। लेविस ने ए. एफ. एल., सी. आई. ओ. तथा रेलवे ब्रदरहुडों के विलय का एक महत्त्वाकाङ्क्षी प्रस्ताव रखा। यह अव्यावहारिक था, क्योंकि ब्रदरहुडों को ऐसी योजना में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी और लेविस पर तुरन्त ही दयानतदारी से काम न करने का आरोप लगाया गया।

ए. एफ. एल. का जवाबी प्रस्ताव था कि सी. आई. ओ. की यूनियनें फिर से अपने पितृ-संगठन में शामिल हो जाएँ किन्तु उनके परिवर्धित अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर कोई निश्चित उत्तर दिए बिना लेविस ने बैठक स्थगित कर दी किन्तु शीघ्र ही उसने यह कहना शुरू कर दिया कि ए. एफ. एल. के नेताओं की, जो "शासन या विनाश" की नीति अपना रहे हैं, अड़ंगेबाजी के रुख के कारण शांति असम्भव है।

सचाई यह थी कि कोई भी पक्ष रियायत देने को तैयार नहीं था। मजदूरों में एकता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. दोनों ने अपने-अपने स्वार्थों को प्रमुखता दी। ग्रीन "शांति के लिए अपनी अदम्य इच्छा" को प्रकट करता रहा किन्तु यह शांति उनकी अपनी शर्तों पर होनी चाहिए थी। लेविस ने यह कहते हुए कि "हमें अपने आन्दोलन का विस्तार करना होगा", शायद ज्यादा स्पष्टवादिता से काम लिया।

मजदूरों की आन्तरिक कठिनाइयाँ, चाहे वे साम्यवादियों के षड्यन्त्रों से उत्पन्न हुई हों या अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी झगड़ों के कारण; १९३९ में दूर नहीं हुई। किन्तु इस बीच विश्व के रंगमंच पर घटित अधिक महत्त्वपूर्ण घटनाओं की मजदूर और राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर अनिवार्य प्रतिक्रिया हुई। रूस और जर्मनी ने अगस्त में अपना प्रसिद्ध करार किया और उसके बाद पोलैण्ड पर हिटलर के आक्रमण से यूरोप युद्ध में कूद पड़ा। इस बीच अमरीका को इस बात का खतरा बढ़ रहा था कि फासिज्म के खिलाफ लड़ाई में कहीं वह भी न घसीटा जाए और लोगों का ध्यान घरेलू समस्याओं से हट कर ज्यादातर विदेशनीति से सम्बन्धित मामलों पर केन्द्रित हो गया। देश इस अहम प्रश्न पर नाजुक दृष्टि से विभक्त हो गया कि क्या मित्र राष्ट्रों को सहायता देने से युद्ध को अपने तट से दूर रखा सकता है; या हमें, अपनी शांति की रक्षा के लिए युद्ध से अलग रहने की नीति अख्त्यार करनी चाहिए।

ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ दोनों संगठनों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के जरिये मजदूरों ने युद्ध में शामिल होने का पुरजोर विरोध किया, किन्तु वे मित्र-राष्ट्रों की सहायता करने और राष्ट्रीय रक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने की रूजवेल्ट की नीति का समर्थन करने को तैयार थे। किन्तु आबादी के अन्य वर्गों के समान यूनियन के सदस्यों में भी इस प्रश्न पर अलग-अलग मत थे। हालाँकि कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन संयुक्त लोकतंत्रीय मोर्चे से हटकर एकदम विषैले पृथकतावाद की हो गई थी। रूजवेल्ट प्रशासन की पहले जितनी जोर से पैरवी की जाती थी अब उतने ही जोर से उसकी निंदा की जाने लगी। इसलिए १९४० के आते-आते यह सवाल बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया कि मजदूर किसे वोट दें। इन परिस्थितियों में सारे राष्ट्र का ध्यान इस बात पर गया कि

लेविस क्या करता है, किन्तु उसने एक विचित्र और अकल्पनीय रोल अदा करना पसन्द किया।

१६३६ में रूजवेल्ट के पुनः राष्ट्रपति चुने जाने के बाद लेविस बड़ी शेखी से यह समझने लगा था कि डैमोक्रैटों की महान् विजय सिर्फ इसी लिए नहीं हुई कि उन्हें मजदूरों के वोट मिले किन्तु इस लिए कि ज्यादातर लेविस के कारण उन्हें मजदूरों के वोट मिले। इस मन्तव्य के अनुसार सी. आई. ओ. तथा नान-पार्टिज़न लीग ने न्यू डील को बचा लिया था। फलस्वरूप रूज़वेल्ट पर यह सीधा दायित्व आ गया था कि वे सी. आई. ओ. की नीति से पूर्णतः सहमत होकर इस राजनीतिक ऋण से उऋण हों। सफलता से लेविस का दिमाग़ इतना फिर गया था कि वह यह समझने लगा था कि राष्ट्रपति को उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए और १६३७ के प्रारम्भ में जनरल मोटर्स के अन्दर बैठे-रहो हड़ताल के दौरान उसने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी।

लेविस ने रिपोर्टरों से कहा कि "६ महीने तक जनरल मोटर्स के आर्थिक अधिपतियों ने अपने पैसे और शक्ति का उपयोग इस प्रशासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश में किया। प्रशासन ने सहायता माँगी और मजदूरों ने वह प्रदान की। अब इन्हीं आर्थिक अधिपतियों के दाँत मजदूरों पर हैं। इस देश के मज-दूर आशा करते हैं कि प्रशासन हर कानूनी तरीके से उनकी मदद करेगा और जनरल मोटर्स में मजदूरों को सहयोग देगा।"

यह एक अभिमान भरा वक्तव्य था और रूज़वेल्ट ने यह समझे जाने पर रोष व्यक्त किया कि वे किसी रूप में सी. आई. ओ. से वचनबद्ध हैं। मोटर उद्योग में शांति स्थापित करने में, जिसे वे सार्वजनिक हित में समझते थे, उन्होंने सी. आई. ओ. को कोई दस्तंदाजी नहीं करने दी और अतीत में लेविस के साथ उनका जो निकट सहयोग रहा था, उसके बारे में उन्होंने कोई राज-नीतिक सौदे-बाजी करने से इन्कार कर दिया। राष्ट्रपति की इस अप्रत्यक्ष भर्त्सना से आहत होकर सी. आई. ओ. के नेता ने अपने मन में एक गाँठ बाँध ली और जब एस. डब्लू. ओ. सी. तथा लिटल स्टील कम्पनियों के बीच भया-नक संघर्ष में रूज़वेल्ट ने एक बयान में कहा "दोनों जहन्नुम में जाएँ" तो यह गाँठ और भी सख्त हो गई। दूसरी बार दी गई इस झिड़की पर विचार करने के

बाद लेविस ने मजदूर दिवस पर रेडियो से भाषण देते हुए इस्पात की हड़ताल के दौरान मजदूरों की मृत्यु और उनके जख्मी होने का उल्लेख किया और राष्ट्रपति पर पुनः आक्षेप किए।

उसने प्रवचनात्मक वाणी में कहा : "जिसने मजदूर की मेज पर भोजन किया है और जिसे मजदूर के घर में शरण दी गई है उसे यह शोभा नहीं देता कि जब मज़दूर और उनके दुश्मन घातक संघर्ष में जूझ रहे हों तब वह एक से जोश और सूक्ष्म निष्पक्षता से दोनों की निन्दा करे।"

किन्तु रूज़वेल्ट और लेविस के बीच बढ़ती हुई उस खाई का एक और भी पहलू था। सी. आई. ओ. जब निरन्तर विजय प्राप्त करती रही और लेविस की प्रसिद्धि बढ़ती रही तो उसके मन में राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएँ जागने लगीं। १९३९ के अन्त में या १९४० के शुरू में जब रूज़वेल्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की संभावना चर्चा का विषय बनी हुई थी तब लेविस राष्ट्रपति के पास एक प्रस्ताव लेकर गया। फ्रांसिस पर्किन्स ने यह किस्सा एक बातचीत का विवरण देते हुए बताया जिसमें रूज़वेल्ट ने उसे तथा ए. एफ. एल. की ड्राइवर-यूनियन के डेनियल टोबिन को बताया कि लेविस ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के मार्ग में आने वाली सब बाधाओं पर विजय पाने का क्या उपाय सुझाया था।

श्रीमती पर्किन्स ने रूज़वेल्ट को उद्धृत करते हुए, जिन्होंने लेविस की बात का उल्लेख किया, बताया "राष्ट्रपति महोदय ! मैंने सब बातों पर गौर किया है और अब मैं आपके सामने विचारार्थ एक सुझाव रखता हूँ। आपके टिकट पर उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अगर जॉन एल. लेविस हो तो ये सब आपत्तियाँ हवा हो जाएँगी। एक शक्तिशाली मजदूर नेता के कारण न केवल आपको मज़दूरों के वोट मिलने निश्चित हो जाएँगे, बल्कि उदारपन्थी लोगों में तीसरे कार्यकाल के बारे में जो शंकाएँ हैं, वे भी मिट जाएँगी।"

यह सुझाव राष्ट्रपति को जँचा नहीं। उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी। किंतु इस घटना का एक और भी विवरण दिया जाता है जिसकी सच्चाई शायद संदिग्ध है। इसके अनुसार लेविस ने रूज़वेल्ट से प्रस्ताव किया कि "राष्ट्र में दो सबसे प्रमुख व्यक्ति होने के नाते" उनका टिकट दुर्जेय होगा और राष्ट्रपति ने स्पष्ट पूछा, "जॉन तुम कौन-सा स्थान लोगे ?"

अपूर्ण महत्त्वाकांक्षा ने लेविस की राजनीतिक टेक निश्चित करने में चाहे कुछ भी भाग अदा किया हो, १९४० तक उसने अपना यह दृढ़ मत बना लिया कि रूज़वेल्ट अब औद्योगिक लोकतंत्र के महान् चैम्पियन नहीं रहे जिनके समर्थन में चार वर्ष पूर्व उसने समस्त मज़दूरों का आह्वान किया था। अब उसने सरकार पर मज़दूरों के ध्येय के साथ दगा देने और मंत्रिमण्डल अथवा नीति का निश्चय करने वाली किसी सरकारी एजेंसी में मज़दूरों को प्रतिनिधित्व देने से इन्कार करने का आरोप लगाया। जनवरी में यूनाइटेड माइन वर्कर्स के एक सम्मेलन में उसने बड़े नाटकीय ढंग से राष्ट्रपति के साथ अपने सब पूर्व-सम्बन्ध तोड़ लिए। उसने अचम्भित श्रोताओं से कहा : "अगर डैमोक्रैटिक नेशनल कमेटी को मजबूर करके रूज़वेल्ट की पुनः नामज़दगी कर दी गई तो मुझे विश्वास है कि उन्हें अपमानजनक हार खानी पड़ेगी।"

लेविस एक खतरनाक खेल खेल रहा था। उसका मार्ग यह प्रतीत होता था कि डैमोक्रेटिक पार्टी को सर्वथा एक मज़दूर दल में परिवर्तित करने में, जिसमें वह खुद रूज़वेल्ट का सम्भावित उत्तराधिकारी हो, असफल रहने के बाद उसका यह विचार हो गया था कि मज़दूरों की नान-पार्टिज़न लीग को एक तीसरी पार्टी के रूप में विकसित किया जाए जो १९४४ में उसकी राजनीतिक महत्त्वकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बने। सी. आई. ओ के अन्य नेताओं के साथ झगड़े और वामपक्षी तथा कम्युनिस्ट ग्रुपों के साथ उसके निकट सम्बन्धों में यही सारा मामला उलझा हुआ था। इसका सम्बन्ध उस टेक से भी था जो उसने विदेश नीति के बारे में अपनाई थी। क्योंकि यूरोप में युद्ध छिड़ने के बाद लेविस पृथकतावादी कैम्प में चला गया था और मित्र राष्ट्रों को सहायता देने के समस्त कार्यक्रम का सरोष विरोध करने लगा। किन्तु व्यक्तिगत विद्वेष तथा राजनीतिक निराशा के बजाय विदेश नीति किस हद तक उसके रूज़वेल्ट के पक्ष को छोड़ देने के लिए जिम्मेदार थी, यह शायद ऐसा सवाल है जिसका स्वयं लेविस भी ईमानदारी से कोई जवाब नहीं दे सकता था।

कुछ भी हो, १९४० का चुनाव आन्दोलन जैसे-जैसे अग्रसर हुआ, उसने खुल्लमखुल्ला रूज़वेल्ट का विरोध किया। उसने कहा कि न्यू डील आर्थिक पुनरुत्थान के कार्य में बिल्कुल विफल रहा है, बल्कि मन्दी को लम्बी खींचने के

लिए एकमात्र यही जिम्मेदार है। कुछ समय तक तो उसने यह जाहिर नहीं किया कि उसके द्वारा रूजवेल्ट के विरोध का मतलब क्या रिपब्लिकन उम्मीदवार वेण्डल विल्की का समर्थन है ? किन्तु २५ अक्तूबर को उसने रेडियो पर जो भाषण किया उससे उसकी स्थिति के बारे में रहा सहा संदेह दूर हो गया। इस भाषण का समय इस दृष्टि से बहुत सावधानी से चुना गया था कि उसका नाटकीय प्रभाव हो।

लेविस ने कहा : "मैं समझता हूँ, राष्ट्रपति रूजवेल्ट का तीसरी बार चुना जाना प्रथम दर्जे की राष्ट्रीय बुराई होगी। अब वह लोगों की पुकार नहीं सुनते। मैं समझता हूँ कि देश की आवश्यकताओं की दृष्टि से वेण्डल विल्की का चुनाव अपरिहार्य है। मैं मजदूर स्त्री-पुरुषों को उन्हें वोट देने की सिफारिश करता हूँ......।

"यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट तीसरी बार तब तक नहीं चुने जा सकते जब तक उन्हें मजदूर स्त्री-पुरुषों के वोट अत्यधिक संख्या में प्राप्त न हों। इसलिए अगर वह फिर चुन लिए जाते हैं तो मैं समझूँगा कि सी. आई. ओ. के सदस्यों ने मेरी सलाह और सिफारिश को ठुकरा दिया है। इसे मैं अपने प्रति अविश्वास का मत समझूँगा और नवम्बर में सी. आई. ओ. के अध्यक्ष पद से हट जाऊँगा।"

किन्तु मजदूर स्त्री-पुरुषों ने अपनी राय लेविस को नहीं बनाने दी। पिछले वर्षों की भाँति १९४० में भी मजदूरों के वोट थाली में रखकर नहीं दिए जा सकते थे। सी. आई. ओ. के अध्यक्ष की चेतावनी को दरगुजर कर उसके बहुत से साथियों ने खुल्लमखुल्ला डैमोक्रैटिक उम्मीदवार का समर्थन किया और एक के बाद एक यूनियन ने तीसरे कार्यकाल के पक्ष में प्रस्ताव पास किए। ए. एफ. एल. के अधिकांश नेताओं और यूनियनों ने भी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का समर्थन किया और इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले दो आम चुनावों की भाँति इस चुनाव में भी मजदूरों के वोट ने रूजवेल्ट को जिताने में बहुत महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया। खान वाले इलाकों में भी जहाँ लेविस के आदेश का आँख मूँद कर पालन किया जाता था, पता चला कि यूनाइटेड माइन वर्कर्स तक के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजनीति में उसकी सलाह मानने से इन्कार कर दिया।

लेविस की घोषणा के सुखद विरोध में चुनावों के बाद ग्रीन ने घोषणा

की कि मज़दूर स्त्री-पुरुषों ने रूज़वेल्ट को इसलिए [illegible] विश्वास करते हैं कि "वह सामाजिक न्याय तथा आर्थिक स्वाधीनता के मित्र और चैम्पियन हैं।"

लेविस ज़रूरत से ज्यादा आगे बढ़ गया था। मज़दूरों द्वारा निर्देश का पालन किए जाने के प्रश्न पर सी. आई. ओ. की अध्यक्षता को दांव पर लगा कर वह न केवल राजनीतिक क्षेत्र से बिल्कुल बाहर चला गया बल्कि जिस संगठन का निर्माण करने के लिए उसने इतना त्याग किया उसका नियंत्रण भी उसने छोड़ दिया क्योंकि अगले सम्मेलन में सी. आई. ओ. की अध्यक्षता से निवृत्त होने की उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मज़दूरों की सभाओं में वह अब भी एक शक्तिशाली प्रभाव डालने में समर्थ था किन्तु उसके चामत्कारिक जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया था। क्योंकि बाद की अपनी गति-विधियों में उसने जो भी चुनौती भरी स्वाधीनता और नाटकीयता प्रदर्शित की, और युद्धकाल में तथा उसके बाद एक हड़ताली नेता के रूप में उसने जो कुछ भी उत्तेजना पैदा की, उस सबके बावजूद वह सी. आई. ओ. के अध्यक्ष के समय की सत्ता और प्रतिष्ठा को फिर प्राप्त नहीं कर सका।

बेशक वह युनाइटेड माइन वर्कर्स का मुखिया बना रहा और जहां तक यूनियन मामलों का सम्बन्ध है उसके सदस्य जहां लेविस गया, उसका अनुगमन करते रहे। यह एक हास्यास्पद भाग-दौड़ रही। लेविस ने उन्हें तीव्रता से सी. आई. ओ. से निकाल लिया और फिर समय रहते ए. एफ. एल. में ले गया। खनिकों को अपनी स्थिति का ठीक-ठीक पता भी न था। लेविस ने स्वयं निश्चय कर साथियों या अनुयायियों के विचार को धता बता दिया। १९४७ के अन्त में खनिकों ने स्वयं को फिर अकेला अनजाने मार्ग पर भटकता पाया जब कि उनका अस्थिरमति सरदार दूसरी बार ऐसे झटके के साथ ए. एफ. एल. से बाहर आ गया जो उसके अपने लिये भी आश्चर्यजनक था। युनाइटेड माइन वर्कर्स के प्रधान कार्यालय में रिपोर्टरों को बुला कर ४ इंच लम्बे तथा दो इंच चौड़े कागज के पुर्जे पर नीली पेंसिल से लिखा एक सन्देश दिखाया गया जिसमें कहा गया था : "ग्रीन, ए. एफ. एल.। हम अलग होते हैं। लेविस १२।१२।४७"

१९४० में सी. आई. ओ. का नया अध्यक्ष एस. डब्लू. ओ. सी. के संगठन

अभियान का हीरो और युनाइटेड माइन वर्कर्स में इतने वर्षों से लेविस क सुयोग्य और वफादार लेफ्टिनेण्ट फिलिप मरे चुना गया। उसकी पृष्ठभूमि ग्रीन और लेविस दोनों से इस बात में बिल्कुल मिलती थी कि उसका परिवा भी ब्रिटिश कोयला खानों में काम करता था। किन्तु स्वयं मरे का जन १८८६ में लंकाशायर (स्काटलैण्ड) में हुआ था और १६ वर्ष का हो जा पर ही वह अमरीका आया। तब उसने खानों में काम करने की पारिवारि परम्परा निबाही। दो वर्ष बाद प्रबन्धकों के साथ उसे पहली कठिनाई भुगतन पड़ी और एक हड़ताल में भाग लेने के कारण उसका काम छूट गया। उस लिखा कि "तब से मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं रहा कि मुझे अपने जीव में क्या करना है।"

१९१६ में वह युनाइटेड माइन वर्कर्स के जिला नं० ५ का अध्यक्ष चुन गया और ४ वर्ष बाद अन्तरजियीय यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया। वह एव अत्यन्त योग्य प्रशासक और संगठनकर्ता के रूप में मशहूर था किन्तु उसर्क प्रसिद्धि का इससे भी बड़ा कारण शायद यह था कि दुर्दिन हो या सुदिन, उसने अपने मुखिया द्वारा निर्धारित नीति का सदा निष्ठापूर्वक समर्थन किया सामाजिक सुधार के व्यापक विचारों में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई किन्तु उसका यह पूर्ण विश्वास था कि किसी भी प्रकार के व्यवसाय के साथ यह ज़रूरी है कि मज़दूर को अच्छा वेतन पाने का हक हो। उसके मत में इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मज़दूर संगठन और सामूहिक सौदेबाजी ज़रूरी थे।

शान्त और स्वयं को प्रकाश में न लाने वाले मरे को चिरकाल तक लेविस की छाया से अधिक नहीं समझा जाता था। किन्तु जब वह सी. आई. ओ. का अध्यक्ष बन गया तब उसने स्वयं को ऐसा दृढ़ विचारों और अत्यन्त स्वाधीन प्रकृति का व्यक्ति ज़ाहिर किया कि वह अपने लिए एक अलग मार्ग बना सका और उस पर चल सका। भले ही उसके कारण उस व्यक्ति के साथ उसके सम्बन्ध टूट गए जिसकी वह सबसे ज्यादा कद्र करता था और जिसके प्रति बाद में भी वह गहरा आदर व्यक्त करता रहा। जैसा कि समय ने दिखाया, मरे में वह खूबियाँ थीं जिन्होंने उसे एक दृढ़ आस्थाओं वाला मज़दूर नेता ज़ाहिर किया जो अपने साथियों की महान् व्यक्तिगत वफ़ादारी भी प्राप्त कर सका।

अपनी स्वतंत्रता का पहला और अप्रत्याशित प्रदर्शन उसने तब किया जब सी. आई. ओ. का अध्यक्ष बनने के लिये उसने यह शर्त रखी कि सम्मेलन कम्युनिज्म तथा अन्य सब विदेशी विचारधाराओं की निन्दा का एक प्रस्ताव पास करे। वामपक्ष के साथ लेविस ने गुपचुप रूप से जो सम्बन्ध बना रखे थे उसके कारण मरे रिकार्ड साफ करने पर आमादा था। उसका इरादा सभी कम्युनिस्टों और उनके अनुयायियों को संगठन से निकाल देने का नहीं था और न ही वह यह चाहता था कि कम्युनिस्टों के अत्यधिक पीछे पड़कर मजदूर आन्दोलन को नुकसान पहुँचाया जाए। किन्तु वह कम्युनिज्म के सख्त खिलाफ था और सी. आई. ओ. को उसने विध्वंसक राजनीतिक हरकतों का मोर्चा बनाने देने से इन्कार कर दिया। इसी स्वतंत्र भावना के साथ उसने पृथकतावाद को ठुकरा दिया जिसका लेविस और कम्युनिस्ट दोनों उपदेश दे रहे थे। युद्ध में अमरीका के प्रवेश का वह अब भी विरोधी था किन्तु रूजवेल्ट की विदेश-नीति तथा रक्षा-कार्यक्रम का समर्थन करने को उद्यत था। यह उसका अपना निर्णय था। एक वर्ष बाद उसने सी. आई. ओ. के सम्मेलन में कहा "जिन बातों की मैंने सिफारिश की उनको मैंने अन्दर या बाहर के किसी ग्रुप के दबाव के कारण नहीं अपनाया था। आप जानते हैं मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो व्यक्तियों अथवा ग्रुपों द्वारा दबाव डाले जाने का विरोधी हूँ। मैं मनुष्य के रूप में अपने व्यक्तिगत चरित्र का भरोसा करता हूँ।"

प्रोत्साहन दिया। अमरीका ने युद्ध में घसीटे जाने का तात्कालिक खतरा महसूस किया किन्तु इस बीच वह अभूतपूर्व समृद्धि का आस्वादन करने लगा था।

मज़दूरों ने कई तरीकों से इन घटनाओं का प्रभाव महसूस किया। उत्पादन वृद्धि से वेकारी तेजी से घटी जो रूज़वेल्ट प्रशासन के यथासंभव सब कुछ किए जाने पर भी ऊँचे स्तर पर कायम थी और इससे वेतन दरों में भी वढ़ोत्तरी हुई। रक्षा उद्योगों में दक्ष मज़दूरों की वढ़ती हुई माँग से मज़दूर वाज़ार में एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई जो १० वर्षों से चली आ रही परिस्थितियों से वहुत भिन्न थी। अप्रैल, १९४० और दिसम्वर, १९४१ के वीच कृषि से इतर धन्धों में लगे लोगों की संख्या ३५० लाख से वढ़ कर ४१० लाख से अधिक हो गई और मज़दूरी की दर सामान्यतः २० प्रतिशत वढ़ गई। रक्षा कार्यक्रम के लिए वुनियादी, जल्दी नष्ट न होने वाले सामान के उद्योगों में औसत आमदनी २९·८८ डालर से वढ़ कर ३८·६२ डालर साप्ताहिक हो गई। युद्ध अमरीकी उद्योग की रक्षा करने आया था और ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. दोनों के संगठित मज़दूरों ने युद्धकालीन धन्धे के वढ़ते हुए मुनाफ़ों में पर्याप्त हिस्सा वँटाया।

मज़दूर अमरीका को "लोकतंत्र का महान् शस्त्रागार" वनाने में पूर्ण सहयोग देने के लिए उद्यत थे किन्तु १९२० की दशाव्दी की पराजयों और धक्कों को याद करके इस वात का आग्रह भी कर रहे थे कि न्यू डील के अन्तर्गत प्राप्त लाभों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यूनियन मान्यता और सामूहिक सौदेवाज़ी के विस्तार का अभियान चलाने के अपने अधिकार पर ज़ोर दिया और जव युद्धकालीन परिस्थितियों में महँगाई तेज़ी से वढ़ी तो मज़दूरों की क्रयशक्ति को वनाए रखने के लिए और ज्यादा वेतन वृद्धि की माँग की। उद्योग फल फूल रहे थे और यूनियनों की ताकत वढ़ रही थी, फलस्वरूप प्रवन्धकों और मज़दूरों में हमारे विकासमान अर्थ तंत्र में अपने रोल को लेकर और संघर्ष के लिए मंच तैयार हो गया। १९४१ का वर्ष मज़दूर इतिहास में एक वड़ा विक्षोभ और हलचल पूर्ण वर्ष रहा।

अधिकांश मामलों में मज़दूर युक्तियुक्त तथा रचनात्मक नीतियों पर चल

रहे थे और उद्योग ने सामूहिक सौदेबाज़ी के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए, वेतन, काम के घण्टों तथा काम की हालतों के बारे में परस्पर लाभदायक समझौते करके उनका आधे रास्ते स्वागत किया। लिटस स्टील कम्पनियों तथा यूनाइटेड स्टील वर्कर्स आव अमरीका में अन्ततः समझौता हो गया और हेनरी फोर्ड ने अपनी यूनियन विरोधी नीतियों को एकदम उलट कर यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स को मान्यता देने और उसे 'बन्द शाप' भी प्रदान करने के एक करार पर दस्तखत कर दिए। किन्तु औद्योगिक संघर्ष को टालने के लिए की गई ये प्रगतियाँ शीघ्र ही नए झगड़े उत्पन्न होने से तिरोहित हो गईं। कुछ मामलों में ये झगड़े यूनियनों की अत्यधिक और अनधिकार माँगों के कारण उत्पन्न हुए तो अन्य मामलों में नई औद्योगिक व्यवस्था के परिणामों को स्वीकार करने से इन्कार करने वाले मालिकों के दुराग्रह के कारण उत्पन्न हुए।

यूनियनों की बढ़ती हुई शक्ति को भूत मानकर कुछ कम्पनियों ने न केवल वेतन सम्बन्धी नई माँगें स्वीकार करने से ही इन्कार कर दिया, बल्कि हर तरह से मजदूरों के पंख बाँध देने की कोशिश की। इस ग्रुप ने यूनियन मान्यता के बारे में और रियायतें देने से इन्कार कर दिया, बन्द शाप को लोकतंत्र-विरोधी और अमरीका विरोधी बताकर उसकी आलोचना की और जहाँ कहीं संभव हुआ सामूहिक सौदेबाज़ी की कानूनी आवश्यकताओं की अवहेलना की। कभी-कभी उन्होंने अपनी यूनियन-विरोधी हरकतों पर यह कहते हुए कि उनका उद्देश्य सिर्फ औद्योगिक उत्पादन को निर्बाध बनाए रखना है, देशभक्ति का मुलम्मा चढ़ाने की भी कोशिश की।

राष्ट्रीय रक्षा की आवश्यकताओं ने वस्तुतः मजदूरों की माँगों के प्रति जनता को अधीर बना दिया और मजदूरों में व्यापक आन्तरिक झगड़ों के कारण भी उनके ध्येय को कोई सहायता नहीं मिली। प्रतिद्वन्द्वी नेताओं के रोष भरे आरोप-प्रत्यारोपों ने अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी हड़तालों तथा यूनियनों में ठगी तथा भ्रष्टाचार के कुछ मामलों के भण्डाफोड़ ने बढ़ते हुए राष्ट्रीय संकट में मज़दूरों की जिम्मेदारी की भावना पर से लोगों का विश्वास डिगा दिया और यह सही है कि कुछ नई विद्रोही यूनियनें अपने हज़ारों नए रंगरूटों में अनुशासन नहीं रख पाईं। मालिकों के प्रति उनके झगड़ालू बर्ताव और वेतन वृद्धि तथा

अन्य रियायतों पर उनके हठ ने अनेक मौकों पर औद्योगिक शांति को उसी प्रकार भंग किया जिस प्रकार प्रतिक्रियावादी व्यवसाय की यूनियन-विरोधी नीतियों ने।

१९४१ में श्रम सम्बन्धी झगड़ों की संख्या सिर्फ १९३७ के एक अपवाद को छोड़कर पिछले किसी भी वर्ष से ज्यादा थी। मोटर उद्योग, जहाज़ घाट, परिवहन, मकान-निर्माण, कपड़ा, इस्पात व खान उद्योगों में हड़तालें हुईं। शायद ही किसी उद्योग में काम न रुका हो और जिसने कम से कम कुछ समय के लिए उत्पादन में रुकावट न डाली हो। राष्ट्र के लगभग ८·४ प्रतिशत मजदूरों ने उन हड़तालों में भाग लिया। और काम के २,३०,००,००० मनुष्य-दिवसों की हानि हुई।

कई हड़तालें साम्यवादियों ने भड़काई थीं। जब तक जर्मनी ने रूस पर हमला नहीं कर दिया, तब तक पार्टी लाइन मित्र-राष्ट्रों के सहायता देने के सख्त खिलाफ रही और राष्ट्रीय रक्षा के कार्यक्रम में पलीता लगाने के लिए क्रांतिकारी वामपंथियों ने कोशिश की। जून, १९४१ के बाद एक बार फिर इस नीति में रातों-रात परिवर्तन हुआ। कम्युनिस्टों द्वारा भड़काई गई हड़तालो ने, जिन्हें रोकने की जिम्मेदार मज़दूर नेताओं ने भरसक कोशिश की, इस वर्ष के प्रथमार्ध में मज़दूर-उपद्रव भड़काने में कम भाग नहीं लिया।

इन हड़तालों से रक्षा-कार्यक्रम को ठेस पहुँचने की आशंका के कारण मार्च, १९४१ में ही एक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा मध्यस्थता बोर्ड (नेशनल डिफेंस मीडिएशन बोर्ड) की स्थापना की गई। यह एक त्रिपक्षीय निकाय था जिसमें मज़दूरों, प्रबन्धकों तथा जनता के प्रतिनिधि थे। इसे रक्षा-उद्योगों में मध्यस्थता अथवा पंचफैसले के जरिये झगड़ों को हल करने का अधिकार दिया गया। इसके अधिकारों में किए गए निर्णयों पर अमल कराने का अधिकार शामिल नहीं था। इसलिए यद्यपि बहुत-से मामलों में वह औद्योगिक शांति स्थापित करा सका तो भी कई महत्त्वपूर्ण अवसरों पर ज्यादा कठोर कार्रवाई की ज़रूरत पड़ी।

इंगलवुड, कैलिफोर्निया में वैमानिक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण [illegible]ता के ज़रिये समझौता कराने से पूर्व ही युद्ध के महकमे ने नार्थ [illegible] ऐवियेशन प्लाण्ट को अपने कब्जे में ले लिया और कीर्नो, न्यूजर्सी में

जब फेडरल शिप बिल्डिंग ऐण्ड ड्राई डाक कम्पनी ने यूनियन की सदस्यता को कायम रखने के प्रस्तावित समझौते को मानने से इन्कार कर दिया और जहाज़ी घाट के मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो नौसेना विभाग ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। किन्तु श्रम सम्बन्धी झगड़ों तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा मध्यस्थता बोर्ड की मुसीबतों दोनों की चरम अवस्था एक कोयला हड़ताल में पहुँची जिसने उत्पादन में इतनी गम्भीर अड़चन उत्पन्न की कि सम्पूर्ण रक्षा कार्यक्रम को ही खतरा पैदा हो गया।

इस्पात उद्योग द्वारा चलाई जाने वाली तथाकथित "अधिकृत" कोयला खानों में यूनियन शाप की स्थापना का प्रश्न मुख्यतः विवादास्पद था। प्रतिरक्षा मध्यस्थता बोर्ड यूनियन करारों में इस प्रकार की माँग को शामिल कराने की प्राथमिकता के बारे में दुविधा में रहा और १९४१ की पतझड़ में जब खान का यह झगड़ा कार्रवाई के लिए उसके सामने रखा गया तो उसने यूनियन शाप को करार का आधार स्वीकार करने से इंकार कर दिया। फलस्वरूप लेविस ने बोर्ड की उपेक्षा कर दी और राष्ट्रपति रूज़वेल्ट की इस अपील के बावजूद कि देश का एक वफादार नागरिक होने के नाते उसे देश की सहायता करनी चाहिए, उसने २६ अक्तूबर को "अधिकृत" कोयला खानों में हड़ताल का आह्वान किया और करीब-करीब समस्त इस्पात उद्योग को बन्द कर देने की धमकी दी।

लेविस द्वारा सरकार को दी गई चुनौती का कोयला खनिकों के अधिकारों की रक्षा से ज्यादा महत्त्व था। लेविस मज़दूरों की एक नाटकीय विजय से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का यत्न कर रहा था और एक स्पष्टवक्ता पृथकतावादी के रूप में विदेशी मामलों में समस्त रूज़वेल्ट कार्यक्रम के प्रति अपना विरोध प्रकट कर रहा था। उसने १९४० में राजनीतिक क्षेत्र में रूज़वेल्ट का विरोध किया था और अब एक वर्ष बाद वह उन्हें आर्थिक क्षेत्र में चुनौती देने के लिए तैयार था। यूनियन शाप के लिए संघर्ष को सत्ता की कसौटी बना लिया गया और देश की आवश्यकताओं तथा अपने तौर-तरीकों के प्रति सार्वजनिक विरोध की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए लेविस अपने मनमाने रास्ते पर जाने को उद्यत था।

हड़ताल का आह्वान किए जाने के तुरन्त बाद रूज़वेल्ट ने रेडियो पर वह

घोषणा की कि देश को कोयला प्राप्त करना ही होगा और "मज़दूर नेताओं की एक अल्प किन्तु खतरनाक संख्या द्वारा डाले जाने वाली स्वार्थपूर्ण बाधाओं से राष्ट्रीय उत्पादन में रुकावट नहीं आने दी जा सकती।" इस बात के संकेत मिले कि वह अंततः हड़ताल-विरोधी कानून को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसका कांग्रेस में पहले से ही प्रस्ताव किया जा रहा था। किन्तु इस बीच लेविस युनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन के माइरन सी. टेलर से समझौतावार्ता कर रहा था, जिसमें यह तय हो गया कि प्रतिरक्षा मध्यस्थता बोर्ड यूनियन शाप के मामले पर फिर विचार करेगा, किन्तु कोई भी पक्ष उसके फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। लेविस को विश्वास था कि देश को तत्काल कोयले की आवश्यकता होने के कारण अब उसकी माँगें स्वीकार करनी होंगी और उसने जब तक बोर्ड इस मामले पर पुनर्विचार करे तब तक के लिए हड़ताल उठा ली।

बोर्ड ने १० नवम्बर को अपना फैसला दिया और ९—२ मतों से यह यूनियन शाप के खिलाफ गया। इसकी रिपोर्ट के खिलाफ सिर्फ बोर्ड में सी. आई. ओ. के दो सदस्यों ने ही मत दिया, जबकि प्रबन्धकों, जनता और ए. एफ. एल. के सब प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट का समर्थन किया। अधिकृत कोयला खानों में ५३००० मज़दूरों में से ९५ प्रतिशत पहले ही युनाइटेड माइन वर्कर्स के सदस्य थे किन्तु यह कहा गया कि यूनियन शाप सामूहिक सौदेबाजी की चीज़ है, वह सरकार के आदेश से स्थापित नहीं की जा सकती और प्रतिरक्षा मध्यस्थता बोर्ड के लिए २,५०० मज़दूरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध यूनियन में शामिल होने के लिए मजबूर करना उचित नहीं होगा।

एक सिद्धान्त दाँव पर लगा हुआ था और लेविस तथा राष्ट्रपति के बीच भिड़न्त अनिवार्य प्रतीत हुई। खनिकों के नेता ने विरामसंधि की अवधि के पश्चात् फिर से हड़ताल कराने का आदेश वापस लेने से इन्कार कर दिया और सी. आई. ओ. ने अपने नेताओं में पारस्परिक कलह के बावजूद लेविस का समर्थन किया। प्रतिरक्षा मध्यस्थता बोर्ड में इसके प्रतिनिधियों ने तुरन्त त्यागपत्र दे दिया और उस समय चल रहे एक सम्मेलन के प्रस्ताव में लेविस के पक्ष का समर्थन किया गया। दूसरी ओर रूज़वेल्ट ने यह घोषणा की कि सरकार किसी भी हालत में यूनियन शाप स्थापित करने का आदेश जारी नहीं

करेगी, कर्मचारियों और इस्पात कम्पनियों के बीच और वार्ता किए जाने का आग्रह किया और साथ ही समझौता न होने की सूरत में खानों पर सरकार द्वारा कब्जा कर लिये जाने की तैयारी की। इस समय कांग्रेस तटस्थता सम्बन्धी कानून में संशोधन पर विचार कर रही थी और अपने विदेश संबन्धी कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के उन सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, जो यह महसूस कर रहे थे कि राष्ट्रपति मज़दूरों के प्रति बहुत नरम हैं, राष्ट्रपति ने यह वायदा किया कि लेविस चाहे कुछ भी करे, कोयला खानों से निकाला जाएगा। "सरकार इसके लिए कृतसंकल्प है।"

इसके बाद एक सप्ताह तक समझौता वार्ताओं का दौरदौरा रहा। देश समझौते के लिए पुकार रहा था किन्तु यूनियन शाप के मामले पर न तो खनिक और न ही इस्पात कम्पनियाँ टस से मस हुई। १७ नवम्बर को हड़ताल फिर शुरू हो गई। अधिकृत खानों में मज़दूरों ने अपने औज़ार रख दिए और अन्य क्षेत्रों में सहानुभूति में की गई हड़तालों से काम बन्द करने वाले मज़दूरों की संख्या शीघ्र ही २,५०,००० हो गई। राष्ट्रीय संकट के तेज़ी से चरम अवस्था में आ जाने से इस्पात उद्योग के हाथ-पाँव बँध गए थे। बताया जाता है कि रूज़वेल्ट अन्ततः ५० हजार सैनिकों को खानों पर कब्जा करने का आदेश देने को तैयार हो गए और स्थिति प्रति घण्टे अधिक तनावपूर्ण होती गई। तब यकायक और अप्रत्याशित रूप से २२ नवम्बर को हड़ताल वापस ले ली गई। लेविस ने तीन व्यक्तियों के न्यायाधिकरण द्वारा यूनियन शाप के मामले पर किए गए पंच फैसले को स्वीकार करने का राष्ट्रपति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। इस अधिकरण में तीन व्यक्ति नियुक्त किए गए, लेविस, युनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन के अध्यक्ष फेयरलेस और निष्पक्ष सदस्य के रूप में युनाइटेड स्टेट्स कान्सिलियेशन सर्विस के जॉन आर. स्टीलमैन।

क्या लेविस ने घुटने टेक दिए थे? उसके यकायक इस कदम के उठाने का रहस्य था अधिकरण में तीसरे व्यक्ति की स्थिति। स्टीलमैन मज़दूरों का दोस्त था और बताया जाता है कि उसे यूनियन शाप के प्रति सहानुभूति थी। खनिकों के सरदार को विश्वास था कि उसका निर्णय क्या होगा और बाद की घटनाओं ने उसका यह विश्वास सत्य सिद्ध कर दिखाया। रूज़वेल्ट ने हार मान ली थी। नए पंच-फैसला न्यायाधिकरण की नियुक्ति का वास्तविक

अभिप्राय प्रतिरक्षा मध्यस्थता बोर्ड को मंसूख करना और लेविस की माँग को स्वीकार करना था। हड़ताल वापस ले ली गई, कोयला खानों से निकाला जाने लगा किन्तु सरकार की सत्ता का निधड़क उल्लंघन किया गया। गम्भीर राष्ट्रीय संकट ने राष्ट्रपति को यह विश्वास करा दिया था कि रक्षा कार्यक्रम को अब और खतरे में नहीं डाला जा सकता, भले ही उसका मतलब लेविस की इच्छा-पूर्ति करना हो। लेकिन यह जो परिपाटी कायम हुई इसके आगे चलकर बड़े गम्भीर परिणाम हुए।

कोयले की हड़ताल से जनता में मज़दूरों के विरुद्ध भावना ज़ोर पकड़ने लगी। यह भावना तभी से देश भर में छाने लगी थी जब रक्षा उद्योगों में इससे पहली हड़तालें प्रारंभ हुई। वर्ष के प्रथमार्ध की हड़तालों ने और खासकर उन्होंने, जो साम्यवादियों ने भड़काई थीं, आशंकित युद्ध के लिए तेजी से हथियारबन्द होते हुए राष्ट्र को कुपित कर दिया था। अखबारों के अग्रलेखों, राष्ट्रीय नेताओं के वक्तव्यों और लोकमत संग्रहों, सभी में मज़दूरों के प्रति सख्त होता हुआ रवैया ज़ाहिर हुआ। कांग्रेस के अन्दर और उसके बाहर यूनियनों की ताकत को कम करने और औद्योगिक उत्पादन में और रुकावटों के खिलाफ लोकहित की रक्षा के लिए नए कानून की माँग की जाने लगी। कोयला हड़ताल और लेविस द्वारा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा मध्यस्थता बोर्ड तथा राष्ट्रपति की सत्ता को चुनौती दिए जाने के भयावह दृश्य ने इस कार्य को तेज़ कर दिया। २२ राज्यों में विभिन्न सख्तियों के मज़दूर-विरोधी कानून बनाए जा चुके थे और यूनियनों पर अंकुश लगाने के कोई ३० बिल कांग्रेस में रखे गए।

कोयला हड़ताल और अन्य मजदूर-अव्यवस्थाओं पर, जिनमें बाल-बाल बची रेलवे हड़ताल भी शामिल थी, अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में प्रतिनिधि सभा नें ३ दिसम्बर को इनमें से एक मजदूर-विरोधी बिल १३६ के विरुद्ध २५२ मतों से पास कर दिया। इसके द्वारा रक्षा उद्योगों में बन्दशाप को लेकर या अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी झगड़ों के कारण कोई भी हड़ताल करने पर पाबन्दी लगाने की बात कही गई थी, जब तक कि ३० दिन के शांत वातावरण के बाद सरकार की निगरानी में कराए गए चुनावों में बहुसंख्यक मज़दूर उस हड़ताल के पक्ष में मत न दें। बिल की ग्रीन ने 'उत्पीड़न का साधन' कह कर निन्दा

की। मर्रे ने कहा कि "अमरीकी लोकतंत्र में इससे ज्यादा विध्वंसक बिल कभी तैयार नहीं किया गया।" ऐसा लगा कि सेनेट इसकी धाराओं में कुछ संशोधन कर देगी और राष्ट्रपति अपेक्षाकृत नरम कानून पास करने के पक्ष में थे लेकिन इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि शीघ्र ही कोई न कोई ऐसा बिल पास किया जाएगा जो रक्षा-तैयारियों में बाधा डालने वाली अनवच्छिन्न हड़तालों के "राष्ट्रीय संकट" का सामना कर सके।

देश कुपित था। मज़दूरों के दोस्तों ने भी इस डर से कि यूनियनों के खिलाफ लोकमत के रोष के कारण वागनर ऐक्ट में दिए गए मूल अधिकारों में ही कोई कटौती न कर दी जाए, ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. के नेताओं को ज्यादा नरमी से काम लेने की सलाह दी। 'न्यू रिपब्लिक' ने अपने अग्रलेख में लिखा: "इस देश में यूनियन आन्दोलन अब एक बच्चा नहीं रहा जिसे संरक्षण की ज़रूरत हो। यह वयस्क हो गया है और एक जिम्मेदार वयस्क की तरह काम करे। इसके लिए यह ज़रूरी है कि यह भी उसी सामाजिक अनुशासन द्वारा नियंत्रित हो जिससे शेष समाज नियंत्रित है।"

१९४१ में जनता की इस प्रतिक्रिया के कारण यह पेण्डुलम किस सीमा तक मज़दूरों के खिलाफ जाता इसका पता लगाना मुश्किल है क्योंकि नई घटनाएँ नाटकीय शक्ति के साथ बीच में आ कूदीं। ७ दिसम्बर को ही, जब कि पंच-फैसला न्यायाधिकरण ने कैप्टिव कोयला खानों में लेविस को यूनियन-शाप प्रदान करने की घोषणा की थी और प्रतिनिधि सभा द्वारा पास किया गया हड़ताल-विरोधी बिल सेनेट में विचारार्थ उपस्थित था, जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। राष्ट्र ने स्वयं को युद्ध-ग्रस्त पाया।

१८ : दूसरा विश्व-युद्ध

पर्ल हार्वर पर आक्रमण ने रातों-रात ऐसी राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा कर दी जैसी देश ने पहले कभी नहीं देखी थी। प्रशान्त महासागर में युद्ध छिड़ जाने से और जर्मनी तथा इटली द्वारा करीब-करीब तुरन्त ही युद्ध-घोषणा कर दिए जाने के वाद राष्ट्रीय रक्षा की परम आवश्यकता के अलावा सब कुछ भुला दिया गया। युद्ध से अलग रहने और युद्ध में कूद पड़ने के हामियों में वाद-विवाद का तुरन्त अंत हो गया, राजनीतिक मतभेद दफना दिए गए और मज़दूर नेताओं ने सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय ध्येय के प्रति अपनी पूर्ण वफादारी का वचन दिया। लेविस ने कहा : "जब राष्ट्र पर हमला किया गया है तब प्रत्येक अमरीकी को उसकी रक्षा में जुट जाना चाहिए। और सब बातें गौण हो गई हैं......।"

देश-भक्ति का यह सुन्दर जोश सदैव इस ऊँचे स्तर पर कायम नहीं रहा। यद्यपि जर्मनी और जापान के साथ लड़ाई की सम्पूर्ण अवधि में अमरीकी समाज के सब वर्गों ने युद्ध-प्रयत्नों में निरन्तर सहयोग दिया किन्तु जब युद्धकालीन अर्थतंत्र राष्ट्र जीवन के सामान्य संतुलन को विगाड़ता प्रतीत हुआ तो उद्योग, मजदूर तथा किसान में से प्रत्येक ने एक साथ अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न किया। यूनियन-सुरक्षा, सरकारी एजेंसियों में प्रतिनिधित्व तथा वेतन और कीमतों के आपसी सम्बन्धों के वारे में मज़दूरों को चिन्ता होनी स्वाभाविक थी। उन्होंने अपनी युद्ध-पूर्व की शक्ति और प्रभाव को कायम रखने का दृढ़-निश्चय कर रखा था। हड़तालें हुईं, विशेषकर लेविस द्वारा बुलाई गई हड़तालें, जिन्होंने कुछ अरसे के लिए सैनिक साज-सामान की सप्लाई को गंभीर रूप से खतरा उत्पन्न कर दिया।

तो भी मज़दूरों से सम्बन्धित समग्र तसवीर बहुत अनुकूल रही। यूनियन के जिम्मेदार नेताओं ने हड़तालों की संख्या कम-से कम रखने की कोशिश की और जब वे हो ही जाती थीं तो उत्पादन में कम-से-कम रुकावट आने देने के खयाल से मज़दूरों को काम पर लौटाने की कोशिश करते थे। कोयला हड़तालों

को शामिल करके भी हड़तालों के कारण कुल उपलब्ध मनुष्य-दिवसों के ·१ प्रतिशत काम की ही हानि हुई जो उस समय के बाद से जब से इस सम्बन्ध में आँकड़े उपलब्ध हैं, शायद १९२९ और १९३० को छोड़कर सबसे अच्छा रिकार्ड था। इन हड़तालों में १९४२ से लेकर १९४४ तक के सम्पूर्ण अरसे में एक दिन प्रति मजदूर से अधिक काम का नुकसान नहीं हुआ।

किन्तु वस्तुतः उत्पादन को हड़तालों से ज्यादा खतरा मजदूरों की कमी, उनके स्थानान्तरण और गैरहाजिरी के कारण था, जो युद्धकालीन परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम थीं। असैनिक रोजगार बढ़ कर ५,३०,००,००० की संख्या पर जा पहुँचे जिनमें ६०,००,००० स्त्रियाँ थीं जिन्होंने ज्यादातर सेना में गए हुए सैनिकों का स्थान लिया था किन्तु कुछ क्षेत्रों में दक्ष कर्मचारियों के लिए नाजुक आवश्यकता बनी रही, यद्यपि उसे पूरा करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया गया। मनुष्य-शक्ति आयोग ने मजदूर प्राथमिकताओं और अनिवार्य सैनिक भरती के स्थगन की जटिल प्रणाली तैयार की किन्तु ऐसे मौके आए जब स्थल सेना व नौ सेना के रंगरूट भरती करने वाले अफसरों का भय और अखबारों की अतिशयोक्तिपूर्ण सुर्खियाँ यह दर्शाती प्रतीत होती थीं कि स्थिति बिल्कुल बेकाबू है।

१९४४ में रूजवेल्ट ने एक राष्ट्रीय सेवा अधिनियम की सिफारिश करने की भी आवश्यकता महसूस की जिससे औद्योगिक कर्मचारियों को सेना में जबरन भरती कर सकना सम्भव होता। किन्तु कांग्रेस ऐसा कदम उठाना नहीं चाहती थी और शीघ्र ही लड़ाई का रुख उत्तरोत्तर अधिक अनुकूल होते जाने के कारण ऐसे उग्र कदम का परित्याग कर दिया गया। मजदूरों पर ऐसे सख्त नियंत्रण लगाए बिना ही युद्ध समाप्त हो गया।

लड़ाई छिड़ने से काफी पहले आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करने वाली, सरकारी एजेंसियों में मजदूरों ने अपने प्रतिनिधित्व के अधिकार पर बल दिया था जो राष्ट्रीय संकट के कारण आवश्यक हो गया था। कुछ समय तक तो प्रशासन इस विषय में यूनियनों की सम्पूर्ण आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अनिच्छुक जान पड़ा और मजदूरों ने बार-बार शिकायत की कि नीति-निर्धारण के स्तरों पर उसकी उपेक्षा की जा रही है। किन्तु ए. एफ. एल तथा सी. आई. ओ. के इस प्रकार के सतत दबाव के फलस्वरूप युद्धकालीन अर्थतंत्र के संचालन

में मज़दूरों को अन्ततः प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान की अपेक्षा अब ज्यादा सरकारी मान्यता मिल गई और यह उनके नए प्रभाव का ज्वलन्त निदर्शन था।

सन् १९४१ में सिडनी हिलमैन ने, जिसे राष्ट्रपति ने इसलिए चुना था क्योंकि वह "जॉन लेविस तथा विल ग्रीन के बिल्कुल बीच का समझा जाता था" विलियम एस. कुण्डसेन के साथ उत्पादन प्रबन्ध कार्यालय में सह-निदेशक का काम किया। जब इस एजेंसी की जगह डोनाल्ड एम. नेल्सन की अध्यक्षता में युद्ध-उत्पादन बोर्ड कायम हुआ तो अनेक श्रम-सलाहकार समितियाँ कायम की गईं और मज़दूरों के प्रतिनिधियों ने उपाध्यक्ष का काम किया जिनके जिम्मे मनुष्य शक्ति की ज़रूरतें पूरी करने और मज़दूरों द्वारा उत्पादन बढ़ाए जाने का काम सुपुर्द था। १९४२ में चालू किए गए युद्ध-उत्पादन अभियान के दौरान जहाज़, विमान, टैंक और गोला-बारूद बनाने में, जिसकी देश को सख्त ज़रूरत थी और भी ज्यादा सहयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिये सम्पूर्ण देश भर के रक्षा उद्योगों में मज़दूर-प्रबन्धक समितियाँ भी कायम की गईं। इन समितियों का कुछ क्षेत्रों में विरोध किया गया। नेशनल ऐसोसियेशन आव मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष ने एक बार कहा : "उद्योगों के प्रबन्धक ही जब हमारी आर्थिक प्रणाली को भली भाँति चला रहे हैं, तब यह नया परीक्षण क्यों ?" किन्तु मालिकों व मज़दूरों के सम्मिलित रूप से उत्पादन बढ़ाने तथा छोटी-मोटी शिकायतें दूर कराने के लिए सहायता देने में ये वस्तुतः बहुत मूल्यवान सिद्ध हुईं। एक वर्ष के अन्दर-अन्दर युद्ध-सामग्री बनाने वाले कारखानों में, जिनमें ४० लाख कर्मचारी काम कर रहे थे, ऐसी १९०० समितियाँ स्थापित हो गईं और इनकी संख्या बाद में ५००० तक जा पहुँची।

मज़दूरों को युद्ध मनुष्य-शक्ति आयोग की मज़दूर-प्रबन्धक नीति समिति में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त था। मूल्य-प्रशासन तथा असैनिक प्रतिरक्षा कार्यालय दोनों में श्रम-नीति समितियाँ थीं तथा ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. के अध्यक्ष ६ आदमियों के आर्थिक स्थिरीकरण बोर्ड पर काम कर रहे थे। युद्ध-प्रयत्न के निचले स्तरों पर मूल्य तथा राशनिंग बोर्डों में यूनियन सदस्य नियुक्त किए गए, असैनिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम के विस्तार में उन्होंने भाग लिया और युद्ध-पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने में प्रभावशाली रोल अदा किया।

किन्तु इनमें किसी भी पद से कही ज़्यादा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय युद्ध-श्रम बोर्ड में मज़दूरों का प्रतिनिधित्व था, जो औद्योगिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालने वाले सम्पूर्ण युद्ध-कालीन कार्यक्रम के लिए एक बुनियादी चीज़ थी। इस एजेंसी को न केवल मज़दूरों तथा प्रबन्धकों के बीच झगड़े तय करने का काम सौंपा गया वल्कि वेतन और काम के घण्टों पर सामान्य नियंत्रण रखने को भी कहा गया। इसका इतिहास समस्त युद्ध-काल में ज़्यादातर वही रहा जो मज़दूरों का।

युद्ध-श्रम वोर्ड की उत्पत्ति मज़दूरों और व्यावसायिफ नेताओं के एक सम्मेलन से हुई जो राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने कांग्रेस के सामने पेश यूनियन विरोधी कानून को टालने और संभावित हड़तालों को कम करने के उद्देश्य से युद्धकालीन सहयोग का एक आधार स्थापित करने के लिये पर्ल हार्वर काण्ड के लगभग तुरन्त बाद वुलाया था। १७ दिसम्बर, १९४१ को वाशिंगटन में इसकी बैठक हुई और लम्बे विचार-विमर्श के बाद एक त्रि-सूत्री कार्यक्रम पर समझौता हो गया। ये तीन सूत्र थे : युद्ध के दौरान कोई हड़ताल और तालाबन्दी न हो, औद्योगिक विवाद शांति से निबटाए जाएँ तथा जिन झगड़ों का कोई हल न निकल सके उन्हें निबटाने के लिए एक श्रम-बोर्ड कायम किया जाए। इस बैठक में यूनियन सुरक्षा के बुनियादी मामले पर, जिसके कारण राष्ट्रीय प्रति-रक्षा मध्यस्थता बोर्ड भंग हो गया था, मज़दूरों तथा प्रवन्धकों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। तब इति गतिरोध को जबर्दस्ती रूज़वेल्ट ने यह आग्रह करके दूर किया कि 'यह सवाल नए युद्ध श्रम-बोर्ड द्वारा हल किए जाने के लिये छोड़ दिया जाए।

तव जनवरी, १९४२ में एक सरकारी आदेश से यह बोर्ड कायम कर दिया गया। यह त्रिपक्षीय था और इसमें १२ सदस्य थे—४ प्रवन्धकों के, ४ मज़दूरों के और ४ आम जनता के। इसका अध्यक्ष प्रतिरक्षा मध्यस्थता बोर्ड के भूतपूर्व मुखिया विलियम एच. डेविस को वनाया गया। बाद में इसी अनुपात में वैकल्पिक प्रतिनिधि तथा सह-सदस्य और शामिल कर लिए गए। मूलतः बनाए गए युद्ध-श्रम बोर्ड का मुख्य काम युद्ध मंत्री द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद हल न होने वाले ऐसे किसी भी औद्योगिक झगड़े को अपने हाथ में लेना था जो "युद्ध के सफल संचालन में सहायता देने वाले कार्यों में रुकावट पैदा कर

सकता हो।" इसके निर्णय उद्योग तथा मज़दूर दोनों के लिए अनिवार्यतः मान्य कर दिए गए।

युद्ध-श्रम बोर्ड को दिए गए अधिकारों का वास्तविक अभिप्राय युद्धकाल में सामूहिक सौदेवाज़ी की सामान्य प्रक्रिया को स्थगित कर देना था। मज़दूरों ने अपने हितों की रक्षा के लिए हड़ताल का अन्तिम उपाय के रूप में प्रयोग का परित्याग कर दिया और काम और रोज़गार की शर्तें तथा हालात अन्ततः बोर्ड तय करता था। इसके अलावा बोर्ड के निर्णय त्रिपक्षीय निर्णय होते थे जिसमें प्रबन्धकों तथा मज़दूरों के सहमत न हो सकने पर अन्तिम राय स्वभावतः जनता के प्रतिनिधियों की चलती थी।

युद्ध-श्रम बोर्ड का १९४२ में शुभ-आरम्भ हुआ जब इसने सदस्यता बनाए रखने के तथाकथित समझौतों में यूनियन सुरक्षा के प्रश्न का समाधान किया। न तो बन्द शाप ही और न यूनियन शाप ही लागू की गई। यूनियन के सदस्यों अथवा बाद में यूनियन में शामिल होने वालों के लिए यह ज़रूरी कर दिया गया कि उनकी तरफ से किए गए करार के एक अंग के रूप में करार के कायम रहने तक वे यूनियन के सदस्य बने रहें और अगर किसी समय उनका यूनियन-रिकार्ड अच्छा नहीं रहा तो उन्हें अपने काम से हटाया जा सकता था। युद्ध-श्रम बोर्ड में प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था का विरोध किया और उन्होंने कभी भी इसे पूर्णतः नहीं माना, किन्तु जब बोर्ड के फैसले में यह व्यवस्था कर दी गई कि यूनियन में शामिल होने के बाद १५ दिन के अन्दर-अन्दर कोई कर्मचारी अपने किसी हित को नुकसान पहुँचाए बिना यूनियन से अलग हो सकता है तो उन्होंने चुपचाप इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। एक बार तय हो जाने पर सदस्यता को कायम रखने के सिद्धान्त का सारे युद्धकाल में पालन किया गया। अन्त में यह कोई ३० लाख कर्मचारियों पर अथवा यूनियन समझौतों में समाविष्ट मज़दूरों के लगभग २० प्रतिशत हिस्से पर लागू कर दिया गया।

औद्योगिक शांति में इस आश्वासन से ज्यादा और कोई चीज़ योग नहीं दे सकती थी कि यूनियन सुरक्षा और व्यक्ति के काम की स्वतंत्रता दोनों की हिफ़ाज़त की जाएगी और इस बुनियादी मामले पर युद्ध-श्रम बोर्ड की नीति

सीधा परिणाम यह हुआ कि १९४२ में हड़तालें कम हो गईं। वर्ष की

समाप्ति पर ए. एफ. एल. के वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्ष ग्रीन ठीक ही यह दावा कर सका कि मजदूरों ने "पहले किसी भी समय की अपेक्षा निरन्तर, निर्बाध उत्पादन का शानदार रिकार्ड रखा है।" और इस रिकार्ड को राष्ट्र के सभी सिविल तथा सैनिक नेताओं ने स्वीकार किया। सम्मेलन को भेजे गए एक सन्देश में रूज़वेल्ट ने कहा कि युद्ध-प्रयत्नों में मजदूरों का सहयोग अपनी कहानी आप कह रहा है—"यह बड़ा शानदार है।"

किन्तु शीघ्र ही यूनियन सुरक्षा से भी अधिक कठिन समस्या आ खड़ी हुई। युद्धकाल में चीज़ों के दाम बढ़ने से उसके अनुरूप वेतनों में हेर-फेर की माँग की जाने लगी। युद्ध-श्रम बोर्ड ने इस मामले को पहले व्यक्तिगत आधार पर हल करने की कोशिश की और जहाँ परिस्थितियों को देखते हुए उचित जान पड़ा वहाँ वेतन-वृद्धि की अनुमति भी दी। किन्तु मुद्रा-प्रसार के रुख पर सरकार बहुत चिन्तित थी और अप्रैल, १९४२ में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश में उसने मूल्य और वेतन स्थिरीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम अपनाया। युद्ध-श्रम बोर्ड के लिए कोई ऐसा फार्मूला निकालना जरूरी हो गया जो वेतन दरों में आम वृद्धि को रोकने की बुनियादी आवश्यकता और जहाँ उचित प्रतीत हो वहाँ वेतनों में वृद्धि के बीच समन्वय करे। रूज़-वेल्ट ने इस प्रश्न पर कोई विशिष्ट निर्देश नहीं किया क्योंकि यह महसूस किया गया कि वेतनों को बिल्कुल अवरुद्ध कर देना अव्यावहारिक होगा। इसलिए यह बोर्ड पर छोड़ दिया गया कि वह वर्तमान अनौचित्यों और एक निश्चित स्तर से कम वेतनों को मद्दे-नज़र रखते हुए यथाशक्ति उत्तम ढंग से वेतनों में स्थिरता स्थापित करे।

युद्ध-श्रम बोर्ड के लिए इस विषय में एक सामान्य नीति निर्धारित करने का पहला अवसर तब आया जब लिटल स्टील कम्पनियों के कर्मचारियों ने जुलाई में १ डालर प्रतिदिन की वेतन-वृद्धि की माँग की। लम्बी सुनवाई के बाद यह तय किया गया कि कोई भी वेतन-वृद्धि जनवरी, १९४१, जबकि मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर थे तथा मई १९४२ के जबकि मुद्रा प्रसार विरोधी कार्यक्रम अमल में लाया गया था, बीच के समय में बढ़ी हुई महँगाई के बराबर होनी चाहिए। ब्यूरो आव लेबर स्टैटिस्टिक्स की मूल्य तालिका के आधार पर (जिसे बाद में उपभोक्ता मूल्यसूचक अंक कहा गया) यह

१५ प्रतिशत के बराबर थी। इस आनुपातिक वृद्धि के कारण लिटल स्टील के कर्मचारियों को उनकी एक डालर की मांग के मुकाबले ४४ सेण्ट दैनिक की वेतन-वृद्धि प्रदान की गई।

यही तथाकथित लिटल स्टील फ़ार्मूला था। वेतन-सम्बन्धी सभी विवादों को हल करने में बाद में युद्ध-श्रम बोर्ड ने यही बुनियादी कसौटी अपनाई। यह इस धारणा पर अपनाई गई थी कि स्थिरीकरण कार्यक्रम से "मूल्य और वेतनों में दुःखद होड़ समाप्त हो जाएगी" जो पहले १६४१ में शुरू हुई थी। अगर इस धारणा का आधार मज़बूत होता तो वेतन सम्बन्धी झगड़ों को निबटाने का बोर्ड का काम अपेक्षाकृत आसान होता। किन्तु मूल्य सख्ती से स्थिर नहीं रखे जा सके और बोर्ड को अपने फार्मूले में महँगाई के आशा से अधिक बढ़ जाने के कारण निरन्तर हेर-फेर करना पड़ा।

लिटल स्टील फार्मूले को शीघ्र ही सरकारी आदेश से अन्य जगहों पर भी लागू कर दिया गया था, जहाँ वेतन सम्बन्वी विवाद उत्पन्न नहीं हुए थे। अक्तूबर, १६४२ में आर्थिक स्थिरीकरण अधिनियम पास हो जाने के बाद युद्ध-श्रम बोर्ड को मुद्रा-प्रसार विरोधी कार्यक्रम के एक अंग के रूप में समस्त उद्योगों में वेतन-वृद्धि को लिटल स्टील के फार्मूले के मुताबिक प्रति घण्टे की दर से वेतन पाने वालों के लिए १५ प्रतिशत तक सीमित रखने का आदेश दिया गया। इसमें सिर्फ उन्हीं उद्योगों को अपवाद माना गया जहाँ बहुत शोचनीय और अनुचित हालात विद्यमान थे। इसलिए युद्ध के शेष दिनों के लिए बोर्ड के दो स्पष्ट काम रहे: विवादों को निबटाना और ऐच्छिक वेतन समझौतों को स्वीकृति प्रदान करना। इन दोनों वर्गों में लिटल स्टील फार्मूलों की सभी वेतन-वृद्धियों के लिए अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई।

मज़दूर सामान्य स्थिरीकरण के कार्यक्रम का समर्थन करने को तैयार थे और जब तक मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से बढ़ने से रोका जा सके तब तक उनका लिटल स्टील फार्मूले से कोई झगड़ा नहीं था। किन्तु मुद्रा प्रसार की वेगवती धारा को रोकने के लिए बनाए गए बांधों में जैसे-जैसे दरारें पड़ती गईं, इसको कार्यान्वित करने से रोष बढ़ता गया। १६४३ के शुरू तक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक लिटल स्टील फार्मूले के समय ११५ से बढ़कर १२४ तक पहुँच चुका था और यूनियनों का तो यह कहना था कि मूल्यों में

वास्तविक वृद्धि तालिका में दिखाई गई वृद्धि से कहीं ज्यादा हुई है। मज़दूर अनुभव करने लगे कि उन्हें महँगाई की मार सहने के लिए मजबूर किया जा रहा है जबकि किसान व अन्य उत्पादक उससे लाभ उठा रहे हैं।

सरकार ने इस स्थिति के खतरे को महसूस किया किन्तु वेतन में वृद्धि करने के बजाय उसने कीमतें गिराने का प्रयत्न किया। राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने अप्रैल में अपना प्रसिद्ध "मूल्य-रोको" आदेश जारी किया और एक उचित मूल्य-वेतन सम्बन्ध को कायम रखने की हर संभव कोशिश की गई। ये नियंत्रणकारी कदम अपेक्षाकृत ज्यादा सफल रहे। इसके बाद १९४४ के अन्त तक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक सिर्फ एक प्वाइंट बढ़ा और अगस्त, १९४५ में भी १२९ से ज्यादा नहीं था किन्तु सच्चाई यह थी कि यद्यपि मूल्यों पर अंकुश लगा दिया गया था तो भी उन्हें गिराया नहीं जा सका था रहन-सहन की लागत लिटल स्टील फार्मूले के अन्तर्गत प्रदान की गई वेतन-वृद्धि से काफी ज्यादा ही रही।

इन घटनाओं के फलस्वरूप, १९४३ में मज़दूर अधिकाधिक बेचैन हो गए और पिछले १२ महीनों में औद्योगिक शांति का असाधारण रिकार्ड स्थिर नहीं रह सका। वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही हुई हड़तालों में करीब २० लाख मज़दूरों ने काम बन्द किया, जिनकी संख्या १९४२ से दुगनी थी और ४१,८३,००० मनुष्य-दिवसों के मुकाबले कुल १,३५.००.००० मनुष्य-दिवसों की हानि हुई। यद्यपि यह अब भी कुल कार्यकाल के सिर्फ १.७ प्रतिशत से कुछ ही ज्यादा था तो भी यह स्थिति में गम्भीर बिगाड़ आ जाने का ही सूचक था।

ये हड़तालें ज्यादातर असन्तुष्ट मज़दूरों द्वारा की गई स्थानीय हड़तालें थीं जिनके लिए ए. एफ. एल. अथवा सी. आई. ओ. के नेताओं ने मंजूरी नहीं दी थी। विवादग्रस्त मामलों को हल करने में युद्ध-श्रम बोर्ड के अत्यधिक विलम्ब से अधीर होकर अथवा छोटी-मोटी शिकायतों पर जिनके समाधान से मज़दूर सन्तुष्ट नहीं थे, उत्तेजित होकर मज़दूर प्रायः लगाम स्वयं अपने हाथ में ले लेते और यकायक काम छोड़ देते थे। युद्धकालीन परिस्थितियों ने यह खिंचाव और तनाव और बढ़ा दिया। अन्य परिस्थितियों में जिन्हें बहुत तुच्छ-सी बात समझा जाता, उन पर जोर से रोष प्रकट किया गया। लम्बे समय

तक भारी दबाव में काम करने के कारण और युद्धकालीन बस्तियों में रहते हुए, जहाँ की भीड़-भाड़ से आदमी आसानी से उत्तेजित हो जाता था, अगर स्त्री-पुरुष कभी अपनी शिकायतों पर विचार करने में प्रबन्धकों की कथित असफलता के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए अपने औज़ार रख देते थे या मशीनों पर काम करना छोड़ देते थे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कभी-कभी ये हड़तालें मज़दूरों की "यकायक भड़की हुई संक्षिप्त हड़तालों" से अधिक कुछ नहीं होती थीं। जब मज़दूर एक बार अपने अधिकार जताकर अपनी भाप निकाल देते थे तो झगड़े शीघ्र निबट जाते थे और उत्पादन बिना किसी गम्भीर रुकावट के फिर प्रारम्भ हो जाता था।

इन संक्षिप्त और अनधिकृत हड़तालों में एक अपवाद १९४३ की ग्रीष्म ऋतु में लेविस द्वारा कराई गई कोयला-हड़तालें थीं। ये सरकार की वेतन नीति तथा युद्ध श्रम बोर्ड के अधिकार को चुनौती थीं जिनके गम्भीर और व्यापक परिणाम हुए।

अप्रैल में जब युनाइटेड माइन वर्कर्स तथा खान मालिकों में वार्षिक करार को फिर से नया करने का समय आया तब लेविस ने वेतन सम्बन्धी नई माँगें रखीं। ये कोई तुच्छ माँगें नहीं थीं। उसने ५,३०,००० खनिकों के लिए दो डालर दैनिक वेतन वृद्धि की और इसके अलावा जमीन के नीचे सफर करने के लिए एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाने की दर से वेतन दिए जाने की माँग की। इस झगड़े को युद्ध-श्रम बोर्ड ने अपने हाथ में लिया। लेविस ने इसकी सत्ता को मानने से इन्कार कर दिया। उसने इसे "पक्षपातपूर्ण" और "बुरा" बता कर इसकी निन्दा की और इसकी सुनवाई का उसने चुनौती भरा बायकाट किया। उसने जता दिया कि अगर उसकी माँगें स्वीकार नहीं की गई तो कोई समझौता नहीं होगा और एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी। बेशक वह युद्ध-काल में हड़ताल नहीं कराएगा किन्तु "खनिक करार के अभाव में कोयला खान-मालिकों की सम्पत्ति पर पदाक्रमण करने के इच्छुक नहीं हैं।"

यूनाइटेड माइन वर्कर्स के सदस्यों को इससे आगे और किसी निर्देश की प्रतीक्षा नहीं थी। जब उन्होंने ३० अप्रैल को मौजूदा करार की अवधि बाकायदा समाप्त हो जाने से पहले ही काम छोड़ना शुरू कर दिया तो देश के सामने

कोयला-उत्पादन ठप्प हो जाने का संकट उपस्थित हो गया जो अधिक लम्बा चलने पर युद्ध के सम्पूर्ण अर्थतंत्र पर विपज्जनक प्रभाव डाल सकता था। संकट १९४१ की पतझड़ से भी ज्यादा गम्भीर था और रूज़वेल्ट ने विवश होकर इस पूर्ण और विनाशकारी हड़ताल को टालने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कोयला खानों पर सरकार की ज़ब्ती का आदेश जारी किया और दो मई को रेडियो पर खनिकों से काम पर लौट जाने की अपील की।

करार सम्बन्धी वार्ता के भंग होने का पूर्ण उत्तरदायित्व युनाइटेड माइन वर्कर्स के नेताओं के कन्धों पर डाला गया। राष्ट्रपति ने कहा कि लेविस मजदूरों द्वारा हड़ताल न करने की प्रतिज्ञा में भागीदार था और औद्योगिक झगड़ों को शांतिपूर्वक निवटाने वाले युद्ध-श्रम बोर्ड से कोई वास्ता न रखने से इन्कार करके वह सरकार की सत्ता को चुनौती दे रहा है। रूज़वेल्ट ने खनिकों से सहानुभूति प्रकट की और जो चीज़ें उन्हें खरीदनी पड़ती थीं उनकी कीमतें गिराने का वायदा किया। किन्तु उन्होंने मजदूरों को यह भी याद दिलाया कि जो कोई व्यक्ति कोयला निकालने से इन्कार करता है वह युद्ध-प्रयत्न में बाधा डाल रहा है, अमरीकी योद्धाओं व नौसैनिकों के जीवन से खेल रहा है और सब लोगों की भावी सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। उत्पादन जारी रखना ही होगा। खानें गृह-मंत्री द्वारा पुराने करार के अन्तर्गत चलायी जाएँगी किन्तु युद्ध श्रम-बोर्ड जो नया समझौता मंजूर करेगा उसे अतीत से लागू किया जाएगा। अन्त में रूज़वेल्ट ने कहा कि "कल कोयला खानों पर सितारों व धारियों वाला झण्डा लहराएगा। मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक खनिक उस झण्डे के नीचे काम कर रहा होगा।"

रूज़वेल्ट ने अपील निकाली और कुछ ही दिनों में खनिक वापस काम पर आगए, किन्तु इसलिए नहीं कि राष्ट्रपति ने अपील की थी। राष्ट्रपति के रेडियो-भाषण से सिर्फ २० मिनट पहले लेविस ने १५ दिन की अस्थायी संधिकी (जो बाद में ३० दिन की कर दी गई) घोषणा कर दी थी जिस बीच सेक्रेटरी आइक्स के साथ सहयोग से एक नए करार के लिए कोशिश की जानी थी। उसने आत्मसमर्पण नहीं किया था, वह पीछे भी नहीं हटा था। उसने अपनी कोई भी माँग वापस लिए विना सिर्फ एक अस्थायी राहत प्रदान की थी।

विवाद अगले ६ महीने तक चलता रहा, जिसमें कभी काम रोक दिया

जाता था और कभी अस्थायी विराम-संधि कर ली जाती थी। अन्त में खानें इस आशा से निजी मालिकों को सौंप दी गईं कि अब और सरकारी हस्तक्षेप के बिना उनके तथा यूनियन के बीच एक समझौता हो सकता है किन्तु समझौते की प्रस्तावित शर्तों को युद्ध-श्रम बोर्ड ने लिटल स्टील फार्मूले के विरुद्ध बतला कर अस्वीकृत कर दिया। लेविस ने किसी भी समय बोर्ड की सत्ता को अथवा कोयले के उत्पादन में सार्वजनिक हित को स्वीकार करने में ज़रा सी भी इच्छा नहीं दिखाई। अक्तूबर के आखिर में अंतिम संकट आ पहुंचा जबकि चौथी बार ५ लाख खनिकों ने अपने औज़ार रख दिए और लेविस की मूक वाणी का अनुसरण कर खानों से दूर रहे। सरकार ने खानों पर पुनः कब्जा कर लिया और इस बार सैक्रेटरी आइक्स को सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि खानों पर सरकारी अधिकार रहता है, विशेष वेतन समझौता करने के लिये कहा गया। किन्तु यह समझौता भी युद्ध-श्रम बोर्ड द्वारा मंजूर किया जाना था।

मूलतः दांव पर लगे मामलों को जनता बहुत पहले ही भूल चुकी थी और तसवीर बहुत अधिक झमेले वाली हो गई थी। खनिकों तथा खान मालिकों में, खनिकों और सरकार के बीच तथा युद्ध-श्रम बोर्ड और गृहमंत्री के मध्य भी बार-बार संघर्ष हुए किन्तु लेविस अब भी स्थिति का स्वामी था। कोयले की अनिवार्य आवश्यकता के होते हुए भी उसकी कठोर और गुह्य टेक ने संघर्ष के अन्य सभी पहलुओं को गौण कर दिया था। मामले पर कोई निश्चित रुख अख्त्यार न करने तथा कठोर कार्रवाई न करने के लिए राष्ट्रपति की व्यापक आलोचना की गई किन्तु आम जनता की राय में सारा दोष लेविस का था। अन्य मज़दूरों को यद्यपि कोयला-श्रमिकों से सहानुभुति थी और कीमतें कम रखने में विफलता को नाटकीय ढंग से ज़ाहिर करने के कारण वे हड़ताल का स्वागत भी करते थे तो भी उनके प्रवक्ताओं ने लेविस की आलोचना की। सी. आई. ओ. की कार्यकारिणी ने युद्ध-श्रम-बोर्ड के प्रति उसके रवैये की तथा "अमरीका के राष्ट्रपति के खिलाफ़ उसके निजी और राजनीतिक दोषारोपणों" की खुल्लमखुल्ला निन्दा की।

खानों पर दूसरी बार कब्ज़ा किए जाने के बाद लेविस और सैक्रेटरी आइक्स में अन्ततः एक समझौता हो गया। यह एक बड़ा जटिल समझौता

था। ज्यादातर खान के एक द्वार से दूसरे द्वार तक की यात्रा के भुगतान को शामिल करके और खनिकों के काम के घण्टे बढ़ाकर उनके वेतनों में १·५० डालर प्रतिदिन की वृद्धि की गई। चूँकि बुनियादी वेतन दर के लिए लिटल स्टील फार्मूले की नाममात्र को रक्षा कर ली गई थी इसीलिए युद्ध-श्रम-बोर्ड ने अनमने भाव से उसे स्वीकार कर लिया था। तो भी लेविस ने सरकार को मजबूर कर दिया था और भले ही उसने इतना कुछ प्राप्त न किया हो, जितना दावा करता था तो भी उसकी यह एक महान् विजय प्रतीत होती थी। इसके अलावा नए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद ही उसने खनिकों को काम पर लौटने का हुक्म दिया।

लेविस कठोर बनकर अपनी टेक पर अड़ा रहा। पर्ल हार्बर से ऐन पहले की पूर्व हड़ताल के समान अब भी उसने बार-बार यही कहा कि राष्ट्रीय संकटकाल को खनिकों के शोषण का बहाना नहीं बनाया का सकता। वेतन वृद्धि की उनकी मांग को सिर्फ एक न्याय की बात कहा गया जो कोयला-उत्पादन अथवा राष्ट्रीय-रक्षा की किसी भी धारणा से ऊँची चीज समझी गई। स्वयं खनिक लेविस के आदेशों का बिना आनाकानी पालन करते थे। जब लेविस उन्हें काम करने के लिये कहता था तो वे काम करते थे, जब वह उन्हें घर पर रहने या मछली पकड़ने जाने को कहता तो वे घर पर रहते थे या मछली पकड़ने चले जाते थे। वे अपनी यूनियन के अध्यक्ष का आदेश मानते थे, अमरीका के राष्ट्रपति का नहीं।

जब कभी भी इन खनिकों ने हड़ताल की, तब लोकमत के क्रोध की बौछारों का उनके रवैये पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रहन-सहन के खर्चे में वृद्धि से जो उनके वेतनों से बहुत आगे निकल गई थी, तंग आकर, कठिन और खतरनाक ढंग का परिश्रम करते हुए और यह अच्छी तरह महसूस करते हुए कि अतीत में प्राप्त किए गए सब लाभ उन्होंने संघर्ष से प्राप्त किए हैं, एक दूसरे से छितरे हुए कोयला-नगरों में लोकमत के सीधे प्रभाव से अछूते ये खनिक अनुभव करते थे कि उनकी हड़ताल बिल्कुल जायज है चाहे उससे अन्य सब उद्योगों के लिए निहायत जरूरी उत्पादन रुक जाता हो।

१९४३ की वसन्त के आखिरी दिनों और ग्रीष्म ऋतु में जब यह कोयला-

विवाद जारी था तब युद्ध प्रयत्न पर आए इस ख़तरे पर तथा अन्यत्र काम रुक जाने की आशंका पर जहाँ स्थिति बेकाबू होती दीख रही थी, लोगों के रोष ने मज़दूरों के विरुद्ध एक शक्तिशाली लहर चला दी। जून में राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने घोषणा की कि खनिकों का रवैया "असह्य" है और ग़ैर-लड़ाकू सेवा के लिए भरती की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव किया जिससे उन्हें सेना में भरती किया जा सके और चेतावनी दी कि "कोयला-हड़तालों ने बहुत अधिक अमरीकी जनता में रोष और नाराज़गी उत्पन्न कर दी है।" राष्ट्रपति का यह अन्तिम कथन शायद वास्तविकता से कुछ कम ही था। अख़बारों ने करीब-करीब एक स्वर से कोयला खानों में देश भक्ति-हीन मज़दूर नेताओं की निन्दा की और अन्य क्षेत्रों में हड़तालों के विस्तार को उन्होंने युद्ध-प्रयत्नों में मज़दूरों के पूर्ण सहयोग की गारण्टी के लिए की गई हड़ताल न करने की प्रतिज्ञा का भंग बताया।

किन्तु मज़दूरों के अत्यधिक बहुमत ने जिस प्रकार हड़ताल-न-करने की प्रतिज्ञा निबाही और जिम्मेदार मज़दूर नेताओं ने ग़ैर-कानूनी हड़तालों को रोकने के लिए जिस कदर कोशिशें कीं उन्हें देखते हुए ये आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। अखबार मज़दूरों की उचित शिकायतों का कभी उल्लेख नहीं करते थे। किन्तु साथ ही कोयला हड़तालों के अलावा तस्वीर के कुछ ऐसे भी पहलू थे जिनसे यूनियनों की नीतियों के बारे में लोकमत की आलोचना को बल मिलता था और मज़दूरों पर वे अंकुश लगाने की माँग तेज़ कर दी गई जो १९४१ में स्थगित कर दिए गए थे।

यह सही है कि युद्धकाल में यूनियनों ने अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अनेक बार मनमाने ढंग से काम किया। काफी अरसे से कुछ यूनियनों में श्रम को बचाने वाले यंत्र लगाने अथवा लागत कम करने के अन्य उपाय अपनाने का विरोध करके मज़दूर-इजारेदारियों का निर्माण करने या उन्हें बनाए रखने की प्रवृत्ति पैदा हो गई थी। "फैदर बैडिंग" के कुछ उदाहरण (फैदर बैडिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें यूनियनें अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाने का आग्रह करती हैं, जबकि उनकी वस्तुतः ज़रूरत नहीं होती) या दर्शक, जिनका काम सिर्फ स्वार्थपूर्ण यूनियन विशेषाधिकारों की रक्षा करना होता था, कई व्यव-यों में बदनाम थे। अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी हड़तालों और यूनियनों के आपसी

झगड़ों का जिनसे काम ठप्प हो जाता था, सारा नुकसान प्रबन्धकों और आम जनता को उठाना पड़ता था, यद्यपि उन पर इनका कोई बस नहीं था। इन हड़तालों से मजदूरों के इस या उस गुट के स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की ही सिद्धि होती थी। और अन्त में जनता इस बात पर अत्यधिक चिन्तित हुए बिना न रह सकी कि मज़दूर इस बात की कोई गारण्टी नहीं दे सके कि आवश्यक जन-सेवाओं में, जिन पर समस्त समाज का जीवन अवलम्बित है, हड़ताल करके जान-बूझ कर रुकावट नहीं डाली जाएगी, यद्यपि युद्ध के कारण उन जन-सेवाओं का जारी रहना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गया था।

यूनियनों की ग़ैर-जिम्मेदारी के हर मामले का यूनियन विरोधी मालिक अधिक-से अधिक लाभ उठाते थे और उद्योग-व्यापी हड़तालों के खतरे को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते थे। संगठित मज़दूर भी यह आशा नहीं कर सकते थे कि लोकमत का उचित ध्यान रखने में इसकी कमियों, गलतियों और विफलताओं का उसके विरोधी लाभ नहीं उठाएँगे। किन्तु सामूहिक समझौतों के परिपालन की संख्या यद्यपि वस्तुतः बढ़ रही थी तो भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि युद्धकाल में मज़दूर कभी-कभी राष्ट्रीय हितों के प्रति कठोर अवहेलना दिखाते थे। कुछ भी हो, १९४३ में देश का मूड कांग्रेस और विधान-सभाओं में ऐसे कानून बनाए जाने के नए अभियान के रूप में प्रकट हुआ जिनसे हड़तालों तथा मजदूरों की अन्य ज्यादतियों से जनता की रक्षा हो सके। इस अभियान का इतना व्यापक समर्थन किया गया कि उसे सिर्फ़ नेशनल ऐसोसियेशन आव मैन्युफैक्चरर्स या यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स आव कामर्स के अक्खड़ व्यक्तियों का काम कह कर आसानी से टाला नहीं जा सकता था।

कांग्रेस में प्रस्तुत प्रतिबन्धात्मक बिलों में से सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि-सभा के स्मिथ तथा सेनेटर कौनाली द्वारा पेश किया गया बिल था। इसको शक्तिशाली समर्थन प्राप्त हुआ और कोयला-हड़तालों से उत्पन्न उत्तेजना में जून में प्रतिनिधि-सभा तथा सेनेट में निर्णायक बहुमत से आनन-फानन में पास कर दिया गया। बिल में सर्वप्रथम युद्ध-श्रम बोर्ड को विधिसम्मत सत्ता प्रदान की गई। श्रम-विवाद को हल करने में इस बोर्ड के असफल रहने की दशा में

राष्ट्रपति को ऐसे किसी भी कारखाने अथवा उद्योग को अपने कब्जे में लेने का अधिकार प्रदान किया गया जहाँ उत्पादन रुकने से युद्ध-प्रयत्नों को खतरा उत्पन्न होता हो और इसके बाद जो कोई व्यक्ति हड़ताल करे या हड़ताल के लिए उकसाए उसके लिए जरायम सजाओं की व्यवस्था की गई। जब सरकार हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझती थी तब हड़ताल पर इतने कठोर प्रतिबन्ध लागू नहीं होते थे। किन्तु उन्हें ३० दिन तक शांति रखने की अवधि से रोका जाता था जिसके दौरान हड़ताल के बारे में नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड सब सम्बन्धित मज़दूरों का वोट लेता था। अन्त में स्मिथ-कौनाली ऐक्ट ने राजनीतिक आन्दोलन कोषों में यूनियनों द्वारा दिए जाने वाले समस्त चन्दों पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

इस बिल पर शीघ्रता से लिया गया वोट युद्ध-काल में किसी भी हड़ताल के विरुद्ध जन-सामान्य के तीव्र रोष का परिणाम था और जॉन एल. लेविस के दम्भपूर्ण तौर-तरीकों ने इस अग्नि में आहुति का काम किया। यद्यपि युद्ध-काल में औद्योगिक उत्पादन की रक्षा व्यवस्था करने की जरूरत थी तो भी कांग्रेस इस दिशा में आवश्यकता से कहीं अधिक बढ़ गई। इसने बिल में जरायम दण्ड की व्यवस्था करके हड़ताल-न-करने की प्रतिज्ञा का मज़दूरों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए परिपालन की उपेक्षा कर दी और विचित्र बात तो यह है कि अन्य परिस्थितियों में इसने हड़ताल-मत लिए जाने की व्यवस्था की जिससे मजदूर हड़ताल-न-करने के अपने दायित्व से मुक्त हो गए। अर्थात् यूनियनों पर अनुशासन उनके स्वीकृत अधिकार के प्रयोग पर पाबन्दी लगाकर स्थापित करने का यत्न किया गया, यद्यपि उन्होंने स्वयं युद्ध-काल में अपने इस अधिकार का प्रयोग न करने का वचन दिया था और सामान्यतः उसका वे पालन भी कर रही थीं। ए. एफ. एल. ने तीखेपन से कहा : कि इस बिल का जन्म "कांग्रेस के प्रति क्रियावादी सदस्यों की घृणा और ईर्ष्या से हुआ है" और मर्रे ने उसकी बात का समर्थन करने वाले सी. आई. ओ. के एक सम्मेलन में कहा कि "देश मज़दूरों और उनके अधिकारों पर राष्ट्र के इतिहास में अब तक के सबसे कुटिल और सतत प्रहार को देख रहा है।"

राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने स्मिथ-कौनाली बिल पर अपने निषेधाधिकार का [illegible] । उन्होंने ग़ैर-ज़िम्मेदार यूनियनवाद के खिलाफ सतर्कता की जरू-

रत को स्वीकार करते हुए इसकी कुछ धाराओं को मंजूर कर लिया किन्तु वे ३० दिन की शांति रखने की अवधि और हड़ताल के बारे में मत लेने की व्यवस्था के खास तौर से विरुद्ध थे। उन्होंने कांग्रेस को यह समझाने की कोशिश की कि यह बिल सरकार के हड़ताल न होने देने के कार्यक्रम के, जिसका यूनाइटेड माइन वर्कर्स की मनमानी टेक के बावजूद सामान्यत: मजदूरों ने समर्थन किया है, बिल्कुल विपरीत जाता है और इससे औद्योगिक शांति होने के बजाय मजदूरों में बेचैनी बढ़ेगी। किन्तु उस समय की मूड में कांग्रेस ने उनकी आपत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके निषेधाधिकार को रद्द कर दिया। न्यूयार्क टाइम्स ने इस ऐक्ट को जिसे सरकारी तौर पर युद्ध-श्रम-विवाद अधिनियम कहा जाता था, "ठीक तरह से बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में पास किया गया विभ्रमपूर्ण कानून बताया" किन्तु इसके बाद युद्ध की समाप्ति तक यह कायम ही रहा।

स्मिथ-कौनाली ऐक्ट ने युद्ध-श्रम बोर्ड को कानूनी सत्ता प्रदान की थी और मजदूरों में अशांति को देखते हुए, जो नए कानून से मुश्किल से ही दूर हुई थी, इसने औद्योगिक झगड़े निबटाने के अपने काम को अधिकाधिक कठिन पाया। जब सब यह स्वीकार करते थे कि जीवन के रहन-सहन का खर्चा बढ़ गया है तब लिटल स्टील फार्मूले की सीमाओं से आगे वेतन-वृद्धि की मजदूरों की माँग का मजबूत आधार था। इस चीज को कोयला हड़ताल में किए गए अंतिम समझौते को स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रच्छन्न रूप से, भले ही अनिच्छा से स्वीकार कर लिया गया था। बोर्ड में प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर कोई घोषित सरकारी नीति को उलटना चाहे तो उसे सिर्फ जोरों से हड़ताल करने की जरूरत है और लेविस की माँग पर की गई कार्रवाई को मजदूरों का तुष्टीकरण और स्थिरीकरण कार्यक्रम का बलिदान बताया। लेकिन सचाई यह थी कि वेतनों और कीमतों के बीच खाई ने मजदूरों के जीवन स्तर को गम्भीर क्षति पहुँचाई थी जब कि बाकी देश युद्ध-कालीन समृद्धि के उच्च स्तर का उपभोग कर रहा था।

इसके अलावा १९४४ में एक मामला ऐसा हुआ, जब सरकार युद्ध-श्रम बोर्ड के कार्य-क्षेत्र से बाहर के एक श्रमविवाद को हल करने के लिए लिटल

स्टील फार्मूले से आगे बढ़ गई तो भी यह इसकी नीतियों पर प्रभाव डाले बिना न रह सकी। यह थी धमकित रेलवे हड़ताल जो रेलवे लाइनों पर सरकार द्वारा कब्जा कर लिये जाने के बाद बाल-बल बच गई।

युद्ध अथवा शांतिकाल में रेलवे मजदूर सम्बन्धों पर १९२६ का संशोधित रेलवे मजदूर ऐक्ट लागू होता था जिसमें कहा गया था कि अगर राष्ट्रीय मध्यस्थता बोर्ड के तत्त्वावधान में मध्यस्थता अथवा पंच-फैसले से कोई श्रमविवाद हल न हो सके तो उस पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक विशेष आपातकालीन बोर्ड द्वारा विचार किया जाना चाहिए और ३० दिन की शांति रखने की अवधि में कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए। १९४३ की पतझड़ में वेतनों में हेरफेर के प्रश्न पर रेलवे मज़दूरों और प्रबन्धकों के विभिन्न दृष्टिकोणों में समझौता कराने के लिए उठाए गए प्रारम्भिक कदमों की विफलता के बाद राष्ट्रपति ने बाकायदा एक आपातकालीन बोर्ड नियुक्त किया। इसने वस्तुतः रेलवे यूनियनों की माँगें पूरी कर दीं किन्तु इसके लिटल स्टील फार्मूले की परिधि को लाँघ जाने के कारण आर्थिक स्थिरीकरण कार्यालय ने इसे नामंजूर कर दिया। तब रेलवे मजदूरों ने वोट लेकर ३० दिसम्बर से हड़ताल करने का निश्चय किया।

राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने तुरन्त प्रस्ताव किया कि आपात बोर्ड और आर्थिक स्थिरीकरण के बीच एक पंच के रूप में सारा मामला अंतिम और अवश्य पालनीय निर्णय के लिए उन्हें सुपुर्द कर दिया जाए। रेलवे के संचालन-कार्य से असम्बद्ध दो यूनियनों ने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया किन्तु लोकोमोटिव फायरमेन, रेलवे कण्डक्टर्स तथा स्विचमेन्स यूनियन ने इसे नामंजूर कर दिया। उन्होंने अपने हड़ताल के नोटिस वापस लेने से इन्कार कर दिया। तब सरकार ने तुरन्त ही रेलवे लाइनों की जब्ती का आदेश जारी कर दिया और उस पर अमल किया। रूज़वेल्ट ने कहा: "युद्ध प्रतीक्षा नहीं कर सकता और मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता क्योंकि अमरीकियों का जीवन और अमरीका की दाँव पर लगी हुई है।"

मामला तूल पकड़ने से पहले राष्ट्रपति के हस्तक्षेप को स्वीकार करने वाली यूनियनों के लिए पंचफैसले की घोषणा कर दी गई। आर्थिक स्थिरीकरण कार्यालय के बजाय आपात बोर्ड की बात रखी गई और राष्ट्रपति ने

लिटल स्टील फार्मूले से अधिक वेतन वृद्धि को इस आधार पर उचित ठहराया
कि वे ओवर टाइम तथा छुट्टियों की तनख्वाह के जिसके रेल कर्मचारी हकदार
हैं, बदले दी गई है। इन रियायतों से अपनी माँगें सत्रांश में पूरी होते देख
राष्ट्रपति के हस्तक्षेप को अस्वीकार करने वाली तथा स्वीकार करने वाली
दोनों ही प्रकार की यूनियनों ने पंचफैसले को स्वीकार कर लिया और पहले
प्रकार की यूनियनों ने अपने हड़ताल के नोटिस वापस ले लिये। रेल-सर्विस
में वस्तुतः कोई रुकावट नहीं हुई थी और १८ जनवरी, १९४४ को रेलवे
लाइनें संक्षिप्त सरकारी नियंत्रण के बाद निजी मालिकों को लौटा दी गईं।

किन्तु जब रेल-मजदूरों और कोयला खनिकों ने पर्याप्त वेतन वृद्धियाँ
प्राप्त कर लीं चाहे वे यात्रा-समय अथवा अवकाश-वेतन के रूप में ही दी गई
हों तो युद्ध-श्रम-बोर्ड मजदूरों को माँगें पूरी करने के लिए आनुषंगिक लाभ
देने को मजबूर हो गया। इस समय तक देश के सभी मजदूरों को लिटल
स्टील फार्मूले के अन्तर्गत अधिकतम वेतन-वृद्धि मिल चुकी थी और जहाँ तक
प्रति घण्टे वेतन की दर का प्रश्न है, यह यद्यपि कायम रही तो भी इन
रियायतों से मजदूर ज्यादा तादाद में पैसा घर ले जाने लगे। इनमें सवेतन
छुट्टियाँ, सफर के समय और भोजन के समय के लिए भत्ता, बोनस तथा
प्रोत्साहन भुगतान और पालियों में तब्दीली के कारण वेतनों में हेर-फेर
शामिल था। उसके अलावा यह फैसला देकर कि स्वास्थ्य और बीमा कोष
के बारे में सामूहिक सौदेबाजी उचित है और उसकी समीक्षा की जरूरत नहीं
है, युद्ध-श्रम-बोर्ड ने और भी अप्रत्यक्ष वेतन-वृद्धियों के लिए रास्ता खोल
दिया। ये आनुषंगिक लाभ युद्ध-काल में औद्योगिक अशांति को दूर करने में
बड़े सहायक रहे और इन्होंने वे हड़तालें नहीं होने दीं जो कीमतें बढ़ती जाने
की हालत में लिटल स्टील फार्मूले को पत्थर की लकीर मानकर कार्यान्वित
करने से अवश्य ही भड़क उठतीं। किन्तु कार्यनियोजन के तौर-तरीकों में एक
बिल्कुल नई परिपाटी डालने में सहायक होने के कारण इनका ज्यादा स्थायी
महत्त्व था। उदाहरणार्थ सवेतन छुट्टी अमरीका के औद्योगिक कर्मचारियों के
लिए बहुत महत्त्वपूर्ण नई चीज थी और अधिकाधिक व्यापक क्षेत्रों में उसे
स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त युद्ध-श्रम बोर्ड की नीतियों ने कई अन्य
तरीकों से भी देश के मजदूरों की स्थिति को सुधारने का काम किया। उसने

सभी मज़दूरों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की व्यवस्था की, एक जैसे या एक ही कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के बीच वेतन की विषमता को दूर करने का यत्न किया और ज्यादा एकसार वेतन-नीतियां निर्धारित कराने में अपने प्रभाव का उपयोग किया।

युद्ध-श्रम बोर्ड ने युद्धकाल में अपना उत्तरदायित्व निबाहते हुए २ करोड़ मज़दूरों के लिए कोई ४,१५,००० ऐच्छिक वेतन समझौते मंजूर किए और इतने ही मज़दूरों के लिए २०,००० विवादग्रस्त मामलों में स्वयं द्वारा किए गए निर्णयों पर अमल कराया। यह एक विशाल और श्रम साध्य काम था जिसका कोई पूर्व उदाहरण नहीं था और यद्यपि मामले निबटाने में देरी के लिए बोर्ड की प्रायः आलोचना की जाती थी तो भी १९४३ के बाद आए विशाल कार्य को देखते हुए इसने बड़ी कुशलता से अपना काम किया।

विवादग्रस्त मामलों में न तो सरकारी आदेशों ने और न स्मिथ-कोनाली ऐक्ट ने सीधे अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड को कोई अधिकार प्रदान किया। किन्तु जब इसकी अपनी सत्ता और अन्य एजेंसियों की मार्फत डलवाया गया दबाव प्रभावहीन सिद्ध होता था तब बोर्ड राष्ट्रपति को युद्ध के काम के किसी भी कारखाने की ज़ब्ती सिफारिश कर सकता था और फलस्वरूप अपने आदेश मनवाने के लिए सीधा दबाव डाल सकता था। किन्तु विवादग्रस्त पक्ष इस चीज़ की नौबत आने दिए बिना ही सामान्यतः बोर्ड के निर्णयों को स्वीकार कर लेते थे। सिर्फ ४० मौकों पर ही राष्ट्रपति को कारखानों की जब्ती का आदेश जारी करना पड़ा—२६ बार यूनियनों द्वारा बोर्ड के आदेशों को चुनौती दिए जाने के कारण और २३ बार मालिकों की अडंगेबाजी के कारण। और सिर्फ एक मौका ऐसा आया जबकि बोर्ड के निर्णय को न तो यूनियन ने माना और न प्रबन्धकों ने।

मालिकों की तरफ से दी गई चुनौती का सबसे नाटकीय उदाहरण मौण्टगुमरी वार्ड कम्पनी का था जिसने इस आधार पर युद्ध श्रम बोर्ड का अधिकार क्षेत्र स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि मेल आर्डर के धन्धे का युद्ध-प्रयत्नों से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। जब इसने सी. आई. ओ. की एक यूनियन को अपने कर्मचारियों के लिए सामूहिक सौदेबाजी का एजेण्ट
।८ करने के आदेश को मानने से इन्कार कर दिया तो रूज़वेल्ट ने

कम्पनी कारखाने को जब्त कर लिए जाने का आदेश दिया और औद्योगिक एकता बनाए रखने के सरकारी कार्यक्रम की अविवेकपूर्ण अवहेलना के लिए इसके अफसरों की खुल्लम-खुल्ला आलोचना की। कम्पनी के अध्यक्ष सिवेल एवरी ने जिसका यूनियनों के प्रति रवैया उसके इस कथन से ज़ाहिर है कि 'बन्दशाप और संविधान परस्पर असंगत हैं', कम्पनी की सम्पत्ति पर कब्ज़ा करने के सरकारी अधिकार को मानने से दृढ़ता से इंकार कर दिया। मामला हल होने से पहले देश को यह विचित्र दृश्य देखने को मिला कि कारखाने पर कब्ज़ा करने वाली सेनाओं के दो कद्दावर सैनिकों ने एवरी को सशरीर उसके कार्यालय से हटा दिया।

उद्योग ने युद्ध-श्रम बोर्ड की आलोचना की कि वह लिटल स्टील फार्मूले पर ज़्यादा सख्ती से अमल नहीं करा सका और ऐसी रियायतें दीं जो अनुचित वेतन-वृद्धियों के बराबर हैं। मज़दूरों ने इस पर एक बिल्कुल विपरीत आधार पर आक्षेप किए। उन्होंने कहा कि यह लिटल स्टील फार्मूले की अत्यधिक सख्त व्याख्या करके मूल्यवृद्धि पर पर्याप्त गौर करने को अनिच्छुक है। आम जनता यह कहती थी कि सुनवाई करने तथा आदेश जारी करने में बोर्ड द्वारा की जाने वाली देरी ही मज़दूर-अशांति और अनावश्यक हड़तालों के लिए जिम्मेदार है। किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि त्रिपक्षीय श्रम पंचाट के इस महत्त्वपूर्ण परीक्षण का समग्र रिकार्ड सफलता का रिकार्ड रहा है। हड़तालों की संख्या युद्ध-पूर्व की अपेक्षा एक-तिहाई पर रही, युद्ध के पश्चात् बोर्ड के नियंत्रण भंग हो जाने के बाद तक स्थिरीकरण कार्यक्रम जितना समझा जाता था उससे कहीं अधिक अच्छी तरह चलता रहा; और मज़दूरों के अधिकारों की सहानुभूतिपूर्वक रक्षा की गई। वस्तुतः युद्ध-श्रम बोर्ड द्वारा सदस्यता कायम रखने की वकालत, अवकाश के वेतन, स्वास्थ्य तथा बीमा कोष और महिलाओं के लिए समान वेतन के बारे में इसकी रज़ामन्दी और मूल्यों के स्वरूप के बारे में इसके आम सर्वेक्षणों का राष्ट्रव्यापी प्रभाव सभी मज़दूरों के लिए प्राप्त किए गए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन लाभ थे।

अब भी सौदेबाज़ी की उपयुक्त इकाई का चुनाव करने वाले तथा मालिकों के अनुचित तौर-तरीकों से यूनियनों की रक्षा करने वाले नेशनल लेबर रिलेशन्स बोर्ड के ऊपर थोपे गए वार लेबर बोर्ड (युद्ध-श्रम-बोर्ड) के प्रभाव ने

हो जाने के संभावित खतरे ने उन आशंकाओं को और बढ़ा दिया जिनसे प्रेरित होकर स्मिथ-कौनाली ऐक्ट के मातहत राजनीतिक अभियान कोषों में चन्दा देने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। यूनियनों से लोग अब भी नाराज़ थे। १९४४ में लोकमत का सर्वे करने पर पता चला कि जिन लोगों से पूछ-ताछ की गई उनमें से ६७ प्रतिशत यूनियनों की गतिविधियों पर और अंकुश लगाने के पक्ष में थे और अखबारों की टिप्पणियाँ अधिकाधिक खिलाफ होती जा रही थीं।

राजनीतिक कार्रवाई समिति ने गौम्पर्स के समय से चली आ रही मज़दूर संगठनों की परम्परा को निवाहते हुए रिपब्लिकन और डैमोक्रैटिक दोनों सम्मेलनों में सुनवाई कराने का यत्न किया किन्तु इसके निकटतम सम्बन्ध स्वभावतः डैमोक्रैटिक पार्टी के साथ थे जिसने मज़दूरों के लक्ष्य को इतने उल्लेखनीय ढंग से आगे बढ़ाया था और जो स्वयं मज़दूरों के राजनीतिक समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर करती थी। राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार छाँटने में इसका प्रभाव बहुत महत्त्वपूर्ण रहा। हेनरी वालेस की नामज़दगी कराने में विफल रहने के बाद इसने जेम्स एफ. बायर्न्स का रास्ता रोक दिया और हेरी ट्रूमन के लिए मार्ग साफ कर दिया। इन राजनीतिक तारर्बकियों के पीछे सबसे शक्तिशाली हाथ हिल-मैन का बताया जाता है और इस किस्से के फैलने से कि रूज़वेल्ट ने "सब कुछ सिडनी से साफ करा लेने" का आदेश दिया है, उसकी चढ़ती हुई महत्ता देशव्यापी हो गई। यद्यपि इस कहानी से सब सम्बन्धित लोगों ने इन्कार किया तो भी प्रेस ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और राष्ट्रपति के विरोधियों ने हरदम इसका उपयोग किया।

राजनीतिक कार्रवाई समिति पर उसे क्रांतिकारी, ग़ैर-अमरीकी और उन कम्युनिस्टों द्वारा प्रभावित बता कर चोटें की गईं जो इस युद्ध-कालीन चुनाव आन्दोलन में रूज़वेल्ट का दृढ़ता से समर्थन कर रहे थे। ग़ैर-अमरीकी हरकतों पर डाइस कमेटी की लम्बी रिपोर्ट के आखिर में यह आरोप लगाया गया कि "सम्पूर्ण आन्दोलन अमरीकी कांग्रेस को अपने तानाशाही कार्यक्रम के अनुकूल ढालने का एक विध्वंसक कम्युनिस्ट अभियान है।" यूनियन पैसिफिक रेलरोड के अध्यक्ष ने गम्भीरता से यह चेतावनी दी कि राजनीतिक कार्रवाई समिति

एक "घृणित नवीकरण है जो अमरीकी राजनीति में वस्तुतः धोखा देकर घुस आई है।" ओहायो के गवर्नर ब्रिकर ने कहा कि यह "क्रांतिकारी और कम्युनिस्टी कार्यक्रमों से हमारी सरकार पर हावी होने की चेष्टा कर रही है।"

हिलमैन चूँकि विदेश में जन्मा और यहूदी था इसलिए उस पर अन्य असहिष्णुतापूर्ण आक्षेप भी किए गए। चुनाव के बाद सी. आई. ओ. के सम्मेलन में भाषण देते हुए उसने कहा कि "राजनीतिक कार्रवाई समिति को बदनाम करने के व्यापक प्रयत्न झूठों का एक अम्बार और अखबारों का सफेद झूठ साबित हुआ जिनके सम्पादक, मुझे विश्वास है, अपने अग्रलेखों को पढ़ पढ़कर अब शर्मिन्दा हो रहे होंगे...उनके लिए कोई भी निन्दा बहुत बुरी, लोगों की भावनाओं से की गई कोई भी अपील बहुत मतान्ध और कोई भी चाल बहुत सिद्धान्तभ्रष्ट नहीं थी" यह एक उचित आरोप था और खुफिया विभाग द्वारा की गई जाँच-पड़ताल से सिद्ध हो गया कि हिलमैन के खिलाफ लगाए गए कम्युनिज़्म के आरोप बिल्कुल निराधार थे।

ए. एफ. एल. के बहुत-से नेताओं तथा ए. एफ. एल. से सम्बद्ध यूनियनों ने सी. आई. ओ. की राजनीतिक कार्रवाई समिति के साथ सहयोग किया। अन्य उदार ग्रुपों ने या तो इसके साथ अप्रत्यक्ष रूप से काम किया या इससे सम्बद्ध राष्ट्रीय नागरिक राजनीतिक कार्रवाई समिति के साथ काम किया। ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. के कोई १४० अखबारों के, जिनकी कुल ग्राहक-संख्या ६० लाख थी, राष्ट्रव्यापी मत-सर्वेक्षण से रूज़वेल्ट के लिए मज़दूरों का समर्थन स्पष्ट जाहिर हो गया। बड़े-बड़े शहरों के अखबारों के तुलनात्मक सर्वेक्षण के नतीजों के बिल्कुल विपरीत उसने बताया कि इन सब मज़दूर-अखबारों में से सिर्फ एक ड्यूई का समर्थक है और केवल ११ ए. एफ. एल. की निष्पक्षता की अधिकृत नीति के हामी हैं। रूज़वेल्ट जिस भारी बहुमत से फिर चुने गए उसका श्रेय निस्सन्देह राजनीतिक कार्रवाई समिति के मज़दूरों के वोट उन्हें दिलाने के लिए किए गये अथक प्रयत्नों को है। यह भी दावा किया गया कि १७ सेनेटर, १२० प्रतिनिधि-सभासद और ६ गवर्नर भी, जिनकी उम्मीदवारी की स्थानीय रूप से प्रस्तावना की गई थी, इस समिति की बदौलत ही चुने गए।

चुनाव-आन्दोलन के बाद सी. आई. ओ. ने तीसरी पार्टी की स्थापना के

विरुद्ध अपनी सम्मति को फिर दोहराया किन्तु राजनीतिक कार्रवाई समिति को राष्ट्रव्यापी आधार पर एकतामय राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के हेतु एक स्वतन्त्र निर्दलीय समिति के रूप में जारी रखना मंजूर किया। अध्यक्ष मर्रे ने कहा : "मजदूरों न अब काफी अरसे से समझ लिया है कि आर्थिक कार्रवाई से वे जो लाभ प्राप्त करते हैं उनकी रक्षा, परिपालन और विस्तार तभी किया जा सकता है जब वे विधि-निर्माण का एक प्रगतिशील कार्यक्रम अपनाएँ और राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में प्रभावशाली ढंग से भाग लेकर उसका कानून बनना निश्चित कर दें।"

जर्मनी के खिलाफ लगातार आगे बढ़ते जाने और प्रशान्त महासागर में सफल कार्रवाइयों के बाद जब युद्ध अन्ततः समाप्त हुआ तो मजदूर चामत्कारिक प्रगति कर चुके थे। उन्होंने युद्ध को जीतने में महान् योग दिया और अपने निजी प्रयत्नों से अपने आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव के निर्माण में चामत्कारिक प्रगति की। प्रथम विश्व-युद्ध की तरह राष्ट्रीय आपातकाल अवसरों का काल सिद्ध हुआ और मजदूरों ने उससे भरपूर लाभ उठाया।

विजय की प्राप्ति में संगठित मजदूरों का योग उत्पादन के शानदार रिकार्ड से जाहिर हो जाता है जो राष्ट्रीय रक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे अर्थतन्त्र के चामत्कारिक परिवर्तन में राष्ट्र के मजदूरों द्वारा पूरा सहयोग दिए बिना सम्भव न होता। जुलाई, १९४० तथा जुलाई १९४५ के बीच प्रबन्धकों तथा मजदूरों के सम्मिलित प्रयत्नों से २ लाख लड़ाई के कामके विमान, ७१,००० नौसैनिक जहाज, ५००० मालवाही जहाज, ९००० भारी तोपें, २०,००,००० भारी मशीनगनें, १,२०,००,००० रायफलें और कार्बाइन, ८६,००० टैंक, १६,००० बख्तरबन्द गाड़ियाँ, २४,००,००० सैनिक ट्रकें, ६०,००,००० विमान से गिराए जाने वाले बम, ५,३७,००० तारपीडो बम, बनाए गए। कोयले का उत्पादन ६,००,००० टन प्रति वर्ष के रिकार्ड पर जा पहुँचा, विद्युत् शक्ति का उत्पादन १३,००,००० लाख किलोवाट घण्टे से बढ़कर २३,००,००० लाख किलोवाट घण्टे जा पहुँचा और लोहे के ढोकों का निर्माण ४,७०,००,००० टन से बढ़कर ८,००,००,००० टन हो गया।

इन चामत्कारिक सफलताओं में मजदूरों के योग की घर और बाहर दोनों

जगह अमरीकी नेताओं ने सराहना की। जनरल आइज़नहावर और ऐडमिरल किंग ने, युद्ध-मन्त्री और नौसेना मन्त्री ने, युद्ध-उत्पादन-बोर्ड डोनाल्ड नेल्सन ने और युद्ध मनुष्य-शक्ति आयोग के पाल वी॰ मैकनट ने हमारी स्थल और नौसेना को इतनी उत्कृष्ट और लड़ाकू सेना बनाने में सहायता के रूप में मज़दूरों द्वारा किये नए शानदार काम की बार-बार सराहना की। राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने कहा कि आगामी पीढ़ियों के लिए अपनी विरासत को सुरक्षित रखने के अमरीकी मज़दूरों के दृढ़ संकल्प ने "विश्व के इतिहास में उत्पादन की महानतम सफलता" को सम्भव बना दिया।

जहाँ तक व्यक्तिगत लाभ का प्रश्न है, युद्धकाल में संगठित मज़दूरों की यूनियन सदस्यता ५० प्रतिशत बढ़ गई। युद्ध की समाप्ति पर कुल सदस्य संख्या १,४०,००,००० थी। इनमें से ए. एफ. एल. के ६८,००,००० सदस्य और सी. आई. ओ. के ६०,००,००० सदस्य थे। अन्य सदस्य रेलवे ब्रदरहुडों, युनाइटेड माइन वर्कर्स तथा अन्य स्वतंत्र यूनियनों के थे। सामूहिक उत्पादन के बड़े उद्योगों में जहाँ एक दशाब्दी पूर्व मज़दूर बिल्कुल असंगठित थे, वहाँ प्रायः सभी मज़दूरों पर अब सामूहिक सौदेबाज़ी के समझौते लागू हो गए थे। यद्यपि ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. के बीच फूट अभी खत्म नहीं हुई थी जो कभी-कभी दोनों में वह सहयोग स्थापित नहीं होने देती थी, जिसकी बदौलत मज़दूरों के हितों की ज्यादा प्रभावशाली ढंग से रक्षा की जा सकती, तो भी अमरीकी मज़दूर आन्दोलन की संगठित शक्ति पहले किसी भी समय से अधिक प्रबल हो गई थी।

साथ ही मज़दूरों को इतनी तेज़ी से प्राप्त इतने अधिक लाभों ने न केवल व्यावसायिक हितों को, जिन्हें प्रबन्धकों की नियंत्रण व्यवस्था पर खतरा आया प्रतीत होता था, भयभीत किया बल्कि, जैसा कि हमने देखा अन्य लोगों में भी यह व्यापक भय उत्पन्न कर दिया कि क्या मज़दूर अपनी नई प्राप्त शक्ति का उपयोग जनकल्याण का उचित ध्यान रखते हुए करेंगे। कुछ यूनियनों की ज्यादतियों और बहुत से मज़दूरों की आक्रामक रूप से उग्रभावना ने, जिन्होंने सामूहिक सौदेबाज़ी से आई औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिरता को खतरा पैदा कर दिया था, मज़दूरों को प्रदान किए गए विशेषाधिकारों में और कटौती की माँग को तेज कर दिया था जिसकी अभिव्यक्ति स्मिथ-कोनाली ऐक्ट के

रूप में हुई। मज़दूरों की शक्ति को कम करने के हर प्रयत्नों में जब उद्योग अपना पूरा सहयोग देने को तैयार रहते थे तब वस्तुतः यूनियनों की स्थिति, जैसी कि युद्धकालीन विकास से प्रतीत होती थी, उससे ज्यादा सुभेद्य थी।

यूरोप और प्रशान्त महासागर में जब तोपें शान्त हो गईं तो मजदूर एक महत्त्वपूर्ण चौराहे पर खड़े थे। अगर उन्हें अपनी शक्ति बनाए रखनी थी, जनता का विश्वास फिर से प्राप्त करना था, और राष्ट्रीय अर्थतंत्र के स्थिरीकरण तथा औद्योगिक शांति को कायम रखने में अपनी भूमिका अदा करनी थी तो स्पष्ट ही उसने उनसे उच्चकोटि की राजनीतिज्ञता की अपेक्षा की जाती थी।

—:o:—

१९ : युद्धोत्तर काल में श्रमिकों की स्थिति

युद्ध की समाप्ति भी अमरीकी जनता के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती थी जितनी युद्ध का प्रारम्भ। जर्मनी और जापान पर विजय पाने के लिए आवश्यक मनुष्य-शक्ति और युद्ध सामग्री मुहैया करने की एकमात्र दृष्टि से संचालित अर्थतंत्र को किसी-न-किसी प्रकार शांति की उतनी ही कठिन आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। राष्ट्र के सामने समस्या यह थी कि बेकारी को राष्ट्र को तत्काल मंदी में झोंके देने बिना और मुद्रा प्रसार के दबावों को बढ़ते हुए मूल्यों और बढ़ते हुए वेतनों की क्रिया-प्रतिक्रिया प्रारम्भ करने दिए बिना, जिससे खुशहाली और फिर विस्फोट के उतने ही खतरनाक चक्र को प्रोत्साहन मिल सकता है, यह परिवर्तन कैसे लाया जाए।

मज़दूर बहुत चिन्तित थे। युद्ध की समाप्ति से पहले ही यह भय फैलने लगा था कि शांति का मतलब होगा—बेकारी और कम वेतन और यूनियनों की शक्ति को कम करने की इच्छुक यूनियन-विरोधी ताकतें और ज्यादा तादाद में उभर आएँगी। जापान पर विजय के बाद असुरक्षा की यह भावना मज़दूरों, उद्योगपतियों और सरकारी अर्थशास्त्रियों की इस सर्व-सम्मत घोषणाओं से और भी बढ़ गई कि १९४६ की वसन्त ऋतु तक बेरोज़गारी १ करोड़ तक बढ़ सकती है। ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. दोनों ने ही यह कहा कि राष्ट्रीय अर्थतंत्र में यह विध्वंस राष्ट्र की क्रय शक्ति को बनाए रखने और औद्योगिक सामान के लिए विस्तृत बाजार बनाने के लिए पूर्ण रोजगार तथा वेतन-वृद्धियों के एक कार्यक्रम का सक्रिय समर्थन करके ही रोका जा सकता है।

जब शांति का तात्कालिक परिणाम ४० घण्टे के सप्ताह पर लौट आने के कारण कम वेतन-प्राप्ति हुआ और अपनी मशीनें बदलने के लिए कारखानों के बन्द हो जाने से मज़दूर व्यापक क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बेकार हो गए तो वेतन-वृद्धियों पर मज़दूरों का आग्रह ज़ोर पकड़ गया। आलोचकों ने इन माँगों को "लूट-खसोट के लिए कदम" ही बताया, किन्तु मज़दूरों ने महसूस

किया कि उनसे तो मशीनों के नवीकरण का बोझा उठाने को कहा जा रहा है किन्तु सरकार कर वापस करके तथा अन्य प्रकार से अप्रत्यक्ष सहायता देकर वस्तुतः उद्योगपतियों की मदद कर रही है। इसके अलावा कीमतें चढ़ रही थीं। युद्ध-श्रम बोर्ड ने वेतनों में जो सीमित हेर-फेर की अनुमति प्रदान की थी वह पहले लगाये गये नियन्त्रणों में ढील दे दिए जाने के कारण रहन-सहन का खर्चा बढ़ जाने की वजह से बिल्कुल अपर्याप्त हो गई थी। एक के बाद एक यूनियन ने वास्तविक क्रयशक्ति की दृष्टि से युद्धकालीन वेतनों को बनाए रखने के लिए प्रति घण्टा मज़दूरी की दर बढ़ाए जाने की माँग की।

जब उद्योगों ने इन माँगों को सामान्यतः अस्वीकार कर दिया तो मज़दूरों का जवाब था—हड़ताल। जब तक मज़दूरों की ताकत बनी थी तब तक संभावित मंदी और बेकारी से यूनियनों के कमज़ोर हो जाने से पूर्व ही उन्होंने अपने हितों की रक्षा करने का संकल्प किया। इस आन्दोलन के पीछे सी. आई. ओ. की एक सुविचारित योजना थी और मजदूर नेता जानते थे कि वे क्या करने जा रहे हैं। वे राष्ट्रीय नीति की बात करते थे और उपभोक्ता की क्रयशक्ति तथा मजदूरों के अधिकार दोनों पर निरन्तर ज़ोर दे रहे थे।

स्थिति १९१९ से बहुत भिन्न थी। तब भी मज़दूर युद्धकालीन लाभों को प्राप्त रखने के लिए भरसक-संघर्ष करने को उद्यत थे। सिर्फ इस्पात को छोड़कर बाकी उद्योगों में १९१९ में जो हड़तालें हुई वे जहाँ-तहाँ, इक्की-दुक्की और किसी प्रभावशाली संगठन अथवा नेतृत्व के बिना यकायक उद्भूत हुई थीं, उनसे हिंसा-प्रतिहिंसा जाग उठी थी। अन्त में यूनियनों के प्रति बढ़ते हुए विरोध के वातावरण में सरकार ने उद्योग को अपना समर्थन प्रदान किया था। कुछ अस्थायी लाभों के बावजूद संगठित मज़दूरों को बचाव के पैंतरे पर आने को मजबूर कर दिया गया और शनैः-शनैः पीछे हटने को बाध्य किया जो १९२० की दशाब्दी की मुख्य बात थी।

सन् १९४५ की मज़बूत यूनियनों की एकता बनाए रखने की शक्ति ने इस तसवीर को बदल दिया था और युद्ध के बाद जिन उद्योगों में हड़तालें हुईं उन्होंने उत्पादन बनाए रखने की कोशिश भी नहीं की। संघर्ष १९१९ की अपेक्षा कम कठिन नहीं था किन्तु यह एक ढीले-ढाले मैच के बजाय कष्ट-सहन प्रतियोगिता थी। १९४६ के शुरू में यद्यपि पहले किसी भी समय से अधिक

रियायतें दे सकें और इन मामलों को तय करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी पर निर्भर किया जा सके। २० अक्तूबर को राष्ट्रपति ने कहा कि "मज़दूरों पर आए धक्के को सम्हालने, पर्याप्त क्रय शक्ति बनाए रखने, और राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए वेतनों में वृद्धियाँ अनिवार्य हैं,...सौभाग्य से मूल्यों के वर्तमान स्तर को कायम रखते हुए ही उद्योग के लिए वेतन दरों में इन रियायतों को देने की गुंजायश मौजूद है।"

इस नीति के बखान को न्यू डील के राजनीतिक पक्षपात को जारी रखने का प्रयत्न कहकर उसकी अधिक आलोचना की गई। सेनेटर टैफ्ट ने गुस्से से इसे सी. आई. ओ. के सामने घुटने टेक देना कहा किन्तु राष्ट्रपति के दुश्मन यद्यपि इसे तुष्टीकरण कहकर उनके कार्यक्रम की आलोचना कर सकते हैं तो भी युद्ध के बाद मज़दूरों का समर्थन करने की उनकी नीति उस विचारधारा की पुष्टि करती थी जिसमें राष्ट्र के करोड़ों औद्योगिक मज़दूरों की बेकारी से रक्षा करना और उनका जीवन स्तर उन्नत करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना सरकार का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय क्रयशक्ति को बनाए रखना ट्रूमन के चिन्तन में भी उतना ही बुनियादी था जितना रूज़वेल्ट के चिन्तन में। समग्र देश की खुशहाली के लिए मज़दूरों की खुशहाली को आवश्यक समझा गया।

तो भी स्थिरीकरण प्रोग्राम को अस्त-व्यस्त किए बिना राष्ट्रपति द्वारा सुझाई गई वेतन-वृद्धियाँ किस हद तक दी जा सकती हैं, यह विषय बहुत विवादास्पद बना रहा। ट्रूमन की स्थिति सरकार के उन सर्वेक्षणों से और मजबूत हो गई थी जिन्होंने यह जाहिर किया कि उद्योग २४ प्रतिशत वेतन बढ़ाकर भी युक्तियुक्त मुनाफा कमा सकते हैं। युद्धकाल में कम्पनियों का रिकार्ड देखने से पता चला कि उन्हें युद्ध-पूर्व के समय की अपेक्षा २॥ गुना कमाई हुई है और युद्ध लाभबन्दी तथा अनुपरिवर्तन (वार मोबिलाईजेशन ऐण्ड रिकन्वर्शन) के निदेशक जॉन आर. स्टीलमैन ने अक्तूबर, १९४६ में रिपोर्ट दी कि टैक्स कटकटा कर बचने वाले मुनाफे अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा हैं। किन्तु उद्योगों के प्रवक्ताओं ने इन रिपोर्टों की प्रामाणिकता से स्पष्ट इन्कार किया, स्थिति का बिल्कुल भिन्न विश्लेषण किया और कहा कि

क वेतनों से लागत बहुत बढ़ जायगी, जिसे शायद मौजूदा मूल्य-ढाँचे में

खपाया न जा सके।

इसके बाद वेतन और मुनाफों के बारे में समाप्त न होने वाली जो बहस छिड़ पड़ी उसमें सच्चाई कहीं भी हो, तथ्य यह था कि यह मामला सामूहिक सौदेबाज़ी पर छोड़ दिया जाना कामयाब नहीं रहा। शायद सरकारी नियंत्रण के ज़माने में मज़दूर और उद्योग दोनों को ही इस तरीके को आज़माने के लिए जंग लग गया था और कुछ भी हो उन्होंने परस्पर मिल बैठने की कोई इच्छा ज़ाहिर नहीं की। मज़दूर मौजूदा प्रतिघण्टा दर में ३० प्रतिशत वृद्धि की माँग कर रहे थे और उद्योगों का कहना था कि इतनी वेतन वृद्धि वे तब तक नहीं दे सकते जब तक कि चीज़ों की ऊँची कीमतों के रूप में उन्हें उसका भार आम जनता पर डालने की अनुमति नहीं दी जाती। तब जब यूनियनों ने यह सिद्ध करने के लिए कि मूल्य बढ़ाए बिना वेतन-वृद्धियाँ दी जा सकतीं हैं, कम्पनी के रिकार्डों की छानबीन करने का अधिकार दिए जाने की प्रार्थना की तो प्रबन्धकों ने उलटकर तेज़ी से प्रहार किया और कहा कि यह उनके कार्यों पर अतिक्रमण की कोशिश करना और व्यवसाय के परिचालन पर मज़दूरों के नियंत्रण के लिए द्वार खोलना है। इस तरह के सब प्रस्तावों को उद्योग को दी गई एक चुनौती समझा गया और व्यवसाय की स्वतंत्रता के नाम पर उनका विरोध किया गया।

मज़दूरों की माँग के विरोध में इस तथ्य से भी मज़बूती आई कि बहुत-सी कम्पनियाँ उस अग्नि-परीक्षा का स्वागत करने की स्थिति में थीं जिसका देर-सवेर आना अवश्यम्भावी था। १९४६ में घाटा होने की हालत में पहले दिए गए अत्यधिक मुनाफा-कर में से एक अंश की वापसी का अधिकार सीमित उत्पादन के संभावित प्रभावों का महत्त्वपूर्ण मुआवज़ा था। किन्तु अगर उद्योग अपनी रक्षा के लिए कृतसंकल्प था तो मज़दूरों का 'आक्रमण' का इरादा उनसे भी पक्का था। और भी अधिक व्यापक मोर्चे पर झगड़े बढ़ने लगे और राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध बोर्ड के पास स्मिथ-कौनाली ऐक्ट की शर्तों के मुताबिक हड़ताल-मत लिए जाने की प्रार्थनाओं का ढेर लग गया। अक्तूबर, १९४५ तक ऐसी ८०० प्रार्थनाएँ बोर्ड के पास पहुँच चुकी थीं और अधिकांश मामलों में इस बात की कोई परवाह नहीं की गई थी कि हड़ताल-मत लिए जाने पर उसका परिणाम क्या होगा।

सामूहिक सौदेबाजी की विफलता और गंभीर औद्योगिक अशांति की ऐसी बढ़ती हुई साक्षी को देखकर राष्ट्रपति ट्रूमन १६१६ में ऐसी ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति विल्सन की तरह मज़दूर-प्रबन्धक सम्मेलन की ओर झुके। ५ नवम्बर, १६४५ को यूनियनों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों को वाशिंगटन बुलाया गया और उनसे "औद्योगिक शांति तथा प्रगति के लिए एक व्यापक और स्थायी आधार" नियत करने की कोशिश करने को कहा गया। वे बाकायदा मिले और बातचीत हुई किन्तु इसमें उन्हें उससे ज्यादा सफलता नहीं मिली, जितनी विल्सन को मिली थी। सामूहिक सौदेबाज़ी के बुनियादी सिद्धान्त पर एक सामान्य समझौता कर सकना संभव हुआ जो १६१६ की स्थिति पर वास्तव में एक वास्तविक प्रगति थी, किन्तु कार्यविधि के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका जिससे वर्तमान गतिरोध दूर हो सकता। श्रम विभाग की मेल कराने वाली सेवा के विस्तार की सिफारिश करने के अलावा सम्मेलन का कोई क्रियात्मक परिणाम नहीं निकला।

इसकी विफलता अप्रत्याशित नहीं थी क्योंकि जब इसकी बैठकें चल रही थीं तभी हड़तालों की लहर जिसकी पतझड़ के शुरू में ही आशंका की जा रही थी, पूरी तेज़ी से आ गई। तेल साफ़ करने वाले कारखानों के कर्मचारी, काष्ठ कर्मचारी, कांच कर्मचारी, सानफ्रांसिस्को में मशीन चालक और जहाज़ी घाट के कर्मचारी, न्यूयार्क में इमारती मजदूर और ज़हाज़ों पर माल लादने उतारने का काम करने वाले कर्मचारी, मिडवेस्ट के ट्रक ड्राइवर और पेंसिलवेनिया के कोयला खनिक उस विद्रोह की अगली पंक्ति में थे जो सारे देश में फूट पड़ा था। बीसियों शहरों में प्रदर्शन-पट्ट लिए जलूस निकाले गए जिनमें यूनियन सुरक्षा तथा युद्धकालीन वेतनों के बराबर घर ले जा सकने वाली तनख्वाह की माँग की गई। उस वक्त नारा था "४० के बदले ५२, वरना संघर्ष।"

तब २१ नवम्बर को १२ राज्यों में जनरल मोटर्स के कारखानों के कोई २ लाख कर्मचारियों ने काम बन्द कर दिया जिससे राष्ट्रव्यापी हड़तालियों की संख्या ५ लाख पहुँच गई और एक सप्ताह बाद मनहूस वोट ने ७,५०,००० इस्पात कर्मचारियों की आसन्न हड़ताल की सूचना दी। नवम्बर [illegible] दिन जब मजदूरों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधि वाशिंगटन में अपना

बोरिया-बिस्तर समेट रहे थे तब राष्ट्र के सामने एक ऐसा संकट खड़ा था जिससे अनु-परिवर्तन (युद्धकालीन अर्थतंत्र को पुनः शांतिकालीन अर्थतंत्र में लाना) का सारा प्रोग्राम खतरे में पड़ गया।

जनरल मोटर्स की हड़ताल न केवल अपने आप में महत्त्वपूर्ण थी, बल्कि इसलिए भी इसका महत्त्व था कि १९४६ के शुरू में जिन हड़तालों ने इतने व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय अर्थतन्त्र को छिन्न-भिन्न किया यह उनका एक नमूना था। जैसा खयाल था उससे पहले ही यह प्रारम्भ हो गई थी। सी. आई. ओ. के कुशल नीतिज्ञ पहली परख इस्पात के बुनियादी उद्योग में करना चाहते थे जिस पर अन्य सब निर्माता उद्योग इतना ज्यादा निर्भर करते थे; किन्तु मोटर कर्मचारियों में व्याप्त अशांति तथा यूनियन की राजनीति ने युनाइटेड आटोमोबाइल वर्कर्स को मजबूर कर दिया था। युद्धोत्तर काल के वस्तुतः पहले बड़े पैमाने के मज़दूर-प्रहार की बड़ी चोट जनरल मोटर्स को सहन करनी पड़ी।

इस समय यू. ए. डब्लू. का अध्यक्ष यद्यपि आर. जे. टामस था तो भी जनरल मोटर्स की हड़ताल का संचालन वाल्टर रूथर के ओजपूर्ण नेतृत्व में किया गया। रूथर मोटर कर्मचारियों की यूनियन में एक उदीयमान नक्षत्र था जो शीघ्र ही संघर्ष करते-करते इसका अध्यक्ष बन गया। अभी वह ४० वर्ष का भी नहीं हुआ था कि मज़दूर संघर्षों में उसे अनुभवी समझा जाने लगा था और फोर्ड कारखानों में कर्मचारियों का संगठन करने के शुरू के प्रयत्नों में कम्पनी के सर्विस विभाग के कर्मचारियों ने उसे बुरी तरह पीटा था। देखने में वह कठोर संघर्षकारी मज़दूर नेता के बजाय एक नौजवान समृद्ध उद्योगपति-सा लगता था; कठिन रुचि का, अच्छे वस्त्र पहनने वाला, गम्भीर स्वभाव का रूथर अपने जिम्मे लिए गए काम के प्रति दृढ़ आस्थावान तथा साथ ही अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी साबित हुआ। वह न धूम्रपान करता था और न शराब पीता था और समाज के झंझटों से अलग रहकर एकाग्रभाव से अपनी सारी शक्तियाँ एक जगह केन्द्रित करते हुए वह सदा अपने काम में ही जुटा रहता था जिसकी बदौलत वह शनैः-शनैः समस्त मज़दूर आंदोलन में एक अत्यन्त शक्तिशाली नेता बन गया।

सामूहिक सौदेबाजी की विफलता और गंभीर औद्योगिक अशांति की ऐसी बढ़ती हुई साक्षी को देखकर राष्ट्रपति ट्रूमन १९१९ में ऐसी ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति विलसन की तरह मजदूर-प्रबन्धक सम्मेलन की ओर झुके। ५ नवम्बर, १९४५ को यूनियनों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों को वाशिंगटन बुलाया गया और उनसे "औद्योगिक शांति तथा प्रगति के लिए एक व्यापक और स्थायी आधार" नियत करने की कोशिश करने को कहा गया। वे बाकायदा मिले और बातचीत हुई किन्तु इसमें उन्हें उससे ज्यादा सफलता नहीं मिली, जितनी विलसन को मिली थी। सामूहिक सौदेबाज़ी के बुनियादी सिद्धान्त पर एक सामान्य समझौता कर सकना संभव हुआ जो १९१९ की स्थिति पर वास्तव में एक वास्तविक प्रगति थी, किन्तु कार्यविधि के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका जिससे वर्तमान गतिरोध दूर हो सकता। श्रम विभाग की मेल कराने वाली सेवा के विस्तार की सिफारिश करने के अलावा सम्मेलन का कोई क्रियात्मक परिणाम नहीं निकला।

इसकी विफलता अप्रत्याशित नहीं थी क्योंकि जब इसकी बैठकें चल रही थीं तभी हड़तालों की लहर जिसकी पतझड़ के शुरू में ही आशंका की जा रही थी, पूरी तेज़ी से आ गई। तेल साफ़ करने वाले कारखानों के कर्मचारी, काष्ठ कर्मचारी, कांच कर्मचारी, सानफ्रांसिस्को में मशीन चालक और जहाजी घाट के कर्मचारी, न्यूयार्क में इमारती मज़दूर और जहाज़ों पर माल लादने उतारने का काम करने वाले कर्मचारी, मिडवेस्ट के ट्रक ड्राइवर और पेंसिलवेनिया के कोयला खनिक उस विद्रोह की अगली पंक्ति में थे जो सारे देश में फूट पड़ा था। बीसियों शहरों में प्रदर्शन-पट्ट लिए जलूस निकाले गए जिनमें यूनियन सुरक्षा तथा युद्धकालीन वेतनों के बराबर घर ले जा सकने वाली तनख्वाह की माँग की गई। उस वक्त नारा था "४० के बदले ५२, वरना संघर्ष।"

तब २१ नवम्बर को १२ राज्यों में जनरल मोटर्स के कारखानों के कोई २ लाख कर्मचारियों ने काम बन्द कर दिया जिससे राष्ट्रव्यापी हड़तालियों की संख्या ५ लाख पहुँच गई और एक सप्ताह बाद मनहूस वोट ने ७,५०,००० इस्पात कर्मचारियों की आसन्न हड़ताल की सूचना दी। नवम्बर [illegible] दिन जब मजदूरों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधि वाशिंगटन में अपना

बोरिया-बिस्तर समेट रहे थे तब राष्ट्र के सामने एक ऐसा संकट खड़ा था जिससे अनु-परिवर्तन (युद्धकालीन अर्थतंत्र को पुनः शांतिकालीन अर्थतंत्र में लाना) का सारा प्रोग्राम खतरे में पड़ गया।

जनरल मोटर्स की हड़ताल न केवल अपने आप में महत्त्वपूर्ण थी, बल्कि इसलिए भी इसका महत्त्व था कि १९४६ के शुरू में जिन हड़तालों ने इतने व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय अर्थतन्त्र को छिन्न-भिन्न किया यह उनका एक नमूना था। जैसा खयाल था उससे पहले ही यह प्रारम्भ हो गई थी। सी. आई. ओ. के कुशल नीतिज्ञ पहली परख इस्पात के बुनियादी उद्योग में करना चाहते थे जिस पर अन्य सब निर्माता उद्योग इतना ज़्यादा निर्भर करते थे; किन्तु मोटर कर्मचारियों में व्याप्त अशांति तथा यूनियन की राजनीति ने युनाइटेड आटोमोबाइल वर्कर्स को मजबूर कर दिया था। युद्धोत्तर काल के वस्तुतः पहले बड़े पैमाने के मज़दूर-प्रहार की बड़ी चोट जनरल मोटर्स को सहन करनी पड़ी।

इस समय यू. ए. डब्लू. का अध्यक्ष यद्यपि आर. जे. टामस था तो भी जनरल मोटर्स की हड़ताल का संचालन वाल्टर रूथर के ओजपूर्ण नेतृत्व में किया गया। रूथर मोटर कर्मचारियों की यूनियन में एक उदीयमान नक्षत्र था जो शीघ्र ही संघर्ष करते-करते इसका अध्यक्ष बन गया। अभी वह ४० वर्ष का भी नहीं हुआ था कि मजदूर संघर्षों में उसे अनुभवी समझा जाने लगा था और फोर्ड कारखानों में कर्मचारियों का संगठन करने के शुरू के प्रयत्नों में कम्पनी के सर्विस विभाग के कर्मचारियों ने उसे बुरी तरह पीटा था। देखने में वह कठोर संघर्षकारी मज़दूर नेता के बजाय एक नौजवान समृद्ध उद्योगपति-सा लगता था; कठिन रुचि का, अच्छे वस्त्र पहनने वाला, गम्भीर स्वभाव का रूथर अपने जिम्मे लिए गए काम के प्रति दृढ़ आस्थावान तथा साथ ही अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी साबित हुआ। वह न धूम्रपान करता था और न शराब पीता था और समाज के झंझटों से अलग रहकर एकाग्रभाव से अपनी सारी शक्तियाँ एक जगह केन्द्रित करते हुए वह सदा अपने काम में ही जुटा रहता था जिसकी बदौलत वह शनैः-शनैः समस्त मज़दूर आंदोलन में एक अत्यन्त शक्तिशाली नेता बन गया।

उसके विचार व्यापक और समावेशक थे जो उसे व्यावसायिक यूनियनवाद की तात्कालिक समस्याओं से बहुत दूर ले जाते थे। रूथर का विश्वास था कि मजदूर "समाज के साथ प्रगति करके ही" अब तक प्राप्त किए गए लाभों को स्थिर रख सकते हैं। उसके विचारों में कुछ-कुछ समाजवादी सिद्धान्तों की छाया थी किन्तु यू. ए. डब्लू. के अन्दर कम्युनिस्ट तत्त्वों का वह प्रबल विरोधी था और अध्यक्ष बनने के बाद वह निरन्तर उनका मुकाबला करता रहा और अन्त में उन्हें सत्ता से च्युत कर दिया। उसके बुनियादी दृष्टिकोण अमरीकी प्रगतिवाद की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुरूप थे। रूथर का विश्वास था कि संगठित श्रमिकों को देश के राजनीतिक और आर्थिक जीवन में बड़ी भूमिका अदा करनी चाहिए।

एक बार उसने कहा कि "हम जैसा मजदूर आन्दोलन चाहते हैं वह अपने वेतन के लिफाफे में पैसे आए जान सन्तुष्ट हो जाने वाले किस्म का नहीं है। हम मजदूर आन्दोलन का निर्माण इसलिए नहीं कर रहे कि पुरानी दुनिया को सुधारें जिससे आदमी कई बार भूखा रहे बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि एक नई दुनियाँ बनाएँ जिसमें मजदूरों को अपने श्रम का लाभ मिले।"

इसी विचारधारा से प्रेरित होकर उसने जनरल मोटर्स की हड़ताल का संचालन किया। यूनियन ३० प्रतिशत वेतन-वृद्धि की माँग कर रही थी। रूथर का कहना था कि मोटरों के मूल्य में कोई वृद्धि किए बिना इतना वेतन बढ़ाया जा सकता है। आँकड़ों की साक्षियाँ इसकी पुष्टि कर रही थीं। उसने कहा कि कीमतें न बढ़ने देने के लिए वह उद्योग की क्षमता से ज्यादा वेतन-वृद्धि की माँग नहीं कर रहा। वह सिर्फ मोटर कर्मचारियों के लिए अधिक वेतन के बजाय राष्ट्रीय क्रयशक्ति और मूल्यों के स्थिरीकरण की दृष्टि से सोच रहा था। जब जनरल मोटर्स ने यह घोषित कर दिया कि उसके लिए १० प्रतिशत से अधिक वृद्धि कर सकना संभव नहीं है और यूनियन की शर्तें "पंच-फैसले का प्रस्ताव नहीं बल्कि कारखाना छोड़ देने की माँग है" तो रूथर का जवाब 'हिसाब की किताबें दिखाई जाएँ," आगे चलकर उसकी इस माँग ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। कम्पनी ने जब क्रोधपूर्वक ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करना अस्वीकार कर दिया तो करार की बातचीत भंग हो गई और जनरल मोटर्स की हड़ताल शुरू हो गई।

इन घटनाओं के तथा इस्पात की आगामी हड़ताल के प्रकाश में ट्रूमन के सामने उनकी युद्धोत्तर श्रम नीति की विफलता आ खड़ी हुई। वे औद्योगिक सम्बन्धों में सरकार का हस्तक्षेप अब भी कम से कम रखना चाहते थे किन्तु ऐसी कोई कार्रवाई करने के लिए विवश थे जिससे तुरन्त श्रमिक शांति कायम करने में मदद मिलती और मुद्रा प्रसार के बढ़ते हुए खतरे में आम स्थिरीकरण कार्यक्रम को बल प्रदान करती। उन्होंने किसी भी हड़ताल के आह्वान से पूर्व ३० दिन शांति रखने का प्रस्ताव किया और इस बीच विवाद-ग्रस्त मामले राष्ट्रपति के तथ्यान्वेषक बोर्डों को सुपुर्द करने के लिए कहा जो सब सम्बद्ध जानकारी के सम्बन्ध में खुल्लमखुल्ला अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों का सुझाव स्वीकार करते हुए कहा कि इन तथ्यान्वेषक बोर्डों को औद्योगिक रिकार्डों की समीक्षा करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।

मज़दूरों अथवा उद्योगों में से किसी ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया। मज़दूरों ने कहा कि इससे उनके हड़ताल करने के अधिकार पर आँच आती है, और उद्योग सरकारके "जाल में फँसाने के अभियान" के लिए कम्पनी के खाते खोलने को तैयार नहीं थे। जब किसी भी क्षेत्र से इतना कम सहयोग मिला तो कांग्रेस ने राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर कोई कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया।

किन्तु जहाँ तक तथ्यान्वेषक बोर्डों की नियुक्ति का प्रश्न था ट्रूमन ने अपने अधिकार की बदौलत आगे बढ़ने का निश्चय किया और २७ नवम्बर, १९४५ तथा १७ जनवरी, १९४६ के बीच ऐसे ६ बोर्ड नियुक्त किए गए। पहला बोर्ड तेल साफ करने के कारखानों में चल रही हड़ताल के लिए नियुक्त किया गया, जहाँ सरकार कारखानों पर पहले ही कब्जा कर चुकी थी। किन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण बोर्ड जनरल मोटर्स के झगड़े में १२ दिसम्बर को नियुक्त किया गया। जनरल मोटर्स के प्रबन्धकों ने सहयोग करने से इन्कार कर दिया। जब ट्रूमन ने यह कहा कि "वेतन देने की क्षमता प्रासंगिक चीज है" तो जनरल मोटर्स ने बोर्ड की सुनवाई का बहिष्कार कर दिया। आटो मोबाइल की हड़ताल टूटने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि यूनियन और कम्पनी दोनों अपने-अपने मूल प्रस्तावों पर अड़े रहे। यह गतिरोध छठे सप्ताह तक भी चलता रहा

जब कि मजदूर अब भी काम पर नहीं जाते थे और कम्पनी के कारखाने बन्द पड़े थे। तनातनी बढ़ती गई जबकि विवाद के दोनों फ़रीकों की नीयत पर आरोप-प्रत्यारोपों ने मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच खाई पैदा करने वाले अविश्वास और विद्वेष को और बढ़ा दिया।

इस बीच जब सी० आई० ओ० यूनियनों ने सामूहिक उत्पादन के उद्योगों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान की अपनी नीति को और विकसित किया तो हड़तालें अन्य उद्योगों में भी फैलने लगीं। तेल साफ करने के कारखानों में विवाद, जिसमें ४०,००० कर्मचारी हड़ताल पर थे, अभी हल नहीं हुआ था; वर्ष की समाप्ति के शीघ्र पश्चात् मांस पैक करने वाले २,००,००० कर्मचारियों ने हड़ताल करदी और इन कारखानों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया; इसके बाद जनरल इलैक्ट्रिक, वेस्टिंग हाउस और जनरल मोटर्स के वैद्युतिक उपकरण विभाग में हड़ताल के कारण हड़तालियों की संख्या १,८०,००० और बढ़ गई; और अन्त में २१ जनवरी को ७,५०,००० इस्पात कर्मचारियों ने अपने एक पूर्व वोट के मुताबिक काम बन्द कर दिया। जनरल मोटर्स के कर्मचारियों को मिलाकर इस समय समस्त राष्ट्र में एक साथ हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की संख्या २०,००,००० की विशाल संख्या पर जा पहुँची थी। एक छोर से दूसरे छोर तक अखबारों की सुर्खियों में औद्योगिक संकट की गम्भीरता पर बल दिया गया और जनता ने कुछ-न-कुछ औद्योगिक शांति कायम करने के लिये निर्णायक कार्रवाई की मांग की। सबका ध्यान खास तौर से इस्पात पर था। इसका उत्पादन करीब करीब बिल्कुल ठप्प हो जाने के कारण जब अन्य उद्योगों पर भी बढ़ते हुए औद्योगिक लकवे का प्रभाव पड़ा तो हजारों अन्य कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया।

ट्रूमन अपने तथ्यान्वेषण कार्यक्रम पर अटल रहे। अधिक सीधी कार्रवाई के लिए लोकमत की मांग बावजूद उन्होंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक विभिन्न सम्बन्धित उद्योगों के बारे में जाँच-पड़ताल से हड़तालों के समाधान का ऐसा तरीका न निकल आए जिससे मजदूरों की उचित मांगें भी पूरी हो जाएँ और मूल्य भी स्थिर रहें। अन्त में यह नीति अपनायी गई कि १९४१ के बाद से अनुमानतः रहन-सहन के खर्च में जो ३० प्रतिशत वृद्धि हुई है उसके अनुरूप वेतन-वृद्धि की ...नति दे दी जाए और यदि किसी कम्पनी की आय युद्ध-पूर्व की औसत आय

से कम है तो उसके माल की कीमतों में आवश्यक वृद्धि की अनुमति प्रदान की जाए। इस कार्यक्रम को अमल में लाने का अभिप्राय था कि लिटल स्टील फार्मूले के अन्दर जो वेतन-वृद्धि प्रदान की गई है उससे विभिन्न उद्योगों में १७॥ से २० प्रतिशत अधिक वेतन प्रदान किए जाने का अधिकार दिया जाए यद्यपि मजदूरों की माँग ३० प्रतिशत वृद्धि किए जाने की थी। इस फार्मूले से व्यवहारतः १८॥ सेण्ट प्रति घण्टा वेतन-वृद्धि हुई और इससे रहन-सहन के बढ़े हुए खर्च के अनुरूप काफी हद तक वेतन-दर में हेर-फेर करना सम्भव हुआ यद्यपि ओवरटाइम का सिलसिला खत्म हो जाने के कारण मजदूरों द्वारा प्रति सप्ताह घर ले जायी जाने वाली तनख्वाह युद्ध-कालीन स्तर से तब भी काफी कम रही।

नई वेतन-मूल्य नीति की १४ फरवरी को बाकायदा घोषणा कर दी गई और इस तारीख से पहले ही इसी रूपरेखा पर तेलशोधक कारखानों तथा पैकिंग उद्योगों में झगड़े निबटा लिए गए थे। किन्तु इस्पात के विवाद पर इसको लागू करना औद्योगिक गतिरोध को भंग करने में और भी निर्णायक सिद्ध हुआ। इस विवाद में यूनाइटेड स्टील वर्कर्स और उनके मालिकों के बीच, जिनके प्रवक्ता थे, यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरेशन के अध्यक्ष फेयरलेस, मतभेद शनैः-शनैः पहले ही काफी कम कर लिए गए थे और राष्ट्रपति ट्रूमन ने तब सीधा १८½ सेण्ट प्रति घण्टा वेतन वृद्धि का समझौता-प्रस्ताव रखा। किन्तु यूनियन ने जहाँ यह वेतन-वृद्धि तुरन्त स्वीकार करली वहाँ उद्योग ने इसे तब तक मानने से इन्कार कर दिया जब तक उसे कीमतों में राहत देने का कोई निश्चित आश्वासन प्रदान नहीं किया जाता। जब नई वेतन-मूल्य-नीति लागू की गई और इस्पात उद्योग को एक टन इस्पात पर ५ डालर कीमत बढ़ा देने की अनुमति प्रदान करने की विशेष व्यवस्था की गई तो समझौते में अंतिम बाधा भी दूर हो गई। तीन सप्ताह की हड़ताल के बाद जिसमें देशभर में भट्टियाँ ठण्डी हो गई थीं और उत्पादन कुल क्षमता का सिर्फ ६ प्रतिशत रह गया था, राष्ट्रपति के फार्मूले के आधार पर यूनियन और प्रबन्धकों में समझौता हो गया।

जनरल मोटर्स की हड़ताल को निबटाना अभी बाकी था और अंतिम समझौता होने से पूर्व इसे चलते हुए चार महीने हो चुके थे, जिसमें मजदूरों

को १३,००,००,००० डालर की और कम्पनी को ६० करोड़ डालर की हानि उठानी पड़ी। नए करार में १८½ प्रतिशत वेतन वृद्धि प्रदान की गई। वैद्युतिक कर्मचारियों को भी समझौता करने में काफी देर लगी किन्तु वहाँ भी अन्ततः १८½ प्रतिशत की सामान्य वेतन वृद्धि के फार्मूले पर समझौता हो गया। मार्च तक देशभर में हड़तालियों की संख्या घटकर २,००,००० से भी कम रह गई और वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्र के सामने जो संकट दिखाई देता था वह हल हो गया था। अनुपरिवर्तन के कार्यक्रम को काफी धक्का पहुँचा था किन्तु राष्ट्रीय अर्थ-तंत्र की लोच ने तेज़ी से पुनः अपना करिश्मा दिखाया।

तो भी यह सवाल बना रहा कि औद्योगिक शांति के लिए क्या बहुत बड़ी कीमत अदा नहीं की गई। जिन उद्योगों में हड़तालें हुई थीं उनसे इतर उद्योगों के कर्मचारियों ने भी स्वभावतः अपने वेतन तथ्यान्वेषक बोर्डों द्वारा सिफारिश स्तर तक बढ़ाए जाने की माँग की और उस समय की परिस्थितियों में मालिकों के पास उनकी माँग को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अप्रैल में राष्ट्रीय वेतन स्थिरीकरण बोर्ड के समक्ष ऐसे ४,००० ऐच्छिक समझौते स्वीकृति के लिए पेश किए गए और उस ज़माने में औद्योगिक मज़दूरों को औसतन प्रतिशत की वेतन-वृद्धि प्रदान की गई।

मूल्य नियंत्रण का कोई प्रभावशाली कार्यक्रम इन अपेक्षाकृत सीमित वेतन-वृद्धियों से उत्पन्न महँगाई के दबाव के सामने क्या सफल हो सकता था? खतरे के संकेत स्पष्ट नज़र आ रहे थे। तो भी ट्रूमन का अपनी सफलता में विश्वास बना रहा। अपनी नई वेतन-मूल्य नीति का दिग्दर्शन कराते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि "रेखा में खरोंच जरूर आ गयी है किन्तु अगर आप सब मेरे साथ सहयोग करेंगे तो इसे कहीं से कटने नहीं दिया जाएगा।"

किन्तु यहीं इति नहीं थी। मज़दूरों को इतने अधिक लाभ प्रदान करने वाली ये पहली हड़तालें मुश्किल से समाप्त ही हुई थीं कि कोयला खनिकों के लिए नए करार की बातचीत अनिवार्यतः भंग हो गई। लेविस से अलग रहने की आशा नहीं की जा सकती थी और समय को पहचानने में अपनी परम्परागत चतुराई के साथ वह अपनी माँगों में सी. आई. ओ. से भी एक कदम आगे बढ़ गया। सदा की भाँति वेतन-वृद्धि ही विवाद का मुख्य विषय थी किन्तु

खान मालिक जब राष्ट्रपति के नए फार्मूले को स्वीकार करने को तत्पर हो गए तो उसने कामकी हालतों में अतिरिक्त सुरक्षितताएं प्रदान किए जाने तथा खान से निकाले गए प्रत्येक टन कोयले पर खनिक कल्याण कोष के लिए ७ सेण्ट की रायल्टी जमा कराए जाने का आग्रह किया। जब प्रबन्धकों ने यह कह कर कि रायल्टी से ६,००,००,००० डालर का वार्षिक खर्चा बढ़ जाएगा, उसकी माँग नामंजूर करदी तो लेविस यकायक सम्मेलन से बाहर चला गया और उसने कहा बताते हैं, "नमस्कार, भाइयो! हमें विश्वास है कि अब समय ही, जब वह तुम्हारी थैलियों में कटौती कर देगा, शायद तुम्हारे कंजूसी से भरी और समाज-विरोधी नीयत में सुधार करेगा।" एक अप्रैल को पश्चिम पेंसिलवेनिया, पश्चिम वर्जीनिया, अलाबामा, केण्टकी, इलिनीयस और आयोवा के छोटे-छोटे नीरस नगरों में कोई ४ लाख खनिकों ने खानों में अपने कामों से एक बार फिर छुट्टी मनाई।

पहले की कोयला हड़तालों का ही ढर्रा दोहराया गया। प्रस्तावों, प्रति प्रस्तावों से कोई लाभ नहीं हुआ, मध्यस्थता के प्रयत्न पूर्णतः विफल हो गए, एक अस्थायी विरामसंधि शीघ्र भंग हो गई और दुराग्रही खनिकों का सरदार जो पिछले १३ वर्षों में अपने तौर-तरीकों से खनिकों का वेतन १५ डालर प्रति सप्ताह से बढ़ाकर ६३ डालर प्रति सप्ताह करवा देने में सफल रहा था, खान-मालिकों, सरकार और लोकमत को सदा की भाँति चुनौती देते हुए अपनी माँग पर डटा रहा। खानों से निकले हुए कोयले का स्टाक सिर्फ ३ सप्ताह का रह गया और इस्पात उद्योग अपनी आधी से कुछ अधिक क्षमता पर काम करने को मजबूर हो गया। माल-परिवहन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगा दिया गया और एक छोर से दूसरे छोर तक शहर, कोयले को सार्वजनिक उपयोग के लिए बचाने के हेतु फालतू रोशनी न करने का आदेश जारी करने को मजबूर हुए।

मई में १२ दिन की विराम संधि के दौरान नए सिरे से चलाई गई बातचीत जब फिर विफल हो गई तो बढ़ते हुए संकट ने सरकार को हस्तक्षेप के लिए मजबूर किया और उस अधिकार के मातहत जिसकी लेविस ने "बदनाम स्मिथ-कौनाली ऐक्ट" कह कर निन्दा की थी, खानों पर कब्जा कर लिया गया। और तब तूफान के समान समझौते के आगे के प्रबन्ध गृहमंत्री के सामंजस्य में

हुए जहाँ अन्ततः सरकार और यूनियन के बीच एक समझौता हो गया। खनिकों को १८½ सेण्ट प्रति घण्टा वेतन वृद्धि प्रदान की गई, सभी खानों में सुरक्षा के संघीय नियम लागू कर दिए गए और एक कल्याण कोष में ५ सेन्ट प्रति टन रायल्टी प्रदान किए जाने का निश्चय किया गया। कोष पर खान-मालिकों व यूनियन का संयुक्त प्रशासन रखा गया। कल्याण कोष के मामले में लेविस ने कुछ रियायतें जरूर दीं किन्तु सामान्यतः उसने एक और आश्चर्यजनक विजय प्राप्त की थी। यूनियन ने गर्वपूर्वक "सन् १८९० में यूनियन के जन्म के बाद से किसी एक ही वेतन-समझौते में यूनाइटेड माइन वर्कर्स द्वारा प्राप्त महानतम आर्थिक व सामाजिक लाभों" की घोषणा की।

यह समझौता एक और हड़ताल की पृष्ठभूमि में किया गया था जिसने अपने नाटकीय परिणामों के कारण इस संकटपूर्ण वर्ष में अन्य सब हड़तालों को फीका कर दिया। रेलवे कर्मचारियों और रेल कम्पनियों के बीच वेतन सम्बन्धी वार्ता भंग हो गई थी। रेलवे श्रम अधिनियम की भारी-भरकम मशीनरी एक बार फिर उस संकट को टालने में विफल रही जो इस्पात व कोयला उद्योगों में काम बन्द हो जाने से भी ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा को खतरा पहुँचा रहा था। हमारे बहुत अधिक अन्योन्याश्रित अर्थतंत्र में रेलवे हड़ताल का भीषण परिणाम हुए बिना नहीं रह सकता था तो भी सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए यथासम्भव कोई कदम उठाये बिना यह आसन्न प्रतीत हो रही थी। एक आपातकालीन बोर्ड अन्त में ऐसी शर्तें तैयार करने में कामयाब हुआ जिन्हें रेलवे के संचालन कार्य से असम्बद्ध यूनियनों और दो रेलवे-ब्रदरहुडों ने स्वीकार कर लिया। वे वेतन सम्बन्धी मामले पर पंचफैसले के लिए तथा नियमों में परिवर्तन की माँग को स्थगित करने के लिए राज़ी हो गई किन्तु इस बार रेलवे ट्रेनमैनों और लोकोमोटिव इंजीनियरों ने, जिनकी संख्या ३,००,००० थी, उनका साथ देने से इन्कार कर दिया। १८ मई से हड़ताल करने का आदेश जारी कर दिया गया।

१९४३ में रूज़वेल्ट की भाँति ट्रूमन ने तुरन्त ही रेलों पर कब्ज़ा किए जाने का आदेश जारी कर दिया। हड़ताल की नियत तारीख से एक दिन पहले उन पर कब्ज़ा कर लिया गया और राष्ट्रपति हड़ताल को ५ दिन स्थगित क॰ में सफल हो गए। किन्तु इस बीच यद्यपि अन्य सब यूनियनें तत्काल

वेतन-वृद्धियों के बोर्ड के फैसलों को मानने के लिये राजी हो गईं, ट्रेनमैन और इंजीनियर वेतन-वृद्धियों के अलावा नियमों में परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता की अपनी टेक से टस से मस नहीं हुए। २३ मई को हड़ताल हो गई। सब रेल परिवहन ठप्प हो गया। इंजनचालकों ने अपने गन्तव्य स्थानों पर पहुँच कर और कोई ट्रेन ले जाने से इन्कार कर दिया था।

अगले दिन राष्ट्रपति ने रेडियो पर ट्रेनमैनों और इंजनचालकों से राष्ट्र-व्यापी अपील की कि वे अपने यूनियन नेताओं के आदेशों की अवज्ञा कर काम पर लौट जाएँ। उन्होंने कहा, "यह हड़ताल आपकी सरकार के खिलाफ हड़ताल है......सरकार को इस चुनौती का सामना करना होगा वरना उसे अपनी अशक्तता स्वीकार करनी होगी" तब हड़तालियों को अल्टीमेटम दिया गया। उन्हें वही शर्तें पेश की गईं जो अन्य यूनियनों ने स्वीकार कर ली थीं लेकिन चेतावनी दी गई कि अगर अगले दिन तीसरे पहर ४ बजे तक वे काम पर नहीं लौटे तो सरकार रेलों का संचालन अपने हाथ में ले लेगी और "इस आवश्य-कता की घड़ी में अपने देश की पुकार पर जो कोई व्यक्ति भी ध्यान देगा" उसकी रक्षा के लिए सशस्त्र सैनिक मुहैया करेगी।

तब भी हठी यूनियन नेताओं ने—लोकोमोटिव इंजीनियर्स के ऐलवनले जौन्स्टन तथा रेल रोड ट्रेनमैन के ए. एफ. ह्विटनी ने अपने आदमियों को काम पर लौटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। चौथाई सदी पूर्व निरोधादेशों की कार्रवाई के बाद से अत्यन्त कठोर हड़ताल विरोधी कार्रवाइयों की तैयारी की गई और जब अल्टीमेटम की अवधि समाप्त होने को आई तो सारा देश उत्तेजित हालत में प्रतीक्षा कर रहा था और राष्ट्रपति अपनी नीति के लिए विशेष रूप से अधिकार माँगने काँग्रेस के समक्ष गए। यह एक विशेष संयुक्त अधिवेशन था—तनावपूर्ण और आतुरता से भरा हुआ।

ट्रूमन ने शुरूआत देशभक्ति के अभाव के लिए हड़ताली नेताओं की निन्दा से की। उन्होंने कहा कि बातचीत सर्वथा "दो व्यक्तियों के दुराग्रह-पूर्ण दम्भ" के कारण भंग हुई है। उन्होंने जन-हित को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी आपातकाल में हड़ताली नेताओं के खिलाफ निरोधादेश के लिए अर्जी देने के अस्थायी अधिकार की माँग की, साथ में हड़तालियों को वरिष्ठता के अधिकारों से वंचित करने और सरकार के खिलाफ हड़ताल करने पर

उन्हें जबरन सेना में भरती करने के हक की भी मांग की। जब वह भाषण देते-देते यहाँ तक आ पहुँचे तो यकायक उन्हें टोक दिया गया। एक क्लर्क ने उन्हें जल्दी-जल्दी में लिखा एक नोट अर्पित किया और चुप्पी के बीच उन्होंने मन्द स्वर में घोषणा की, "अभी-अभी सूचना मिली है कि रेलवे हड़ताल राष्ट्रपति की शर्तों पर खत्म कर दी गई है।" किन्तु इस घोषणा के स्वागत में तुमुल करतल ध्वनि जब शान्त हुई, तब ट्रूमन अपना तैयार किया हुआ वक्तव्य पढ़ते रहे। अपने मन्तव्य में कोई हेर-फेर किए बिना उन्होंने कांग्रेस से कहा कि मैं जिन कदमों का प्रस्ताव कर रहा हूँ, वे सख्त प्रतीत हो सकते हैं किन्तु तात्कालिक संकट का सामना करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने जरूरी हैं।

कांग्रेस के समक्ष आने से पूर्व क्या राष्ट्रपति को मालूम था कि हड़ताल वापस ले ली गई है? उनकी कार्रवाई ने बड़ा तीव्र विवाद उत्पन्न कर दिया। सेनेटर मोर्स ने आरोप लगाया कि ह्वाइट हाउस के सलाहकारों को दोपहर से पहले ही मालूम हो गया था कि दोनों ब्रदरहुडों ने झुक जाने का फैसला कर लिया है और इस तथ्य को राष्ट्रपति ने इसलिए छिपाया कि मजदूर-विरोधी भावना उग्र बनी रहे और वे कांग्रेस से अपना बिल पास करा लें। बीच में भाषण रोके जाने के बारे में सेनेटर की स्पष्टवादितापूर्ण टिप्पणी थी: "मैंने इतनी अधिक नाटकीयता का भद्दा प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा।" किन्तु अल्टीमेटम की अवधि खत्म होने का समय इतना नजदीक था कि इसका सही-सही विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यूनियनों और रेल कम्पनियों के बीच वास्तविक समझौते पर ३-५५ पर दस्तखत हुए, ३-५७ पर हड़ताल वापस ली गई और ट्रूमन की घोषणा ४-१० पर हुई।

प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति की अपील पर तुरन्त ध्यान दिया और १३ के खिलाफ ३०६ के भारी बहुमत से उनके द्वारा पेश किया गया बिल पास कर दिया। किन्तु जब रेल हड़ताल खत्म हो गई तो सेनेट में इस बिल का विरोध बढ़ गया। सामान्य गंठबन्धनों में विचित्र परिवर्तन हुआ। कंजरवेटिव, रिपब्लिकन और विशेषकर सेनेटर टैफ्ट ने सरकार के बिल को मजदूरों के प्रति अन्यायपूर्ण तथा उनके नागरिक अधिकारों पर आघात करने वाला बता उसकी निन्दा करने में नेतृत्व किया। उनके आग्रह पर प्रतिनिधि सभा

द्वारा पास किए गए बिल में पहले बुनियादी तौर पर संशोधन किया गया और जब तब भी विरोध खत्म नहीं हुआ तो कमेटी में जाकर वह निःशेष हो गया।

उदार क्षेत्रों और मज़दूरों में ट्रूमन के कार्यक्रम की तीव्र आलोचना हुई। राष्ट्रपति पर बिलकुल यूनियनों के खिलाफ हो जाने का आरोप लगाया गया। सी. आई. ओ. के सम्मेलन में उन्हें "अमरीकी बैंकरों और रेल कम्पनियों का अव्वल दर्जे का हड़तालभंजक" कहकर उनकी तीव्र निन्दा की गई और रेलवे ट्रेनमैनों के क्रुद्ध नेता ए. एफ. ह्विटनी ने उन्हें व्यंग्य से एक "राजनीतिक दुर्घटना" बताया। ट्रूमन अगर फिर चुनाव लड़ना चाहें तो उन्हें हराने के लिए यूनियन के खजाने में पड़े ४,७०,००,००० डालर के समस्त कोष का उपयोग करने का वचन दिया गया।

१९४६ की ग्रीष्म ऋतु में कुछ अन्य हड़तालें भी हुईं, या हड़तालों का खतरा सिर पर आया। अत्यन्त जटिल नौ-यातायात झगड़े कुछ समय के लिए विशेष रूप से विक्षोभकारी रहे। इनमें पूर्व-पश्चिम दोनों तटों पर ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. दोनों की यूनियनों से सम्बन्धित जहाज़ी मजदूरों ने भाग लिया। किन्तु करीब-करीब अन्तिम क्षण में समस्त जहाज़ यातायात ठप्प होने से बचा लिया गया। अन्य विवादों में टी. डब्लू. ए. हवाई सर्विस के पायलटों द्वारा २०,००० डालर के वेतन स्तर की माँग से लेकर हालीवुड के अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी झगड़े तक शामिल थे जिसमें मेकअप कलाकार तथा तरह-तरह की शैली के बाल बनाने में कुशल कारीगर मोशन पिक्चर कस्ट्यूमर्स के खिलाफ सन्नद्ध हो गए थे। किन्तु बड़े-बड़े उद्योगों में हड़तालें शांत हो गई थीं और देश अधिक आसानी से साँस ले पा रहा था।

जापान में विजय के बाद के १२ महीनों का रिकार्ड बहुत खराब रहा। कुल ४६३० हड़तालें हुईं जिनमें ५० लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। १२ करोड़ मनुष्य-दिवसों की हानि हुई। तो भी इन हड़तालों ने अनु-परिवर्तन कार्यक्रम में जो भी रुकावटें डालीं, उन सबके बावजूद उत्पादन और रोजगार वस्तुतः शांतिकाल के एक नए स्तर पर जा पहुँचे। दसियों लाख मजदूरों द्वारा अ-विद्यमान रोजगारों की खोज करने के बजाय, जैसा होने की भविष्यवाणी की गई थी, सेना से छँटनी किए गए व्यक्तियों को ज्यादातर

उद्योगों में खपा लिया गया। १९४६ के अन्त तक रोज़गार में लगे असैनिक कर्मचारियों की संख्या अब तक के सबसे ऊँचे रिकार्ड ५,५०,००,००० पर जा पहुँची थी।

उद्योगों के अनुपरिवर्तन में जो सफलता मिली वह महँगाई को रोकने में नहीं मिल सकी। वेतन-वृद्धियाँ प्राप्त कर लेने के बाद मज़दूर मूल्यों पर नियंत्रण जारी रखने के प्रबल समर्थक बन गए। दूसरी ओर उद्योग मूल्य-नियंत्रण उठा लेने के पक्ष में था। उसकी युक्ति यह थी कि उत्पादन की वृद्धि में रुकावट पड़ रही है और राष्ट्रीय आर्थिक तंत्र में संतुलन स्वाभाविक प्रतियोगिता तक ताकतों को खुली छूट देकर ज्यादा अच्छी तरह कायम किया जा सकता है। किन्तु जो चीज़ें युद्धकाल में उपलब्ध नहीं थीं उन्हें उत्पादन बढ़ाकर उपभोक्ता को उपलब्ध कराने तक क्या मूल्य स्थिर रह सकेंगे? मज़दूरों ने साफ कह दिया कि अगर रहन-सहन की लागत और बढ़ी तो नई वेतन-वृद्धि आवश्यक हो जाएगी। सी. आई. ओ. के अध्यक्ष मर्रे ने स्पष्ट चेतावनी दी कि १९४६ के प्रारम्भ के समझौते "वर्तमान सरकार के इस वचन और आश्वासन पर ही स्वीकार किए गए हैं कि मूल्य बढ़ने नहीं दिए जाएँगे।"

रेखा में खरोंच आ जाने पर भी मध्यग्रीष्म में स्थिरीकरण कार्यक्रम अभी कारगर प्रतीत हो रहा था। अप्रैल, १९४३ में जब राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने अपने मूल्य-वृद्धि-रोक आदेश की घोषणा की थी उसके बाद से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सिर्फ १० अंश बढ़ा था किन्तु जापान पर विजय होने के बाद से अनेक वेतन वृद्धियाँ देने के बावजूद यह अंक सिर्फ ४ अंश बढ़ा था किन्तु मूल्य-वेतन के सम्बन्धों में यह आपेक्षिक स्थिरता अल्प-स्थायी ही रही जबकि मौजूदा नियमों के विरोधियों ने सरकार की नीति पर एक के बाद एक चोटें कीं।

ओ. पी. ए. नियंत्रण जब पहली बार हटाए गए और आंशिक रूप से फिर लगा दिए गए और अन्ततः फिर खत्म हो जाने दिए गए, तब जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी के बारे में प्रशासन और उसके राजनीतिक दुश्मनों के बीच राजनीतिक संघर्ष के कारण गरमागरम आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए। ... हो, १९४६ तक स्थिरीकरण का सारा कार्यक्रम इतिहास बन चुका

था और जीवन-यापन का खर्चा तेजी से बढ़ रहा था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई में ७ अंश बढ़ गया था और सितम्बर में ४ अंश और बढ़ गया। वर्ष की समाप्ति पर यह मध्यग्रीष्म की अपेक्षा २० अंश अधिक हो गया था। १५३ पर पहुँच जाने के बाद इसमें पिछले ६ महीने में इतनी वृद्धि हो गई थी जितनी ओ. पी. ए. कण्ट्रोल के समस्त तीन वर्षों में नहीं हुई थी।

उद्योग ने वेतन-वृद्धियों के कारण इसकी ज्यादा जिम्मेदारी मजदूरों पर डाली और मजदूरों ने कहा कि मुनाफ़ों के ज्याद लोभ के कारण कसूरवार उद्योग है। इस प्रकार जब दोनों में मुखालफत बढ़ रही थी तो दोनों यह भूल गए कि जीवन-यापन का खर्चा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण खाद्य पदार्थों के मूल्यों में ३४ प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाना है। यह कटुतापूर्ण बहस चलती रही और उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस विवाद के कुहासे में से एक ही चीज प्रत्यक्ष हुई और वह थी निस्सन्देह बढ़ती हुई महँगाई।

इन चेतावनियों के बावजूद कि इन परिस्थितियों में और वेतन-वृद्धियों की माँग का मतलब होगा अतिरिक्त मूल्य-वृद्धि को खुला न्यौता देना, मजदूर अधिकाधिक बेचैन होते गए। एक के बाद एक यूनियन ने बढ़ती हुई मूल्य-तालिका के साथ कदम मिलाकर चलने के एकमात्र साधन के रूप में नई वेतन-वृद्धियों की माँग का आधार तैयार करना शुरू कर दिया। जब मोटर और इस्पात कर्मचारियों दोनों ने वर्तमान करारों पर पुनर्विचार करने को कहा तो १९४६ की शरद् ऋतु तक उद्योग को एक और चुनौती के लिए मंच तैयार हो गया। किन्तु वेतन-वृद्धियों के माँग के इस दूसरे दौर की शुरुआत का संदिग्ध श्रेय सी. आई. ओ. यूनियनों को नहीं मिला। यह काम यकायक लेविस ने अपने हाथ में ले लिया। नवम्बर में राष्ट्र को ५ वर्षों में ८वीं बार कोयला संकट का सामना करना पड़ा।

वर्ष के शुरू में सरकार से जो समझौता किया गया था उसके स्थान पर खनिकों और खान मालिकों के बीच एक नया करार कराने के सब प्रयत्न विफल हो गए। मालिकों के प्रस्ताव को ठुकराते हुए लेविस ने कहा : "हम नहीं चाहते कि तुम्हारे प्रस्ताव से आहिस्ता-आहिस्ता गला घोटे जाने के लिए हमें मूक पशुओं की तरह बूचड़खाने में घसीटकर ले जाया जाए।" यूनाइटेड माइन वर्कर्स की दलील यह थी मूल्य-वेतनों में अनुपात बदल जाने से सरकार

के साथ किए गए करार पर फिर से विचार करना ज़रूरी हो गया है और वेतन-वृद्धि तथा काम के घण्टों में कमी करने की दोनों माँगें उसने पेश कीं। गृहमंत्री क्रुग ने करार पर फिर से गौर करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक खानों पर सरकारी नियंत्रण है तब तक यह करार चलेगा और तब तक खनिकों को हड़ताल करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। जब लेविस अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और खनिक "करार नहीं तो काम नहीं" का अपना चिर-परिचित नारा लगाते हुए काम छोड़ गए तो क्रुग ने वाशिंगटन में संघीय जिलान्यायालय के न्यायाधीश टी. ऐलन गोल्ड्सबरो से हड़ताल से सम्बन्धित समस्त हलचल को रोकने के लिये निरोधादेश जारी किए जाने की प्रार्थना की।

स्थिति जैसी बताई गई, बड़ी नाजुक थी। अबकी बार यह निश्चय करके कि लेविस के सामने झुकना नहीं है, सरकार ने कहा कि खानों से अलग रहने का खनिकों का निश्चय एक हड़ताल ही है जो जनहित को खतरे में डाल रही है और जिसपर निरोधादेश की कार्रवाई किया जाना उचित है। यूनियन ने इसका तीव्र प्रतिरोध करते हुए कहा कि ऐसी कोई भी कार्रवाई नौरिस-ला गार्दिया ऐक्ट के खिलाफ होगी जिसके अन्तर्गत श्रम सम्बन्धी विवादों में निरोधादेश के प्रयोग की मुमानियत है और इसकी हड़ताल सरकार के खिलाफ नहीं है क्योंकि खानों पर गृहमंत्रालय का नियंत्रण नाममात्र का है। चूँकि अस्थायी रोक आदेश के बावजूद काम रुका रहा इसलिए मूल प्रश्न को अब समाधान के लिए अदालतों में ले जाया गया। सारा देश अमरीका के राष्ट्रपति और यूनाइटेड माइन वर्कर्स के अध्यक्ष के बीच उत्पन्न होने वाले इस स्पष्ट संघर्ष के परिणामों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था।

कानूनी कार्रवाई बहुत जटिल रही किन्तु इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि न्यायाधीश गोल्ड्सबरो ने फैसला दिया कि नौरिस-ला गार्डिया ऐक्ट उन श्रम-विवादों पर लागू नहीं होता, जिनमें एक फरीक सरकार हो और अपनी सार्वभौम सत्ता का प्रयोग करते हुए सरकार यूनियन को समाज को "एक सार्वजनिक विपत्ति" से बचाने का आदेश दे सकती है। जब लेविस ने भी अदालत के आदेश को मानने से इन्कार किया, तब उसके खिलाफ की तौहीन करने का अभियोग चलाया गया और ४ दिसम्बर को उसे

बाकायदा अपराधी घोषित कर दिया गया। यूनाइटेड माइन वर्कर्स पर ३५,००,००० डालर जुर्माने की और स्वयं लेविस को १०,००० डालर जुर्माना भरने की सज़ा दी गई।

इन घटनाओं से उत्पन्न अत्यधिक आवेशपूर्ण वातावरण में निरोधादेश के उपयोग पर बहस खनिकों के रवैये पर हुई पहली बहसों से भी ज्यादा उग्र थी। लेविस ने अदालत में कहा कि "मैं निरोधादेश द्वारा प्रशासन की भद्दी पुनरावृत्ति को स्वीकार नहीं कर सकता" और ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. दोनों में उसकी वैयक्तिक अप्रतिष्ठा के बावजूद मजदूरों ने सामान्यतः उसके कथन का समर्थन किया। दूसरी ओर गोल्ड्सबरो की इस युक्ति को कि "हड़ताल एक बुराई, शैतानी और स्वयं लोकतंत्रीय सरकार को एक खतरा है," आम जनता का व्यापक समर्थन मिला। कुछ समय तक तो खनिक फिर भी काम पर नहीं आए, किन्तु अदालत की तौहीन के जिम्मेदार ठहराये जाने के बाद लेविस ने एक अन्य विरामसंधि करते हुए उन्हें काम पर वापस जाने का आदेश दिया। सुप्रीमकोर्ट में तुरन्त अपील करने के प्रयत्न किए गए और लेविस ने कहा कि जब इस अदालत में मामले पर विचार हो रहा हो तब मैं "आर्थिक संकट के आतंक से उत्पन्न लोकमत के दवाव से" मुक्त हो जाना चाहता हूं।

अन्त में सुप्रीम कोर्ट ने निरोधादेश जारी करने और उसका पालन न करने पर लेविस तथा युनाइटेड माइन वर्कर्स दोनों को अदालत की मान-हानि का अपराधी घोषित करने के न्यायाधीश गोल्ड्सबरो के निर्णय को पुष्ट किया। यह सिद्धान्त, भले ही ४ के विरुद्ध ५ मतों से, स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर दिया गया कि जहाँ हड़ताल राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को खतरे में डालती हो उसके बारे में नौरिस-ला गार्दिया ऐक्ट सरकार को निरोधादेश प्राप्त करने से नहीं रोकता किन्तु युनाइटेड माइन वर्कर्स पर किया गया जुर्माना घटाकर इस शर्त पर ७,००,००० डालर कर दिया गया कि हड़ताल स्थायी रूप से वासप ले ली जाए और १९ मार्च को लेविस ने अन्ततः ऐसा आदेश जारी कर दिया।

लेविस को अस्थायी रूप से पीछे हटने को बाध्य होना पड़ा किन्तु कोयला खान मालिकों से उसकी सौदेबाजी की क्षमता को ज्यादा क्षति नहीं पहुँचे

थी। जब स्मिथ-कौनाली ऐक्ट की समाप्ति के बाद कोयला खानें ३० जून, १९४७ को पुनः निजी खानमालिकों को वापस करनी पड़ीं तो वह एक नया करार करने में सफल हुआ जिसमें वेतन वृद्धि प्रदान की गई, काम के घण्टे कम कर दिये गए और खनिक कल्याण कोष में रायल्टी चन्दे की मात्रा बढ़ा दी गई।

कोयला-विवाद के अंतिम रूप से हल होने के पहले ही एक वर्ष पूर्व-की-सी परिस्थितियों में अन्य यूनियनों ने वेतन-वृद्धि की माँगों का दूसरा दौर प्रारम्भ कर दिया था। १९४६ के बाद से जीवनयापन का खर्चा १८ प्रतिशत और बढ़ गया था और महँगाई में वृद्धि अभी जब जारी ही थी तो मजदूरों ने फिर यह महसूस किया कि उद्योग के तो मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं किन्तु उनके हितों की उपेक्षा की जा रही है। अब २३ प्रतिशत वेतन-वृद्धि की माँग की जाने लगी और मजदूरों ने पुनः इस बात पर बल दिया कि उद्योग चीजों के मूल्य बढ़ाए बिना यह वेतन-वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। उनके इस कथन भी पुष्टि राबर्ट आर. नाथन की उस प्रसिद्ध रिपोर्ट से होती थी जिसमें दिखाया गया था कि उद्योगों के मुनाफ़े वस्तुतः ५० प्रतिशत बढ़ गए हैं। प्रबन्धकों ने भी तोता रटन्त की तरह यह बात दोहरायी कि अतिरिक्त वेतन वृद्धियों से कीमतों का और बढ़ना अनिवार्य है। ऐसा लगा कि देश मुद्रा-प्रसार के दुष्चक्र में फँस गया है। उद्योगों को ज्यादा मुनाफा मिलता हो या मजदूरों को ज्यादा वेतन, यह बात निश्चित थी कि उपभोक्ताओं को सदा खरीदी गई चीजों के लिए उत्तरोत्तर अधिक कीमत देनी पड़ रही थी। इसमें कोई सन्देह नहीं था कि मज़दूरों को जितना लाभ वेतन-वृद्धि से हुआ उससे ज्यादा नुकसान उपभोक्ता के नाते उन्हें चीजें खरीदने में होता था किन्तु जीवन-यापन का खर्चा बढ़ने के तात्कालिक दबाव के कारण वे नई माँगें रखने को विवश थे।

तो भी १९४७ में उद्योग और मज़दूर दोनों १९४६ की अपेक्षा समझौते की ज्यादा मूड में थे। यूनियन सुरक्षा का प्रश्न जो पहले वेतन वृद्धियों जितना ही मूल्यवान् था अब उतना महत्त्वपूर्ण नहीं रह गया था। मज़दूरों ने अपनी शक्ति दिखला दी थी और बारहमासी वेतन-विवादों का कोई भी फरीक ...लों का एक और दौर देखने का इच्छुक नहीं था, जिनसे सबको बहुत

नुकसान होता था। फलस्वरूप सामूहिक सौदेबाजी बड़े उद्योगों में समझौते कराने में कामयाब हुई। औसतन १५ सेण्ट प्रति घण्टा वेतन वृद्धि के समझौते किए गए।

बहुत तीव्र हो गई थीं मजदूरों के प्रति इस वैरभाव को अगर सिद्धान्ततः यूनियन-संगठन के विरोधी प्रतिक्रियावादी तत्वों ने और बढ़ाया तो बार-बार लिए हुए लोकमत सर्वेक्षणों से यह जाहिर हो गया कि अमरीकी जनता की आम राय में मजदूर नेता अपनी शक्ति के मुताबिक जिम्मेदारी की भावना प्रदर्शित करने में असफल रहे। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने वाली हड़तालों को, चाहे वे कोयला, रेलवे, इस्पात या अन्य बड़े उद्योगों में की गई हों इतना खतरनाक समझा गया कि उन्हें सहन नहीं किया जा सकता था। यह अधिकाधिक महसूस किया गया कि राष्ट्र के आर्थिक तंत्र पर किसी संगठित अल्पमत को, भले ही वह मजदूरों का व्यापक प्रतिनिधित्व करता हो, तानाशाही ढंग से हावी होने से रोकने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। अतीत में सरकार को बड़े उद्योगपतियों पर अपना अंकुश रखने को मजबूर किया गया था अब उसे बड़ी यूनियनों की उतनी ही बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए कहा गया।

मजदूर यूनियनों पर ज्यादा प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने की यह लोकप्रिय माँग कांग्रेस में फिर प्रतिक्षिप्त हुई। वागनर ऐक्ट में, जिसमें यकीनन सिर्फ मालिकों की तरफ से की जाने वाली श्रम सम्बन्धी नाजायज हरकतों को ही ग़ैर-कानूनी ठहराया गया था, संशोधन की माँग पहले-पहल १९४६ के संकट में की गई जब कि समस्त अनु-परिवर्तन को कार्यक्रम ठप्प पड़ जाने का खतरा पैदा हो गया था। फरवरी में प्रतिनिधिसभा ने एक सख्त प्रतिबन्धात्मक बिल पास किया जिसे प्रतिनिधि केस ने प्रस्तुत किया था। तात्कालिक हड़ताल का खतरा टल जाने पर इस बिल के बारे में आगे कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जब कोयला और रेलवे हड़तालों ने पुनः सार्वजनिक आशंका उत्पन्न कर दी तो सेनेट ने इस बिल पर विचार किया और उसे मंजूर कर दिया। २९ मई को केस बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया। अन्य बातों के अलावा इसमें एक संघीय मध्यस्थता बोर्ड की स्थापना, हड़ताल करने से पूर्व ६० दिन तक शांति बनाए रखने और इन परिस्थितियों में काम छोड़ देने पर किसी भी मजदूर को अधिकारों से वंचित किए जाने की व्यवस्था रखी गई; गौण बहिष्कारों तथा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी हड़तालों दोनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया और हिंसात्मक तथा बाधात्मक धरने को रोकने के लिए निरोधादेशों के

उपयोग का अधिकार दिया गया।

राष्ट्रपति ट्रूमन ने बिल पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया। यद्यपि यह बिल उतना सख्त नहीं था जितना उनका अपना हड़तालियों को फौज में भरती करने का प्रस्ताव, तो भी उन्होंने महसूस किया कि एक स्थायी कानून बन जाने की हालत में यह यूनियनों पर अनावश्यक प्रतिबन्ध लगा देगा, झगड़ों के कारणों को दूर करने के बजाय सिर्फ उनके ऊपरी लक्षणों का इलाज कर सकेगा। राष्ट्रपति ने कांग्रेस से कहा कि औद्योगिक शांति कायम रखने के किसी भी दीर्घकालीन कार्यक्रम में यूनियन सुरक्षा के बुनियादी सिद्धान्त पर कोई आंच नहीं आने देनी चाहिए। यह उद्देश्य उनके मत में प्रस्तावित कानून से पूरा नहीं हो सकता था इसलिए उन्होंने कांग्रेस से सारे कार्यक्रम पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया।

कांग्रेस ने उनके निषेधाधिकार को लांघकर केस बिल को पास नहीं किया लेकिन उसका इस मामले को यूँही छोड़ देने का कोई इरादा नहीं था। १९४६ के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकनों की विजयों से मजदूर-विरोधी ताकतें मजबूत हुई और वर्ष के अन्त तक यूनियनों पर अंकुश लगाने के आन्दोलन में नई शक्ति आ गई। वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में इस चुनाव का यह अभिप्राय लगाया गया कि पिछले १४ वर्षों में जो पलड़ा मजदूरों के पक्ष में इतना ज्यादा झुका दिया गया था उसे संतुलित करने के लिए कठोर कदम उठाने के हेतु यह लोकमत का सीधा आदेश है। १९४७ में कांग्रेस में ही नहीं बल्कि कोई ३० राज्यों में नए प्रतिबन्धात्मक कानून पास किए गए।

मजदूर अपने हितों पर आए इस खतरे से एकदम चौकन्ने हो गए और उनके शब्दों में "मजदूर आन्दोलन को नष्ट नहीं तो पंगु करने के लिए जान-बूझ कर चलाए गए शैतानी आन्दोलन" का मुकाबला करने के लिए उन्होंने संयुक्त कार्रवाई की अपील की किन्तु अन्त में विधि-निर्माण की चक्की ने पीस

मज़दूर यूनियनों को कमज़ोर कर देना है, यह मज़दूरों को उनके बुनियादी अधिकारों की वैधानिक रक्षा से वंचित कर हड़तालों को हतोत्साहित करने के बजाय प्रोत्साहित करेगा और "हर समझौते की मेज़ पर सरकार को एक अवांछनीय भागीदार" बना देगा। उन्होंने कहा कि "इसकी व्यवस्थाएँ भयावह हैं, मज़दूरों के लिए बुरी हैं, प्रबन्धकों के लिए बुरी हैं और देश के लिए बुरी हैं।" किन्तु इस बार कांग्रेस का इसे कानून बनाने का दृढ़ संकल्प था। राष्ट्रपति के रवैये पर तीक्ष्ण प्रहार करते हुए और गलत प्रतिनिधित्व का अप्रच्छन्न आरोप लगाते हुए २३ जून, १९४७ को उनकी आपत्तियों को रद्द कर दिया गया और उनके निषेधाधिकार की अवहेलना कर बिल पास कर दिया गया।

टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट अत्यधिक लम्बा और जटिल कानून था जिसकी बीसियों धाराओं में से कोई निश्चित बात निकाल लेना कठिन था। इसका घोषित उद्देश्य मालिक व कर्मचारियों के बीच सौदेबाज़ी की क्षमता में फिर से सन्तुलन कायम करना था। इस उद्देश्य के लिए वागनर ऐक्ट में मज़दूरों को प्रदान किए गए बुनियादी हक लौटाए नहीं गए किन्तु उनके मुकाबले के अधिकार मालिकों को भी प्रदान कर दिये गए। या अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पहले के कानूनों ने जहाँ सिर्फ मालिकों के नाजायज़ तरीकों की निन्दा की गई थी वहाँ नए कानून में मज़दूर यूनियनों की नाजायज़ हरकतों पर अंकुश लगाया गया था। अब से यूनियनों को कर्मचारियों के साथ ज़ोर-ज़बर्दस्ती करने, सामूहिक करार से इन्कार करने, अत्यधिक सदस्यता-फीस लेने, या गौण बहिष्कार अथवा अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी हड़तालों की अनुमति प्रदान नहीं की जाती थी। दूसरी ओर यद्यपि मालिकों के लिए यूनियनों को मान्यता देना और उनके साथ सामूहिक करारों की बातचीत करना लाज़िमी था वहाँ उन्हें बदले की धमकियों अथवा लाभ के प्रलोभनों को छोड़कर यूनियन-संगठन के बारे में अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आज़ादी दे दी गई और उन्हें सामूहिक सौदेबाज़ी के लिए कौन-सी यूनियन मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करेगी, इसका चुनाव स्वयं कराने का हक प्रदान कर दिया गया।

किन्तु इस नये कानून ने सौदेबाज़ी की क्षमता को सन्तुलित करने के इरादे आगे जाकर यूनियन सुरक्षा पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले और

अंकुश लगाए। न केवल वन्द-शॉपों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, बल्कि यूनियनशॉपों पर भी अत्यन्त सख्त व जटिल प्रतिबन्ध लगा दिये गए। इसके अलावा यूनियनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि किसी समझौते को समाप्त करने या उसमें संशोधन करवाने के इरादे के लिए ६० दिन का नोटिस दिया जाए और करार भंग करने पर संघीय न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाए जा सकने की व्यवस्था की गई। उन पर राजनीतिक आन्दोलनों में चन्दा देने या कोष खर्च करने का प्रतिबन्ध लगा दिया गया और यूनियन के अधिकारियों से इस बारे में हलफ़नामे दाखिल करने के लिए कहा गया कि वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं हैं।

दूसरे अध्याय में राष्ट्रीय संकटकाल की हड़तालों से निबटने के लिए एक लम्बा-चौड़ा फार्मूला प्रदान किया गया था। जब कभी किसी हड़ताल से समस्त उद्योग पर या उसके बड़े अंश पर प्रभाव पड़ता हो और उससे राष्ट्र के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को हानि पहुँचती हो तो उस हालत में राष्ट्रपति को एक जाँच-बोर्ड नियुक्त करने का और उसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ६० दिन के लिए हड़ताल सम्बन्धी समस्त गतिविधियाँ रोक देने के लिये निरोधादेश प्राप्त करने के हेतु अटार्नी जनरल की मार्फत अर्जी देने का अधिकार प्रदान किया गया। अगर इस अवधि में कोई समझौता न हो सके तो निरोधादेश २० दिन और बढ़ा देने की व्यवस्था की गई, जिस बीच गुप्त मतदान द्वारा समस्त कर्मचारियों की इस बारे में राय ली जानी थी कि मालिकों द्वारा प्रस्तुत समझौते की अन्तिम शर्तें उन्हें स्वीकार हैं या नहीं। अगर इन प्रयत्नों के वाद भी समझौता न हो सके तो ऐक्ट में उसके वाद सिर्फ यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति उस घटना की रिपोर्ट "विचार और उचित कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशों के साथ" काँग्रेस में पेश करें।

अन्त में कुछ प्रशासनात्मक परिवर्तन किये गए थे, जैसे राष्ट्रीय श्रम-सम्बन्ध-बोर्ड का विस्तार और सब अनुचित तौर-तरीकों के बारे में अभियोग दायर करने के लिए एक वड़े वकील की नियुक्ति। एक नई और स्वतन्त्र संघीय मध्यस्थता और मेल-मिलाप सेवा स्थापित की गई जिसे ऐसे किसी भी श्रम-विवाद में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान किया गया जिससे

वाणिज्य में बड़े पैमाने पर रुकावट पड़ने की आशंका पैदा होती हो।

कांग्रेस में बहस के समस्त प्रारम्भिक काल में और विशेषकर निषेधाधिकार के प्रयोग और बिल को फिर पास करने की अवधि के बीच, इस बिल में निहित मसलों पर देश भर में गरमागरम बहस की गई। नेशनल ऐसोसियेशन आव मैन्युफैक्चरर्स के नेतृत्व में मालिकों के एसोसियेशनों की सारी शक्ति बिल को कानून बनाने के आन्दोलन के पीछे लगा दी गई। ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. ने समझौते की कोई प्रवृत्ति दिखाए बिना संघर्ष किया और इस बिल की पूर्ण पराजय की अपनी मांग में कोई रू-रियायत करने से इन्कार कर दिया। उद्योग तथा मज़दूर दोनों ने कांग्रेस की सुनवाइयों में अपने प्रवक्ता भेजे। अपने-अपने दृष्टिकोण जनता के सामने रखने के लिए रेडियो समय खरीदा तथा अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अखबारों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन निकाले।

इस बिल के समर्थकों का कहना था कि प्रस्तावित बिल श्रम-सम्बन्धों में पुनः कुछ न्याय की स्थापना करने से आगे नहीं जाता। सेनेटर टैफ्ट ने कहा : "यह बिल सिर्फ मज़दूर यूनियनों के नेताओं को दिए गए विशेष अधिकारों में कमी करता है।" दूसरी ओर मज़दूरों ने समस्त यूनियनवाद पर इसे बदले की भावना से किया गया आक्षेप बताया। ए. एफ. एल. ने कहा कि "इस देश में प्रतिक्रियावाद की ताकतें स्वतन्त्र अमरीकी मज़दूरों के साथ दो-दो हाथ कर लेना चाहती हैं।"

मज़दूरों की स्थिति में कुछ बुनियादी कमजोरी थी। लोक-समर्थन प्राप्त करने तथा यूनियन सुरक्षा पर चोट करने वाले किसी कानून के प्रति विरोध को एकत्र करने का आन्दोलन उन्होंने बहुत देर से शुरू किया। वागनर ऐक्ट में संशोधन करने के आन्दोलन के लिए एकमात्र यूनियन-विरोधी मालिकों और नेशनल ऐसोसियेशन आव मैन्युफैक्चरर्स को ज़िम्मेदार ठहराते हुए ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. के नेताओं ने इस तथ्य को दर-गुज़र कर दिया कि आम जनता मज़दूरों की "ग़ैर ज़िम्मेदारी पर कितनी विक्षुब्ध थी। उद्योगव्यापी हड़तालों ने जब बुनियादी लोक-सेवाओं में बाधा डाली तो लोगों में निराशा की आम भावना की ज्यादातर उपेक्षा कर दी गई। इससे भी महत्त्व की बात थी कि मज़दूरों ने टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट का कोई विकल्प नहीं रखा। वे अपने

तौर-तरीकों को युद्धोत्तर काल की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के लिए और वागनर ऐक्ट में किसी किस्म के संशोधन की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर कुछ समझौते का रुख अपनाया गया होता तो सम्भव है लोकमत कुछ नरम संशोधनों के पक्ष में हो जाता जिससे यूनियन सुरक्षा पर कोई आँच आए बिना लोकहित की रक्षा हो सकती। सितम्बर में किए गए लोकमत के सर्वेक्षणों में जिन लोगों से पूछ-ताछ की गई या जिन्हें टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट की जानकारी थी उनमें से ५३ प्रतिशत का खयाल था कि इसमें या तो संशोधन किया जाए, या इसे रद्द कर दिया जाए। किन्तु मज़दूरों की नीति इस प्रच्छन्न समर्थन को और बढ़ाने या उसे बनाए रखने में विफल रही।

---

२० : ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. का विलय

आगामी वर्षों में आधी सदी गुजर जाने पर भी यद्यपि संगठित मजदूर आन्दोलन पर टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट की छाया लटकती रही तो भी अमरीकी समाज में मजदूरों की हैसियत के निरन्तर सुधरते जाने में कोई रुकावट नहीं पड़ी। यूनियनों के विकास की रफ्तार यद्यपि वह नहीं थी जो १९३० की दशाब्दी के बाद के वर्षों में या १९४० की दशाब्दी के प्रारंभिक वर्षों में थी तो भी सदस्य संख्या बढ़कर करीब ८० लाख हो गई और ऐसे कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही थी जिनपर सामूहिक सौदेबाजी के समझौते लागू होते थे। अप्रत्याशित रूप से स्थिर आर्थिक परिस्थितियों की जिनपर शस्त्रीकरण पर किए जाने वाले खर्च और विदेशों को दी जाने वाली सहायता का काफी हद तक प्रभाव पड़ा था, पृष्ठभूमि में यूनियन गतिविधि भी आम औसत वेतनों में वृद्धि कराने तथा अतिरिक्त आनुषंगिक लाभ प्राप्त कराने में सफल हुई।

इन परिस्थितियों में संगठित मजदूरों की शक्ति और प्रभाव को राजनीतिक दृष्टि से नहीं तो आर्थिक दृष्टि से पहले किसी भी समय की अपेक्षा अधिक स्वीकार किया गया। वेतन और काम की शर्तें निर्धारित करने के लिए प्रबन्धक नियमित रूप से सामूहिक सौदेबाजी का आश्रय ले रहे थे। इस में शायद ही कोई अपवाद रहा हो। पहले के जमाने की परिस्थितियों के बिल्कुल विपरीत उद्योगपतियों के अधिक-से-अधिक पुरातनपन्थी प्रवक्ताओं ने भी राष्ट्रीय अर्थतंत्र तथा अमरीकी समाज के व्यापक क्षेत्रों में यूनियनों के बुनियादी रोल को स्वीकार कर लिया था। फौर्चून के सम्पादकों ने कहा : "उनकी सत्ता और प्रतिष्ठा में वृद्धि स्वयमेव आधुनिक स्वतंत्र व्यवसाय पद्धति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।"

मध्य सदी की इन घटनाओं से यद्यपि यह स्पष्ट था कि टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट 'गुलाम मजदूर' बिल कहना कितना गलत था तो भी इसके खिलाफ ई. ओ. और ए. एफ. एल. दोनों के अभियान में कोई शिथिलता नहीं आई।

इसे रद्द कराने के लिये कांग्रेस पर सब सम्भव दबाव डाला गया और मौजूदा राजनीतिक गठबन्धनों में कंज़रवेटिव और लिबरल तत्त्वों के बीच यह एक अत्यन्त स्पष्ट विवाद का विषय बन गया। जब १९४८ का राष्ट्रपति का चुनाव नज़दीक आया तो दोनों बड़े दल इस प्रश्न पर कोई न कोई टेक लेने को बाध्य हो गए और १९३० की दशाब्दी का वही बुनियादी राजनीतिक ढाँचा फिर दोहराया गया। डैमोक्रैटों ने टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट को तुरन्त रद्द किए जाने पर जोर दिया और रिपब्लिकनों ने इस विषय में इससे ज्यादा सीधा और कुछ नहीं कहा कि उनकी पार्टी "मज़दूर-प्रबन्धक सम्बन्धी कानूनों को निरन्तर सुधारते जाने" के पक्ष में है।

राष्ट्रपति ट्रूमन की अप्रत्याशित विजय ने तुरन्त मज़दूरों की यह आशा बढ़ादी कि इस ऐक्ट को अब रद्द कर दिया जाएगा। किन्तु वह उनका भ्रम साबित हुआ। कांग्रेस पर रिपब्लिकनों और दक्षिण के डैमोक्रैटों के, जिनको संगठित मज़दूरों की माँग से कोई सहानुभूति नहीं थी, एक मिले-जुले ब्लाक का नियंत्रण रहा और सेनेटर टैफ्ट ने वर्तमान कानून में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सख्त मुखालफ़त की। एक संशोधन सन् १९५१ में किया गया। यूनियन शापों का चुनाव कराते-कराते अनुभवों से इस विषय में मज़दूरों का रवैया इतना स्पष्ट हो गया था (इन चुनावों में करीब ८७ प्रतिशत मज़दूर यूनियन का समर्थन करते थे) कि चुनावों की देखरेख में किए जाने वाले खर्च को बचाने के लिए कांग्रेस ने कानून में संशोधन कर मज़दूरों के वोट लिए बिना यूनियन-शाप समझौते करने की अनुमति दे दी। इसको छोड़कर टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट ज्यों-का-त्यों रहा, चाहे इसके मज़दूर-दुश्मनों ने इसके बारे में कुछ भी कहा हो या कुछ भी किया हो।

की नियुक्ति का (यह कहा जाता था कि राष्ट्रपति आइजनहावर के मंत्रिमण्डल में ९ करोड़पति और एक प्लम्बर है) और २ फरवरी को कांग्रेस में दिए गए उनके इस वक्तव्य का कि अनुभव ने टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट में सुधार की आवश्यकता प्रदर्शित की है, यह अर्थ लगाया गया कि यद्यपि इस कानून के रद्द होने की आशा छोड़नी पड़ेगी तो भी इसमें संशोधनों के लिए द्वार खुला रखा गया है।

तो भी अब की बार भी कुछ नहीं किया गया। डर्किन ने १९ संशोधन तैयार किए और यह खयाल करके कि इन्हें राष्ट्रपति आइनजहावर का समर्थन प्राप्त है उन्हें कांग्रेस में पेश किए जाने के लिए एक सिफारिश का मसविदा प्रकाशित कर दिया। आइजनहावर ने इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने इनका समर्थन करने का वचन दिया है। एक 'पूर्व-सहमत' नीति का प्रतिवाद कर दिए जाने से नाराज होकर डर्किन ने मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति आइजनहावर ने यद्यपि अपनी स्थिति को स्पष्ट करने और मजदूरों को अपनी सहानुभूति का आश्वासन दिलाने की कोशिश की तो भी यूनियन नेताओं को यकीन हो गया था कि राष्ट्रपति को घेरे रहने वाली कंजरवेटिव ताकतों ने राष्ट्रपति को अपने वायदे से मुकर जाने को विवश कर दिया। राष्ट्रपति के लिए यह कह देना ही काफी नहीं था, जैसा कि उन्होंने सितम्बर में ए. एफ. एल. के सम्मेलन में कहा कि "वह यह खूब अच्छी तरह समझते हैं कि संगठित मजदूरों ने इस देश के लिए क्या किया है।" टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट के संशोधन में अपने ही मंत्री का समर्थन न करने पर यूनियनें क्रुद्ध हो गईं। ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. दोनों के नेताओं ने अधिक सौहार्दपूर्ण कानून बनवाने के लिए सब संभव राजनीतिक दबाव डालने के अपने संकल्प को पुनः दृढ़ता से व्यक्त किया।

किन्तु इस चीज का अब भी कोई वास्तविक प्रमाण नहीं था (शायद कुछ क्षेत्रों में संगठन के नए आन्दोलनों पर सम्भवतः कुछ प्रतिबन्धात्मक प्रभाव को छोड़कर) कि टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट ने मजदूर आन्दोलन की बढ़ती हुई शक्ति में पर्याप्त रुकावट डाली है। कानून की निरोधादेश सम्बन्धी व्यवस्थाओं को, जो राष्ट्रीय आपत्तिकाल की हड़तालों पर अपनाई जाती थीं, विरले ही कभी लागू किया गया और इसकी तथाकथित यूनियन विरोधी धाराओं का ऐसा कोई [illegible]म नहीं हुआ जैसी मजदूरों को आशंका थी। इन दिनों के मजदूर-

प्रबन्धक झगड़ों से यह बात ज़ाहिर हुई कि बड़ी यूनियनों की सौदेबाजी की शक्ति में कोई ह्रास होने के बजाय उनकी शक्ति बढ़ रही है।

पहला बड़ा विवाद, जिसमें ट्रैफ्ट-हार्टले ऐक्ट का इस्तेमाल किया गया, बारह-मासी अशान्त कोयला उद्योग में खड़ा हुआ, जहाँ १९४७ में हुए समझौते के बावजूद जान एल. लेविस के अब भी आक्रामक नेतृत्व में रुक-रुक कर हड़तालों का होना जारी था। लेविस के इस अभियोग के बारे में कि खान मालिकों ने स्वास्थ्य और कल्याण कोष के विषय में अपने करारों को पूरा नहीं किया है, खनिकों और खानमालिकों के बीच एक नया विवाद, उत्पन्न हो गया। १९४८ में महीने भर की हड़ताल के बाद इस बारे में हुए समझौते से भी कोयला-खानों में पुनः शांति कायम नहीं हुई और लेविस उद्योग की सामान्यतः अनिश्चित हालतों पर अधिकाधिक चिन्तित हो उठा। ऊँचे वेतनों और अधिक अनुकूल करार के लिए मालिकों पर और दबाव डालने के हेतु नाममात्र को खानों में होने वाली मौतों और घायलों की संख्या पर विरोध प्रकट करते हुए उसने खनिकों से रुक-रुक कर हड़ताल करते रहने का आह्वान किया। सम्पूर्ण १९४९ में उत्पादन में बाधा पड़ती रही; और दिसम्बर में यद्यपि कुछ खान-मालिकों के साथ नए समझौते हो गए तो भी अनधिकृत हड़तालें जारी रहीं।

अन्त में, ६ फरवरी, १९५० को यूनाइटेड माइन वर्कर्स को सीधा करने के लिये राष्ट्रपति ट्रूमन ने टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट की राष्ट्रीय आपातकालीन व्यवस्थाओं का आश्रय लिया और आगे कोई और हड़ताल न करने के लिये अस्थायी निरोधादेश जारी किया गया। यूनियन अधिकारियों ने खनिकों को वापस काम पर जाने के आदेश जारी कर दिए किन्तु इनकी ज्यादातर उपेक्षा कर दी गई। तब यूनाइटेड माइन वर्कर्स के खिलाफ अदालत की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। सरकार ने कहा कि हड़तालियों को काम पर वापस जाने के लिए कहकर यूनियन ने सिर्फ 'लाक्षणिक' रूप में निरोधादेश का पालन किया है। किन्तु एक संघीय न्यायालय ने इस आधार पर अभियोग को सम्पुष्ट करने से इन्कार कर दिया कि यूनियन के आदेश में बदनीयती साबित नहीं हुई। इस गतिरोध में ट्रूमन ने कांग्रेस से कोयलाखानों पर कब्जा करने का अधिकार माँगा किन्तु कोई कार्रवाई किए जाने से पूर्व मार्च में खान-मालिकों तथा यूनियन के बीच नए समझौते हो गए। कुछ-कुछ व्यवस्था तो

स्थापित हो गई किन्तु टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट का अनुभव कम-से-कम बहुत अधूरा रहा।

इन्हीं, १९४९ और १९५० के वर्षों में अन्य कई महत्त्वपूर्ण हड़तालें हुईं, विशेषकर मोटर और रेल उद्योगों में किन्तु टैफ्ट-हार्टले एक्ट लागू नहीं किया गया। क्रिसलर कम्पनी और यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स में अन्तिम समझौता होने से पूर्व कर्मचारी १०० दिन तक कारखाने से बाहर रहे। इससे भी लम्बी रेल कर्मचारियों की हड़ताल १९५१ तक जारी रही। बार-बार की जाने वाली इन रेल हड़तालों को देखकर सरकार ने रेलों पर कब्जा कर लिया और एक बार सेनामंत्री ने काम पर न आने वाले सब कर्मचारियों को बर्खास्त कर देने की धमकी दी। अन्त में १९५२ में एक समझौते के बाद सरकारी नियंत्रण हटा लिया गया। इस समझौते में अन्य बातों के अलावा रेलों का संचालन-कार्य करने वाले मजदूरों से इतर मजदूरों के लिए एक यूनियन शाप की व्यवस्था रखी गई थी।

टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट को लेकर सबसे प्रखर विवाद १९५२ की इस्पात हड़ताल थी जो इस उद्योग के इतिहास में सबसे लम्बी और महँगी पड़ी। कोरिया युद्ध तथा एक आपातकालीन स्थिति की पृष्ठभूमि में यह हड़ताल हुई थी, जिसमें सरकार ने वेतनों तथा मूल्यों दोनों पर फिर से नियंत्रण लगा दिए थे। लोगों को १९४१ से लेकर १९४५ तक का जमाना याद आने लगा।

उद्योग तथा यूनाइटेड स्टील वर्कर्स के बीच नए करार की बातचीत १९५१ की समाप्ति पर भंग हो गई किन्तु यह विवाद नए वेतन स्थिरीकरण बोर्ड को सौंपे जाने के बाद यूनियन ने उसकी रिपोर्ट आने तक हड़ताल सम्बन्धी कोई भी कार्रवाई स्थगित रखना स्वीकार कर लिया। तीन महीने बाद घोषित फैसले को मजदूरों ने तो स्वीकार कर लिया किन्तु उद्योग ने इसमें यूनियन शाप को मान्यता दिए जाने की निन्दा की और प्रस्तावित वेतन-वृद्धि को तब तक मानने से इन्कार कर दिया जब तक उसकी भरपाई के लिए इस्पात के मूल्य में वृद्धि नहीं की जाती। आर्थिक स्थिरीकरण निदेशक ने मूल्य बढ़ाना स्वीकार नहीं किया और आगे बातचीत टूट जाने से यूनाइटेड स्टील वर्कर्स ने हड़ताल की तैयारी कर दी।

उद्योग ने तुरन्त टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट की आपातकालीन व्यवस्थाओं को

लागू किए जाने का आग्रह किया किन्तु मज़दूर क्योंकि तीन महीने से रुके रहे थे इसलिए ट्रूमन ने इसका प्रयोग करने से इन्कार कर दिया। इसके बदले ८ अप्रैल, १९५२ को उन्होंने आपातकाल में उत्पादन चालू रखने के एक मात्र उपाय के रूप में इस्पात मिलों पर कब्ज़ा करने का कड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा : "मुझे विश्वास है कि इस विशेष समय पर सब इस्पात मिलों को बन्द हो जाने देकर संविधान मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए नहीं कहता।"

उनकी इस कार्रवाई पर विवाद और विरोध का तूफान उठ खड़ा हुआ। इस्पात उद्योग मामले को तुरन्त ही अदालतों में ले गया और कारखानों पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध प्रारम्भिक निरोधादेश अदालती आदेश के अस्थायी स्थगन, रुक-रुक कर होने वाली हड़तालों और आगे होने वाली व्यर्थ बातचीत की पृष्ठि-भूमि में कानूनी दांव-पेंच लड़े जाते रहे। अन्त में २ जून को सुप्रीम-कोर्ट ने फैसला दिया कि मिलों पर ज़ब्ती सरकार का असांविधानिक कार्य थी और राष्ट्रपति को मजबूर होकर इस्पात मिलें उनके मालिकों को लौटाए जाने का आदेश जारी करना पड़ा। लगभग ६,५०,००० इस्पात कर्मचारियों ने तुरन्त अपनी हड़ताल शुरू कर दी और समस्त उद्योग में उत्पादन ठप्प हो गया।

इसके बाद दो महीने और गुजर गए, जबकि २६ जुलाई को इस्पात कम्पनियों तथा यूनियन में आखिरकार एक समझौता हो गया जो बहुत कुछ वेतन स्थिरीकरण बोर्ड द्वारा पहले प्रस्तुत सुझावों के अनुरूप था। अनुमानतः इस हड़ताल से उद्योग को ३५ करोड़ डालर का और मज़दूरों को ५ करोड़ डालर के वेतन का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त इस हड़ताल ने सिर्फ इस्पात उद्योग को ही ठप्प नहीं किया था; इस्पात का उपयोग करने वाले बहुत से कारखाने इसके कारण बन्द हो गए थे और मोटरों का निर्माण भी कुछ समय के लिए रुक गया था। ट्रूमन द्वारा टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट को अमल में लाने से इन्कार करने तथा इस्पात कम्पनियों को सरकारी नियंत्रण में लेने के उनके प्रयत्नों पर जब राजनीतिक संघर्ष जारी था तो कोरिया में सैनिकों को सामान की सप्लाई कुछ अरसे के लिए गम्भीर रूप से ख़तरे में पड़ गई थी।

१९५२ के वर्ष में यदि इस्पात हड़ताल की प्रधानता रही तो १९५३ की सबसे विशिष्ट हड़ताल न्यूयार्क के गोदी व जहाजी घाट कर्मचारियों की रही।

इस विवाद के परिणाम अत्यन्त जटिल रहे। वेतन और काम की शर्तों के बारे में इसमें इण्टरनेशनल लोंगशोर मैन्स ऐसोसियेशन तथा न्यूयार्क शिपिंग ऐसोसियेशन में संघर्ष हो गया। किन्तु अन्ततः शांति स्थापित होने से पूर्व सेनेट की एक जाँच समिति ने इस यूनियन को भ्रष्टाचार, कम्युनिज्म और अपराधियों की जमात वताया। न्यूयार्क और न्यूजर्सी दोनों राज्यों के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया। ए. एफ. एल. ने आई. एल. ए. को ज़ोर-ज़बर्दस्ती से रकम वसूल करने और गवन के आरोपों में फेडरेशन से निकाल कर गोदी कर्मचारियों की एक नई यूनियन वना दी और राष्ट्रपति आइज़नहावर ने टैफ्ट-हार्टले एक्ट का सहारा लिया। किन्तु इनमें से किसी भी कार्रवाई से हिंसा और गुण्डागर्दी खत्म नहीं हुई और सेनेट की जांच समिति ने इस यूनियन के बारे में जो कुछ कहा था, वह सव सच प्रतीत होने लगा।

इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध वोर्ड ने वन्दरगाह पर सौदेवाज़ी के लिए अधिकारी एजेण्ट के चुनाव की व्यवस्था करके पुरानी आई. एल. ए. तथा ए. एफ. एल. द्वारा स्थापित नई यूनियन के बीच पैदा हुई विद्वेषपूर्ण प्रतिद्वन्द्विता को दूर करने का प्रयत्न किया। इसमें जॉन एल. लेविस द्वारा पुनः संगठित तथा समर्थित पुरानी आइ. एल. ए. विजयी हुई किन्तु चुनाव परिणाम आतंक और ज़ोर-ज़बर्दस्ती के आरोपों पर रद्द कर दिए गए। तव अन्धा-धुन्ध अनेक हड़तालें हुईं, जो १९५४ तक भी चलती रहीं और राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध वोर्ड ने उन्हें खत्म किए जाने की शर्त पर दुवारा चुनाव कराने की व्यवस्था की। ये चुनाव मई में हुए और सब तरफ से लगाए गए आरोपों और ए. एफ. एल. के अब भी जारी विरोध के बावजूद पुरानी यूनियन ही पुनः जीत गई। २७ अगस्त, १९५४ को राष्ट्रीय श्रम-सम्बन्ध वोर्ड ने इसे गोदी मज़दूरों का अधिकृत सौदेवाज़ी-एजेण्ट स्वीकार कर लिया और ए. एफ. एल. ने नई यूनियन बनाने का प्रयत्न छोड़ दिया। यद्यपि इसके वाद भी कभी-कभी काम रुका किन्तु अन्त में नवम्बर में हड़ताल और ताला-वन्दी पर प्रतिवन्ध का दो वर्ष का एक समझौता कर लिया गया। किन्तु यह अभी देखना था कि पुरानी आई. एल. ए. की अच्छे व्यवहार की प्रतिज्ञा तथा व्यवस्था वनाए रखने के लिए न्यूयार्क और न्यूजर्सी के कमीशनों द्वारा उठाए गए कदम क्या स्थिति को सफलतापूर्वक सुधार सकेंगे ? किन्त अशान्त बन्दरगाह पर फिलहाल बेचैनीपूर्ण शांति

कायम हो गई थी।

गोदी मजदूरों के आपसी संघर्ष और कोयला, इस्पात, मोटर तथा रेल उद्योगों में हुई हड़तालें सदा अखबारों की मोटी-मोटी सुर्खियाँ बनाती थीं। बिना काम रोके किए गए समझौतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, यद्यपि ऐसा होना एक अपवाद के बजाय सामान्य बात थी। टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट के स्वीकार किए जाने के बाद ६ वर्षों का रिकार्ड वस्तुतः यह बताता है कि राष्ट्रव्यापी हड़तालों में और उनके द्वारा हुई काम की हानि में निरन्तर कमी हुई। १९२७ से १९५१ तक औसतन ४ करोड़ मनुष्य दिवसों की प्रतिवर्ष हानि हुई, (१९४६ में यह संख्या ११,६०,००,००० मनुष्य दिवस थी) १९५२ में ५५० लाख हो गई, अगले वर्ष लगभग आधी हो गई और १९५४ में २,२०,००,००० रह गई जो सब मजदूरों के कुल कार्य समय के ०·२५ प्रतिशत से अधिक नहीं थी।

इस काल की किसी भी हड़ताल में मजदूरों को गम्भीर क्षति नहीं उठानी पड़ी। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण हड़ताल में अंतिम समझौते के फलस्वरूप मजदूरों को और ज्यादा वेतन-वृद्धियाँ मिलती थीं और कई मामलों में तो प्रवन्धकों ने मजदूरों को अतिरिक्त आनुषंगिक लाभ प्रदान किए। समृद्धि बढ़ते जाने के कारण यूनियनें इस प्रकार की माँगों पर जोर दे सकीं और मालिक एक सीमित और अपनी हानि को बचाने के संघर्ष से ज्यादा कुछ नहीं कर सके: नए समझौतों में बराबर वेतन-वृद्धियों के अलावा काम की बहतर हालतों, बीमा सम्बन्धी लाभों, संवेतन छुट्टियों, और सबसे महत्त्वपूर्ण बात विस्तृत पेंशन कोषों की व्यवस्था की गई।

इस काल में सामूहिक सौदेबाजी के जितने समझौते किए गए उनमें एक सबसे मजेदार मई, १९५० में जनरल मोटर्स और युनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स के बीच किया गया। यह समझौता इस उद्योग में तथा अन्य उद्योगों में बाद के समझौतों के लिए एक नमूने की चीज बन गई। इसमें एक उदार पेंशन प्रणाली, विशेष बीमा लाभों, वार्षिक वेतन-वृद्धियों और श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के जीवनयापन के खर्च के सूचकांक के अनुसार वेतनों में हेरफेर की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त यह करार ५ वर्ष के लिए किया गया। शायद इस मध्य सदी की किसी और अकेली घटना ने मजदूरों और प्रबन्धकों

के बीच सम्बन्धों में की गई चामत्कारिक प्रगति का इतना पूर्ण प्रदर्शन नहीं किया जितना इस व्यापक और समावेशक समझौते ने।

सामान्यतः मज़दूरों द्वारा प्राप्त किए गए लाभ इस मूल तथ्य में प्रगट हुए कि १९५० के दशक के मध्य तक दो-तिहाई ग़ैर-कृषिजीवी मज़दूरों—लगभग ३ करोड़ पर—सामूहिक सौदेबाज़ी के समझौते लागू हो गए थे। निर्माता उद्योगों में काम करने वाले मज़दूरों की आय बढ़कर ७५ डालर हो गई थी। यह वृद्धि डालर की कीमतों में हुए हेरफेर को और मूल्य-वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए भी १९३९ के स्तर से ५० प्रतिशत अधिक थी। इस वेतन-वृद्धि में अनेक प्रकार के आनुषंगिक लाभ भी शामिल करने होंगे जो अब अपवाद नहीं, नियम बन गए थे।

संगठित मज़दूरों का प्रमुख लक्ष्य यद्यपि अब भी यूनियन सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए आर्थिक कार्रवाई करना था तो भी ये राजनीतिक गतिविधियों में काफी उलझे रहे। सी. आई. ओ. की पालिसी ऐक्शन कमेटी तथा राजनीतिक शिक्षा के लिए ए. एफ. एल. की लेबर लीग द्वारा १९४८ और १९५२ दोनों चुनाव आन्दोलनों में डैमोक्रैटिक सरकार के चुनाव के लिए चलाए गए आन्दोलन इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त मज़दूर सामाजिक सुरक्षा को और व्यापक बनाने, न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि तथा टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट में संशोधन के लिए ज़ोर-शोर से आन्दोलन करते रहे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनकी सफलता नाटकीय नहीं तो महत्त्वपूर्ण अवश्य थी। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बुढ़ापा तथा उत्तराधिकारी बीमा-लाभों के सिलसिले में अधिकाधिक मज़दूरों पर लागू किया गया। न्यूनतम वेतन दरें भी ऊँची की गईं और १९५५ में राष्ट्रपति आइज़नहावर ने उस समय की न्यूनतम दर को ७५ सेंट से बढ़ाकर ९० सेंट प्रति घण्टा कर देने का प्रस्ताव किया। मज़दूरों की माँग १·२५ डालर की थी। इन दोनों के बीच की संख्या पर यह समझौता उचित ही था।

किन्तु मज़दूरों को सिर्फ अपने वेतनों या सामान्य राष्ट्रीय विषयों से सम्बन्धित कानूनों की ही चिन्ता नहीं थी। वे घरेलू क्षितिज से भी परे देखते थे। जब स्थायी शाँति की महान् आशाएँ कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद तथा शीत-युद्ध के कठोर परिणामों से छिन्न-भिन्न हो गईं तो विदेशनीति मज़दूरों तथा

अमरीकी समाज के अन्य तत्वों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई ।

ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. दोनों ने ट्रूमन सरकार की और बाद में आइज़नहावर सरकार की बुनियादी नीतियों का ज़ोरदार समर्थन किया। उनके वार्षिक सम्मेलनों तथा अनेक इन्टरनेशनल यूनियनों के सम्मेलनों में पास किए गए प्रस्तावों में ट्रूमन सिद्धान्त की पुष्टि की गई, मार्शल योजना का ज़ोरदार समर्थन किया गया, चार-सूत्री कार्यक्रम पर पूरे अमल की माँग की गई और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में अमरीका की भागीदारी का समर्थन किया गया। कम्युनिज्म की रोकथाम करने के लिए उठाया गया कोई कदम ऐसा नहीं था जिसे मजदूरों का हार्दिक समर्थन न मिला हो, और राष्ट्र के सामने विद्यमान संकटों को ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिये अपील करने में मज़दूर नेताओं ने बार-बार पहल की ।

जनवरी, १९४८ में ए. एफ. एल. के तत्कालीन सचिव-कोषाध्यक्ष जार्ज मीनी ने 'अमेरिकन फेडरेशनिस्ट' में लिखते हुए इस बात पर बल दिया कि शांति प्राप्त करने के लिए अमरीका को अपने साथी लोकतंत्रों को स्वतंत्र रखने की कोशिश करनी चाहिए। मार्शल योजना को यूरोप में तानाशाही के अग्रिम प्रसार को रोकने का सर्वोत्तम साधन बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी वार्षिक कीमत उससे ज़्यादा नहीं होगी, जितना राष्ट्र ने युद्ध के सिर्फ १६ दिनों में स्वेच्छा से खर्च किया है। बाद में उन्होंने एक और लेख में उत्तरी अटलांटिक संधि की ज़ोरदार वकालत की। उन्होंने कहा : "इस गंभीर संकट की घड़ी में अमरीका के लोग इस बात पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि अमरीकी श्रमिक देश में और देश के बाहर दोनों जगह लोकतंत्र के एकनिष्ठ, दृढ़ और जीवट वाले चैम्पियन हैं।"

इसी प्रकार के वक्तव्य सी. आई. ओ. के नेताओं ने भी दिए। वाल्टर रूथर और फिलिप मर्रे ने ट्रूमन अचेसन नीति का निरन्तर समर्थन किया; संयुक्त राष्ट्रसंघ को मजबूत करने के लिये और कार्रवाई का अनुरोध किया और चतुःसूत्री कार्यक्रम के महत्त्व पर बल दिया। रूथर ने एक अवसर पर देश के रक्षा और विदेश-सहायता कार्यक्रम के समर्थन में सामाजिक कार्रवाई का एक व्यापक कार्यक्रम" तैयार करने के लिये कहा। सी. आई. ओ. न्यूज़ में एक लेख में कहा गया कि पर्याप्त समर्थन से चतुःसूत्री कार्यक्रम को इतना

विकसित किया जा सकता है कि इससे न केवल दो-तिहाई मानवता का ही हित हो, बल्कि अमरीका में भी लोगों को और रोजगार मिले।

सन् १९५० में कोरिया में युद्ध छिड़ने के बाद ए. एफ. एल. ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके कहा कि इस युद्ध के प्रकाश में स्वतन्त्र मजदूर आंदोलन का महानतम् कार्य सोवियत साम्राज्यवाद को रोकना और मुमकिन हो तो उसे निर्णायक पराजय देना है। सी. आई. ओ. ने भी इस अवसर पर "साम्यवादी आक्रमण के खिलाफ संघर्ष में अपनी सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ को अपने पूर्ण समर्थन का फिर वचन दिया।"

अपने नज़दीकी कार्यक्षेत्र में अमरीकी मज़दूर अंतर्राष्ट्रीय श्रम-कार्यालय से सहयोग करते रहे, जब यह लगा कि ट्रेड यूनियनों का विश्व संघ पूर्णतः कम्युनिस्टों के प्रभाव में जा रहा है तो इसके प्रतिनिधि (ए. एफ. एल. नहीं, किन्तु सी. आई. ओ. मूलतः इसमें शामिल हुई थी) इससे हट गए और १९४९ में नए स्वतन्त्र ट्रेड यूनियनों के अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ के निर्माण में उन्होंने सहयोग किया। साथ ही स्वदेश में मज़दूर आंदोलन पर से कम्युनिज्म के किसी भी धब्बे को मिटा डालने के लिए ज़ोर-शोर से कार्रवाई की गई।

१९४९ के सी. आई. ओ. के सम्मेलन में यह प्रश्न बड़ा विवाद का विषय बन गया, वामपक्ष और दक्षिण का संघर्ष उत्पन्न हो गया और यूनियनों में किसी भी कम्युनिस्ट नेतृत्व को मिटा डालने के लिए कदम उठाए गए। संविधान में संशोधन कर कम्युनिस्टों पर सी. आई. ओ. के भीतर किसी प्रशासनिक पद के लिए चुने जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और कम्युनिस्टों की राह पर चलने वाली किसी भी राष्ट्रीय यूनियन को दो-तिहाई मतों से संगठन से निकाल देने की व्यवस्था की गई। यूनाइटेड इलैक्ट्रिकल, रेडियो ऐण्ड मशीन वर्कर्स के मामले में तुरन्त कार्रवाई की गई और १० अन्य यूनियनों की, जिनपर साम्यवादियों के प्रभाव में होने का आरोप था, नीति की समीक्षा करने के लिये तीन समितियाँ बना दी गईं। अगले वर्ष एक अपवाद को छोड़कर उन्हें भी संगठन से निकाल दिया गया।

सी. आई. ओ. ने निष्कासित यूनियनों के स्थान पर नई यूनियनें बनाने की कोशिश की और अपनी खोई हुई सदस्य संख्या को फिर से प्राप्त करने में हुई। फिलिप मर्रे ने कहा कि कम्युनिस्ट-नियंत्रित यूनियनों के अधि-

कारी कम्युनिस्ट कार्यक्रम के प्रति आस्था रखते हुए, "परेशान करने, मुखालफ़त करने और अड़ंगे डालने" की नीति पर चल रहे हैं। किन्तु सी. आई. ओ. संगठन में उनका "एक बहुत छोटा पर शोर मचाने वाला गुट है।"

कोरियाई युद्ध के कारण संगठित मजदूरों के सामने कुछ वैसे ही सवाल आए, जैसे दूसरे युद्ध के दौरान आए थे। राष्ट्रीय अर्थतंत्र पर फिर से सरकारी नियंत्रण हो जाने तथा आर्थिक स्थिरीकरण एजेंसी के एक अंग के रूप में वेतन स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना ने सामूहिक सौदेबाजी के संपूर्ण कार्यक्रमों में अनेक नई बातों का समावेश किया। १९४१-४५ के वर्षों की भांति मजदूर सरकार से पूर्ण सहयोग के लिए उद्यत थे। राष्ट्रीय आपातकाल में औद्योगिक शांति के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने का प्रयत्न करने के हेतु श्रम-सम्बन्धी नीतियों के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिये ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. ने मिलकर एक संयुक्त श्रम नीति समिति स्थापित की। इसका तात्कालिक कार्य मनुष्य शक्ति सम्बन्धी समस्याओं, उत्पादन, वेतन, मूल्य और सार्वजनिक पदों पर यूनियन अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में बड़ी यूनियनों के बीच समझौते कराना था।

इस कार्यक्रम को अमली रूप देने में काफी संघर्ष पैदा हो गया और कुछ समय तक सरकार व संगठित मजदूरों के सम्बन्ध काफी तनावपूर्ण रहे। मजदूरों के दृष्टिकोण पर बहुत कम ध्यान दिए जाने और जनवरी १९५० के स्तर से १० प्रतिशत से अधिक वेतन वृद्धियों पर पाबन्दी लगाने की नीति अपनाए जाने के कारण संयुक्त श्रम नीति समिति ने मजदूर सदस्यों से वेतन स्थिरीकरण बोर्ड तथा अन्य सरकारी एजेंसियों से हट जाने को कहा। यह बहिष्कार दो महीने जारी रहा किन्तु अन्त में विवादग्रस्त मामले हल हो गए। तब मजदूरों ने लाभबन्दी नीति पर राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में अपने प्रतिनिधि भेजना स्वीकार कर लिया और पुनर्गठित वेतन स्थिरीकरण बोर्ड में भी वे लौट आए।

संयुक्त श्रमनीति समिति जिसने इन सब घटनाओं में बहुत भाग लिया था और असाधारण यूनियन सहयोग प्रदर्शित किया था ए. एफ. एल. सदस्यों के हट जाने के कारण यकायक भंग हो गई। किन्तु उस वक्त तक इस कथन का औचित्य काफी हद तक सही साबित हुआ था कि "काफी हद तक इसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया।" क्योंकि सब प्रकार की कठिनाइयों और

सरकारी एजेंसियों में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो जाने के बावजूद संगठित मजदूर राष्ट्रीय रक्षा प्रयत्नों को सहयोग देते रहे। १९५१ और १९५२ के आखिरी दिनों में हड़ताल सम्बन्धी गतिविधि वस्तुतः बहुत कम हो गई।

शांतिपूर्ण सामूहिक सौदेबाजी अथवा हड़तालों के जरिये मजदूरों की सुरक्षा को बढ़ाने तथा घरेलू राजनीति और विदेशी मामलों में मजदूरों के अधिकाधिक भाग लेने के अलावा अन्य भी कारणों से नवम्बर, १९५३ का महीना अमरीकी मजदूरों के इतिहास में एक असाधारण महीना सिद्ध हुआ। ९ नवम्बर को जॉन एल. लेविस के त्यागपत्र देने के बाद से ही सी· आई· ओ. के अध्यक्ष फिलिप मर्रे यकायक दिल की धड़कन बन्द हो जाने से गुज़र गए, और २१ नवम्बर को ३० वर्ष से चले आ रहे ए· एफ· एल. के अध्यक्ष विलियम ग्रीन भी इतने ही अप्रत्याशित रूप में चल बसे। १२ दिनों की अल्प अवधि में संगठित मजदूरों को दो प्रबल आघात लगे थे और सी· आई· ओ. तथा ए· एफ· एल. दोनों के सामने नए नेता चुनने का कठिन सवाल उत्पन्न हो गया।

इससे पूर्व कि सी· आई. ओ· की अध्यक्षता, प्रतिभाशाली कठोर प्रहार करने वाले यूनाइटेड आटो वर्कर्स के ओजस्वी मुखिया वाल्टर रूथर को सौंपी जाती, काफ़ी संघर्ष हुआ। हाल के वर्षों में उसका सितारा काफी ऊँचा चढ़ा है। 'वह एक तीसरा मज़दूर दल बनाना चाहता है,' इस तरह की रिपोर्टें, बन्द हो जाने पर भी उसकी महत्त्वाकांक्षाओं के बारे में कुछ ठीक पता नहीं चलता था तो भी इसमें शक नहीं कि मज़दूरों के हित-साधन के पीछे वह पूर्णतः और एक निष्ठता से दीवाना था। रूथर लेविस के पद का वाजिब उत्तराधिकारी था।

ए· एफ· एल· ने अपना नया अध्यक्ष सचिव-कोषाध्यक्ष जॉर्ज मीनी को चुना। यूनियन सदस्यों के बाहर प्रायः अज्ञात मीनी ने अपना व्यावसायिक जीवन एक अप्रैण्टिस प्लम्बर से शुरू किया था और संगठित मजदूरों में उसकी [illegible]वि[illegible]यों का एक लम्बा रिकार्ड था। यूनियन व्यावसायिक एजेण्ट, न्यूयार्क [illegible] ट्रेड्स काउंसिल के सचिव ए· एफ· एल· के राज्य-अध्यक्ष और १९३९

से राष्ट्रीय महासंघ के सचिव-कोषाध्यक्ष के पद पर उसने काम किया। २२८ पौण्ड वजन के भारी भरकम शरीर वाले इस व्यक्ति को "बुल डाग व सांड के बीच की चीज" कहा जाता था। वह पुराने ढंग का परम्परागत मजदूर नेता लगता था और एक बड़े सिगार को पीते हुए या दृढ़ता से एक सिगार को चबाते हुए चित्रित किया जाता था लेकिन दिलचस्पी की व्यापकता में वह अपने पूर्ववर्तियों से कतई नहीं मिलता था। नृत्य के शौकीन, सुन्दर पियानोवादक को खेलों में भी बड़ी दिलचस्पी थी और गोल्फ खेलने वाला वह पहला ए. एफ. एल. का अध्यक्ष था।

अन्य यूनियन नेताओं तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों के साथ सम्बन्धों में मीनी स्पष्टवादिता और कभी-कभी आवेश से काम लेता था। वह ए. एफ. एल. के उन गिने चुने अधिकारियों में से था जो लेविस के सामने तनकर खड़े होना चाहते थे और खड़े हो सके। १९४७ में उसने कम्युनिस्ट न होने के हलफनामों पर दस्तखत करने के प्रश्न पर लेविस के रुख को सफल चुनौती दी और जहाँ तक ए. एफ. एल. का सम्बन्ध है, उसने कामयाबी हासिल की। वह परिस्थितियों के मुताबिक जितना चाहे उतना सख्त हो सकता था।

अपने समस्त व्यावसायिक जीवन में वह प्रगतिशील सिद्धान्तों का हामी रहा जो सदा ए. एफ. एल. की नीति से सोलहों आने मेल नहीं खाते थे और जिस काम को वह अपने हाथ में लेता उसे पूरा करने के लिए जी-जान लड़ा देता था। किसी भी प्रकार के जातीय अथवा धार्मिक भेदभाव का वह कट्टर विरोधी था। ए. एफ. एल. के अन्य अधिकारियों की अपेक्षा राजनीति में ज्यादा रुचि रखते हुए मीनी को सामाजिक मामलों में चिरकाल से दिलचस्पी थी और वह समझता था कि यूनियन सदस्यों को इन प्रकार की गतिविधियों में ज्यादा हिस्सा लेना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के पक्ष में मजदूरों के समर्थन का दृढ़ता से बखान करते रहे।

इसके अलावा क्षितिज पर एक नई घटना घट रही थी। उसको भी इन्होंने नया सम्बल प्रदान किया। यह था ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. का चिर-विचारित विलय जिसकी समय-समय पर भविष्यवाणी की जाती थी किन्तु जिसे हमेशा स्थगित कर दिया जाता था। इन दोनों महान् राष्ट्रीय संगठनों के बीच मूल विवादास्पद प्रश्न कभी के मिट चुके थे और आंतरिक राजनीतिक मतभेद धीरे-धीरे दूर किए जा रहे थे। इसलिए दोनों के राष्ट्रीय नेतृत्व में एक साथ परिवर्तन के कारण ऐसा लगा कि परम्परागत प्रतिद्वन्द्विताओं को अन्तिम रूप से खतम कर देने का और मजदूरों की बड़ी ताकतों को एक ही राष्ट्रीय संघ में एकजूट कर देने का अद्वितीय अवसर आ पहुँचा है।

वर्ष गुज़रते जाने के साथ ए. एफ. एल और सी. आई. ओ. के बीच आपेक्षिक संतुलन भी बदल गया था। कुल १,८०,००,००० यूनियन सदस्यों में से ए. एफ. एल. के ६५ लाख, तथा सी. आई. ओ. के लगभग ६० लाख सदस्य थे और २५ लाख रेलवे ब्रदरहुडों, युनाइटेड माइन वर्कर्स तथा दोनों संघों के बाहर अन्य स्वतंत्र यूनियनों के सदस्य थे। सी. आई. ओ. ने औद्योगिक यूनियनवाद पर जो बल दिया था वह ए. एफ. एल. को सामूहिक उत्पादन के उद्योगों में संगठन सम्बन्धी हलचलें बढ़ाने की आवश्यकता तथा सब तरफ अधिक ज़ोरदार नीतियाँ अपनाने के प्रति सजग करने में सहायक बना रहा। इसके अलावा जिस प्रकार दोनों संगठन आर्थिक कार्रवाई से सम्बन्धित मामलों में एक दूसरे के निकट आ गए थे इसी प्रकार सी. आई. ओ. का उदाहरण राजनीतिक कार्रवाई के क्षेत्र में अधिक बड़ा रोल अदा करने के लिए ए. एफ. एल. को प्रेरित किया करता था। सहयोग अधिकाधिक एक नियम बन गया था। सी. आई. ओ. की नीति कार्रवाई समिति 'राजनीतिक शिक्षा के लिए मज़दूरों की लीग' के साथ निकट सहयोग पूर्वक काम कर रही थी।

सम्भावित विलय के प्रति, जिसकी तरफ अनेक यूनियनें व्यक्तिगत रूप से पहले भी मार्गदर्शन कर चुकी थीं, पहला महत्त्वपूर्ण कदम यह था कि जून १९५४ में ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. की घटक यूनियनों के बीच दो का अनतिक्रमण समझौता हो गया। तथ्यों से पता लगा कि व्यापक रूप

से प्रचलित यूनियन सम्बन्धी लूट-खसोट और उसके फलस्वरूप होने वाली अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी हड़तालें हर दृष्टि से निरर्थक तथा समय और शक्ति का महँगा अपव्यय था। मीनी और रूथर में ऐसे क़दम उठाने के लिए आवश्यक उदार दृष्टि और अधिकार थे जो यूनियनों में आपसी कलह को बन्द कर समस्त मजदूर जगत् में अधिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर सके। १९५५ तक ए. एफ. एल. की ११० में से ८० यूनियनों ने और सी. आई. ओ. की सिर्फ दो यूनियनों को छोड़कर बाकी सब यूनियनों ने इस अनतिक्रमण समझौते को सम्पुष्ट कर दिया।

इस बीच एक संयुक्त एकता समिति भी काम करने लगी जिसमें पुनः मीनी और रूथर ने बड़ी भूमिका अदा की। अनतिक्रमण समझौते ने वस्तुतः इस बात की आशा बाँधी कि इस समिति के विचार-विमर्श से शायद कोई ठोस परिणाम निकल सके और इस बात के संकेत मिल रहे थे कि सी. आई. ओ. तथा ए. एफ. एल. की अनेक अन्तर्राज्यीय यूनियनें एकता के लिए अधिकाधिक प्रयत्न कर रही हैं। किन्तु विलय-वार्ता क्या वस्तुतः सफल हो रही है, इसका बहुत ही अंतरंग मज़दूर क्षेत्रों से बाहर कुछ पता नहीं था। ९ फरवरी, १९५५ को नाटकीय आकस्मिकता के साथ संयुक्त समिति ने घोषणा की कि दोनों संगठनों के विलय के बारे में ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. दोनों के प्रतिनिधियों के बीच पूर्ण समझौता हो गया है।

यह कहा गया कि इस प्रस्तावित विलय से अनतिक्रमण समझौता जारी रहने के कारण प्रत्येक घटक राज्यीय व अन्तर्राज्यीय यूनियन अपनी अखण्डता को सुरक्षित रख सकेगी और ए. एफ. एल. के अन्दर मौजूदा विशेष विभागों की तरह औद्योगिक संगठन की विशेष परिषद् स्थापित करके सी. आई. ओ. का विशिष्ट अस्तित्व बना रहेगा। इस प्रकार नए संघ ने हर तरह से यह कबूल कर लिया कि संगठित मज़दूरों में औद्योगिक यूनियनों तथा शिल्प यूनियनों दोनों का स्थान है और हर मामले में सम्बन्धित मज़दूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावशाली संगठनात्मक साधन निर्णायक तत्त्व होगा।

एकता से यह भी आशा बँधी कि अब मज़दूरों की बड़ी समस्याओं का सामना करने में प्रभावशाली कदम उठाया जा सकेगा। इसने कम्युनिस्टों की

घुसपैठ, पैसा ऐंठने और जातीय भेदभाव जैसी बुराइयों से जूझने वाली ताकतों को बहुत मज़बूत किया। एकता समिति की रिपोर्ट में खास तौर से कहा गया कि संयुक्त संघ अमरीकी ट्रेड यूनियन आन्दोलन को "किसी भी या सब तरह के भ्रष्ट प्रभाव से, कम्युनिस्ट एजेंसियों और हमारे लोकतंत्र तथा स्वतंत्र और लोकतंत्रीय ट्रेड यूनियनवाद के बुनियादी सिद्धान्तों की मुखालफत करने वाले अन्य सब तत्त्वों से" बचाने की हर कोशिश करेगा।

प्रस्तावित विलय में जो बाधा सदैव दुर्लंघ्य रही, अर्थात् नए संगठन के नेतृत्व की, वह सी. आई. ओ. द्वारा स्वेच्छा से नेतृत्व ए. एफ. एल. को सौंप दिए जाने के कारण दूर हो गई। एक बार जब विलय को दोनों संगठनों ने अंतिम रूप से सम्पुष्ट कर दिया तो एकता समिति को प्रदान किए गए समर्थन तथा ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. दोनों की कार्यसमितियों द्वारा की गई अनुकूल कार्रवाई से यह पहले ही स्पष्ट हो गया कि जार्ज मीनी समस्त राष्ट्र और सम्पूर्ण उद्योगों में १५० लाख सदस्यों वाले नए संघ के अध्यक्ष बनेंगे।

ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. को एक संयुक्त ट्रेड यूनियन अन्दोलन में गूँथने के अंतिम समझौते की घोषणा करने वाले अपने ऐतिहासिक वक्तव्यों में मीनी और रूथर ने संयुक्त रूप में कहा :

"हमें विश्वास है कि दोनों यूनियन ग्रुपों का जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं विलय इस तनावपूर्ण युग में हमारे राष्ट्र और उसकी जनता के लिए एक वरदान होगा। हमें खुशी है कि हम अपने ढंग से ऐसे समय में अमरीकी मज़दूर आन्दोलन में एकता स्थापित कर सके जब विश्व शांति और सभ्यता पर कम्युनिस्टों के खतरे को देखते हुए समस्त अमरीकी जनता की एकता तुरन्त ही परमावश्यक है।"

स्वतंत्र और लोकतंत्रीय ट्रेड यूनियनवाद के लक्ष्य को अग्रसर करने की दृष्टि से इस प्रस्तावित विलय का मज़दूरों में ही स्वागत नहीं किया गया। राष्ट्रीय निर्माता ऐसोसियेशन के अध्यक्ष के इस वक्तव्य के अलावा कि विलय को "ग़ैर-कानूनी" करार दिया जाना चाहिए तथा अनुदार मंत्रियों के कभी-कभी प्रकट किए गए इस भय को छोड़कर कि इससे मज़दूरों का एकाधिपत्य स्थापित हो जाएगा, व्यावसायिक वर्ग के समाचार-पत्रों ने भी इस कदम का ... किया और आशा प्रकट की कि इससे औद्योगिक शांति स्थापित होगी।

वाल स्ट्रीट जर्नल ने इन्कार किया कि इस विलय से किसी भी प्रकार मज़दूरों के एकाधिपत्य में वृद्धि होगी और 'नेशन्स बिज़नेस' ने यह कहते हुए भी कि इस विलय का मतलब 'एक राजनीतिक शक्ति-स्रोत" हो सकता है, बताया कि अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी झगड़े कम हो जाने से इस विलय से उद्योगों को क्या लाभ हो सकते हैं।

अन्य अखबारों में न्यूयार्क टाइम्स ने विलय को 'राजनीतिज्ञता का करिश्मा' बताया, वाशिंगटन पोस्ट तथा टाइम्स हैरल्ड ने इसे "मज़दूरों द्वारा प्राप्त की गई परिपक्वता तथा जिम्मेदारी की भावना का प्रभावशाली प्रदर्शन" बताया, 'क्रिश्चियन साइन्स मानीटर' ने भी इसे मज़दूरों में परिपक्वता और जिम्मेदारी की बढ़ती हुई भावना का प्रतीक बताया और वाशिंगटन स्टार ने यह विश्वास प्रकट किया, जो अन्य अखबारों में भी प्रतिध्वनित हुआ कि इस विलय से "मज़दूर प्रबन्धक सम्बन्धों में दीर्घकालीन स्थिरता" आनी चाहिए। मज़दूर-संगठन के प्रति अनुदारपन्थी रवैया पिछली दो दशाब्दियों में कितना बदल गया था, इसका इससे बढ़िया और क्या सबूत मिल सकता था कि ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. के विलय का देशभर में स्वागत किया गया।

विलय की घोषणा के कुछ ही देर बाद मीनी ने 'फौर्चून' में एक महत्त्वपूर्ण लेख लिखा जिसमें उसने संगठित मज़दूरों के नए लक्ष्यों और महत्त्वाकांक्षाओं की रूपरेखा बताई। यूनियनों की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने मज़दूरों की स्थिति में और सुधार की निरन्तर आवश्यकता तथा आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की कार्रवाई के महत्त्व पर बल दिया। उन्होंने कहा : सरकारी नीतियों में मज़दूरों का हिताहित ज़्यादा संलग्न रहने के कारण " हम राजनीति में रहेंगे।"

मज़दूर विशेष रूप से और क्या चाहते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में मीनी ने लिखा :

"हम अमरीकी समाज को किसी खास सैद्धान्तिक शक्ल में नहीं ढालना चाहते। हम चाहते हैं मज़दूरों का जीवन स्तर हमेशा उन्नत होता जाए। साम गौम्पर्स ने यही बात एक बार संक्षेप में कही थी। यह पूछे जाने पर कि मज़दूर आन्दोलन क्या चाहता है, उसने कहा था 'अधिक'। अगर बेहतर जीवन स्तर से हमारा अभिप्राय अधिक पैसे के अलावा अधिक अवकाश तथा समृद्धतर

सांस्कृतिक जीवन भी है तो उस प्रश्न का उत्तर अब भी 'अधिक' ही है।"

इसी समय रूथर इस बात को और भी स्पष्ट कर रहा था कि बड़े निर्माताओं तथा युनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स के बीच नए समझौतों में गारण्टी प्राप्त वार्षिक वेतन के विचारों को समाविष्ट करके वह भी मज़दूरों के लिए 'अधिक' वेतन चाहता है। यह उसका तात्कालिक उद्देश्य था और उसने अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया कि समस्याएं कठिन भले ही लगें मोटर उद्योग तथा उसके कर्मचारियों के पारस्परिक हित की दृष्टि से उनका समाधान सम्भव है। वह यह नहीं समझता था कि वार्षिक वेतन की गारण्टी अथवा जिसे कभी-कभी वर्ष पर काम पर लगे रहने की गारण्टी कहा जाता था, औद्योगिक सम्बन्धों का रामबाण इलाज है किन्तु वह यह ज़रूर समझता था कि यह उद्योग मालिकों के नज़रिये को ऊँचा उठाने में जरूर सहायक हो सकता है जिससे कि अपनी योजनाएं बनाते समय वे आय और क्रय शक्ति के सतत प्रवाह के बारे में अपने कारखाने के मज़दूरों और समस्त समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखें।

तो भी १९५५ की वसन्त ऋतु में गारण्टी प्राप्त वेतन की इस योजना का व्यावसायिक वर्ग में व्यापक विरोध था और वे इसकी व्यावहारिकता में सन्देह करते थे। १ मार्च को जर्नल आव कामर्स ने राष्ट्र के प्रमुख उद्योगों में बड़े-बड़े प्रबन्धकों की इस भावना को मूर्त रूप दिया। यह अभी देखना था कि उक्त विरोध के बावजूद वार्षिक वेतन की गारण्टी को "आर्थिक दृष्टि से हितकारी और नैतिक दृष्टि से उचित" समझने वाले रूथर के साथ इस मामले पर कोई समझौता हो सकता है या नहीं।

इस मामले पर संघर्ष करने के उसके इरादे के बारे में कोई सन्देह नहीं था। रूथर ने कहा कि "यह एक जिहाद, आर्थिक बाहुल्य को मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का जिहाद है। हम प्रबन्धकों को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर अपनी दृष्टि का कुछ अंश उन्हें प्रदान करना चाहते हैं। हम उन्हें यह दिखाना चाहेंगे कि अगर स्वतंत्र मज़दूर, स्वतन्त्र प्रबन्धक, स्वतंत्र सरकार और स्वतंत्र जनता अमरीका की शक्ति को जुटाने और उससे लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में परस्पर सहयोग करें तो कैसे महान् नए संसार की सृष्टि की जा सकती है।"

ग्रीष्म के प्रारम्भ में नए समझौतों के लिए मोटर उद्योग के साथ बातचीत में रूथर अपने नए यूनियन उद्देश्य की प्राप्ति में काफी हद तक सफल हुआ। प्रमुख कम्पनियाँ वस्तुतः वार्षिक वेतन की गारण्टी के सिद्धान्त पर सहमत हो गईं और युनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स ने हड़ताल की धमकियों के बिना ही अधिक से अधिक आशावादी यूनियन सदस्यों की आशा से भी अधिक लाभ प्राप्त किए। फोर्ड कम्पनी ने और उसके तुरन्त बाद ही जनरल मोटर्स ने सर्वप्रथम ऐसे समझौते किए जिनमें करीब-करीब सामान्य दर पर कम-से-कम आधे वर्ष के वेतन की गारण्टी प्रदान की गई थी।

वार्षिक वेतन की गारण्टी के अलावा मज़दूरों की और भी समस्याएँ थीं। अनेक राज्यों में (१९५५ में १७ राज्यों में) "काम के अधिकार" का व्यापक अस्तित्व बन्द शाप तथा यूनियन शाप दोनों के खिलाफ भेदभाव में यूनियन सुरक्षा को बड़ा खतरा समझा जाता था। यह कानून टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट की एक धारा के मातहत बनना संभव हुआ, जिसमें कहा गया था कि यूनियन सुरक्षा के बारे में राज्य के कानून यदि संघीय कानून से ज्यादा प्रतिबन्धात्मक हैं तो राज्य के कानून ही चलेंगे। यद्यपि नए श्रममंत्री जेम्स पी. मिचेल ने राज्यों से इन कानूनों को रद्द कर देने के लिये कहा तो भी संगठित मजदूर उनका मुकाबला करने का सबसे अच्छा उपाय यही समझते थे कि टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट की उस धारा को ही खत्म करा दिया जाए, जिसके मातहत उन कानूनों का बनना संभव हुआ है।

यूनियन सदस्यों के लिए शायद इस से भी महत्त्वपूर्ण बात ऑटोमेशन-मशीन द्वारा मशीनका-संचालन-द्वारा बेकारी बढ़ने का संभावित परिणाम थी। मजदूर ऑटोमेशन का विरोध नहीं कर रहे थे किन्तु उनका कहना था कि वार्षिक वेतन की गारण्टी या अन्य ऐसे उपायों से फैक्ट्री मजदूरों की तेज़ी से की जाने वाली छँटनी के धक्के को झेलने लायक बनाने की व्यवस्था की जाए। यह एक ऐसा प्रश्न था जिस पर धन्धे की सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामूहिक क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक पूर्ण रोजगार की जरूरत की दृष्टि से भी मजदूर स्वयं को अपनी आवाज सुने जाने के अधिकारी मानते थे।

यह स्पष्ट था कि इन समस्याओं तथा टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट के संशोधन के

बारे में संगठित मज़दूर सब मज़दूरों के हितों की रक्षा और उनको अग्रसर करने में सब कुछ कर डालने के लिये अपनी समस्त आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का जो ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. के विलय से और मज़बूत हो गई थी, प्रयोग करने पर आमादा थे। 'अधिक' का भावी लक्ष्य निरन्तर अपने ध्यान में रखने का निश्चय किया गया।

तो भी 'फौर्चून' में अपने लेख की परिसमाप्ति करते हुए मीनी अतीत का महान सफलता की दृष्टि से सिंहावलोकन कर सका। उसने लिखा कि अमरीकी मज़दूरों का जीवन-स्तर १९०० के बाद से दुगना हो गया है और काम का समय एक-तिहाई घट गया है। वह स्वतन्त्र व्यवसाय प्रणाली के ढांचे के अन्तर्गत जिसकी बदौलत अमरीकी समाज में अमरीकी मज़दूरों की अच्छी स्थिति संभव हो सकी है, इन्हीं दिशाओं में और प्रगति करने का विश्वासपूर्वक स्वप्न लिया करता था।

—:o:—

२१ : मज़दूरों के सामने अनिश्चित भविष्य

ए. एफ. एल तथा सी. आई. ओ. के विलय और १६५५ में मज़दूरों की सामान्यतः अनुकूल स्थिति से मजदूर आन्दोलन के और ज्यादा विकास की बहुत आशा बँध रही थी। अगले ५ वर्षों में ये आशाएँ पूर्णतः पूरी हुईं। वस्तुतः १६६० की दशाब्दी के आरम्भ में संगठित मज़दूर हार-पर-हार खाते प्रतीत हुए जिससे मज़दूर नेताओं में गम्भीर चिन्ता उत्पन्न हो गई और ए. एफ. एल. सी. आई. ओ. के सम्मेलन में अन्धकार-सा छा गया।

संयुक्त संघ ने अपने पहले सम्मेलन में अगले १० वर्षों में यूनियन-सदस्यता को दुगुना करने का लक्ष्य रखा था किन्तु इसकी आधी अवधि बीत जाने पर भी सदस्यता में कोई वृद्धि नहीं हुई और संगठन सम्बन्धी हलचल करीब-करीब ठप्प रही। अनेक यूनियनों में भ्रष्टाचार तथा पैसे ऐंठे जाने की वारदातों के भण्डाफोड़ से, जिसका मजदूर व प्रबन्धक क्षेत्र में अनुचित तौर-तरीकों पर सेनेट की समिति की रिपोर्ट से व्यापक प्रचार हो गया था, यूनियनों की जिम्मेदारी की भावना में जनता का विश्वास उत्पन्न नहीं हो सका। अन्त में काँग्रेस ने १० वर्षों में लैण्ड्रम-ग्रिफिन ऐक्ट नाम से पहला कानून बनाकर यूनियनों की शक्ति पर महत्त्वपूर्ण अंकुश लगा दिए। यूनियनें जहाँ यह समझती थीं कि १६५८ के मध्यावधि चुनावों में उदारपंथियों की विजयों की विजय के बाद टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट को रद्द कराना अथवा उसमें संशोधन करा लेना उनके लिए बहुत आसान हो गया है वहाँ संगठित मज़दूरों ने न्यूडील के बाद से अब तक किसी भी समय में अपने हाथ पाँव सबसे ज्यादा बंधे हुए पाए।

हो सकता है कि १६६० के दशक के प्रारम्भ में मज़दूरों में व्याप्त यह निराशा पूर्णतः उचित न हो। इन सब धक्कों के बावजूद यूनियनें बहुत शक्तिशाली थीं और राष्ट्रीय अर्थतंत्र पर बहुत प्रभाव डाल सकती थीं। बड़ी औद्योगिक यूनियनों द्वारा किए गए सामूहिक सौदेबाजी के समझौतों से उनके सदस्यों को अधिक वेतन और ज्यादा आनुषंगिक लाभों के रूप में फ़ायदा होता रहा। १६५६-६० की लम्बी इस्पात हड़ताल में, देश के बुनियादी उद्योग में

पुराने ढंग के सत्ता-संघर्ष में, अन्ततोगत्वा मज़दूरों की ही आपेक्षिक जीत हुई थी। तो भी राष्ट्र के अर्थतन्त्र में बुनियादी परिवर्तनों—विशेषकर मज़दू-शक्ति के स्वरूप में परिवर्तन और बहुत से उद्योगों में ऑटोमेशन की तेज़ रफ्तार ने भविष्य की अनिश्चितताओं को सामने ला खड़ा किया। '६० के दशक में मज़दूर कहाँ जा रहे हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में एक सुप्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री ने नि:संकोच उत्तर दिया "बहुत दूर नहीं।" संगठित मज़दूरों ने स्वयं यह अनुभव किया कि अगर उन्हें अपना वह आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव कायम रखना है जो पिछली चौथाई सदी के राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका की विशेषता रही है तो उन्हें अपनी कुछ नीतियाँ बदलनी होंगी।

ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. के प्रशासनिक निकायों के अधिकृत विलय से ही मज़दूर आन्दोलन में वह सामष्टिक एकता कायम नहीं हो गई जो उसके राष्ट्रीय नेताओं का लक्ष्य थी। राज्य-संघों तथा स्थानीय संगठनों में मेल कराने और मज़दूर आन्दोलन के समस्त विक्षुब्ध इतिहास में उसके लिए अभिशाप रूप अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी झगड़ों को रोकने के अधिक प्रभावशाली उपाय करने की कठिन और दुरूह समस्या बनी रही। यद्यपि ए. एफ. एल. सी. आई. ओ. के अध्यक्ष के रूप में जार्ज मीनी संयुक्त श्रमिक शक्ति का इतना प्रभावशाली नेता सिद्ध हुआ कि अनेक समस्याएँ उसे सिर्फ यही कह कर सौंप दी जाती थीं कि "अरे, यह काम जार्ज पर छोड़ दो," तो भी उसे राज्य संघों अथवा वैयक्तिक यूनियनों में अधिकारियों का सदा पूरा सहयोग नहीं मिला। स्थानीय विलय वार्ताएँ प्राय: कच्छपगति से चलती रहीं और १९५० के दशक की समाप्ति तक ही समस्त राज्यों में यह विलय पूरा हो सका। तब भी कुछ ऐसे स्थानीय संगठन मौजूद थे जिन्होंने एक पूर्णत: संयुक्त श्रम मोर्चा उपस्थित करने के लिए अंतिम व्यवस्थाएँ पूरी नहीं की थीं।

इसके अतिरिक्त यूनियनों के भ्रष्टाचार के बारे में सेनेट की जाँच के परिणामों के प्रकाश में अपसरण और निष्कासनों के कारण भी इन वर्षों में ए. एफ. एल. तथा सी. आई. ओ. दोनों से सम्बद्ध राज्यीय तथा अन्तर्राज्यीय यूनि-नों की संख्या कम हो गई थी। १९६० की दशाब्दी के प्रारम्भ में मज़दूरों के संयुक्त संघ में १३४ यूनियनें थीं किन्तु उनके सदस्यों की संख्या १९५६

में १,७०,००,००० से घटकर १,३५,००,००० रह गई थी। इस ह्रास का बहुत बड़ा कारण टीमस्टर्स यूनियन का निष्कासन था, जिसके फलस्वरूप असम्बद्ध यूनियनों की सदस्य संख्या भी बढ़ी।

ए. एफ. एल. सी. आई. ओ. से अलग हो जाने से भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यूनियन सदस्यता में सामान्य कमी हो जाना था, जो इन आँकड़ों से ज़ाहिर होती थी। १९५८ में अधिकृत द्विवार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि सदस्य संख्या दो दशाब्दियों में पहली बार कम हुई है। यह १,८५,००,००० से घट कर १,८१,००,००० हो गई। अगले दो वर्षों के अनुमानों में भी इस संख्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि जनवरी १९६० में कुल सिविल श्रम-शक्ति के मुकाबले में, जो लगभग ६,८२,००,००० की हो गई थी, यूनियन सदस्यों का अनुपात राष्ट्र के मजदूरों के एक चौथाई से भी कम था। वाल्टर रूथर ने स्पष्ट कहा: "हमारे कदम पीछे हट रहे हैं।"

यूनियनों की सदस्य संख्या में इस कमी के कई कारण थे, किन्तु इसका मूल कारण संभवतः यह था कि निर्माण, खान तथा परिवहन उद्योगों में कर्मचारियों की संख्या प्रशासन, थोक न परचून व्यापार, वित्त विनियोग, और विशेषकर सर्विस उद्योगों में कर्मचारियों की बढ़ती हुई संख्या के अनुपात में घट रही थी। रोज़गार के स्वरूप में इस परिवर्तन के दोनों कारण थे। उत्पादन उद्योगों में अधिकाधिक ऑटोमेशन का सहारा लिया जा रहा था जहाँ नई-नई प्रक्रिया और नई-नई मशीनें आवश्यक कर्मचारियों की संख्या कम करती जा रही थीं और अधिक सर्विस चालू करने की जनता की माँग पूरी करने के लिये अनुत्पादक उद्योगों का विस्तार किया जा रहा था। वस्तुतः हो यह रहा था कि जो कर्मचारी सदा से संगठन प्रेमी रहते आए थे उनका अनुपात कम हो गया और जो यूनियन सदस्यता के विचार के घोर विरोधी थे, उनका अनुपात बढ़ रहा था। सफेदपोश कर्मचारी नीलपोश कर्मचारियों पर हावी हो रहे थे।

संगठन सम्बन्धी गतिविधियों में ए. एफ. एल.—सी. आई. ओ. को अन्य कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। जिन उद्योगों में यूनियन की जड़ें बहुत गहरी जमी हुई थीं वहाँ भी यूनियन की सदस्यता में दिलचस्पी कम हो गई थी और दक्षिण में यूनियन-संगठन की मुख़ालफ़त घटने के बजाय बढ़ गई।

स्वयं मज़दूर नेताओं में १६३० और १६४० के दशकों का-सा जोश ठण्डा हो गया प्रतीत होता था। किन्तु राष्ट्रीय एकता के हित में ए. एफ. एल. और सी. आई. ओ. का विलय करते हुए संयुक्त मज़दूर आन्दोलन ने अपने और विकास की जो आशा व्यक्त की थी, उसकी पूर्ति में विफलता का बड़ा कारण राष्ट्र की श्रमिक शक्ति के स्वरूप का बदल जाना ही था।

राजनीतिक क्षेत्र में नए संघ ने राजनीतिक शिक्षा के लिए एक नई समिति बनाकर मज़दूरों के हितों को अग्रसर करने में तत्परता से काम करना शुरू कर दिया। दोनों में से किसी भी बड़े राजनीतिक दल के साथ मज़दूरों को सम्बद्ध करने का अब भी कोई इरादा नहीं था। राजनीतिक शिक्षा समिति ने "पूर्णतः निर्दलीय नीति" अपनाए रखने का संकल्प व्यक्त किया किन्तु १६५६ में दोनों पार्टियों के सम्मेलन में मज़दूरों द्वारा जो प्रस्ताव पेश किए गए उनपर डैमोक्रैटिक पार्टी का ज्यादा अनुकूल रुख देख कर मज़दूरों ने राष्ट्रपति-पद के चुनावों में डैमोक्रैटिक पार्टी का ही समर्थन किया जैसा कि वे रूज़वेल्ट के ज़माने से निरन्तर करते आए थे। ए. एफ. एल. सी. आई. ओ. की कार्यकारिणी ने ऐडलाई स्टीवेंसन की उम्मीदवारी का समर्थन किया और राजनीतिक शिक्षा समिति ने उनकी तरफ से और कांग्रेस के लिए ऐसे उम्मीदवारों के पक्ष में चाहे वे डैमोक्रेट हों या रिपब्लिकन जिनकी नीति का यह समर्थन करती थी, जोरदार चुनाव आन्दोलन किया। राष्ट्रपति आइज़नहावर के पुनर्निर्वाचन से निराश होकर भी मज़दूरों को कांग्रेस में डैमोक्रैटिक और लिबरल तत्त्वों के अधिक संख्या में आ जाने से सन्तोष हुआ।

संगठन सम्बन्धी अभियान अथवा राजनीतिक कार्रवाई की भी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण एक अन्य मोर्चे पर ए. एफ. एल. सी. आई. ओ. की आशाएँ चकनाचूर हो गईं। विलय का एक मुख्य उद्देश्य यूनियन संगठन को नई ताकत देने के अलावा ग़ैर-जिम्मेदार यूनियनों पर अधिक प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करना भी था। इस उद्देश्य के लिए संघ ने एक नैतिक आचरण समिति स्थापित की जो एक आचार संहिता लागू करके मज़दूरों पर लगाए गए अधिकाधिक गम्भीर आरोपों के सामने अपने घर की गड़बड़ी खुद ठीक कर लेने की आशा रखती थी। मज़दूरों पर लगाए जाने वाले ये आरोप थे—यूनियन [illegible]पों का, विशेषकर कल्याणकार्य व पेंशन योजनाओं में लगाए गए धन का

दुरुपयोग; यूनियन नेताओं का दुर्व्यवहार तथा यूनियन सम्बन्धी मामलों में भ्रष्टाचार तथा अनैतिक आचरण के अन्य उदाहरण। किन्तु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि अनेक यूनियनों में स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि जनता व कांग्रेस में से कोई भी इस मामले को पूर्णतः ए. एफ. एल. सी. आई. ओ. के डण्डे के लिए ही नहीं छोड़ देना चाहता था, बल्कि वे सरकारी जाँच-पड़ताल और संभावित सरकारी कार्रवाई के लिए आग्रह कर रहे थे।

फलस्वरूप कांग्रेस ने १९५७ में मज़दूर या प्रबन्ध जगत् में से कहीं भी अनुचित तौर-तरीकों की जाँच के लिए एक प्रवर समिति नियुक्त की और आरकन्सास के सेनेटर जॉन एल मैक्लेल्लान की अध्यक्षता में इसने तुरन्त ही आम सुनवाइयाँ शुरू करदीं जिनमें प्रकट असलियत से सारा देश स्तब्ध रह गया। तानाशाही नियंत्रण, व्यापक भ्रष्टाचार, हिंसा और पैसा ऐंठे जाने की वारदातें वस्तुतः कुछ ही यूनियनों के बारे में प्रकट हुईं किन्तु इससे सारे मज़दूर आन्दोलन को शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा और इसके नेताओं को बचाव के पैंतरे पर आना पड़ा।

कांग्रेस की जाँच-पड़ताल का एक मुख्य लक्ष्य टीमस्टर्स यूनियन थी। समिति की सुनवाइयों में एक के बाद एक गवाह ने जो चौंका देने वाले रहस्य खोले उनसे पता चला कि इसका अध्यक्ष डेविड बेक इस यूनियन को मनमाने ढंग से चला रहा था और उसका बहुत सा धन उसनें अपने निजी कार्यों में खर्च कर दिया था। घमण्डी और समिति की सत्ता की अवहेलना करने वाले इस टीमस्टर्स के अध्यक्ष ने सवालों का जवाब देने से बार-बार इन्कार कर दिया और जब इसपर मानहानि का दावा दायर करने की धमकी दी गई तो उसने ५वें संशोधन की शरण ली। तो भी उसके खिलाफ जो साक्षियाँ पेश की गईं, उससे वह यूनियन की अध्यक्षता छोड़ने को मजबूर हो गया और अन्ततोगत्वा उस पर आयकर अदा न करने और लूट खसोट के अभियोगों में मुकदमा चलाया गया तथा सजा दी गई।

समिति की जाँच-पड़ताल से यह भी पता चला कि टीमस्टर्स की स्थानीय शाखाओं में चुनावों में धाँधलेबाज़ी से काम लिया जाता था। यूनियन के अधिकारी मालिकों के साथ ज़ोर-जबर्दस्ती करते थे, डरा-धमकाकर रुपया पैसा ऐंठे जाने की घृणित वारदातें की जाती थीं; यूनियन अधिकारियों तथा

कुख्यात गुण्डों में (विशेषकर न्यूयार्क में) निकट सम्बन्ध था और हिंसा तथा आतंक के अन्य विविध कुकृत्य होते थे। बाद में यह भी पता चला कि टीमस्टर्स यूनियन में डेविड बेक का स्थान लेने वाला जेम्स आर. हौफा भी वही सब कुछ किया करता था जिसके लिए उसकी यूनियन बदनाम थी। मैक्लेल्लान समिति की रिपोर्ट के अनुसार वह एक "गुण्डों का राज्य" चला रहा था।

यह स्थिति और ज्यादा उलझन पूर्ण हो गई। कुछ यूनियन सदस्यों ने हौफा के खिलाफ़ चुनावों में धांधलेबाज़ी का अभियोग चलाया। सब कानूनी उपायों से उसने इसका मुकाबिला किया। अन्त में अदालतों ने यूनियन के मामलों की निगरानी तथा संचालन के लिए एक मानीटर बोर्ड नियुक्त कर दिया। किन्तु ये कानूनी दांव-पेंच जारी थे और हौफा के खिलाफ दुराचरण के अनेक आरोप लगाए गए तो भी वह अपने पद पर कायम रहा और यूनियन के मामलों में प्रायः अदालतों और कांग्रेस दोनों को चुनौती देता रहा।

मैक्लेल्लान समिति ने जो सुनवाइयाँ कीं उनमें टीमस्टर्स के बारे में की गई सुनवाई सबसे ज्यादा सनसनीखेज़ थी। किन्तु होटल ऐण्ड रेस्तरां एम्प्लायीज, बेकरी ऐण्ड कन्फैक्शनरी वर्कर्स, आपरेटिंग इंजीनियर्स, एलाइड इण्डस्ट्रियल वर्कर्स और यूनाइटेड टैक्सटाइल वर्कर्स के मामले में खुले रहस्य इससे कुछ ही कम सनसनीखेज़ थे। एक के बाद एक गवाह ने यूनियन नेताओं तथा मालिकों के बीच साँठ-गाँठ की, यूनियन कोषों के दुरुपयोग की, जबर्दस्ती पैसा ऐंठे जाने और हिंसात्मक कार्यों के बारे में साक्षियाँ दीं। समिति की सुनवाइयों से यह तसवीर सामने आई कि ऐसी बहुत-सी महत्त्वपूर्ण यूनियनें हैं जहाँ सिद्धान्तहीन और बेईमान नेताओं ने जो टीमस्टर्स की तरह प्रायः ही स्थानीय समाज के अपराधी तत्त्वों से निकट सम्बन्ध रखते हैं, लोकतंत्रीय परम्पराओं तथा यूनियन सदस्यों के अधिकारों की बिल्कुल उपेक्षा कर रखी थी। यह स्थिति ऐसी थी, जिसमें यूनियन सदस्यों, प्रबन्धकों और जनता के हितों को नुकसान पहुँचाने वाला भ्रष्टाचार और हिंसा पनपती थी।

इस प्रकार के रहस्योद्घाटन के पश्चात् ए. एफ. एल., सी. आई. ओ. की नैतिक आचरण समिति ने तुरन्त कार्रवाई की। इसने अभियुक्त यूनियनों से जवाब तलब किया और आन्तरिक सुधारों के बारे में समिति की शर्तों को [illegible] ने के लिये मोहलत दी। अपने घर की गड़बड़ी ठीक न करने पर संघ

उन्हें निकाल देने को तत्पर था और दिसम्बर, १९५७ में टीमस्टर्स यूनियन, लाण्ड्री वर्कर्स तथा बेकरी ऐण्ड कन्फेक्शनरी वर्कर्स के मामलों में उसने उक्त कार्रवाई की। ए. एफ. एल., सी. आई. ओ. जिम्मेदार यूनियन नेतृत्व के उच्च स्तर और अनुशासन लागू करने के मज़दूरों के दृढ़ संकल्प का इज़हार कर रहा था।

तो भी मार्च, १९५८ में अपनी पहली रिपोर्ट में मैक्लेल्लान समिति ने आग्रह किया कि यूनियन-भ्रष्टाचार के बारे में जो रहस्य उसने सप्रमाण उद्घाटित किए हैं, उनका इलाज करने के लिए कांग्रेस कदम उठाए और जनता यूनियनों पर सरकार का और नियंत्रण स्थापित करने का समर्थन करती प्रतीत होती थी। जब राष्ट्रपति आइज़नहॉवर ने "मजदूर-प्रवन्धक समझौतों में भ्रष्टाचार, लूट-खसोट और विश्वस तथा सत्ता के दुरुपयोग" को रोकने के लिये कानून वनाने को अपील की तो कांग्रेस उसके लिए तैयार थी।

किन्तु कानून बनाने की इस कोशिश से मज़दूर यूनियनों के कानूनी अधिकार का समस्त विवादग्रस्त विषय और टैफ्ट-हार्टले कानून में संशोवन करने या उसे रद्द करने का पुराना प्रश्न तुरन्त फिर उभर आया। मज़दूरों के दुश्मनों ने भ्रष्टाचार के रहस्योद्घाटनों से उपलब्ध अवसर का लाभ उठाकर यूनियनों की उपयुक्त गतिविधियों पर भी नए प्रतिबन्ध लगवाने की चेष्टा की। मज़दूरों के दोस्त भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता स्वीकार करने को तैयार थे किन्तु वे स्थिति का लाभ उठाकर यूनियनों के पूर्व स्वीकृत अधिकारों में कटौती कर देने के प्रयत्नों का ज़ोरदार विरोध कर रहे थे। तथाकथित डगलस-कैनेडी-आइव्स ऐक्ट नाम के एक कानून पर समझौता हो गया, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारी-कल्याण और पेंशन योजनाओं पर पूरी रोशनी डाली जाए, किन्तु बुनियादी मामलों के बारे में ज्यादा सख्त कानून बनाने का हर प्रयत्न आगामी मध्यावधि चुनावों के कारण गहरे होते जाने वाले राजनीतिक विवाद के कारण विफल हो गया। अन्त में सेनेट ने एक और आइव्स-कैनेडी विल पास किया जो एक नरम भ्रष्टाचार-विरोधी कानून था किन्तु प्रतिनिधि सभा ने इसे नरम होने के कारण ही अस्वीकृत कर दिया।

१९५८ का स्थान जब १९५९ ने लिया तब भी मैक्लेल्लान समिति द्वारा

यूनियनों के अनुचित तौर-तरीकों का भण्डाफोड़ जारी रहने के कारण मजदूरों के मामले कांग्रेस की बैठकों में प्रमुख विषय बन गए। सेनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में मजदूरों के दुश्मनों तथा मजदूरों के मित्रों के बीच एक बार फिर संघर्ष छिड़ गया और मध्यवर्ती चुनावों में डैमोक्रैटिक पार्टी की जीत के बावजूद यह धीरे-धीरे स्पष्ट हो गया कि यूनियनों पर सन् १९४८ के बाद किसी भी समय से सबसे अधिक सख्त नियम लागू करने के लिए कांग्रेस कृत-संकल्प है। लोकमत काफी उत्तेजित हो गया था। प्रस्तावित कानून को सिर्फ भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों तक सीमित रखने के संघर्ष में मजदूर हारते जा रहे थे।

इस तीव्र संघर्ष के फलस्वरूप बने कानून पर राष्ट्रपति आइजनहावर ने १४ सितम्बर, १९५८ को दस्तखत कर दिए और इसे '१९५९ का मजदूर-प्रबन्ध रिपोर्ट और रहस्योद्घाटन अधिनियम', का भारी-भरकम नाम दिया। प्रतिनिधि-सभा में दोनों दलों के प्रस्तावकों के नाम पर इसका ज्यादा लोकप्रिय नाम लैण्ड्रम-ग्रिफिन ऐक्ट था। इसमें मजदूरों को दिए गए बुनियादी अधिकारों की रूपरेखा निर्दिष्ट की गई थी, जिसमें यूनियनों के अंदर लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं के संरक्षण की और यूनियन कोषों का दुरुपयोग करने के अपराधी किसी भी अधिकारी के लिए जुर्माने व कैद की सजा का विधान करके इन कोषों की रक्षा की व्यवस्था की गई थी; किसी कम्युनिस्ट अथवा सजायाफ्ता व्यक्ति पर कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होने अथवा जेल से छूटने के बाद ५ वर्ष तक यूनियन के अधिकारी बनने पर पाबन्दी लगा दी गई और यूनियन सदस्यों के अधिकारों में जबरन हस्तक्षेप को संघीय अपराध घोषित कर दिया गया। भ्रष्टाचार तथा रुपया-पैसा ऐंठे जाने की वारदातों से सम्बन्धित व्यवस्थाएँ करने के अलावा इस नए कानून की बदौलत बहिष्कार और धरना दिए जाने के मामलों में टैफ्ट हार्टले ऐक्ट में संशोधन भी कर दिए गए थे जिससे सब यूनियनों की आर्थिक शक्ति बहुत सीमित हो गई।

लैण्ड्रम-ग्रिफिन ऐक्ट में गौण बहिष्कार की, जिस पर टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट के मातहत पहले ही प्रतिबन्ध लगा हुआ था, परिभाषा व्यापक करके उसमें यूनियनों के हितों को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक मालिक को किसी दूसरे . से व्यापार करने देने के लिए मजबूर करना भी शामिल कर दिया

गया था; और इसमें कहा गया कि जिस कम्पनी में कोई और यूनियन कानूनी रूप से मान्य है, उसके खिलाफ़ धरना देना मज़दूरों का अनुचित तरीका है। एक अन्य किन्तु विवादास्पद प्रश्न पर भी इसने उन सब श्रम विवादों को जिनमें राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध बोर्ड कार्रवाई करने से इन्कार कर दे, राज्यों को अपने कार्य-क्षेत्र में लेने का अधिकार प्रदान किया।

लैण्ड्रम-ग्रिफिन ऐक्ट किसी के लिए भी पूर्णतः सन्तोषजनक नहीं था। प्रबन्धक तो इस चीज से असंतुष्ट थे कि बहिष्कार तथा धरना देने के बारे में यूनियनों पर काफी सख्त नियंत्रण नहीं लगाए गए और मज़दूर इसलिए बहुत दुःखित थे कि टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट की कट्टर मज़दूर विरोधी व्यवस्थाओं में संशोधन करने के बजाय उन्हें और मज़बूत कर दिया गया। ए. एफ. एल. सी. आई. ओ. की कार्यकारिणी ने नए कानून की स्पष्ट निन्दा की और कहा कि मज़दूरों के लिहाज से 'यह एक दशाब्दी में सबसे सख्त धक्का है।" 'फैडरेशनिस्ट' ने कहा कि इसका उद्देश्य "मज़दूरों को नष्ट करना" है। विधि-मोर्चे के अन्य क्षेत्रों में मज़दूर सफल संघर्ष कर रहे थे। १९५५ के बाद से सिर्फ दो और राज्यों ने "काम का अधिकार" सम्बन्धी अत्यन्त विवादास्पद कानून पास किए और १९५८ में जब कैलिफोर्निया, ओहायो, कोलोरैडो, इडाहो और वाशिंगटन ने ऐसे कानून बनाने से इन्कार कर दिया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि इस सारे आन्दोलन को एक निर्णायक धक्का लगा है। किन्तु कांग्रेस ने, उस समय जब कि अधिकांश मज़दूर नेता यह आशा कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ युक्तियुक्त संरक्षणों के साथ-साथ संगठन सम्बन्धी गतिविधियों के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, ऐसी टेक अपनाई जिसे अत्यन्त मज़दूर-विरोधी समझा गया।

शक्ति के बुनियादी आधारों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया । इसका सौदेबाज़ी के एकमात्र अधिकार, अनिवार्य यूनियन सदस्यता या यूनियनों के कानूनी संरक्षणों पर, जो रूढ़िपन्थी उद्योग के वास्तविक निशाने थे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा । और इसमें ग़ैर-जिम्मेदारी या भ्रष्ट यूनियन-नेतृत्व के खिलाफ रक्षात्मक बाधाएँ खड़ी करके यूनियन-लोकतंत्र को जो संरक्षण प्रदान किया गया था वह मजदूरों तथा आम जनता के हित में था । इसके अतिरिक्त पहले के श्रम-कानूनों की तरह लैण्ड्रम-ग्रिफिन ऐक्ट के अन्तिम परिणाम भी इस कानून के बारे में अदालती परिभाषा पर निर्भर थे ।

यूनियन-भ्रष्टाचार के भण्डा-फोड़ से जहाँ संगठित मजदूरों की शक्ति के बारे में ये कानूनी संघर्ष लड़े जा रहे थे वहाँ स्वतः राष्ट्र के औद्योगिक मजदूरों को उत्तरोत्तर अधिक लाभ मिल रहे थे । जैसे अधिक वेतन, काम के कम घंटे और बेहतर कल्याण कार्यक्रम जो दूसरे विश्व-युद्ध के बाद से देश के आर्थिक इतिहास की विशेषता रही है । १९५० के दशक के उत्तरार्ध में सामूहिक सौदेबाज़ी के जो समझौते किए गए उनमें करीब-करीब बिना अपवाद यूनियन सदस्यों को नए लाभ प्राप्त हुए । उदाहरणार्थ यूनाइटेड स्टील वर्कर्स ने १९५६ में एक अत्यन्त लाभप्रद त्रिवर्षीय करार प्राप्त किया और दो वर्ष बाद युनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स ने जो समझौता किया वह यद्यपि आशा के अनुकूल नहीं रहा तो भी उसमें वार्षिक सुधार, जीवन-यापन के खर्चे की तालिका के अनुसार वेतनों में हेर-फेर तथा बीमा व पेंशन के लाभों में वृद्धि की व्यवस्था की गई थी ।

इन वर्षों के दौरान औद्योगिक वेतनों में निरन्तर वृद्धि से औसत साप्ताहिक आय ९२.५२ डालर हो गई और काम का औसत सप्ताह ४० घण्टे का हो गया । यह सही है कि ये लाभ महँगाई में निरन्तर वृद्धि से कुछ हद तक बराबर हो गए तो भी महँगाई में वृद्धि की रफ्तार काफी कम हो गई थी जिससे राष्ट्र के मजदूरों की आय में डालर ही नहीं बढ़े, अपितु वास्तविक आमदनी भी बढ़ी । अधिकांश कर्मचारियों को अधिक पेंशन, अन्य पूरक लाभ, लम्बी छुट्टियाँ और अधिक अवकाश के जो अन्य लाभ मिले, उनकी तुलना इस सम्पूर्ण क्षेत्र में चामत्कारिक युद्धोत्तरवर्ती विकास से पहले की परिस्थितियों से मुश्किल से ही की जा सकती है ।

किन्तु तात्कालिक आर्थिक लाभ की तसवीर का एक दूसरा पहलू भी था। १९५० के दशक की आम समृद्धि में १९५७-५८ की मन्दी से रुकावट पड़ी। औद्योगिक हलचलों में कमी का, जो सौभाग्य से बहुत थोड़े दिन तक रही, वेतनों पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा किन्तु इससे बेकारी एकदम बढ़ गई। मन्दी जब पूरे यौवन पर थी तो बेकारों की संख्या ५४,००,००० अर्थात् कुल श्रमिक शक्ति का ६ प्रतिशत थी। अपने-आप में यह बात बहुत विक्षोभकारी नहीं थी किन्तु मज़दूरों के लिए इससे भी ज़्यादा चिन्ता की बात यह थी कि जब अर्थव्यवस्था सुधर गई और औद्योगिक उत्पादन फिर बढ़ गया तब भी बेकारों की संख्या अनुपात से बहुत ज़्यादा रही। मंदी के बाद काफी औद्योगिक क्षेत्र अवसाद में पड़े रह गए जिनके तथा देश की आम समृद्धि बीच बड़ा फर्क हो गया था और १९६० की वसन्त ऋतु में बेकारों की संख्या अब भी ३५ लाख अथवा कुल श्रमिक शक्ति की ४.९ प्रतिशत थी।

यह भविष्य के लिए बुरा संकेत था। ऐसा प्रतीत हुआ कि हमेशा बनी रहने वाली इस बेकारी का कारण अस्थायी मन्दी उतना नहीं, जितना औद्योगिक ऑटोमेशन, जिसने १९५७-५८ के समय की कठिनाइयों को और बढ़ा दिया था। ऑटोमेशन के, जिसे मज़दूरों के जिम्मेदार नेता राष्ट्र के भावी आर्थिक विस्तार में अनिवार्य समझते थे, और अतिक्रमणों से यूनियन सदस्यों की रक्षा कैसे की जाए, यही संगठित मज़दूरों की सबसे कठिन समस्या बन गई। इसे फिकर हुई कि नए लोगों को रोज़गार प्राप्त होना तो दूर की बात है, औद्योगिक उत्पादन में ऑटोमेशन के कारण, जिससे उत्पादन बढ़ने पर भी उपलब्ध रोज़गार कम हो जाते हैं, काम पर लगे हुए श्रमिकों की संख्या क्या बरकरार रखी जा सकती है। इस मूल समस्या का कोई हाज़िर जवाब नहीं था किन्तु यूनियनों को एक ऐसा कार्यक्रम बना लेना सम्भव प्रतीत होता था जिससे जहाँ, कहीं सम्भव हो वहाँ रोज़गार की रक्षा हो सके और अन्यत्र हटाए हुए कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण अथवा वैयक्तिक अनुकूलनों के जरिये नए अवसर प्रदान किए जा सकें। बढ़ी हुई कार्यकुशलता के लाभों को मानना तो लाज़िमी था तो भी मज़दूर नेता यह मानने को तैयार नहीं थे कि मज़दूरों की सहायता के अन्य उपाय किए बिना ऑटोमेशन की वेदी पर उनकी पूर्णतः बलि चढ़ा दी जाए।

सामान्यतः १९५० की दशाब्दी का उत्तरार्ध किसी अधिक विध्वंसक औद्योगिक संघर्ष से मुक्त रहा। सामूहिक सौदेबाज़ी की प्रक्रिया जब भंग हो जाती थी तो बेशक हड़तालें होती थीं किन्तु इनसे मनुष्य दिवसों की हानि ज्यादा नहीं हुई। १९५७ में इनकी संख्या सिर्फ १७० लाख रह गई जो युद्ध के बाद के वर्षों में सबसे कम थी और १९५८ में भी यह संख्या सिर्फ २३० लाख तक ही पहुँची। किन्तु अगले वर्ष एक ऐसी हड़ताल हुई जितनी लम्बी किसी बड़े उद्योग में देश ने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। यह ११६ दिन तक चली, हर किसी के लिए बहुत महँगी पड़ी और कुछ समय के लिए तो राष्ट्रीय अर्थतन्त्र के लिए बहुत खतरनाक प्रतीत हुई। और इस्पात उद्योग की इस महान् हड़ताल के पीछे औद्योगिक ऑटोमेशन की तेज़ रफ़्तार से उत्पन्न समस्याएँ ही मूल कारण थीं। यह वस्तुतः मज़दूरों और प्रबन्धकों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष था। इसमें इस्पात कर्मचारी काम के नियमों के बारे में अपना अधिकार क्षेत्र कायम रखने की कोशिश कर रहे थे जिससे रोज़गारों की रक्षा हो सकती और इस्पात उद्योग उत्पादन के सब नए साधनों पर नियंत्रण के लिए खुली छूट पाने को प्रयत्नशील था।

यह स्वाभाविक था कि यह शक्ति-परीक्षा इस्पात उद्योग में होती। इस हड़ताल से उन पुराने बड़े संघर्षों—होमस्टेड, १९१९ की इस्पात हड़ताल, १९३७ की लिटल स्टील हड़ताल की याद आ गई जिनमें मज़दूरों ने देश के विशालतम उद्योग की मज़बूती से जमी ताकत के खिलाफ़ अपने अधिकारों के लिए जमकर लोहा लिया था। और १९५९ में पुनः संगठित श्रमिकों और उद्योग की समस्त ताकतों ने यह महसूस किया कि इस्पात की हड़ताल के परिणामों पर उनके समस्त हितों का दारोमदार है। इस बार हिंसा और आतंक के दौर-दौरे के बजाय कष्ट-सहिष्णुता की अग्नि-परीक्षा थी।

पहले संघर्ष का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ था। यूनाइटेड स्टील वर्कर्स तथा इस्पात उद्योग में नए करार की बातचीत वेतनों के बारे में कभी समाप्त न होने वाली सौदेबाज़ी का एक और अध्याय प्रतीत होती थी और यह आम खयाल था कि अन्त में कोई न कोई ऐसा समझौता हो जाएगा, जैसे युद्धोत्तर काल में होते आए हैं। असहाय जनता आशंकित थी कि मज़दूरों के वेतन बढ़ेंगे, उसके बाद इस्पात का मूल्य बढ़ाया जाएगा और उसके फलस्वरूप

अन्त में महँगाई बढ़ेगी।

वेतन सम्बन्धी बातचीत के प्रारम्भिक दौर में इस्पात उद्योग का जो रवैया सामने आया उससे पता चला कि इस बार वह वेतनों में और वृद्धि प्रदान न करने के लिए कटिबद्ध है। उसके प्रवक्ताओं ने कहा कि महँगाई पर नियंत्रण रखने का एकमात्र यही उपाय है और उनकी इस दलील को आम जनता का भी बहुत समर्थन मिला। दूसरी ओर इस्पात मज़दूरों का कहना था कि उत्पादन में वृद्धि तथा महँगाई बढ़ जाने—इन दोनों कारणों से वे अधिक वेतन पाने के हकदार हैं और उन्होंने दृढ़ता से कहा कि इस्पात कम्पनियों के मुनाफ़े इतने ज़्यादा हैं कि वे इस्पात के दाम बढ़ाए बिना मज़दूरों की अधिक वेतन की माँग को पूरा कर सकती हैं। स्वयं इसी बात पर भी समझौता होना कठिन था किन्तु धीरे-धीरे यह प्रकट हुआ कि उलझनें और भी हैं। क्योंकि जब उद्योग ने काम के मौजूदा नियमों में संशोधन की माँग की तो इस्पात कर्मचारियों ने अपना प्रतिरोध कड़ा कर दिया। जिसे वे अपने लिए वेतनवृद्धि से भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण चीज़ समझते थे, उस पर उन्होंने कोई भी रियायत देने से इन्कार कर दिया। वेतन के मामले में तो वे समाझौते को सदा संभव समझते थे।

इन परिस्थितियों में जुलाई के मध्य में करार की बातचीत टूट गई और देश भर में इस्पात कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। मज़दूरों तथा उद्योग के बीच खाई को पाटने के बाद में किए गए प्रयत्न ऊबा देने वाली नियमितता से विफल होते चले गए और जब हड़ताल असमाप्त हफ्तों तक खिचती चली गई और इस्पात की सप्लाई खात्मे पर आ गई तो राष्ट्र का सम्पूर्ण अर्थतंत्र लड़खड़ाने लगा। क्रुद्ध जनता, जो दाँव पर लगे मामलों को अब भी ठीक से नहीं समझ रही थी, बल्कि यही समझ रही थी कि इस्पात यूनियन तथा उद्योग आम जनता को नुकसान पहुँचाकर अपना निजी वेतन-युद्ध लड़ रहे हैं औद्योगिक शांति और समृद्धि के हक में सरकार के हस्तक्षेप की माँग करने लगी। आइज़नहावर सरकार ने बड़ी मन्द गति से और बड़ी अनिच्छा से कदम उठाया। राष्ट्रपति अन्त तक भी किसी श्रम-विवाद में नहीं उलझना चाहते थे। अन्त में वे कार्रवाई के लिए मजबूर हुए और अक्तूबर के अन्त में उन्होंने टैफ्ट हार्टले ऐक्ट की आपातकालीन व्यवस्थाओं का आश्रय लिया अर्थात्

उन्होंने घोषणा की कि हड़ताल का जारी रहना राष्ट्र के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा लिए खतरा है और जाँच के लिए एक बोर्ड नियुक्त कर दिया। जब इस बोर्ड ने यह रिपोर्ट दी कि हड़ताल के समाधान का कोई आधार नहीं मिल सका तो उन्होंने न्याय विभाग को यूनियन के खिलाफ ८० दिन का निरोधादेश प्राप्त करने का आदेश दिया। सर्किट कोर्ट ने जिला अदालत द्वारा दिए गए निरोधादेश की पुष्टि की और यद्यपि यूनियन ने इस आधार पर अपील की कि हड़ताल ने कोई राष्ट्रीय संकट उत्पन्न नहीं किया है (राष्ट्रीय रक्षा के लिए आवश्यक सब इस्पात बनाने का उसने वायदा किया था) सुप्रीम कोर्ट ने ७ नवम्बर को १ के विरुद्ध ८ मतों से निचली अदालत के फैसले को सम्पुष्ट किया तब हड़ताली काम पर लौट गए किन्तु यूनाइटेड स्टील वर्कर्स ने हड़-ताल को भंग करने के लिए प्रशासन पर तीव्र आक्षेप किए और किसी भी मुद्दे पर नरम हुए बिना वह निरोधादेश की अवधि समाप्त हो जाने पर पुनः हड़ताल करने पर आमादा प्रतीत हुई।

यह गतिरोध अलङ्घ्य प्रतीत हुआ। वेतन सम्बन्धी मामले की तो बड़ी चर्चा होती थी किन्तु वास्तविक अड़चन, जिस पर कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था, काम के नियमों के बारे में उत्पन्न विवाद और ऑटोमेशन के साथ उन नियमों का सम्भावित सम्बन्ध ही बना रहा। वर्ष की समाप्ति पर हड़ताल फिर प्रारम्भ हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गई और इस्पात का सारा स्टाक पिछली हड़ताल में खत्म हो जाने के कारण अब राष्ट्र के लिए इसके और भी गम्भीर परिणामों की संभावना से लोग इसके और भी खिलाफ हो गए। तो भी यूनियनों ने हड़ताल के लिए कमर कस रखी थी। वस्तुतः काम के नियमों के बारे में उद्योग के दुराग्रही रवैये के कारण इस्पात कर्म-चारियों का हड़ताल का संकल्प और मजबूत हो गया था। जब कैसर कम्पनी ने इस्पात उद्योग के संगठन से अलग होकर यूनियन के साथ स्वतन्त्र समझौता कर लिया तो कुछ समय के लिए तो उद्योग का मोर्चा टूटता प्रतीत हुआ किन्तु उसने अपनी दरार शीघ्र ही भर ली। उद्योग के प्रवक्ताओं ने किसी भी करार के लिए आवश्यक शर्त के रूप में काम के नियमों में परिवर्तन पर फिर जोर दिया।

तब ५ जनवरी, १९६० को एक आकस्मिक और नाटकीय समझौते की

चुनाव के वर्ष में कुछ करना नहीं चाहती थी और कुछ करने की आश्यकता के बारे में उस वक्त की चर्चाओं के बावजूद एक बार समझौता हो जाने पर इस्पात की हड़ताल को बिल्कुल भुला दिया गया प्रतीत होता था। संगठित मज़दूरों तथा उद्योग के बीच उच्चस्तर पर सम्मेलन के प्रस्ताव किए गए जिसका राष्ट्रपति आइज़नहावर ने समर्थन किया और बाद में ऐसा सम्मेलन बुलाया भी; किन्तु इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि जब तक देश के सामने पुनः राष्ट्रीय संकट उपस्थित न हो जाए तब तक उद्योग-व्यापी हड़तालों को पहले से ही रोकने के लिए कोई और कदम उठाया जाएगा।

१९५९ में अन्तर्राज्यीय खलासी-यूनियन समेत अन्य यूनियनों की तरफ से अन्य अनेक हड़तालें हुईं और उनमें भी राष्ट्रपति ने टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट की संकट-कालीन व्यवस्थाओं का आश्रय लिया किन्तु औद्योगिक जगत् पर इस्पात की हड़-ताल छायी रही। यह बड़ा दुःखदायी अनुभव साबित हुआ। आर्थिक मोर्चे पर इस संघर्ष में अन्ततः मज़दूरों की जीत ने राजनीतिक क्षेत्र में उनकी हार की भर-पाई कर दी। तो भी इस वर्ष की घटनाओं ने ए. एफ. एल. सी. आई. ओ. के नेताओं को झकझोर दिया और जैसा कि कार्यकारिणी ने घोषणा की, इसने महसूस किया कि "ट्रेड यूनियन इतिहास के कुछ सबसे खराब तूफानों में से मज़दूर आन्दोलन मुश्किल से ही बचकर निकल सका है।

इन घटनाओं के कारण १९६० के दशक के प्रारम्भ में संगठित मज़दूरों ने अपनी स्थिति को काफी कठिन पाया। यद्यपि इसने इस्पात उद्योग पर विजय प्राप्त की थी तो भी इन कठोर सत्यों को दर-गुज़र नहीं किया जा सकता कि राष्ट्र के मज़दूरों को और संगठित करने का आन्दोलन अपना वेग खो चुका था और लैण्ड्रम-ग्रिफिन ऐक्ट में शामिल नए प्रतिबन्धों में प्रतिक्षिप्त लोकमत पिछली दशाब्दी या इससे भी अधिक अर्से में किसी भी समय की अपेक्षा अब ज्यादा यूनियन-विरोधी प्रतीत हुआ। जब १९५९ की शरद् ऋतु में ए. एफ. एल., सी. आई. ओ. का वार्षिक सम्मेलन हुआ तो उसके नेताओं और सदस्यों दोनों की मूड निराशामय थी और सम्मेलन में मुख्यतः इसी बात की चर्चा रही कि नए मज़दूर-विरोधी अभियान की, जिसे संपूर्ण मज़दूर आन्दो- को कमज़ोर करने अथवा नष्ट करने के लिए बड़े उद्योगपतियों का

चित्र निर्मित करने की आशा करता था।

श्रमिकों के नेताओं ने मज़दूरों के लक्ष्यों तथा सामान्य लक्ष्यों को व्यापक बनाने तथा अपने 'नैतिक नेतृत्व के उत्तरदायित्व' पर कितना ही ज़ोर दिया हो, ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लिए मज़दूरों की खुशहाली ही मुख्य चिन्तनीय विषय रही। पहले के प्रत्येक ज़माने की भाँति अब भी मज़दूर नेताओं से मज़दूरों के तात्कालिक हितों की प्रभावशाली रक्षा और बढ़ोतरी के लिए अच्छी नीतियों के निर्माण की ही सबसे पहले आशा की जाती थी। 'मज़दूर आम लोगों के समर्थन पर निर्भर करते हैं और यह समर्थन लोगों के इस विश्वास पर निर्भर है कि मज़दूर ज़िम्मेदारी से काम करने को तैयार हैं', इस मान्यता का यह अर्थ लगाया जा सकता था कि नए युग में मज़दूरों की स्थिति का अत्यन्त यथार्थवादी मूल्यांकन किया गया है। इस धारणा को लेकर क्या मज़दूर नेता संगठित मज़दूरों के सामने विद्यमान गहन समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करने के उपाय ढूँढ सकेंगे, यह अभी देखना है।

२२ : उप-संहार

अमरीका के सम्पूर्ण इतिहास में कुछ बुनियादी बातों ने संगठित आन्दोलन पर गहरा प्रभाव डाला है। अमरीका में विद्यमान स्वाधीनता तथा जीवन-यापन के अवसर ने किसी वर्गीय भावना को पनपने से रोके रखा। हाल के वर्षों तक बाहर से श्रमिकों के आते रहने के कारण मज़दूरों की बहुतायत ने प्रभावशाली मज़दूर संगठन को असाधारण रूप से कठिन बना दिया था; जाति, भाषा और धर्म सम्बन्धी भेद कुछ अरसे के लिए सामूहिक उत्पादन के उद्योगों में सहयोग स्थापित करने के मार्ग में अलङ्घ्य बाधा सिद्ध हुए। और प्रबन्धक इतने लम्बे अर्से तक न केवल आर्थिक लाभ के आधार पर बल्कि उन्मुक्त अर्थ-व्यवस्था की व्यापक विचारधारा के कारण भी मज़दूर यूनियनों के सख़्त विरुद्ध थे और उद्योगों में एकाधिकारी प्रवृत्तियों के बावजूद वे मज़दूरों को सम्मिलित कार्रवाई का अधिकार देने से इन्कार करते थे।

अमरीका में जीवन-यापन की परिस्थितियों के कारण ही अमरीका के मज़दूर आन्दोलन की यूरोपीय देशों के मज़दूर आन्दोलनों के समान कोई निश्चित ढंग की विचारधारा नहीं रही। औद्योगिक क्रांति के शुरू के दौरों में अमरीकी मज़दूर नेता एक सहकारी कोमनवेल्थ के निर्माण का धुँधला-सा स्वप्न लिया करते थे जिसमें उत्पादन के साधनों के स्वामी अन्ततोगत्वा स्वयं मज़दूर ही बन जाएँगे। किन्तु ये सुनहरे स्वप्न कठोर वास्तविकताओं के साथ अनुकूलन की बजाय उद्योगवाद के परिणामों से बचने के प्रयत्न प्रतीत होते थे और मज़दूरों ने शायद ही कभी उन्हें अपना हार्दिक समर्थन प्रदान किया हो। अपने लिए और उससे भी ज़्यादा अपने बच्चों के लिए अमरीकी जीवन के अवसरों में विश्वास रखते हुए उनकी लोकतंत्रीय पूँजीवाद में मौलिक आस्था थी। उन्हें समाज के मौजूदा ढाँचे में सिर्फ़ अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने से ही वास्ता था।

अमरीकी मज़दूरों पर मार्क्सवादी समाजवाद के मन्तव्यों का कभी भी कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा था। वे राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों पर

मूलतः रूढ़िवादी रुख से ज़्यादा इधर-उधर नहीं भटके। उग्र हलचलों के इक्के-दुक्के उदाहरण जैसे आई. डब्लू. डब्लू. के हिंसात्मक कार्य अथवा कम्युनिस्टों की तरफ से किया गया प्रचार और साजिशें सिर्फ इस बात को ही और ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने लाती हैं कि अमरीकी मज़दूरों की बहुत अधिक संख्या का दृष्टिकोण नरम ही था। न ही आज की आर्थिक घटनाओं से मज़दूरों का यह विश्वास ढीला पड़ा है कि स्वतन्त्र व्यवसाय प्रणाली में उनका भविष्य और भी उज्ज्वल है। मज़दूरों में हाल के मत सर्वेक्षणों से पता चला है कि वे अमरीका में व्यक्ति और समूहों दोनों की प्रगति की संभावनाओं में विश्वास ही नहीं करते बल्कि अधिकांश का यह खयाल है कि उनके बच्चे उनसे भी ज़्यादा सुख-सुविधाओं का उपभोग कर सकेंगे।

इन कारणों से मज़दूर दल बनाने का हर प्रयत्न विफल रहा। उन्हें एक करने के लिए समाजवाद जैसे किसी निश्चित ध्येय के अभाव में मज़दूर अमरीकी समाज के अन्य किसी भी वर्ग के सदस्यों की भाँति अपनी राजनीतिक निष्ठा में सदा से विभक्त ही रहे। किन्तु अगर उनके बारे में कोई सामान्य बात कही जा सकती है तो वह यही है कि उन्होंने अपना प्रभाव सामाजिक सुधार और प्रगतिशील ताकतों के पक्ष में डाला। मज़दूरों के मौलिक लक्ष्य एक वर्ग के रूप में उनके तात्कालिक हितों से ज्यादा व्यापक सिद्ध हुए। हर आर्थिक और राजनीतिक आन्दोलन की भाँति अमरीकी मज़दूर आन्दोलन में भी अवसरवादिता, संकीर्ण स्वार्थपरता और ग़ैर-जिम्मेदारी की भावनाएँ विद्यमान थीं किन्तु सभी ट्रेड यूनियन नेताओं के दिमाग़ में मज़बूत लोकतंत्रीय धारणाएं बद्धमूल रहीं। वे शनैः-शनैः एक ऐसे समाज के विकास की आशा करते रहे हैं जिसमें अमरीकी जीवन के अवसर तथा पुरस्कार उत्तरोत्तर बढ़ती हुई समानता के आधार पर सभी लोगों को प्राप्त हों।

मज़बूत एकजूट मज़दूर आन्दोलन की स्थापना में राष्ट्रीय मज़दूर यूनियन तथा नाइट्स आव लेबर दोनों की विफलता के बाद १९वीं सदी की समाप्ति के दिनों में नए ढंग का संगठन किया गया। व्यावहारिक व्यावसायिक यूनियनवाद पर ज़ोर दिया गया। ए. एफ. एल. ने अपने ट्रेड यूनियन सदस्यों के लिए काम की हालतों में तुरन्त सुधार करने से आगे अधिक व्यापक तथा दूर के ...ों को दृढ़ता से तिलांजलि दे दी। यह कार्यक्रम उस ज़माने की परिस्थितियों

से बहुत अच्छा मेल खाता था और ए. एफ. एल. पहली बार अमरीकी मजदूरों में एक स्थायी राष्ट्रीय संघ बनाने में कामयाब हुआ। किन्तु न्यू डील से उत्पन्न संभावनाओं के कारण संगठन सम्बन्धी दृष्टिकोण में एक बार फिर परिवर्तन सम्भव हुआ और राजनीति तथा सुधारों में, जो सिर्फ राजनीतिक कार्रवाई से ही किए जा सकते थे, मजदूरों की दिलचस्पी फिर जाग उठी। सी. आई. ओ. ने जहाँ शिल्प-यूनियनवाद के विरुद्ध औद्योगिक यूनियनवाद के दावों पर जोर देने के लिए एक मुकाबले का संगठन बना लिया और इस दिशा में औरों से आगे बढ़ गया, वहाँ ए. एफ. एल. ने भी अपना दृष्टिकोण व्यापक किया और अपनी नीतियाँ बदलीं। आज के बहुत से मजदूर नेताओं के विचार सैम्युअल गौम्पर्स की बनिस्बत विलियम सिलविस तथा टेरेंस पाउडरली के विचारों के अधिक निकट हैं। मजदूरों में सहज मतभेदों के बावजूद सामान्य उद्देश्यों के बारे में जो यूनियन सुरक्षा तथा वेतन-घण्टा समझौतों से कहीं आगे तक जाते हैं, काफी मतैक्य है। और यद्यपि मजदूर तीसरे दल की स्थापना का अब भी विरोध करते हैं तो भी राजनीतिक दृष्टि से वे पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हैं और कहीं ज्यादा सफल हैं।

वस्तुतः तो हाल के वर्षों में मजदूर राजनीतिक व आर्थिक दोनों दृष्टियों से इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वे अपनी शक्ति का उपयोग किस तरह करते हैं, यह सबसे महत्त्वपूर्ण बात हो गई है। यूनियन गतिविधियों में अच्छाई तथा बुराई दोनों की विशाल क्षमता है और स्वतंत्र व्यवसाय का भविष्य जितना उद्योग में जिम्मेदार नेतृत्व पर निर्भर करता है उतना ही जिम्मेदार श्रमिक पर भी अवलम्बित है।

मज़दूरों की स्थिति में निरन्तर सुधार से हमारी आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं के संरक्षण में पर्याप्त योग मिलना चाहिए अधिक वेतन से परिवर्तित क्रयशक्ति और काम के घण्टे कम हो जाने से सामाजिक कार्यकलापों में अधिक भाग लेकर ही मज़दूर अमरीकी जीवन-प्रणाली की स्थिरता को कायम रखने में अपना योग दे सकते हैं। यह कहना ठीक ही होगा कि मज़दूरों के लाभ अन्ततः सारे राष्ट्र के लाभ हैं। तो भी आजकल की बड़ी यूनियनें अगर अन्य किसी कारण से नहीं तो अपने बड़े आकार के कारण ही अपनी आर्थिक शक्ति के अन्धाधुन्ध प्रयोग के कारण लोकतंत्रीय समाज के लिए खतरा बन सकती

हैं। मज़दूरों के एकाधिपत्य को उद्योग के एकाधिपत्य से ज्यादा माफ़ नहीं किया जा सकता। जिन नीतियों में जन-हित की अवहेलना कर दी जाती है वे चाहे संगठित मज़दूरों की हों या संगठित उद्योगपतियों की, वे समान रूप से खतरनाक हैं। लोकतंत्र किसी भी एक ग्रुप को चाहे उसका आधार कितना भी व्यापक हो, आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र में अनियंत्रित प्रभुत्व प्राप्त नहीं करने दे सकता।

युद्धोत्तर काल कई दृष्टियों से असाधारण रहा है। इसकी प्रमुख विशेषता-कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए खतरे के फलस्वरूप विदेशी मामलों की प्रमुखता ने औद्योगिक सम्बन्धों पर भी उतना ही सीधा प्रभाव डाला है जितना घरेलू जीवन के अन्य पहलुओं पर। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तथा विदेश-सहायता की आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई उत्पादन-वृद्धि ने और इन कार्यक्रमों से उत्पन्न मुद्राप्रसार के दबाव ने, जिसने राष्ट्रीय अर्थतंत्र पर गहरा प्रभाव डाला है, मज़दूरों की स्थिति को मज़बूत करने में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है। क्योंकि समृद्धि ने प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच तात्कालिक विवाद के मामलों को औद्योगिक आय के बँटवारे में सीमित कर देने में सफलता प्राप्त की। यह आय इतनी अधिक थी कि एक तरफ़ तो इससे कम्पनियों को पर्याप्त और कभी-कभी तो रिकार्ड मुनाफ़े हुए और दूसरी ओर मज़दूरों के वेतनों में शनैः-शनैः वृद्धि होती गई। इन सौभाग्यपूर्ण परिस्थितियों में बड़े परचून व्यवसायों और महान् कृषि व्यवसाय के साथ बड़े उद्योग और बड़ी मज़दूर यूनियनों की संतुलनकारी शक्तियों ने काफ़ी संतुलित अर्थव्यवस्था बनाए रखी है। और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने में बड़ी सरकार का भी और अधिक गहरा और कभी-कभी ज्यादा उलझनपूर्ण प्रभाव रहा है।

आर्थिक गतिविधियों में ह्रास तथा संभावित मन्दी का इन संतुलनकारी ताकतों के मौजूदा संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह बिल्कुल दूसरी बात है और बड़ी सरकार के भावी रोल के बारे में और भी ज्यादा अनिश्चितताएँ हैं। तथापि १९६० में संगठित मज़दूर यूनियन सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए एकमात्र नहीं तो ज्यादातर अपनी आर्थिक शक्ति पर भरोसा करते प्रतीत होते हैं। जैसा कि टैफ्ट-हार्टले ऐक्ट और राज्यों के 'काम का अधिकार' सम्बन्धी कानूनों के खिलाफ़ इनके निरन्तर अभियान से स्पष्ट है,

मजदूर मैत्रीपूर्ण कानून के महत्त्व को पूर्णतः स्वीकार करते हैं, नई कोशिशें अधिक सामान्य बातों के लिए संघीय कानून पास कराने के लिए की गई जिनसे अधिक विशिष्ट सरकारी संरक्षण प्राप्त होने के बजाय सर्वप्रथम वागनर ऐक्ट द्वारा संस्थापित मौलिक सिद्धान्तों का अस्तित्व बना रहे।

हाल के वर्षों में मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच जो संघर्ष उत्पन्न हुए उनसे कभी-कभी राष्ट्र के आर्थिक जीवन में गम्भीर बधाएँ पड़ीं। कभी-कभी उनमें सरकार को हस्तक्षेप भी करना पड़ा। यह मानना पड़ेगा कि जहाँ प्रबन्धकों तथा मजदूरों के बीच समझौता न हो सकने के कारण जन-कल्याण पर संकट उत्पन्न होता हो, वहाँ सरकार पर आम जनता के हित की रक्षा के लिए अपने अधिकारों के प्रयोग का उत्तरदायित्व है। पहले जमाने के उन्मुक्त अर्थ-व्यवस्था के विचार अब बिल्कुल दफना दिए गए हैं। तो भी हम यहाँ फिर इस बात को दोहरा दें कि कुछ थोड़ी सी हड़तालें, जिन्होंने वाकई खतरनाक सूरत अख्त्यार करली थी या जिनमें सरकार को दखल देना पड़ा था, उन अधिकांश मामलों पर पर्दा डाल देती हैं जिनमें समूहिक सौदेबाजी सफलता-पूर्वक सम्पन्न की गई और जिनमें प्रबन्धकों तथा मजदूरों के बीच बिना हड़ताल अथवा तालाबन्दी के रजामन्दी के साथ समझौते कर लिए गए।

इस प्रकार की सामूहिक सौदेबाजी का शनैः-शनैः विस्तृत होता हुआ क्षेत्र; बातचीत अस्थायी रूप से भंग हो जाने पर पंचफैसले अथवा मध्यस्थता की व्यवस्था को अधिकाधिक अपनाया जाना; यूनियन करारों में आम प्रगति तथा हड़ताल अगर हो ही जाए तब भी हिंसा की कम होती जाने वाली वारदातें इस बात की साक्षी हैं कि प्रबन्धकों और मजदूरों दोनों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ रही है। आधुनिक समाज में औद्योगिक सम्बन्ध अब भी एक अत्यन्त विवादास्पद विषय है। तो भी यूनियनों की, विशेषकर नई औद्योगिक यूनियनों की बढ़ती हुई परिपक्वता इस बात की अत्यधिक आशा बंधाए हुए है कि अपने अधिकारों को मनवाने के लिये अमरीकी मजदूरों के लम्बे अभियान से न केवल राष्ट्र के मजदूरों को बल्कि सामान्यतः आम जनता को लाभ हो रहा है।

तानाशाही ख़तरे के सामने अमरीकी लोकतंत्र के मौलिक सिद्धान्तों की रक्षा के लिए संगठित मज़दूर अन्दोलन से ज्यादा शक्तिशाली और कोई प्रभाव काम नहीं कर रहा। जैसा कि स्वदेश और विदेशों दोनों जगह उदार नीतियों को दिए गए इसके सहयोग और समर्थन से स्पष्ट है, मज़दूर आन्दोलन ने स्वयं को उन ताकतों से असंदिग्ध रूप में सम्बद्ध कर लिया है जिनका सतत लक्ष्य एक स्वतंत्र और सुरक्षित संसार में एक स्वतंत्र और सुरक्षित अमरीका की सृष्टि करना है।